

बैंकिंग के सिद्धान्त ➤

और

उनका प्रयोग

लेखक

कान्तानाथ गर्ग, एम० ए०, बी० काम

प्रिन्सपल चम्पा अग्रवाल कालेज,

मथुरा



प्रकाशक

जने

किताब मंदिर इलाहाबाद, बंग - ने अपने यह
महाजना को

विषय-सूची

पृष्ठाव	विषय	पृष्ठ
* १	विषय-प्रवेश	१
२	ग्रन्थों की प्रसिद्धि का इतिहास और उसमें उन्नति	१०
३	बैंकों के भेद	१५
X ४	व्यापारिक बैंक के काम	३०
५	व्यापारिक बैंक के काम करने में प्रणाली	४२
६	केन्द्रीय बैंकिंग (१)	६३
७	केन्द्रीय बैंकिंग (२)	८४
८	सात्र और साव-ग्र	१००
९	बैंक का नाशक तत्त्व सम्बन्ध	१२८
१०	सूचना के लिए बैंकों में उपयोग के मानकों	१५६
११	बैंकों का निर्यात	१७३
१२	भारतीय बैंकिंग	१७६
X १३	बैंकिंग की देशी प्रणाली	१८६
१४	कृषि सम्बन्धी आर्थिक व्यवस्था	२२१
१५	उद्योग सम्बन्धी आर्थिक व्यवस्था	२४५
X १६	व्यापारिक बैंक	२६७
१७	इंग्लैण्ड के बैंक आफ इण्डिया	२८३
१८	विनिमय बैंक	३१३
१९	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया	३२४
२०	बैंकिंग विधान	३४६
२१	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	३५१
२२	देश का विभाजन और उसका बैंकिंग पर प्रभाव	३५३
२३	दोष और भविष्य	३५६

अध्याय १

विषय-प्रवेश

बैंकिंग का विषय वास्तव में प्रथमशः के विषय का ही एक अंग है। किन्तु आज-कल के आर्थिक संगठन में इसका महत्व इतना बढ़ गया है कि हमारे लिए इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक हो गया है। सच बात तो यह है कि किसी देश की औद्योगिक तथा व्यापारिक उन्नति इस समय अर्थशास्त्र में उसके बैंकिंग के संगठन की कुशलता पर ही निर्भर है। अतः हम यहाँ पर इसका अध्ययन प्रत्येक रूप से ही करेंगे।

बैंकिंग का अर्थ

'बैंकिंग' शब्द एक प्रकार से द्रव्य (Money) के व्यवसाय के लिये प्रयोग में आता है। यद्यपि, इस द्रव्य के व्यवसाय में विशेषतया निम्नांकित चारों सम्मिलित हैं — (१) द्रव्य का पारस्परिक विनिमय (Exchanging Money), (२) द्रव्य उधार देना (Lending Money), (३) द्रव्य जमा के रूप में लेना (Depositing Money) और (४) द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थानों को भेजना (Remitting Money)।

अर्थशास्त्र देशों में उपर्युक्त कार्य उपर्युक्त क्रम से ही आरम्भ हुये हैं। हमारे ही देश में वैदिक काल में, महाजन लोग भिन्न-भिन्न मुद्राये (coins) बदलने का काम किया करते थे। इसमें एक राज्य की मुद्रायें दूसरे राज्य की मुद्राओं में और एक प्रकार की मुद्रायें दूसरे प्रकार की मुद्राओं में बदली जाती थीं। साथ ही वे अपेक्षित (needs) लोगों को व्याज पर अथवा व्याज के बिना ही ऋण भी दिया करते थे। बाद में, शायद मनु के बहुत पहिले वे अपने यहाँ द्रव्य जमा के रूप में भी लेने लग गये थे और अन्त में उने एक स्थान से दूसरे स्थानों को भेजने भी लगे थे। उदाहरण के लिये ई. स. १२४४ में तृतीय एडवर्ड ने अपने यहाँ सोने और चाँदी की मुद्रायें बदलने के लिये कुछ राजकीय मराना तालिकाएँ

की थी। ये प्रत्यक्ष बीदे में होते प्रतिशत लाभ लेते थे। साथ ही ये राजों की मुद्रायें तथा देशों की मुद्राओं का साथ भी प्रदान देते थे। इनके गिरे उनके यहाँ विनिमय की दशा थी एक तालिका लटकी रहती थी जिसमें अनुसार ही इनका विनिमय करना पड़ता था। उनका विनिमय लाभ में राजा का भी एक भाग रहता था। यहाँ पर मातृ राज्य के समय में उधार देने की भावना बिल्कुल चालू हो चुकी थी। यहाँ तक कि धीरे धीरे यहाँ और स्वीट्जरलैंड के मुख्य हण्डल (Money-lenders) का साथ में और जब इनके देश के बाहर निगल दिया गया। वे लोग स्वयं देश के स्वर्ण (Goldsmiths) ने ही लिया। जहाँ लगभग अर्धशती वर्षों में १६५० के आदमी बढ़ा। उस समय तक यहाँ अपना व्यवसाय राजस्वोप में ही जमा करती थी, किन्तु उस वर्ष प्रथम बार में उनका प्रत्यक्ष ही राजा निगल दी। इसमें मन्दो न कि यह राजा माद न बाध ले ही नहीं थी, किन्तु इससे राजनीय मर्यादा बढ़ती गई और लोग अपना व्यवसायोप में जमा करने की श्रद्धा मर्यादा में जमा करना अधिक पसन्द करने लगे। अन्य पहिले तो एक स्थान के दूसरे स्थान में भेजने के लिये मनुष्य काम में लाये जाते थे, किन्तु अब यह विनिमय का माग होने लगा, किन्तु पहिले तो केवल व्यापारी वर्ग ही मर्यादा और सेवा करते थे, किन्तु बाद में बैंकर्स वर्ग (Bankers) भी मर्यादा और सेवा करने लगे। आधुनिक काल में बैंकिंग का प्रचार यह सभी काम सम्मिलित हो और बहुत और भी जिनका अध्ययन हम उचित स्थान पर करेंगे।

बैंकिंग की उत्पत्ति

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि बैंकिंग का काम किसी न किसी रूप में भारतवर्ष में ही बहुत ही प्राचीन काल से होता आ रहा है। फ्रान्सीसी लेखक रेवलेट का कहना है कि बैंक और बैंक नोट वेनीज़ोनिया में ईसा के ६०० वर्ष पूर्व भी प्रचलित थे। किन्तु बैंकिंग शब्द का प्रयोग पहिले-पहल ग्रायट ब्रिटी में ही मध्य काल में वेनिस के बैंक की स्थापना के साथ ही हुआ था। उस समय उस देश में बहुत से गणराज्य (city states) थे, जो आपस में लड़ा करते थे। सन् ११७१ में ऐसा हुआ कि वेनिस का राज्य अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध में कैसे रहने के लिए एक बड़े आर्थिक संकट में पड़ गया। जब परिषद् (Grand

Council) के सामने और कोई चारा न रहा तब उसने प्रत्येक नागरिक से उसकी सम्पत्ति का एक प्रतिशत अनिवार्य ऋण के रूप में माँगा। इस पर पोंच प्रतिशत वार्षिक व्याज भी रखा गया। ऋण-दाताओं को व्याज देने और ऋण पत्रों की लेवा-वेची का प्रबन्ध करने के लिये कमिश्नरों की भी नियुक्ति की गई। इटालियन भाषा में ऐसे ऋण के लिए 'मोन्टे' (Monte) नामक एक शब्द है। 'मौन्टे' के हिन्दी अर्थ पहाड़ हैं। वास्तव में इस ऋण से जो द्रव्य प्राप्त हो गया था वह पहाड़ की ही तरह दिखाई पड़ता था। 'मौन्टे' के लिये ज्वाइन्ट स्टॉक फण्ड (Joint Stock Fund) भी प्रयोग में आता था। ज्वाइन्ट स्टॉक फण्ड के हिन्दी अर्थ हैं सम्मिलित पूँजी कोष। वास्तव में ऋण की रकम सम्मिलित पूँजी तो थी ही। इस समय इटली के एक बहुत बड़े भाग पर जर्मनी का अधिकार था। अतः, वहाँ पर 'मौन्टे' का जर्मनी पर्यायवाची शब्द बैंक (Banck) भी प्रयोग में आने लगा। धीरे-धीरे इटली वाले इसे बैंको (Banco), फ्रान्स वाले बैंके (Banke) और अन्त में अङ्गरेज बैंक (Bank) कहने लगे। वेनिस के लेखों से, जिनमें उसने वेनिस के सरकारी ऋणों का वेनिस के तीन बैंका (Bankes) से सकेत किया है, यह पता लगता है कि अङ्गरेज लेखक सत्रहवीं शताब्दी में भी बैंके (Banke) शब्द का ही प्रयोग करते थे। ऐसे बैंक बाद में इटली के अन्य नगरों में भी स्थापित हो गये थे। इनमें मिलन का बैंक, फ्लारेन्स का बैंक और नैपोल का सेन्ट जार्ज बैंक, इत्यादि थे। क्रामवेल के समय इंगलिस्तान में भी उपर्युक्त परिस्थितियाँ में ही एक बैंक की स्थापना करने के लिये एक प्रस्ताव किया गया था, किन्तु जैसा हमें अगले अध्याय के अध्ययन से पता चलेगा, यह सन् १६६४ के पहिले सफलीभूत नहीं हो सका। इस वर्ष ऐसी ही परिस्थितियों में जिन्होंने वहाँ की सरकार को ऋण दिया था उन सत्रा का एक बैंक "बैंक ऑफ इंग्लैण्ड" के नाम से बना और उसे सरकार से एक वार्षिक आय दी जाने लगी। ✓

इस शब्द की उत्पत्ति एक अन्य तरह से भी अनुमानित की जाती है। इसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति बैंक शब्द में है जिसका अर्थ एक ऐसी बैज्र है जिस पर इटली के महाजन अपने मामने-भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्राएँ यह दिखलाने के लिए रखते थे कि वे उन

व्यवसाय करते हैं। किन्तु मकलियट अपनी पुस्तक 'बैंकिंग के सिद्धान्त और उनके प्रयोग' (Banking Theory and Practice) में इस विचार का पूरी तरह से गण्डन करता है। उसका कहना है कि यह उदात्ति बिल्कुल असोत्पादक है। यदि ऐसा था तो यह मराजिन मध्यमाल में बन्चियरी (Benchieri) क्यों नहीं बहने लगे ? उसने अपने कथन की सत्यता प्रमाणित करने के लिये अन्य कई लेखकों द्वारा दिये गये प्रमाण भी दिये हैं। अन्त में यह कहता है कि यह विद्वान् लेखक बहुत ही ठीक कहते हैं। इसका वास्तविक अर्थ एक डेर अथवा पगड है और यह शब्द बहुत से लोगों द्वारा एकत्रित किये गये। एक सम्मिलित कोष का द्योतक है।

बैंकिंग की परिभाषा

यदि अथवा यद्यपि शब्द की अनेक परिभाषायें होने लगे भी निश्चिन्ता तो इस बात की है कि आज तक उसकी कोई ऐसी सन्तोषजनक परिभाषा नहीं बनी है जो सर्वमान्य हो। इसका एक

*Definitions by eminent authorities on the subject —

(1) The word bank expresses the business which consists in effecting on account of others receipts and payments, buying and selling either money of gold and silver or letters of exchange and drafts, public securities and shares in industrial enterprises—in a word—all the obligations whose creation has resulted from the use of credit on the part of states and societies and individuals—*Gautier*

(2) No one and nobody corporate and otherwise can be a banker who does not (i) take deposit accounts, (ii) take current accounts, (iii) issue and pay cheques drawn upon himself (iv) collect cheques crossed and uncrossed for his customers—and it might be said that even if all the above functions are performed by a person or body corporate, he or it may not be a banker or bank unless he fulfils the following conditions

(i) banking is his or its known occupation, (ii) he or it must profess to be a banker or bank and the public take him or it as such, (iii) has an intention of earning by so doing, (iv) this business is not subsidiary—*John Pagel*

मात्र कारण यही है कि बैंकिंग में अनेक प्रकार के कार्य सम्मिलित हैं, जिससे उन सब का एक परिभाषा के अन्तर्गत लाना असम्भव सा है। अधिकांश देशों में तो यह विधानतः निर्धारित दृढ़ से ही किया जाता है जिससे इसके वैधानिक अर्थ में लेश मात्र भी सन्देह नहीं रह जाता है। किन्तु जितने लोग अथवा जितनी संस्थाएँ यह काम करती हैं वे सब विधान की पकड़ में नहीं आतीं। हमारे ही देश में बैंकिंग कम्पनी की एक परिभाषा सन् १९३६ के कम्पनी विधान की २७७ वी धारा में दी गई थी किन्तु रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इस बात की अनेक शिकायतों की थी कि बहुत से बैंक उस धारा के अन्तर्गत दिये हुए काम न करने के कारण उन्हें अपने सम्बन्ध में, जो सूचनाएँ उसे देनी चाहिये, नहीं देते थे। यही कारण था कि सन् १९४२ में उक्त धारा में निम्न आशय का एक संशोधन जोड़ा गया था—‘यदि कोई कम्पनी अपने नाम के साथ बैंक अथवा बैंकिंग शब्द प्रयोग करती है तो चारों ओर उसके यहाँ चालू खातों में द्रव्य जमा किया जाता हो अथवा नहीं वह बैंकिंग कम्पनी समझी जायगी।’ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बैंकों को सघ सरकार से अथवा किसी स्टेट सरकार से एक अधिकार-पत्र प्राप्त करना पड़ता है साथ ही उनके कार्य भली भाँति बता दिये गये हैं और उन्हें उनको विधानतः निर्धारित दृढ़ पर करने के लिये बाध्य किया जाता है। स्थान-स्थान पर ऐसे निरीक्षक नियुक्त हैं जो उनकी

(3) A banker or bank is a person, firm or company, having a place of business where credits are opened by the deposit or collection of money or currency subject to be paid or remitted upon draft, cheque or order or where money is advanced or loaned on stocks, bonds, billon and bills of exchange and promissory notes are received for discount and sale—*Findlay Shirras*

(4) Bank is an establishment which makes to individuals such advances of money or other means of payment as may be required and safely made and to which individuals entrust money or means of payment when not required by them for use—*Kinley*

(5) A banker is one who, in the ordinary course of his business, honours cheque drawn upon him by persons from and for whom he receives money on current account—*Dr H L Hart.*

देख रहे हैं। किन्तु इतने पर भी जनक मन्त्रार्थ ऐसी प्रज्ञा जाती है जो किसी न किसी प्रकार का ब्रिग का कार्य करती है और फिर भी विधान का प्रस्तर्गन नहीं आती है। इस विरहीत गालिन्मान में कोई भी ऐसी विधानिक परिभाषा नहीं करती है। मगर १७८५ में मन्त्रालय (House of Commons) में दी गई एक प्रस्ताव के निम्न आशय का प्रयोग गिरा दिया गया। एक पुस्तक में उद्धृत किया है—“मैं चाहूँ कि प्रस्ताव है” इस नाम में मन्त्रालय का एक गुट है और प्रतिभाषा में जो मन्त्रालय का नाम है उसी गुट के अंतर्गत आता है किन्तु जहाँ प्रस्ताव का नाम है उसमें कोई भी प्रमाण नहीं है। जहाँ प्रमाण नहीं है प्रमाणों का विधान नहीं कर दिया गया है। प्रचलित प्रथा के अनुसार हम ऐसे लोगों को चर्चन करते हैं जिनकी दृष्टान्त है उनमें प्रमाण का काम करनेवाले हैं, दूसरा या दूसरा जमा करने के लिये और मांगने पर उनके सामने प्रमाणों का विधान रखेंगे। जब कोई व्यक्ति ऐसी दृष्टान्त पाल जाता है तब चाहें उसके यहाँ प्रमाण जमा ली जाय या नहीं, हम मान लेते हैं कि वह प्रमाणों के बिना ही हम उसे प्रमाण कहेंगे। तब से प्रमाणों की विधि बहुत ही बढ़ गई है। मन्त्रालय मन्त्रालय (Goldsmith Bankers) मन्त्रालय से चुके हैं। अपने को बहुत प्रमाणों की सम्पत्ति में स्थापित हो चुकी है। किन्तु यह तो अब भी सत्य है कि प्रमाणों पर विधानों के ब्रिग की आज भी कोई परिभाषा नहीं है। वास्तव लोचन करता है ‘तथापि कम से कम आज तो इंग्लैण्ड में सर्वप्रमाणों को ब्रिग शब्द का एक अर्थ ही स्पष्ट जानते हैं। किन्तु यदि इसकी कोई परिभाषा बनाई जाय तो वह अवश्य ही उस परिभाषा में भिन्न होगी जो अन्य किसी देश में है अथवा इसी देश में एक सौ वर्ष पहिले होती। उसने जो परिभाषा दी है वह इस आशय की है ‘एक वह व्यक्ति अथवा मन्त्रालय है जो सर्व साधारण का इच्छा के लिये मॉर्गने पर तुरन्त ही वापस करने की शर्त पर जमा करने के लिये तैयार रहता है अथवा रहती है।’ इस परिभाषा में जहाँ कि उसने स्वयं कहा है किन्तु के व्यवसाय का केवल एक ही अर्थ बतलाया गया है। किन्तु इंग्लैण्ड में तथा उन सभी देशों में जिनमें इंग्लैण्ड की ही ब्रिग के व्यवसायों के अर्थ हैं उन्नति, बृद्धि और उनमें हमारा भावतत्पर्य भी सम्मिलित है किन्तु एक काम बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण उस परिभाषा को जो कि मनुष्यानुकूल काल में तो अवश्य ही

क मानी जा सकती है। किन्तु अन्य देशों में विशेषतया यूरोपीय देशों में, जहाँ चेकों का इतना चलन नहीं है, कोई अन्य काम कर यह परिभाषा बनानी पड़ेगी। फ्रांसीसी लेखक बैङ्क शब्द को अपनी परिभाषाओं में विलो पर अथवा अन्य प्रकार से ऋण देने पर अधिक महत्व देते हैं।

एक अन्य बात भी है जिसे कभी भी नहीं भूलना चाहिये और वह यह कि बैङ्क विलों पर अथवा अन्य प्रकार से केवल उतना ही ऋण देने की समता नहीं रखते जितना उनके यहाँ जमा होता है। सत्य तो यह है कि वह ऋणदाताओं और ऋण लेनेवालों के बीच में केवल मध्यस्थ ही नहीं हैं और यदि कोई परिभाषा ऐसा बताती है तो वह सन्तोषजनक नहीं ठहर सकती है। लन्दन के सराफों ने जो इंग्लैण्ड के सर्वप्रथम महाजन (Bankers) थे अपनी उन्नति के प्रारम्भ ही में यह बात समझ ली थी कि उनके यहाँ जितना द्रव्य जमा किया जाता है उसने कई गुना अधिक वह ऋण दे सकते हैं। वास्तव में यही बैङ्किंग के व्यवसाय की विशेषता है, यद्यपि बहुत बड़े बड़े लेखक भी कभी-कभी यह बात भूल जाते हैं। वे जितना द्रव्य जमा हो उससे अधिक ऋण देने के सर्वथा विरुद्ध रहे हैं। वेनिस, एम्स्टर्डम और हेम्बर्ग के बैंक उनमें जमा किए गये द्रव्य की सीमा के अन्दर ही अपने नोट निकालते थे। मिल ने लिखा है कि नोटों का चलन राष्ट्र के लिये हितकर है, किन्तु उन्हें जमा की हुई रकम से अधिक रकम में निकालना एक प्रकार की ठगी है। वास्तव में यदि ग्राज कल का बैंकिंग का सिद्धान्त देखा जाय तो वह यही है और यदि मिल की बात मानी जाय तो ठग और ठगी सभी जगह प्रचलित हैं। बैङ्किंग की-मकलता तो उपलब्ध साधनों को कई गुना बढ़ा देने पर ही निर्भर है। इस सम्बन्ध की सारी स्थिति केवल इसी वाक्य से स्पष्ट हो जाती है कि दूसरों का द्रव्य और महाजनों की बुद्धि (The Bankers' brain and others' money) यही बैङ्किंग का व्यवसाय है।

अभी यहाँ पर कुछ अन्य भ्रमोत्पादक विचारों का स्पष्टीकरण करना भी आवश्यक है। प्रथम तो यह है कि ऋण देने का काम बैङ्किंग का मुख्य काम अवश्य है किन्तु केवल यही उसके निमित्त-व्यय नहीं है। अतः, हम यह कह सकते हैं कि ऋणदाता केवल ऋणदाता होने पर ही बैंकर नहीं कहे जा सकते हैं। बैङ्कर कहे जाने के लिये यह आवश्यक है कि वे द्रव्य जमा के

रूप में भी लें क्योंकि बैंकिंग व्यवसाय में द्रव्य जमा के रूप में लेना और ऋण देना दोनों सम्मिलित हैं। अकेले रूप से बैंकिंग का व्यवसाय पूरा नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि साव (Credit) के उत्पादन का, जो बैंकिंग के कार्य का एक मुख्य अंग है, यह अर्थ नहीं है कि उमड़े लिये नोट चलाने का अधिकार होना आवश्यक है। वास्तव में इसी क्रमपूर्ण विचार के कारण इंग्लैण्ड में सम्मिलित पूँजी की बैंकिंग की गति दिनां तक उन्नति नहीं हो सकी। बैंक आफ इंग्लैण्ड के अधिकार-पत्र के परिवर्तन के सम्बन्ध में सन् १७०८ में जो विधान बना था उसने उक्त बैंक को छोड़कर अन्य किसी ऐसे बैंक को, जो छ व्यक्ति या न अधिक को मिलाकर बना हो नोट चलाने का काम करने की मनाही कर दी थी। किन्तु उस समय के लोगों का यह विश्वास था कि नोट चलाने का काम छोड़कर जो बैंक बैंकिंग का काम कर ही नहीं सकता है। अतः, उपर्युक्त मनाही के कारण उस देश में गति दिनां तक सम्मिलित पूँजी के किसी अन्य बैंक की स्थापना हो ही नहीं सकी। हाँ, सन् १८३३ के उस विधान में जो बैंक आफ इंग्लैण्ड के उस वर्ष के अधिकार-पत्र के परिवर्तन के सम्बन्ध में बना था, इस बात के स्पष्टीकरण के बाद कि नोट चलाने का काम छोड़कर भी बैंकिंग का व्यवसाय किया जा सकता है, लन्दन में सम्मिलित पूँजी के बैंक स्थापित किये गये। तब इन्होंने जमा लेने और चेकों पर भुगतान देने के उस काम की उन्नति की जिसकी उन्नति स्वयं का काम करनेवाले सराफ मद्राजन उद्धृत दिनों से करते आ रहे थे। कहना न होगा कि वहाँ पर चेकों का चलन ग्राज-क्ल नोटों के चलन से भी कहीं अधिक है। लन्दन के बाहर सम्मिलित पूँजी के बैंकों की स्थापना सन् १८२६ ही से आरम्भ हो चुकी। उस वर्ष इस बात की घोषणा की जा चुकी थी कि वे लन्दन से ६५ मील के व्यास क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में अपने नोट चला सकते हैं।

उपसंहार

उपसंहार में हम यह कह सकते हैं कि बैंकिंग शब्द पहिले-पहिले बारहवीं शताब्दी में ही प्रयोग में आया। हाँ, बैंकिंग का व्यवसाय किसी न किसी रूप में अवश्य ही बहुत ही प्राचीन काल से होता आ रहा था। पहिले-पहिले यह शब्द सम्मिलित कोष का आशय व्यक्त करने के लिये ही प्रयोग में लाया गया था। बाद में द्रव्य जमा करने और

ए देने के काम, जो आधुनिक बैंकिंग के व्यवसाय के मुख्य अङ्ग माने जाते हैं, लन्दन के सर्राफ़ महाजनों द्वारा प्रोत्साहित किये गये। किंतु वे द्रव्य प्राप्त करनेवालों और ऋण लेनेवालों के बीच के केवल मध्यस्थ ही नहीं बरन् जितना द्रव्य जमा के रूप में पाते थे उतने से कहीं अधिक द्रव्य ऋण के रूप में देते थे। चेकों का प्रयोग भी अवश्य ही उन्होंने प्रारम्भ किया था किंतु इसकी उन्नति बाद में लन्दन के सम्मिलित पूँजीवाले बैंकों द्वारा ही हुई। बात यह थी कि वे अपने नोट तो चला ही नहीं सकते थे, अतः, उन्होंने अपनी चेक चलाने के लिये उत्तरोत्तर प्रयत्न किये और वे सबमें सफल भी हो सके। उस समय से इसने इतना महत्व पा लिया है कि अब तक बैंक शब्द की परिभाषा में इसके ऊपर जोर नहीं डाला जाता, वह परिभाषा सन्तोषजनक नहीं मानी जाती। किन्तु यह उसकी परिभाषा के लिये सब जगह आवश्यक नहीं है। यह केवल इंग्लैण्ड और उन सभी देशों में बनी हुई परिभाषाओं के लिये आवश्यक है जिनके यहाँ बैंकिंग की उन्नति इंग्लैण्ड की बैंकिंग की उन्नति के सदृश्य ही हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि बैंक शब्द की कोई भी परिभाषा सब देशों के लिये और सब समय के लिये उपयुक्त नहीं हो सकती।

प्रश्न

१ 'बैंक' शब्द के क्या अर्थ हैं ? क्या इससे केवल बैंकों के जमा प्राप्त करने और ऋण देने के कार्यों का ही बोध होता है ?

२ आपके विचार से 'बैंक' शब्द की क्या उत्पत्ति है ? क्या इसकी उत्पत्ति और इसका व्यवसाय दोनों समकालीन हैं ?

३. 'बैंक' शब्द की परिभाषा बताइये। आपकी परिभाषा बनाने के सम्बन्ध की कौन-कौन सी कठिनाइयाँ हैं ?

४. निम्नांकित की आलोचना कीजिये —

(अ) 'ऋणदाता बैंकर नहीं है।' (ब) 'बैंकर ऋणी और ऋणदाता के बीच का मध्यस्थ है।' (स) 'बैंकिंग का व्यवसाय नोट चलाने का अधिकार पाये बिना नहीं किया जा सकता।' (द) 'बैंक का व्यवसाय केवल द्रव्य को साख पत्रों में और साख पत्रों को द्रव्य में परिवर्तित करने का ही है।'।

अध्याय २

अंग्रेजी बैरिंग का इतिहास और उसकी उन्नति

परिचित ज्ञा जो पार विवेक मन्त्रार्थ ने मणि व अम्रेजी मणि पर निराला हो न मण्डल यन् अत्यावश्यक हो गया है कि हम प्रयत्न नमस्व करे जिस पार उत्तमो उत्तम का अध्ययन हो प ले जो विवेक स्वतः प्रती है । प्रन् इस प्रध्याय न हम दया पर ध्यान देना ।

प्रारम्भ

उत्तर में प्रायः गंगा के तटों की लॉन्गवुड के प्रति वृक्षों ने ही सर्वप्रथम उत्तम रूप में जिनके समय उन्होंने लंदन के उत्तम व्यापारियों को लाया था जिन्होंने राज भी इस लाभकारी स्ट्रीट का नाम से पुकारते थे। डॉ. एच. क. पांडे द्वारा यानेवाल राजाजी न दिन-प्रतिदिन उनके हाथों पर जो धरा लगाये थे उनके माध्यम से तथा अधिक दिनों तक नहीं ठहर सके। किन्तु जमा जमा करने वाले लोगोंने यद्यपि अफ़्गानिस्तान छोड़ दिया, किन्तु उस व्यापार और परिवर्धक, अफ़्गानिस्तान, जो उन्होंने बड़ा चालू किया था उस देश को बढ़ा के लिये धनी बनाता रहा। जो दो, आधुनिक राष्ट्र तो इंग्लैंड में फ़ैबलर मनु १६४० के बाद ही उन समय प्रारम्भ हुई जब बराबर के सर्राफ़ महाजनों ने पिछले अष्टादशवीं शताब्दी परिस्थितियों के कारण जनता का द्रव्य जमा के रूप में लेना प्रारम्भ कर दिया। उसके स्थान में पहिले तो वे ऐसी ग्मीटें देते थे जिनमें उन्हें मौँग पर वापिस देने का उचित दिया जाता था। कहा न होगा कि इस जमा में पाये हुये द्रव्य में वे अनेक प्रकार के लाभ कमाते थे। उस समय की मुद्रायामें उनकी हाथ से ढाले जाने के कारण धातु की आवश्यकता ही कुछ कमो और अधिकता होती थी। वस, ये सर्राफ़ महाजन इसे पूरा समझते थे। अतः, वे जमा में पाये हुये द्रव्य में से वह मुद्राय छोटकर निर्यात (Export) करके लाभ उठा लेते थे, जिनमें अधिक बाहु होती थी। इसके अनिश्चित वे उसे ऋण में देकर और व्यापारियों के विनिमय मिल डिस्काउंट करके अर्थात् समय से पहिले उनका उस समय का मूल्य देकर व्याज भी कमाते थे।

उनके साधनों के कारण उनके पास धीरे-धीरे बहुत से बनी ग्राहक भी आने लगे। क्रौमवेल की और अन्य राजाओं की सरकार भी उनसे ऋण लेने लगीं। अतः यह व्यवसाय लाभदायक होने के कारण उनमें द्रव्य जमा के रूप में लेने की प्रतियोगिता बढ़ने लगी, जिससे उन्होंने उस पर व्याज देना भी प्रारम्भ कर दिया। धीरे-धीरे उनकी रसीड़े नोटों की तरह चलने लगी और कुछ समय में ही वे सुविधाजनक रकमों में निकाली जाने लगीं। सर्राफ़ महाजन पाम बुको का भी प्रयोग करते थे। ये उनके लेजरो से दिन-प्रतिदिन तैयार की जाती थी। द्रव्य जमा करनेवाले जब चाहे तब इन्हें मिलान करने के लिये मँगवा लेते थे और इन्हीं के आधार पर अपने भुगतान के ड्राफ्ट (Draft) दे दिया करते थे। कुछ समय के उपरान्त ये ड्राफ्ट निर्धारित रकमों में छड़ने लगे और द्रव्य जमा करनेवालों को उनके भुगतान करने के लिये दिये जाने लगे। वे इन पर हस्ताक्षर करके उन व्यक्तियों को दे देते थे जिन्हें उन्हें भुगतान देना होता था। इस तरह से उन्हें हम आज फल की चेकों के प्रतिरूप ही कर सकते हैं। सर्राफ़ महाजनो द्वारा चलाई गई यह प्रणाली धीरे-धीरे उनके अन्य बहिन पड़ोसियों द्वारा भी अपनाई जाने लगी। अंग्रेजों में ये शराब के अथवा कपड़े के ऐसे व्यवसायी थे, जिनका जन्मता में यथेष्ट मान था और जो अपनी अच्छी साख के लिये भी कुछ प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। किन्तु उन्होंने चेकों का प्रयोग अधिक बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया। वास्तव में बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड के नोट तो केवल लन्दन में ही बहुत चालू थे। उस समय उसकी शाखाएँ लन्दन के बाहर तो थी ही नहीं, और न रेल इत्यादि मावन ही ऐसे थे कि जिनमें उनके नोट अन्य स्थानों में प्रचलित हो सकते। अतः उन बनी व्यवसायियों के नोट उनके अपने अपने स्थानों में चलते थे और उन्हें चेकों का प्रयोग बढ़ाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। सत्य तो यह है कि पहिले तो लन्दन के सर्राफ़ महाजनो ने आरंभ फिर लन्दन में सम्मिलित पंजीवाले बैंकों ने चेकों का प्रयोग खूब बढ़ाया।

बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड की संस्थापना

इस बात का संकेत तो पहिले अध्याय में ही किया जा चुका है कि यद्यपि इटली के बैंकों की तरह ही इंग्लैण्ड में भी एक बैंक की संस्थापना करने का प्रस्ताव तो क्रौमवेल के ही काल में किया जा चुका था,

किन्तु उसकी सस्थापना जून मन् १६६८ में ही हो सकी। तृतीय विलियम के निधनान्तर होने पर महामन्त्र (Parliament) के अधिवार उठ गये और उसका राष्ट्रीय ग्राह्य-व्यय पर भी नियन्त्रण हो गया। इसका स्तूप में यह फल हुआ कि जो राजकीय मर्यादा पत्रों के राजाओं के दुर्व्यवहार के कारण नष्ट हो गई थी वह फिर से स्थापित हो गई। मन्त्रिमण्डल (Ministry) को द्रव्य से पूर्ण प्रायश्चित्त था और जन-सम्पत्ति उसे पूरा करने के पक्ष में थी। उस मन्त्र का यह परिणाम हुआ कि विलियम पेट्रुस की वह योजना जिसमें कि वह जनता ने १२ लाख पाउण्ड एकत्रित करने राज्य को देना चाहता था, मन्त्र को बहुत पसन्द आया और बैंक आफ इंग्लैण्ड की सस्थापना का बिल महामन्त्र ने पार होकर २५ अप्रैल, मन् १६६४ को राजा द्वारा स्वीकृत भी हो गया। विज्ञापन के इस दिनों के अन्दर ही पूरा द्रव्य मिल गया और ऋण-दाताओं की बैंक आफ इंग्लैण्ड के नाम से एक सस्था बन गई। इस सस्था को उपर्युक्त ऋण पर सन्कार की ओर से ८ प्रतिशत का वार्षिक व्याज और ४००० पाउण्ड प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष के लिये मिलने लगे। इन्हे १२ लाख पाउण्ड तक के नोट चलाने की भी आज्ञा प्रदान कर दी गई।

प्रतियोगी बैंकों पर नोट चलाने के प्रतिबन्ध

और उनका परिणाम

बैंक आफ इंग्लैण्ड की सफलता महामन्त्र के उदार दल (Whigs) की सफलता थी। अतः, जब शक्ति अनुदार दल (Tories) के हाथ में आई तो उसने उसी प्रकार के एक भूमि बैंक (Land Bank) की सस्थापना के लिये प्रस्ताव पार करवाया। किन्तु यह सफल नहीं हो सकी। अस्तु बैंक आफ इंग्लैण्ड के किसी प्रतियोगी बैंक की पुनर्स्थापना रोकने के लिये उदार दलवालों ने पुनः शक्ति प्राप्त करने पर मन् १७०८ में उक्त बैंक के अविकार-युक्त के परिवर्तन के समय इस आशय का एक विधान रखा कि जब तक उक्त बैंक आफ इंग्लैण्ड काम करता रहे, इस बैंक के अतिरिक्त कोई भी ऐसा बैंक जिसमें बैंक जिसमें छ से अधिक व्यक्ति सदस्य हों अपने विनिमय बिल और प्रण-पत्र इंग्लैण्ड में छ महीने से पहिले माँगने पर द्रव्य देने की शर्त पर न चालू कर सके। इसका परिणाम यह हुआ कि लन्दन में और उसके

समीपवर्ती स्थानों में (उस समय बैंक आफ इंग्लैण्ड का आफिस केवल लन्दन में ही था) नोट चलाने का एक मात्र अधिकार विधानतः नहीं तो क्रियात्मक रूप से ही केवल बैंक आफ इंग्लैण्ड ही के हाथ में रह गया । यह सत्य है कि छ' से कम व्यक्तियों के बने हुये बैंक लन्दन में भी अपने नोट चला सकते थे । किन्तु बैंक आफ इंग्लैण्ड के नोट राज्य द्वारा भी स्वीकृत हो जाते थे । जिससे वे सर्राफ़ महाजनो के नोटों की अपेक्षा कहीं अधिक चालू थे । हाँ, लन्दन के बाहर अवश्य उनके नोट चलते थे । बैंक आफ इंग्लैण्ड के नोट सन् १८३३ में विधानतः ग्राह्य (Legal Tender) भी बना दिये गये । अतः, यह स्पष्ट है कि सर्राफ़ महाजनो ने पहिले और अन्य सम्मिलित पूँजीवाले बैंको ने सन् १८३३ के बाद जब वे लन्दन से ६५ मील के व्यास क्षेत्र में नोट न चला सकने के प्रतिबन्ध के साथ वहाँ पर स्थापित हुए, नोटों के स्थान पर चेको का प्रयोग बढ़ाने के निरन्तर प्रयत्न किये । आवागमन के साधनों के उन्नत दशा में न होने के कारण बैंक आफ इंग्लैण्ड ने अपना दफ्तर सन् १८२५ तक केवल लन्दन में ही रक्खा । अतः, तब तक उसके नोट लन्दन से बाहर इतने परिमाण में नहीं पहुँच सके कि वहाँ के महाजनो के नोट वहाँ पर न चल सके । अतः वहाँ के महाजनो ने वहाँ पर चेको के प्रयोग के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया ।

प्रतिबन्ध का संशोधन

सन् १८२६ के विधान ने नोट चलानेवाले सम्मिलित पूँजी के बैंको की स्थापना की इस शर्त पर आज्ञा दे दी कि वे लन्दन में और वहाँ से ६५ मील के व्यास क्षेत्र के अन्दर कहीं भी न तो अपने आफिस खोले और न नोट चलावे । इसके फलस्वरूप देश में लन्दन के बाहर महत्वशाली बैंक खुल गये । सन् १८३३ में इन्हें लन्दन में भी इस शर्त पर अपनी शाखाये खोलने की आज्ञा दे दी गई कि वे वहाँ पर अपने नोट न चलावे । इससे यह बैंक वहाँ भी खुल गये ।

बैंक आफ इंग्लैण्ड का सन् १८४४ का विधान

अब हम बैंक आफ इंग्लैण्ड के सन् १८४४ के उस विधान की ओर आते हैं जिसका अंग्रेजी बैंकिंग की उन्नति में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । इस विधान के पास होने के पहिले कुछ वर्षों से इंगलिस्त्रान की बैंकिंग

की व्यवस्था प्राप्त की जावनीय हो गयी थी। उसमें अनेक जोड़िम (Cases) उठानी पड़ रही थी और इन के बाद दूसरा महान् प्रयास करना दिखाना निकालता चला जा रहा था जिसमें उनके नोट प्रयोग में लानेवाली पन्ना की निम्नतर गति हो रही थी। अतः यह हम विधान के विवरण में गये की जिसके कारण विमानता पड़ी गेली थी। जो विमानता को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था। अतः तो विधान में चुम्बक विधान १८२६ के विधान के अनुसार लन्दन के बाहर नोट चलावनेवाले बाहर मन् १८२९ के विधान के अनुसार बाहर लन्दन में भी नोट न चलावनेवाले का प्रवर्तित पृष्ठों के अन्तर्गत स्थानों की योजना की जा चुकी थी। अतः यह एक साधारण-वर्णनी। बाहर की यह प्राप्ति अगले वर्ष में भी नहीं प्राप्त हुई। अतः अगले वर्ष में अपनी जायदे मोती की रीति उनके हाथ जावनीय की मन्ताया मिल चुकी थी और उसमें स्ट्राइकेस्टर् मेन्चेस्टर तथा म्यान्ची में अपनी जायदे मोल भी ली थी। उन वर्ष प्राप्ति का एक मात्र उद्देश्य शक्तिीय मन्तायों के नोटों का चलावना कम करना था। जो भी, मन् १८२८ के विधान में हमारे लिये उद्देश्य के अन्तर्गत बाहर मन् की गई। तथा वह नोटों के निवर्तन का प्रश्न था, इस समय में विचार बाहर चल रही था, (१) करन्सी से विचारधारा (Currency Principle) और (२) बैंकिंग से विचारधारा (Banking Principle) प्रथम के अनुसार केवल उतनी रकम के नोट चल सके, जितनी के मूल्य का सोना और चादी कोष में हो और दूसरे के अनुसार उनका परिमाण उतना हो सकता था जितने की मन्चेस्टर के लिये नहीं परन्तु वित्तीय व्यापार के लिये आवश्यकता हो। एक प्राप्ति अगले वर्ष मन् १८२८ का विधान प्रथम विचारधारा के लोगों की जीत का प्रतीक था। उसकी मुख्य-मुख्य धाराएँ निम्न आशय की थी—

(१) एक कुल मिलाकर १४० लाख पाउण्ड के नोट मात्र पत्र की जमानत पर चालू कर सकता था। कहना न होगा कि इस १४० लाख पाउण्ड की रकम में १, १०, १५, १०० पाउण्ड तो उस ऋण के ही सम्बन्ध के थे जो बैंक ने समय-समय पर^१ इंग्लैण्ड की सरकार को दिये थे।

^१ बैंक सरकार को उत्तर ऋण देती जाती थी। मन् १८६४ के १२ लाख पाउण्ड से बढ़कर इस समय तक यह १, १०, १५, १०० पाउण्ड हो गया था।

(२) १४० लाख के मूल्य के उपर्युक्त नोटों के अतिरिक्त बैंक को अन्य नोट चालू करने का तभी अधिकार था जब उनके लिये उनके पास शत-प्रतिशत मूल्य का सोने और चाँदी^२ का सुरक्षित कोष हो। हाँ, चाँदी के कोष का मूल्य किसी समय भी सोने के कोष के मूल्य से चतुर्थांश से अधिक नहीं हो सकता था।

(३) यह विधान पास हो जाने के बाद केवल उन्हीं का^३ नोट चलाने का अधिकार रह गया जो छः मई सन् १८४४ को नोट चला रहे थे।

(४) बैंक आफ इंग्लैण्ड को छोड़कर अन्य जो महाजन अथवा बैंक नोट चलाने का अपना उपर्युक्त अधिकार रखना चाहते थे उनके लिये यह आवश्यक कर दिया गया कि वे स्टाम्प कमिश्नर को यह सूचित करें कि २७ अप्रैल सन् १८४४ के पहिले १२ सप्ताहों के बीच में उनके चालू नोटों के मूल्य का क्या औसत^४ था। भविष्य में उसका ४ सप्ताहों का औसत उपर्युक्त औसत से अधिक नहीं हो सकता था।

(५) यदि कोई बैंकर अपने दिवालिया हो जाने के कारण अथवा चाँथी धारा भङ्ग करने के कारण नोट चलाने का अपना अधिकार खो देता था तो फिर वह उसे कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता था।

(६) यदि कोई बैंकर नोट चलाने का अपना अधिकार खो देता था बैंक आफ इंग्लैण्ड उस लोये हुये अधिकार के दो-तिहाई मूल्य के नोट स्वयं अपने साख-पत्रों पर निर्धारित नोटों का परिमाण बढ़ाकर चला^५ सकता था।

(७) नोट चालू करने के अपने एकाधिकार के लिये और उन पर स्टाम्प लगने से मुक्त रहने के लिये बैंक को १,८०,००० पाउण्ड प्रति वर्ष सरकार को देना पड़ने लगा। १४०,००,००० पाउण्ड की रकम के अतिरिक्त अन्य नोट चलाने से बैंक को जो लाभ होता था यह सब भी उसे सरकार को देना पड़ने लगा। इसके लिये बैंक का नोट चलाने का और बैंकिंग के काम करने का ये दो भिन्न-भिन्न विभाग बनाये गये—(१) नोट प्रसार विभाग

^२ सन् १६२८ में चाँदी का सुरक्षित कोष ५५ लाख पाउण्ड का था। उस वर्ष से इसकी गणना साख-पत्रों की श्रेणी में की जाने लगी।

^३ उस समय इंग्लैण्ड और वेल्स में इनकी संख्या २५६ थी।

^४ सब का औसत मूल्य ८६, ३१, ६४७ पाउण्ड था।

(Issue Department) और (२) बैंकिंग विभाग (Banking Department) इन दोनों विभागों का विचार-विस्तार भी अत्यन्त-प्रयत्न रहे लगा ।

उपरोक्त मांगों का एक मात्र उद्देश्य महाजनता और सम्मिलित पूँजी के द्वारा नोट चलाने का अधिकार छीन लेना था । किन्तु समय बड़ा समर्थ लगा और अन्तिम सफलता सन् १९२१ में श्री फाब्रि पाउलर कम्पनी के लाया-गए एक से एकोन-गुना हो जाने पर मिली । हाँ, नोट बनाने की शक्ति भी हमने बड़ी उन्नति अथवा को प्राप्त हो गई ।

सम्मिलित पूँजी के बैंकों के महाजनों का शोषण और पारम्परिक एकीकरण

जिन समय बैंक ग्राफ इंग्लैण्ड का सन् १८४४ में विधान पार हुआ था उस समय इंग्लैण्ड में निम्न प्रकार के बैंक काम कर रहे थे —

(१) बैंक ऑफ इंग्लैण्ड—इसका मुख्य दफ्तर लन्दन में और दूसरी शाखाएँ प्रांतीय शहरों में थीं । इसके नोट दिन-प्रतिदिन प्रचलित हो रहे थे ।

(२) लन्दन के ग्राफ महाजन—इनका नोट चलाने का सीमित अधिकार था । किन्तु ये विगेषतः चेक बनाने की प्रोत्साहित कर रहे थे ।

(३) लन्दन के सम्मिलित पूँजी के बैंक—इन्हें नोट चलाने का अधिकार नहीं था । हाँ, ये भी चेक बनाने की प्रोत्साहित कर रहे थे ।

(४) लन्दन के बाहर के महाजन—इन्हें नोट चलाने का सीमित अधिकार था ।

(५) लन्दन के बाहर के सम्मिलित पूँजी के बैंक—इन्हें भी नोट चलाने का सीमित अधिकार था ।

कुछ समय तक तो उपरोक्त सभी महाजन और बैंक काम करते रहे । किन्तु बाद में उनमें एकाग्रता का भाव बढ़ा और वे शोषण (Absorp-

“ इस धारा के अनुसार बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के साख-पत्रों पर निर्धारित नोट का परिणाम बराबर बढ़ता गया और अन्त में सन् १९२१ में जब अन्तिम महाजन और बैंक का यह अधिकार छीना गया, यह रकम १,६७, ५०,००० पाउण्ड हो गई थी ।

tion) और एकीकरण (Amalgamation) के द्वारा अपनी संख्या तो कम करते गये लेकिन शाखाये फैलाते गये। इस सम्बन्ध की जेम्स डिक की तालिका, जिसे साइक्स ने भी अपनी पुस्तक में उद्धृत किया है, बड़ी ही रोचक है :

वर्ष	बैंकों की संख्या	दफ्तरों की संख्या	एक दफ्तर द्वारा सेवित व्यक्तियों की संख्या
१८८३	३१७	२,३८२	११,३१५
१८९१	२६१	३,२३१	८,९१५
१९०१	१७१	४,८७२	६,६६७
१९११	९९	६,४१३	५,६३०
१९२१	४०	८,०२२	४,७२२

यह अक इंग्लैण्ड और वेल्स के हैं और इनमें स्काच बैंक तो सम्मिलित हैं किन्तु अन्य विदेशी बैंकों की लन्दन स्थित शाखाये सम्मिलित नहीं हैं। वर्तमान समय में समस्त देश में एक दर्जन से अधिक बैंक नहीं हैं।

जिन कारणों से एकाग्रता का भाव बढ़ा उनका सकेत भी साइक्स ने अपनी पुस्तक में किया है। उसका कथन है कि लन्दन के सम्मिलित पूँजी के बैंकों ने लन्दन के बाहर के महाजनो का शोषण तो लन्दन के बाहर अपनी शाखाये बढ़ाने के उद्देश्य से और सम्मिलित पूँजी के प्रान्तीय बैंकों ने लन्दन के सर्राफ महाजनो का शोषण लन्दन में अपनी शाखाये खोलने के उद्देश्य से किया। साथ ही बड़े-बड़े बैंकों का पारस्परिक एकीकरण अपने-को शक्तिशाली बनाने और पारस्परिक प्रतियोगिता दूर करने के लिये हुआ।

कहीं-कहीं ऐसी शंका की गई थी कि कहीं हम एकाग्रता का परिणाम बैंकिंग के व्यवसाय में ऐसा एकाधिपत्य उत्पन्न कर देने का न हो कि वह जनता के लिये हानिकर सिद्ध हो। किन्तु ऐसा नहीं हुआ, वरन् इसके विपरीत इसके कार्य-संचालन में एकरूपता आ गई जिससे बैंकिंग का व्यवसाय एक बहुत ही कुशल ढङ्ग से होने लगा और उससे सुरक्षा बढ़ गई। फिर, इससे एक लाभ और हुआ और वह यह है कि इनकी संख्या बहुत कम होने

के कारण जब कभी भी सारे देश में एक प्रकार की ही नीति पालन करने की आवश्यकता पड़ी तब उन्होंने शीघ्र ही एक नीति परस्पर तय कर ली जिससे जनता बहुत नैतिक सम्बन्ध का बर्दाशीलता से सामना कर सकी।

बैंक आफ इंग्लैण्ड का राष्ट्रीयकरण

आजकल लोगों का जो भ्रम समाजवाद की तरफ हो रहा है उसमें कारण मजदूर तब वे इंगलिस्तान में शक्ति ग्रहण करने के समय में ही बैंक आफ इंग्लैण्ड के राष्ट्रीयकरण की मांग उत्तरोत्तर बढ़ती गई। अतः, १८ फरवरी सन् १९४६ के एक विधान ने इसे पूरा किया गया। उक्त विधान में मुख्यतः निम्न बातें दी हुई हैं —

(१) बैंक के पूँजी पत्र (Capital Stocks) सत्त्वान्त हो राज-कोष के नाम हस्तान्तरित कर दिये जायें।

(२) इंग्लैण्ड का राजा बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और अन्य सचालक नियुक्त करे।

(३) राज-कोष के अधिकारी बैंक के गवर्नर के साथ मन्त्रणा करके उसका प्रमुख एक सचालक-मण्डल को नियुक्त करें।

(४) बैंक को इस बात का अधिकार है कि वह राज-कोष के अधिकारियों की इच्छा से किसी भी बैंक से कोई भी सूचना मांग ले और उसे किसी भी प्रकार की प्राप्ति दे दे।

हरजाने की योजना के अनुसार बैंक के हिस्सेदारों को उनके १०० पाउण्ड के प्रत्येक हिस्से के लिये ४०० पाउण्ड का एक प्रतिशत वार्षिक व्याज का ऐसा सरकारी साख-पत्र दिया गया जिसका भुगतान राज-कोष के अधिकारी ५ अप्रैल सन् १९६६ के बाद जब चाहें तब उसका पूरा मूल्य देकर कर सकते हैं। हिस्सेदारों को इस प्रकार अपने हिस्सों पर वह १२ प्रतिशत व्याज मिल रहा है जो उन्हें, जिस समय बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ या उसके पिछले २० वर्षों से मिल रहा था। बैंक राज-कोष को उसके स्टॉकों पर कोई लाभ नहीं देता। हाँ, उसे उसको उतनी रकम अवश्य देनी पड़ती है जो राज-कोष उपर्युक्त सरकारी साख-पत्र पर व्याज की तौर पर देता है। हिसाब की दृष्टि से तो इस नई व्यवस्था में केवल एक बहुत ही सीधे-सादे लेख का परिवर्तन हुआ है किन्तु वास्तव में बैंक को राज-

कोष के अधिकारियों की इच्छा से, अन्य बैंकों से जो किसी प्रकार की भी सूचना माँगने और किसी प्रकार की भी आज्ञा देने का अधिकार मिल गया है वह सरकार द्वारा जब भी वह चाहे तभी किसी भी राजनैतिक अथवा निजी कारणों से दुरुपयोग में लाया जा सकता है। इतना अवश्य है कि इस सम्बन्ध का मिल जब महासभा द्वारा पास किया जा रहा था तब उसमें सुरक्षा के आशय से कुछ सशोषन कर दिये गये थे जिनसे यह स्पष्ट हो गया है कि (अ) बैंकों से पृथक्-पृथक् खातों की स्थिति नहीं पूछी जा सकती, और (ब) कार्यरूप में यह अधिकार राजकोष के अधिकारियों के कहने से नहीं; बल्कि बैंक जब उचित समझे तभी प्रयोग में लाया जा सकता है।

प्रश्न

(१) सर्राफ़ महाजनो के व्यावसायिक कामों का एक सक्षिप्त विवरण दीजिये और यह बताइये कि उन्होंने नोटों के चलन की अपेक्षा चेकों के चलन पर क्यों अधिक जोर दिया ?

(२) उस परिस्थिति का वर्णन कीजिये जिसमें बैंक आफ इंग्लैण्ड की स्थापना हुई थी। इसे लन्दन में नोट चलाने का एकाधिकार कैसे प्राप्त हो गया ?

(३) बैंक आफ इंग्लैण्ड का सम्मिलित पूँजी की बैंकिंग का एकाधिकार कब और कैसे छिन गया ?

(४) किन परिस्थितियों में बैंक आफ इंग्लैण्ड का सन् १८४४ का विधान बना ? उसकी मुख्य-मुख्य धाराएँ बताइये और यह समझाइये कि उनका क्या प्रभाव पड़ा ?

(५) सन् १८४४ का विधान पास होने के समय किन-किन प्रकार के बैंक इंग्लैण्ड में काम कर रहे थे ? बाद में उनका क्या हुआ ?

अध्याय ३

बैंकों के भेद

आज-कल के हमारे आर्थिक जीवन के प्रत्येक भाग में विशिष्टता (Specialisation) की जो लहर दिखाई दे रही है वह बैंकिंग में भी

भली-भांति व्यक्त है। अतः, भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्देश्यों या वृत्तियों के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के बैंक भी खुल गये हैं। किन्तु उसके बाद अब नहीं है कि यह विनिश्चिता हर जगह पूर्ण रूप से चकल हो गई है और भिन्न-भिन्न प्रकार के बैंकों के साथ ही भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यापार भी चलते हैं और एक प्रकार की बैंकिंग तो दूसरे प्रकार की बैंकिंग के साथ बहुत ही प्रचलित है।

१ व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)

जहाँ में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक बैंक हैं। यहाँ यह कि वह भी हम किसी विशेषण का प्रयोग किये बिना ही 'बैंक' शब्द का प्रयोग करते हैं वह व्यापारिक बैंक का ही प्रोच समझा जाता है। इसके प्रारम्भिक हम प्रथम श्रेणी के व्यापारिक बैंकों के ही समर्थन में आते हैं। जैसा कि इसके विशेषण से सिद्ध हो जाता है वह बैंक विशेषतः व्यापारियों के ही सम्बन्ध रखता है। यह उनकी चालू पूँजी जमा के रूप में सहाय करता है और उनके व्यापारिक लेन-देन के सम्बन्ध की प्रत्यावृत्ति आसज्यताओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसके यहाँ जो रकम जमा की जाती है वह माँग पर देय होती है। अतः, यह लग्नी अवधि के लिये आर्थिक सहायता नहीं प्रदान कर सकता। इससे इस प्रकार के बैंक का यह नियम रहा है कि वह लग्नी अवधि का ऋण नहीं देता और न आय पर लगाने के लिये पूँजी की ही व्यवस्था करता है। साथ ही यह व्यापार के लिये भी स्थायी तौर पर पूँजी नहीं देता वरन् व्यापार करने में जो कभी-कभी पूँजी की कमी पड़ जाती है अथवा उसमें द्रव्य लगाना पड़ता है उसकी यह व्यवस्था कर देता है। इसे व्यापार के लिये ऋण लेनेवालों और सट्टे के लिये ऋण लेनेवालों के बीच में भी भेद करना पड़ता है। एक व्यापारिक बैंक व्यापार के लिये ऋण लेनेवालों को तो प्रोत्साहन देता है और सट्टे के लिये ऋण लेनेवालों को रोकता है। यह किसी दृष्टि में भी जोखिम नहीं उठा सकता और न अवसरवादी ही हो सकता है। इसके यहाँ द्रव्य जमा करनेवालों का इस पर विश्वास रहता है और वह विश्वास इसे उनकी माँग पूरा करने के निवाहना पड़ता है, यहाँ तक कि यदि यह उनकी माँग भी नहीं पूरी कर सकता तो यह समाप्त हो जाता है। किन्तु इसके ऋण देने की क्षमता इसके यहाँ जमा किये हुये द्रव्य तक ही सीमित नहीं रहती। बैंक साव

(Credit) उत्पन्न करते हैं । उनके अधिकांश ऋण नकदी में नहीं भुगतते । यथामुभव वे उसी प्रकार चेकों द्वारा सकारे (Honour) जाते हैं जिस प्रकार उनके यहाँ के जमा के द्रव्य सकारे जाते हैं । इन्हें अनुभव से यह मालूम हो गया है कि एक तो सब लोगों की माँगे एक ही समय में नहीं आती और दूसरे जब एक तरफ इनके कोष से द्रव्य दिया जाता है तो दूसरी तरफ वह प्राप्त भी होता रहता है । इन्हें अपने ऊपर की सारी चेकों के लिये भी नकदी नहीं देनी पड़ती । उनमें से कुछ तो दूसरे बैंकों द्वारा आती हैं और उन चेकों द्वारा सफर जाती हैं जो उन्हें उन्हीं बैंकों के ऊपर की अपने ग्राहकों में प्राप्त होती हैं । इससे यह स्पष्ट है कि वह उनके पास जितनी नकदी होती है उससे कहीं अधिक मूल्य का ऋण देने की जोखिम ओढ़ सकते हैं । जहाँ तक यह प्रश्न है कि उनकी नकदी उनके ऋण की कितनी प्रतिशत हो, इसका उत्तर स्पष्ट शब्दों में नहीं दिया जा सकता । यह प्रत्येक बैंक के ग्राहकों की श्रेणी और उसके लागत (Investments) की श्रेणी के ऊपर निर्भर रहता है । कभी-कभी तो यह ऋण परिवर्तन के साथ साथ भी परिवर्तित होता रहता है । फिर यह जनता के बैंकिंग की आदत बदलने से भी एक बहुत बड़े काल में बदल जाता है । 'तथापि बैंकों के प्रत्येक व्यवस्थापक के मस्तिष्क में उस प्रतिशत का अनुमान अवश्य रहता है जिसे उसे रखना चाहिये और जिसे कम कर देने से उसे जोखिम उठानी पड़ती है तथा बढ़ा देने से लाभ की क्षति होती है ।' जिन कार्यों का विवरण ऊपर दिया जा चुका है उनके अतिरिक्त अन्य कार्य भी व्यापारिक बैंक करते हैं । इनका विस्तृत अध्ययन हम उचित स्थान में करेंगे । हाँ, इतना अवश्य है कि ये कार्य हर देश में समान नहीं हैं, कहीं कुछ हैं तो कहीं कुछ हैं । इनमें काम करने के दलों के विषय में भी यही कहा जा सकता है । जब अंग्रेजी बैंक और विशेषतया लन्दन के बैंक लागत का व्यवसाय (Investments Banking) नहीं करते, जर्मन और फ्रान्सीसी बैंक ऐसा करते हैं । अंग्रेजी बैंक चेकों के प्रयोग पर भी बहुत जोर डालते हैं किन्तु जर्मन और फ्रान्सीसी बैंक ऐसा नहीं करते ।

२. केन्द्रीय बैंक (Central Banks)

यद्यपि केन्द्रीय बैंकों के कार्यों की क्रमिक उन्नति तो बहुत दिनों से होती आ रही थी किन्तु इस शताब्दी के प्रारम्भ तक वे स्पष्ट रूप से प्रकट

नहीं हो पाये थे। प्रत्येक बैंक के व्यवस्थापक उस समय तक अपनी इच्छा के अनुसार ही मनमाने कार्य किया करते थे। बहुत से प्राचीन देशों में तो एक बैंक धीरे-धीरे बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा था और विशेषतः नोट चलाने का और सरकार के बैंकिंग के काम करने का एकाधिकार अपना मुख्य अधिकार प्राप्त करता जा रहा था। यही बैंक प्राग्भ में 'केन्द्रीय बैंक' न कहे जाकर नोट चलाने वाले बैंक (Bank of issue) अथवा राष्ट्रीय बैंक (National Bank) कहे जाते थे। रा. जीने-घॉरे उनके काम और उनके अधिकार बढ़ने गये तथा उनके साथ 'केन्द्रीय' शब्द एक विशेष कार्य के साथ प्रयोग में आने लगा। कहना न होगा कि बैंक आक स्मलण्ड ही गायब ऐसा बैंक था जिम्मे करने परिले 'केन्द्रीय' बैंकों का नाम म्ता प्राग्भ कर दिया था। अतः, 'केन्द्रीय बैंकिंग' के सिद्धान्त में व्याख्या करने के लिये इसी ही उक्ति का इतिहास सर्वत्र अध्ययन किया जाता है। प्रसङ्गवश यही बैंक इंग्लैण्ड का सम्मिलित बैंकों का सर्वप्रथम बैंक भी था। उसीमें १९०० की शताब्दी में भिन्न भिन्न राष्ट्रों ने या तो अपने यहाँ के किसी पुराने बैंक को ही नोट चलाने का एकाधिकार अथवा मुख्य अधिकार दे दिया था या किसी नये बैंक की स्थापना करके उसे यह अधिकार दे दिया था। हाँ, नई दुनिया के सभी देश और पुरानी दुनिया के भारतवर्ष और चीन अवश्य ही ऐसे वचे थे कि जिनके यहाँ इस शताब्दी के प्राग्भ तक कोई भी 'केन्द्रीय बैंक' नहीं खुल सका था। यहाँ तक कि आधुनिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देश अर्थात् संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी सन् १९१४ तक कोई भी 'केन्द्रीय बैंक' नहीं खुल पाया था। इस वर्ष यहाँ पर भिन्न-भिन्न स्थानों के लिये १२ 'केन्द्रीय बैंक' खुले जिनमें फेडरल रिजर्व बैंक (Federal Reserve Banks) कहते हैं। साथ इनके कार्यों के एकीकरण के लिये एक बोर्ड भी बनाया गया जिसे फेडरल रिजर्व बोर्ड (Federal Reserve Board) कहते हैं। 'केन्द्रीय बैंकों' ने प्रथम महायुद्ध के समय और उसके बाद ही अपने-अपने यहाँ के राष्ट्रों को इतना लाभ पहुँचाया और सहायता दी कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक अविशेष ने, जिसकी बैठक सन् १९२० में ब्रुसेल्स में हुई थी, सभी राष्ट्रों को अपने यहाँ इन्हें खोलने के लिये मन्त्रणा दी। अतः, तब से यूरोप में जो नये राष्ट्र बने उन्होंने और नई और पुरानी दुनिया के उन सभी राष्ट्रों ने, जिनके यहाँ उस समय तक 'केन्द्रीय बैंक' नहीं थे अपने यहाँ उन्हें खोल लिया है। चीन का सेंट्रल बैंक और भारतवर्ष का रिजर्व बैंक

क्रमशः सन् १९२८ मे और सन् १९३५ मे स्थापित किये गये थे। वास्तव में बैंकिंग और वाणिज्य की आधुनिक परिस्थितियों के कारण प्रत्येक देश में चाहे उसके आर्थिक उन्नति की कैसी भी दशा क्यों न हो, इस बात की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है कि वहाँ की नकदी का कौष केन्द्रित रहे और करन्सी और साख के नियन्त्रण पर किसी न किसी प्रकार की 'राष्ट्र' की देख-रेख और यथासम्भव उसका हाथ रहे। केन्द्रीय बैंकों के कारण भिन्न-भिन्न देशों के बैंकों के बीच में पारस्परिक सहयोग और सम्बन्ध की मात्रा भी बढ़ गई है।

३ विनिमय बैंक (Exchange Banks)

विनिमय बैंकों का एक मात्र लक्ष्य विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता पहुँचाना और भिन्न-भिन्न देशों के पारस्परिक लेन-देनों का भुगतान करना ही है। उनकी शाखाएँ सारी दुनिया में फैली रहती हैं और विशेषतया व्यापारिक देशों में तो अवश्य ही रहती हैं। शायद यही कारण है कि उन्हें बहुत अधिक पूँजी की भी आवश्यकता पड़ती है। फिर, विनिमय का व्यवसाय कुछ पेचोदा भी है और उसे करने के लिये अनुभव और कार्य-कुशलता की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जोखिम भी यथेष्ट है। हाँ, यह इधर विनिमय मान (Exchange Standards) के चलन से अवश्य कुछ कम हो गई है। इसके पहले स्वर्ण मान (Gold Standard) और रजत मान (Silver Standard) वाले देशों के बीच की विनिमय दरों में बहुत परिवर्तन होते थे और उनके विनिमय के सम्बन्ध एक प्रकार से बहुत ही जोखिम के होते थे। इन सब कारणों से साधारण व्यापारिक बैंक यह काम कर ही नहीं सकते थे। अतः, इसके लिये एक विशेष प्रकार के बैंकों की आवश्यकता पड़ी। ये बैंक निर्यात करनेवाले व्यापारियों से उनके विनिमय बिल खरीद लेते हैं और उन पर वसूल हुई रकम आयात करनेवाले व्यापारियों के हाथ वेच देते हैं। अधिकांश निर्यात के लिये निर्यात करनेवाले व्यापारी (Exporters) उनका आयात करनेवाले व्यापारियों (Importers) के ऊपर विनिमय बिल कर देते हैं और फिर उनकी वसूली के लिये न रुककर उन्हें विनिमय बैंकों के हाथ या तो वेच देते हैं या डिस्काउण्ट करा लेते हैं। अब, ये बैंक उन्हें या तो उनके भुगतान की तिथि तक अपने पास रखते हैं या उसके पहिले ही विदेशों में विशेषतः लन्दन

और न्यूनान के बाजारों में जहाँ मई में उनकी माँग गहरी है, बेच देते हैं। जिस देशों में उनकी माँग नहीं होती उनमें उनके प्रतिनिधि होते हैं। अतः, वहाँ पर वह उनकी क माँग काम करते हैं। वे उन पर अपने प्रतिनिधियों को मिल करते हैं और जिन्हें मात्र सुगताय लेना होता है वह उन्हें उन के पत्र में लिखवाकर ले लेते हैं जिन्हें उन्हें सुगताय लेना होता है। वे बैंक प्रत्यर्गशीय सुगताय के अन्तर्गत भाग का सुगताय मोना, चांदी और ताँबे का मगताय प्रत्यर्ग मोना करते हैं। अतः, इन व्यवसाय में उन्हें इनका व्यापार करने का भी परस्पर मिल जाता है। वे जहाँ के प्रतिनिधियों (Forward Exchange) का भी रूप और विचार करते हैं जिन्हें भिन्न भिन्न समय के प्रतिनिधियों के भागों के बीच का परस्पर अंतर हो काम होता जाता है, और व्यापारियों की प्रतिनिधियों द्वारा के परिवर्तन से जो लाभ होती है वह भी इनके अपने द्वारा जोड़िये ओढ़ लेने के कारण अचर्य होती है। जहाँ तक इनकी रकम की जोड़िये का प्रश्न है उसे भी वे विरुद्ध मोढ़े करके अर्थात् रकम के लिये प्रिय करके और प्रिय के लिये रकम करके बचा लेते हैं। भारतवर्ष में तो नहीं किन्तु अन्य देशों में तो प्रतिनिधियों के अतिरिक्त व्यापारी बैंक भी यह व्यवसाय करते हैं। वहाँ पर प्रतिनिधियों के विदेशी बैंक हैं जो इसे अपनाये हुये हैं।

५ औद्योगिक बैंक (Industrial Banks)

औद्योगिक बैंक कृषि के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योग धन्वों की आर्थिक सहायता करते हैं और उन्हें अन्य प्रकार में भी मदद पहुँचाते हैं। व्यापारिक बैंक अपने विशेष उत्तरदायित्व के कारण यह कार्य नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त उनके पास उद्योग-धन्वों का अनुभव रखनेवाले व्यक्ति भी नहीं होते। औद्योगिक बैंकों के पास लग्नी अवधि के लिये जमा की हुई रकम रहती है और साथ ही उनके पास ऐसे अनुभवों व्यक्ति भी रहते हैं जो उद्योग-धन्वों के पेशीदा प्रश्न समझते हैं। वे उन औद्योगिक कंपनियों के ऊपर जो उनसे सहायता प्राप्त करती हैं उनके यहाँ अपने प्रतिनिधि रखकर अपना नियन्त्रण भी रखते हैं। जब कोई औद्योगिक कंपनी किसी औद्योगिक धन्वों से अपने हिस्से और ऋण पत्र जनता के सामने रखने में सहायता माँगी है तब वह बैंक जो पहिला काम करता है वह उसकी योजना समझने तथा उसका विश्लेषण करके उसके भविष्य पर दृष्टि डालने का है। कभी-कभी जब किसी कंपनी के निकाले हुये सब हिस्से अथवा उनका वह न्यूनतम भाग

जो उसके विवरणपत्र (Prospectus) में दिया जाता है जनता द्वारा यथा समर्थ नहीं ले लिया जाता तब यही बैंक उसे स्वयं ले लेने है। प्रायः नई कम्पनियों के िस्तों की बिक्री का ये लोग प्रारम्भ ही से एक प्रकार का प्रीमा कर देने हैं। ये अपने ग्राहकों को उनकी रकम लगाने के सम्बन्ध में भी उल्लास देते हैं और जहाँ तक होता है उन्हें अच्छे लागत के चुनाव में सहायता पहुँचाते हैं। इनसे कारबारिया को भी यह लाभ होता है कि वे हिस्से बेचने के सम्बन्ध में मुक्त हो जाते हैं। सत्य तो यह है कि ये इस काम में निपुण होने के कारण हिस्सों और मृण-पत्र सम्बन्धी विज्ञापन करने और उन्हें बेचने में कारबारियों ने कहीं अधिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जर्मनी, म्युन्ख राइट्र अमेरिका और जापान, इत्यादि देशों की औद्योगिक उन्नति इन्हीं बैंकों के कारण हो पाई है।

५ कृषि बैंक (Agricultural Banks)

कृषि में अपना समझाये होती है। अतः, उसकी आर्थिक सहायता करने के लिये पृथक् बैंक भी होते हैं। इनके दो भेद हैं—(१) एक तो वे जो लम्बी अवधि की आवश्यकताएँ (Long-term needs) पूरी करते हैं और (२) दूसरे वे जो थोड़ी अवधि की आवश्यकताएँ (Short term-needs) पूरी करते हैं। लम्बी अवधि के ऋण-भूमि में स्थायी सुधार करने के लिये, अधिक भूमि खरीदने के लिये और कृषि के अच्छे तरीके और औजार प्रयोग में लाने के लिये जाते हैं। और थोड़ी अवधि के ऋणों का उद्देश्य कृषकों की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताएँ पूरी करना है। उनमें बीज और खाद खरीदना, अपने खर्च, मजदूरों की मजदूरी, सिंचाई तथा अन्य करों का भुगतान, इत्यादि सभी सम्मिलित हैं। कृषकों के पास जो जमानत (Security) रहती है और जिन अवधि के लिये उन्हें ऋण की आवश्यकता रहती है वह सब ऐसे हैं कि उनकी व्यापारिक बैंक, विनिमय बैंक तथा औद्योगिक बैंक सहायता कर ही नहीं सकते। अतः इस काम के लिये भूमि-बन्धक बैंक (Land Mortgage Banks) और सहकारी बैंक (Co-operative Banks) हैं। भूमि-बन्धक बैंक तो लम्बी अवधि की और सहकारी बैंक थोड़ी अवधि की माँगें पूरी करते हैं।

भूमि-बन्धक बैंक—ये बैंक भूमि से चालू साग-भत्र बना लेते हैं। ये शहरी और देहाती दोनों होते हैं। शहरी बैंक मकान, इत्यादि बनाने में सहायता देते हैं। अतः, हम लोग यहाँ पर इनका अध्ययन नहीं करेंगे।

देहानी पैसा की स्वयं की रहन पूरी होती है। यह इन दिनों अत्यंत मृग-पत्तों की बिक्री के प्राप्त होती है। इनके यानी पत्तों रहन पर देने के कारण उसमें जो भूमि प्राप्त होती है उसका जमानत पर यह जगह में अपने मृग-पत्र चालू करते हैं। जब कुछ भूमि की जमानत पर चालू किये तब मृग-पत्रों के प्राप्त रकम अन्य भूमि के रहन में लग जाती है तब बड़ी अन्य भूमि फिर नये मृग-पत्रों की जमानत के लिये काम में आ जाती है और उनमें नई पत्तों प्राप्त हो जाती है। यह प्रसार यह चलता रहता है। ये केवल उत्साहन के लिये न मृग-पत्र देते हैं और जो भूमि इनके यहाँ रहन की जाती है उनका ये बहुत गतिधारी से नूतन निर्वाहित कर लेते हैं। फिर, उन पर यथा की गुणांश (margin) रखकर मृग-पत्र देते हैं। इनके मृग-पत्र संग्रहण बार्किंग निर्यात में होता है और वह एक बहुत लम्बा अवधि में निर्वाहित कर दिया जाता है। उस पर उचित व्याज भी लिया जाता है। इनके द्वारा निकाले हुए मृग-पत्र सुरक्षित होने के कारण यह प्रिय होते हैं और जनता में उनकी बड़े माग होती है। उनमें इन्स्ट की आर गोमे की रकम भी लगान की आशा से दी गई है। भूमि और मकान, इत्यादि आवासीयों में नदी बिक पाते। इसमें अनेक वैधानिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। किन्तु इनसे जो चालू माज-पत्र निकाले जाते हैं वे आमानी से हस्तान्तरित किये जा सकते हैं वे बाजारों में बिकने भी हैं। अतः, इनके कारण उपर्युक्त कठिनाई दूर हो जाती है। फ्रान्स का क्रेडिट फोन्सियर (Credit Foncier) जिसकी स्थापना सन् १८५२ में हुई थी भूमि-बन्धक बैंक का पिता कहा जाता है और वह जर्मनी, स्पेन, आस्ट्रिया, हंगरी और जापान के ऐसे ही बैंकों के माय-माय बहुत ही उन्नति कर रहा है। इंगलिस्तान का कृषिक भूमि बन्धक कारपोरेशन भी जो अब से कुछ वर्षों पहले स्थापित किया गया था बहुत काम रहा है। हमारे देश में भी ऐसे बैंकों की संख्या बढ़ती जा रही है। किन्तु यह अभी तक सन्तोषजनक नहीं है। वास्तव में इस देश के मुख्यतः कृषक-देश होने के कारण और यहाँ की कृषि की अवस्था पिछड़ी होने के कारण यहाँ पर ऐसे बैंकों की बहुत आवश्यकता है।

सहकारी बैंक—ये बैंक कृषकों के स्वयं के बैंक होते हैं। उनके दूर-दूर फैले रहने के कारण उन्हें थोड़े समय के लिए छोटी छोटी रकम मृग-पत्र देना इतनी जोखिम का काम है कि उसे कोई भी आधुनिक बैंक नहीं कर

सकता । इसमें सन्देह नहीं कि इसे करने के लिये महाजन हैं । वास्तव में उनका जो स्थानीय प्रभाव रहता है और वहाँ के लोगों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है उसके कारण वे इसके लिये बहुत उपयुक्त हैं । किन्तु उनकी शर्तें इतनी कठिन रहती हैं कि वे कृषकों के मित्र नहीं बरन् उनके लिये जोक के समान हैं । यदि देखा जाय तो इस काम में जितनी जोखिम है उसके लिये यह उचित ही है । जहाँ तक लम्बी अवधि के ऋण का प्रश्न है उसकी जमानत के लिये तो कृषकों की भूमि है किन्तु थोड़ी अवधि के लिये तो उनके पाम उनके हल, बैल तथा मोपड़ी छोड़कर कुछ भी नहीं बचता । अतः, उन्हें इस मामले में स्वावलम्बी होना पड़ता है और सहकारिता की शरण लेनी पड़ती है । इसका प्रारम्भ गत शताब्दि में पहले-पहिल जर्मनी में हुआ था । वहाँ की कृषि की दयनीय दशा का रैफेसिन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने स्थिति सुधारने के लिये सहकारी समितियों की स्थापना की जो थोड़ी अवधि की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये धन एकत्रित करने के उनके स्वयं के संगठन हैं । अपने सम्मिलित साधन एकत्रित करके अपने वैयक्तिक उत्तरदायित्व के सहारे वे द्रव्य के बाजार से द्रव्य उधार लेते हैं और उसे अपने में से जिन्हें आवश्यकता पड़ती है उन्हें कम व्याज पर देते हैं । ऋण की अदायगी प्रायः मासिक किस्तों द्वारा होती है और वह लेने वालों के प्रण-प्रत्रों की जमानत पर मिलता है । फिर, इन पर कुछ अन्य सहयोगी सदस्यों के हस्ताक्षर कराके इनके द्वारा बाजार से और अधिक ऋण प्राप्त कर लिया जाता है । यह प्रणाली ईमानदारी को पूँजी बनाने की प्राणाली (Capitalisation of Honesty) कही गयी है । इससे वैयक्तिक जमानत एक बहुत बड़ी मात्रा में बिकने योग्य जमानत में परिवर्तित हो जाती है । कृषि की थोड़े समय की आर्थिक माँग पूरा होने के साथ-साथ इससे अन्य भी बहुत से लाभ होते हैं । इससे सदस्यों के बीच में स्वावलम्बन और मितव्ययता का भाव बढ़ता है और उन्हें स्वशासन की कला की शिक्षा भी प्राप्त होती है ।

५. सेविंग्स बैंक (Savings Bank)

ये बैंक सच पूछा जाय तो बैंक नहीं हैं । वास्तव में ये साधारण स्थिति के लोगों में मितव्ययता का प्रचार करके उनकी थोड़ी-थोड़ी बचत एक-

जिन रुपये मुद्रित करने लगे हैं । इनके मादलों का समाजी
 हरे रक्तमिनी जानेवाली रक्तम की प्रपेक्षा समान कर प्रधिक रक्तम
 है । अतः, इनका उस मशीन द्वारा (liquid plate) में रखने
 में भी आवश्यकता नहीं रहती । लगे सम्पूर्ण उनमें व्यापारिक क्षेत्रों
 के समान प्रमाणों का वाद समान में वाणिज्य होने वाले क्रमों में भी
 लगाने की आवश्यकता नहीं रहती । किन्तु यह उत्तम धनत्व भी नहीं
 रहते । इनका तान आनी पानी के साथ कुछ मुद्रित लागता में ही लगाने के
 लिये भाग्य करता है । उनमें द्रव्य जमा करने और उनमें निम्नलने के नियम
 भी भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न हैं । प्रायः कोई भी इनके यहाँ अपना
 पाना मोल करता है । प्रत्येक राज्य को एक नाम-मुद्रक दी जाती है निम्न
 बंद में उनका जो खाता रहता है उसकी प्रतिनिधि होती है । उच्च प्राप्त
 समाह में केवल एक प्रयत्न दो बार ही निम्नला जा सकता है और गद्दी-गद्दी
 रक्तम निम्नलने के लिये पत्रों में कुछ समय में सूचना देनी पड़ती है ।
 जिनकी रक्तम इनमें जमा होती है उनमें अधिक निम्नलने में कभी भी आशा
 नहीं मिलती । सयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अनेक प्रकार के सेविंग बैंक हैं ।
 इङ्गलिस्तान में आकर यह काम करते हैं और हमारे देश में भी ऐसा ही है ।
 किन्तु यहाँ पर व्यापारिक बैंक भी अपने यहाँ ऐसे करने करते हैं ।

७ निजी बैंक (Private Banks)

उपर्युक्त सभी बैंक आधुनिक काल के बैंक हैं । किन्तु इनके अतिरिक्त
 कुछ ऐसे निजी बैंक भी हैं जो व्यापार के साथ-साथ बैंकिंग भी करते हैं ।
 इनके काम करने के दृष्टि भी बहुत पुराने हैं । इङ्गलिस्तान के ऐसे सराफ
 मशहून तथा अन्य महाजनों के विषय में हम पहिले ही पढ़ आये हैं । हमारे
 देश में इनकी संख्या आज भी बहुत है । वास्तव में ऐसा कोई स्थान नहीं है
 जहाँ यह न पाये जाते हों । प्रायः कृषि के सारे धन और देशान्तर्गत
 व्यापार के एक बहुत बड़े भाग को यही आर्थिक सहायता पहुँचाने हैं ।
 इनके सुधार की आवश्यकता तो अवश्य है किन्तु जैसा कि किसी विद्वान्
 ने कहा है यह हमारे आर्थिक संगठन के बहुत ही आवश्यक अङ्ग हैं और
 इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता । साथ ही इनसे समाप्त कर देने
 से न केवल भारतवर्ष ही को बल्कि समस्त संसार के सभी देशों को एक बहुत

बही क्षति उठानी पड़ेगी। कुछ ऐसे बैंक आज भी सभी देशों में पाये जाते हैं।

८ अन्य प्रकार के बैंक (Miscellaneous Banks)

लोगों की विशेष आवश्यकतायें पूरी करने के लिये आधुनिक काल में स्थान-स्थान पर कुछ अन्य प्रकार के भी बैंक खुल गये हैं। उदाहरण के लिये इंग्लैण्ड और अमेरिका में लागत लगानेवाले - बैंक (Investment Banks) हैं जिनका काम पूँजी को अनेक प्रकार के प्रयोगों में विभाजित करना है। फिर, अमेरिका में मजदूर सङ्घों के अपने मजदूर बैंक (Labour Banks) भी हैं जिनमें उनके मजदूर अपनी बचत जमा करते हैं। हमारे ही देश में कुछ बड़े-बड़े कालिजों में विद्यार्थियों का द्रव्य जमा रखने के लिये विद्यार्थी बैंक (Student Banks) हैं। लन्दन के सौदागर महाजन (Merchant Bankers) और वहाँ की विलों पर स्वीकृति देनेवाली सस्थाये (Accepting Houses) एक अन्य प्रकार की ऐसी सस्थाये हैं जो एक विशेष प्रकार का काम करती हैं। आजकल व्यापार साख पर निर्भर हैं। किन्तु जब कोई व्यापारी विदेशों में उधार माल बेचाता है तब उसे इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि वह अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति पर बराबर ध्यान रखे। अतः, यह काम उपर्युक्त सौदागर महाजनों ने अपने ऊपर ले रखा है। उनका सम्बन्ध सभी देशों से रहता है। अतः, वे भिन्न-भिन्न देशों के ऊपर किये गये विनिमय विलों पर भी उनकी ओर से स्वीकृति दे सकते हैं। कभी-कभी वे इसके लिये विनिमय बैंकों की मंत्रणा भी ले लेते हैं। इनके अतिरिक्त लन्दन में कुछ डिस्काउन्टिंग सस्थाये (Discounting Houses) हैं जो सारे शहर में ऐसे विनिमय विलों के तलाश में रहती हैं जिनका उस समय का मूल्य वह दे देती हैं। उनके साधनों में उनका स्वयम् की पूँजी, जनता की उन्हीं शर्तों पर जमा की गई रकम जैसी अन्य बैंकों की होती हैं, हाँ, ऊँची दरों पर अवश्य और कभी-कभी बैंकों से सप्ताह भर के लिये अथवा रात्रि भर के लिये (Overnight) लिये दिये ऋण सम्मिलित रहते हैं। विलों का उस समय का मूल्य प्राप्त करनेवाले लोगों और व्यापारिक बैंकों के बीच में वे दलाली का भी काम करते हैं। ये सब थोड़े से उदाहरण हैं। ससार में सभी जगह भिन्न-भिन्न प्रकार की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए अगणित प्रकार की बैंकिंग सस्थाये हैं।

प्रश्न

(१) 'वैकिंग में भी विशिष्टता पाई जाती है, यद्यपि यह अभी पूरी तरह से सफलभूत नहीं हुई है।' समझाये।

(२) हमारे डेयन में प्रप्रिकाश में किन-किन तरह के वैद्व आते हैं ? उनका सन्निप्र विवरण दीजिये।

अध्याय ४

व्यापारिक वैद्वों के काम (Functions)

जैसा कि हमें ज्ञात हो चुका है व्यापारिक वैद्वों का प्रारम्भ लोगों का द्रव्य जमा करने के विचार से केवल उस समय के बाद ही हुआ था जब लन्दन में जनता ने वहाँ के सर्गीर मराजनों के पास अपनी रक्म जमा करना प्रारम्भ कर दिया था। उन्हें यह बात समझने में भी आधक देर नहीं लगी कि यदि वह जमा में पाये हुये द्रव्य वास्तव करने के पहिले प्राप्त कर सकें तो उसे उधार देकर यह व्यवसाय बहुत ही लाभदायक बनाया जा सकता है। धीरे-धीरे उन्हें यह भी मालूम हो गया कि उनके प्रतिदिन के भुगतानों के लिये उन्हें प्रतिदिन ही थोड़ा रकम प्राप्त हो जानी है, यतः, इस बात की आवश्यकता भी नहीं है कि उधार दी हुई रकम जमा की हुई रकम की वापसी के पहिले ही प्राप्त हो जाय। इसमें सन्देह नहीं कि उन्हें ऋण देने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता था और उचित जमानत लेनी पड़ती थी। कभी-कभी उनकी बहुत हानि भी हुई है। उदाहरण के लिये जेफ़री द्वितीय ने अपना लिया हुआ ऋण लौटाने से इकार कर दिया था। अतः, यह स्पष्ट है कि वैकिंग के दो मुख्य काम द्रव्य उधार लेना और देना है। उस, हम यहाँ पर इन्हीं का अध्ययन करेंगे। किन्तु आज फल के वैद्व इनके अतिरिक्त कुछ अन्य काम भी करते हैं जिससे जनता को सुविधा मिलती है।

इत तमाम कामों का हम चार शीर्षक में अध्ययन कर सकते हैं—

(१) जमा लेना।

(२) ऋण देना।

(३) आदत के काम करना ।

(४) अन्य कार्य ।

जमा लेना (Receiving Deposits)

जमा कई खातों में ली जाती है जिनमें मुख्य तो चालू खाता (Current Account) है, किन्तु अन्य भी कई खाते हैं जैसे स्थायी खाता (Fixed Deposit Account), बचत खाता (Savings Bank Account), गोलक खाता (Home Safe Account) इत्यादि । पहले-पहल जो जमा प्राप्त होती थीं वह तो स्थायी खातों ही में होती थीं । किन्तु शीघ्र ही सर्राफ़ महजनों ने यह समझ लिया है कि यदि जमा में प्राप्त होनेवाली रकम एक बहुत बड़ी मात्रा में है तो वह इस बात पर निर्भर रहकर कि उसमें से एक बहुत बड़ी रकम बहुत दिनों तक वापिस नहीं माँगी जायगी वह रकम ऋण में भी दे सकते हैं । अतः, उन्होंने माँग की वापिसी की शर्त पर भी जमा (Demand Deposits) प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया । इस तरह से चालू खातों की नींव पड़ी जिनमें से जमा करनेवाले अपनी रकम जब चाहे तब प्राप्त कर सकते हैं । इसके बाद चेकों का प्रादुर्भाव हुआ जिससे कि चालू खातों से रकम निकालने में बहुत सुविधा पड़ने लगी । फिर, जब चेकें अच्छा अधिकार देनेवाले पुर्जों (Negotiable Instruments) की तरह जन साधारण में स्वीकृत होने लगी और हाथों-हाथ चलने लगीं तब जमा प्राप्त करनेवाली बैंकिंग की प्रणाली और भी उन्नति प्राप्त करने लगी । यह अवश्य ही लन्दन से प्रकट हुई है । चालू खातों में साधारणतया व्याज नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि कभी-कभी यह शर्त भी रहती है कि जमा करनेवाले उसमें से न्यूनतम रकम कभी भी नहीं निकाल सकेंगे । लन्दन में तो इन पर व्याज न देने का एक चलन ही हो गया है । बैंक इन्हें केवल इसीलिये रखते हैं कि उन्हें एक मुक्त रकम (Free Balance) मिल जाती है । यह रकम उतनी होती है कि जितने का व्याज खाता रखने के खर्च के बराबर होता है, और यह खर्च भी लेजर के पृष्ठों के चलने और चेकों के प्रयोग की सख्या पर निर्भर रहता है । यदि यह मुक्त रकम नहीं छोड़ी जाती तो फिर बैंक ग्राहकों से एक कमीशन लेता है जैसा कि हमारे देश में चलन है । यह छमाही लिया जाता है । इसे प्रासंगिक व्यय (Incidental Charges) कहते हैं । हाँ, कुछ ऐसी भी बैंकें हैं जो व्याज देते हैं ।

मुद्रितान के अन्य प्रयोग म तो जगा है म्मा है यद लन्दन म भी है ।
भारे देश म भी एमे प्राक है ।

स्वाधीनता न ता म्मय जमा की जाती है यद प्राधि भी जाने
म पहिले नम निमाता म तम है निमहे लिये यद ता सी मरं बी । म्मी-
म्मी यद पहिले न म्मा देम भी निमाता जाती है । इन्ट्रानेरिका
मे मन्व क लि । मम जमा (Time Deposits) भी करने है । इन्ट्र
व्याज म्म मर्कमि किया जाता है लिखी दम चितना प्रविद्ध म्मय होजा
है उतनी ही अधिक होती है । लन्दन मे यद मात म्मिों की सूचना मर भी
जमा किये जाने है किन्तु मात दिना की सूचना मेन के पहिले इन्ट्र म्म ने
कम एक माद तरु अस्थाय जमा म्मना पड़ता है । इनके व्याज की दर बैंकों के
जमा की दर (Bank Deposit Rate) रही जाती है । भारतवर्ष मे
म तीन मरीना, छ मरीना ना मरीना और एक मर के लिये जमा होते है ।
इच्छ म्म एक मर मे ऊपर के लिये भी जमा (Time Deposits) प्राप्त
करते है, किन्तु ऐसा बहुत कम किया जाता है ।

कुछ समय के लिये जमा और मांग पर धारण होने वाली जमा
(Demand Deposits) होती की रकम आपस मे बदलती भी रहती
है । जब व्यापार मन्दा हो जाता है तब चालू खातों की रकम स्वाधी खातों
मे चली जाती है और जब व्यापार की तेजी होती है तब इसका उलटा हो
जाता है । अच्छी बैंकिंग के अर्थ यह है कि जमा अधिकाश मे चालू खातों
मे हो हो । निम्नात बैंकों ने स्वाधी खातों और व्याज देने होना के विरोध
मे बहुत कुछ कहा है । व्यापारिक बक तो व्यापारियों से काम करते हैं जिनके
पाग स्थायी खातों मे रखने के लिये फालतू रकम नही होती, उन्हें तो पंचल
उतनी ही पूंजी रखनी चाहिये जितनी उनके व्यापार के लिये आवश्यक है ।
अतः, इन्ट्र उन्हें चालू खातों में ही रखना चाहिये । निर्धारित समय के लिये
जमा प्राप्त करने का काम तो लागत वाले बैंकों (Investment Bank)
का है । अतः, व्यावसाय की छीना-झाड़ी नहीं होनी चाहिये । किन्तु भारतवर्ष
ऐसे देश मे जहाँ लागत के बैंक हैं ही नहीं व्यापारिक बैंकों के यह काम करने
मे कोई हानि नहीं मालूम पड़ती ।

कुछ देशों में और विशेषतः भारतवर्ष मे व्यापारिक बैंक वचत खातों
में भी जमा प्राप्त करते हैं सम्पूर्ण जमा की रकम का जो अंश वर्तमान काल
में इन खातों में है वह प्रथम युद्ध के पहिले के काल की अपेक्षा कहीं अधिक

है। इसका एक मात्र उद्देश्य था जो प्रायः चाले लोगों में भित्तव्ययता का प्रचार करना है। प्रायः में यह काम भी व्यापारिक बैंकों के लिये उत्पन्न नहीं है किन्तु वे इसे बगल करते पाते हैं और इसका मतलब भी इतना बढ़ गया है कि इसे प्रचलित नहीं तो गोंदा या प्रकृत्य उनके विषय में जायजत कर लेना चाहिये। इन गाँवों की राम एक निर्धारित सीमा के ऊपर नहीं जान दो चागी। उन्हें कोई भी प्रकृत्य अपने नाम में अथवा किसी अथवा समस्तक नगरनी के नाम में अथवा किसी ऐसे कमस्तक के नाम में लिखा कर प्रभितभारक लिखन दुग हो, गोन गता है। इसमें जमा तो जय चाहें नय को जा मन्ना है किन्तु इसमें से निकाला मन्ना में केवल एक अथवा दो बार ही जा मन्ना है। कुछ बेटे जय चैज के प्रयोग की भी सुविधा देने लगे हैं। प्रती-इहो यः सुविधा प्राप्त करने के लिये एक न्यूनतम मुक्त रकम रखना भी आवश्यक है। पाचवीं बागीच के प्रन्त के गोन म दिन भी न्यूनतम रकम होती है उनी पर पूरे एक माह का व्याज लगाया जाता है। कहीं कहीं, एक निर्धारित रकम में प्रकृत्य रकम निकालने के लिये कुछ दिनों की सूचना को भी आवश्यकता पडती है।

गोलक गाना वचत गाने की ओतर है। इसे हमारे देश के केन्दल बैंक के अधिकारियों ने चालू किया था। इसका ध्येय प्रती में भी भित्तव्ययता की प्राप्ति डालना है। जय कोई व्यक्ति यह खाता गोलता है तब उसे एक मुन्दर गोलक द दिया जाता है जिसे वह अपने घर ले जाता है और जिसमें वह समय-समय पर अपने पने डालता रहता है। एक गोलक भर जाता है तब वह उसे बैंक में वापस ले जाता है जहाँ पर उसे सोलकर उसका रुपया, उसके खाते में जमा कर लिया जाता है। गोलक के स्थान पर एक मुन्दर घड़ी भी मिलती है जिसमें प्रति दिन एक आना, छोड़ने में चाभी भरी जाती है। इस खात में वचत खाते की ही तरह व्याज लगाया जाता है।

जमा अन्य खातों में भी प्राप्ति की जाती है। निजी पच देने के लिये निरूपित (Private Accounts) गोलें जाते हैं। इसके प्रतिरिक्त अन्य विशेष कामों के लिए विशेष खाते खुलते हैं। उदाहरण के लिए प्रचा के विगड के लिये द्रव्य प्रकृत्य करने के लक्ष्य से विवाड खाता (Marriage-Account) खोला जाता है।

जमा के भैद (Nature of Deposits)

जमा कई प्रकार में प्राप्त होते हैं। ग्राहक नकद जमा कर सकते हैं अथवा

नकदी मिलने के अपने अधिभार को जमा कर सग्न है। ये चेक, विनिमय बिल और प्रण-पा, इत्यादि हो सकते हैं। बैंक इनमें भुगतान प्राप्त करके उसे खाते में जमा कर लेता है। बैंक के ऋण इन में अथवा विनिमय बिल जिन्नाउण्ट कर देने में भी उन्हें जमा प्राप्त हो जाता है। इनके सजित जमा (Created Deposits) कहते हैं। बान्धन में प्राप्त सजित जमा की रकम अन्य प्रकार में उत्पन्न दृढ़ जमा की रकम में नहीं अधिक होती है। अतः, यह मान लोचना कि बैंक के चिट्ठे (Balance Sheet) में जितना जमा (Deposits) दिखाया गया है उतना उसे नकद प्राप्त दृढ़ा है, भ्रमपूर्ण है। मॉस्लियट का कहना है कि यह रकम उस रकम की योग्य नहीं है जो बैंक को उनका व्यवसाय चलाने के लिये प्राप्त हो चुकी है। यह तो यह मतलबी है कि बैंक ने जितना व्यवसाय किया है और उसने अपने का अपना उत्तरदायित्व (Liabilities) बढ़ा कर लिया है। अतः, यह जमा की रकम जिन्हें बहुत से लेखक नकद प्राप्त दृढ़ रकम समझते हैं वे सब उन मान की योग्य हैं जो बैंक ने उस नकद, विनिमय बिल और ऋण के बदले में उत्पन्न कर ली है जो उसके चिट्ठे में सम्पत्ति और पाउने (Assets) की तर्फ दिखलाई गई है। जब किसी ग्राहक को थोड़े समय के लिये द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है तब वह बैंक में या तो ऋण (Loan) लेने अथवा अधिक द्रव्य निकालने—अविधिक (Overdraft) अथवा नकद मान प्राप्त करने (Cash Credits) अथवा बिल भुनाने (Bill Discounting) की प्रार्थना करता है। बैंक तो यह जानता है कि द्रव्य रखने के लिये नहीं बरन् भुगतान करने के लिये माँगा जा रहा है। अतः, प्रायः वह इस शर्त पर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेता है कि ग्राहक सत्र रकम नकद न लेम्ब जब कभी उसे भुगतान करना होगा तब चेक काटेगा। हम जानते हैं कि चेक काटने का यह अधिकार तो नकद जमा करने पर भी मिलता है, अतः, हम यह कह सकते हैं कि इसे चाहे ग्राहक स्वयम् प्राप्त कर ले अथवा बैंक उसे दे दे। जब ग्राहक नकदी जमा करता है तब वह इसे स्वयम् प्राप्त करता है और जब बैंक उसे किसी भी रूप में ऋण देता है तो बैंक उसे इसे देता है। किन्तु बैंक की यह अधिकार देने की शक्ति उसके पास जितनी नकदी होती है उसी के अनुसार सीमित रहती है। अतः, जैसा कीन्स ने कहा है हम भी कह सकते हैं कि ऋण जमा के बच्चे हैं और जमा ऋण के बच्चे हैं^१।

^१ Loans are the children of deposits and deposits are the children of loans

किन्तु बहुत से लोग उपर्युक्त बात नहीं समझ पाते हैं और कहते हैं कि बैंक के लेखक (Clerks) जितनी चाहे उतनी साख उत्पन्न कर सकते हैं^२। यदि उनमें दुर्भाव न हो तो इतनी अधिक साख उत्पन्न हो जाय कि ससार से से दरिद्रता और पसीना बहानेवाली सख्त मेहनत सदा के लिये नष्ट हो जाय। वे यह बात नहीं सोचते कि^३ यदि बैंकर के पास इतनी शक्ति है तो वह चीज क्यों कम करता है जिससे वह व्यापार करता है और अपनी रोटी कमाता है।

ऋण देना (Granting Loans)

यह तो बतलाया ही जा चुका है कि बैंकर प्रायः नकद ऋण नहीं देते। अधिकांश में उनके ग्राहकों के ऋण चेक काटने के अधिकार के रूप में ही होते हैं। इनके कई रूपा हैं, जैसे साधारण ऋण (Loans and Advances), जमा की गई रकम से अधिक रकम निकालने देना—अधिविकर्ष (Overdrafts), नकद साख (Cash Credits) अथवा विनिमय बिल भुनाना (Bill Discounting) इत्यादि, इत्यादि। बैंकर अपनी पेंजी नहीं देते। इसके विषय में लार्ड ओवरस्टन नाम के एक प्रसिद्ध बैंकर ने कहा है “यह मेरी स्वयम् की बुद्धि है और दूसरे का द्रव्य है।” रेकाडों ने भी इसी अशय की बात कही थी। उसका कहना था “कोई व्यक्ति तभी बैंकर कहला सकता है जब वह दूसरों का द्रव्य उधार देता है।” वास्तव में बैंकों के पास अपना नकद कोष रखने और मृत स्टॉक (Dead Stock) खरीदने के बाद अपनी स्वयम् की, पेंजी ऋण के रूप में देने के लिये नहीं बचती। अतः, वह इस काम के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कर सकते कि दूसरे द्वारा जमा किया हुआ द्रव्य इस काम में लगावे। किन्तु इन्हे उन्हें मॉग पर वापिस करना पड़ता

2 Credit is the mere creation of the bank clerk's pen and that but for the malevolence of the wicked banker enough of it could be created to remove poverty and banish toil from the world

3 Why the banker should be so concerned to reduce the volume of the material in which he trades and from which he earns his living it he has the power they think he has ?

८। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वित्तियोगी घोषित कर भिये जाते हैं जिससे उनका काम ही प्रन्द हो जाता है। यह सब भी जान है कि वह केवल उम्मीदों से काम चलाते हैं। यह सब प्रमाण देने हैं। उस समय में प्रत्यक्ष ही उक्ति का आवश्यकता पड़ती है। यह व्यवस्थाओं की स्थिति वास्तव में बदली टानीय है। एक तरह से शिन्नेयर उनसे अधिनाधिम लाभ प्रदान का प्राप्ति करते हैं जो जोषिम उठाये प्रिया हो ही नहीं सकता। यह दूसरी तरफ उनके व्यवसाय के एक होने के कारण कि जिससे उन्हें रक्षा का सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है वह अधिनाधिम लाभ भी नहीं उठा सकता। किन्तु यह काम बहुत स्थिति नहीं है। प्राचार्य टाजिग (Taussig) कहते हैं "मगर बातें ये हैं जिनसे व्यापारिकों को लाभ बहुत स्थिति नहीं है। उनके लिये पूर्व विचार, साधुता नियमपालन तथा व्यवसायियों के अच्छे ज्ञान की आवश्यकता है।"

जहाँ तक ऋण के रूपों का प्रश्न है, साधारण ऋण (Loans and Advances) तो एक तरह का ऋण के नाम छोड़कर (उनके एकाउन्टों को डेबिट करके) और दूसरी ओर उनसे चालू खाता में जमा करके (उनके क्रेडिट एकाउन्ट को क्रेडिट करके) दे दिया जाता है। यह व्यवसाय बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि इसमें तो बैंक केवल अपनी ताकत ही जिनसे जनता केवल इसलिये मानती है कि उसका नाम बहुत प्रसिद्ध होता है ऋण के रूप में देता है। यदि वह तनिक भी ध्यान रखता है तो इसमें उसे लोस मान भी जोषिम नहीं उठानी पड़ती। एक हर प्रकार की जमानत पर ऋण नहीं देते। वे केवल वही जमानत स्वीकार करते हैं जो आसानी से भिन्न सकती हैं। उनका मूल्य हान भी नहीं होना चाहिये। जार्ज ने ने कहा है कि बैंक के लिये दोषरहित जमानतें वही हैं जो अन्त में भी सुरक्षित हैं, जिनका भुगतान थोड़ी अवधि के बाद ही एक निश्चित तिथि पर होने को है, जिनमें आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ही भिन्न जाने की योग्यता है और जो हास की जोषिम से मुक्त है। कभी-कभी ऋण लेनेवालों की वैयक्तिक जमानत ही ले ली जाती है, अथवा एक संयुक्त प्रणपत्र अथवा दो नामवाला साख पत्र ही ले लिया जाता है। इस ऋण में पूरी रकम पर व्याज लगाया जाता है।

जमा की हुई रकम से अधिक निकालने—अधिविक्रय (Overdraft) का अधिकार भी केवल एक व्यवस्थापक के पहिले ही तय कर लेने पर प्राप्त हो सकता है। इसे प्राप्त करने से लिये प्राहका को उसके पास जाना पड़ता

है अथवा उससे लिखा-पढी करनी पड़ती है। इसमें यह भी तय हो जाता है कि इस तरह से अधिक से अधिक कितनी रकम निकाली जा सकती है। फिर, जितने दिनों के लिये यह सुविधा दी जाती है वह भी पहिले से ही निश्चित हो जाती है। इतना हो जाने पर बैंकर उस निश्चित रकम तक चेक सरकाता जाता है। साधारण ऋण (Loan) और जमा की हुई रकम से अधिक प्राप्त करने—अधिविकर्ष (Overdraft) में एक यह भी अन्तर है कि जब कि साधारण ऋण (Loan) में ग्राहक ऋण की पूरी रकम पर व्याज देता है जमा की हुई रकम से अधिक प्राप्त करने—अधिविकर्ष (Overdraft) में वह उतनी ही रकम पर व्याज देता है जितनी दिन प्रति दिन उसके नाम पड़ी रहती है। इसके यह अर्थ है कि जमा की हुई रकम से अधिक प्राप्त करने—अधिविकर्ष (Overdraft) में ग्राहको को साधारण ऋण (Loans) की अपेक्षा कहीं अधिक लाभ होता है। किन्तु बैंक इन पर ऊँचे दर से व्याज लगाकर ऐसा नहीं होने देते। ऋण की तरह यह भी जमानत पर अथवा जमानत के बिना ही प्राप्त हो सकते हैं।

नकद साख (Cash Credit) देने की प्रणाली स्काटलैण्ड में जहाँ यह पहिले-पहिल चालू हुई थी, बहुत ही प्रिय है। मैकिलयड का कहना है कि वहाँ की उन्नति केवल इसी प्रणाली के कारण हुई है। उसका कथन है कि नाइल नदी ने जो कुछ मिश्र के लिये किया है वही नकद साख (Cash Credit) प्रणाली ने स्काटलैण्ड के लिए किया है, अर्थात् वह उत्पादन बढ़ानेवाली सिद्ध हुई है। लेवी कहता है 'स्काच बैंको ने बहुत से दरिद्र स्काचो को केवल दो घण्टे व्यक्ति द्वारा लिखे हुए साख पत्रों पर ही नकद साख देकर योग्यता की स्थिति में ही नहीं वरन् बहुत ही महत्वपूर्ण स्थितियों में पहुँचा दिया है।' हमारे देश में भी यह प्रणाली व्यापारिक बैंको को बहुत ही प्रिय है। किन्तु वे इसे केवल वैयक्तिक जमानतों पर ही न देकर ऐसे प्रणपत्रों की जमानत पर देते हैं जिनके पृष्ठ पर हिस्से अथवा अन्य साखपत्र रहते हैं अथवा रुई, पाट और चावल जैसी वस्तुये होती हैं। यदि माल बैंको के गोदामों में रख दिया जाता है तो उनके वहाँ पहुँचने पर ऋण दे दिया जाता है और उसकी जैसे-जैसे वापसी होती जाती है वह छुटता जाता है। ऋण देते समय उचित छूट (Margin) रख ली जाती है। इसमें भी जमा की हुई रकम से अधिक निकालने अधिविकर्ष (Overdrafts) की तरह ही जो रकम मृगी लिये रहता है उसी पर व्याज

लगता है। हो, दोनों में एक अन्तर यह है कि जब इसमें ऋणी के नाम का एक नया खाता गिने उल्टा चालू खाता (Inverse Current Account) रखा जा सकता है, खोना जाता है उसमें वही पुनः चालू खाता चलता रहता है।

मिल भुना करने भी ऋण प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक व्यापार खाते पर भी निर्भर है। नकद सौदे का केवल सुदृढ़ व्यापार में ही होते हैं। उद्योग धन्य के सम्बन्ध के बहुत से सौदे तो खाते पर होते हैं। फच्चे माल के उत्पादक उन्हें माल बनाने आलो के दाये नाम पर ही बेचते हैं। ऐसे ही माल बनाने वाले योग्य व्यापारियों के दाय, योक्त व्यापारी सुदृढ़ व्यापारियों को खाते पर ही माल बेचते हैं अतः यह आदि ने अन्त तक फैला हुआ है और हम यह बात जान किसी विरोध के बिना कह सकते हैं कि ग्राहक का सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पाद माध्यम से बज्जोर में चला जाता है। यदि यह अपने इस विन्मोह रूप में न फैला होता तो उन्नति का ग्राहक कल का इतना बड़ा रूप सम्भव ही न होता। खाते ने व्यापार की मशीन की चाल बढ़ा दी है। जब कोई साख या मादा होता है तो विन्मोह एक विनिमय मिल तयार करता है जिसमें वह विन्मोह ने एक निश्चित अवधि जीत जाने पर उसमें दी रकम देने की मांग करता है। भुगतान का यह तरीका बहुत ही सुविधाजनक है। प्रथम तो इसका भुगतान बन्ने द्वारा होने के कारण मुद्राओं और नोटों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरे विनिमय मिलों से भुगतान की तारीख भी निश्चित हो जाती है और यह एक प्रकार के साक्षी का भी काम देते हैं। भुगतान के दिन यदि उसका ऊपरवाला धनी (Drawer) भुगतान नहीं करता तो वह अदालत में यह नहीं कह सकता कि उसके ऊपर ऋण नहीं चाहिये। जिस सौदे के सम्बन्ध में कोई मिल किया जाता है, उस सौदे के विषय में कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। मिल स्वयं ही ऋण का द्योतक माना जाता है। तीसरे, इसका अधिकारी (Holder) इसे अपने ऋण के भुगतान में इस्तान्तरित (Transfer) कर सकता है। अन्तिम बात यह है कि आवश्यकता पड़ने पर इसके अधिकारी को इसे भुनाने से इसके भुगतान की तारीख के पहिले ही इसकी रकम मिल जाती है। वास्तव में जिन व्यापारियों के पास पेजी तो कम है किन्तु साख पर काम करना है उनके लिए रकम पाने का यह अच्छा साधन है।

बिल भुगाने का तरीका एक ऐसा तरीका है जिसमें बैंकर कोई अन्य जमानत लिए बिना ही श्रृण दे देता है। इस स्थिति में उसके लिये केवल लिखने वाले धनी (Drawer) और ऊपरवाले धनी (Drawee) दोनों की वैयक्तिक जमानत ही रहती है। कभी-कभी यह बिल पहिले तो भुनाने का काम करने वाली सस्थाओं (Discounting Houses) अथवा बिलों के दलालों (Bill Brokers) से भुना लिया जाता है और फिर वे इसे किसी बैंक से भुनाते हैं। ऐसी अवस्था में इन मध्यस्थों की एक और जमानत हो जाती है। भारतवर्ष में सर्राफ अथवा देशी महाजन (Indigenous Bankers) यह मध्यस्थ का काम करते हैं। बिल पर रकम देनेवाला महाजन (Banker) शेष अवधि का व्याज काटकर बिल की रकम उसके अधिकारी के खाते में जमा कर देता है और वह उसमें से बैंक द्वारा धीरे-धीरे निकालता रहता है। बैंक इसे भुगतान की तारीख तक अपने पास रखते हैं और अन्त में ऊपर वाले धनी से उनकी रकम प्राप्त कर लेते हैं। ऊपर वाला धनी किसी बिल पर अपनी स्वीकृति देने के समय अपने बैंक को जिसका नाम वह स्वीकृति के साथ-साथ भुगतान देने के स्थान की जगह पर लिख देता है उसका भुगतान करने के लिए सूचित कर देता है।

बिला पर श्रृण देना बैंकों के लिये बहुत ही लाभप्रद है—

(१) बिल पर मिलने वाली रकम निश्चित रहती है। वह कभी भी नहीं बदल सकती। इसके विपरीत ग्रन्थ जमानती रकम बदलती रहती हैं। उनके गिर जाने से हानि भी हो सकती है।

(२) बिल की अवधि बीत जाने पर उसका भुगतान मिल जाना पूर्णतया निश्चित हो रहता है। बात यह है कि किसी बिल के खड़े रह जाने पर (Dishonour) उसके ऊपरवाले धनी की बड़ी बदनामी होती है जिसे कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। फिर, यदि वह उसका भुगतान नहीं करता तो उस पर और जो धनी उत्तरदायी होते हैं वह उसका भुगतान कर देते हैं।

(३) किसी भी बैंक का व्यवस्थापक बिलों पर श्रृण देते समय इस बात का ध्यान रख सकता है कि उनमें से कुछ बराबर भुगतान के लिये पकते रहें। इससे उसे बराबर रकम मिलती रहती है।

(४) केन्द्रीय बैंक अन्तर्गत बिलों पर फिर से ऋण देने (Rediscounting) के लिये तैयार करते हैं। इन पर यह अपनी बैंक दर (Bank-rate) से व्याज लेते हैं।

(५) यदि इन्हें गुमान की दर और व्याज की दर एक ही होती है तो भी इनके ऊपरी-मूल्य (Face-value) पर न कि जितना ऋण दिया गया है उस पर डिस्कोन्ट (Discount) मिलने के कारण धनी का लाभ ही होता है। इससे प्रतिदिन इनका यह लाभ ऋण देने के समय ही मिल जाता है और अन्य ऋणों का न्याज कुछ समय बीतने पर मिलता है। अतः, बैंक इस रकम से भी लाभ उठा सकते हैं।

किन्तु इस व्यवसाय में भी इनके बेरगवाणी में करने पर खड़ी तोषिम है। यह बात विशेषतः इसलिये है कि विनिमय बिल एक प्रकार के होते हैं—वास्तविक (Genuine), अनामदी (Non-genuine)। इन दोनों में विभेद करना भी असम्भव सा है। वास्तविक बिल व्यापारिक सौदों के सम्बन्ध में किये जाते हैं। अतः, उनके भुगतान की तारीख तब माल बिक जाने की सम्भावना होने से उनका भुगतान तो एक प्रकार से निश्चित मा ही रहता है। किन्तु अनामदी बिल तो केवल उनके धनियों की साख पर ही निर्भर रहते हैं। अतः, उनके भुगतान में सन्देह हो सकता है। कभी-कभी ये बिल केवल अपने व्यापारी मित्रों की आर्थिक सहायता करने के विचार में ही स्वीकृत कर लिये जाते हैं, और उनके भुन जाने में लिखनेवाले धनी को द्रव्य तो मिल ही जाता है। लिखनेवाला धनी इसके भुगतान की तारीख के पहिले ऊपरवाले धनी के पास इसकी रकम पहुँचा देने का वायदा कर लेता है। अतः, यदि वह ऐसा नहीं करता तो सम्भव है कि ऊपरवाला धनी उसका भुगतान न कर सके। राऊ कहता है कि यदि सहायता के सम्बन्ध के बहुत से बिल हो जायें और लिखनेवाले तथा ऊपरवाले धनियों की आशाएँ सफलीभूत न हों तो यह सम्भव है कि ऐसे बिलों का भुगतान न होने के कारण बैंक की हानि हो जाय। ये बिल साख पर तो निर्भर होते ही हैं और साख का अनुचित प्रयोग कभी भी किया जा सकता है। सहायता के बिल (Accommodation Bills) पक्की बिल (Kite Bills) भी कहे जाते हैं। आशा पर किये गये बिल (Anticipatory Bills) अर्थ बिल (Financial Bills) भी कहलाते हैं। ये वर्तमान सम्पत्ति के ऊपर नहीं बरन् भविष्य में उत्पन्न होने वाली सम्पत्ति पर किये जाते हैं। ये अमेरिका में बहुत प्रचलित हैं और कृषकों

को उनके दैनिक व्यय देने के लिये किये जाते हैं। ये भी बैंकरो के लिये उद्युक्त नहीं है क्योंकि खड़ी खेती के मूल्य पर निर्भर रहना जोखिम से खाली नहीं है।

आदत के काम (Agency Services)

बैंकर अपने ग्राहकों के लिये अनेक प्रकार के आदत के काम भी किया करते हैं। वे उनके चेकों, बिलो, प्रणपत्रों, व्याजपत्रों, (Coupons), लाभ को बंटनी के पत्रों (Dividend-warrants), चन्दे (Subscriptions), किराये, आय कर, बीमे के प्रीमियम, इत्यादि की वसूली भुगतान और जमा करते हैं। वे उनकी तरफ से हिस्से-पत्रों, स्टॉको, ऋणपत्रों, इत्यादि की स्टॉक एक्सचेंज में और अन्य वस्तुओं की अन्य बाजारों में लेवा-बेची करते हैं। वास्तव में वे आदत पाने पर उनके लिये कोई भी काम कर सकते हैं। कभी-कभी तो वे इन्हें आदत लिए बिना ही केवल जमा प्राप्ति की लालच में ही किया करते हैं। किन्तु वे जब आदत का काम करते हैं तब उनके ऊपर बहुत से महत्वपूर्ण दायित्व आ पड़ते हैं।

अन्य काम (Miscellaneous Services)

अन्य कामों में बैंकरो द्वारा किये जानेवाले अनेक काम सम्मिलित हैं। वे अपने ग्राहकों की मूल्यवान सम्पत्ति, गहने और जवाहिरात तथा मूल्यवान कागज सुरक्षित रखने (Safe custody) के लिये भी लेते हैं। वे सम्पत्ति देने (Referee) का भी काम करते हैं। जब कोई व्यवसायी किसी अन्य व्यवसायी की आर्थिक स्थिति का पता लगाना चाहता है तब उसे उसके बैंकर का हवाला (Reference) दे दिया जाता है जो उसे उसके विषय में सारी सूचनाएँ दे देता है। वे अपने ग्राहकों के सम्भावित ग्राहकों की स्थिति का पता भी लगा देते हैं जिससे वे उनकी साख पर काम करने अथवा न करने का निश्चय करते हैं। वे साख-पत्र (Letters of credit) और बैंक ड्राफ्ट भी निकालते हैं। इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थानों को भेजी जाती हैं। किन्तु किसी बैंकर का सबसे महत्वपूर्ण काम तो यह है कि वह अपने ग्राहकों को सच्ची मित्रता और सहनशीलता सिखाता है। बैंकिंग की कार्य-कुशल प्रणाली साख के दर्जे की और समाज की व्यवसायिक सचरित्रता की इतनी उन्नति

तरती है कि वह माधुगानता, प्रियतामयता, ईमानदारी, सत्यता और योग्यता के निर्माता कह जाय है। किन्तु राष्ट्र के यहाँ जहाँ भी गो-मायी प्रत्येक प्रणाली के स्थान पर पेशवा साध-प्रणाली चालू हो जाती है नही हमें इस बात का पता चलता है कि उद्युक्त गुणों के उनके जनना कारण में हट-हट कर भर जाने में क्या लाभ होता है।

प्रश्न

(१) व्यापारिक बैंकों के कामों का सक्षम वर्णन कीजिये।

(२) बैंक किन किन विभिन्न ग्याता में जमा प्राप्त करने ? उनमें से प्रत्येक के महत्वपूर्ण लक्षण बताइये।

(३) बैंकों को जमा किन-किन तरीकों से बनती है? साथ ही यह भी बतनाइये कि वह उन्हें कहाँ तक शक्ति प्रदान करती है?

(४) 'माग की उत्पत्ति बैंक के लेखक को लेखनी पर ही निर्भर है।' उक्त की आलोचना कीजिये।

(५) कॉन्स का कथन है "ऋण जमा के बच्चे हैं और जमा ऋण के बच्चे हैं।" इससे आप कहाँ तक सहमत हैं?"

(६) बैंकों के ऋण देने के सम्बन्ध में लार्ड थोमसटन का जो यह कथन है कि यह मेरी बुद्धि है और दूसरों का द्रव्य है, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं?

(७) बैंकों के ऋण के जितने रूप हो सकते हैं उनका एक सक्षम विवरण दीजिये। डिस्काउन्ट का व्यवसाय बैंकों को क्यों अधिक प्रिय है?

अध्याय ५

व्यापारिक बैंकों के काम करने की प्रणाली

(Banking Operations)

व्यापारिक बैंकों के काम करने की प्रणाली में निम्न चार बातों का अध्ययन करना पड़ता है —

(१) बैंकों को उनकी कार्यशील पूँजी (Working Capital) कैसे प्राप्त होती है ?

(२) बैंक अपनी कार्य-शील पूँजी का कैसे उपयोग करते हैं ?

(३) बैंक कैसे लाभ कमाते हैं ?

(४) बैंक अपने लाभ का किस प्रकार उपयोग करते हैं ?

बैंकों को उसकी कार्यशील पूँजी कैसे प्राप्त होती है

बैंकों की उनकी कार्यशील पूँजी अनेक ढङ्ग से प्राप्त होती है। प्रथम तो अन्य व्यापारिक सस्थाओं की तरह वह भी अपने हिस्से (Shares) निकालते हैं। किसी बैंक के सत्यापक यह निश्चय करते हैं कि उनके बैंक की रजिस्ट्री कितनी पूँजी से होनी चाहिये। सारी पूँजी बराबर-बराबर रकम के कुछ भागों में विभक्त कर दी जाती है, और प्रत्येक भाग एक हिस्सा (Share) कहलाता है। ये हिस्से जनता को क्रय करने के लिये दिये जाते हैं। कभी-कभी सब हिस्से प्रारम्भ ही में जनता के क्रय के लिये नहीं निकाले जाते, बल्कि उनमें से कुछ भविष्य में निकालने के लिये रोक लिये जाते हैं। फिर, जितने हिस्से निकाले जाते हैं उन सब को जनता हमेशा ले भी नहीं लेती है। अब यदि विवरण पत्रिका (Prospectus) में दी हुई न्यूनतम पूँजी (Minimum-subscription) के हिस्सों के लिये उचित समय के अन्दर जनता के प्रार्थना-पत्र नहीं आ जाते हैं तो उनकी बँटनी (Allotment) नहीं होती और बैंक भुङ्ग कर दिया जाता है। फिर, हिस्सों की पूरी रकम भी न मँगाई जाकर केवल कुछ अंशों में ही मँगाई जा सकती है। शेष रकम आवश्यकता पडने पर भविष्य में मँगाने के लिये छोड़ी जा सकती है। अन्तिम, यह भी सम्भव है कि सब हिस्सेदार कुछ माँगी हुई रकम न दे पावें। अब, पूँजी के भिन्न-भिन्न रूप हैं और उनके भिन्न-भिन्न नाम भी हैं। जिस पूँजी में बैंक की रजिस्ट्री होती है उसे अधिकृत अथवा रजिस्टर्ड अथवा नामपत्र की पूँजी (Authorised, Registered or Nominal Capital) कहते हैं, निकाली हुई पूँजी प्रसारित पूँजी (Issued Capital), खरीदी हुई पूँजी कौत पूँजी (Subscribed-Capital), माँगी हुई पूँजी (Called up Capital) और प्राप्त पूँजी प्रदत्त पूँजी (Paid up Capital) कही जाती हैं। प्राप्त पूँजी और माँगी हुई पूँजी के अन्तर की रकम बाकी

पूँजी (Calls in a/c) वागताती है। यह अन्तर आचार दिनों तक नष्ट चलता। उचित समय आती हो जाने पर उन व्यक्तियों के हिस्से जफ्त (Forfeit) कर लिये जाते हैं जो उन पर की गई मांग नहीं पाते हैं और उन्हें दूसरी के नाम बेच दिया जाता है। दायित्व (Reserved Liability of the Shareholders) कहा जाता है। वैयक्तिक बैंकों (Individual Bankers) और नाभके के अंगों का दायित्व तो असीमित रहता है अर्थात् यदि उनके व्यवसाय का अणु उनके व्यवसाय में पूँजी के नहीं पूरा हो पाता तो उसे उन्हें अपनी निजी पूँजी से पूरा करना पड़ता है। किन्तु सम्मिलित पूँजी के बैंकों के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। उनका हिस्सेदार तो केवल उनमें पूँजी की रकम ही देनी पड़ती है। यदि ध्यान में देखा जाय तो यह ठीक ही है। वैयक्तिक बैंक और नाभके बैंक अपना व्यवसाय स्वयं चलाने हैं और उसकी नीति निर्धारित करने हैं। अतः, उनका उत्तरदायित्व भी प्रसीमित रह सकता है। किन्तु मत्र हिस्सेदार तो व्यवसाय देगने नहीं अतः, उनका उत्तरदायित्व सीमित ही रहना चाहिये। सीमित दायित्व का सबसे पहिला विधान सन् १८५५ में इंगलिस्तान में पार किया गया था किन्तु उस समय यहकेवल अन्य व्यापारों के लिए था, बैंकिंग के लिये नहीं। अधिकांश लोगों का यह विचार था कि बैंकों की स्थिति ऐसी दायित्वपूर्ण है और उनके पास लोगों की इतनी अधिक जमा रहती है कि उनका दायित्व सीमित नहीं किया जा सकता। सन् १८५७ में बड़े संकट का समय आ गया और उसमें बहुत से बैंक विशेषतः स्कॉटलैण्ड का पश्चिमी बैंक (Western Bank of Scotland) भी फल हो गया। अतः यह देखा गया कि धनी लोग बैंकों के हिस्से नहीं खरीदते। उनके अधिकतर हिस्से गरीबों के पास ही रहते हैं। इसलिये धनी लोगों को बैंकों के हिस्से लेने को प्रोत्साहित करने के लिये सन् १८५८ में बैंकों के हिस्सेदारों का दायित्व भी सीमित कर दिया गया। किन्तु बहुत से बैंकों ने यह मोचकर कि कहीं ऐसा करने से उनके ग्राहकों का उनके ऊपर से विश्वास न उठ जाय, ऐसा नहीं किया। लेकिन सन् १८७८ में ग्लासगो शहर के बैंक (City of Glasgow Bank) के फल हो जाने पर उसके हिस्सेदारों की बहुत क्षति हो जाने के कारण बैंकों के हिस्सेदारों में इतना डर समा गया कि उन्हें दायित्व सीमित करना ही पड़ा। सन् १८७६ में सुरक्षित दायित्व का एक विधान पास किया गया जिसके अनुसार बैंक अपने हिस्सों का पूर्ण मूल (Nominal value) इस शर्त पर प्रदाय सकते थे

कि वह बड़ा हुआ मूल्य केवल उनके दिवालिया होने पर ही आवश्यकता पड़ने पर लिया जा सकेगा। वस, यह उनका सुरक्षित दायित्व कहलाया। इसका फल यह हुआ कि जब एक ओर तो हिस्सेदारों का दायित्व सीमित हो गया दूसरी ओर बैंकों में जमा करनेवालों को यह विश्वास हो गया कि यदि वह फल भी हो जायेंगे तो उनकी रकम के भुगतान के लिये कुछ-रकम तो सुरक्षित दायित्व से मिल ही जायगी। तब से यह प्रथा प्रचलित है और बैंक अपने हिस्सेदारों से उनके खरीदे हुये हिस्सों की पूरी रकम नहीं माँगते। हमारे देश में सीमित दायित्व का सिद्धान्त सन् १८६० में माना गया था। अतः, उसके बाद ही यहाँ पर बहुत से बैंक स्थापित हुये। ऊँचे दर्जे के बैंकों की प्रसारित पूँजी और क्रीत पूँजी में कोई अन्तर नहीं होता। बात यह है कि उनके निकाले हुये सभी हिस्सों के खरीदार मिल जाते हैं। अधिकृत पूँजी और निकाली हुई पूँजी का अन्तर इस बात का द्योतक है कि व्यवसाय बढ़ने पर बैंक की पूँजी भी बढ़ जायगी। किन्तु इन सब में सबसे महत्वपूर्ण तो प्राप्त पूँजी ही है। वही तो बैंक की कार्यशील पूँजी का एक विशेष अंग है। किन्तु यह अंग अन्य अंगों की अपेक्षाकृत बहुत ही कम होता है। एक बात और ध्यान देने की है और वह यह है कि हिस्सेदार अपनी पूँजी पर कुछ आय भी चाहते हैं। बैंकों को लाभ तो मिलता ही है, किन्तु उसमें से कुछ तो वे सुरक्षित कोष (Reserve fund) के लिये बचा लेते हैं। हाँ, शेष हिस्सेदारों में लाभ के रूप में (Dividend) बाँट दिया जाता है। सुरक्षित-कोष अन्त में हिस्सेदारों का ही होता है। अतः, वह भी पूँजी का ही एक अङ्ग माना जाता है। किसी बैंक के सब हिस्से बिक जाने और उनकी पूरी रकम मँगा लेने के कारण जब व्यवसाय बढ़ने पर उस बैंक की पूँजी बढ़ने का कोई तरीका नहीं रह जाता तब इसी तरीके से बराबर उसकी पूँजी बढ़ती रहती है।

कार्यशील पूँजी प्राप्त करने का एक दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण साधन जमा प्राप्त करने का है। जैसा कि हम पहिले ही देख चुके हैं यह जमा भिन्न-भिन्न रूपों में और भिन्न-भिन्न खातों में प्राप्त की जाती है। अतः, केवल वही जमा कार्यशील पूँजी बढ़ाती है जो नकदी के रूप में अथवा ऐसे अविकारों के रूप में होती है, जिससे नकदी प्राप्त हो सकती है। विनिमय बिलों पर अथवा अन्य तरह से ऋण देकर जो जमा प्राप्त की जाती है वह कार्यशील पूँजी नहीं बढ़ाती। पहिले प्रकार की जमा प्रत्यक्ष जमा (Direct depo-

1115) और दूसरे प्रकार की जमा अथवा जमा (Indirect deposits), करता है। अगर अपने दायरे की वह रकम भी जो उनके पास खाते के काम के सम्बन्ध में आती है, उस समय तक प्रयोग में ला सकते हैं, जिस समय तक वह खाते के काम में नहीं आती। उदाहरण के लिये जब एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए द्रव्य दिया जाता है तो जब तक वह पानेवाले को नहीं दे दिया जाता तब तक वह उसे प्रयोग में ला सकता है, इत्यादि।

जिन्नु एक जमा का व्यवहार या तो अधिकार का वास्तविक विनिमय है या द्रव्य और अधिकार का विनिमय है। सोचें कि जब द्रव्य पाता है तब वह जमा करनेवाले को अपनी इच्छा पर उसे निभालने का अधिकार देता है। जब उसे विनिमय मिल, चेक, प्रत्यक्ष लानपत्र, व्याजपत्र इत्यादि उनकी रकम व्यर्थ करने के लिये मिलती है तब उसे द्रव्य जमा करने का अधिकार मिलता है और वह उसके स्थान पर उसे निभालने का अधिकार देता है। जब उसे चन्दा, किराया, आयकर, बीमा का प्रीमियम और दूसरे सामयिक भुगतान मिलते हैं तब वह द्रव्य पाता है और जिनके लिये वह ऐसा करता है उनको इन्हें निकालने का अधिकार देता है। अगर वे उधर द्रव्य में नंगे में भी वह द्रव्य पाता है और निभालने का अधिकार देता है। जहाँ तक अप्रत्यक्ष जमा का प्रश्न है उसमें वा केवल अधिकारों का ही विनिमय होता है। दूसरे जगहों में यह सात का व्यवसाय है क्योंकि आदमी आरबकों के बीच में जितने लेन-देन होते हैं उनमें सब में विश्वास की मात्रा प्रधान होता है। इसके बिना कोई किसी को द्रव्य प्रयत्न उसे पाने का अधिकार सौंप ही नहीं सकता है।

राज के कथन के अनुसार बैंकों का जमा का व्यवसाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वह इधर-उधर पड़ी हुई दस, बीस, पचास और सौ-सी की छोटी छोटी रकम एकत्रित करता है। अगले इनमें कोई आर्थिक कुशलता नहीं है, किन्तु जब बैंक इन्हें प्रयोग में लाते हैं तब यह बड़े से बड़े काम कर डालते हैं। चेनहौट के कथन के अनुसार इंगलिस्तान के द्रव्य बाजार के इतना घनी और महत्वशाली होने का यदि एक मात्र नहीं तो मुख्य कारण यही है कि वहाँ पर द्रव्य की एकाग्रता पाई जाती है। लोगों की रकम जमा करना और

1 "The whole deposit business of a Bank consists in the exchange of rights against rights or rights against money"

उन्हें व्यापारियों और उद्योगपतियों को देना यह बैंकों की समाज के प्रति पहिली सेवा है और इसकी कुशलता इस बात पर निर्भर है कि उन्होंने कितना रकम जमा कर ली है और व्यापार और उद्योग-बन्धों की कितनी माँग पूरी की है। भारतीय बैंक बहुत कुशल नहीं कहे जा सकते क्योंकि न तो उन्होंने यहाँ के सर्वधारण की वचत ही प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और न वे व्यापार और उद्योग-बन्धों की माँग ही पूरी कर पाते हैं।

बैंक अपने ग्राहकों को उनके जमा के सम्बन्ध में चेक काटने के अधिकार देकर अविनाशिक क्रय-शक्ति उत्पन्न करते हैं। यह उनकी दूसरी समाज सेवा है। राज के कयन के अनुसार जमा से उत्पन्न होने वाली कर्न्सी (Deposit currency) अथवा चेक कर्न्सी अथवा बैंकों का यह द्रव्य चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, बहुत ही लोचप्रद (Elastic) है। वास्तव में चेक सम्बन्धी कोई वैधानिक ग्रहचन न होने से वे सुरक्षा और समाज हित का ध्यान रखते हुये किसी भी रकम तक निकाले जा सकते हैं। अब, यह सुरक्षा और समाज हित क्या है यह तो पहिले ही बताया जा चुका है। इनका उलथन इन सेवा कार्य को अहित में परिणत कर देता है। रक्षा की नीमा पार करने से बैंक फेल हो सकते हैं और समाज हित त्याग देने में इतनी क्रय-शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि उसमें वस्तुओं का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाने से समाज का अहित होना है। साथ उत्पन्न करना हो तो आसान किन्तु उसी के अनुपात में उत्पत्ति बढ़ाना कठिन है।

पूँजी प्राप्त करने का तीसरा साधन नोट चलाना है। किन्तु यह साधन अब अधिकांश बैंकों के लिये उपलब्ध नहीं है। धात्विक-द्रव्य की तरह नोट चलाने का अधिकार सदा से ही राज्याधिकार माना गया है। किन्तु जब धात्विक-द्रव्य निकालने का अधिकार राज्य ने बराबर उपयोग किया है, तब कुछ विशेष हालत छोड़कर नोट चलाने का अधिकार उसने बैंकों ही को सौंप दिया है। यदि कहीं बैंक स्वयं ही अपने नोट चलाते आ रहे थे तो वहाँ राज्य ने पहिले तो उनकी सुरक्षा के लिये कुछ वैधानिक नियम बनाकर उन्हें ऐसा करते रहने की विधानत आज्ञा दे दी, किन्तु शीघ्र ही उसने यह बात अनुभव की कि इसमें समानता लाने के लिये, अच्छे निरीक्षण के लिये और इससे उत्पन्न हुए लाभ में राज्य का हिस्सा बढ़ाने के लिए इसका या तो किसी एक बैंक को एकाधिकार अथवा शेषाधिकार (Residuary power) देना पड़ेगा। बेरस्मिथ के अनुसार शेषाधिकार वह है जब कई बैंक नोट

चाने हैं किन्तु उनमें से एक को छोड़कर सब में वह अधिकार सीमित रहता है। वास्तव में एक मुख्य बात के ही नोट विमोक्त, चालू रहते हैं और उनी पर प्रधिकारण प्रणाली का कार्य चलता है। हम जानते हैं कि यह सन् १८४४ में अंग्लैण्ड में हुआ। हालाँकि में यह सन् १८१४ ही में हो चुका था। फ्रांस में यह सन् १८४८ में, जर्मनी में सन् १८७५ में स्वीडेन में सन् १८६७ में गुरुक्त राष्ट्र में सन् १८१४ में, दक्षिणी अफ्रीका के यूनियन में सन् १८२४ में, सोवियतिया में सन् १८२३ में, ग्राट्ब्रिज में सन् १८५४ में, चिली में सन् १८२५ में, इटली में सन् १८२६ में, न्यूजीलैण्ड में सन् १८३४ में, प्रोर कनाडा में सन् १८३५ में हुआ। नागरिकों में बैंकों के पास नोट चलाने की यह शक्ति सन् १८६१ तक रही। उस वर्ष सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया और सन् १८७५ में यह इस देश के केन्द्रीय बैंक, रिजर्व बैंक आफ इंग्लैंड को अन्तान्तरित कर दी गई।

जब कोई बैंक नोट निगलता है तो वह स्वयं अपनी कार्यशील पूँजी उपन करता है। पहिले पहिले जो नोट चलाये गये थे उन द्रव्य की रसीदें थीं। साथ ही उन्हें चलाने वालों ने यह भी शोच ही समझ लिया था कि जैसा जमा की रसीदों के सम्बन्ध में है वैसा ही उनके सम्बन्ध में भी है अर्थात् इन सब का भुगतान भी कभी एक साथ नहीं करना पड़ेगा। अतः, वह वास्तविक द्रव्य का एक बड़ा अंश चाह जिस काम में लावें, उसने उनके नोटों के भुगतान में तनिक भी अड़चन नहीं पड़ेगी। जब तक किसी बैंक की सारा मानी जाती थी तो तक उनके नोट नगदी ही समझे जाते थे और विधानतः ग्राह्य द्रव्य (Legal tender money) के महसूस ही माने जाते थे। अब, मिल भुनाने में और ऋण देने में भी यही नोट देना प्रारम्भ हो गया और लोग उन्हें सहर्ष लेने लगे। बैंकों के लिये भी इस बात में कोई अन्तर नहीं था कि उनके माल की उत्पत्ति नोटों में हो अथवा अप्रत्यक्ष जमा में हो। यदि इनमें कोई अन्तर था तो वह केवल रूप का ही था। किन्तु व्यापारियों की दृष्टि में नोटों की अपेक्षाकृत जमा के अधिक लाभप्रद जँचने के कारण और जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, नोट निकालने पर अधिकारिक बन्धन लग जाने के कारण जमा बहुत ही महत्व पसन्दगी गई यहाँ तक कि उसकी करन्सी समार के प्रगतिशील देशों में आज नोट करन्सी से कहीं अधिक प्रचलित है। राज इन दोनों की सदृश्यता के विषय में जो कहता है उसका यहाँ पर संकेत कर देना भी आवश्यक अनुपपन्न

न होगा। वह करता है दोनों का प्रयोग ग्राहकों को श्रृणु देने में अथवा उनके प्रणयों और बिलों का विनिमय करने में किया जा सकता है। दोनों ही प्रणयों के रूप में अथवा ग्राहकों के बिलों के रूप में जनता की सेवा करते हैं। दोनों में ही बैंकों ने विमानत ग्राह्य द्रव्य मॉगने का अधिकार रहता है। दोनों ही बैंकों के लिये प्राय के साधन हैं। बैंक के लिये दोनों मॉग पर पूरा करनेवाले दायित्व हैं। प्रागे चलकर उसने इनके अन्तर भी बताया है—
“बैंक नोट जमा की अपेक्षाकृत कहीं अधिक सुरक्षित दायित्व है। अतः, बैंक अपनी सारा इस रूप में चलाना अधिक पसन्द करता है। उद्योग-धन्धों में चाहे जितनी मन्दी क्यों न आ जाय जब तक बैंक जनता का विश्वासमान है तब तक उसके नोट चलते ही रहते हैं। जमा को तो उसके ग्राहक किसी समय भी अपना दायित्व पूरा करने के लिये प्रयोग में ला सकते हैं, किन्तु छोटे नोट बहुत दिनों तक चलत रहते हैं और प्रायः जमा के रूप में बैंकों के पास वापस आते हैं। बैंक नोट में चलन-शक्ति चेकों के अपेक्षाकृत कहीं अधिक है। जिस प्रकार चन्द्रमा गरीबों की लालटेन कहा जा सकता है उसी प्रकार बैंक नोट गरीबों की जमा कही जा सकती है। अतः, लोगों की वास्तविक मॉग पूरा करने के लिये नोट देने में अधिक कठिनाई नहीं पड़ती।” किन्तु यह सब सैद्धान्तिक है। वास्तव में साधारण बैंकों के पास तो अब नोट चलाने का अधिकार रह ही नहीं गया है।

बैंक अपनी कार्यशील पूँजी का कैसे उपयोग करते हैं

उपर्युक्त विवरण से यह तो स्पष्ट हो हो गया है कि बैंकों की अधिकांश कार्यशील पूँजी मॉग पर देय है। हाँ, उनके हिस्सेदारों से प्राप्त पूँजी और उनके लाभ का वह अंश जिसे वह हिस्सेदारों में न बाँटकर सुरक्षित कोष के रूप में रख लेते हैं, अथवा ही स्थायी होता है। किन्तु बैंकिंग के व्यवसाय का अर्थ पूँजी रख छोड़ना नहीं बल्कि उसे चलायमान रखना है। बैंकों को थोड़ा सा नकद कोष रखने के अतिरिक्त शेष सभी ऐसी लागतों में लगा देना चाहिये जो आवश्यकता पड़ने पर उनके खाली हो जानेवाले कोष का स्थान लेने के लिये उपलब्ध हो सकें। थोड़े-थोड़े समय पर प्रायः ऐसे अवसर आते रहते हैं कि लोग अधिकाधिक द्रव्य निकाल लेते हैं। कभी-कभी तो इन अवसरों पर ग्राहक श्रृणु लेने भी आ जाते हैं, जिन्हें पूरा करना भी बैंकों के लिये बहुत ही आवश्यक है। अतः, हम अगले पृष्ठों में यह बात समझाने का

प्रयत्न करेंगे कि वे अपनी सम्पत्ति और अपने पासने (Assets) जिस रूप में रखते हैं और उनका पुनार ग उन्हें जिन जिन बातों का ध्यान रखना पड़ता है।

कुशल और ऐसी योजना लागत बढ़ते रहते हैं जो प्राप्ताती से बचल हो जाना है, और गुणवत्ता के लिए लागतार पड़नी पड़ती है। यह प्राथमिक स्थितियों का प्रगतिमान ध्यान रखने है और उन्हीं के अनुसार अपनी लागतों में बदलाव करते रहते हैं। मोटे तौर पर इन्हें दो विभागों में बाँटा जा सकता है—(१) लाभ न देने वाली और (२) लाभ देने वाली। प्रथम में तो उनके नकद कोष और मृत नटाक और दूसरे में माँग पर वापिस होनेवाली लागत, (Call money) मिलों पर की लागत (Discounts) ऋण (Advances) राजारू माँग-पत्रों पर की लागत (Investments), और मिल नवीकार करना (Acceptances), इत्यादि सम्मिलित हैं।

पहिले हम नकद कोष लेते हैं—इसे अग्ररेखों में टिल मनी (Till money) कहते हैं। इसका अर्थ बैंकों के पत्रों में और केन्द्रीय बैंक में रक्ता हुआ द्रव्य है। इन्हें मिलानर उनकी रक्षा की प्रथम प्थार (First line of defence) बनती है। यह दिवालियापन से बचाती है। सचेतन में यह पूर्व विधान युक्ति (Precautionary measure) है। बैंकों को यथेष्ट नकद कोष रखने और उसे निरन्तर सुदृढ बनाने का मदा प्रयास करत रहना चाहिये। इसके लिये उन्हें देर में बचल होनेवाली लागत शीघ्र बचल होने वाली लागत में परिवर्तित करते रहना चाहिये। जहाँ तक यह प्रश्न है कि नकद कोष और माँग पर देय गकम (Demand liability) का क्या अनुपात रहना चाहिये यह बात जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका चुका है, बहुत सी बातों पर निर्भर है और परिवर्तित होती रहती है। यह निम्नांकित है—

(१) कहीं कहीं व्यवस्थापक सभाओं (Legislatures) ने कुछ प्रतिशत निश्चित कर दिया है। इससे नवमिसियों को अवश्य सहायता मिलती है और अत्यधिक साहस करने वालों के ऊपर भी प्रतिबन्ध रहता है। किन्तु इसके अतिरिक्त यह कुछ नहीं है। वास्तव में बैंक प्रबन्धकों को विधान के द्वारा नॉचने की अपेक्षाकृत उनकी स्वयं की सच्चाई, बुद्धि और निर्णय

शक्ति पर विश्वास करना अधिक अच्छा है। कोई वैधानिक सीमा निर्धारित कर देने से उनके मस्तिष्क में झूठी सुरक्षा का बोध हो जाता है और वे सोचने लगते हैं कि उन्हें जो कुछ करना था वह उन्होंने कर दिया है। फिर, यह बतलाना भी कठिन है कि यह निर्धारित प्रतिशत क्या होनी चाहिये क्योंकि भिन्न-भिन्न देशों की व्यवस्थापक सभाओं ने जो प्रतिशत निर्धारित किये हैं वे सभी एक दूसरे से बहुत ही भिन्न हैं। उदाहरण के लिये डेनमार्क में यह चालू जमा का १० प्रतिशत है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न है, अर्जेण्टाईना में यह स्थायी जमा का ८ प्रतिशत और चालू जमा का १६ प्रतिशत है, चिली में यही क्रमशः ८ प्रतिशत और २० प्रतिशत है, इन्वेडोर में यह क्रमशः १० प्रतिशत और २५ प्रतिशत और बोलिविया में क्रमशः १० प्रतिशत और २० प्रतिशत है। कुछ देशों में इस प्रतिशत में केवल बैंकों में रक्खा हुआ सुरक्षित कोष और कुछ में इसमें यह और केन्द्रीय बैंकों में भी रक्खा हुआ सुरक्षित कोष दोनों सम्मिलित हैं। हमारे देश में रिजर्व बैंक के सदस्य बैंकों (Scheduled Banks) को उक्त बैंक के पास उनकी चालू जमा का ५ प्रतिशत और स्थायी जमा का २ प्रतिशत रखना पड़ता है। उनके स्वयं के बक्सों में रखे जाने वाले कोष पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसके विपरीत अन्य बैंकों (Non Scheduled Banks) को उनकी स्थायी जमा का २ प्रतिशत और चालू जमा का ५ प्रतिशत अपने ही बक्सों में रखना पड़ता है।

(२) यह साधारणतः रखे जानेवाले प्रतिशत पर भी निर्भर रहता है। यदि किसी स्थान का एक बैंक अधिक प्रतिशत रखता है तो उस स्थान के अन्य बैंकों को भी जनता का विश्वास प्राप्त बनने के लिये वैसा ही करना पड़ता है। अन्य स्थानों के बैंकों की अपेक्षाकृत हंगलैण्ड के बैंक बहुत कम प्रतिशत रखते हैं।

(३) किसी बैंक के नकद कोष का परिमाण उसके प्रत्येक ग्राहक की जमा के औसत के परिमाण पर भी निर्भर रहता है। वास्तव में यह उतना होना चाहिये जितना सबसे अधिक जमा रखनेवाले ग्राहक की माँग पूरा करने के लिये काफी हो।

(४) जिन देशों में अधिकांश भुगतान चेकों द्वारा होते हैं उन देशों में उनकी अपेक्षाकृत कम कोष रखने की आवश्यकता पड़ती है जिनमें अधिकांश भुगतान नकदी में होते हैं।

(५) यदि निक्काव प्रणाली (Clearing system) मजबूत हो उठती है तो बैंकों पर की गई प्रविवरण चेकों का भुगतान परम्पर हो हो जाता है । मान लीजिये 'अ' बैंक के ग्राहकों ने 'ब' 'स' 'द' बैंकों के ग्राहकों के भुगतान में 'अ' बैंक के ऊपर के चेक दिये हैं । इसी तरह ने 'ब' 'स' बैंकों 'द' बैंकों के ग्राहकों ने भी अपने से अन्य बैंकों के ग्राहकों के भुगतान में अपने-अपने बैंकों के चेक दिये हैं । अतः, प्रत्येक बैंक की ग्राहकों को अपने बैंक के ग्राहकों से उनका अपने-अपने बैंकों के ऊपर के जो चेक प्राप्त हुये होंगे उन्हें वे अपने अपने बैंकों को देंगे । अतः, सभी बैंकों को अन्य बैंकों के पाना और देना भी होगा । अतः, यदि निक्काव प्रणाली है तो इन चेकों का परम्पर भुगतान हो जायगा, नकदी नहीं देने पड़ेगी । अतः, ऐसी अवस्था में बैंकों को बहुत कम नकद कोष रखना पड़ता है ।

(६) जहाँ पर लोग अपने पास नकदी न रख कर बैंकों द्वारा काम करते हैं, वहाँ पर उसके बराबर चालू रखने से जो बैंक एक तरफ उसे देते हैं दूसरी तरफ उसे पाते भी हैं । अतः, उनका काम कम नकदी रखने पर भी चल जाता है ।

(७) यदि किसी बैंक के ग्राहक ऐसे हैं जो कभी कभी बहुत बड़े निक्काव लेते हैं जैसे मिलों के दफ्तर, इत्यादि तब उसे इन्हें पूरा करने के लिये काफी नकद कोष रखना पड़ता है ।

(८) यदि किसी बैंक की लागत ऐसी है जिसकी जगहों ग्रामानी से हो सकती है तो कम नकदी रखने से भी काम चल सकता है । जिन देशों में द्रव्य बाजार और मिल बाजार बहुत उन्नत दशा में हैं उनमें उन्हीं में लागत लगाई जाती है । अतः, आवश्यकता पड़ने पर उनकी वसूली भी हो सकती है, इंग्लैण्ड में बहुत काफी द्रव्य मिलों और स्टॉक एक्सचेंज के दलालों को जो अपने ऋणों के लिये बहुत उच्च श्रेणी की देयनहार सिक्योरिटीज गिरवी रख देते हैं और उन्हें तीन से दस दिनों के अन्दर अथवा दूसरे ही दिन वापस करने का वायदा कर लेते हैं, दे दिया जाता है । वास्तव में यह ऋण जो बहुत ही थोड़ी अवधि के लिये अथवा दैनिक ही होते हैं एक तरह से बराबर चालू रहते हैं । इन्हें मॉग पर अथवा लघु-कालीन ऋण (Money at call and short notice or Call money) अथवा रात्रि ऋण (Overnight money) कहते हैं । इनके अतिरिक्त मिल डिस्काउण्ट करने के व्यवसाय में भी जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, मिलों की लागत

आदर्श लागत है। यदि केन्द्रीय बैंक है और आजकल तो सभी जगह केन्द्रीय बैंक है तो आवश्यकता पड़ने पर इन्हें ठकने भुनाया भी जा सकता है।

(६) अन्तिम, यदि बैंक व्यापारिक क्षेत्र में स्थित है तो उन्हें उन बैंकों की अपेक्षा कम नकदी रखनी पड़ती है जो कृष्यक्षेत्र में स्थित हैं। यान पर है जिस कृष्यक्षेत्र को बार-बार द्रव्य निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नव व्यापारियों को इसकी आवश्यकता पड़ती है।

यद्यपि मृत स्टॉक (*Dead stock) का प्रश्न है उनमें हमारे और उनके सम्बन्ध की अन्य चीजें जैसे पन्नीचर, इत्यादि सम्मिलित हैं। बैंकों के लिये अपना व्यवसाय करने के लिये इसका होना अत्यावश्यक है। किसी बैंक को इमागत काफ़ी पैसा और भद्रहीनी होनी चाहिये। वास्तव में निम्नलिखित काम देता है। प्राचीन इमारतें अच्छे प्रकार प्राकृतिक करती हैं। यह ऐसी होती चाहिये कि जिसमें न तो चंग लगाई जा सके और न प्राण लग सके। पुराने और नये गिराई रखने के लिये उमम विशेष कमरे होने चाहिये। किन्तु उतना होने लूये भी उनमें बहुत अधिक लागत लगा देना उचित नहीं है। राज के जब्ता में 'एक बैंक के लिये ठोस नकदी होना है ठो और चूने में लागत लगा देने की अपेक्षाकृत कहीं अधिक प्रच्छा है।' मृत स्टॉक का विषय मठिन है। एक तो वह आसानी से बिकता ही नहीं और दूसरे उसे बेचने में बैंक की बदनामी भी हो जाती है, उसे तो बैंक फल में जाने पर ही बेचा जा सकता है, पहिले नहीं।

अब हम बैंकों की कार्यशाला पूँजी के लाभदायक प्रयोगों की ओर आते हैं, उनका एक अंश मृत स्टॉक और नकद कोष में कैसा देने के बाद प्रत्येक बैंक प्रबन्धक यह सोचता है कि शेष को वह कैसे लघुकालीन और दीर्घकालीन ऋणों में लगावे। यह स्पष्ट है कि वह काफी रकम केवल लघुकालीन ऋणों में ही लगाना चाहता है। किन्तु ऐसा करने के पहले वह यह करने का प्रयत्न करता है कि जितनी भी रकम सम्भव हो ऐसी लागत में लग जाय जिससे उसे कुछ आय भी मिले और जो काम पड़ने पर उसी समय प्राप्त भी हो सके। कुछ देशों में भाग्यवश यह सम्भव भी है क्योंकि वहाँ पर त्रिलों और स्टॉक एक्सचेंज के दलाल अगर ऐसा ऋण लेने की ताक में लगे रहते हैं।

1 It is always preferable for a bank to have solid cash in its hands rather than invest it in bricks and mortar

जिलों के दलालों को तो उनकी आवश्यकता उनके प्रत्येक सम्पत्ति में और स्टॉक एक्सचेंज में दलालों को इसकी आवश्यकता प्राचिण भुगतानों के बीच के दिनों में स्टाफ लेने के लिये पड़ती है। ये कन्सॉल्स (Consols), सरकारी बॉण्ड (Exchequer bonds) और लन्दन गवर्नेमेन्ट और नागरिक फाउन्डेशन के बॉण्ड जो आमतौर पर निकल जाते हैं और जिन्हें सरकारी व्यक्ति भी सुरक्षित नीति को संकटों, समानता की तरफ पर देते हैं। प्रो. टाविंग के कथनानुसार देश की दृष्टि में ये उनके व्यवसाय के बहुत ही सुविधापूर्ण श्रद्धा हैं। इनमें कभी थोड़ी और कभी बहुत निम्न हमेशा यथेष्ट आय हो जाती है और साथ ही यदि किसी एक देश को आवश्यकता पड़ती है तो ये नफ़्ती में प्रचलित परिवर्तित भी किये जा सकते हैं। वे लगभग इन्फ्लेक्शन के समय अथवा किसी अन्य लाभदायक लागत में लगाने के लिये उपयोग में ला सकते हैं। फिर जाता के लाभ की दृष्टि में भी ये लाभदायक हैं। कुछ आवश्यक कार्यों के लिये हमेशा थोड़ी और निश्चित प्रवृत्ति के लिये नफ़्ती की आवश्यकता पड़ती रहती है और उसके लिये यही माग पर वापिस होने वाले श्रद्धा बहुत ही उपयुक्त साबित होते हैं।² गऊ के कथन के अनुसार इसमें धैर्य कुछ इसी तरह का असम्भव सा काम करता है कि मोटी बची भी रहती है और खाने के काम में भी आ जाती है। किन्तु ये बुराईयां ने विल्कुल खाली नहीं हैं। इनसे सट्टेबाजी प्रोत्साहित होती है। इसके अतिरिक्त ये साधारण समय के लिये तो अच्छे हैं किन्तु संकट काल के लिये व्यर्थ हैं अर्थात् जम जाते हैं (Become frozen)। ऐसे समय में इनका भुगतान मिलना कठिन हो जाता है और इनमें जो द्रव्य लगा रहता है वह ठीक उसी समय जब उसकी नफ़्ती के रूप में एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, फँस रह जाता है। अतः, बहुत ने धैर्य इनकी अच्छी सम्पत्ति में गणना नहीं करते। लार्ड गारान ने इनके विरुद्ध कहा है।³ तथापि ये लन्दन और न्यूयार्क में बहुत प्रचलित हैं। भारतवर्ष में ये प्रथम युद्ध के पहिले तक तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कराची तर्क में प्रचलित नहीं थे। किन्तु उसके पश्चात् इनका प्रयोग प्रारम्भ हो गया। यहाँ पर इनकी माँग सोने,

2 In the case of Call Money the banker seems to accomplish the impossible feat of 'Having the cake and eating it too'.

3 It is not an asset which constitutes a reserve—useful in the general interest of community at large.

चौदी के और स्टोको के बाजारों में है। यह किसी जमानत के बिना उच्चतम श्रेणी के लोगों को दिया जाता है। ऋण की मन्दी और तेजी पर इनके व्याज की दर निर्धारित रहती है। तेजी की ऋण में यह बहुत ऊँची दर पर भी नहीं प्राप्त होती और मन्दी की ऋण में यह १ प्रतिशत पर मिल जाते हैं। कुछ दिनों से यह द्रव्य सरकारी खजानों के बिलों (Treasury Bills) में लगा दिया जाता है। यह बैंकों के पारस्परिक ऋण (Inter bank loans) में भी लगा रहता है।

किन्तु इस प्रकार की लागत तो केवल कुछ रकम लगाने के लिये ही उपयुक्त है। कार्यगोल पूँजी का एक बहुत बड़ा भाग तो अधिक आय पाने के लिये किसी अन्य काम में लगाया जाता है। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, बैंकर्स की दृष्टि से बिलों की लागत सबसे अच्छी है। यह ऋण व्यापारियों द्वारा लिया जाता है। कभी-कभी बिलों और स्टोको के दलाल भी इनसे लाभ उठा लेते हैं। हम जानते हैं कि बिल डिस्काउण्टिंग हाउस और बिल के दलालों से भी भुनाये जाते हैं जो आवश्यकता पडने पर उन्हें फिर बैंकों से भुना लेते हैं। बिलों के दलाल साधारणतया तो उन पर अपनी पूँजी से ही रकम देते हैं, किन्तु कभी-कभी उन्हें बैंकों की भी शरण लेनी पड़ती है। वे उनसे इस आशा पर ऋण ले लेते हैं कि शीघ्र ही जब उनके कुछ बिल पक जायेंगे तब वह उन्हें लौटा देंगे। बिलों के वास्तविक और झूठे (Genuine and Non Genuine) होने के कारण बैंकों को जो कठिनाता पड़ती है उसे हम पहिले ही समझ आये हैं किन्तु जो ग्राहक अपने बिल भुनाते हैं उनके ऊपर दृष्टि रखने से यह कठिनाता भी दूर हो सकती है। प्रायः, प्रत्येक बैंक के पास कुछ ऐसे ग्राहकों के नाम रहते हैं जिनके बिलों पर वे ऋण देने के लिये तैयार रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राहक के नाम के आगे एक रकम लिखी रहती है जिस तक के ही उसके बिलों पर बैंक ऋण देते हैं, और यदि इस बात पर ध्यान रक्खा जाता है तो कोई डर नहीं रहता। बिलों पर ऋण देने के पहिले यह भी देख लेना चाहिये कि वह सब तरह से पूर्ण हैं, अर्थात् वह नियमानुसार लिखे, स्वीकृत किये और वेचान किये गये हैं। उनके लिखने वाले, ऊपर वाले और वेचान करने वाले धनियो की व्यापारिक स्थिति भी पता लगाते रहना चाहिए क्योंकि उनका भुगतान तो इन्हीं के ऊपर निर्भर रहता है। फिर एक ही प्रकार

के तीसरे के सम्बन्ध के तीसरे पर सब सम्बन्ध नही लगा दनी चाहिये क्योंकि हमने उस व्यापार के सम्बन्ध पर जाने पर सम्बन्ध देने का काम कर रखा है। अन्तिम बात यह कि किसी एक को लगाकर पढ़ने वाले दिलों पर ही अपनी रकम लगानी चाहिये जिससे वह धीरे-धीरे मिलती भी रहे। इससे उसके ग्राहकों की मांग बराबर पूरी होती रहेगी।

प्रथम मुख्य प्रश्न में और जाते हैं। व्यापार में प्रश्न के अन्तर्गत का मत है। प्रत्येक प्रश्न का ज्ञान है, क्या वह कि प्रतीति पर दिया जाने वाला प्रश्न भी आ जाता है। किन्तु मांग पर वास्तव होने वाले और दिल पर दिये जाने वाले प्रश्नों को प्रथम मुख्य प्रश्न के सम्बन्ध नहीं मिनते और सम्बन्ध मयद ठीक भी है, क्योंकि इन पर लगी यह रकम तो ब्रज चाहिए सब प्रश्न की ता सम्बन्ध है। अतः, प्रश्न तो बची है जो हर समय वास्तव न हो सके। प्रश्न भी तीस प्रकार के हैं। प्रथम तो जमा की हुई रकम ने अधिक निकालने में प्राणा अधिग्रहण (Overdrafts) के रूप में, दूसरे नवद सात (Cash credit) के रूप में और तीसरे साधारण प्रश्न (Loans and advances) के रूप में। ये प्रश्नों की, अन्य जमानतों की तथा वैयक्तिक जमानत की भी प्रतीति पर दिये जाते हैं। सच तो यह है कि इनकी की वास्तव्यता पर प्रेमों का लाभ निर्भर रहता है। किन्तु मुद्रा के विचार से यह बहुत उपयुक्त नहीं है, अतः, इनके सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए —

(१) प्रत्येक ब्रेकर को नकदी का योग्य कोष अपने पास रखना चाहिए। यदि यह अधिक हो जाय तो कोई हर्ज नहीं, किन्तु कम नहीं होना चाहिए।

(२) जैसा प्राय कदा जाता है उसे अपने नारे ग्रहण एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिये। इसके यह अर्थ हैं कि उसे अपनी प्रश्न देने की सारी रकम एक ही व्यक्ति को नहीं दे देनी चाहिये। जहाँ तक हो वह अधिकाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली रहनी चाहिए अर्थात् न तो एक व्यक्ति ही हो, न एक तरह का व्यापार ही हो, न एक स्थान हो और न एक प्रकार की जमानत ही हो।

(३) उसे जमानतें भी भली भाँति देख लेनी चाहिये। इस विषय पर राऊ ने जो कुछ कहा है उसे तो हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। जो भी जमानत ली जाय उसे हर दृष्टि से देख लेना चाहिये। किन्तु जैसा

कि एक अगले अध्याय में बताया जायगा कोई भी जमानत आदर्श जमानत नहीं है। भूमि और मकान का रेहन तो सबसे निकृष्ट है। उसे न तो आसानी से और शीघ्र से बेचा जा सकता है और न तो उसके मूल्य का कोई ठिकाना है।

(४) उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसे व्यापारियों के केवल चालू लेन देन का ही प्रबन्ध करना है। उसे न तो सब तरह के न बिकनेवाले धन द्रव्य के रूप में परिणत करने हैं और न उससे इमकी आशा की जाती है कि वह भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साख ही उत्पन्न करेगा।

(५) उसे अपने पक्ष में सदा यथेष्ट गुजाइश (Margin) रख लेनी चाहिये। जितनी अधिक मूल्य में घट-बढ़ होने की सम्भावना हो उतनी ही अधिक यह गुजाइश रखनी चाहिये।

(६) व्यापारिक बैंकों का उद्देश्य केवल लघुकालीन साख उत्पन्न करना है। अतः, यदि वे इस नियम से लेशमात्र भी विचलित हो जाते हैं तो बड़ी आपत्ति आ जाती है। इमम सन्देह नहीं कि यूरोप के बैंक और विशेषतया जर्मन बैंक उद्योग-धंधों में भी रुकम फँसा देते हैं, किन्तु उनके यहाँ की जमा और इंगलैण्ड के तथा अन्य देशों के यहाँ की जमा में जिनकी बैंकिंग इंगलैण्ड की बैंकिंग की तरह की है, एक बड़ा अन्तर है। अतः, इसमें कोई हर्ज नहीं है। प्रत्येक बैंकर को अपने ग्राहक से यह पूछ लेना चाहिये कि उसे कितनी अवधि के लिए ऋण की आवश्यकता है और उसका जो पहिला उत्तर हो वही ठीक समझना चाहिये। प्रायः यह देखा गया है कि जब कोई व्यापारी अधिक दिनों के लिये ऋण माँगता है और उसे वह नहीं प्राप्त होता तब वह यह कहकर कि वह बाट में किसी अन्य जगह से ऋण प्राप्त करके बैंक को वापिस कर देगा उसे जोड़े समय के लिए ही प्राप्त कर लेता है। ऐसा ऋण कभी भी वापिस नहीं होता। वाल्टर लीफ ने अपनी पुस्तक में ऐसे दो ऋणों के उदाहरण दिये हैं—एक में तो किसी बीमा कम्पनी से रेहन पर ऋण लेने की और दूसरे में नये हिस्से बेचकर ऋण लेने की बात थी, किन्तु यह कुछ भी न हो सका। ऐसे ऋण सदा के लिए चालू रह जाया करते हैं।

(७) ऋणों का बारम्बार का नवीनकरण भी अच्छा नहीं है। ऐसा करने से वे जाम (Freeze) हो जाते हैं। इन्हें खातों का पोषण करना (Nursing of Accounts) कहा जाता है।

(८) ऋण के उद्देश्य का भी पता लगा लेना चाहिये । ऐसा कहा जाता है कि उधार के लिए ऋण नहीं देने चाहिए । किन्तु मनुष्य महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि ऋण कहां से वापिस लिया जायगा । कभी-कभी लोग ऐसी सम्भावनायें (Prospects) लेकर आते हैं जो पूरी नहीं हो सकती । यदि बैंकर इन पर उधार नहीं देता तो उसने न केवल उसी की वस्तु-प्राप्ति की भी प्रवृत्ति हो जाती है ।

(९) जो जमानतें दी जायें उनके मूल्य की गट-बट पर भी बैंकर की दृष्टि रखनी चाहिये । यदि उसमें हानि हो जाए तो उसे अन्य जमानत में गारंटी फौरन पूरा कर लेना चाहिये ।

(१०) कम व्याज की नीति भी बहुत अच्छी नहीं होती । इसमें लोग अत्यधिक उधार ले लेते हैं । किन्तु व्याज तो फेन पैन्ती ही में नहीं चलता है उसके लिए अन्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है । अतः, उनके न रहने पर जो पैन्ती लगाने जाती है वह भी व्यर्थ चली जाती है ।

(११) अन्तिम बात यह है कि ऋण मागनेवाले का चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिये । सच तो यह है कि अच्छे चरित्र ने बँकर कोई दूसरी जमानत नहीं है । जो लोग उधार माँगते हैं उन्हें विश्वासघात होना चाहिये क्योंकि विश्वास ही तो साव की एक मुख्य चीज है । अतः इस विश्वास के लिए ईमानदारी, गम्भीरता, तत्परता, न्यायपरता और व्यवस्थापालन करने की आदत होना बहुत ही जरूरी है ।

जहाँ तक इन ऋणों के रूप का प्रश्न है उन्हें तो हम पहिले ही देय चुके हैं । यह जमानत पर अथवा बिना जमानत भी दिए जा सकते हैं । जहाँ तक भिन्न भिन्न प्रकार की जमानत का प्रश्न है उनका हम आगे चलकर विस्तृत अध्ययन करेंगे । अतः रह गये बिना जमानत के ऋण से वह वैयक्तिक जमानत पर दिए जाते हैं । इसमें ऋण लेने वाले के चरित्र की छान-बीन बहुत ही महत्व रखती है । उसकी कुल सम्पत्ति और ऋण वापस करने की क्षमता पर भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है । प्रत्येक बैंकर के कुछ ऐसे ग्राहक अवश्य होते हैं जो उसके सरदार की तरह होते हैं । इन्हें उसे किसी जमानत के बिना भी ऋण देना पड़ता है । उन्हें ज़रूर बहुत ही आवश्यकता पड़ती है तभी वह ऋण माँगते हैं । अतः, बैंकर उन्हें नाराज नहीं करना चाहते । वास्तव में आवश्यक बातें ध्यान में रखकर ऐसे ऋण देने से बैंकों की कभी हानि नहीं होती ।

बैंक अपनी रकम सरकारी, अर्ध-सरकारी, जनहित के लिए बनी हुई सस्थाओं और उद्योग-घरों सम्बन्धी साख-पत्रों में भी लगाते हैं। यदि सच पूछा जाय तो ऐसा करना उनके लिये उपयुक्त नहीं है। उनका काम तो पेंजी चालू रखना है। उसे फँसा रखना नहीं है। किन्तु वे इस काम में अपनी रकम केवल इसीलिए लगाते हैं कि वह इसमें से आवश्यकता पड़ने पर आसानी से वसूल हो जाती है। इन पर की वार्षिक आय भी अधिक नहीं होती। वह बिलों पर तथा अन्य प्रकार के ऋणों पर की आय की अपेक्षाकृत बहुत ही कम होती है। हाँ, इन साख-पत्रों की कीमत बढ़ जाने पर अवश्य लाभ हो जाता है, किन्तु यह तो सट्टेबाजी है जो बैंकिंग के व्यवसाय के विरुद्ध है। किन्तु ये स्टॉक एक्सचेंज के बाजार में किसी समय भी बेचे जा सकते हैं। अतः, वसूली की दृष्टि से तो यह लागत आदर्श लागत है। सरकारी साख-पत्र जिन्हें स्वर्ण साख-पत्र (Gilt-Edged Securities) भी कहते हैं शायद इस दृष्टि से सबसे अच्छे होते हैं। उनके मूल्य का हास भी प्रायः कम होता है। किन्तु बैंक एक ही प्रकार की लागत में अपनी सारी रकम कभी नहीं लगाते, चाहे वह सरकारी साख-पत्र की हो, चाहे किसी की भी हो। उनकी रकम तो भिन्न-भिन्न प्रकार की लागतों में लगी रहती है।

एक अन्य प्रकार का ऋण भी होता है जिसे बिलों की स्वीकृति (Acceptance business) का ऋण कहते हैं। हम यह तो पहिले ही देख चुके हैं कि जब विक्रेता क्रेता के ऊपर कोई बिल करता है तब क्रेता उस पर स्वीकृति देता है। किन्तु ऐसा भी हो सकता है कि उसकी साख इतनी व्यापक न हो कि उसके द्वारा स्वीकृत बिल पर हर बैंक ऋण देने के लिये तैयार हो जाय। ऐसी स्थिति में क्रेता का बैंक उस पर के बिल पर अपनी स्वीकृति दे देता है। इसमें वह अपने ग्राहक के सकीर्ण साख के स्थान पर अपनी विस्तृत साख दे देता है। इसके लिये वह उससे प्रतिकूल (Commission) भी पाता है। यह काम पहिले-पहिल यूरोप के उन बड़े-बड़े व्यापारी महाजनों द्वारा आरम्भ किया गया था जिन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी में नेपोलियन युद्ध के समय इंगलिस्तान द्वारा हालैंएड के हराये जाने पर एम्स्टर्डम का जो दौर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में था उसके समाप्त हो जाने पर लन्दन में अपनी शाखाएँ खोल ली थीं। उन्होंने शायद यह बात समझ ली थी कि भविष्य में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी ही अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में

गलैरड ती रातगानी का ध्यान लेगी। कुछ बड़ी बड़ी समस्यायें अनेकियावालीं
 गभाया। यथाये ये प्रचानू बागी में जमा प्राप्त करने का काम न करने
 क काम्य प्राप्ति को प्राप्त करने तथापि ये उनमें के महत्त्व मान्यता है।
 समस्त कर्तव्य मन्त्रपूर्ण देगा के तागी में इनके सम्मान है जिसमें ये सभी
 स्थाना के गंगा क प्रिय म जानसारे गये हैं इसने ये उनके ऊपर जि
 गये मिला म स्थापति मो दे मत्ते है। इनमें जानी गाय है कि इनके राज
 स्वाह्न मिय गन मिला पर सभी प्रथम गुण देन न लिये तैयार हो जाते हैं।
 गाय न केना में इन बात का वाक्य क्य तेने ह कि यह एते मिल करने
 में ताराय क तीन दिन रहित उनका राम दे देन। प्रावम्भ क ज्ञाता
 गहाजन मिनिय रीकों की मन्त्रणा से भी मिला पर मन्त्रुति देते हैं। प्रथम
 गहायुज के समय में अमेरिकीयानों न भी नृपार्थ को सन्तन का प्रयोग
 बनाने के मन्त्र से प्रवृत्त मिये ह। अतः, ऐसी समस्याय अत्र वर्गों भी यद्ये
 माना न तुल्य गह है। इसके प्रतिष्ठित यह काम अत्र वेकों के हाथ में
 आया गया है। बात यह थी कि उक्त युद्ध के छिड़ने पर व्यापारी
 महानता में युगम के मनु देशों से जो कुछ पाना था वर नहीं मिल
 सका। अतः, उनके लिये उनके द्वारा म्नीकृत मिलों का भुगतान
 करना कठिन हो गया। किन्तु उनकी सात प्रचाना आवश्यक था।
 अतः, सन्तारी आना से उन मिलों का भुगतान वैद्व प्राक रगलैरड ने कर
 दिया। युद्ध के बाद जब यह रकम बचून हुई तब वैद्व प्राक रगलैरड ही को
 मिली। तब से यह काम वैद्व करने लगे। समुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह
 काम वैद्विग का एक व्यवसाय माना जाता है। किन्तु भारत के सम्मिलित
 पूँजी वाले वैद्व या काम नहीं करते। हाँ, यहाँ के सर्वक प्रवश्य उन व्या-
 पारियों को दुरिडियों जरीद लेते हैं जिन्हें वे जानते हैं। अतः, इसने उन पर
 उनका दायित्व भी हो जाता है और इसी कारणवश उन पर वैद्व भी श्रृण
 दे देते हैं।

वैद्व कैसे लाभ कमाते हैं

अब हम इस बात की ओर आते हैं कि व्यापारिक वैद्व कैसे लाभ
 कमाते हैं। हम यह तो देख ही चुके हैं कि वे अपनी कार्यशील पूँजी किन्-
 किन लाभदायक प्रयोगों में लगाते हैं। वास्तव में वही उनकी आय के मुख्य
 साधन हैं। यहाँ पर हम उन्हें फिर दोहराये देते हैं—

(१) माँग पर वापिस होनेवाले श्रृणों पर का व्याज।

(२) बिलों पर ऋण देने की कटती (Discount Charges) ।

(३) ऋणों पर का व्याज ।

(४) साख-पत्रों पर की लागतों पर का व्याज

(५) बिलों पर स्वीकृति देने का प्रतिफल (Commission)

इनके अतिरिक्त प्रासङ्गिक मूल्य (Incidental Charges) की और आदत तथा अन्य कार्य करने से जो आय होती है वह भी उनके लाभ में सम्मिलित है । हम जानते हैं कि बैंक अपने ग्राहकों की चेकों, उनके विनिमय बिलों, प्रण-पत्रों, व्याज के पत्रों (Coupons), बँटनी पत्रों (Dividend warrants), चन्दे किराये, आयकर और बीमा के प्रीमियम की वसूली और उनका भुगतान भी करते हैं । इनमें से अधिकांश काम तो वे नि शुल्क करते हैं, किन्तु कुछ के लिये उन्हें प्रतिफल भी प्राप्त होता है । जैसे बाहर की चेक वसूल करने तथा हिस्सों, स्टकों और ऋण-पत्रों का स्टॉक एक्मचेजों में और अन्य सामानों का उनके बाजारों में क्रय-विक्रय करने के लिये वे दलालों की दलाली के अतिरिक्त अपना प्रतिफल भी लेते हैं । फिर उन्हें धरोहरी (Trustees), नर्वराहकार (Administrators) और साधक (Executors) की हैमियत में काम करने पर भी उचित प्रतिफल मिलता है । इसी तरह से बहुमूल्य वस्तुओं जैसे जेवरों और जवाहिरात, लेखपत्र, इत्यादि अपने पास रखने (Sale Custody) के लिये भी उन्हें प्रतिफल प्राप्त होता है । यह कार्य सचमुच बहुत ही जोखिमपूर्ण है किन्तु जोखिम लेने के बिना तो कोई काम चल ही नहीं सकता । इससे उन्हें न केवल यथेष्ट लाभ होता है बल्कि यह उनके व्यवसाय का एक मुख्य अङ्ग भी है । साख-पत्र रखने पर उनके ऊपर उनके व्याज, इत्यादि और उनके पकने पर उन्हें स्वयं वसूल करने का उत्तरदायित्व भी रहता है । धन मेजने और विनिमय के व्यवसाय से भी उन्हें विशेष लाभ होता है । भारतवर्ष में प्रायः व्यापारिक बैंकों को धन मेजने से बहुत आय होती है । हाँ, विनिमय का काम वे प्रायः नहीं करते क्योंकि वह विदेशी विनिमय बैंकों के हाथ में है ।

बैंक अपने लाभ का किस प्रकार उपयोग करते हैं

लाभ के सब मद ऊपर दिये गये हैं । किन्तु यह सब लाभ हिस्सेदारों के बीच में विभक्त करने के लिये नहीं रहता । इसमें से वह सब खर्च काट दिये जाते हैं जिन्हें करना प्रत्येक बैंकर के लिये आवश्यक रहता है । ये निम्नांकित हैं —

- (१) रथा ती जमा तथा अन्य ग्यामी पर का न्याय ।
- (२) सजानण और दिमाग निगेछा का शुल्क, कर्मचारियों के वेतन, पेन्शन और प्रॉडिन्ट फण्ड का गवर्न ।
- (३) रथ्या के भेजा, इत्यादि के गदम्य शुल्क ।
- (४) दस्तर मागरी गवर्न जैसे छगछ, गार गवर्न, गीजापन गवर्न, गेगनरी रवर्न, गिगया और गोगे गे प्रीनियम, इत्यादि ।
- (५) प्रतिनिधियों का सकर गवर्न और उनके तथा अदतियों के शुल्क ।
- (६) स्यान्डर और सार ग्यामी ती लागत के फास का प्रगन्ध ।
- (७) अप्राप्य कृण और र्वाक के कर्मचारियों द्वारा गिने गये गवर्न ।
- (८) आय तथा अन्य कर ।

फिमी एक का पक्का मुनाफा (Net Profit) उसके प्रगन्ध की कुशलता पर ही निर्भर रहता है । मुद्रा जमा अधिक न्याज न देकर बरत गहरा हो सुविधाय देकर तथा उनसे अनेक प्रकार की सेवायें करके प्राप्त किये जाते हैं । कम वेतनवाले कर्मचारी रखने से कोई लाभ नहीं होता । उनसे प्रगन्ध की वह कुशलता नहीं प्राप्त होती, जो होनी चाहिये । हमारे देश में कुछ बंक थोड़े-थोड़े वेतन पर मनेतर इत्यादि रख लेते हैं जिससे गवर्न इत्यादि बहुत होता है । अधिक वेतनवाले कर्मचारी प्रायः कम वेतनवाले कर्मचारियों की अपेक्षाकृत सन्ने पड़ते हैं । उन्हें अधिक काम मिल जाता है और वे उसे भली भाँति निवाह भी लेते हैं । बड़ा लाता भी कम हो जाता है है और गवर्न भी नहीं होता । पक्के मुनाफे में से उसके हित्सेदारों के बीच में एक निश्चित दर से बँटनी करने के उपरान्त कुछ सुरक्षित कोष के लिये भी रख लिया जाता है । यह कभी कभी ऐसे वर्षों में बँटनी की दर बढ़ाने के भी काम आता है जब लाभ कम होता है । किन्तु प्रायः यह दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले काम के साथ-साथ दिन प्रतिदिन पूँजी बढ़ाने के उद्देश्य से भी संचित किया जाता है ।

प्रश्न

- (१) बैंको की कार्यशील पूँजी कौन-कौन से साधनों द्वारा प्राप्त होती है ? उनमें से प्रत्येक का एक सचित्त विवरण दीजिये ।
- (२) बैंकरो के जमा किम तरह के होते हैं ? इस सम्बन्ध में आप सचित्त जमा से क्या समझते हैं ?

(३) बैंकों की पूँजी कितने प्रकार की होती है ? हिस्सेदारों के सुरक्षित दायित्व से आप क्या समझते हैं ?

(४) 'बैंकों की जमा का सारा काम अधिकारों का पारस्परिक परिवर्तन और उनका द्रव्य के साथ परिवर्तन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है'—इसका विश्लेषण कीजिये ।

(५) एक बैंकर जमा प्राप्त करके अपने ग्राहकों की और समाज की कौन कौन सी सेवाएँ करता है ? क्या इससे वह समाज की कोई हानि भी कर सकता है ?

(६) 'किसी बैंक को जमा प्राप्ति का कार्य और नोट चलाने के कार्य दोनों एक ही प्रकार के हैं'—इसका विश्लेषण कीजिये ।

(७) कोई बैंक अपनी कार्यशील पूँजी कैसे प्रयोग में लाता है ? इस सम्बन्ध में माँग पर वापिस होनेवाले ऋणों से आप क्या समझते हैं ?

(८) किसी बैंकर को अपने ग्राहकों को ऋण देने के समय कौन-सी बातें ध्यान में रखनी चाहियें ? इसे स्पष्टतया समझाइये ।

(९) बैंकों के स्वीकृति के कार्यों से आप क्या समझते हैं ? यह कैसे प्रारम्भ हुआ ?

(१०) वे कौन-कौन से तरीके हैं जिनसे बैंकर अपना लाभ कमाते हैं ? क्या वह सभी हिस्सेदारों में विभक्त किया जा सकता है ?

अध्याय ६

केन्द्रीय बैंकिंग (१)

केन्द्रीय बैंकिंग ने एक विशिष्ट व्यवसाय (Specialised Banking) का रूप तो केवल इसी शताब्दी में ही धारण कर लिया है । इसके पूर्व यूरोप में प्रायः सभी देशों में, पूर्व में जापान और जावा में तथा अफ्रीका में मिश्र और अल्जीरिया में नोट चलानेवाले और सरकारी काम करनेवाले बैंक तो अवश्य स्थापित हो चुके थे, किन्तु जैसा कि तीसरे अध्याय में बताया जा चुका है उन्हें केन्द्रीय बैंकों के कार्यों का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं था । हाँ, यह व्यवसाय

- (२) सरकार के साधारण बैंकिंग और आदत के काम करना ।
- (३) व्यापारिक बैंकों के नकद कोष रखना ।
- (४) राष्ट्र का धात्विक कोष रखना ।
- (५) व्यापारिक बैंकों, बिल के दलालों तथा अन्य ऐसे ही अर्थ से सम्बन्ध रखनेवाले व्यवसायियों को विनिमय अथवा सरकारी बिलों तथा अन्य उपयुक्त साख-पत्रों के ऊपर ऋण देना ।
- (६) जब कहीं से ऋण न मिल सके तब ऋण देने का दायित्व स्वीकार करना ।

(७) बैंकों के पारस्परिक लेन-देनों के लिये निकास-गृह (Clearing House) का प्रबन्ध, इत्यादि करना ।

(८) व्यापार की आवश्यकता के अनुसार और विशेषतः राज्य द्वारा चलाई हुई द्रव्य-प्रणाली स्थिर रखने के उद्देश्य से साख नियन्त्रण करना ।

उसने केन्द्रीय बैंकों का एक अन्य आवश्यक गुण भी बताया था जो यह है कि वे साधारण व्यापारिक बैंकों के व्यवसाय भी न करें अर्थात् न तो वे प्रत्येक व्यक्ति से जमा ही प्राप्त करें और न साधारण लोगों को किसी प्रकार का ऋण दे । किन्तु यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि बहुत से केन्द्रीय बैंक, जैसे फ्रांस के बैंक, आस्ट्रेलिया के बैंक, जावा के बैंक, और मिश्र के राष्ट्रीय बैंक यह काम करते हैं । इधर कुछ दिनों से यह स्पष्ट हो गया है कि कुछ परिस्थितियों को छोड़कर जब राष्ट्र के आर्थिक हित के लिये यह आवश्यक प्रतीत हो, केन्द्रीय बैंकों को यह काम नहीं करने चाहिये । अतः, उपर्युक्त बैंक भी या तो इन्हे धीरे-धीरे कम कर रहे हैं या किसी विशेष कारणवश करते जा रहे हैं । भारतवर्ष में और अर्जेंटीना में जहाँ क्रमशः इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया और अर्जेंटीना राष्ट्र का बैंक कुछ केन्द्रीय कामों के साथ-साथ ऐसा करते थे नये केन्द्रीय बैंक स्थापित किये जा चुके हैं और उन पर ऐसा करने की रोक लगा दी गई है ।

अब हम ऊपर दिये हुये सब काम का पृथक् रूप से विस्तृत अध्ययन करेंगे :—

(१) कागजी मुद्रा चलाना—प्रायः सभी जगह यह काम सबसे पहिले केन्द्रीय बैंकों को सौंप दिया गया था । हम यह बात जानते हैं कि बैंक आफ इंग्लैण्ड इसे अपनी स्थापना के समय से ही करता आ रहा है । इस विषय के कुछ बड़े-बड़े लेखक इसे केन्द्रीय बैंकों का एक मुख्य काम समझते हैं ।

सभी केन्द्रीय बैंकों के पास एकाधिकार था तो इसका एकाधिकार अथवा शेयरधिकार है। पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि कुछ बड़े-बड़े केन्द्रीय बैंकों को यह अधिकार कब दिये गये थे। जिस केन्द्रीय बैंक के पास उस समय इसका एकाधिकार है उनके यहां के प्रमुख बैंकों में था तो किसी समय एक-दूसरे को उनके चालू नोटों का भुगतान करने को मजबूर किया गया था क्योंकि उन्हें धीरे-धीरे समाप्त करने का आदेश दे दिया गया था। हाँ, कुछ ऐसे केन्द्रीय बैंक भी हैं जिन्हें प्रमुख बैंकों के चालू नोटों का अधिकार कुछ शर्तों पर अपने ऊपर ही ले लेना पड़ा था। इंग्लैंड में जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है सन् १८४४ में निजी बैंकों को अपने चालू नोट जारी रखने का अधिकार तो दे दिया गया था किन्तु एक ऐसी शर्त लगा दी गई थी कि जिससे उनका यह अधिकार धीरे-धीरे समाप्त होता गया। जर्मनी में नोट चलानेवाले अधिकारशाली बैंकों ने सन् १८३५ के बहुत पहिले ही उनके इस अधिकार पर जो ध्यान लगा दिये गये थे उनके कारण इसे वहाँ के रीजर्व बैंक को हस्तान्तरित कर दिया था और जो बच रहे थे उन्हें भी इस वर्ष अपना यह अधिकार उसे हस्तान्तरित करने को विवश किया गया। आगमल कुछ ही ऐसे केन्द्रीय बैंक बचे हैं जिनके पास इसका एकाधिकार नहीं है और उनमें से भी केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और चीन ही के केन्द्रीय बैंक मुख्य हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रीय बैंकों के नोटों का भुगतान तो सन् १८३५-३६ में कर दिया गया था, किन्तु उस समय भी कुछ सरकारी नोट चालू थे, यद्यपि उनका परिमाण बहुत ही कम है। कनाडा में भी चार्टर्ड बैंकों के नोटों का परिमाण बहुत ही कम है, अधिकार में तो वहाँ के केन्द्रीय बैंक अर्थात् बैंक ऑफ कनाडा के ही नोट चालू हैं। हाँ, चीन में अक्सर उन तीनों गेज केन्द्रीय बैंकों के जिन्हें नोट चलाने का अधिकार प्राप्त है सन् १८३८ के मई के अन्त में १२३ करोड़ चीनी डालर के नोट चालू थे और इसके विरुद्ध चीन के केन्द्रीय बैंक के केवल ४७ करोड़ चीनी डालर के नोट चालू थे। भारतवर्ष में सन् १८४० की जुलाई से यहाँ की सरकार ने भी रिजर्व बैंक के नोटों के साथ-साथ जिसके पास उन्हें चलाने का एकाधिकार प्राप्त है अपने एक-एक रुपये के नोट उसी प्रकार चलाना प्रारम्भ कर दिया है जिस प्रकार ब्रिटिश राजकोष ने प्रथम युद्ध के समय एक-एक पाउण्ड और आधे-आधे पाउण्ड के नोट चलाने प्रारम्भ कर दिये थे।

नोट चलाने का एकाधिकार कई कारणों से केन्द्रीय बैंकिंग के व्यवसाय

का एक मुख्य अंग माना जाता है। पहिली बात तो यह है कि इससे नोट करन्सी में जो आनकल की द्रव्य-प्रणाली में सभी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है सादृश्यता आ जाती है। दूसरे, इससे केन्द्रीय बैंकों का एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है जिसकी उन्हें सङ्कटकाल में बहुत आवश्यकता पड़ती है। तीसरे, इससे उसे व्यापारिक बैंकों की साख उत्पन्न करने की शक्ति पर नियन्त्रण करने का भी अवसर प्राप्त हो जाता है। जैसा कि आगे चलकर शत होगा उन्हें साख वृद्धि के लिये या तो अपने यहाँ का नकद कोष अथवा केन्द्रीय बैंक में अपनी जमा बढ़ानी पड़ती है। बात यह है कि उन्हें अपने द्वारा उत्पन्न की गई साख का एक निश्चित प्रतिशत इन्हीं में रखना पड़ता है। अब यदि केन्द्रीय बैंक यह समझता है कि साख की वृद्धि देश के हित में नहीं है तो वह ऐसे बैंकों की सहायता नहीं करता। और यदि वह इसका उल्टा समझता है तो ऐसा करता है। अन्तिम बात यह है कि इससे सरकार को नोटों की सुरक्षा के विचार से उन्हें नियन्त्रित रखने में भी बड़ी सहायता मिलती है। इसके विपरीत यदि यह अधिकार कई बैंकों में बँटा रहता है तो इसमें उसे कठिनाई पड़ती है।

जहाँ तक नोटों के नियन्त्रण का प्रश्न है यह कम से कम सात प्रकार से किया जा सकता है। पहिले को अंग्रेजी में फिक्स्ड फाइडुसियरी इश्यू सिस्टम (Fixed Fiduciary Issue System) कहते हैं। इसमें एक निश्चित रकम के नोट तो सरकारी साख-पत्रों पर निकाले जाते हैं, किन्तु उसके ऊपर जो नोट रहते हैं, उनके लिये शत प्रतिशत धात्विक कोष रक्खा जाता है। इसमें लोच नहीं है जिससे धात्विक कोष के धातु की बाहरी अथवा भीतरी माँग के कारण काफी कम हो जाने पर नोटों का परिमाण भी घटाना पड़ता है। फिर, यदि करन्सी की बहुत माँग हो जाती है तो जब तक उसी मूल्य की धातु न प्राप्त हो जाय तब तक वह बढ़ाई भी नहीं जा सकती। किन्तु इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि यह अच्छी स्थिति में करन्सी का अत्यधिक बढ़ जाना रोके रहता है। हाँ, सन् १९२८ से अंग्रेजी प्रणाली में इसमें कुछ लोच आ गया है। इस वर्ष वहाँ पर इस बात की आज्ञा दे दी गई थी कि कोष की आज्ञा से आवश्यकता पड़ने पर अधिक से अधिक दो वर्षों के लिये निश्चित रकम से ऊपर के नोट भी सरकारी साख पत्रों की बिना पर चालू किये जा सकते हैं। हम ये तो जानते ही हैं कि सरकारी साख-पत्रों की बिना पर नोट चालू करने की जो रकम है वह वहाँ पर किस तरह से धीरे-धीरे प्रारम्भ

फ १२ लाख पाउण्ड में बढ़कर सन् १९२१ तक १६,७५० ००० पाउण्ड हो गई थी। किन्तु प्रथम दुष्काल समय राजकोष ने १००० पाउण्ड और प्राप्ति-प्राप्ति पाउण्ड के नोटों की चलाय ५। यत्न, सन् १९२८ में उनका दायित्व ना बैंक को निश्चिन्तित कर दिया गया और सरकारी साधनों की बिना पर चालू करने के नोटों का परिमाण भी २६ करोड़ पाउण्ड कर दिया गया। तब से अब तक का प्रत्यक्ष प्रसार बढ़ता जा चुका है। अंग्रेजों प्रणाली जानान और नारयें ने भी अपनाई है और इसमें योदान्ता पारवर्तन करके वो इसे पंद्रह देशों ने अपना लिया है।

दूसरी प्रणाली वह है जिसमें नोटों का परिमाण विधानत निश्चित कर दिया जाता है (Fixed legal maximum of note-issue) यह सन् १८७० से सन् १९२८ तक प्राम में चालू रही। लेगीइन का कहना है "यह गलत ही बड़ी प्रणाली है और द्रव्य के आधुनिक बाजारों की आवश्यकता पूरी करने के लिये निरुत्तल ही अनुगुक्त है। इससे नोट-प्रसार रूका रहने का कोई सम्भावना नहीं रहती क्योंकि मदासभा (Parliament) जब चाहती है, तब नोट चालू करने का परिमाण विधानत बढ़ा देती है।

तीसरी प्रणाली वह है जिसमें नोट सरकारी साधन-पत्रों की बिना पर चालू किये जाते हैं और साथ ही बैंक की प्राप्त पूंजी और सुरक्षित धोप से अधिक नहीं हो सकते। यह प्रणाली संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रीय बैंकों के नोटों के सम्बन्ध में चालू थी। इसमें भी लोच नहीं है। जैसा प्रग्रेस ने कहा है इसमें चानू नोटों का परिमाण सदा के लिये निश्चित सा हो जाता है और न तो वह मन्दी में घट सकता है और न तेजी में बढ़ सकता है।

चौथी प्रणाली वह है जिसमें नोटों का एक निश्चित प्रतिशत ठेकाहरण के लिये २५, ३०, ३३ १/३ अथवा ४० प्रतिशत धात्विक कोष में रक्खा जाता है और शेष इस शर्त के साथ कि आवश्यकता पड़ने पर अधिकाधिक व्याज देकर कुछ समय के लिये इस धात्विक कोष का प्रतिशत कम भी किया जा सकता है सरकारी साधन पत्रों और व्यापारिक विलों में रक्खा जाता है। इसे सन् १८७५ में जर्मनी ने और सन् १९११ में कुछ संशोधनों के साथ

१ सन् १९४७ के अन्त में नोटों का परिमाण १३६ २ करोड़ पाउण्ड था और स्वर्ण कोष का परिमाण २० ४६ लाख पाउण्ड था।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने तथा प्रथम युद्ध के बाद कुछ अन्य देशों ने अपनाया था। इसमें यह अन्तर्ज्ञाई है कि जब एक तरफ तो इसमें लोच है तब दूसरी तरफ इसमें धात्विक कोर न मिलने पर अत्यधिक द्रव्य प्रसार नहीं हो सकता।

पाँचवीं प्रणाली वह है जिसमें चौथी प्रणाली ही की तरह नोटों का कुछ प्रतिशत तो धात्विक कोर में रखा जाता है किन्तु शेष के लिये कोई प्रबन्ध नहीं रहता। हाँ, बैंक फेल होने पर उसकी सम्पत्ति पहिले नोटों के और फिर अन्य भुगतानों में लगाई जाती है। इसमें बैंकों के लिये चौथी प्रणाली की अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्रता रहती है। यह प्रणाली हालैण्ड में बहुत समय तक चालू थी, और आज-कल दक्षिणी अफ्रीका के साथ में चालू है।

छठी प्रणाली अनुपातिक जमा प्रणाली (Proportional Deposit Method) है। इसमें नोट चलाने वाले बैंकों को जितने के नोट चालू किये गए हैं उतने का एक विशेष प्रतिशत सरकारी साख-पत्रों अथवा धातु में केन्द्रीय बैंक में जमा कर देना पड़ता है। यह प्रणाली संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सदस्य बैंकों के नोटों के सम्बन्ध में चालू है। वहाँ पर उक्त बैंक को एक निश्चित प्रतिशत सरकारी साख-पत्रों में लगाना पड़ता है और फिर उन्हें फेडरल रिजर्व बोर्ड के पास जमा कर देना पड़ता है।

सातवीं प्रणाली चौथी प्रणाली की ही संशोधन-मात्र है। इसमें एक निश्चित प्रतिशत तो धातु में रखनी पड़ती है, और कुछ किसी दूसरे देश के सरकारी साख-पत्रों में अथवा किसी विदेशी केन्द्रीय बैंक में जमा रखनी पड़ती है। भारतवर्ष में सन् १८६१ से सन् १९२० तक तो प्रथम प्रणाली (Fixed Fiduciary Issue Method) चालू थी और आज-कल यह सातवीं प्रणाली एक विशेष रूप में चालू है।

अन्त में यह कह देना भी आवश्यक है कि प्रायः सभी राष्ट्रों ने केन्द्रीय बैंकों को नोट चलाने का जो एकाधिकार दे रखा है उससे उन्हें जो भारी लाभ होता है उसका उन्होंने बँटवारा करना प्रारम्भ कर दिया है। कहीं-कहीं पर तो नोट चलाने से इन्हें जो लाभ प्राप्त होता है उसका और इनके दूसरे बैंकिंग के कार्यों से जो लाभ प्राप्त होता है उसका अर्थात् दोनों का हिसाब अलग अलग रखा जाता है और नोट चलाने से जो लाभ प्राप्त होता है वह पूरा राष्ट्र को दे दिया जाता है। अन्य स्थानों में या तो हिस्सेदारों को पहिले एक निश्चित प्रतिशत की बँटनी देकर शेष सब राष्ट्र का हो जाता है या

मन की मन में कुछ और गह्र का रिश्री विधान प्राग निर्धारित तरीके का बंटवारा होता है। तब आप इंग्लैंड के मण्डोपकरण के पार्लो छो ठमरे नोट चलाने से उनके विधान का मन तोता था तब सभी सरकार से होती तो और भारत में मण्डोपकरण के पार्लो हिस्सेदारों को केवल ३३ प्रतिशत ही ज़ेदनी दी जाने के बाद उम्मा साग लागू नज़रों में चला जाता था।

(२) राज्य के प्राधान्य और आदत के ज़ायें करना और आर्थिक मामलों में सरकार को मन्त्रणा देना पुगने केन्द्रीय बैंक तो यह काम उस समय भी करते थे जिस समय वह पूर्ण रूप से केन्द्रीय बैंक नहीं बन पाये थे, और न केन्द्रीय बैंकों के तो उन विधान के प्रारम्भ ही में विधान वह स्थापित हुये हैं, यह दिया हुआ है कि वह वह सब काम करेंगे।

प्राजसल तो केन्द्रीय बैंक यह काम केवल इन लिए ही नहीं कि यह राज्य के लिए सुविधाजनक और प्रत्यक्ष्ययी है शक्ति दस्तलिये भी करते हैं कि इनका देश के द्रव्य बाजारों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और यदि वह इनके न करें तो उनका इन पर नियन्त्रण भी न रह सके। वास्तव में एक केन्द्रीय बैंक उनकी सरकार के जो लेन-देन होने हैं उसका उसके देश के द्रव्य बाजारों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे सभी दूर कर सकता है जब वह राज्य के लिये बैंकर, प्रदलिये और मन्त्रणा देने का काम करता हो। केन्द्रीय बैंकों का विनिमय सम्बन्धी दायित्व भी रहता है और सरकार के इनके लेन-देन इतने अधिक रहते हैं कि जब तक यह सब उनके द्वारा न सम्पादित किये जायें तब तक वह अपना यह उत्तरदायित्व नहीं पूरा कर सकते। केन्द्रीय बैंकों के द्रव्य बाजारों से सीधी तौर पर सम्बन्धित होने के कारण वह सरकार को आर्थिक मामलों में भी सरकार और देश दोनों के हितों के अनुकूल मन्त्रणा दे सकते हैं।

केन्द्रीय बैंक सरकार के बैंकर की हैसियत से अपने यहाँ की भिन्न-भिन्न सरकारों की तरफ से और उनके विभागों की तरफ से पूँजी सम्बन्धी और आय-व्यय सम्बन्धी दोनों ही प्रकार के जमा प्राप्त करते हैं और भुगतान देते हैं। वह राज्य के आय और जनता से उनके लिये ऋण की बसूली की सम्भावना पर उन्हें ऋण भी देते हैं। कोई केन्द्रीय बैंक वास्तव में अपनी सरकार को स्थायी (Permanent) ऋण नहीं देता। हाँ, कुछ केन्द्रीय बैंक प्रवश्य अपनी सरकार को स्थायी ऋण देने के विचार से ही संस्थापित किये गये थे। किन्तु बाद में उन्हें भी और अधिक ऐसे ऋण देने के लिये

मना कर दिया गया। हम जानते हैं कि बैंक आफ इंग्लैण्ड की स्थापना वहाँ की सरकार को उसकी प्रारम्भ की १२ लाख पाउण्ड की सारी पूँजी देने के लिये ही हुई थी और बाद में भी धीरे-धीरे उसने उसे इतना ऋण दिया कि वह सन् मिलाकर सन् १८०० तक १४,६८६,००० पाउण्ड हो गया। किन्तु फिर सन् १८३३ में इसे घटाकर ११,०१५,००० पाउण्ड कर दिया गया जो सन् १८२८ तक रहा। इसके बाद भी इस रकम में कई बार परिवर्तन किये जा चुके हैं। बैंक आफ फ्रांस ने भी सन् १८५७ से राज्य को स्थायी ऋण देना प्रारम्भ कर दिया था जो सन् १८२६ तक ३८०० करोड़ पाउण्ड हो गया। फिर, सन् १८२८ में यह घटाकर २० करोड़ फ्रैंक कर दिया गया। यह कमी जनता से ऋण लेकर और बैंक के स्वर्ण और विनिमय कोष का फ्रैंक को नई विनिमय दर से जो पहिले की दर की केवल ६ ही रखी गई थी मूल्य लगाकर की गई थी। किन्तु कुछ ही समय बाद फिर उसने सरकार को ३०० करोड़ फ्रैंक का स्थाई ऋण दिया। इसके बाद सन् १८३५ से सन् १८३८ तक में उसने उसे कई लघुकालीन ऋण दिये जिनका कुल जोड़ ५००० करोड़ फ्रैंक था। किन्तु इस वर्ष बैंक और सरकार के बीच में एक प्रतिज्ञा पत्र लिखा गया जिससे बैंक के स्वर्ण और विनिमय कोष का फिर से प्रति पाउण्ड १७० फ्रैंक के हिसाब से मूल्य लगाने से जो लाभ हुआ उससे बैंक ने सरकार को जो लघुकालीन ऋण दे रक्खा था उसका आंशिक भुगतान किया गया और बैंक का सरकार के ऊपर ३२० करोड़ फ्रैंक का स्थायी ऋण माना गया। यह केवल दो उदाहरण मात्र हैं। प्रायः प्रत्येक केन्द्रीय बैंक ने आवश्यकता पड़ने पर अपनी सरकार को अवश्य ही कुछ न कुछ स्थायी ऋण दिये हैं। नये ऋण देने के बाद बार-बार भविष्य में ऐसा करने पर बन्धन लगाये गये और फिर उन्हें तोड़ा गया। यह ऋण देने के अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक अपनी-अपनी सरकार के साख-पत्र और विल भी एक बहुत बड़े परिमाण में खरीद कर अपने पास रखते हैं। संसार के दो बड़े केन्द्रीय बैंक आफ इंग्लैण्ड और संयुक्त राष्ट्र-अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक, प्रथम युद्ध के समय से अब तक बराबर अपनी-अपनी सरकारों की इसी प्रकार सहायता करते आ रहे हैं।

यहाँ पर यह बता देना भी आवश्यक है कि सरकार को ऋण देकर किसी केन्द्रीय बैंक के अपनी साख बढ़ाने से बैंकों के नकद कोष बढ़ जाते हैं और उनका साख के प्रसार पर वही प्रभाव पड़ता है जो नोटों के प्रसार पर पड़ता है। यह संसार के कई महत्त्वपूर्ण देशों में सन् १९१४-१८ के बीच में और

उनके नार न दृष्टा था। जब गेई केन्द्रों। "क अपनी सरकार को श्रृंखला देता है ता सरकार उसे जानता हो या नौ मान सराद कर या उम्मे नाम श्राकर दे देती है। फिर, यही बात न नामा के रूप में प्राप्त हो जाती है जिनसे उनकी सात पत्रों पर की लागत (Investments) मिली पर की लागत तथा श्रृंखला के परिमाण उदा लिने जाते हैं।

भारत में १९५४ यूनिवर्सल सरकार को किसी भी सीमा तक इस कार्य पर श्रृंखला दे सकता है कि वह नौन मद्रासों के अन्दर-अन्दर वापिस हो जायें। सिन्धु यह उनके सात-पत्र भी अपनी पूर्ण श्रृंखला में सुचित होय और अपने ब्रिग विभाग के नामा के ६० प्रतिशत के मूल्य तक रूप सकता है। हाँ, इनमें से जो साल भर के बाद पत्ते गले हैं और जो टन साल के बाद पत्ते गले हैं उनका परिमाण उन्नीस पूर्ण और उनके सुचित गोप के अलावा ब्रिग विभाग के नामा के समस्त ४० प्रतिशत और २० प्रतिशत में अधिक नहीं हो सकता। लघुमालीन सात पत्रों का परिमाण इंग्लिये अधिक रक्का गया है कि जिससे उनके मूल्य के साथ से उनके क्षति न उठानी पड़े और साथ ही यह जब चाहे तब उन्हें बचा भी कर ले।

सरकार के अदसिये और नती की दृष्टियत से नौ केन्द्रीय बैंकों को बहुत से काम करने पड़ते हैं। वह सरकारी श्रृंखला का प्रबन्ध करते हैं, उनके सम्पन्न से स्टॉक और प्रमाण-पत्र हस्तान्तरित होने पर जिस रजिस्टर में उनके लेखे होते हैं उन्हें रखते हैं, सरकारी श्रृंखला निकालने हैं, उन्हें दूसरे श्रृंखला में बदलते हैं अथवा उनका भुगतान करते हैं, सरकारी मिल निकालते हैं और उनके भुगतान करते हैं, विनिमय की निकासी (Clearing) का तथा अन्य बहुत से कार्य करते हैं।

(१) व्यापारिक बैंकों के नकद कोष रखना—व्यापारिक बैंकों ने अपने अपने केन्द्रीय बैंकों में धीरे-धीरे अपने नकद कोष रखने प्रारम्भ कर दिये। वास्तव में यह तभी विशेष तौर पर होने लगा जब उन्होंने यह समझ लिया कि उनकी नोट चलाने की शक्ति के कारण और विशेषतः उनके देश के अन्दर बहुत ही विश्वासपात्र तथा विस्तृत क्षेत्र में चालू होने के कारण उनके यहाँ अपने खाते रखने से उन्हें बहुत लाभ होगा। सच तो यह है कि केन्द्रीय बैंकों में नामा की हुई रकम उनके स्वयं के पास की रकम के ही सदृश्य है इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंकों से घनिष्ठ सम्बन्ध उत्पन्न हो जाने में वह अपने एक बहुत बड़ा सम्मान भी समझने लगे। इंग्लैण्ड के अटारहवीं शताब्दी

के निजी बैंकों ने भी यह सब बातें भली भाँति समझ ली थीं और इसी से वह बैंक आफ इंग्लैण्ड में अपने हिसाब रखने लग गये थे। सन् १८२६ के बाद जब सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों की स्थापना हुई तब उन्होंने भी पूर्वोक्त चलन चालू रक्खा। दूसरे देशों में भी यही हुआ। किन्तु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना के साथ ही इस सम्बन्ध के एक नये सिद्धान्त का प्रारम्भ हुआ जो यह है कि प्रत्येक बैंक अपने-अपने देशों के केन्द्रीय बैंक के पास अपनी जमा का विधान द्वारा निश्चित प्रतिशत अवश्य रखे। उसके बाद जितने केन्द्रीय बैंक स्थापित हुये हैं उनमें से प्रत्येक के विधान में यह बात दी हुई है। हमारे देश में भी जैसा एक पिछले अध्याय में बताया जा चुका है सब सदस्य बैंकों (Scheduled Banks) को उनकी माँग पर वापिस होनेवाली और एक निश्चित अवधि दी जाने पर वापिस होनेवाली दोनों प्रकार की जमा के क्रमशः ५ प्रतिशत और २ प्रतिशत का नकद कोष रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है।

जहाँ तक किसी देश की द्रव्य सम्बन्धी और बैंकिंग सम्बन्धी स्थिति का प्रश्न है वह नकद कोष के इस प्रकार केन्द्रीय होने से चाहे वह विधान द्वारा हो चाहे चलन के अनुसार हो बहुत ही अर्थपूर्ण हो जाती है। उसके तेजी और आवश्यकता के समय पर पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो सकने के कारण उसकी बिना पर साख की लोच बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि हम ससार के मुख्य-मुख्य देशों के बैंकों द्वारा जो नकद कोष उनके यहाँ केन्द्रीय बैंकों की स्थापना के पहिले रखे जाते थे और जो उसके बाद रखे जाते हैं उनकी तुलना करें तो हमें यह अवश्य ही शत हो जायगा कि इससे उनकी भी कमी हो जाती है। भारतवर्ष ऐसे कृषि-प्रधान देश में कृषि की ऋतु में जो अत्यधिक साख की आवश्यकता पड़ती है उसे पूरा करने के लिये बैंकों के नकद कोष केन्द्रीय रखना बहुत ही आवश्यक है, किन्तु यहाँ के रिजर्व बैंक की बैंक दर के बराबर एक समान रहने पर भी हम यह नहीं कह सकते कि उक्त बैंक की स्थापना के बाद से नकद कोष के उसके पास केन्द्रीय रहने पर भी यहाँ की अत्यधिक साख की माँग बराबर पूरी हो जाती है। किन्तु जो कुछ कठिनाई है वह जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे केवल इसी कारण है कि यहाँ के द्रव्य के आधुनिक बाजार और देशी बाजार के बीच में कोई घनिष्ट सम्बन्ध नहीं है।

(४) राष्ट्र का घात्विक कोष रखना—प्रत्येक केन्द्रीय बैंक को प्रायः

विधान के अनुसार ही अपने पाप गणेश नाटिक कोप रखना पड़ता है। पाले तो यह धात्विक मॉग केवल नोटों के लिये ही रखना पड़ता था किन्तु तेरे भोरे उस गान की भी आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि यह जमा के लिये भी होना चाहिये। मच तो यह है कि प्रायः सभी आगे बढ़े हुए देशों में आज़-जल जमा की जिना पर निपटारे गये थे जो का प्रयोग नोटों के प्रयोग का अपेक्षान्त की अधिक बढ़ गया है। अतः, ऐसा होना आवश्यक हो गया है। किन्तु रमार्तण म और उसका साथ ही अन्य बहुत से देशों में आज भी जमा के संग्रह में धात्विक कोप रखने के लिये कोई किरान नहीं है। हाँ, यह देश ऐसे ही इतना अधिक धात्विक कोप रखते हैं जितना कि केवल उनके नोटों के कारण नहीं होना चाहिये। फिर यह शोध कितना होना चाहिये यह बात मदा के लिये नहीं निश्चित की जा सकती। अन्त में इसे उम विशेष केन्द्रीय बैंक के निश्चय पर ही छोड़ देना पड़ेगा। वास्तव में जो चीज अनिश्चित है वह यह है कि किसी देश की विभिन्न दर और उसकी अन्य-प्रणाली स्थिर और चालू रखने के लिये किने धात्विक कोप की आवश्यकता पड़ेगी। एक ही देश में भिन्न-भिन्न समय में और भिन्न-भिन्न देशों के बीच में यह बराबर परिवर्तित होती रहती है। जितने देश हैं उनकी समी आर्थिक स्थिति और प्रणाली में पारस्परिक विभिन्नता के साथ-साथ उनकी जनता की प्रकृति में भी विभिन्नता है, और वास्तव में इन्हीं सब बातों पर उनके धात्विक कोप की मात्रा की आवश्यकता निर्भर रहती है। इसमें सन्देह नहीं कि केन्द्रीय बैंकों के प्रबन्धकर्ता स्वयं ही यह बात अपने अनुभव से सीधे लेते हैं और इसी कारण इसके लिये उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता दी जा सकती है। हाँ, जब कोई नया केन्द्रीय बैंक खुलता है तब अवश्य उसके प्रबन्धकर्ताओं के अनुभवहीन होने के कारण इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि यह मात्रा निश्चित कर दी जाय।

कुछ देश अवश्य ऐसे हैं जिनकी विशेष परिस्थितियों के कारण उन्हें जो प्रायः आकस्मिक माँग पूरी करनी पड़ती है उसके कारण अवश्य उन्हें इसकी एक बहुत बड़ी मात्रा रखनी पड़ती है। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं—(१) जिनके यहाँ से कुछ थोड़ीसी ही वस्तुएँ अत्यधिक निर्यात होती हैं जैसे अर्जेंटीना, ब्रेजिल, चिली, कनाडा और न्यूजीलैण्ड। इनके मूल्य गिर जाने से इनकी व्यापारिक विषमता (Balance of Trade) इनके विपरीत हो जाती है जिससे इनके यहाँ के केन्द्रीय बैंकों को अत्यधिक धात्विक कोप निका-

यह बात इधर कुछ दिनों से सही नहीं है।

लाना पड़ता है। (२) वे जिनके यहाँ विदेशियों के लघुकालीन कोष जमा रहते हैं जैसे ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इन्हें कभी भी माँगा जा सकता है। (३) वे जिनके यहाँ की राजनैतिक परिस्थिति गड़बड़ होने के कारण उनकी करन्सी के विनिमय मूल्य में बराबर परिवर्तन होता रहता है, जैसे फ्रांस।

सन् १९३२ के पहिले बैंक आफ इंग्लैण्ड के पास बहुत कम स्वर्णकोष था। किन्तु इसके बाद उसने इसे नोटों और विनिमय समता कोष (Exchange Equalisation Fund) के सम्बन्ध में बहुत बढ़ा लिया था। हाँ, द्वितीय महायुद्ध के कारण इस समय फिर यह बहुत कम हो गया है, किन्तु धीरे-धीरे अवश्य बढ़ जायगा। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की फेडरल रिजर्व प्रणाली में भी इसकी बाहुल्यता है। अब, केन्द्रीय बैंकों के अन्य कार्य लेने के पहिले यह भी कह देना आवश्यक है कि प्रायः इनके नाम में रिजर्व (Reserve) शब्द आने के कारण जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक, दक्षिणी अफ्रीका का रिजर्व बैंक, पीरू का केन्द्रीय रिजर्व बैंक, न्यूजीलैण्ड और भारत के रिजर्व बैंक, इत्यादि बहुत से लोग इनके रिजर्व अर्थात् कोष रखनेवाले कामों का बहुत महत्व समझते हैं।

(५) व्यापारिक बैंकों, विलों के दलालों और व्यापारियों तथा इसी प्रकार की अन्य द्रव्य से सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा लाये हुये विनिमय विलों, सरकारी विलों और दूसरे उपयुक्त साख-पत्रों पर इन्हें ऋण देना और (६) जब कहीं ऋण न मिल सके तब उसे देने का दायित्व स्वीकार करना—व्यापारिक बैंकों, विलों के दलालों और व्यापारियों तथा इसी प्रकार की अन्य द्रव्य से सम्बन्धित संस्थाएँ प्रायः अपने केन्द्रीय बैंकों के पास ऋण के लिये तब तक नहीं जाती जब तक उनके स्वयं के और बाहर के वह सब साधन नहीं समाप्त हो जाते जिन तक उनकी आसानी से पहुँच हो सकती है। अतः, केन्द्रीय बैंक जब अन्य कहीं ऋण न मिल सके तब उसे देनेवाले समझे जाते हैं और क्योंकि वह यह काम प्रायः विनिमय विलों, सरकारी विलों और दूसरे उपयुक्त साख-पत्रों की विना पर करते हैं, अतः, (५) और (६) काम हम एक साथ ही लेते हैं। किन्तु यहाँ पर यह कह देना भी आवश्यक है कि यद्यपि बैंक आफ इंग्लैण्ड ने विनिमय विलों, सरकारी विलों और दूसरे साख-पत्रों पर बहुत दिनों पहिले से ही ऋण देना प्रारम्भ कर दिया था तो भी वह जब कहीं ऋण न मिल सके तब उसे देने का दायित्व स्वीकार करने के लिये काफी

समय तक तैयार नहीं था। मई १९५५ तक तो यह उन विलों के वित्ति-
 प्रत्यक्ष लेन के लिये तैयार हो नहीं पाया था किन्तु यह राय-संज्ञा चल
 पा रहा था। हाँ, उस रीति में प्रत्यक्ष या धैर्य और दूसरी दृष्टि साधनों
 सम्पादना के साथ यह विचार नहीं था कि वह लेने के लिये तैयार था कि
 उसने अत्यन्त ही कम-से-कम कुछ-कुछ प्रतिष्ठापूर्वक दया दी। इसके बाद
 अन्य आर्थिक मन्त्र के प्रयत्नों पर भी उसने बहुत प्रतिष्ठा दिगताई किन्तु
 सन् १९५२ तक विले-विले तक जब 'बेजलीज' की 'बोम्बर्ग' स्ट्राट नामक पुस्तक
 प्रकाशित हुई तो उसने यह दायित्व पूर्णतया स्वीकार करना प्रारम्भ कर दिया
 था। अन्य के प्रायः विलों ने भी यह धर्म-तौर पर लिया। सन् १९६३ में
 जब मधुक राष्ट्र अमेरिका के फूल रिजर्व बैंक स्थापित हुये उस समय तक
 यह काम केन्द्रीय बैंक का एक मुख्य काम समझा जाने लगा था। नाममात्र में
 इसका मतलब सब जगह समझने वाले का कार्य ही हीटर के सदृश पैसा के
 सभी बड़े-बड़े लेन-देन के केन्द्रीय बैंक के कार्यों में से इसे बहुत ही महत्व
 प्राप्त माना है। जितना पर ऋण देने (Re-discounting) के अर्थ
 साधारणतया वो विनिमय के बहुत ही अन्धे विलों पर ऋण देने के ही हैं
 किन्तु इनमें इसमें सरकारी विल और अन्य साव-यंत्र भी सम्मिलित हो गये हैं
 बाल्य में इस व्यापकता का एक मात्र कारण यही है कि केन्द्रिय बैंक ने कहीं
 भी ऋण न मिलने पर ऋण देने का अनुरोध दायित्व स्वीकार कर लिया है
 और उसके लिये बहुत अच्छे विनिमय विल सदा नहीं मिलते। बैंक, इत्यादि
 विनिमय विलों के वित्ति-संस्कारों विलों और अन्य साव-यंत्रों पर भी ऋण
 देने हैं। सच तो यह है कि प्रथम युद्ध के समय में सरकारी विलों और अन्य
 साव-यंत्रों का परिमाण विनिमय विलों की अपेक्षाकृत बहुत अधिक बढ़ गया
 है। "विलों पर ऋण देने का काम नोट चालू करने और नकद जोष रखने
 के कामों से बहुत ही सम्बन्धित है क्योंकि यह दोनों जब केन्द्रिय हो जाते हैं तो
 केन्द्रीय बैंकों की ऋण देने की शक्ति भी अत्यधिक बढ़ जाती है। नोट चलाने
 के अधिकार के कारण कोई भी केन्द्रीय बैंक उसने जो हाथ-हाथ चलाने-
 वाली करन्सी की माँग होती है उसे और नकद कोष केन्द्रित होने के कारण
 उसके पास जो विलों, इत्यादि पर ऋण देने की प्रार्थना की जाती है उसे पूरी
 करने में पूर्णतया समर्थ रहता है।"

किन्तु व्यापारिक बैंकों को इस सुविधा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये।
 साधारणतया वो उन्हें स्वयं के साधनों पर ही निर्भर रहना चाहिये। 'जब कि

प्रत्येक केन्द्रीय बैंकों के संकट के समय उनकी सहायता करने के लिये तैयार रहना चाहिये और जब उन्हें कहीं से भी ऋण न मिल सके तब उन्हें ऋण देना चाहिये, इसके यह हर्गिज भी अर्थ नहीं है कि बैंकों को हर परिस्थिति में अपने केन्द्रीय बैंक से अपरिमित ऋण लेने का अटल अधिकार प्राप्त है ।' भारतवर्ष में अभी हाल तक बैंकों को इस सम्बन्ध का एक बहुत बड़ा भ्रमोत्पादक विश्वास था और यहाँ के रिजर्व बैंक को उस समय बहुत बुरा भला कहा गया था जब उसने प्रावक्कुर नेशनल क्लिलन बैंक को सन् १९३८ के मध्य में जिस समय वह बड़ी कठिनाई में पड़ा हुआ था और अन्त में उसका काम बन्द हो गया था, मदद नहीं दी । अन्त में बैंक के ७वीं दिसम्बर सन् १९३८ के 'सदस्य बैंकों के बिलों पर तथा अन्य प्रकार से ऋण देने के सम्बन्ध के पत्र' द्वारा जो निम्न आशय का था, यह बात स्पष्ट की गई :—

“संसार के दूसरे देशों में केन्द्रीय बैंकों का जो चलन है उसके अनुसार तथा इस देश में बैंकिंग को एक उचित मार्ग पर चलाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक अपने सदस्य बैंकों को साख देने के समय केवल उनके द्वारा लाई गई जमानतों पर ही नहीं बल्कि उनके लागत की किस्मों पर और उनका व्यवसाय करने का जो ढंग है उदाहरण के लिये वह जमा आकर्षित करने के लिये व्याज की ऊँची दर तो नहीं देते हैं. अथवा साधारण अवसरों पर जब द्रव्य बाजारों में काफी द्रव्य रहता है तब वह रिजर्व बैंक से सहायता नहीं लेते हैं, अथवा वह अत्यधिक व्यापार तो नहीं करते हैं और वस्तुओं पर अथवा साख-पत्रों पर सट्टेबाजी के लिये अत्यधिक साख तो नहीं देते हैं अथवा जमानत प्राप्त किये बिना तो बहुत अधिक व्यवसाय नहीं करते हैं इस पर भी विचार करेगा । इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखना चाहिये कि रिजर्व बैंक विधान के अनुसार केवल अस्थायी ऋण ही दे सकता है । यह बात निश्चय करने के लिये कि वह जो साख दे रहा है उसका किसी प्रकार का दुरुपयोग तो नहीं होगा । रिजर्व बैंक उधार लेनेवाले बैंकों से कोई भी ऐसी सूचना माँग सकता है अथवा उन पर कोई भी ऐसे बन्धन लगा सकता है जो उसकी दृष्टि में वाञ्छनीय हैं और सहायता की प्रार्थना करनेवाले किसी भी सदस्य बैंक को उपर्युक्त सूचना देनी पड़ेगी तथा बन्धनों को मानना पड़ेगा ।

किसी अन्य बैंक की तरह रिजर्व बैंक को भी कोई कारण बताये बिना भी किसी बैंक को उसके कारगजों पर ऋण देने की मनाही कर देने का पूर्ण

अधिकार है। किन्तु जो सदस्य 'बैंक' उचित ढंग पर व्यवसाय करते हैं वे रिजर्व 'बैंक' से सफ्ट के समान अथवा प्राग्ज्यमाना पदार्थ पर उचित जमानत देने पर अवश्य सहायता पाने की आशा रख सकते हैं।

इसने यह स्पष्ट है कि कौन-कौनसे केन्द्रीय बैंक जब भी श्रृंखला न मिले तब श्रृंखला देने का अपना दायित्व स्वीकार करते हुये भी अपने यहाँ के बैंकों का काम करने का खर्च उँचा कर सकता है। मशुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी इस सम्बन्ध की स्थिति अक्टूबर मन् १९३७ के एक पेंल रिजर्व पर में स्पष्ट की गई थी।

(७) बैंकों के पारस्परिक लेन-देन को निकाम-गृह (Clearing house) द्वारा निपटाना—यह काम केन्द्रीय बैंक या तो स्वयं ही या विधान क कहने पर करने लग गये हैं। इसमें नौ बैंक आफ इंग्लैण्ड का ही सलाह दियाया हुआ है। स्त्रोक के प्थन के अनुसार इनका प्रारम्भ मन् १८५४ में हुआ था। वाल्व में बैंकों के नफ़ा कोष अपने पास रखने के उपरान्त बैंक आफ इंग्लैण्ड के लिये यह काम करना आवश्यक हो गया था। दूसरे केन्द्रीय बैंकों ने भी शीघ्र ही इसे प्रारम्भ कर दिया। बैंकों का यह अनुभव है कि दूसरे बैंकों के पास उनके ऊपर के जो चेक, इत्यादि होते हैं उनकी रकम लगभग उन चेकों, इत्यादि की रकम के बराबर ही होती है जो उनके पास दूसरे बैंकों के ऊपर की होती हैं। हो सकता है कि दिन-प्रतिदिन के हिसाब में यथेष्ट ग्रन्तर हो, किन्तु अन्त में यह बिल्कुल भी नहीं रह जाता। अतः, दिन-प्रतिदिन के हिसाब का निपटारा उनके जो पाते केन्द्रीय बैंक में होते हैं उन्हीं में जमा नाम करके कर दिया जाता है। अब, यदि इससे किसी विशेष बैंक के पाते में उतनी बाकी नहीं रह जाती जितनी विधानतः और चलन के अनुसार रखनी चाहिये तब वह बैंक अपने विलों, इत्यादि पर केन्द्रीय बैंक से श्रृंखला लेकर उसे पूरा कर देता है। यह काम बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। प्रथम तो इससे भिन्न-भिन्न बैंकों के पारस्परिक लेन-देन एक बहुत ही सौधे-सादे ढंग से निपट जाते हैं, अर्थात् केवल उनके खातों में ही लेखे करने पड़ते हैं। दूसरे, इससे इस काम में द्रव्य के प्रयोग की बचत होती है। अन्तिम बात यह है कि देश की बैंकिंग-प्रणाली बहुत ही सुदृढ बन जाती है।

कुछ देशों में जहाँ व्यापारिक बैंकों ने केन्द्रीय बैंकों की सत्थापना के पहिले ही अपने पारस्परिक लेन-देनों के निपटारे के लिये स्वयं ही निकास गृहों में

प्रबन्ध कर लिये थे अथवा जहाँ केन्द्रीय बैंकों ने प्रारम्भ में इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया था, जहाँ पर अब भी स्वतन्त्र निकास-गृह हैं और उनके स्वयं के विधान तथा काम करने के स्थान हैं। किन्तु वहाँ भी केन्द्रीय बैंक एक तो उनके सदस्य हैं ही, साथ ही प्रत्येक निपटारे के बाद उनकी बाकी के निपटारे का भी प्रबन्ध करते हैं। अन्य स्थानों में वह प्रायः निकास-गृह के लिये स्थान देते हैं, उनके काम करने की विधि सम्बन्धी नियम बनाते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं और अन्त में उनकी बाकी के निपटारे का प्रबन्ध भी करते हैं।

इंग्लैण्ड में लन्दन में बैंक आफ इंग्लैण्ड का स्वयं का आफिस है, और साथ ही उन ग्यारह प्रान्तीय शहरों में से जिनमें निकास-गृहों का प्रबन्ध है मातृ में भी उसकी शाखाएँ हैं। तथापि इन सभी स्थानों के निकास-गृह स्वतन्त्र हैं। हाँ, इनकी बाकी का निपटारा अवश्य सभी जगह बैंक आफ इंग्लैण्ड द्वारा किया जाता है। लन्दन में जहाँ उसका आफिस है और सातों प्रान्तीय शहरों में जहाँ उसकी शाखाएँ हैं, यह निपटारा उक्त आफिस और उसकी शाखाओं के ऊपर जैसा हो चेके काट करके किया जाता है। किन्तु उन चार शहरों में जहाँ उसका कोई आफिस अथवा उसकी कोई शाखा नहीं है यह उन बैंकों के लन्दन स्थित प्रधान आफिसों के बीच में उनके जो खाते बैंक आफ इंग्लैण्ड के लन्दन के आफिस में हैं, उन्हीं पर चेक काट करके उसी तरह से होता है, जिस तरह से यह लन्दन के निकास-गृह की बाकी के सम्बन्ध में होता है।

भारतवर्ष में रिजर्व बैंक की स्थापना के पहिले भी यहाँ के मुख्य-मुख्य स्थानों में स्वतन्त्र निकास-गृह थे और उनमें कार्य संचालन का अधिकार स्वाभाविक रूप से ही इम्पेरियल बैंक को था जो इस सम्बन्ध के सारे काम सब सदस्यों की ओर से करता था। यद्यपि रिजर्व बैंक विधान की ५८ (क) धारा के अनुसार उसे निकास-गृहों के सम्बन्ध के नियम बनाने के अधिकार हैं, तो भी उसने अभी तक इस विषय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा है और पूर्वोक्त निकास-गृह पहिले की तरह स्वतन्त्र रूप से अपना कार्य करते आ रहे हैं। हाँ, उनमें से कुछ के कार्य संचालन का अधिकार अवश्य इसने ले लिया है, किन्तु कलकत्ता और कानपुर जैसे दो स्थान आज भी ऐसे हैं जहाँ क्रमशः इसके आफिस और इसकी शाखा होने पर भी इसने इस सम्बन्ध के कार्य-संचालन का कार्य दूसरों के ऊपर ही छोड़ रखा है।

कलकत्ते में तो यह काम क्रियविग बैंक एसोसियेशन की साधारण कमेटी द्वारा नियुक्त एक निरीक्षक के माध्यम से है और कानपुर में यही इम्पीरियल बैंक के माध्यम से है। किन्तु इन सभी स्थानों पर जब बैंक अपनी बाकी का निपटारा उनके गिर्ज्य बैंक में तो बात है उन्हीं के ऊपर चैक काटकर करने हैं। कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ न तो रिजर्व बैंक के प्राप्ति हैं और न उनकी शाखाएँ हैं। अतः, यहाँ इम्पीरियल बैंक न केवल निरास-रह सम्बन्धी कार्यों का संचालन ही करता है बल्कि उसकी बाकी का भी निपटारा करता है।

(८) व्यापार की प्राप्ति का अनुसार और सरकार द्वारा निर्वाहित द्रव्य प्रणाली विवरणों के उद्देश्य से मान का नियन्त्रण करना - वास्तव में केन्द्रीय बैंकों का यह कार्य अन्य उन कार्यों को तुलना में सबसे महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में गा ने कहा है "किसी केन्द्रीय बैंक का एक मात्र वास्तविक और सबसे महत्वपूर्ण काम मान नियन्त्रण है।" इसका एक मात्र कारण ही है कि आधुनिक काल में सब प्रकार के द्रव्य-सम्बन्धी और व्यापार-सम्बन्धी लेन-देनों के निरादारे में मान का ही भाग सबसे प्रमुख हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में ६० प्रतिशत भुगतान मुद्राओं और नोटों द्वारा न किये जाकर चेकों द्वारा किये जाते हैं। ऐसा होने के कारण साख अचूक और सुरे दोनों के लिये कार्यका में लाई जा सकती है, अतः, देश के हित के लिये इसका नियन्त्रण बहुत ही प्राप्ति हो गया है। इसके अतिरिक्त मान चालू करने और ठप्पे पारिस करने का काम वास्तविक रूप में बैंकिंग के व्यवसाय के अन्तर्गत आने के कारण उसका नियन्त्रण भी राज्य के किसी विभाग द्वारा किये जाने की अपेक्षाकृत किसी बैंक द्वारा ही किया जाना चाहिये और यह बहुत से बैंकों की अपेक्षाकृत एक ही बैंक द्वारा बहुत ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जहाँ तक इस नियन्त्रण के उद्देश्य का प्रश्न है इस नियम में बहुत मतभेद है। इसका चालू और जो कुछ ही दिनों के पहिले तक मुख्य उद्देश्य था वह विनिमय दर स्थिर रखने का था। हमारे देश में तो यह उद्देश्य बराबर ब्रिटिश राज्य के अन्त तक रहा। किन्तु विनिमय दर की स्थिरता के यह आवश्यक अर्थ नहीं है कि चीजों के मूल्य भी स्थिर रहेंगे। प्रायः उनमें बहुत घट-बढ़ होती रहती है। यदि हम यह बात भूलो भोंवि सोचें तो हमें यह विदित हो जायगा कि विनिमय दर की स्थिरता की अपेक्षाकृत चीजों के मूल्य की स्थिरता कहीं अधिक वाछनीय है। यह तो सभी जानते हैं कि मूल्य परिवर्तन से बहुत

से परिवर्तन हो जाते हैं और आधुनिक आर्थिक संगठन बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है तथा उससे जो बेतरतीबी फैल जाती है उसके आर्थिक और सामाजिक फल बहुत बुरे होते हैं। फिर विनिमय स्थिरता को अत्यधिक महत्व देने वाले देश प्रायः किसी एक बड़े देश के अथवा कई मुख्य देशों के आश्रित हो जाते हैं। जब से भारतवर्ष ने स्टर्लिंग विनिमय मान अपनाया था तब से इस देश में भी यही हो रहा था। इसकी द्रव्य-सम्बन्धी नीति बराबर इंग्लैण्ड की द्रव्य-सम्बन्धी नीति पर ही आश्रित रही है। इन देशों की आर्थिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होने के कारण भारतवर्ष के लिये यह बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ है। विनिमय अथवा मूल्य की स्थिरता का उद्देश्य छोड़कर साख नियन्त्रण का एक उद्देश्य व्यापारिक चक्र (Business cycles) से रक्षा करना अथवा उसे बिल्कुल दूर करना भी है। अब धीरे धीरे लोगों का यह विश्वास होता जा रहा है कि साख नियन्त्रण का सबसे मुख्य उद्देश्य व्यापारिक कार्यों की साधारण एव बराबर उन्नति करना और अत्यधिक तेजी तथा मन्दी रोकना ही है।

जहाँ तक साख नियन्त्रण के तरीकों का प्रश्न है भिन्न-भिन्न केन्द्रीय बैंकों ने भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न तरीकों का प्रयोग किया है। और कभी-कभी तो उन्हें एक ही अवसर पर साथ-साथ ही कई तरीकों का प्रयोग करना पड़ा है। इनमें से बैंक दर नीति (Bank rate policy) और बाजार में खुले तौर पर सौदा करने की प्रणाली (Open-Market Operation) बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं। किन्तु हम इनका विस्तृत अध्ययन अगले अध्याय में ही करेंगे। हाँ, किसी देश में उसका केन्द्रीय बैंक साख नियन्त्रण में कहाँ तक सफल हो सकता है यह भी बहुत सी बातों पर निर्भर है। पहिले तो यह उसके द्रव्य बाजार की उन्नति के स्तर और उसके और केन्द्रीय बैंक के पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर है। अधिकांश देशों में द्रव्य के सुसंगठित बाजार हैं ही नहीं। हमारे ही देश में द्रव्य के दो बाजार हैं—एक देशी और दूसरा आधुनिक—तथा इन दोनों में कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। देशी बाजार आधुनिक बाजार की बहुत कम सहायता लेता है, और इसी प्रकार आधुनिक बाजार भी देश के केन्द्रीय बैंक की बहुत कम सहायता लेता है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि व्यापारिक बैंकों में से कितने बैंक केन्द्रीय बैंक के सदस्य हैं। तीसरे, उनके और केन्द्रीय बैंक के बीच में कैसा सहयोग है, और अन्तिम यह कि केन्द्रीय बैंक का व्यापारिक बैंकों पर तथा अन्य अर्थ से सम्बन्धित समस्याओं पर कैसा प्रभाव है। ये भिन्न-भिन्न देशों में

मित्र-मित्र हैं। हाँ, केन्द्रीय बैंक हम उद्देश्य से एक राय में नीति पर चलकर स्थिति को प्रबल ही सुधार मंगते हैं।

केन्द्रीय बैंकों का सरकार से सम्बन्ध

केन्द्रीय बैंकों के दो कार्य हैं उनके महत्व के कारण हमें उनके और सरकार के बीच के सम्बन्ध का भी अध्ययन अवश्य ही कर लेना चाहिये। प्रायः सभी देशों की सरकारों ने अपने-अपने मुख्य बैंकों के कार्यों में किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करना आवश्यक समझा है। उन्नीसवीं शताब्दी में तो यह बात विधान में ही स्पष्ट कर देने का चलन हो गया था। किन्तु प्रथम युद्ध के समय सरकार के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण उनसे जो जनता का अहित हो गया था, उसके कारण कुछ दया बटल गई थी। सन् १९२० में ब्रूमेल्ल फान्मेन्स ने जो यह निश्चय किया था कि बैंकों और विशेषकर नोट चलाने-वाले बैंकों पर उनकी सरकार का कोई दबाव नहीं रहना चाहिये और उन्हें अर्थ-सम्बन्धी मामलों में दूरदर्शी नीति पालन करनी चाहिये वह उस समय के जनमत का द्योतक है। किन्तु बहुत से स्पष्ट कारणों से अफ्रीका देशों में यह बात मान ली गई है कि प्रत्येक केन्द्रीय बैंक के संचालक मण्डल की रचना में उसकी सरकार का हाथ अवश्य रहना चाहिये और इससे तो उनका राष्ट्रीयकरण भी हो रहा है।

प्रथम तो कुछ ऐसे केन्द्रीय बैंक हैं जिनकी सारी पूँजी उनकी सरकार द्वारा ही प्राप्त हुई है, अथवा वह सरकार की और व्यापारिक बैंकों की, तथा लोगों की सम्मिलित पूँजी है। भारतवर्ष के रिजर्व बैंक की पूँजी के स्वामित्व के सम्बन्ध में सन् १९२७ ही में एक बड़ा गहरा मतभेद उत्पन्न हो गया था किन्तु अन्त में जब इसकी स्थापना हुई थी उसके पहिले ही बात पूर्णतया मान ली गई थी कि वह जनता के लोगों की निजी पूँजी ही होनी चाहिये। किन्तु अभी हाल ही में सरकार ने फिर इसके सब हिस्से स्वयं ही खरीद लिये हैं। इस सम्बन्ध में यह भी कह देना आवश्यक है कि सरकार के स्वामित्व का इस समय कोई विशेष महत्त्व नहीं है क्योंकि वह अब इसके बिना भी अनेक प्रकार से अपने-अपने केन्द्रीय बैंकों पर अपना नियन्त्रण रख सकती है। दूसरे, उनके प्रधान कार्यकर्ताओं की नियुक्ति भी सरकार द्वारा स्वयं ही, अथवा उनके संचालक मण्डल की मन्त्रणा से अथवा व्यवस्थापक सभाओं की स्वीकृति से की जाती है। यदि सरकार अपने यहाँ के

बैंक की पूँजी एकत्रित करने में कोई भी हिस्सा नहीं बँटाती है तो भी इसके यह अर्थ नहीं हैं कि वह उनके सचालकों की नियुक्ति में भी हिस्सा नहीं बँटा सकती है। कुछ देशों में उनकी सरकारों को उनके केन्द्रीय बैंकों की पूँजी में हिस्सा न भी बँटाने पर उनके सचालकों की नियुक्ति में ऐसा करने का अधिकार है। भारतवर्ष में भी रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पहिले ऐसा ही था।

प्रश्न

(१) 'केन्द्रीय बैंकिंग ने केवल इसी गतावृत्ति में ही एक विशिष्ट व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है।' उपरोक्त कथन पर अपना मत दीजिये।

(२) केन्द्रीय बैंकिंग के प्रायः कौन-कौन से काम हैं ? क्या यह आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक साधारणतः व्यापारिक बैंकों के कार्य न करे ?

(३) नोट चलाने के एकाधिकार अथवा शेषाधिकार से आप क्या समझते हैं ? ससार के मुख्य-मुख्य केन्द्रीय बैंकों ने यह अधिकार कब प्राप्त किये हैं ? इस अधिकार के कौन-कौन से लाभ हैं ?

(४) नोट चलाने का नियन्त्रण करने के लिये कौन-कौन से तरीके हैं ? उसमें से प्रत्येक के विषय में उदाहरण के साथ बताइये।

(५) 'सरकार' के बैंकर' के क्या अर्थ हैं ? क्या केन्द्रीय बैंक अपनी सरकार को ऋण दे सकते हैं ? उदाहरण देकर बताइये कि इस सम्बन्ध के बन्धेज किस प्रकार से बारम्बार तोड़े गये हैं।

(६) यह बतलाइये कि रिजर्व बैंक देश की सरकार को कहाँ तक आर्थिक सहायता दे सकती है।

(७) केन्द्रीय बैंक किन-किन तरीकों-से व्यापारिक बैंकों के नकद कोष रखते हैं ? इस कार्य से कौन-कौन सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं।

(८) राष्ट्र का धात्विक कोष प्रायः किस रूप में उसके केन्द्रीय बैंक के पास रहता है ? वास्तविक रकम किस बात पर निर्भर रहती है ? अपने उत्तर के सम्बन्ध में कुछ उदाहरण दीजिये।

(६) बिलों पर छूट देने और जब कभी छुट न मिले तब छुट देने का दायित्व स्वीकार करने में क्या सम्बन्ध है ? यह बताइये कि उसके बाद बाणें कार्य की किस प्रकार और-धरि उन्नति हुई हैं। भारतवर्ष के रिजर्व बैंक की इस सम्बन्ध में क्या नीति है ?

(१०) निजाम-गृह का क्या सिद्धान्त है ? उनसे कौन-कौन से लाभ हैं ? इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बैंकों का क्या भाग रहता है ? अपने उत्तर में भारतवर्ष और इंग्लैण्ड के उदाहरण दीजिये।

(११) केन्द्रीय बैंक द्वारा मास नियन्त्रण में आप क्या समझते हैं ? इसका क्या उद्देश्य होता चाहिये ? उसे करने के दो मुख्य तरीके बताइये।

(१२) किसी केन्द्रीय बैंक का उसकी सरकार से प्रायः क्या सम्बन्ध रहता है ? अपने उत्तर के सम्बन्ध में उदाहरण दीजिये।

अध्याय ७

केन्द्रीय बैंकिंग (२)

सन् १९१४-१८ के महायुद्ध के पहिले मुख्यतः बैंक दर नीति ही के द्वारा साख नियन्त्रण किया जाता था।

१. बैंक दर

बैंक दर का अर्थ—बैंक दर वह दर है जिस पर कोई केन्द्रीय बैंक सर्वाच्च कोटि के बिल फिर से डिस्काउण्ट (Rediscount) करने के लिये तैयार रहता है। यह हर सप्ताह में एक विशेष दिन बैंक मचालकों की एक विशेष बैठक में निश्चित किया जाता है और फिर घोषित कर दिया जाता है। जहाँ तक होता है यह एक बार निश्चित हो जाने पर फिर एक सप्ताह के अन्दर नहीं बदला जाता। आजकल यह वह दर भी है जिस पर कोई केन्द्रीय बैंक अपने सदस्य बैंकों को उनकी सर्वोच्च कोटि की जमानतों को दिना पर छूट देने के लिये भी तैयार रहता है। यह परिवर्तन केवल इसीलिये हुआ है कि इधर बिलों की बहुत कमी हो गई है और सरकारी साख-पत्र तथा बिल बहुत बढ़ गये हैं। यह बिलों की कमी कई कारणों से हुई है जिनमें से मुख्य तो यह है कि इधर

व्यापारिक बैंक प्रायः अपने ग्राहकों को उनके द्वारा जमा की हुई रकम से कहीं अधिक रकम निकालने की आशा, अधिविक्रय (Overdraft), नकद साख (Cash Credit) तथा जमानती ऋण (Collateral Loans) देने लगे हैं। इसके अलावा पहिले द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के सम्बन्ध में भी विलों का प्रयोग होता था, किन्तु अब ऐसा नहीं है। व्यापारिक बैंकों की सख्या बढ़ती जा रही है और वह यह कार्य अधिकाधिक अपने बैंक ड्राफ्टों द्वारा करते हैं। यह लन्दन में भी हो रहा है और अन्य स्थानों में भी हो रहा है। इसके अलावा प्रथम महायुद्ध के पहिले लन्दन के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान का केन्द्र होने के कारण वहाँ पर अनेक विदेशी विल डिस्काउण्ट होने के लिये आते थे। किन्तु उसके बाद से अन्य स्थान भी अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के केन्द्र बन गये हैं, जिससे विल डिस्काउण्ट होने का कार्य उनके बीच में बँट गया है। साथ ही सरक्षण की नीति चालू हो जाने के कारण, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कमी हो गई है जिससे यह विल भी अब उतने नहीं निकलते जितने पहिले निकलते थे। इसके विपरीत सरकारी साख-पत्रों और विलों का प्रयोग विभिन्न सरकारों के ऋण के परिणाम में वृद्धि हो जाने के कारण बहुत बढ़ गया है। यह ऋण परिणाम की वृद्धि प्रथम और द्वितीय महायुद्ध की और उनके बीच के समय की कठिनाइयों दूर करने के हेतु हो चुकी है।

साख नियन्त्रण में बैंक दर का प्रयोग—साख नियन्त्रण में बैंक दर का प्रयोग पहिले-पहिले बैंक आफ इंग्लैण्ड ने सन् १८३६ में किया था। इसके पहिले बैंक दर ४ अथवा ५ प्रतिशत रहती थी। यदि बाजार की दर ४ प्रतिशत से नीचे गिर जाती थी तो बैंक अपनी दर चार प्रतिशत से कम नहीं करता था। इसका अर्थ यह होता था कि उसके पास डिस्काउण्ट कराने के लिये विल आना रुक जाता था। बैंक को अपनी दर ५ प्रतिशत से अधिक बढ़ाने का भी अधिकार नहीं था। बात यह थी कि उस समय वहाँ पर अन्य व्याज के विरुद्ध एक विधान (Usury Law) था। तीन महीनों तक की अवधि पर के विलों के लिये सन् १८३३ में इसका बन्धन हटा दिया गया था। इसके कुछ वर्ष बाद ही यह हर अवधि के विलों पर के लिये हटा दिया गया। किन्तु इसके यह अर्थ नहीं है कि बैंक आफ इंग्लैण्ड सन् १८३६ के पहिले साख-नियन्त्रण के लिये कुछ नहीं करता था। वह दूसरे तरीके प्रयोग में लाता था। एक तो वह हर प्रार्थी के ऋण की

रकम सीमित करने का एक तरफ से राजन बांध देता था। दूसरे का मिल वह डिस्काउंट करने के लिये तैयार करता था उनको अवधि कम कर देता था। मन् १८३६ में बैंक दर पहिले तो ५२ प्रतिशत और फिर ६ प्रतिशत कर दी गई। किन्तु इसके साथ ही जो मिल वह डिस्काउंट करने के लिये तैयार करता था उसकी अवधि भी उसने ६५ दिन से घटाकर ३० दिन कर दिया था। किन्तु साव नियन्त्रण के लिये बैंक दर नीति का अविवेक प्रयोग केवल मन् १८४४ के ११ विधान पास हो जाने के बाद ही होना प्रारम्भ हुआ और जैसे-जैसे बैंक ने और कहीं घृण न मिलने पर स्वयं श्रुण देने का दायित्व स्वीकार कर लिया जैसे-जैसे यह दायित्व निरादने के लिये उसे साव-नियन्त्रण के पहिले वाले तरीके छोड़ने पड़े। मन् १८४७ में जब एक संकट का समय (Crisis) उपस्थित हुआ तब बैंक को साव-नियन्त्रण की इस नई नीति की परीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ। किन्तु पहिले तो उसने कुछ नहीं किया और चुपचाप बैठा रहा और बाद में जब उसने वह नीति अपनाते का प्रयत्न किया तब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। अतः सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसने मन् १८४४ के विधान का वह भाग कुछ दिनों के लिये रद्द कर दिया जिसके द्वारा बैंक एक निश्चित रकम छोड़ कर अन्य के नोट गत-प्रतिशत स्वर्ण रखे बिना नहीं चालू कर सकता था। किन्तु इसके प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी। केवल इसके पास कर देने से ही नकट टल गया। मन् १८५७ और १८६६ के संकट काल के समय भी इसने शीघ्रता नहीं की, और अपनी दर उस समय न बढ़ाकर जब साव की अत्यधिक बाढ़ हो रही थी केवल उसी समय ही बढ़ाई जब देश से स्वर्ण निर्यात होने लगा। अतः इन दोनों अवसरों पर भी मन् १८४४ के विधान के जिस भाग का ऊपर संकेत किया गया है उसे रद्द करने के लिये प्रयत्न करना पड़ा और मन् १८५७ के संकट के समय इसे प्रयोग में भी लाना पड़ा। हाँ, मन् १८७३ में जब इसे एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा तब इसने शीघ्रता की और उससे इसे सफलता भी मिली। इसके बाद अन्य अवसरों पर भी इसने यही किया और उनमें भी यह सफल रहा। मन् १८६० में एक तरफ तो इसने अपनी दर बढ़ाकर साव का अत्यधिक फैलाव रोका और दूसरी तरफ अन्य अंग्रेजी बैंकों और अर्थ सम्बन्धी संस्थाओं के सहयोग से वारिंग ब्रदर्स के जो फेल हो चुके थे, उनके पकने पर देने का विश्वास दिलाया। इसने न केवल जनता का भय दूर हो गया बल्कि बैंक की मर्यादा भी काफी बढ़ी। किन्तु धीरे-धीरे

साख-नियन्त्रण के अन्य तरीके भी प्रयोग में आने लगे जैसे लन्दन बाजार में उधार लेना, किसी हद तक स्वर्ण के क्रय-विक्रय के अपने दर बढ़ाना और घटाना तथा फ्रांस और रूस में साख का प्रवन्व करना और उसे स्वीकार करना। तथापि प्रथम महायुद्ध के पहिले और विशेषतः सन् १८४४ के विधान पास हो जाने के बाद तक साख-नियन्त्रण का मुख्य तरीका बैंक दर नीति ही रहा। कहना न होगा कि अन्य केन्द्रीय बैंकों ने भी बैंक आफ इंग्लैण्ड के नियन्त्रण सबधी अनुभव से लाभ उठाया किन्तु इसका और कहीं भी इतने जोर से और इतनी जल्दी-जल्दी प्रयोग नहीं हुआ। लूवेट के कथन के अनुसार जब कि बैंक आफ इंग्लैण्ड ने सन् १८७५ और १९०० के बीच में इसका १६७ बार उपयोग किया, बैंक आफ फ्रांस ने केवल २५ बार और रीश बैंक (जर्मनी के केन्द्रीय बैंक) ने केवल ८४ बार इसका उपयोग किया। इसके कई कारण थे—(१) लन्दन के स्वर्ण का एक स्वतन्त्र बाजार होने के कारण वह विदेशी पूँजी की लागत के लिये बहुत ही उपयुक्त स्थान माना जाता था। अतः, जब कहीं भी गड़बड़ मचती थी और वहाँ की पूँजी लन्दन से निकाली जाती थी तब लन्दन में अवश्य कठिनाई उत्पन्न हो जाती थी। (२) ब्रिटिश साख की रचना की तुलना में इस समय बैंक आफ इंग्लैण्ड का स्वर्ण कोष बहुत ही थोड़ा रहता था। (३) ब्रिटिश पूँजी विदेशों में लगने के कारण ग्रेट ब्रिटेन के बैंकिंग के साधनों पर बराबर बोझ पड़ता रहता था और उसका यह प्रभाव होता था कि कभी-कभी अत्यधिक लागत लग जाती थी तथा उत्पत्ति और व्यापार सीमा उलघन कर जाते थे जिससे सट्टेबाजी बढ़ जाती थी। यह केवल बैंक दर ही बढ़ाकर और कभी-कभी तो अत्यधिक बढ़ाकर ही रोकी जा सकती थी।

बैंक दर नीति साख नियन्त्रण तभी कर सकती है जब केन्द्रीय बैंक के डिस्काउण्ट की दर के परिवर्तन से द्रव्य के अन्य दरों में भी उसी अनुपात से परिवर्तन हो। इंग्लैण्ड में द्रव्य की विभिन्न दरों के बीच में एक बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था। बैंक दर प्रायः बाजार के डिस्काउण्ट दर से कुछ ऊँचा रहा करता था। यह एक प्रकार से दह देनेवाली दर थी। अतः, बाजारवाले बैंक से उसी समय ऋण लेते थे जब उन्हें और कहीं ऋण नहीं मिलता था। साथ ही बैंक का यह सबसे नीचा दर था। इस पर बैंक केवल सर्वोच्च बिल डिस्काउण्ट करने के लिये तैयार रहता था। निम्न भेणी के बिल डिस्काउण्ट

करने के लिये यह और ऊँची दर लगाता था। बैंक समानता पर जो श्रृण देता था उन पर भी इनने १ प्रतिशत ऊँची दर लेता था। बैंक दर के परिवर्तन पर बाजार के डिस्काउन्ट दर में भी परिवर्तन होता था। बैंक मात दिन की सूचना भी जहाँ पर भी प्रमा प्राप्त पत्रों में उस पर जो व्याज देते थे उसकी दर प्रायः एक दर में ११ प्रतिशत कम रहती थी। सन् १९२१ में तो यह अन्तर २ प्रतिशत तक हो गया था; माँग पर वापिस होनेवाले श्रृणों पर भी व्याज दर प्रायः जमा के व्याज दर में १ प्रतिशत अधिक होती थी। फिर, बैंक अन्य श्रृणों के सम्बन्ध में अपने ब्राह्मणों ने जो व्याज लेते थे उसकी दर बैंक दर से प्रायः एक प्रतिशत ऊँची होती थी और कम में कम ५ प्रतिशत अवश्य होती थी। कभी-कभी यह प्रम नहीं चलता था, किन्तु प्रायः यही रहता था। किन्तु अन्य देशों में यह सम्बन्ध इतना निश्चित नहीं रहता था। अतः, यहाँ का बैंक दर नीति साधन-नियन्त्रण में इतनी मजबूत नहीं होती थी। निम्न परिस्थितियों में कोई केन्द्रीय बैंक साधन-नियन्त्रण कर सकता है उनका अध्ययन तो हम पहिले ही कर चुके हैं। और यह भी स्पष्ट है कि इंग्लैण्ड को छोड़कर किसी भी दूसरे देश में वह परिस्थितियाँ सम्पूर्ण रूप में नहीं पाई जाती।

जब सन् १९१४ में फेडरल रिजर्व बैंक ने कार्यारम्भ किया था तब उन्होंने बैंक आफ इंग्लैण्ड के साधन-नियन्त्रण के तरीकों का अवलम्बन करना चाहा था और न्यूयार्क में एक बहुत ही उन्नत द्रव्य बाजार की स्थापना का निरन्तर प्रयत्न किया था। इसमें संदेह नहीं कि वे इसमें बहुत अंशों तक सफल भी हो गये थे। किन्तु उनके यहाँ के बैंक दर और बाजार दरों का सम्बन्ध कुछ भिन्न परिस्थितियों के कारण भिन्न था। ग्रेट ब्रिटेन में बैंक बैंक आफ इंग्लैण्ड से सीधे श्रृण की याचना नहीं करते थे। आवश्यकता के समय वह जो करते थे वह इस प्रकार था कि वे बिल के दलालों से और अन्य श्रृण लेनेवालों से अपने माँग पर वापिस होनेवाले श्रृण माँग लेते थे और साथ ही उनके बिल डिस्काउन्ट करना बन्द कर देते थे। इसका स्वभावतः यह फल होता था कि बाजारवाले बैंक आफ इंग्लैण्ड से सहायता माँगते थे और वह उनसे यथोचित व्यवहार करता था। इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रिजर्व बैंकों के सदस्य बैंक सीधे रिजर्व बैंक के साथ काम करते थे। फिर, जब इंग्लैण्ड में बैंक आफ इंग्लैण्ड से श्रृण प्राप्त करने का सनसे नीचा दर बैंक दर या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह बात नहीं थी। डिस्काउन्ट दर के अतिरिक्त फेडरल

रिजर्व बैंक अन्य बैंकों द्वारा स्वीकृति हुये बिलों के क्रय की एक अन्य दर भी घोषित करते थे जो बिल बाजार की सहायता करने और उन्हें बनाये रखने के उद्देश्य से डिस्काउन्ट दर से नीची और प्रायः बाजार दर के बराबर होती थी। अतः, जब सदस्य बैंक रिजर्व बैंकों से उँचे दर पर अपने व्यापारिक साख-पत्र डिस्काउन्ट कराते थे तब वह बाजारवालों के बैंकरों द्वारा स्वीकृत किये हुये बिल वह नीची दर पर खरीद लेते थे। इसका यह फल होता था कि वहाँ पर साख-नियन्त्रण के लिए बैंक दर नीति उतनी कारगर नहीं होती थी जितनी ग्रेट ब्रिटेन में होती थी। तीसरे, जब से फेडरल रिजर्व बैंक स्थापित हुये हैं तब से वहाँ पर स्वर्ण कोष की बाहुल्यता रही है जिससे वह करन्सी प्रसार के लिये काम में आता रहा था। इन सब कारणों के साथ-साथ कुछ अन्य कारण भी थे, जैसे वहाँ पर सट्टेबाजी की अत्यधिक सुविधा और वहाँ के लोगों का उसके प्रति अत्यधिक भुकाव। फिर, रिजर्व बैंकों को बैंक दर निर्धारित करने की उतनी स्वतन्त्रता भी नहीं है जितनी बैंक ऑफ इंग्लैंड को है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब रिजर्व बैंकों की प्रार्थना पर बोर्ड ने बैंक दर बढ़ाने की अनुमति नहीं प्रदान की।

प्रथम महायुद्ध के काल में और उसके बाद भी अनेक अवसरों पर केन्द्रीय बैंक बैंक दर नीति का पालन केवल इसलिए नहीं कर सके कि उन्हें सरकार की अर्थ-सम्बन्धी आवश्यकताओं का ध्यान रखना था। किन्तु जैसे ही अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान अपना लिया गया और केन्द्रीय बैंक अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिये मुक्त हो गए वैसे ही साख-नियन्त्रण के लिये बैंक दर नीति का फिर से अधिकाधिक प्रयोग होने लगा। हाँ, साख नियन्त्रण के अन्य तरीकों जैसे बाजार में खुले तौर पर काम करना अपना नैतिक प्रभाव डालना, इत्यादि की अपेक्षाकृत इसका प्रयोग घटता गया। हम यह बात तो देख चुके हैं कि बिलों की कमी क्यों पड़ने लगी थी और केन्द्रीय बैंक उनके स्थान पर सरकारी बिलों और साख पत्रों की जमानत पर ऋण देने में बैंक दर का किस प्रकार प्रयोग करने लगे थे। किन्तु इससे अधिक लाभ नहीं हुआ क्योंकि कुछ अन्य परिस्थितियों में भी परिवर्तन हो चुका था और हो रहा था। एक तो द्रव्य के जितने मुख्य बाजार थे वह सब द्रवित अवस्था में थे। बात यह थी कि उनके यहाँ के केन्द्रीय बैंकों में अथवा सरकार के विनिमय सम्बन्धी खातों में इस समय काफी स्वर्ण कोष था, अतः, उसी से उसके यहाँ करन्सी का काफी प्रसार भी था। दूसरे, सरकारी बिलों की रकम बढ़ जाने के कारण इस समय

केन्द्रीय बैंकों की अपेक्षाकृत सस्तर का प्रभाव बाजार पर कहीं अधिक था। अन्तिम बात यह है कि जब से स्वर्णमान सारे सगर भर से हट गया है तब से उसके स्थान पर कृत्रिम कम्पन्डी मान चल रहा है। साथ ही प्राजकल अधिकांश देशों में स्वाभाविक तौर पर काम करने के स्थान में योजनाओं के अनुसार काम हो रहा है जिसमें मूल्य में, मालदूरी के दर में, उत्पत्ति में और व्यापार में द्रव्य की दूरी के और साथ ही स्थितियों के परिवर्तन के माध्य-माध्य योजना के अनुसार ही परिवर्तन हो गाने हैं। वेल्बैन का न्यून है कि बैंक दर नीति उसी आर्थिक संगठन में माल हो सकती है जिसमें मूल्य, मालदूरी और व्यापार प्रायः आवश्यकता के अनुसार स्वाभाविक तौर पर ही कृत्रिम तरीकों से योजना के अनुसार नहीं बदलते रहते। किन्तु कृत्रिम कम्पन्डी और योजनाओं की प्रणाली के अन्तर्ग ऐसा नहीं होता। परन्तु, इन परिस्थितियों में बैंक दर नीति का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

किन्तु प्रायः सभी केन्द्रीय बैंक हर सप्ताह में अपने-अपने बैंक दर अन्न भी घोषित करते हैं। अधिस्तरी तो उनके विधानों में ही यह दिया हुआ है कि उन्हें अपना बैंक दर निश्चित और घोषित करना पड़ेगा। इससे बैंक दर के अन्न भी महत्वपूर्ण होने का पता लगता है। पहिले तो इससे यह मालूम हो जाता है कि केन्द्रीय बैंक कुछ विशेष प्रकार के साधनों की समानता पर किस दर से अन्न देने के लिये तैयार हैं। दूसरे, यह इस बात का भी द्योतक है कि अन्न साधारणतः किस दर पर प्राप्त हो सकता है। तीसरे, इससे यह भी पता लगता है कि केन्द्रीय बैंक का देश की साधन की स्थिति के विषय में क्या मत है। कभी कभी तो इससे यहाँ की साधारण आर्थिक स्थिति के विषय में भी बैंक के मत का पता चलता रहता है। निम्न के शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि बैंक दर की वृद्धि आर्थिक स्थिति के विकृत रूप की चेतावनी देती है। एडिस के कथनानुसार^१ यह व्यापारियों के लिये भयसूचक लाल रोशनी

^१ 'A rise in Bank rate may be regarded as the amber coloured light of warning of a robot system of finance and economics'—Gibson

^२ 'A rise in Bank rate is a danger signal, the red light warning to the business community of rocks ahead on the course in which they are engaged. A fall in it on the other hand may be looked upon as the green light indicating that the coast is clear and that the ship of commerce may proceed on her way with caution'—Addis

का काम करती है और उन्हें इस बात की चेतावनी देती है कि आगे चलकर उनके ठोकर खाकर गिर जाने की सम्भावना है। इसके विपरीत इसकी कमी हरी रोशनी की द्योतक है जो यह बतलाती है कि रास्ता बिल्कुल साफ है और व्यापार रूपी पोत सावधानी के साथ आगे बढ़ सकता है।

२. साख-नियंत्रण के लिये बाजार में खुले तौर पर काम करना

(Open market operations)—यह तो पहिले ही बतलाया जा चुका है कि बैंक आफ इंग्लैण्ड साख-नियन्त्रण के सम्बन्ध में बैंक दर नीति के साथ-साथ अन्य कई तरीकों का प्रयोग प्रथम महायुद्ध के और उसके बाद के साल के बहुत पहिले से ही करता आ रहा था। अब, इन सब में से बाजार में खुले तौर पर काम करने की नीति (Open market policy) ही धीरे-धीरे विशेष तौर पर प्रधानता प्राप्त करती गई—यहाँ तक कि आजकल यह बैंक दर नीति के सहायक रूप में न रहकर स्वयं ही एक स्वतन्त्र नीति से प्रयोग में आने लगी है। इस नीति के यह अर्थ हैं कि केन्द्रीय बैंक स्वयं ही बाजार में प्रत्यक्ष रूप से उन सब साख-पत्रों का क्रय और बिक्रय करने लगे जिन्हें वह साधारण तौर पर लेता और बेचता है, चाहे वह सरकारी साख-पत्र हों अथवा जनता के दूसरे साख-पत्र हों, अथवा बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये विल हों अथवा व्यापारियों के विल हों। लेकिन चलन यही है कि बैंक केवल सरकारी साख-पत्र ही लेते और बेचते हैं। हाँ, वह दीर्घकालीन और लघुकालीन दोनों होते हैं। जनता के दूसरे साख-पत्र वह कुछ स्पष्ट कारणों से नहीं छूते। वास्तव में यह सम्भव भी केवल इसीलिये हो सका है कि आजकल की सरकारों ने बहुत से ऋण ले रखे हैं। यह दीर्घकालीन और लघुकालीन दोनों प्रकार के हैं। ऐसा करने में बैंक अपनी तरफ से बाजार में काम करता है, बाजार के लोग उसके पास स्वयं नहीं जाते। उन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बैंक को देश के हित में ऐसा करना आवश्यक मालूम होता है।

किन्तु इस नीति का प्रभाव केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही पड़ सकता है। प्रथम तो यह आवश्यक है कि देश की बैंकिंग की प्रणाली बहुत ही उन्नत अवस्था को पहुँच गई हो, अर्थात् लोग अपनी बचत की रकम अपने पास न रखकर बैंकों में ही रखते हों। यदि ऐसा नहीं होता तो जब केन्द्रीय बैंक साख-पत्र बेचने लगता है तब उन्हें लोग अपने पास की रकमों

ने गरीब लेते हैं जिन्होंने तो के ऊपर मोड़ प्रभाव नहीं पड़ता। किन्तु जब उनकी बचत बैरों में जमा रहती है तब केन्द्रीय बैंक द्वारा बेचे गये साख-पत्र गरीबों के लिये लोग धँसाते अथवा स्वयं निकालते हैं और बैरों के नकद कोष में इन प्रयोग से कमी आ जाने पर उनकी मांग उत्पन्न शक्ति में भी कमी आ जाती है। यही साख नियन्त्रण है। यह साख-नियन्त्रण जब समय भी नहीं हो पाता जब विदेशी लोग केन्द्रीय बैंक द्वारा बेचे हुये साख-पत्र गरीब लेते हैं। दूसरे, बैंकों के नकद कोष में वृद्धि होने और कमी पड़ने पर उनकी साख उत्पादन शक्ति पर भी प्रभाव पड़ना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता तो साख नियन्त्रण नहीं किया जा सकता। प्रमुखा ऐसा होता है कि नकद की वृद्धि पर भी व्यापारिक बैंक साख नहीं बढ़ाते। तीसरे, इसमें केवल यही प्रश्न नहीं है कि व्यापारिक बैंक केन्द्रीय बैंक की लक्ष्य पूर्ति के लिये तैयार हो, बल्कि यह भी प्रश्न है कि कुछ मादमी लोग काम चलाने के उद्देश्य से अणु लें और उनका इतना विश्वास हो अथवा उनके पास इस तरह की जमानत हो कि जिस पर बैंक उन्हें उधार दे सके। यदि यह दोनों बातें नहीं हैं तो बैंकों की इच्छा रहने पर भी साख प्रदान नहीं हो सकता। इसी तरह से यदि काम करने वालों को व्यापार और मष्टे में लाभ दिलाने पड़ता है तो बैंक प्रयत्न करने पर भी शायद साख की माँग में कमी नहीं कर सकते। अन्तिम बात यह है कि बैंकों की जमा की चाल (Deposit velocity) में भी कोई परिवर्तन न हो। व्यापारिक तौर पर जो व्यापार की वृद्धि से इसमें वृद्धि और उनकी मदी ने इसमें मन्दी हो जाती है। किन्तु सब बातों तो यह है कि उपर्युक्त में से कोई भी बात पूरी तौर से किसी देश में भी नहीं मिलती। लेकिन माधारणतया आचार में खुले तौर पर काम करने को यह नीति मुख्य-मुख्य देशों में अपना प्रभाव अग्रसर रहती है। इसका महत्त्व यह है कि यह बैंकों के नकद कोष में अथवा घटा देती है और इन परिवर्तनों से द्रव्य की दरों और साख की स्थितियों में भी परिवर्तन हो जाते हैं जिससे मूल्य और व्यापारिक स्थितियों में भी आवश्यक उलट-फेर हो जाते हैं। हाँ, यदि कहीं कोई रुकावट पड़ जाती है तो अवश्य इच्छित प्रभाव नहीं पड़ता।

जहाँ तक लन्दन का प्रश्न है वहाँ के किंग नामक एक बैंक अध्यक्षाली ने यह कहा है कि बैंक आफ इंग्लैण्ड अपने प्रत्यक्ष काम से वहाँ का नकद कोष घटा-बढ़ाकर वहाँ के बैंकों की जमा प्रसार और संकुचन बढ़े जोरो से और जान-बूझकर कर सकता है और करता है तथा इसी तरह साख नियन्त्रण

में सफल होता है। एम० एच० डी काक ने बैंक आफ इंग्लैण्ड की इस नीति के लक्ष्य के विषय में निम्न बातें बतलाई हैं :—

(१) बैंक दर का प्रभाव उत्पन्न करना अथवा बैंक दर में परिवर्तन करने के लिये स्थिति पैदा कर देना ।

(२) सरकारी द्रव्य की अथवा ऋतु सम्बन्धी गति विधि से द्रव्य बाजारों में जो हलचल पैदा हो जाती है, उसे रोकना ।

(३) स्वर्ण निर्यात और आयात रोकना ।

(४) नये ऋण निकालने और पुराने ऋण नये ऋणों में बदलने की अवस्था में सरकारी साख की रक्षा करना ।

(५) व्यापार के पुनर्निर्माण में सहायता पहुँचाने के लक्ष्य सस्ते द्रव्य की स्थितियाँ उत्पन्न करना और उन्हें बनाये रखना ।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंकों की भी खुले तौर पर बाजार में काम करने की नीति के लक्ष्य के विषय में यही कहा जा सकता है। हाँ, उनके कामों में और उनके इस पर जोर देने तथा इसे करने के स्तर (Standard) में अवश्य कुछ विशेष अन्तर है।

भारतवर्ष के रिजर्व बैंक को भी आवश्यकता पड़ने पर इस नीति का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है, और साथ ही जहाँ तक सम्भव हो सका है उन परिस्थितियों को भी उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है जिनसे इसका यथेष्ट प्रभाव पड़ सकता है। किंतु अभी तक कोई ऐसा अवसर नहीं आया जब वह यह नीति प्रयोग में लाया हो।

साख नियन्त्रण के अन्य तरीकों का प्रयोग

साख नियन्त्रण के अन्य तरीकों में से कुछ का सकेत तो हम बैंक दर नीति के सम्बन्ध में ही कर चुके हैं। वहाँ पर यह भी बतलाया जा चुका है कि सन् १८३६ के पहिले बैंक आफ इंग्लैण्ड (१) प्रत्येक प्रार्थी के ऋण की रकम बाँध करके साख की राशनिंग कर दिया करता था, और (२) जिन विलों का डिस्काउण्ट करने को तैयार रहता था उनकी अवधि भी घटा देता था। उसने इस वर्ष साख नियन्त्रण के लिये वास्तव में बैंक दर नीति के साथ साथ उपर्युक्त दूसरी नीति भी अपनायी थी और डिस्काउण्ट करनेवाले विलों की अवधि ६५ दिन के स्थान पर केवल ३० दिन ही कर दी थी। उसी सम्बन्ध

मे हम यह भी देख चुके हैं कि बीरे-तोने बैंक ने सात नियंत्रण के अन्य तरीकों का भी प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया था जैसे मदन बाजार में गृह लेना, मर्ग का कय और विक्रय दर एक विशेष सीमा के अंदर रखा देना और प्राप्त तथा रूप से उधार लेना प्रथम स्वीकार करना। इधर शाल में कुछ अन्य तरीकों का भी प्रयोग होने लगा है। किंतु उन सब का अप्रयोजन करने के पहिले हम एक बार भाग की राशनिंग का तरीका फिर से भली-भाँति समझ लेना है। बात यह है कि इधर तानाशाही (Fascist) सरकारों ने राज में भी इसका फायदा प्रयोग किया था। सन्तु में राष्ट्रीय योजनायें कार्यान्वित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो जाता है।

३ भाग की राशनिंग—जर्मनी ने इसका प्रयोग सन् १९२४ में अपने निठ रेंटनमार्क के मूल्य का एक रोकने के लिये किया था। फिर वहाँ पर सन् १९२६ में भी यही प्रयोग में लाई गई थी। उस वर्ष युद्ध योजना के सम्बंध को पेरिस की वार्तालाप के कारण वहाँ से ड्रव्य का निर्यात प्रारम्भ हो गया था जिससे वहाँ की फर्मों की स्थिति बिगड़ने की सम्भावना उत्पन्न हो गई थी। अतः, उसे इसी नीति द्वारा भाग नियंत्रण करके संभाला गया था। सन् १९३१ में भी वहाँ पर सीरा बैंक ने सात का कोटा (Quota) थोड़ा करके बड़े-बड़े बैंकों को फेल होने से बचाया था। रूस में तो यह तरीका वहाँ के सरकारी बैंक की साधारण वार्षिक नीति का प्रायः एक अङ्ग ही बन गया है। कज़नलनबाम (Katzellenbaum) का कथन है कि केन्द्रीय बैंक का दर न तो पूरा सन्तुष्टी कोष की माँग और भरती (Supply) का सूचक है और न उसकी भरती ठीक करता है। जहाँ तक रूस के सरकारी बैंक में जमा होनेवाले कोष का प्रश्न है उसके सम्बंध में वह एक अन्य सिद्धांत के अनुसार चलता है अर्थात् जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है उन्हें वह एक निश्चित योजना के अनुसार देता है और कभी-कभी जब उनकी माँग उसके पास के कोष की अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है तब वह उसे उनके बीच में एक विशेष योजना के अनुसार बाँट देता है। द्वितीय महायुद्ध के काल में प्रजातन्त्र राज्यों में भी इस तरीके का काफी प्रयोग किया गया था।

४ प्रत्यक्ष कार्यवाही करना और नैतिक प्रभाव डालना

(Direct action and moral suasion)—वास्तव में प्रत्यक्ष कार्यवाही करने में नैतिक प्रभाव डालना भी सम्मिलित है। किंतु एम० एच० डी० काक ने इन दोनों के बीच में कुछ अंतर दिखाने का प्रयत्न किया है।

उसके कथन के अनुसार प्रत्यक्ष कार्यवाही करने के अर्थ हैं किसी व्यापारिक बैंक के विरुद्ध कुछ कड़े उपायों का प्रयोग करना और नैतिक प्रभाव डालने के अर्थ हैं उपयुक्त प्रकाश डालकर अपना लक्ष्य सिद्ध करना । इसमें केन्द्रीय बैंक का प्रभाव और उसकी स्थिति समझने की और उसी के अनुसार काम करा लेने की शक्ति का अधिक महत्त्व है । केन्द्रीय बैंकों ने इन तरीकों का प्रयोग किसी न किसी रूप में बैंक दर नीति और बाजार में खुले तौर पर काम करने की नीति अपनाने के साथ-साथ अथवा उनसे पृथक्-पृथक् अनेक बार समय-समय पर किया है । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जब-जब फेड्रल रिजर्व बोर्ड ने बैंक दर में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी और विशेषकर सन् १९२८-२९ में उसने उसके स्थान पर यही तरीके काम में लाने के लिये इशारा किया था । किन्तु क्लार्क के कथनानुसार हम यह कह सकते हैं कि फेड्रल रिजर्व बैंकों को इनके प्रयोग का जो अनुभव हुआ है उससे यह ज्ञात होता है कि यह काफी उपयोगी नहीं सिद्ध हुये, अतः, इनका प्रयोग बहुत ही समझ-बूझ कर करना चाहिये । हाँ, रीश बैंक ने भी प्रायः इनका प्रयोग किया है और वह इसमें फेड्रल रिजर्व बैंकों की अपेक्षाकृत अधिक सफल हुआ है । किन्तु यह केवल इसीलिये हो सका कि उसमें बहुत कड़े उपाय प्रयोग में लाने का भय दिखाया गया था जोकि केवल तानाशाही शासन-प्रणाली ही के अन्तर्गत सम्भव है ।

केन्द्रीय बैंकों में व्यापारिक बैंकों द्वारा रखी जानेवाली न्यूनतम नकदी में परिवर्तन—पाँचवें अध्याय में जब हम व्यापारिक बैंकों के नकद कोष के विषय में अध्ययन कर रहे थे तब हमने यह देखा था कि कुछ देशों में इन बैंकों को चालू जमा और स्थायी जमा का एक निर्धारित अंश अपने यहाँ केन्द्रीय बैंकों में रखना पड़ता है । इधर केन्द्रीय बैंकों ने कभी-कभी यह अंश घटाने बढ़ाने की शक्ति का भी प्रयोग किया है । पहिले-पहिले इसका आविष्कार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सन् १९३३ में हुआ था और फिर इसका संशोधन वहाँ पर सन् १९३५ में किया गया था । इसके सम्बन्ध का जो विधान बना था उसके द्वारा फेड्रल रिजर्व प्रणाली के शासक मण्डल को साख का हानिकारक प्रसार और सकुचन रोकने के लिये सदस्य बैंकों द्वारा उनके पास उनकी जमा का जो अंश जमा किया जाता है उसे घटाने बढ़ाने का अधिकार दे दिया गया है । वस्तुतः इसका प्रयोग वहाँ पर सन् १९३६ के अगस्त में किया गया था । उस वर्ष जमा होनेवाले कोष का अंश पहिले से थोड़ा कम

दिया गया। उस समय शासन मण्डल ने यह पाया था कि इसकी अपेक्षाकृत कि पहिले तो यह अत्यधिक गोर सात जगह के काम में आये और फिर उने मासि लिया गया यह अधिक बढ़कर है। इनके प्रयोग में आने के पहिले ही इसके एक अंश की उपायनर्जात गोर दी जाय। किन्तु मर्या का बसाव पायात होने के कारण बहुत देर के पोंप रक्त नष्ट प्रायः सन् १९३७ के आरम्भ में शासन मण्डल को फिर उनके गोर जमा लिये जानेवाले कोष का अनुमान दो किन्ता न बदलना पड़ा जिसने मदस्य "सो" में आगम्य १९३६ के पहिले जो न्यूनतम गमा रखनी पड़ती थी उसने अरु दुगुनी जमा रखनी पड़ने लगी। परन्तु सन् १९३८ में यह जमा लिये जानेवाले कोष का प्रतिशत नये प्रतिशत से १२३ प्रतिशत कम कर दिया गया। न्यूनीकृत और स्वीडेन ने भी नाट में इस तरीके का प्रयोग किया था।

निगन्दे शासन-नियन्त्रण का यह तरीका बहुत ही अच्छा है किन्तु साथ ही इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। प्रथम तो सर देश के कोष एक साथ तथा एक ही मास में नहीं बढ़ते-गड़ते। अतः, केन्द्रीय बैंकों का उनके यहाँ जमा किये जानेवाले अंश घटा-बढ़ा देने से भिन्न-भिन्न बैंकों पर भिन्न-भिन्न असर पड़ता है। दूसरे, यह तरीका तभी सफल हो सकता है कि जहाँ बाजार में खुले तार पर काम करने की नीति सफल बनाने के लिये तिन परिस्थितियों का होना आवश्यक है वह मा परिस्थितियाँ यह तरीका प्रयोग में लाने के लिये भी मौजूद हों।

६ साख-पत्रों के मूल्य का वह अंश घटाना-बढ़ाना जिसके बराबर उनकी बिना पर ऋण दिये जाते हैं—सन् १९३४ के साख-पत्र विनियम विधान (Securities Exchange Act) द्वारा केन्द्रल रिजर्व प्रणाली को साख नियन्त्रण का एक अन्य तरीका भी बतला दिया गया है, अर्थात् साख-पत्रों के मूल्य का वह अंश घटाना-बढ़ाना जिसके बराबर उसकी बिना पर ऋण दिये जाते हैं। जैसा कि स्पष्ट है इसका उद्देश्य साख-पत्रों की सट्टेबाजी रोकना है। सन् १९३६ में मंडल (Board) ने बैंकों और दलालों के लिये यह आवश्यक कर दिया था कि वह लोग साख पत्रों की जमानत पर अपने ग्राहकों को ऋण देते समय उनके मूल्य की कम से कम ५५ प्रतिशत की ग्युआंरं अपने पक्ष में रख लें। फिर, सन् १९३७ के नवम्बर में यह घटाकर ४० प्रतिशत कर दी गई थी। द्वितीय महायुद्ध के समय यह तरीका कई अन्य देशों में भी प्रयोग में लाया गया था।

7 विज्ञप्ति—सभी केन्द्रीय बैंक समय-समय पर किसी न किसी रूप में आवश्यक कुछ न कुछ विज्ञप्ति करते रहते हैं। किन्तु साख नियन्त्रण के लिये इसका प्रयोग जितना मयुक्त 'राष्ट्र अमेरिका' में हुआ है उतना अन्य किसी भी देश में नहीं हुआ है। ब्रगेस के कथनानुसार फेडरल रिजर्व प्रणाली के अफसरों के वक्तव्यों की साख नियन्त्रण के लिये कभी-कभी तो उतना ही असर पड़ा है जितना कि शायद उनके प्रत्यक्ष दबाव का पड़ता। रीश बैंक ने भी इसका काफी प्रयोग किया है।

केन्द्रीय बैंकों की व्यापारिक चक्र (Business cycles)

रोकने की शक्ति

केन्द्रीय बैंकों के साख नियन्त्रण के कार्य के सम्बन्ध में यह तो पिछले अध्याय में ही बताया जा चुका है कि इसका एक उद्देश्य व्यापारिक चक्र का प्रभाव कम करना अथवा उसे विलकुल रोक देना भी है। साथ ही हम वहीं पर यह भी देख चुके हैं कि ग्राज-कल तो इस साख नियन्त्रण का पहिला उद्देश्य व्यापारिक कार्यों की बराबर स्वाभाविक तौर पर उन्नति करते रहना और तेजी-मन्दी (Booms and slumps) रोकना ही है, अन्य सब बातें तो बाद में आती हैं। अब, यह बात समझने के पहिले कि केन्द्रीय बैंक इसमें कहाँ तक सफल हुए हैं, हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि व्यापारिक चक्र, तेजी और मन्दी (Booms and slumps) के क्या अर्थ हैं। जहाँ तक व्यापारिक चक्र के प्रयोग का प्रश्न है वह इसलिये होने लगा है कि व्यापारिक कार्यों की जो घट-बढ़ होती है वह एक प्रकार से चक्र ही की तरह की है। बैसले मिचेल ने व्यापारिक चक्र की जो परिभाषा दी है वह कुछ इस आशय की है.—यह व्यापारिक कार्यों का एक क्रमिक प्रसार और सकुचन है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि तेजी और मन्दी का परिवर्तन एक सङ्कट के रूप में हो। इसमें दो तेजी की भी अवधि हो सकती है और दो मन्दी की भी अवधि हो सकती है। इसी बिना पर एम० एच० डी० काक इसमें चार

* Business cycle is any single succession of expansion and contraction of business activity, i e between one period of prosperity and another or between one depression, and another, irrespective of whether the transition from prosperity to depression is of the nature of a crisis or merely mild recession—Wesley Mitchell

प्रकाश की गतिविधि सम्मिलित रहता है, अर्थात् उत्थान (Prosperity), वापसी (Recession) कुणव (Depression) और पुनरुत्थान (Revival)। इनमें से उत्थान की अवधि तेजी की अवधि (Boom period) और कुणव की अवधि मंदी की अवधि (Slump period) कहलाती है। तब तब इसके कारणों का प्रश्न है यह द्वय सम्बन्धी (Monetary) और गैर द्वय सम्बन्धी (Non-monetary) दोनों हैं। अतः द्वय सम्बन्धीकरण पूरी तरह से नहीं तो कुछ अंशों में सम्भव ही होके जा सकता है। बावजूद कि उत्थान और प्रकाश के समय के बाद जो वापसी अवस्था सफट का समय आता है वह केवल अत्यधिक सट्टेबाजी के कारण ही आता है। म० १८८०-८१ जी० काव ही के कथन के अनुसार उत्थान के और व्यवसाय की वृद्धि के समय जन-आधारण में साहस और आशा की भावना स्वाभाविक रूप से ही दृष्टिगोचर होने लगती है। ऐसे समय में व्यवसाय में आगामी से लाभ बढ़ाने के लिये व्यापारी समुदाय अपनी विनी और उत्पादन भी बढ़ाता है और उसके लिये बर्बाद की सहायता प्राप्त करना चाहता है। इसका फल यह होता है कि बैंक उत्पादकों और अन्य व्यवसायियों को साह देने हैं और उत्पादक और व्यवसायी भी अच्छी परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपने ग्राहकों को साह देने हैं। अतः, पूँजी की तुलना में व्यवसाय के अनुपात की उपभोग तथा उत्पाद के सामान के उत्पादन और व्यापार के परिमाण की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है और चांगे तरफ तेजी ही तेजी (Boom) दिखाई पड़ने लगती है। अब यह लाभ की वृद्धि या, बढ़ते हुये व्यापार और उत्पादन का, अतिकाधिक सट्टेबाजी का और भूमि, सामान तथा माज-पयों के मूल्योन्वर्ध का क्रम सदा के लिये तो नहीं बढ़ सकता। कभी न कभी तो विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और मिलकुल उल्टा हो जाता है। वास्तव में सट्टा रोकना ही चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि बैंकों के पास जन समुदाय की भावनायें रोकने के साधन तो नहीं हैं किन्तु वह ऐसे साधन का नियन्त्रण करके उनका कार्यान्वित होना तो रोक ही सकते हैं। इसमें वापसी (Recession) भी रुक जाती है। वापसी तथा सफट के क्रम का विश्लेषण करके माट्रक्स ने तीन मुख्य बातें बताई हैं जो निम्नांकित हैं—(१) इसके लिये सट्टे की भावना होनी चाहिये; (२) सट्टे का प्रभाव मूल्य वृद्धि द्वारा दृष्टिगोचर होता है, (३) सट्टा मूल्य को साह वृद्धि द्वारा ही प्रभावित करता है। अतः, उसका फल यह है कि बैंक साह नियन्त्रण करके मूल्य नियन्त्रण कर सकते हैं और मूल्य नियन्त्रण से सट्टेबाजी रुक सकती है जिससे वापसी

रुक जाती है। केन्द्रीय बैंक बैंकों का प्रधान है। अतः, वह उनकी स्वाभाविक स्थिति पर दृष्टि रखकर उन्हें सचेत कर सकता है और यदि इतने पर भी कोई सकट में पड़ जाय तो वह उसकी सहायता भी कर सकता है।

प्रश्न

(१) 'बैंक दर' से आप क्या समझते हैं ? इधर इसके अर्थ में जो परिवर्तन हो गया है वह किन कारणों से हुआ है ?

(२) 'बैंक दर' नीति उन्नीसवीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में तथा अन्य देशों में साख नियन्त्रण के सम्बन्ध में क्यों अधिकाधिक प्रयोग में आने लगी। फिर, सन् १९१४-१८ के महायुद्ध के काल से इसका महत्व क्यों घट गया है ?

(३) 'बैंक दर' और दूसरी दरों के बीच में लन्दन के द्रव्य बाजार में क्या सम्बन्ध था ? बैंक आफ इंग्लैण्ड का 'बैंक दर' अन्य केन्द्रीय बैंकों के 'बैंक दर' से किन-किन बातों में भिन्न था ?

(४) 'साख नियन्त्रण के लिये बैंक दर नीति' अन्य देशों में न तो उतनी प्रभावोत्पादक ही सिद्ध हुई और न उतनी प्रयोग में ही आई जितनी इंग्लैण्ड में।' उपर्युक्त के क्या कारण थे ?

(५) बाजार में खुले तौर पर काम करने से आप क्या समझते हैं ? साख नियन्त्रण के लिये इस नीति की सफलता किन-किन परिस्थितियों पर निर्भर है ? अपना उत्तर बहुत स्पष्ट शब्दों में दीजिये।

१ (६) साख नियन्त्रण के निम्न तरीकों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये — (१) साख की राशनिंग, (२) डिस्काउण्ट के योग्य बिलों की मुदत घटाना, (३) प्रत्यक्ष कायवाही करना, (४) नैतिक प्रभाव डालना, (५) न्यूनतम नकद कोष में परिवर्तन, (६) जमानत के जिस अंश के बराबर ऋण दिया जाता है उसमें परिवर्तन, और (७) विज्ञप्ति।

(७) 'व्यापार चक्र', 'तेजी' और 'मन्दी' से आप क्या समझते हैं ? क्या केन्द्रीय बैंकों के पास व्यापार चक्र रोकने की शक्ति है ?

अध्याय ८

साख और साख-पत्र

आधुनिक व्यवसाय और उद्योगों में उन्वनि दोनों ही साख और साख-पत्र के प्रयोग पर निर्भर हैं। भौतिकीय के अनुसार यन्त्र के लिए जितना आवश्यक इतना है, गणितशास्त्र के लिये जितना आवश्यक गणन (Calculus) है उतनी ही आवश्यक व्यवसाय के लिये साख है।

साख क्या है ?

साख का आर्थिक अर्थ तो विरुद्ध है, किन्तु वास्तविक रूप में इसका अर्थ भुगतान टालना (Postponement of Payment) है। हम यह समझते हैं कि यह वह विनियम है जो एक निश्चित समय बीत जाने के पश्चात् पूरा नहीं होता है। साख में तीन आवश्यकताएँ हैं — (१) मूल्य विनियम, (२) समय, और (३) विज्ञापन—यह विज्ञापन श्रमों की श्रम श्रदा करने का समय और समागम दोनों में होना चाहिये।

प्रकृति (Nature) — प्रायोगिक कान्ति के समय से साख ने इतना महत्व प्राप्त कर लिया है कि कुछ लोग इसे धन अथवा पूँजी और उत्पत्ति का साधन समझने लगे हैं। अब, इसकी सत्यता निश्चित करने के लिये हम यह जानना आवश्यक है कि क्या साख किसी अन्य चीज की सहायता के बिना अनुपपन्न हो सकती है, क्योंकि धन का यही तो एक विशेष लक्षण है। फिर, यदि इसका उत्तर 'हाँ' में है तो हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि क्या यह उत्पत्ति करने के लिये प्रयोग में आ सकती है, क्योंकि धन इसी तरह से तो पूँजी बनता है। प्रथम तो साख स्वयं ही धन नहीं है। हमारा किसी पर कितना ही विश्वास क्यों न हो, इस अकेले विश्वास से ही तो उसे पूँजी नहीं मिल जायगी, पूँजी मिलने के लिये तो किसी के पास धन भी होना चाहिये। हम उस पर विश्वास तो करते हैं किन्तु हमारे पास धन तो है ही नहीं। अतः, हम उसे पूँजी दे नहीं सकते हैं। किन्तु हम देखते हैं कि वेकों के पास जितना धन रहता है उससे कहीं अधिक मूल्य की साख वह उत्पन्न कर देते हैं। अतः, लोग कहते हैं कि धन से अधिक जितनी साख उत्पन्न हुई है वह तो धन है ही। किन्तु सत्य यह है कि हम उठे हुये धन को तब पर कुछ वास्तविक धन है जिसके बिना यह बड़ा हुआ धन उत्पन्न हो ही नहीं सकता था। अतः, हम यह कह सकते हैं कि साख से धन बढ़ जाता है और वही जब प्रयोग में आने लगता है तब पूँजी बन

जाता है और सक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि साख धन को अधिक उपयोगी बना देती है। अतः, यह उत्पादन का साधन (Factor) नहीं है, वरन् तरीका (Method) है। वह पूँजी को उसी प्रकार अधिक कुशल बना देती है जिस प्रकार श्रम विभाजन (Division of Labour) श्रम को कुशल बना देता है।

रूप—साख के अनेक रूप हैं—व्यवसायिक साख (Commercial Credit), बैंक की साख, सरकारी साख (Public Credit), औद्योगिक साख (Industrial or Capital Credit), वैयक्तिक साख (Individual or Personal Credit)। जब कोई व्यवसाय अपनी साख के कारण उधार माल खरीदता है तब वह व्यवसायिक साख कहलाती है। किन्तु इस साख का क्षेत्र बहुत ही सीमित रहता है और यह बहुत जल्द ही समाप्त हो जाती है। अतः, इसका क्षेत्र और इसकी अवधि बढ़ाने के लिये इसका विनिमय बैंक साख से करना पड़ता है। विनिमय बिल व्यवसायिक साख के रूप हैं। उनका चलन सीमित रहता है। किन्तु जैसे ही उनका विनिमय बैंक की साख के साथ अर्थात् नोटों तथा बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये बिनों और साख पत्रों (Letters of Credit) जैसे अन्य साख पत्रों (Credit Instruments) के साथ हो जाता है वैसे ही वह एक बहुत बड़े क्षेत्र में चालू किये जा सकते हैं। किसी व्यवसायी को तो कुछ ही व्यवसायी जानते हैं। अतः, वह अन्य व्यवसायियों से अपनी साख पर उधार माल नहीं खरीद सकता। किन्तु जब वह अपनी साख बैंक साख से बदल लेता है तब वह कहीं से भी उधार माल खरीद सकता है, बैंक उसे चेक और बिल काटने (Draw) की आज्ञा दे देता है। बिल तो प्रायः उस व्यवसायी को माल उधार देने वाले स्वयम् करते हैं। हमने इनके विषय में बहुत काफी अध्ययन पाँचवें अध्याय में ही बैंकों द्वारा स्वीकृत किये जानेवाले बिलों के अन्तर्गत कर लिया है। सरकारी साख के अन्दर सरकार द्वारा उधार लेना आ जाता है। वे अपने व्याज साख-पत्र निकालते हैं। औद्योगिक साख के अन्तर्गत उद्योग-धन्वों द्वारा उधार लेना आता है। वैयक्तिक साख के अन्तर्गत उपभोक्तियों द्वारा उपभोग के लिये उधार माल खरीदना अथवा उधार द्रव्य लेना आ जाता है। उधार या तो साख-पत्रों की बिना पर या हिसाब-किताब की पुस्तकों में किये गये लेखों की बिना पर मिलता है। जब वह हिसाब-किताब की पुस्तकों में किये गये लेखों की बिना पर मिलता है तब हम उसे किताबी साख (Book credit) कहते हैं।

लाभ—साग में साग-पत्रा की डगनि होती है जो भौतिक मुद्रा के रूप में काम करते हैं। (अ) यह भौतिक मुद्राओं की अपेक्षाएँ विनिमय के लिये मायम पद्धत में (ब) यह उद्दान करने में अधिक सुविधाजनक रहते हैं, और (ग) यह भाग्य में मुद्रा की जमी पूरा करते हैं—मानव में भौतिक मुद्रा अस्सी प्राप्ति के विनिमय के मायम की आवश्यकताओं पूर्ण बना कर मक्ती। उनके प्रयोग के लिये नीचे की गयीं गुरुत्व उपयोगों में प्राप्ति के लिये मुक्त हो जाती है। १४ मुद्रा की गुरुत्व में प्रेम के काम में भी आते हैं। तन्त्रशास्त्रीय समान तो उनके माग्य पद्धत की प्राप्ति में सुगम होते हैं।

साग के कारण जब समुदाय का तन्त्र केन्द्रित हो जाती है, तब उसने प्रकृत करने वाले और वस्तु या उपयोग करनेवाले दोनों की लाभ होता है। अतः, समुदाय में प्रयोग हो जाता है। फिर, जब केन्द्रित रूप में उपयोग-धर्मों प्रयोग व्यवस्था में तब जाती है तब उनमें प्रत्यक्ष व्यक्तियों का जीवन-निराद होता है। प्राधुनिक माग्य का मान्य उत्पादन साग ही के कारण सम्भव हो सका है।

साग में जीवन की पट्टा भी कम हो जाती है। जब कभी द्रव्य में आवश्यकता पड़ती है तब यह साग के रूप में उसे उत्पन्न कर देते हैं, और जब उसकी आवश्यकता नहीं रहती है तब वह उसे समेट लेते हैं।

साग में राष्ट्र प्रपने वहाँ के आर्थिक मकदूर कर लेते हैं। इसी के कारण वे लम्बी-लम्बी लड़ाईयाँ लड़ते हैं।

जब कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिये तब मकदूर में पड़ता है तब उसे भी साग के ही कारण उधार मिल जाता है और उसका काम चल जाता है।

हानियाँ—जहाँ पर साग से इतने लाभ हैं वहाँ पर उससे अनेक हानियाँ भी होती हैं। वास्तव में उसमें अपने अधिक बुराई तो हमने अत्यधिक उपयोग में आ जाने के कारण होती है। जब अत्यधिक साग उत्पन्न हो जाती है तब बहुत उत्पाद बढ़ जाता है और उससे अत्युत्पादन तथा महंगाई बढ़ जाती है। इससे अयोग्य व्यक्तियों को भी सहेवाले तथा अन्य हानिकारक व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, जिसमें न केवल उन्नी की वस्तु दूसरों की भी हानि होती है। जो उपभोक्ता साग प्राप्त कर सकते हैं, वह प्रायः अधिक व्यय होकर अपनी आर्थिक अवस्था खराब कर लेते हैं। फिर, इससे पूँजीवाद और उसमें उत्पन्न अन्य बुराइयों की, जैसे प्रतियोगिता तथा भ्रम कोषण, इत्यादि की उत्पत्ति हो जाती है।

साख-पत्र

साख से अनेक प्रकार के साख-पत्रों की उत्पत्ति हो गई है। अतः, उन सब का तो यहाँ पर अध्ययन करना असम्भव-सा है। किन्तु उनमें से कुछ का अध्ययन अवश्य हम यहाँ पर (१) विनिमय साध्य साख-पत्रों (Negotiable Instruments), (२) हुण्डियो तथा (३) अन्य साख-पत्रों के शीर्षक के अन्तर्गत करेंगे।

विनिमय साध्य साख-पत्र—इनमें चेक, विनिमय बिल और प्रणपत्र सम्मिलित हैं। साधारणतः ये हस्तान्तरकृत को अच्छा अधिकार देते हैं किन्तु इनकी यह शक्ति (Negotiability) इन पर प्रतिबन्ध युक्त वेचान (Restrictive endorsements) करके अथवा चेक में उस पर अविनिमय साध्य रेखाङ्कन (Not negotiable Crossing) करके समाप्त अथवा सीमित भी की जा सकती है। हाँ, इस शक्ति की समाप्ति अथवा उसके प्रतिबन्ध के यह अर्थ नहीं है कि यह साख-पत्र हस्तान्तरित (Transfer) भी नहीं किये जा सकते हैं। हस्तान्तरित होने की शक्ति (Transferability) और विनिमय साध्यता (Negotiability) का अन्तर भली भाँति समझ लेना चाहिये। जिस साख-पत्र में विनिमय साध्यता नहीं होती अथवा उसे समाप्त अथवा सीमित कर दिया जाता है उसे, जितनी बार चाहे उतनी बार हस्तान्तरित तो किया जा सकता है, किन्तु यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा चुरा लिया जाता है अथवा किसी अन्य अनुचित तरीके पर उसके पास पहुँच जाता है, तब उस पर हस्तान्तरकृत (Transferee) का उनी हस्तांतरकर्ता (Transferor) ही की तरह का अधिकार होता है जिसने उसे चुरा लिया था अथवा अन्य अनुचित तरीके पर प्राप्त कर लिया था, अर्थात् उससे उसने जो लाभ उठाया है उसे आवश्यकता पड़ने पर उसके वास्तविक स्वामी को लौटाल देना पड़ता है। स्पष्ट है कि यदि हस्तांतरकर्ता ठीक है तो हस्तान्तरकृत की कोई हानि नहीं है। इसके विपरीत यदि किसी ऐसे विनिमय साध्य साख-पत्र को जिसकी यह विनिमय साध्यता समाप्त अथवा सीमित नहीं कर दी गई है कोई व्यक्ति उसके पूरे मूल्य पर प्राप्त कर लेता है तो उसे उसका लाभ उसके वास्तविक स्वामी के जिससे उसे चुरा लिया गया था अथवा किसी अनुचित तरीके पर प्राप्त कर लिया गया था विरोध में भी अपने पास रखने का अधिकार है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जब हस्तांतरित

होने से शक्ति निम्नमेन म्याम्नि (Absolute ownership) नहीं प्रदान करती, विनिमय साध्यता ऐसा करता है।

चक्र—विनिमय साध्य पुरों के भारतीय विधान की धर्मी धारा में चेक की जो परिभाषा दी गई है यह इस आशय की है --चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो एक विशेष बैंक के ऊपर लिखा जाता है और जिसके भुगतान देने का आदेश मौग पर द्योदर अन्य किसी प्रकार नहीं हो सकता है। प्रत्येक बैंक तीन विशेषताएँ हैं।

(१) यह विनिमय पत्रों के समान है, (२) इसमें ऊपरवाला धनी कोर्ट ईश्वर होता चाहिये, और (३) यह दर्शनी होनी चाहिये, अर्थात् इसका भुगतान माँगने पर फौरन देना चाहिये।

उपर्युक्त विधान में धर्मी धारा में विनिमय पत्रों की भी परिभाषा दी हुई है। वह निम्न प्रकार की है --यह एक ऐसा लिखित पत्र है जिस पर इसे लिखनेवाले के हस्ताक्षर होते हैं और जो उसमें लिखित किसी व्यक्ति ने उसमें लिखित किसी अन्य व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार अथवा उसके वाहक को उसमें लिखित रकम किसी शर्त देना देने की आज्ञा देता है।

प्रत्येक उपर्युक्त परिभाषाएँ ध्यान में रखते हुये हम चेक की अपनी परिभाषा भी बना सकते हैं जो कुछ निम्न प्रकार की होगी --एक चेक एक ऐसा शर्त रहित लिखित आज्ञापत्र है जिसमें उसे लिखनेवाला अपने हस्ताक्षर से उसमें लिखित किसी विशेष व्यक्ति को अथवा उसकी आज्ञानुसार अथवा उसके वाहक को उसमें लिखित एक विशेष रकम मौग पर देने के लिये कहता है। यद्यपि इस परिभाषा का प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है तो भी इसमें निम्न विशेषताएँ मिलती हैं --

(१) यह एक आज्ञापत्र है।

(२) यह लिखित होता है।

(३) यह शर्त रहित होता है।

(४) यह किसी विशेष बैंक पर होता है।

(५) इस पर इसे लिखनेवाले के हस्ताक्षर होते हैं।

(६) इसमें लिखित रकम माँगने पर फौरन देनी पड़ती है।

(७) इसकी रकम निश्चित होती है।

(८) जिसे भुगतान दिया जाता है उसका नाम इसमें लिखित होता है। अथवा उसके आदेशानुसार होता है अथवा इसका वाहक होता है।

चेक से सम्बन्धित धनी तीन प्रकार के होते हैं --

(१) लिखनेवाला धनी (Drawer)—इसका बैंक में चालू खाता होता है, (२) ऊपरवाला धनी (Drawee)—यह बैंक होता है और (३) पानेवाला धनी (Payee)—जिसे चेक का धन मिलना होता है। यदि पानेवाला धनी कोई कल्पित व्यक्ति रहता है तो चेक का धन चेक के वाहक (Bearer) को मिलता है।

पानेवाले धनी का नाम लिखने के लिये जो स्थान होता है उसके अन्त में 'आर्डर (Order) अथवा बेर (Bearer)' छपा होता है। अतः चेक लिखनेवाले को इसमें से एक काट देना चाहिये। यदि आर्डर कट जाता है तो बेरर चेक (Bearer Cheque) रह जाता है और यदि बेरर कट जाता है तो आर्डर चेक (Order Cheque) रह जाता है। बेरर चेक के अर्थ हैं कि उसका दाम उसके वाहक को दे दिया जाय और आर्डर चेक के अर्थ हैं कि उसका दाम ऊपरवाले धनी के आदेशानुसार दिया जाय। आर्डर चेक का वेचान होता है। उसके बारे में हम आगे चलकर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर तो यह कह देना ही काफी है कि एक आर्डर चेक वेचान द्वारा ही हस्तांतरित की जा सकती है। कभी कभी बेरर और आर्डर दोनों ही शब्द काटकर 'केवल' (Only) लिख दिया जाता है। ऐसी चेक भी आर्डर चेक कहलाती है। आर्डर चेक को हम फरमानजोग चेक और बेरर चेक को देखनहार चेक कहते हैं।

चेक के उसी स्थान की कर्त्तनी में काटनी चाहिये जिस स्थान में बैंक रहता है। यदि चेक किसी अन्य कर्त्तनी में काट दी गई है तो बैंक चाहे तो इसका भुगतान उस समय की विनिमय दर के अनुसार कर दे अथवा उसे लौटा दे।

चेक का नमूना

No 135	No 135	Dated July 10, 1948
Dated 10 July	ALLAHABAD COMMERCIAL BANK LTD ALLAHABAD	
In favour of Mr. Ram Prasad	Pay Mr Ram Prasad	ORDER BEARER
Rs. 100/-	Rupees One hundred only	
	Rs. 100/-	
		G Dayal

म० १३५	१० १३५	ता० १० जुलाई, १९४८
ता० १० जुलाई, १९४८	इलाहाबाद कमिश्नर बैंक, निमिटेड
पानेवाला धनी, श्री राम-	इलाहाबाद
	श्री रामप्रसाद को प्रथम उनके आवेद
प्रत्यक्ष रूप से उक्त	के प्रत्यक्ष की कथा अंगित ।
प्रत्यक्ष रूप से उक्त	रु० १००)	जी० दयाल
R० १००	..	

चेक का रूप (Foil) और प्रतिकर (Counter-foil) दोनों होते हैं। बायाँ भाग प्रतिकर (Counter-foil) और दायाँ भाग रूप (Foil) कहलाता है। प्रतिकर अपने पास रख लिया जाता है, रूप पानेवाले धनी को दे दिया जाता है।

चेक लिखते समय उसमें रूप और प्रतिकर दोनों भरने चाहिये। प्रथम तो तारीख रहनी है। इसे ठीक-ठोक भरना चाहिये। आगे की तारीख भर देने में तब तक बट तारीख नहीं आ जाती उसका भुगतान नहीं होता। ऐसी चेक उत्तर तिथीय (Post-dated) कहलाती है। यदि किसी चेक में पीछे की तारीख भर दी गई है तो यदि वह छे माह में भी पहिले की हो जाती है तो उसका भुगतान नहीं हो सकता। पहिले की तारीख भर देने में चेक पूर्व तिथीय (Ante-dated) हो जाती है और छे महीने से ज्यादा की चेक पुरानी (Stale) हो जाती है। हाँ, यदि किसी चेक में शिक्तुल ही तारीख नहीं भरी जाती तो उसे पानेवाला धनी अथवा अन्य कोई व्यक्ति उस पर सही तारीख भर सकता है। यदि कोई गिना तारीख की चेक बैंक में पहुँच जाती है तो बैंक चाहे तो उस पर सही तारीख भरकर उसका भुगतान कर दे अथवा अपूर्ण (Incomplete) लिखकर वापिस कर दे।

तारीख भरने के बाद पानेवाले धनी का नाम भरना पड़ता है। इसे उन्हीं अधिकारी में भरना चाहिये जो पानेवाला धनी लिखता है, अन्यथा जब वह दस्तावेज करेगा, गलती हो जाने का डर रहेगा। यदि रकम स्वयम् के लिये निकालनी है तो उसमें 'मुझी को दीजिये' (Pay to self) लिखना

चाहिये। इसके बाद प्रायः हर चेक में जैसा कि पहिले बताया जा चुका है 'वेरर' अथवा 'आर्डर' शब्द दिये रहते हैं। इनमें से आवश्यकतानुसार एक रख लेना चाहिये और दूसरा काट देना चाहिये। कभी-कभी दोनों काटकर 'केवल' लिख दिया जाता है।

पानेवाले धनी के नाम के बाद धन लिखना पड़ता है। यह धन पहिले तो शब्दों में और फिर अङ्कों में लिखा जाता है। शब्दों और अङ्कों में एक ही धन होना चाहिये। यदि अन्तर है तो वेकर अपनी इच्छानुसार या तो शब्दों की रकम या शब्दों और अङ्कों में से जिसकी रकम कम है उसका भुगतान कर सकता है। किन्तु प्रायः वेकर 'शब्दों और अङ्कों के धन में अन्तर हैं (Amounts in words and figures differ)' लिखकर चेक वापस कर देते हैं। धन लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि शब्दों के बीच में और द्वादशों के बीच में कोई अन्तर नहीं छोड़ना चाहिये वरना जालसाजी की सम्भावना रह जाती है।

अन्त में लिखनेवाले धनी के हस्ताक्षर होते हैं। इस धनी ने बैंक में जब अपना हिसाब खोला होगा तब वहाँ पर हस्ताक्षर का नमूना दिया होगा। अतः, यह हस्ताक्षर उसी से मिलना चाहिये यदि यह हस्ताक्षर नहीं मिलता तो चेक का भुगतान नहीं किया जाता।

जहाँ तक चेक की सुरक्षा का प्रश्न है, आर्डर चेक वेरर चेक की अपेक्षाकृत कहीं अधिक सुरक्षित रहता है। किन्तु जैसा कि पहले बताया जा चुका है 'केवल' (Only) शब्द लिख देने से वह और भी अधिक सुरक्षित हो जाती है। ऐसी चेक का हस्ताक्षरकर्ता हस्ताक्षरकृत को उस पर वैसा ही अधिकार देता है जैसा उसका स्वयं का रहता है। चेकों को रेखांकित (Crossed) भी बनाया जा सकता है। इसके लिये उसके ऊपरी बाएँ कोने पर दो आड़ी समानान्तर रेखाएँ खींच दी जाती हैं। यदि इनके अन्दर किसी विशेष बैंक का नाम नहीं लिखा जाता तब तो यह साधारण रेखाङ्कन (General Crossing) कहलाता है। रेखाङ्कन के अर्थ हैं कि उसका भुगतान किसी बैंक की मार्फत किया जाय। अतः, कोई बैंक किसी चेक का धन तभी तो लेगा जब उसकी उस व्यक्ति से जान-पहचान होगी जिसके लिये वह भुगतान ले रहा है। ऐसा व्यक्ति प्रायः उसका ग्राहक होता है। स्पष्ट है कि रेखाङ्कित चेक अन्य चेकों की अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित रहती है। यदि इसे और अधिक सुरक्षित बनाना है तो रेखाओं के अन्दर किसी विशेष बैंक

का नाम दिया जा सकता है। ऐसा रेखांकन विशेष रेखांकन (Special Crossing) कहलाता है। यदि किसी चेक पर विशेष रेखांकन दिया गया है तो उसका भुगतान केवल उसी बैंक की मार्फत लिया जाता है जिसका नाम रेखांकन के अन्तर्ग दिया गया है। जब यदि इसे और अधिक सुरक्षित बनाना है तो रेखांकन के बीच में गोल-गोल रेखांकन में और विशेष रेखांकन में भी 'केवल पानेवाले की कृपा में' (Account payee only) अथवा 'अविनिमय साध्य' (Not Negotiable) प्रथम दोनों लिख दिये जाते हैं। 'केवल पाने वाले की कृपा में' (Account Payee only) लिख देने से उसका भुगतान करने वाला बैंक (Collecting Banker) उससे रकम पांचे वालों के खाते में जमा कर देता है उसे नष्ट नहीं देता। 'अविनिमय साध्य' (Not Negotiable) लिख देने से उस पर हस्तान्तरण या पैसा की अधिकार हो जाता है ऐसा हस्तान्तरण नहीं हो पाया। अतः, यह रेखांकन चेक से और भी अधिक सुरक्षित बना देते हैं।

चेक के अधिकारी (Holder of a cheque) को उसे अपने ऊपर वाले बैंक के पास उचित समय के अन्दर ले जाना चाहिये। वह काम वह स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा कर सकता है। यदि कोई अधिकारी अपना चेक अपने पास रखते रहता है और इन बीच में ऊपरवाला बैंक फेल हो जाता है तो इसमें जो हानि होती है उसका उत्तरदायित्व उसी अधिकारी के ऊपर पड़ता है। मान लीजिए कि राम ने श्याम को एक चेक दी है, और श्याम ने उसका भुगतान उचित समय के अन्दर नहीं लिया है तथा ऊपरवाला बैंक इसी बीच में फेल हो गया है, तब यदि राम को ऊपरवाले बैंक से केवल आधी रकम मिलती है तो राम श्याम को उस चेक की आधी रकम ही देगा। जिस चेक में रेखांकन नहीं होता वह चेक खुली चेक (Open cheque) कहलाती है।

चेक का अधिकारी (Holder)—विनिमय साध्य पुर्जे के विधान की ध्वी धारा में चेक के, प्रण-पत्र के और विनिमय त्रिल के अधिकारी की जो परिभाषा दी हुई है वह कुछ निम्न आशय की है—“यह वह व्यक्ति है जिसे उसे रखने का और जिनके ऊपर उसके भुगतान का दायित्व है उनसे उसका भुगतान पाने और वसूल करने का अधिकार है। यदि कोई चेक, प्रण-पत्र अथवा विनिमय त्रिल खो भी गया है अथवा नष्ट हो गया है तो भी उसका अधिकारी वही है जिसे उसके खोने अथवा नष्ट होने के पहिले उपर्युक्त

अधिकार थे। साथ ही उसे उस चेक, प्रण-पत्र तथा विनिमय बिल की एक अन्य प्रतिलिपि भी उनके ऊपर वाले धनी से इस बात का वायदा करके प्राप्त कर लेने का अधिकार है कि यदि उनके किसी निरपराधी व्यक्ति के हाथ में पड़ जाने से उसकी कोई हानि होगी तो वह उसे पूरा कर देगा। यदि कोई साख-पत्र डाक से भेजा जाता है और वह रास्ते में खो जाता है तो उसका दायित्व उस भेजनेवाले ही के रूप में पड़ता है। हाँ, यदि भेजने वाले ने उसे जिसके पास भेजा गया था उसके आदेशानुसार ऐसा किया था तो वही जिसके पास उसे भेजा गया था उसका जिम्मेदार होता है।

मूल्य दिये हुये पुर्जे का अधिकारी (Holder for value)—जिस पुर्जे का मूल्य किसी ने कमी भी चुका दिया है उस पुर्जे का अधिकारी, मूल्य दिये हुये पुर्जे का अधिकारी माना जाता है। मान लीजिये कि एक चेक 'ब' के पक्ष में है और 'स' का 'ब' के ऊपर द्रव्य चाहिये जिससे 'ब' ने 'स' के पक्ष में उसका वेचान कर दिया है। अब यदि 'स' उसे 'द' को दान में दे देता है तो 'द' मूल्य दिये हुये पुर्जे का अधिकारी है। उसने स्वयं तो इसका मूल्य नहीं दिया है किन्तु इसका मूल्य 'स' के द्वारा दिया जा चुका है।

चलन के अनुसार अधिकारी (Holder in due course)—इसकी परिभाषा भी उपर्युक्त विधान ही में दी हुई है। यह निम्न आशय की है—यदि कोई चेक, प्रण-पत्र और विनिमय बिल वाहक को देय है तो उसका चलन के अनुसार अधिकारी वही व्यक्ति है जिसने उसके प्रतिफल के विनिमय में उसे प्राप्त किया है, और यदि वह आदेशानुसार देय है तो इसके लिये उपर्युक्त के अलावा उसे या तो उसका पानेवाला धनी अथवा वेचान द्वारा हस्तान्तरकृत होना चाहिये। साथ ही चलन के अनुसार अधिकारी के लिये यह भी आवश्यक है कि उसने उसके पक जाने के पहिले और उसके हस्तान्तरकर्ता पर इस बात का सन्देह किये बिना कि उस पर उसका अनुचित अधिकार है उसे प्राप्त किया हो। अतः, यह स्पष्ट है कि वाहक को देय पत्र में तो वह उसे दिया गया हो और आदेशानुसार देय-पत्र में या तो वह स्वयं उसका पानेवाला धनी हो या उसके नाम वह वेचान किया गया हो। साथ ही इसके लिये निम्न बातें भी आवश्यक हैं—

(१) वह किसी प्रतिफल के विनिमय में प्राप्त किया गया हो।

(२) जब वह प्राप्त किया गया हो तब पक न चुका हो।

(२) उन्हे इस बात का मन्त्र होने में तनिक भी आशङ्का न रही हो कि उसके हस्ताक्षरों का उस पर कोई अनुचित अधिकार था ।

सत्तेर म यह 'बोनाफ़िदे नीधन के मूल्य के विनिमय में किसी संदेह बिना प्राप्त करनेवाला अधिकारी' (Bonafide holder for value without notice) माना चाहिये । यह वास्तविक चेदमा अस्मय है, किन्तु स्वयं स्पष्ट है ।

किसी विनिमय माध्यम पुर्न के चलन के अनुसार अधिकारी का ही उस पर अधिकार होता है ।

चिह्नित चेक (Marked Cheque)—यह यह चेक है जिस पर ऊपरवाले बैंक ने कोर ऐसा चिह्न बना दिया है जिससे यह मालूम पड़ता है कि जिस समय वह चिह्न बनाया गया था उस समय यदि उसका भुगतान माँगा जाता तो वह दे देता । एमो चेक का भविष्य में भुगतान होना, इस बात पर निर्भर होता है कि निम्नलिखित धनी क हाते में रक्म शेष है या नहीं । कोर चेक उसके निम्नलिखित धनी को अथवा उसके पानेवाले धनी को और उगने किसी भी अधिकारी की प्रार्थना पर चिह्नित किया जा सकता है ।

विनिमय बिल (Bill of Exchange)—विनिमय बिलों की परिभाषा तो ऊपर दी ही जा चुकी है । इसके भी चेक ही की तरह के तीन धनी होने हैं, हों, यह अन्तर प्रश्न रहता है कि यह आवश्यक नहीं है कि ऊपरवाला धनी कोई बैंक ही हो । यह देशी और विदेशी (Inland and Foreign) दो प्रकार के हो सकते हैं । देशी बिल वह है जिसे जिस देश में लिखा जाता है उसी देश में उसका भुगतान होता है, अथवा उसका ऊपरवाला धनी उसी देश का रहनेवाला होता है । इसके विपरीत विदेशी बिल वह है जिसमें उपर्युक्त बातें नहीं होती हैं ।

देशी बिल का नमूना

२ आ०

रु० ८००)

प्रयाग

१५ जनवरी, सन् १९४८

उपरोक्त तिथि से एक माह बाद **हार्ड** मो रुपया पहुँचे दाम बाबू प्रकाशचन्द को अथवा उनके आदेशानुसार दे देना ।

जोग देना

भार्गे मोहनलाल,

नीची बाग,

कलकत्ता ।

रामदान हरिदास

Allahabad,

Jan 15, 1948

2 as

Rs 800/-

One month after date pay to B Prakash Chand or order the sum of Rupees Eight hundred only, value received

Ramdas Haridas

To

Mohanlal Esqr,
Nichi Bagh,
Calcutta

विदेशी बिल का नमूना

मूल्य लिपि

२ आ०

पै० ४०

प्रयाग (भारतवर्ष)

१५ जनवरी, १९४८

यह मूल लिपि देखने के नब्बे दिन बाद यदि इसकी दूसरी और तीसरी लिपियों का भुगतान नहीं हुआ है तब चालीस पाउण्ड भाई एडवर्ड स्मिथ को पहुँचे दाम दे दीजिये ।

जोग देना

बी० बादशाह

श्री जेम्स स्मिथ,

लन्दन

FIRST OF EXCHANGE

-/2/-

£ 40—

Allahabad (India),

January 15, 1948

Ninety days after sight of this First of Exchange (Second and third of the same tenor and date unpaid), pay to Edward Smith Esqr the sum of Pounds Forty only, value received

To B Badshah

James Smith Esqr,

London.

मिल लिखने समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए :—

(१) तारीख—जिस दिन मिल लिखा जाता है उसी दिन को तारीख को लिखना जानी चाहिए। या यह है कि मिल पढ़ने को तारीख का पता उपर्युक्त तारीख दो न मिल की प्रतिलिपि जोड़कर निम्नलिखित गणना है।

(२) अवधि—(Tenor or term)—जिस अवधि के लिए जो मिल लिखा जाता है वह उससे अवधि कहलाता है, जैसे- उपर्युक्त तारीख के तीन माह बाद (Three months after date — 3 m/d) अथवा नवने के ६० दिन बाद (90 days after sight-90d/s)। यह अवधि बहुत ही स्पष्ट और पर लिखनी जानी चाहिये। मिल पढ़ने की तारीख निम्नलिखित के लिये उसमें प्राप्त तीन मियादती दिन भी जोड़ जाते हैं। यदि किसी मिल के पढ़ने की तारीख किसी छुट्टी के दिन पड़ जाती है तो उसका भुगतान छुट्टी के पड़ते ही हो जाता है। अंग्रेजी विधान में सार्वजनिक छुट्टियों और बैंक की छुट्टियों में कुछ अन्तर है। यदि कोई मिल किसी बैंक की छुट्टी के दिन पड़ता है तो उसका भुगतान उसके प्रगते दिन होता है। भारतीय विधान में ऐसी कोई बात नहीं है, यतः, यहाँ के विद्यार्थियों को सार्वजनिक छुट्टियों और बैंक की छुट्टियों के बीच का अन्तर जानने की आवश्यकता नहीं है। मिल दर्शनी (Demand) भी हो सकते हैं। उनमें मियादती दिन नहीं जुड़ते।

(३) धन की रकम—यह दो बार लिखनी जानी है—शब्दों में और अंकों में। कुछ लोग मिलों के बीच में जितनी रकम का मिल होता है उसमें कुछ बढ़ाकर उससे नीचे (Under Rs) लिख देते हैं।

(४) मिल के धनी—पानेवाले धनी का नाम तो इमारत के साथ ही दिया रहता है और उसमें आदेशानुसार अथवा वाहक शब्द (Order or Bearer) दिया रहता है। लिखनेवाले धनी का नाम इमारत के नीचे दाहिनी तरफ और ऊपरवाले धनी का बायीं तरफ दिया रहता है।

(५) स्टाम्प—दर्शनी मिलों को छोड़कर अन्य सब मिलों पर उनके रकम के अनुसार स्टाम्प लगा रहता है।

(६) पहुँचे दाम (Value Received)—प्रत्येक मिल में यह शब्द अवश्य लिखे जाते हैं। इनके हेतु अर्थ है कि ऊपरवाले धनी को इसका मूल्य किसी न किसी रूप में मिल गया है।

विदेशी मिलों की दो अथवा तीन लिपियाँ एक साथ पैगार की जाती हैं। अतः, प्रत्येक लिपि में अन्य लिपियों का संकेत रहता है। ऊपरवाले धनी को

केवल एक ही लिपि का भुगतान करना पड़ता है। प्रत्येक प्रतिलिपि अंग्रेजी में वाया (via) कहलाती है। यदि किसी विदेशो बिल की एक ही लिपि तैयार की जाती है तो उसे सोला बिल (Sola) कहते हैं। कहीं-कहीं अन्य देशों में लिखे गये बिलों पर उनके भुगतान के लिये आने पर फिर से स्टाम्प लगाना पड़ता है।

प्रत्येक मुदती बिल पर ऊपरवाले धनी को अपनी स्वीकृति (Acceptance) देनी पड़ती है। यह वह उसके बीच में हस्ताक्षर करके करता है। यदि वह चाहे तो स्वीकार किया (Accepted) और अमुक स्थान पर भुगतान होगा (Payable at..) भी उस पर लिख सकता है। जब तक बिल पर स्वीकृति नहीं होती उसे ड्राफ्ट कहते हैं, और जब यह हो जाता है तब वह स्वीकृत बिल (Acceptance) कहलाता है। बिल को स्वीकृति साधारण (General) तथा विशेष (Special) हो सकती है। साधारण स्वीकृति में ऊपरवाला धनी उसे उसमें दी हुई शर्तों पर स्वीकार करता है और विशेष स्वीकृति में वह इन्हे बदल देता है। अतः, यह निम्नांकित हो सकते हैं—

(१) हेतुमत् शर्ती, (Conditional)—जब भुगतान के पहिले कोई शर्त पूरी हो जाने के लिए लिख दिया जाता है, जैसे माल आ जाना।

(२) आंशिक (Partial)—जितनी रकम लिखी हुई है उममें कम के लिए स्वीकृति देना।

(३) स्थानिक (Local)—जब किसी विशेष स्थान पर ही भुगतान देने के लिये लिख दिया जाता है—केवल इलाहाबाद बैंक में ही भुगतान मिलेगा और कहीं नहीं (Payable at Allahabad Bank and there only)। जिस जगह भुगतान दिया जायगा उसका स्थान लिख देने से वह बिल स्थानीय बिल (Domiciled-Bill) कहलाता है।

अवधि परिवर्तन—इसमें ऊपरवाला धनी बिल में दी हुई अवधि से कुछ अधिक अवधि में बिल का भुगतान करने की स्वीकृति देता है।

ऊपरवाले सब धनियों द्वारा न स्वीकृत होना—मान लीजिए कि एक बिल राम, श्याम और हरी के ऊपर लिखा गया है, किन्तु उस पर केवल राम की ही स्वीकृति होती है।

ड्राफ्ट स्वीकृति के पहिले भी हस्तान्तरित किया जा सकता है। यदि किसी बिल पर विशेष स्वीकृति मिली है तो उसका अधिकारी उसे अस्वीकृत मान

मना है। हा, यदि उसने उसे निपटनेवाले धनी तथा उससे ऊपर जिन अन्य धनियों का दायित्व है उसने पट्टा मिला ही ऐसा कर लिया है तो मित्रों स्वीकृति के कारण निपटने दायित्व में ऊपरगाता धनी बन जाता है। उसने ही दायित्व से अन्य नए धनी भी बन जायेंगे। किसी बिल की स्वीकृति के लिये उसके उतरवाले धनी को दृष्टिया छाड़कर ४८ घंटे का समय दिया जाता है।

बिल प्रपनी स्वीकृति और अपने भुगतान के लिये विम्वृत्त हो अथवा नमरा जा सफा है (Dishonoured)। किसी बिल के नकारे जाने पर उसके अधिकारी का वह कर्तव्य हो जाता है कि वह उन सब धनियों को इसकी सूचना दे दे कि वह उस पर दायी बनाना चाहता है। फिर उसे उस पर नोट (Noting) भी गाना पड़ता है। उसके लिये नोटेरी पब्लिक (Notary Public) है। यह व्यक्ति यह बिल उसके ऊपरवाले धनी के पास एक बार स्वयं ले जाता है, और यदि तब भी वह नकार दिया जाता है तो वह उस पर यह बात लिख देता है। यही नोटिंग है। इसके लिए नोटेरी पब्लिक अपना शुल्क भी लेता है। कदी-कही पर नोटेरी पब्लिक में एक प्रमाण-पत्र भी ले लिया जाता है। इसे अग्रेजी में प्रोटेस्ट (Protest) कहते हैं। कभी-कभी ऊपरवाले धनी का दिवाला निकल जाने पर उससे बिल के भुगतान के विषय में पूछ-नाछ की जाती है, और यदि इसका कोई ऐसा उत्तर नहीं मिलता कि जिससे यह विश्वास हो जाय कि उसके पकने पर उसका भुगतान हो जायगा तो यह प्रोटेस्ट अच्छी जमानत का प्रोटेस्ट (Protest for better security) कहलाता है।

बिल की नोटिङ्ग हो जाने के बाद अथवा उसकी प्रोटेस्टिङ्ग हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति उसे किसी भी ऐसे धनी के प्रजाय जिसके ऊपर उसका दायित्व है स्वयं उसे सकार सकता है। वह यह स्पष्ट लिख देता है कि वह किसके लिये उसे सकार रहा है।

बिल नमारे जाने से उनके अधिकारियों को जो कठिनाई उठानी पड़ती है उसे दूर करने के लिये कभी कभी तो लिखनेवाला धनी पहले ही से उसके नीचे यह लिख देता है कि आवश्यकता पड़ने पर यह अमुक धनी के पास ले जाया जाय (Drawee in case of need)।

विशेष परिवर्तन (Material Alterations)—किसी भी विनिमय साध्य पुर्जे पर कोई भी विशेष परिवर्तन कर देने से उस पर जो उत्तरदायित्व पड़ जाता है उसके लिए यदि वह उनकी आज्ञा से नहीं किया

गया है जो उसके लिये दायी है तो वह उनके ऊपर लागू नहीं होता। निम्न परिवर्तन साधारण परिवर्तन हैं। अतः, वह उन लोगों पर लागू हैं जो उस पर उत्तरदायी हैं।

साधारण परिवर्तन--(१) अर्धलिपित पुर्जा (Inchoate Stampcd Instruments) पूरा कर देना।

(२) जब कोई साधारण वेचान उसके ऊपर किसी का नाम लिखकर विशेष वेचान में परिवर्तित कर दिया जाता है।

(३) जब खुली हुई चेक पर साधारण अथवा विशेष रेखांकन कर दिया जाता है अथवा साधारण रेखांकन विशेष रेखांकन में परिवर्तित कर दिया जाता है। वसूल करनेवाला बैंक अपने पक्ष के रेखांकन में किसी अपने अदतिया बैंक की जिसके द्वारा वह उसे वसूल कराना चाहता है विशेष रेखांकन भी कर सकता है।

विशेष परिवर्तन के निम्न उदाहरण हैं--

(१) किसी पुर्ज की अवधि बदलने के विचार से उसकी तारीख बदलना।

(२) उसका धन बदलना।

(३) उसकी अवधि बदलना।

(४) उस पर दायी धनी बदलना।

(५) व्याज अथवा विनिमय दर बदलना।

(६) भुगतान का स्थान बदलना।

प्रणपत्र--यह वह लिपित पुर्जा है (जैसे नोट और परसो नोट नही) जिसमें उसका लिखनेवाला उसमें दिये हुए किसी धन को अथवा उसके आदेशानुसार अथवा जिसके पास वह पुर्जा हो विला किसी शर्त से उसमें किसी दूसरे एक निश्चित रकम देने का प्रयत्न करता है।

प्रणपत्र में केवल दो ही धनी होते हैं--(१) लिखनेवाला, (२) धनियाला।

प्रणपत्र लिखनेवाला धनी प्रणपत्र अथवा नोट में मुद्रित हो सकते हैं। मुद्रित प्रणपत्र लिखनेवालों पर उनके भुगतान को केवल मुद्रित धनी के पक्ष में प्रयत्न करने की निम्नोद्धारिता हो सकती है। प्रयत्न प्रणपत्र में तो उसका धन धनी धनी सब लिखनेवाले धनियों से उक्त भुगतान करने की शक्ति प्राप्त होती है। प्रणपत्र पर मुद्रित धनी प्रणपत्र में या बाह्य में प्रयत्न करने

घाते धनी से अलग-अलग भी उसका भुगतान करने को कह सकता है, किन्तु इसमें शर्त यह है कि उसे उतना ही भुगतान मिलेगा जितना प्रणपत्र में लिखा है।

प्रणपत्र का नमूना

२ ग्रा०

रु० ३००)

मनास,

६ जनवरी, १९४८

उपरोक्त तारीख से एक माह बाद मैं भाई लाटामल को केवल तीन सौ रुपया पहुँचे दाम देने का प्रण करता हूँ।

शिवनाथ शर्मा

संयुक्त प्रणपत्र

२ ग्रा०

रु० १००)

जौरो रोड,

एलाहाबाद।

जनवरी १२, १९४८

हम श्री हरवेश जी को उनके माँगने पर केवल एक सौ रुपया पहुँचे दाम देने का प्रण करते हैं।

ब्रजमोहन साहू

कृष्णमोहन साहू

संयुक्त और पृथक्

२ ग्रा०

रु० ६००)

मेन्टन रोड,

कानपुर।

फरवरी १५, १९४८

हम संयुक्त और पृथक्-पृथक् भाई रामलाल को आज से तीन महीना बाद केवल छ सौ रुपया पहुँचे दाम देने का प्रण करते हैं।

गोपीकृष्ण अग्रवाल

सीताराम केसरवान

SPECIMEN P/N

-/2/-

Rs 400/-

Allahabad,

Nov 25, 1947

One month after date I promise to pay to Mr Jaigopal the sum of Rupees Four hundred only value received

Balramdas

JOINT

- / 2 /

Rs 200/-

Kanpur

Oct 15, 1947.

On demand we promise to pay to Mr Ram Anugrah the sum of Rupees Two hundred only, value received

Brijmohan Lal

Bhagwati Prasad

JOINT and SEVERAL

३/२९

Rs 600/-

Kanpur,

Aug 29, 1947

Three months after date, we jointly and severally promise to pay to Mr Raghuendra or order the sum of Rupees Six hundred only, value received

Mahmood Khan

Shahabuddin

भारतीय कागजी मुद्रा विधान के अनुसार रिजर्व बैंक छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति ग्रथवा सस्या दर्शनी और देखनहार दोनो प्रणपत्र एक मे नहीं लिख सकती है ।

टुडियो

यद्यपि अन्ध्या विनिमय साध्य पुजें विधान मे केवल तीन ही विनिमय साध्य पुजों अर्यात् चेक, विनिमय विलो और प्रणपत्रों का ही नाम दिया हुआ है किन्तु चलन के अनुसार अन्य कई पुजें भी ऐसे माने गये हैं । टुडियो प्रायः सभी विचार से विनिमय विलों से मिलती जुलती हैं । उन्हीं की तरह उन पर स्टाम्प लगता है, उन्ही की तरह उन पर बेचान होता है और उन्ही की तरह उन्हे सकारा जाता है । हाँ, उनकी लिखावट अवश्य कुछ भिन्न होती है । किन्तु जोखमी हुण्डी अवश्य विनिमय विलों की तरह नहीं होती । जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे इसे लिखने का सिद्धान्त ही कुछ दूसरा है । इसके अलावा जहाजी रसीद, ढक वारण्ट, सुपुर्दगी के आदेश-पत्र (जो सत्र माल सम्बन्धी

दे) शेयर, बॉण्ड, देयनगार, म्यूचुअल (जो व्यक्तिगत श्रम के होते हैं) आशिक विनिमय साधन (Semi-Negotiable Instruments) कहलाते हैं। इनके अधिकारी (राहनीवालों) को इनका अधिकार संपत्ति अपने नाम से प्रचलित करने का अधिकार नहीं होता है किन्तु इन पर उनका पैसा ही अधिकार हो जाता है जैसे उन लोगों का या जो इनको उन्हें एम्पान्नाइज्ड करते हैं।

हुडिया विनियम दो प्रकार की होती है--(१) मुदती, और (२) दर्शनी। मुदती हुडिया वह कहलाती है जिसका भुगतान हुडिया लिखने की तारीख या मिति के बाद हुडिया में लिखी हुई अवधि पूरा होने पर किया जाता है। दर्शनी हुडिया वह कहलाती है जिसमें पढ़ने के बाद प्रथम इसी तरह के अन्य कोई शब्द लिखे जाते हैं जिनका अर्थ यह होता है कि हुडिया में लिखी हुई मिति के बाद किसी दिन भी उसे दिवाने पर उसका भुगतान हो जायगा।

किन्तु हुडियाँ देयनदार, परमान जोग, धनी जोग, शाह जोग और जोतिमी भी हो सकती हैं।

देयनदार हुडिया—यह वह है जिसका भुगतान उसे दिवानेवाले व्यक्ति को किया जाता है। दर्शनी हुडियाँ देयनदार नहीं हो सकती हैं।

नाम जोग या फरमान जोग हुडिया—यह वह है जिसका भुगतान पानेवाले धनी के आदेशानुसार किया जाता है। इसमें वेचान की आवश्यकता पड़ती है।

धनी जोग हुडिया—यह वह होती है जिसका भुगतान केवल पानेवाले धनी को ही हो सकता है।

शाह जोग हुडिया—यह वह है जिसका भुगतान केवल किसी शाह को ही हो सकता है। शाह उस व्यक्ति या फर्म या कंपनी को कहते हैं जिसका नाम उस सूची में लिखा हो जो किसी स्थानीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रकाशित हुआ करती है। आधुनिक काल के बैंक या इनके अलावा जिसे हुडिया भरनेवाला अपनी जानकारी या जाँच के मुताबिक शाह मान ले उसे भी शाह कहते हैं।

जोखमी हुडिया—यह आजकल तो व्यापार का दग बदल जाने के कारण नहीं चलती किन्तु पहिले इसका बड़ा चलन था। मान लीजिये कि बनारस के किसी व्यक्ति के पास कलकत्ते की किसी फर्म का आर्डर आता है।

बनारस का व्यक्ति माल तैयार करके किसी ऐसे व्यक्ति के सुपुर्द कर देता था जो माल ले जाने का, उसका बीमा करने का और उसके सम्बन्ध की हुण्डी का मिति काटकर भुगतान करने के लिये (Discounting) तैयार होता था। यह हुंडी जोखमी होती थी। इसका लिखनेवाला, माल बेचनेवाला, ऊपरवाला, माल खरीदनेवाला और पानेवाला जिसे रखे भी कहते हैं वह होता था जो मिति काटकर इसका भुगतान करता था। मिति काटनेवाले न सिर्फ मिति का व्याज, बल्कि माल बनारस से कलकत्ते ले जाने का किराया और उतने समय की जोखिम की बीमे का प्रीमियम काट लेता था। यदि माल सुरक्षित कलकत्ते पहुँच जाता था तो ऊपरवाला धनी माल लेकर उसे सकार देता था और यदि माल रास्ते ही में खो जाता था तो हुंडी का भुगतान नहीं होता था और रखेवाले धनी का नुकसान होता था। इस तरह से यह हुंडी आजकल के विनिमय बिल, बिल्टो, बीमा पत्र और गिरवी पत्र (Letter of Hypothecation) चारों का काम करती थी। चूँकि इसका भुगतान केवल उसी शर्त पर होता था जब माल ऊपरवाले धनी को सुरक्षित अवस्था में दे दिया जाता था, यह बिला शर्त का पुरजा नहीं था। इसमें और विनिमय बिल में यह सैद्धान्तिक अन्तर है।

हुंडी का नमूना

सिद्ध श्री कानपुर शुभ स्थान श्री पत्नी भाई सीताराम लक्ष्मनदास जोग लिखी प्रयाग जी से माधुरीदास नरायनदास की राम राम बचने। अपरच हुंडी कीनी एक आप ऊपर रुपया ४००) आँकड़े चार सौ के नीमे दो सौ के देने पूरे देना। यहाँ रक्खा भाई पन्नालाल शम्भूनाथ के मिति चैत्र वदी पचमी सवत् २००३ से पूरे पचपन दिन पीछे दाम धनी जोग बिना जाना बाजार चलन हुंडी की रीति ठिकाने लगाय चौकन कर देना। मिति चैत्र वदी पचमी सवत् २००३।

पीठ पर

नीमे के नीमे रुपिया एक सौ का चौगुना पूरा रुपिया चौकन कर दीजो।

४००)

श्री पत्नी भाई सीताराम लक्ष्मनदास, कानपुर।

हुंडी लिखनेवाले भी उनके ऊपरवाले धनी के भुगतान न करने पर उनका

भुगतान करना देने के उद्देश्य से स्वीकारवाले को किसी ऐसे व्यक्ति के नाम चिट्ठी दे देने से जो उनका भुगतान कर दे। यह चिट्ठी जिसके निम्न कटलाती है।

दृष्टियों की स्वीकृति उन पर हस्ताक्षर करने नहीं होती, वरन् ऊपरवाला धनी उनका ब्योरा अपनी टुजी परी में कर लेता है।

यदि टुजी को जाती है तो उसकी प्रतिलिपियाँ मिल सकती हैं। पहिली प्रतिलिपि पैठ, दूसरी पर पैठ, तीसरी दर पैठ और चौथी पचासवीं अथवा सत्तानवाली फलती है।

टुजी का भुगतान करना उसे समझता और टुजी का भुगतान न करना उसे समझना करता है।

चेक और विनिमय विलों में अन्तर

चेक

(१) चेक एक पैरर के ऊपर लिखी जाती है।

(२) यह दर्शनी होती है।

(३) यह प्रायः देशी होती है।

(४) यह देश की ही करेंसी में लिखी जाती है।

(५) इसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।

(६) यदि यह उचित समय के अन्दर बैंक में नहीं ले जाई जाती तो यदि बैंक फल नहीं हो जाता तो उसके लिखनेवाले धनी का इस पर का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता।

(७) यदि लिखनेवाला धनी बैंक को इसे खड़ी रखने के लिये लिख देता है अथवा वह मर जाता है, अथवा पागल हो जाता है, अथवा दिवालिया घोषित कर दिया

विनिमय विल

(१) विनिमय विल किसी के ऊपर भी लिखे जा सकते हैं।

(२) यह दर्शनी और मुदती दोनों हो सकते हैं।

(३) यह देशी और विदेशी दोनों हो सकते हैं।

(४) विदेशी विनिमय विल विदेशी करन्सियों में भी हो सकते हैं।

(५) मुदती विलों में स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है।

(६) यदि यह उचित समय पर ऊपरवाले धनी के पास नहीं ले जाई जाती तो लिखनेवाला धनी तथा अन्य धनी इस पर के दायित्व से मुक्त हो जाते हैं।

(७) इसका ऊपरवाला धनी यदि इसका भुगतान नहीं करता है, तो लिखनेवाला धनी स्वयं इसका भुगतान कर देता है।

जाता है तो इसका भुगतान नहीं होता।

(८) इस पर रेखाङ्कन किया जा सकता है।

(९) यदि इस पर का वेचान जाली है तो बैंकर की कुछ वैधानिक वचत है।

(१०) इसके खड़े रह जाने पर इसके ऊपर जिन लोगों का दायित्व है उन्हें इसकी सूचना देने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

(११) इसकी नोटिङ्ग नहीं होती।

(८) इस पर रेखाङ्कन नहीं होता।

(९) स्थानीय बिलों पर के जाली वेचानों के सम्बन्ध में बैंकरों को कोई भी वैधानिक वचत नहीं दी गई है।

(१०) इसके खड़े रह जाने पर इसके ऊपर जिन लोगों का दायित्व है उन्हें सूचना देनी पड़ती है।

(११) इसकी नोटिङ्ग होती है। कभी-कभी तो इसके प्रोटेस्ट की भी आवश्यकता पड़ती है।

चेक और प्रणपत्रों में अन्तर

चेक

(१) चेक प्रायः जमा रखने-वाले (Creditor) के द्वारा लिखी जाती है।

(२) इसमें भुगतान करने का आदेश रहता है।

(३) इसमें दो से अधिक धनी भी हो सकते हैं।

(४) इसका ऊपरवाला धनी केवल बैंकर ही हो सकता है।

(५) यह प्रायः प्रयोग में आती है। अतः, यह विनिमय के माध्यम का बहुत काम करती है।

प्रणपत्र

(१) प्रणपत्र लिखनेवाले स्वयम् ऋणी (Debtors) होते हैं।

(२) इसमें भुगतान करने का प्रण होता है।

(३) इसमें दो ही धनी होते हैं।

(४) इसका भुगतान कोई भी धनी स्वयम् अथवा किसी के साथ और पृथक्-पृथक् भी कर सकता है।

(५) यह बहुत प्रयोग में नहीं आते। अतः विनिमय के माध्यम की तरह भी काम में नहीं आते।

(६) यह दर्जनी होती है। (६) यह दर्जनी और मुक्त होती है। दोनों ही सम्मते हैं।

विनिमय विलों और प्रणपत्रों में अन्तर

विनिमय विल

(१) इसमें दो ने अधिक धनी भी हो सकते हैं।

(२) उसे प्रायः लेनगा (Creditor) ही लिखता है।

(३) इसमें भुगतान करने का आदेश रहता है।

(४) यदि यह दर्जनी नहीं होता तो उसकी स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है।

(५) इसे किसी की माय रखने के लिए समझा जा सकता है।

(६) विदेशी विलों की कई प्रतिलिपियाँ एक माय लिखी जाती हैं।

(७) इसके ऊपरवाले धनी केवल मयुक्त रूप से ही इस पर दायी होते हैं।

(८) इसकी नोटिङ होती है और इसके विदेशी होने पर उसकी प्रोटेस्टिङ भी होती है।

(९) यह बहुत प्रयोग में आता है।

प्रणपत्र

(१) इसमें दो ही धनी होते हैं।

(२) इसे देनदार (Debtor) लिखता है।

(३) इसमें भुगतान करने का प्रण रहता है।

(४) इसकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती।

(५) यह किसी की माय रखने के लिये नहीं समझा जाता।

(६) यह अकेला ही लिखा जाता है।

(७) उसे लिखनेवाले इस पर मयुक्त रूप से और पृथक् रूप से दोनों प्रकार से दायी हो सकते हैं।

(८) इसकी नोटिङ और प्रोटेस्टिङ की आवश्यकता नहीं पड़ती।

(९) यह बहुत अधिक प्रयोग में नहीं आता।

विनिमय विल और हुण्डी में अन्तर

विनिमय विल

(१) इसमें केवल आवश्यक बातें रहती हैं।

(२) इसकी भाषा निश्चित है।

हुण्डी

(१) यह एक पत्र के रूप में होता है और इसमें राम राम, इत्यादि भी लिखा रहता है।

(३) यह हमेशा बिला शर्त होता है।

(४) इसमें ऊपरवाले धनी का नाम नीचे बाँयें कोने पर दिया होता है।

(५) लिखनेवाले धनी का नाम इसमें नीचे दाहिने कोने पर दिया रहता है।

(६) इसमें धन की रकम दो अथवा अधिक से अधिक तीन बार दी होती है।

(७) इसकी स्वीकृति इसी पर हस्ताक्षर करके की जाती है।

(८) विदेशी बिलों की सभी प्रतिलिपियाँ एक साथ ही तैयार कर ली जाती हैं और भिन्न-भिन्न ढाकों से भेज दी जाती हैं।

(९) यह ससार भर में सब जगह प्रयोग में आते हैं और इसी से देशी तथा विदेशी दोनों हो सकते हैं।

(१०) यह अच्छा विनियम साध्य पुजो के विधान के द्वारा शासित होते हैं।

(११) इनके खड़े रह जाने पर इनकी नोटिङ्ग और कभी-कभी प्रोटेस्टिङ्ग भी होती है।

(२) इसकी भाषा स्थानीय चलन के अनुसार बदलती-बदलती रहती है।

(३) यह किसी शर्त की भी हो सकती है, जैसे जोखमी हुई।

(४) इसमें ऊपरवाले धनी का नाम सिरनामे में ही दिया रहता है। और बाद में इसकी पीठ पर दिया रहता है।

(५) इसमें लिखनेवाले धनी का नाम सिरनामे ही में दिया रहता है।

(६) इसमें धन की रकम पाँच बार दी रहती है। अतः, उसमें जाल नहीं हो सकता।

(७) इसकी स्वीकृति के लिये केवल इसकी मुख्य-मुख्य बातें अलग नोट कर लेनी पड़ती हैं।

(८) इसकी प्रतिलिपियाँ केवल माँगने पर ही की जाती हैं। इसकी चार प्रतिलिपियाँ हो सकती हैं।

(९) यह केवल भारतवर्ष ही में प्रयोग में आती हैं और इसी से केवल देशी होती हैं।

(१०) यह स्थानीय चलन के अनुसार शासित होती हैं।

(११) इनकी नोटिङ्ग और प्रोटेस्टिङ्ग नहीं होती।

विनियम बिल और हुन्डियों में समानता

(१) दोनों में तीन धनी होते हैं।

(२) दोनों दर्जनी ची-मुहती दोनों हो सकते हैं। दोनों में मुहती होने की प्रकृत्या में धन के प्रमाण स्थाय्य लगता है।

(३) दोनों न लिखनेवाले धनी की माय के लिये स्वीकृति दी जा सकती है।

(४) दोनों का मिलि कटकर धन मिल जाता है।

(५) दोनों का बेचान किया जाता है।

(६) दोनों में पकने की तारीख पता लगाने के लिए कुछ गियायती दिन जोड़ने पड़ते हैं।

(७) दोनों ही एक निश्चित गत्तम गुगतान करने के लिये होते हैं।

अन्य मास-पत्र

बैंक ड्राफ्ट— यह भी एक प्रकार का विनिमय मिल ही है। जब प्राप्ति निकाल के बैंक भाग्यार्थी में नहीं भेजते तब बैंक ड्राफ्ट का काम हुडियों ही करती थीं। आजकल यदि किसी धनी को कश द्रव्य भेजना है तो वह किसी बैंक के एक बैंक ड्राफ्ट ले सकता है। यह बैंक ड्राफ्ट एक बैंक का उसके किसी अन्य प्राप्ति के ऊपर अथवा प्रदत्तिया बैंक के ऊपर एक प्रकार का दर्शनी मिल होता है, जिसमें यह लिखा होता है कि वह एक अमुक धनी को अथवा उसके आदेश के अनुसार किसी को एक अमुक रकम दे दे। द्रव्य भेजने में आजकल बैंक ड्राफ्ट का बहुत चलन हो गया है। कोई बैंक अपने किसी प्राप्ति को दर्शनी और देयनदार बैंक ड्राफ्ट नहीं करता।

बैंक ड्राफ्ट का नमूना

इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया

२०११५३०

इलाहाबाद १९४४

२०१०००

मॉगने पर

रुपया पहुँचे ठाम दीजिए। अथवा उनके आदेशानुसार
जोग देना—

इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया

इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया की ओर से

चम्बर

मैनेजर

IMPERIAL BANK OF INDIA

No 1720

Rs 1000

Allahabad 12th March 1965

On demand pay to Mr. Bal Krishna ~~Sarda~~
... ~~Sarda~~ .. or order

Rupees One thousand only value received

To For Imperial Bank of India,

Imperial Bank of India,

Bombay


Agent

डिविडेंड वारन्ट—जब कोई कम्पनी अपना डिविडेंड (हिस्से पर का मुनाफा) बाँटती है तब वह हिस्सेदारों को डिविडेंड वारन्ट भेज देती है । यह चेक की शकल का, अथवा बिल की शकल का अथवा रसीद की शकल का हो सकता है । चेक की शकल का होने पर यह कम्पनी-द्वारा लिखा जाता है और इसका ऊपरवाला कम्पनी का बक तथा पानेवाला हिस्सेदार होता है । ऐसा वारन्ट चेक की तरह ही माना जाता है अर्थात् इस पर रेखाङ्कन भी हो सकता है बिल के रूप का होने पर भी इसके वह घनी होते हैं जो चेक के रूप का होने पर होते हैं । इसके रसीद के रूप में होने पर यह पानेवाले (हिस्सेदार) की तरफ से रसीद होती है जिसपर बीस रुपया अथवा उससे अधिक की रकम होने पर स्टाम्प भी लगता है । यह कम्पनी की तरफ से निकाली जाती है और हिस्सेदार इस पर हस्ताक्षर करके इसे कम्पनी के बैंक में दे देता है ।

व्याज-पत्र (Interest Warrants)—सरकार और सम्मिलित पूँजीवाली कम्पनियों को जब अपनी उधार ली हुई पूँजी पर व्याज देना होता है तब वे व्याज-पत्र निकालते हैं । जब सरकार की ओर से व्याज दिया जाता है तब इसे केन्द्रीय बैंक निकालता है और यह उसी के ऊपर लिखा भी जाता है । जब सम्मिलित पूँजीवाली कम्पनियाँ इसे निकालती हैं तब यह उनके अपने-अपने बैंकों के ऊपर लिखे जाते हैं । जब इसे कोई केन्द्रीय बैंक अपने ही ऊपर करता है तब यह चेक के रूप में नहीं होता ।

सरकारी बिल (Treasury Bill)—यह एंग्लो-इंडियन और भारतीय बैंकों में निम्नलिखित जाते हैं। भारत में इसे केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों निम्नलिखित हैं। यह एक लघुसमय का ऋण है जिसकी अवधि प्रायः तीन मास होती है। बिना बैंक के किसी विभाग के सभी दफ्तर और उच्च शाखाएँ 'कान डिपॉजिट को छोड़कर' इसे बैंक से अथवा मध्यमालीन से ही निकाला है। जब इसे निकालना होता है तब एक सूचना-दाग जिसमें सूचना सभी शाखाओं दी रहती है इसके लिए बैंक में गाये जाते हैं। बैंक के प्रायः सभी शाखाओं में सरकारी बिलों की शर्तों का, उनकी रकम और दर का खुलासा रखा जाता है। दर प्रत्येक शी गवये के लिये रुपये, पानों और पैसों में दी रहती है। बिना सूचना सूचना में लेना है यदि उतने से अधिक के बैंक आ जाते हैं तो उनके अनुपात के हिसाब में बैंकनी दी जाती है। किसी धनी की बैंकनी पचीस हजार रुपये में कम की नहीं होती है। सरकारी बिल पचीस हजार, एक लाख, पाँच लाख, दस लाख और पचास लाख रुपये के होते हैं। जब सप्ताह के बीच में रुद्ध चालू करना होता है तब यह उसी दर से चालू कर दिये जाते हैं जो दर ठम सप्ताह के स्वीकृति बैंकों की होती है। इन सरकारी पत्रों की अवधि भी जाने पर इनका भुगतान रिजर्व बैंक द्वारा ही हो जाता है।

साख-पत्र (Letters of Credit)—साख-पत्र कई प्रकार के होते हैं। एक तो यह गश्ती (Circular) अथवा साधारण (General) हो सकते हैं। दूसरे यह चालू (Running) और विशेष हो सकते हैं।

गश्ती साख-पत्र (Circular Letters of Credit)—जब किसी व्यक्ति को कई स्थानों पर रुपये की आवश्यकता पड़ने की सम्भावना रहती है तब वह गश्ती साख-पत्र लेता है। इसमें एक रकम दी होती है जिस हद तक पानेवाले को किसी एक अथवा कई स्थानों से रकम लेने का अधिकार रहता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को यूरोप के कई शहरों में घूमना है और उसे सब मिलाकर पाँच हजार पाँच की आवश्यकता है जिसको वह थोड़ा थोड़ा करके यूरोप के बड़े-बड़े शहरों में लेना चाहता है। अतः, यदि उसके पास गश्ती साख-पत्र है तो वह जहाँ चाहे वहाँ जिसने ऐसा साख-पत्र निकाला है उसकी किसी शाखा में अथवा उसके किसी अदतिये के यहाँ उसे दिखाकर अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार

द्रव्य प्राप्त कर सकता है। द्रव्य देनेवाला जितना रुपया देता है उसे साख-पत्र पर लिख देता है जिससे पूरी रकम जितनी उसमें लिखी है उससे अधिक न हो जाय।

साधारण (General) साख-पत्र—यह साख-पत्र किसी विशेष व्यक्ति के नाम रहता है जो एक निश्चित रकम तक भुगतान दे सकता है। जो माल खरीदना चाहते हैं उन्हें भी उनके अदतिये के नाम ऐसा पत्र मिल जाता है जिससे कि अदतिया उन्हें माल दे देता है और उसके लिये साख-पत्र लिखनेवाले के ऊपर जो प्राय कोई चैक होता है, विल अथवा हुडी कर लेता है।

चालू (Running or Revolving) साख-पत्र—इस साख-पत्र में एक निश्चित रकम दी होती है जिस तक द्रव्य मिल जाता है और जिसकी वाजसी पर फिर भी द्रव्य मिल सकता है। अतः, यह बराबर चालू रहता है।

विशेष साख-पत्र—इसमें एक विशेष रकम दी रहती है जिस तक एक बार द्रव्य मिल जाता है। इसके भुगतान के बाद फिर द्रव्य नहीं मिल सकता। यदि आवश्यकता पड़े तो एक दूसरा साख-पत्र लिखवाना पड़ता है।

आई० ओ० यू० (I O U)—यह पुर्जा अंग्रेजी के ऐसे तीन शब्दों के उच्चारण के नाम से विख्यात है जिसके अर्थ हैं—मैं तुम्हारा देनदार हूँ। इसमें दाहिनी ओर लिखनेवाले का पता और लिखने की तारीख होती है। फिर उसके बाद बाईं ओर जिसका ऋण चाहिये उसका नाम, पता देकर बीच में आई० ओ० यू० शब्दों के साथ-साथ रकम दी होती है और अन्त में दाहिने किनारे पर फिर लिखनेवाले का हस्ताक्षर होता है।

औद्योगिक साख-पत्र—औद्योगिक कम्पनियों अपने हिस्से और ऋण पत्र निकालती हैं, उन्हें औद्योगिक साख-पत्र कहते हैं।

सरकारी साख-पत्र (Government Securities)—जब सरकार दार्धकालीन ऋण लेती है तब वह सरकारी साख पत्र निकालती है। ये सरकारी साख-पत्र कई शकल के हो सकते हैं, जैसे स्टॉक सर्टिफिकेट्स (Stock Certificates) प्रमिसरी नोट्स (Promissory Notes) और

देखना-गणना (Bearer Bonds) । एक प्रभार के साथ या दूसरे प्रभार के साथ-साथ में परिवर्तिता होने का मकसद है । डॉ. स्ट्राफ और प्रभारों के साथ पर देखना-गणना नहीं किये जाते । स्ट्राफ और देखना-गणना दोनों पर तो उन्हें भेजे बिना भी व्यापार किया जाता है किन्तु प्रभार पत्रों पर केवल उन्हें भेजने पर ही व्यापार मिलता है ।

प्रश्न

(१) 'भाग्य से आप क्या समझते हैं ? यह क्या काम करता है ? उसके कौन-कौन से रूप हैं ? उससे कौन-कौन से लाभ तथा कौन-कौन सी हानियाँ हुई हैं ?

(२) साथ उत्पत्ति का साधन नहीं है वरन् उसकी कार्यक्षमता बढ़ाता है,' उपरोक्त का विवेचना कीजिये ।

(३) विनिमयसाधन पुर्जे से आप क्या समझते हैं ? विनिमय साध्यता और हस्तांतरण से क्या कोई भेद है ? एक विनिमयसाध्य पुर्जा अविनिमय साध्य कैसे बनाया जा सकता है ?

(४) चेक की परिभाषा बताइये और उसका विश्लेषण कीजिये । चेक लिखते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ?

(५) ऐसे कौन-कौन से तरीके हैं जिनसे एक चेक अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है ?

(६) अधिकारी, मूल्य दिये हुये पुर्जों का अधिकारी और चलन के अनुसार अधिकारी में क्या भेद है ?

(७) चिह्नित चेक से आप क्या समझते हैं ? चेक चिह्नित कब बनाये जाते हैं ?

(८) विनिमय विल की परिभाषा बताइये और एक नमूना बनाइये । इसे लिखते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ?

(९) देशी और विदेशी विलों में आप कैसे विभेद करेंगे ।

(१०) क्या विनिमय विलों पर स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है ?

स्वीकृति कैसे दिखलाई जाती है ? विभिन्न प्रकार की स्वीकृति के विषय में बताइये ।

(११) विनिमय विलों के कौन-कौन से धनी होते हैं ? उनमें से प्रत्येक के दायित्व का सक्षेप में दिग्दर्शन कराइये ।

(१२) विलों के सम्बन्ध के निम्नलिखित ण्डों के विषय में बताइये—(१) नोटिङ्ग, (२) प्रोटेस्टिङ्ग, (३) साख के लिये सकारना और (४) विशेष परिवर्तन ।

(१३) प्रण-पत्र किसे कहते हैं ? एक ही व्यक्ति का प्रण-पत्र सयुक्त प्रण-पत्र और सयुक्त तथा अलग-अलग जिम्मेदारी के प्रण-पत्र से आप क्या समझते हैं ?

(१४) हुण्डी किसे कहते हैं ? विभिन्न प्रकार की हुण्डियों के बारे में बताइये ।

(१५) एक बिल चेक, प्रण-पत्र और हुण्डी के किन-किन बातों में विभिन्न हैं और हुण्डी से किन-किन बातों में उसकी समानता है ?

(१६) निम्न पर छोटी-छोटी टिप्पणियाँ लिखिये—(१) बैंक ड्राफ्ट, (२) लाभ-पत्र (Dividend Warrant), (३) सरकारी बिल (Treasury Bill), (४) सरकारी साख-पत्र और (५) औद्योगिक साख-पत्र ।

(१७) साख-पत्रों (Letters of credit) से आप क्या समझते हैं ? ये कितने प्रकार के होते हैं ? प्रत्येक के विषय में अच्छी तरह से समझाइये । इनकी क्या आवश्यकता पड़ती है ?

अध्याय ६

बैंकर का ग्राहक से सम्बन्ध

बैंकर का ग्राहक से क्या सम्बन्ध है यह बात समझने के लिये हमें पहिले यह समझ लेना चाहिये कि बैंकर किसे कहते हैं और ग्राहक किसे कहते हैं । जहाँ तक बैंकर का प्रश्न है वह तो हम पहिले अध्याय ही में देख चुके हैं । अब रह गया ग्राहक का प्रश्न । ग्राहक उसे कहते हैं जो किसी बैंक से निय-

मित बैंकिंग के व्यवसाय में सम्बन्ध रखने वाले लेन-देन बराबर करना रहता है और क्योंकि इस नियमित बैंकिंग के व्यवसाय में पैसल रकम ही जमा और उसे निकालना ही सम्मिलित है, इसके यह अर्थ है कि बैंकर के यहाँ उत्तम चालू खाता होना चाहिये। जिनके अन्य प्रकार के खाते होते हैं अथवा जो नियमित बैंकिंग के तो नहीं बल्कि उसी के महत्त्व अन्य प्रकार के बैंकिंग के व्यवसाय से सम्बन्धित लेन देन करते हैं वे माहक नहीं कहे जा सकते। नियमित बैंकिंग के व्यवसाय के यह अर्थ नहीं हैं कि उनके लिये कुछ समय बीत गया हो। जैसा कि एक मामले में निर्दिष्ट हो चुका है कि यदि उन्नी दिन भी हिसाब खोला गया हो जिस दिन के लेन-देन के सम्बन्ध में कोई भगड़ा है तब भी वह माहक माना जायगा।

कोई भी व्यक्ति (१) एक चालू खाता (Current Account), (२) एक स्थायी खाता (Fixed Deposit Account), (३) एक बचत खाता (Savings Bank Account), इत्यादि खोल सकता है।

(१) चालू खाता खोलना--जब कोई व्यक्ति किसी बैंक में चालू खाता खोलना चाहता है तब उसका उक्त बैंक से बैंक के किसी परिचित व्यक्ति द्वारा परिचय कराया जाता है। खाता खोलने के लिये प्रायः एक छपा हुआ प्रार्थना-पत्र भरना पड़ता है जिसमें परिचय करानेवाले व्यक्ति के

1 A customer 'must have recognisable course of habit of dealing in the nature of the regular banking business and as the transactions peculiar to regular banking business' consist of only deposit and withdrawal, a customer must have a current account with a banker. Persons having other accounts or doing business ancillary or allied to regular banking business are not customers of the bank. The use of the word 'regular' in the above definition does not in any way suggest that some period must elapse after opening an account before one can be entitled to be called a customer. In the case *Commissioner of Taxation vs English Scottish and Australian Bank, Limited*, it has been laid down that 'customer' signifies a relationship in which duration is not of the essence, and includes a person who has opened an account on the day before paying in a cheque to which he has no title.

हस्ताक्षर और पते के लिये भी स्थान होता है। ग्राहक को हस्ताक्षरों की कापी (Autograph Book) में अपने हस्ताक्षर के नमूने भी देने पड़ते हैं। हस्ताक्षर वैसा ही होना चाहिये जैसा कि ग्राहक स्वभावतः ही किया करता है। बात यह है कि उसके भविष्य के हस्ताक्षर इन हस्ताक्षरों से मिलाये जाते हैं, और यदि उनमें तनिक-सा भी अन्तर होता है तो बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। हमारे देश में बैंकवाले प्रति दिन अनेक चेक यह लिखकर कि उनके लिखनेवाले धनी के हस्ताक्षर नहीं मिलते हैं (Drawer's signature differs) वापस कर देते हैं। इतना करने के उपरान्त ग्राहक अपनी पहली रकम जमा करता है, और बैंकर उसे पाने के बाद एक पास बुक, एक जमा करने की किताब (Pay-in Book) और एक चेक बुक देता है।

पाम बुक में बैंकर के लेजर में जो ग्राहक का खाता (Account) रहता है उसकी प्रतिलिपि होती है, और उसे प्रायः उसके पास बनाने के लिये भेजना पड़ता है। ग्राहक को चाहिये कि वह बराबर उसकी जाँच कर ले और यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसे बैंकर को बता दे।

जमा करने की किताब में जमा करने के पर्चे (Pay-in-slips) होते हैं। जब रकम जमा की जाती है तब उसका ब्योग इस किताब में भर दिया जाता है। इसके भी दो भाग रहते हैं, रूप (Foil) और प्रतिरूप (Counterfoil)। रूप बैंक ही में रख लिया जाता है और प्रतिरूप कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित किताब के साथ ही ग्राहक को वापिस कर दिया जाता है। जमा करने की रकम के विषय में बाद में यदि कोई झगडा पड़ता है तो यही देखी जाती है।

चेक बुक में चेक के सादे फार्म होते हैं। वे नाम, रूप और डॉचे, इत्यादि में एक ही तरह के होते हैं। चालू खातों से रकम निकालने के लिये प्रायः चेक ही काम में आती है। वैसे तो इसके लिये लिखकर अलग से भी आदेश दिया जा सकता है, किन्तु जाल से बचने के लिये और समानता की दृष्टि से बैंक चेक का प्रयोग ही अधिक पसन्द करते हैं। चेकों के लिये कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। जब एक चेक बुक की सब चेके काम में आ जाती हैं तब दूसरी चेक बुक मिल जाती है। इसके लिये एक प्रार्थना-पत्र भेजना पड़ता है। प्रायः प्रत्येक चेक बुक के अन्त में यह प्रार्थना-पत्र दिया रहता है जिसे भरकर बैंक को भेज दिया जाता है।

(२) स्थायी खाता खोलना—इस खाते में द्रव्य जमा करने पर ग्राहक को एक जमा की रसीद (Deposit Receipt) मिलती है जो हस्तान्तरित

नहीं की जा सकती। जिस अवधि के लिये द्रव्य जमा किया गया है उसमें जीत जाने पर ग्राहक यह रकम एक जो वापिस कर देता है और उससे व्याज सहित अपना द्रव्य वा जाता है। हाँ, यदि वह इसे फिर से जमा करना चाहता है तो उसे एक नए जमा की रसीद मिल जाती है। श्रवधि जीतने के पहिले इस खाते से कोई रकम नहीं निकाली जा सकती। हाँ, यदि ग्राहक को घन की आवश्यकता है तो वह अपनी जमा की जमानत पर बैंक ने श्रृण ले सकता है। कभी-कभी जो श्रवधि जीत गई है उसका व्याज छोड़ देने पर यह रकम वापिस भी कर दी जाती है इस पर व्याज केवल निश्चित श्रवधि का ही मिलता है। उनका जीत जाने पर यदि रकम फिर से नहीं जमा कर दी जाती है प्रथवा निकाल ली जाती है तो व्याज की हानि होती है।

(२) वचत गाना गोलना — यह खाता भी चालू खाते ही कि तरह एक प्रार्थना-पत्र देन पर खुलता है और इसमें भी हस्ताक्षर का नमूना देना पड़ता है। साथ ही इसमें भी ग्राहक को एक पास बुक और किसी-किसी बैंक में एक जमा करने की किताब (Pay-in-Book) और चेक बुक भी मिलती है। जब जमा करने की किताब और चेक बुक नहीं मिलती, तब जमा करने और निकालने के लिये साधारण कार्म प्रयोग में लाये जाते हैं और ऐसे श्रवसरो पर पास बुक भी ठीक करवानी पड़ती है। महीने में जो सत्रसे कम बाकी रहती है उस पर इत्तम महीने भर का व्याज मिलता है।

अब हम बैंकर के ग्राहक से सम्बन्ध के मुख्य-विषय पर आ सकते हैं। यह सम्बन्ध कई प्रकार के होते हैं। अपनी सुविधा के लिये इन्हें हम तीन वर्गों में बाँट सकते हैं — (१) मुख्य, (२) सहायक, और (३) विशेष ।

मुख्य सम्बन्ध

१। एक बैंकर और ग्राहक के बीच का मुख्य सम्बन्ध देनदार और लेनदार का होता है। प्रायः ग्राहक यह सम्बन्ध बैंकर के पास एक रकम जमा करके स्थापित करता है। ऐसी अवस्था में बैंकर तो देनदार और ग्राहक लेनदार होता है। किन्तु कभी-कभी बैंकर अपने ग्राहक को कुछ रकम उधार दे देता है श्रववा उसकी जितनी रकम उसके पास जमा है उससे अधिक निकालने की उसे आज्ञा दे देता है। ऐसी अवस्था में वह लेनदार और ग्राहक देनदार हो जाता है। जो रकम बैंक के पास जमा की जाती है वह उसके पास धरोहर (Trust) के रूप में नहीं रखी जाती। वह उसे उधार दी जाती है जिससे वह जिस प्रकार चाहे उसे अपने काम में ला सकता है। हाँ, कभी-कभी यह रकम

धरोहर के तौर पर भी रखी जाती है। मद्रास के एक फैसले में¹ यह घोषित किया गया था कि यदि किसी बैंक को कोई रकम किसी कम्पनी के कुछ हिस्से खरीदने को दी जाती है, और बैंक कुछ हिस्से खरीद लेता है किन्तु पूरी खरीद करने के पहिले फेल हो जाता है तो वह शेष रकम का धरोहरी माना जायेगा और उसे ग्राहक को वह रकम पूरी की पूरी वापिस करनी पड़ेगी। किन्तु इस फैसले में और वहीं के एक अन्य फैसले में² जो अन्तर है उसे मली भाँति समझ लेना चाहिये। इस दूसरे फैसले में जिसमें ग्राहक की रकम बैंक के खाते में पहिले ही से थी, ग्राहक ने बैंक से उस रकम के कुछ अंश के सात-अध खरीदने को कहा था और बैंक ने ऐसा करने की स्वीकृति भी दे दी थी, किन्तु ऐसा करने के पहिले ही वह फेल हो गया था यह फैसला दिया गया कि बैंकर जमा की रकम के किसी अंश के लिये भी धरोहरी नहीं है। यदि बैंकर को उसके ग्राहक से चेक और विनिमय बिल वसूली के लिये प्राप्त होते हैं, तो यदि परस्पर कोई विशेष बात नहीं ते हो गई है तो वह वसूली की रकम बैंकर के पास धरोहर नहीं बरन् ऋण के तौर पर समझी जायेगी।

इस सम्बन्ध की कुछ विशेषताये—बैंकर और ग्राहक के बीच में जो यह सम्बन्ध है उनकी कुछ विशेषताये हैं जो साधारण लोगो के इस सम्बन्ध में नहीं हैं। प्रथम तो बैंकर के पास जब कोई रकम जमा कर दी जाती है तो वह जब चाहे तब उसे ग्राहक (लेनदार) को वापिस नहीं कर सकता है। साधारण लोगो के पारस्परिक ऋणी जब चाहे तब लेनदार को रकम वापिस कर सकते हैं। एल० जे० अटकिन (L J Atkin) ने इसे एक फैसले में³ बहुत ही स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने यह कहा था कि बैंकर और ग्राहक के बीच में जो सम्बन्ध होता है उसकी एक शर्त यह रहती है कि उचित सूचना दिये बिना बैंकर ग्राहक का हिसाब बन्द नहीं कर सकता। दूसरे, हमी फैसले में यह भी उपलब्धित था कि भारतवर्ष में खातों के तीन वर्ष तक और इंग्लैंड में छह वर्ष तक सुप्त पड़े रहने पर साधारण ऋणों की तरह उनमें अवधि बीत जाने के कारण अदालत की सहायता न मिल सकने का नियम (Statute of Limitations) नहीं लागू हो सकता। सत्य तो यह है कि बैंकों ने कभी इस नियम का लाभ उठाने का विचार ही नहीं किया क्योंकि इनसे उनकी सत्त्व बिगड़ जाने का डर रहता है। तीसरे, इस अवस्था में बैंकर और

¹ Official Assignee of Madras vs I W. Irwin

² Official Assignee of Madras vs D Rajaram Aiyar

³ Joachimson vs Swiss Bank Corporation

उसके ग्राहक के बीच में यह निश्चितता रहता है कि बैंकर वह रकम ग्राहक की आशा के अनुसार देगा। प्रायः यह आशा चेक पर लिखी जाती है। यदि बैंकर जाल के कारण, प्रत्यक्ष मिथ्या वर्णन के कारण अथवा गतती के कारण साक्षात् के विरुद्ध भुगतान कर देता है तब वही उसका दायी होता है। हाँ, जहाँ पर उसकी स्थिति वैधानिक रूप में सुरक्षित कर दी गई है वहाँ की बात तो दूसरी है। कुछ विशेष परिस्थितियाँ छोड़कर वह अपने ग्राहकों की चेक डिशोनर (Dishonour) को नहीं कर सकता है। एक बात अग्रज्य है कि बैंकर अपने ग्राहक के प्रति ही दायी रहता है। अन्य किसी के प्रति अर्थात् बैंक के अधिकारी के प्रति नहीं। चौथे और अन्तिम बैंक को ग्राहक की उसके ऊपर जो रकम बाँकी है उसे गोपनीय रखना पड़ता है। वह अपने हिमात्र के विषय में किसी को नहीं बता सकता। हाँ, कभी-कभी उसे ऐसा करना पड़ता है। उदाहरण के लिये निम्न परिस्थितियों ली जा सकती हैं—

(अ) जब अदालत उसे ऐसा करने के लिये मने। यह प्रायः सभी होता है जब ग्राहक अदालत द्वारा किसी का श्रेणी (Judgment debtor) मान लिया जाता है।

(२.) जब ग्राहक स्वयं ही उसे ऐसा करने की आशा दे देता है। यह आशा स्पष्ट और उपलब्ध दोनों में से कोई भी हो सकती है।

(३) जब ऐसा करना उसके स्वयं के हित में आवश्यक हो जाता है। मान लीजिये कि उसके और ग्राहक के बीच में अदालत चल रही है। इस सम्बन्ध में उसे अदालत के नामने ग्राहक का साक्षात् रखना पड़ता है।

(४) जब यह जनहित के लिये आवश्यक हो जाता है। वास्तव में उसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। अतः, बैंकर को यह निश्चित करना पड़ना है कि उसे क्या क्या ऐसा करना चाहिये।

हाँ, वह जब कोई उनके ग्राहक के साथ व्यापार करने के ध्येय से उसकी स्थिति के विषय में जानना चाहता है अवश्य उनके हिमात्र की माधुर्य स्थिति बता सकता है। किन्तु हमसे उसे बहुत होशियारी करने की आवश्यकता पड़ती है।

बैंकों के लिये वैधानिक वचन—ऊपर इस बात का सकेत दिया जा चुका है कि बैंकों को चेकों के भुगतान के सम्बन्ध में विधान द्वारा कुछ वचन दी गई हैं— यह उन पर के ग्राहकों के हस्ताक्षर के, रकम के और बेचान के सम्बन्ध की हैं। बैंकों के पास उनके ग्राहकों के हस्ताक्षरों के नमूने रहते हैं जिनसे वह चेकों पर के उनके हस्ताक्षर उनके भुगतान करने के पहिले

मिला लेते हैं। यदि किसी ग्राहक का हस्ताक्षर जाली बना लिया गया है अथवा उसके वास्तविक प्रतिनिधि-द्वारा नहीं किया गया है तो जाल चाहे जितना साफ क्यों न हो बैंक उन पर के भुगतान के लिये ग्राहक को दायी नहीं बना सकता है। हाँ, इस व्यवस्था में एक अपवाद है और वह यह है कि बैंक यह प्रमाणित कर दे कि भुगतान ग्राहक की जानकारी में की गई असावधानी (Negligence imputable to customer) के कारण हुआ है। इस सम्बन्ध का कोई विधान तो नहीं है किन्तु यह स्थिति कुछ फैसलों-द्वारा स्पष्ट की जा चुकी है। सी० जे० वेस्ट ने यंग बनाम फ़ोट के मुकदमे के सम्बन्ध में यह न्याय किया था कि यदि बैंक ने ग्राहक के अपराध के कारण जितना द्रव्य देना था उससे अधिक दे दिया है तो वह उसके लिये दायी नहीं है। यद्यपि यह उस स्थिति के सम्बन्ध में अधिक लागू है जब ग्राहक अपनी असावधानी से चेक पर रकम लिखता है और वह आसानी से बढ़ा दी जाती है तो भी यह उस स्थिति के सम्बन्ध में भी लागू हो सकता है जब ग्राहक की असावधानी से उसके चेकों पर उसके हस्ताक्षर जाली बना दिये जायें। किन्तु ग्राहक की जानकारी में की गई असावधानी (Negligence imputable to a customer) और साधारण असावधानी (Mere carelessness) में अन्तर है। स्कल-फील्ड बनाम लैण्डसबरो के मुकदमे में^४ लार्ड हैल्सबरी ने अपने फैसले के सम्बन्ध में यह कहा था कि यदि ग्राहक अपने किसी काम द्वारा बैंक को कोई काम करके अथवा न करके कोई भुगतान कराने में सहायता देता है, तो यह स्पष्ट है कि वह अपना यह काम अथवा काम न करना बैंक के, जिसे वह घोखा देता है अथवा अपनी असावधानी से घोखा खाने की गुजाइश पैदा कर देता है, अहित में प्रयोग में नहीं ला सकता। ग्राहक के लिये यह भी आवश्यक है कि जैसे ही उसे यह मालूम हो जाय कि उसके हस्ताक्षर जाली बनाये गये हैं वह इस बात की बैंक को सूचना

4 In the case Scholfield vs Land as borough, Lord Halsbury during the course of his Judgment observed that if the customer by any act of his induces the banker to act upon the document, by his act or neglect of some act usual in the course of dealing between them, it is quite intelligible that he should not be permitted to set up his own act or neglect to the prejudice of the banker whom he thus misleads or by neglect permits to be misled

दे दे ताकि बैंक सावधान हो जाय। प्रान्डर बनाम मार्टिम बैंक लिमिटेड के मुकदमे में जहाँ प्राइमर को यह पता लग गया था कि उसकी पन्नी ने उसके चालू खाते से उसके हस्ताक्षर जाली प्रनाम्न कुछ चेम्बो का भुगतान ले लिया है और नौ महीने तक उसने यह बात छिपाये रक्खा, किन्तु जब यह मर गई और बैंक का उससे विरुद्ध कार्यवाही करने का अवसर निकल गया, तब उसने बैंक को सूचित किया यह निश्चय किया गया था कि बैंक गलत भुगतान ने लिये प्राइमर के प्रति दायी नहीं है।

बैंकों को जाली चेचानों पर भी भुगतान करने पर बचत दी गई है। हा, यह अवश्य है कि उन्हें चेम्बो का भुगतान करने में उचित सावधानी करनी चाहिये तथा भुगतान अच्छी नीयत में (In good faith), कोई असावधानी न करके (Without negligence) और अपने व्यवसाय के साधारण दौरान में (In the ordinary course of business) करना चाहिये। हमारे देश में अच्छे विनियमसाध्य पुलों के विधान की धरा (१) धारा में इसे बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया है। उसमें यह लिखा है, कि जहाँ पर आदेश के अनुसार चेम्बो का भुगतान करना है वहाँ पर यदि जिनसे भुगतान मिलता है, उनके चेचान उन्हीं के द्वाग अथवा उनकी ओर से किये हुये मालूम पड़ते हैं, तो यदि बैंक ने उचित रीति में भुगतान कर दिया है तो वह अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। विनियम विलों के अंग्रेजी विधान की ६०वीं धारा में भी यही सिद्धान्त दिया हुआ है। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि यदि वचत उन विलों के भुगतान के सम्बन्ध में लागू नहीं है जिनके भुगतान बैंकों द्वारा किये जाते हैं (Domestic Bills) अब इस प्रश्न का उत्तर देना कि कोई चेचान उसी घनी द्वारा अथवा उनकी ओर से किया गया मालूम पड़ता है अथवा नहीं कि जिसे उसे करना चाहिये था, बहुत ही कठिन है किन्तु बैंक इसका उत्तर अदालतों के इस सम्बन्ध के फैसले और चलन दृष्टि में रखकर अपनी साधारण बुद्धि के बल पर दे लेते हैं। इनका और अधिक विस्तार में अध्ययन हम आगे चलकर चेचान के तरीकों के सम्बन्ध में करेंगे। ऊपर जो शर्तें दी हैं अर्थात् अच्छी नीयत से (In good faith), असावधानी न करके (Without negligence) और व्यवसाय के साधारण दौरान में (In the ordinary course

* It lays down 'where a cheque payable to order purports to be endorsed by or on behalf of the payee, the drawer is discharged by payment in due course'

बैंकर का ग्राहक से सम्बन्ध

उसके भुगतान करने की मनाही कर देता है और बैंकर ने उसका भुगतान पहिले ही कर दिया है तो भी वह कठिनाई में पड़ जाएगा ।

(४) जब चेक पर रेखाङ्कन है और वह किसी बैंक के मार्फत नहीं आती है ।

(५) जब चेक छै माह या उससे अधिक पुरानी है ।

(६) घरोहर सम्बन्धी हिसाब के सम्बन्ध में भुगतान की रकम के उपयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह हो जाने पर भी जब तक वह सन्देह दूर नहीं हो जाता तब तक चेक का भुगतान नहीं किया जाता ।

(७) जब चेक की रकम के विषय में कोई सन्देह हो जाता है । शब्दों और अंकों की रकमें एक सी होनी चाहिये । यदि बैंकर चाहे तो वह शब्दों की रकम अथवा न्यूनतम रकम का भुगतान कर सकता है, किन्तु प्रायः वह ऐसी चेक वापिस कर देता है, चेक पर यदि कोई सशोधन किया गया है तो उसके साथ-साथ ग्राहक का हस्ताक्षर होना चाहिये ।

(८) जब ग्राहक के हिसाब में भुगतान करने के लिये पूरी रकम नहीं रहती । हाँ, यदि जमा की हुई रकम से अधिक निकालने की आज्ञा दी जा चुकी है तो उस सीमा तक चेकों का भुगतान करना ही पड़ता है । यह याद रखना चाहिये कि इस प्रकार के प्रवन्ध की अवहेलना पहिले से सूचना दिये बिना नहीं की जा सकती है । यदि बैंकर ने ग्राहक के पास बुक में बाकी निकालने में गलती कर दी है और उसके कारण उसकी इतनी रकम निकलती हुई मालूम पड़ती है कि चेक का भुगतान हो सकता है तो उसका भुगतान कर देना चाहिये और फिर ग्राहक से कमी की रकम मँगवा लेनी चाहिये ।

(९) जब ग्राहक स्वयम् किसी चेक का भुगतान रोक देता है । इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिये कि प्रत्येक बैंकर को अपने ग्राहकों के आदेश पूरी तरह से मानने चाहिये ।

(१०) जब ग्राहक दिवालिया अथवा पागल घोषित कर दिया गया है अथवा मर गया है ।

(११) जब किसी अदालत की ओर से कोई ऐसा आदेश (Garnishee order) प्राप्त हो गया है । मान लीजिये कि अ के ऊपर ब का रुपया चाहिये और ब को डिक्री (Decree) मिल गई है और साथ ही उसे यह मालूम है कि अ का अमुक बैंक में हिसाब है तो वह उस बैंक के ऊपर सुपुर्दगी

का एक प्रदालती हुकम (Garnishee order) निम्नलिखा मज्ना है। इस हुकम के यह अर्थ है कि बैंक अब तो उस समय तक रकमा न दे जिस समय तक प्रदालत उस रकम के सम्बन्ध में कोई आदेश न दे दे।

(१२) जब चेक अत्यधिक कट-मट गइ है।

चेक विरहृत करने के समय बैंक प्रायः निम्न कारण लिखते हैं --

(१) लिखने वाले धनी से पूछिये Refer to Drawer (R/D) इससे चेक की विरहृति का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। इसके फलज यह स्पष्ट होता है कि कोई न कोई ऐसी बात प्रसरण है जिससे बैंक का भुगतान नहीं किया गया है। प्रायः यह उन परिस्थिति में लिखा जाता है जब लिखने वाले धनी की फाफ़ी रकम उसके सम्बन्ध में नहीं रहती।

(२) प्रवन्ध नहीं किया गया (Not arranged) इससे यह अर्थ है कि जिस हिसाब में ऊपर चेक काटी है उसमें उसके भुगतान के लिये यथेष्ट रकम नहीं है। हाँ, यदि प्रवन्ध किया जाता तो हमारे हिसाबों में उसमें फाफ़ी रकम आ जाती, किन्तु प्रवन्ध नहीं किया गया है। यदि बैंक चारों तरफ़ हमारे हिसाब से भी भुगतान कर सकता है, किन्तु वह ऐसा करता नहीं।

(३) वसूलयानी अभी तक नहीं हुई है चेक फिर लाइयेगा (Effects not yet cleared please present again)। प्रायः यह देखा गया है कि ग्राहक अपने कुछ अधिकार पत्र बैंक को वसूली के लिये भेज देता है, और उन्हीं के बिना पर अपनी रकम यथेष्ट समझ कर चेक इत्यादि काट देता है। किन्तु यदि इस बीच में अधिकार पत्रों की बैंक में वसूली नहीं होती तो उसकी चेकों का भुगतान नहीं होता। अतः, बैंक यह लिख देता है कि वसूलयानी अभी तक नहीं हुई है, चेक फिर लाइयेगा।

(४) प्रवन्ध से अधिक है (Exceeds arrangement)—कभी कभी ग्राहक अपने खातों से रकमा प्राप्त करने का प्रवन्ध कर लेता है किन्तु यदि हतने पर भी उसकी चेक की रकम हतनी अधिक है कि उसका भुगतान नहीं हो सकता तो यह कारण लिख दिया जाता है।

(५) बाकी यथेष्ट नहीं है (Insufficient Funds)—यह कारण तो स्पष्ट ही है किन्तु बैंक प्रायः ऐसा नहीं लिखते।

(६) पूरी रकम नहीं प्राप्त हो पाई है (Full covers not received)—इसके भी प्रायः वही अर्थ है जो (५) के है।

(७) लिखने वाले धनी ने भुगतान रोक दिया है (Payment stopped by the drawer) यह कारण भी स्पष्ट ही है ।

(८) लिखने वाले धनी के हस्ताक्षर नहीं मिलते (Drawer's Signature Differs)—प्रत्येक बैंक के पास उसके ग्राहक के हस्ताक्षरों का नमूना रहता है । अतः, इसके यह अर्थ हैं कि चेक पर के उसके हस्ताक्षर नमूने से उसके हस्ताक्षरों के नहीं मिलते ।

(९) पाने वाले धनी का वेचान अपूर्ण है अथवा नहीं है अथवा अनियमित है अथवा अस्पष्ट है (Payees Endorsement is incomplete, Required / Irregular / Illegible)—यह भी स्पष्ट ही है । अनिश्चित स्थान पर प्रथम, द्वितीय, इत्यादि जैसा हो लिख दिया जाता है ।

(१०) वेचान का बैंक द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है (Endorsement Requires Bank's Guarantee Confirmation)—जब कोई चेक किसी बैंक द्वारा आती है तब यदि कोई वेचान अनियमित होता है तो बैंक द्वारा उसे प्रमाणित करवाया जाता है । अतः, ऐसी परिस्थिति में उपयुक्त कैफियत लिखी जाती है ।

(११) लिखने वाले धनी के हस्ताक्षर का आवश्यकता है (Drawer's Signature Required)—जब लिखने वाला धनी अपने हस्ताक्षर करना भूल जाता है तब यह कैफियत लिखी जाती है ।

(१२) चेक फटी है, अथवा पूर्वतिथीय है अथवा बहुत पुरानी हो गई है (Cheque is mutilated, Post-dated, Out of date)—फटी हुई चेक का भुगतान नहीं होता । यदि वह संयोग से फट गई है तो लिखने वाले धनी को उसे जोड़कर उस पर यह बात लिख देनी चाहिये ।

इसी तरह से यदि किसी चेक पर आगे की तारीख पढ़ी रहती है तो भी उसका भुगतान नहीं किया जाता । फिर जो चेक छै महीने अथवा उससे अधिक पुरानी हो जाती हैं, उसका भी भुगतान नहीं किया जाता ।

(१३) शब्दों और अङ्कों में लिखे हुये धन भिन्न-भिन्न हैं (Amount in words and figures differ)—इसमें जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है या तो शब्दों में लिखा हुआ धन या जो धन भी कम हो वह दे दिया जा सकता है किन्तु ऐसी चेक प्रायः उपर्युक्त कारण देकर वापिस कर दी जाती है ।

(१४) रेखांकित चेक किसी बैंक के मार्फत आनी चाहिए (Crossed cheque must be presented through a Bank)—यह कारण भी स्वयम् स्पष्ट है।

(१५) बखली की मोहर लगनी चाहिये (Clearing Stamp Required)—बखली करने वाले बैंक की अपनी माहर भी चेक पर पड़नी चाहिये। मत, यदि कोई चेक किसी बैंक द्वारा आती है और ठग पर उसकी माहर नहीं पड़ती तो यह कारण लिख दिया जाता है।

(१६) मजबूत पर लिखने वाले धनी के हस्ताक्षर की आवश्यकता है (Alteration requires drawer's confirmation)—यदि चेक पर तानेकना भी संशोधन किया जाता है तो उस पर लिखने वाले धनी के हस्ताक्षर होने हैं। ऐसा न होने पर चेक वापिस कर दी जाती है।

(१७) लिखने वाले धनी का स्वर्गवास हो गया है (Drawer deceased)—यह कैवियत तो स्पष्ट ही है।

(१८) लिखने वाला धनी दिवालिया घोषित कर दिया गया है (Drawer declared bankrupt)—यह कैवियत भी स्पष्ट ही है।

(१९) अदालत की निषेध आज्ञा प्राप्त हो गई है (Garnishee order served)—अदालत की निषेध आज्ञा प्राप्त हो जाने पर फिर चेक का भुगतान नहीं होता।

(२०) चेक टाइप में तैयार की गई है (Type written cheque)—ऐसी चेक का भुगतान प्रायः नहीं किया जाता।

चेक गलती से तिरस्कृत हो जाने पर बैंकर का दायित्व

एक किमी चेक को किसी विशेष कारण बिना नहीं तिरस्कृत करता। हाँ, यदि वह ऐसा गलती से कर जाता है तो उसे न केवल लिखने वाले धनी की हानि ही पूरी करनी पड़ती है वरन् उसकी मान-रानि के लिये भी कुछ देना पड़ता है। बात यह है कि जब किसी व्यापारी की चेक का भुगतान नहीं होता और विशेषतः हिसाब में यथेष्ट रकम न होने के कारण ऐसा नहीं होता तब उस व्यापारी की बढ़ी बदनामी होती है और जैसा कि सभी को शात है व्यापार में बदनामी बहुत ही खराब चीज है। मान हानि की रकम का निश्चय स्वयं अदालत करती है। वह यह देखती है कि उस स्थान के लोग चेकों का तिरस्कृत हो जाना हेतु दृष्टि से देखते हैं अथवा नहीं। वह यह भी देखेगी कि उस ग्राहक की कोई चेक पहिले कभी उसी प्रपराय के कारण तिरस्कृत हुई थी

अथवा नहीं। यदि ऐसा हो चुका है तो इस विस्कार से उसको कोई विशेष बदनामी नहीं समझी जायगी।

वैङ्क द्वारा भुगतान होने वाले बिलों के सम्बन्ध में वैङ्क का दायित्व, कभी-कभी ऊपर वाला धनी बिलों पर स्वीकृत देते समय उनके भुगतान का भी स्थान दे देता है। साधारणतः यह स्थान उसी बैंक का होता है। ऐसे बिल अंग्रेजी में डोमिस्टाइल्ड बिल (Domestic bill) कहलाते हैं। इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिये कि जब कि बैंको के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने ग्राहकों द्वारा काटे गये चेकों का भुगतान करे उनके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने ग्राहकों द्वारा स्वीकृत किये गये बिलों का भुगतान करें। हाँ, यदि यह किसी प्रकार भी पहिले से तै हो चुका है, तो अवश्य ही उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। कोई बैंकर ऐसी परिस्थिति में भी इनका भुगतान करने से केवल निम्न हालतों में मना कर सकता है —

(१) जब वह ठीक हालत में नहीं रहता।

(२) जब उसमें आवश्यक स्टाम्प नहीं लगा रहता। प्रत्येक मुदती बिल में प्रत्येक देश के विधान से निर्धारित कुछ न कुछ मूल्य का स्टाम्प अवश्य लगाना पड़ता है। हमारे ही देश में १३ जनवरी सन् १९४० के विधान के अनुसार एक वर्ष तक की अवधि के बिलों पर २ आना प्रति सहस्र रुपया तथा उसके अंश पर स्टाम्प लगाना पड़ता है।

(३) जब वह पकने की तरीख के पहले पेश किया जाय।

(४) जब उसमें कुछ विशेष सशोषण हो और उन पर ऊपर वाले धनी की सही न हो गई हो।

(५) जब ऊपर वाले धनी के हस्ताक्षर जाली मालूम पड़ते हों। प्रत्येक बैंकर को चाहिये कि वह उपर्युक्त हस्ताक्षरों को उसके पास जो हस्ताक्षरों के नमूने की कितान है उसमें जो उसके ग्राहक के हस्ताक्षर हैं, उससे मिला ले।

(६) जब पाने वाले धनी अथवा अन्य वेचानकर्त्ताओं के उम पर के हस्ताक्षर जाली मालूम पड़ते हों। इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिये कि जाली वेचानों के बिलों पर भुगतान कर देने पर बैंकों को उस तरह की कोई बचत नहीं दी गई है। वैसी जाली वेचानों के चेकों पर भुगतान कर देने पर दी गई है। प्रायः बैंकर बिल के अधिकारी से यह बात लिखवाकर अपनी बचत कर लेता है कि यदि कोई भी वेचान जाली होने के कारण वह दायी ठहराया जायगा तो उसकी क्षति वह पूरी करेगा।

(७) जब ऊपर वाला धनी जियालिया घोषित कर दिया जाता है। उसने स्वर्गपाश की हालत में भी रूबर को उसके उत्तराधिकारी की छद्दी प्राप्त कर लेनी चाहिये।

महायक सम्बन्ध

महायक सम्बन्ध दो प्रकार के होते हैं —

(१) आदत (Agency) के और (२) त्रुष्ट (Trust) के।

(१) आदत का सम्बन्ध

जब कोई बैंक अपने किसी ग्राहक के चेकों अथवा बिलों का भुगतान करता है तब उसके प्रदत्तिये (एजेंटि—Agent) का काम मगता है। अब, यदि वह कोई गलती करता है तो उसके लिये अपने मालिक (ग्राहक) के प्रति ही दायी समझा जाता है। हाँ, उने चेकों के भुगतान के सम्बन्ध में उनके जाली होने की हालत में अवश्य कुछ बचत दी गई है जिसमें हम पहिले ही अध्ययन कर चुके हैं।

फिर, हम यह भी जानते हैं कि वह अपने ग्राहकों की ओर से उनके चेकों, बिलों, प्रण-पत्रों, व्याज पत्रों, (coupons) लाभ बँटनी पत्रों, चन्दे, आयकर बीमा के प्रतिफल, इत्यादि की वसूली करता है। साथ ही वह उसकी तरफ से हिल्लो, रटाकों, ऋण-पत्रों और बाण्डों इत्यादि को खरीदता और बेचता है। इन सब परिस्थितियों में और अन्य बहुतसी परिस्थितियों में उसका और ग्राहक का सम्बन्ध फिर प्रदत्तिये और मुखिये का होता है और इसी कारण वर उनके बीच के अधिकार और दायित्व आदत के नियमों के अनुसार होते हैं। हाँ, हममें एक अपवाद है और वह एक रेखाङ्कित चेक और बैंक ड्राफ्ट के सम्बन्ध का है।

रेखाङ्कित चेक (Crossed Cheque)—यह वह चेक है जिसके ऊपर कुछ शब्दों के साथ-साथ अथवा वैसे ही दो आड़ी समानान्तर रेखाएँ खींच दी जाती हैं। इनका वह प्रभाव होता है कि ऐसी चेकों का भुगतान ऊपर वाला बैंक किसी बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी धनी को नहीं देता है। किसी चेक पर या तो साधारण या विशेष रेखाङ्कन किया जा सकता है।

साधारण रेखाङ्कन (General Crossing)—यदि किसी चेक के ऊपर कुछ शब्दों के साथ-साथ हाँ, किसी बैंक के नाम के साथ नहीं दो

आड़ी समानान्तर रेखायें खींची गई हैं तो वह रेखांकन साधारण रेखांकन होता है। इसके नमूने निम्नांकित हैं :—

1	2	3	4	5	6	7	8
	& Co	Not Negotiable	Not Negotiable & Co	Under one Hundred Rupees & Co	& Co Account payee only	Not Negotiable A/c payee only	Account payee only

बैंक ड्राफ्ट के वसूली के सम्बन्ध में अभी हाल ही में यह बचाव दिया गया है।

साधारण रेखांकन का यह प्रभाव होता है कि उस चेक का भुगतान ऊपर वाला बैंक अपने कटवरे पर किसी बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी घनी को नहीं देता। यदि कोई रेखांकित चेक किसी ऐसे घनी के पास आ जाती है जिसका किसी बैंक में हिसाब नहीं होता तो वह उसको वसूल करने के लिये अपने किसी ऐसे मित्र के नाम उसका ब्रेचान कर देता है जिसका किसी बैंक में खाता होता है।

विशेष रेखांकन (Special Crossing)—यदि किसी चेक के ऊपर के रेखांकन के अन्दर किसी बैंक का नाम दिया रहता है तो वह रेखांकन विशेष रेखांकन कहलाता है। इस तरह के रेखांकन का यह प्रभाव पड़ता है कि उसका भुगतान रेखांकन में दिये हुये बैंक को ही दिया जाता है। किसी चेक के रेखांकन के अन्दर केवल एक ही बैंक का नाम रहता है। हाँ, यदि बैंक उस चेक की स्वयं वसूली नहीं कर सकता तो अवश्य उस पर दूसरे वसूली करने वाले बैंक के नाम का रेखांकन कर दिया जाता है।

बैंकों को रेखांकित चेकों की वसूली के सम्बन्ध में किस

प्रसार का बचाव दिया गया है—वैसे तो यह कोई बँक अपने किसी ग्राहक को प्रोत्साहित करने की बसूली करता है जो उसकी निवृत्ति उसके प्रयत्नो की सी होती है। यद्यपि यदि उस चेक पर ग्राहक का अच्छा प्रतिकार नहीं रहता तो बसूली करने वाले बैंक ना भी अच्छा प्रतिकार नहीं करता किन्तु अच्छा प्रतिकार देने वाले पुर्ण व गम्भीर विभाग की १३१वीं प्राग-जीर विनियम तालिका के अन्तर्गत विभाग की ८२वीं धारा के अनुसार बैंक को उसके करने ग्राहक के लिये एक रेखांकित चेक की बसूली करने पर एक अन्तर्गत होना है। अच्छा प्रतिकार देने वाले पुर्ण के भारतीय विभाग की १३२वीं प्राग-निर्णयित है:—“यदि कोई बैंक अच्छी नीयत से सावधानी के साथ किसी रेखांकित चेक का बाँधे वह साधारण रेखांकित हो जायगा उसी के नाम का विशेष रेखांकित हो अपने ग्राहक के लिये भुगतान प्राप्त कर लेता है तो बाद में यदि वह भी प्रमाणित हो जाता है कि उस पर ग्राहक अविश्वस था तब भी वह उसके वास्तविक मालिक के प्रति केवल इस भुगतान को प्राप्त कर लेने के कारण ही ठीकी नहीं ठहराया जायगा।”

उपर्युक्त को स्पष्ट करने के लिये उनके साथ-साथ ही निम्न टीका भी दी हुई है:—

“इस धारा के सम्बन्ध में कोई बैंक चाहे वह भुगतान पाने के पहिले ही ग्राहक के हिसाब में वह रकम जमा कर दे अथवा नहीं जो भुगतान पाता है, वह अपने ग्राहक के लिये ही पाता है।”

यहाँ यह प्रश्न माद रहता चाहिये कि बैंक को वह बचाव केवल एक रेखांकित चेक की बसूली पर ही दिया गया है और वह भी उसके स्वयं के ग्राहक के लिये होने पर। यदि बसूली किसी खुली हुई चेक की अथवा किसी अन्य पुर्ण की हुई है (हाँ, इधर हाल ही में बैंक ट्राफिक की बसूली के सम्बन्ध में भी यह बचाव दे दिया गया है) अथवा बैंक के स्वयं के ग्राहक के लिये नहीं हुई है तो वह बचत नहीं मिलती। साथ ही उसे यह बसूली अच्छी नीयत से और सावधानी से भी करनी चाहिये। यदि कोई ग्राहक एक चेक जमा करके हिसाब खोलना चाहता है तो बैंक को उसके विषय में पूछ ताछ कर लेनी चाहिये। ऐसा न करने पर बैंक को उपर्युक्त बचत नहीं मिलती। लैटनरक बनाम टौड के मुकदमे में जिसमें एक चोर ने एक चेक पर उसके पाने वाले धनी के नाम का जाली बेचान किया था और फिर उससे एक बैंक

में हिसाब खोलकर उसे वसूल कराकर सारी रकम निकाल ली थी बैंक पर असावधानी करने का अपराध लगाया गया था और उससे सारा द्रव्य वापिस ले लिया गया था। सेण्ट जान के अभिभावकों और चार्लेज के बीच के मुकदमें में भी जिसमें कि चोर ने अपनी पहचान के लिये फिलरौय स्कायर निवासी एक मि० शल्फ का नाम दिया था जिसे बैंक जानता भी नहीं था और जो मिल्कुल जाली था बैंक के ऊपर असावधानी का अपराध लगाया गया था।

वसूल करने वाले बैंक की चलन के अनुसार अधिकारी की स्थिति—चेक, विनिमय बिल और प्रण-पत्र विनिमय साध्य पुर्जे हैं अर्थात् इनकी मुख्य विशेषता यह है कि इनका अधिकार इनका बेचान करके अथवा केवल इन्हें हस्तान्तरित करके हस्तान्तरित किया जा सकता है और हस्तान्तरकृत अगर अच्छी नीयत से किसी प्रतिफल की बिना पर, उचित रूप में और इनके पकने की तारीख के पहिले इन्हें प्राप्त कर लेता है तो चाहे उसने इन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से ही क्यों न पाया हो जिसका इन पर अच्छा अधिकार नहीं है तब भी उसका अधिकार तो इन पर अवश्य ही अच्छा माना जायगा और वह इनकी वसूली के लिये इनके लिए दायी धनियों के ऊपर अपने नाम से नालिश कर सकता है। अतः, यदि कोई वसूली करनेवाला बैंक अपनी इस स्थिति पर निर्भर रहना चाहता है अर्थात् अपने ग्राहक को वसूली के लिये आई हुई चेक का वसूली के पहिले ही मूल्य देकर वह उसका अच्छी नीयत से मूल्य के विनिमय में किसी सन्देह के बिना प्राप्त करने वाला अधिकारी या चलन के अनुसार अधिकारी होने का दावा करता है तो वह ऐसा कर सकता है। किन्तु यदि उसने उसका मूल्य नहीं दिया है, अथवा उस पर के रेखाङ्कन के अन्दर अविनिमय साध्य (Not Negotiable) लिखा हुआ है तो यदि उस पर किसी भी बेचानकर्ता का जाली बेचान है तो उसका उपर्युक्त दावा नहीं चल सकता। अतः, जिस वैधानिक वचन का पहिले वर्णन किया जा चुका है वह वसूली करनेवाले बैंकों के लिये इस विशेष स्थिति में बहुत ही उपयोगी है।

(२) धरोहरी का सम्बन्ध

बैंक अपने ग्राहकों के धरोहरी भी होते हैं। इसका एक उदाहरण तो इस अध्याय के प्रारम्भ ही मुख्य सम्बन्ध के शीर्षक के अन्तर्गत दिया जा चुका

है। हम यह भी जानते हैं कि वे अपने गारकों की बहुमूल्य पगुडें, इत्यादि भी सुरक्षित रखा में रखने के लिये प्रायः तन्ते हैं। तब यह उन काम के लिये कुछ प्रतिफल नहीं लेते हैं तब तो वह मुक्तो धरोहरी की स्थिति में रहते हैं और धरोहर की वस्तु की क्षति हो जाने पर उनके लिये केवल एक बहुत बड़ी असावधानी (Gross negligence) करने पर ही दायी ठहराये जाते हैं। और जब यह इसके लिये कुछ प्रतिफल लेते हैं तब एक प्रतिफल पाये हुये धरोहरी की स्थिति में रहते हैं और ननिष्क भी असावधानी करने पर धरोहर की वस्तु की क्षति हो जाने पर उनके लिये दायी ठहराये जाते हैं। किन्तु यह अंग्रेजी विधान के अनुसार व भारतीय विधान में सुप्री धरोहरी और प्रतिफल पाये हुये धरोहरी की स्थिति में कोई अन्तर नहीं है। उनके अनुसार तो एक धरोहरी को उसके पास जो धरोहर रक्खा जाती है उसके सम्बन्ध में उतनी ही सावधानी रखनी पड़ती है जितनी कि एक साधारण विचारवान मनुष्य उन्हीं स्थितियों में अपने स्वयं के उनी के परिणाम, किन्तु और मूल्य के माल के सम्बन्ध में रखता है और यदि उसने ऐसा किया है तो धरोहर हो जाने, नष्ट हो जाने अथवा खराब हो जाने पर उसकी क्षति का दायी नहीं ठहराया जा सकता है। किन्तु यह वचन गलत सुपुर्दगी के सम्बन्ध में नहीं दी गई है। प्रायः बैंक धरोहर की वस्तु मुद्ररन्ध स्थिति में रोकते हैं और उनका एकमात्र दायित्व यही है कि वह उन्हें उसी मुद्ररन्ध स्थिति में या तो उसे रखने वाले को या उनके आदेश के अनुसार वापिस कर दें। कई मुकदमों में यह फैला किया जा चुका है कि उसकी सुपुर्दगी किसी अनधिकृत व्यक्ति को कर देने में वह गलत सुपुर्दगी होगी और वह किसी हालत में भी खदानत (Conversion) अर्थात् अमानत को अपने प्रयोग में लाने में कम नहीं समझी जाती और उसी के अनुसार विधान द्वारा दण्डनीय मानी जाती है। किन्तु कभी-कभी बैंकों को कुछ साख-पत्र न केवल उन्हें सुरक्षित रखने के लिये बल्कि उन पर की सामयिक प्राय और उनके पकने पर स्वयं उन्हें वसूल करने के लिये भी रखे जाते हैं। ऐसी अवस्था में वह उन पर अपने ऋण की अदायगी के लिये साधारण स्वत्व-ग्राहणाधिकार (General Lien) भी स्थापित कर सकता है। वस्तुतः बैंकों के साधारण स्वत्व-ग्राहणाधिकार (General Lien) को उनके अथवा अन्य व्यक्तियों के विशेष स्वत्व-ग्राहणाधिकार की तुलना में भली भाँति समझ लेना चाहिये।

साधारण स्वत्व-ग्रहणाधिकार बनाम विशेष स्वत्व

ग्रहणाधिकार (General Lien versus Particular Lien) —

विशेष स्वत्व ग्रहणाधिकार तो वह है जिसमें कोई वस्तु उस समय तक अपने पास रोक रखने का अधिकार है कि जब तक उसके सम्बन्ध के सब भुगतान न मिल जायें। इसके विपरीत साधारण स्वत्व ग्रहणाधिकार वह है जिसमें कोई भी वस्तु उस समय तक रोक रखने का अधिकार है जब तक उसके मालिक के ऊपर कोई भी भुगतान बाकी रह जाय। बैंकों के यह दोनों ही प्रकार के स्वत्व-ग्रहणाधिकार हैं किन्तु यदि किसी बैंक का किसी वस्तु पर कोई विशेष स्वत्व-ग्रहणाधिकार है तो उसी के साथ-साथ उस पर उसका साधारण स्वत्व-ग्रहणाधिकार नहीं ठहर सकता। उदाहरण के तौर पर मान लीजिये कि किसी बैंक के पास एक ८००० रुपये के ऋण के सम्बन्ध में कोई १०००० रुपये की जमानत जमा है। अतः, उसका इस जमानत में से ८००० रु० और उसका व्याज वसूल कर लेने का इस पर विशेष स्वत्व-ग्रहणाधिकार है। किन्तु इसका शेष बचने पर उसके पास उसे अपने किसी अन्य ऋण के सम्बन्ध में रोक लेने का कोई साधारण स्वत्व-ग्रहणाधिकार नहीं है। हाँ, यदि वह उसके पास उस विशेष ऋण की अदायगी के बाद भी छोड़ दिया जाता है तो अवश्य उस पर उसका साधारण स्वत्व-ग्रहणाधिकार हो जाता है। स्वत्व-ग्रहणाधिकार जमानत बेचने का अधिकार नहीं देता, वह केवल उसे रोक लेने ही का अधिकार देता है। जमानत काम में लाने के लिये पहिले अदालत से डिक्री के प्राप्त कर लेनी चाहिये, और फिर उस डिक्री के सम्बन्ध में उसे कुर्क करवा लेना चाहिये और तब वह बेची जा सकती है। बैंकों का उनके पास वसूली के लिये आई हुई चेकों पर साधारण स्वत्व-ग्रहणाधिकार हो जाता है और वह उनकी रकम अपने किसी भी ऋण की अदायगी में लगा सकते हैं। हाँ, यदि कोई रकम उनके पास किसी विशेष काम के लिये आई है तो अवश्य ही उसका प्रयोग उसी काम के लिए होना चाहिये।

(३) विशेष सम्बन्ध

किसी बैंकर और ग्राहक के बीच के उपर्युक्त सम्बन्ध तो उनके साधारण सम्बन्ध हैं, किन्तु इनके अलावा उनके कुछ विशेष सम्बन्ध भी हो सकते हैं। अतः, ऐसी स्थिति में बैंकर के ग्राहकों के प्रति कुछ विशेष दायित्व भी उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसा कि हम जानते हैं किसी बैंक को अपने दिवालिया ग्राहक की चेकों का भुगतान नहीं करना चाहिये। यदि

वह लेगा जर देता है तो सरकारी कारमन (Official Assignee) के प्रति जो उसके लेनदारों के हित के लिये उसकी सारी सम्पत्ति का ज़ाबती माना जाता है इसके लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ज़ेबे किसी ऐसे दिवालिये का डिग्री भी नहीं रखता चाहे जितना दिवालिया अदालत द्वारा नष्ट होता हो चाहे इनमें इस बात का डर है कि ज़ेबे जाने चलाने उसमें अदालत का तब सम्मन मांग ले तो उसके पास दिवालिया ने जमा की थी और धीरे धीरे निकाल ली है। हम यह भी देख चुके हैं कि किसी ग्राहक के स्वर्गवास की सूचना पा जाने पर बैंक को उसकी चेकें व भुगतान करना बन्द कर देना चाहिये। ऐसी स्थिति में या तो सन-जेय प्रवर्तक (Liquidator) आवश्यक मूल-जोड़े, अथवा प्रवर्तकप्रकार या ग्राहक या कोई उत्तराधिकार रखता उत्तराधिकार स्वयं ही पेन करते हैं और तब उन्हीं के अनुरोध पर मृतक अधिकारी ने आदेशानुसार उसका भुगतान किया जाता है। यह भी पतले ही बताया जा चुका है कि बैंक एक पागत ग्राहक की चेकों का भी भुगतान नहीं करता है। किन्तु ऐसा करने के पहिले उसे उसके मनगुच पागल हो जाने का पता लगा लेना चाहिये। यदि ग्राहक पागलपाने में भेज दिया गया है यावत् किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया है तब तो बैंक के भुगतान रोक देने में कोई डर नहीं है। किसी नये ने मृत ग्राहक की बराबरी भी पागल व्यक्ति ही में की जा सकती है अतः, ऐसे व्यक्ति के स्वयं ही अपनी चेक का भुगतान लेने के लिये जाने पर भी बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये। जो मक़त है कि ऐसा करने के पहिले कोई विश्वस्त साक्षी ले ली जाय। सत्य तो यह है कि ऐसे लोगों से बैंक को कोई सम्पर्क ही नहीं रखना चाहिये।

बैंकर को अल्पवयस्क ग्राहकों के साथ काम करने में भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिये। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि उन लोगों के पास उनके पायने की बदली के सम्बन्ध में किसी को मुक्त कर देने की शक्ति न होने के कारण बैंकर को उनकी जमा भी उनके द्वारा निकाल लेने पर अतः में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किन्तु कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों ने कहा है कि विधान ने अल्पवयस्कों को जो वचन प्रदान कर रखी है वह इस सीमा तक नहीं जा सकती है। चलन तो यह है कि उनके हितों तो खोल लिये जाने हैं और उनमें से उन्हें रकम निकालने की आशा भी प्रदान कर दी जाती है, किन्तु उन्हें जमा से अधिक रकम निकालने के लिये कभी

नहीं आशा दी जाती। एक अल्पव्ययक वेचान कर सकता है और दूसरे की ओर से उनका प्रतिनिधि भी हो सकता है।

बैंकर को धरोहरियों के साथ काम करने में भी बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये। यह तो पहिले ही कहा जा चुका है कि जिन लोगों के हित के लिये ऐसी धरोहर को जाती है उनके हितों का अदालत बहुत ध्यान रखती है और जिन्हे यह मालूम रहता है कि वह किसी धरोहर से सम्बन्ध रखने वाले कोप में लेन-देन कर रहे हैं उनसे यह आशा की जाती है कि वह जाल, इत्यादि के सम्बन्ध में साधारण तौर पर जो सावधानी करते हैं उससे कहीं अधिक सावधानी इस विशेष सम्बन्ध में करेंगे। धरोहरी लोग अपनी सामूहिक शक्ति अपने में से किसी एक को नहीं सौंप सकते। वास्तव में यह उसी स्थिति में हो सकता है जब धरोहर सम्बन्धी पत्र में ऐसा विशेष रूप से लिखा हो। अतः, इस बात का पता लगाने के लिये कि सब धरोहरियों की ओर से किसी एक धरोहरी के हस्ताक्षर ठीक माने जायें अथवा नहीं, धरोहर पत्र का अवश्य अध्ययन कर लेना चाहिये। यदि एक ग्राहक का एक हिसाब तो उसके स्वयं के नाम में है और दूसरा किसी धरोहर के नाम में है तो यदि वह धरोहर के हिसाब में से कुछ रकम अपने निजी हिसाब में हस्तान्तरित कर देता है तो बैंकर को आवश्यक पूछताछ कर लेनी चाहिये। धरोहर के तनिक भी भङ्ग हो जाने की शका हो जाने पर बैंकर को बहुत ही सावधान हो जाना चाहिये। ऐसे हिसाब के सम्बन्ध में तनिक-सी भूल नहीं करनी चाहिये।

बैंकर को अपने ग्राहकों के कर्मचारियों और प्रतिनिधियों से लेन-देन करने में भी यथेष्ट सावधानी बरतनी चाहिये। बात यह है कि इन लोगों के अधिकार सीमित रहते हैं। अतः, जब भी यह कोई काम करते हैं तभी इस बात का पता लगा लेना चाहिये कि इन्हें वह काम करने का अधिकार है अथवा नहीं। विनिमय साध्य पुजों के भारतीय विधान की २७वीं धारा में यह लिखा हुआ है कि काम करने के और ऋण की वसूली तथा भुगतान करने के एक साधारण अधिकार के यह अर्थ नहीं हैं कि कर्मचारियों अथवा प्रतिनिधियों को अपने मालिक तथा मुखिया के विनिमय बिल स्वीकार करके और वेचान करके उन्हें बाँधने का भी अधिकार मिला हुआ है। इन लोगों के, जब उनके मालिकों के हिसाब के साथ-साथ स्वयं के भी हिसाब होते हैं, सब बैंकर को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि मालिकों के हिसाब से

उनके स्वयं के दिग्गम में यदि कोई नुक़म हस्तान्तरित होती है तो यह उस पर यथेष्ट ध्यान रखने । बटुली करनेवाले बैंक को तो बहुत ही मायमान रहना चाहिये, क्योंकि इस सम्बन्ध की तनिकामी भी असावधानी हो जाने पर उसे विनिमय शास्य पुर्जा के भारतीय विधान में १३१वां भाग के अनुसार जो प्रचल मिली हुई है उसके समाप्त हो जाने का ख़तरा है । इंग्लैण्ड में प्रिमेल् वनाम फ़ास्म के मुक़दमे में जिसमें एक व्यापार में सम्बन्धित यात्री ने अपने मालिक को देय चक्र से जिस पर उसने प्रदालत द्वारा दिये गये अधिकार के नाम से (Per Procuracion) प्रेषण करके एक बैंक में अपने नाम का खाता खोल लिया था, यह निश्चय हुआ था कि ऐसे प्रेषण पर यह बात पता चलने के कारण कि प्रेषण करनेवाले को बहुत ही सीमित अधिकार हैं, बैंक को उसके अधिकारों का पता लगा लेना चाहिये या और उसने ऐसा न करने एक बहुत बड़ी असावधानी कियेलाई थी । वस्तुतः बैंकों को ऐसे हस्ताक्षर देगने हो उनके सम्बन्धी प्रविहार पर अवश्य देख लेने चाहिये ।

अन्तिम, बैंकों को किसी संयुक्त हिन्दू परिवार के ग़ारतों के सम्बन्ध में बह ध्यान रखना चाहिये कि उसकी सब चेकों पर परिवार के प्रमुखकर्ता के ही, जिसे केवल कर्ता कहते हैं और जो प्रायः परिवार का सबसे बड़ा पुरुष व्यक्ति होता है, हस्ताक्षर होने चाहिये । बात यह है कि विधानतः बड़ी संयुक्त परिवार के कर्म की ओर ने सब काम कर सकता है । यह सम्भे की कर्म के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ सम्भे के सभी सदस्यों के विधानतः एक से अधिकार रहते हैं ।

प्रश्न

(१) ग्राहक को परिभाषा दीजिये और उसके सम्बन्ध की विशेष बातें बताइये ।

(२) किसी बैंक में प्रायः कौन-कौन से खाते खोले जा सकते हैं ? उन्हें खोलने के क्रम बताइये ।

(३) किसी बैंकर और ग्राहक के बीच में किस प्रकार के सम्बन्ध रखे हो सकते हैं ? मुख्य सम्बन्ध की विशेषताएँ बताइये ।

(४) चेकों पर के जाल के सम्बन्ध में बैंकों को कौन-कौन सी वचन दी गई हैं । इस सम्बन्ध में (अ) एक जाली प्रेषण-युक्त चेक के और (ब) एक जाली हस्ताक्षर-युक्त चेक के भुगतान हो जाने पर बैंक के दायित्व पर प्रकाश डालिये ।

(५) किसी चेक का बेचान करने के क्या अर्थ हैं ? चेको पर कब आर कैसे बेचान करने चाहिये । विभिन्न प्रकार के वचान बताइये ।

(६) कोई बैंक अपने ग्राहको की चेकें किन-किन परिस्थितियों में भुगतान किये बिना ही वापिस कर सकता है ?

(७) चेकें भुगतान किये बिना ही वापिस करने पर बैंक प्रायः कौन-कौन से कारण लिख भेजते हैं ? उन्हें भली भाँति समझाइये ।

(८) यदि कोई बैंक कोई चेक भुगतान किये बिना ही गलती से लौटाए तो उसके कौन-कौन से दायित्व हैं ? अपने उत्तर के साथ-साथ उपयुक्त उदाहरण भी दीजिये ।

(९) एक स्थानीय (Domiciled) बिल के भुगतान के सम्बन्ध में किसी बैंक के कौन-कौन से दायित्व हैं ? ऐसे बिल किन-किन परिस्थितियों में तिरस्कृत किये जा सकते हैं ।

(१०) एक रेखाङ्कित चेक की वसूली के सम्बन्ध में उसके वसूल करनेवाले बैंक को कौन-कौन से अधिकार और दायित्व हैं ? इस सम्बन्ध में उसे जो वैधानिक वचन दी गई है, उसे स्पष्ट कीजिये ।

(११) रेखाङ्कन से आप क्या समझते हैं ? उसके भिन्न-भिन्न रूप बताइये । रेखाङ्कन का क्या उद्देश्य है ।

(१२) बैंक के स्वत्व (Lien) ग्रहणाधिकार से आप क्या समझते हैं ? इस सम्बन्ध में साधारण स्वत्व-ग्रहणाधिकार और विशेष स्वत्व-ग्रहणाधिकार के अन्तर बताइये ।

(१३) बैंको को किन विशेष प्रकार के ग्राहको से काम करना पड़ता है ? उन्हें इनसे काम करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ?

अध्याय १०

ऋण के लिये बैंकों की उपयुक्त जमानतें

यह तो हम पहिले ही देख चुके हैं कि बैंक केवल अच्छी जमानतों के आधार पर ही ऋण देते हैं। वास्तव में इनके अनेक रूप हैं। उनको जो जोखिम हैं उन्हें समझने के लिये हम उनमें से प्रत्येक के विषय में बहुत ही

प्रच्छेद जाफारी प्राप्त कर लेनी चाहिये। बैंकों को निजी प्रकार ही जमानत पर भी काम करने के समय बहुत ही सावधान रहना चाहिये। उन्हें न केवल यह देखना चाहिये कि जमानत मूल्य से कमी और जीता ही मिल जाने वाली है किन्तु यह भी देखना चाहिये कि डा. सर क. अधिनियम पर ध्यान नहीं भोले।

जमानत के बिना ऋण (Clear advances)

इस बार जब कोई प्रादक बहुत ग. र्जनों मान्य का होता है और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है तब उसे केवल उसकी वैयक्तिक जमानत पर ही ऋण मिल जाता है यद्यपि उसके हाते में ने उसे जमा की हुई रकम से अधिक रकम निकाल लेने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक केवल उसकी ईमानदारी, चांग-चलन और उद्यम तथा व्यापारिक दृढ़ता पर ही भरोसा रखा है। हा, कभी-कभी प्रयत्नी प्रचल के यान से वह उसका लिये हुए प्रण-यन पर किसी एक प्रयत्ना दो स्वतन्त्र व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी ले लेता है, जिससे उन ऋण के सम्बन्ध की उनकी भी वैयक्तिक जमानत हो जाती है। किन्तु समय पर ऋण को बदली न होने पर स्वयं देनदार तो ऋण लेने वाला व्यक्ति ही होता है। बैंक को जमानत के प्रति अपने अधिकारों का तभी प्रयोग करना चाहिये जब उनकी पूरी रकम देनदार की स्वयं की सम्पत्ति ने न बसूल हो सके। ऐसे ऋण बिना जमानती ऋण (Clean advances) रहे जाते हैं।

आ उपर्युक्त जमानत चालू (Continuing) और विशेष (Specific) भी हो सकती है। चालू जमानत की अवस्था में जमानत करने वाला व्यक्ति एक विशेष रकम तब चाहे 'वह कितनी बार ही क्यों न ली दी जाय, दायी रहता है और विशेष जमानत की अवस्था में वह केवल एक ही बार दी हुई रकम पर दायी रहता है। मान लीजिये कि 'अ' पाँच सौ रुपये का ऋण लेता है, और कुछ ही दिनों बाद वह २०० रु० वापिस कर देता है, किन्तु फिर १०० रु० ले लेता है। अब, उस पर ४०० रु० की बाकी बची है। अतः, चालू जमानत में जमानत करनेवाला व्यक्ति ४०० रु० के लिये दायी है और वह उस २०० रु० का लाभ नहीं उठा सकता जो 'अ' ने पहिले वापिस किये थे। हाँ, विशेष जमानत में वह ३०० रु० के लिये दायी होगा क्योंकि २०० रु० तो 'अ' ने वापिस कर दिये थे। इस अवस्था में उससे उन १०० रु० से कोई मतलब नहीं है जो 'अ' ने बाद में फिर

लिये थे। जमानत करनेवाला व्यक्ति जब जमानत की रकम दे देता है तब वह वह रकम मुख्य देनदार से वसूल कर सकता है।

अतिरिक्त आनुसंगिक जमानत (Collateral Securities)

उधार लेनेवाले व्यक्तियों को उधार रकम के सम्बन्ध में प्रायः कुछ अतिरिक्त (आनुसंगिक) जमानत भी जमा करनी पड़ती है। अतिरिक्त (आनुसंगिक) जमानत किसी भौतिक पदार्थ की अथवा उनके सम्बन्ध के अधिकार पत्रों की हो सकती है। यह जमानत वैयक्तिक जमानत के अतिरिक्त होती है और इसीलिये अतिरिक्त जमानत कहलाती है। वास्तव में इन्हें बेचकर ऋण की वसूली तभी की जा सकती है जब देनदार उसे वैसे ही देने से इन्कार कर दे अथवा न दे। यह अतिरिक्त जमानत स्वत्व-ग्रहणाधिकार (Lien) के अथवा गिरवी (Pledge) के अथवा रेहन (Mortgage) के रूप में हो सकती है।

स्वत्व-ग्रहणाधिकार में जमानत अपने पास रोक रखने का अधिकार है, उसे बेचा नहीं जा सकता। हाँ, यदि ऐसा करना है तो पहले अदालत से डिक्री प्राप्त करनी पड़ती है और फिर उस डिक्री में वह चीज कुर्क करवानी पड़ती है और तब बेचा जा सकता है। किन्तु पूर्ण रूप से विनिमय साध्य पत्रों की जमानतों में जैसे देखनहार शेयर वारण्ट, स्टॉक और सर्टीफिकेट, देखनहार और रजिस्टर्ड ऋण-पत्र, विनिमय विल, प्रण-पत्र और चेकों में बैंक के स्वत्व (ग्रहणाधिकार) में देनदार को उचित सूचना देकर इन्हें बेच लेने का भी अधिकार है। जहाँ तक अन्य अधिकार-पत्रों का प्रश्न है उनमें अवश्य यह अधिकार नहीं है। उन्हें केवल रोका जा सकता है।

गिरवी की हालत में बैंक को जमानत रोकने और फिर उचित सूचना देकर बेचने का भी अधिकार है। अतः, स्वत्व (ग्रहणाधिकार) और गिरवी में पूर्ण रूप से विनिमय साध्य पत्रों को छोड़कर शेष में यही अन्तर है कि जब एक में जमानत की वस्तु केवल रोकी ही जा सकती है, दूसरे में वे बेची और रोकी दोनों जा सकती हैं। इसका यह निष्कर्ष है कि गिरवी स्वत्व (ग्रहणाधिकार) से अधिक अच्छा है।

जब जमानत अचल सम्पत्ति की दी जाती है तब उसका रेहन करवाना पड़ता है। इसमें स्वत्व (ग्रहणाधिकार) और गिरवी के विपरीत जमानत की वस्तु का कब्जा लेनदार का नहीं हो जाता। वह या तो देनदार का ही रहता है अथवा देनदार जिसे चाहता है उसका रहता है। इसमें प्रायः

स्वामित्व आवश्यक हस्तान्तरित हो जाता है। न्यून (ग्रहणाधिकार) और गिराव में ऐसा कि हमें मालूम है कच्चा तो प्रायः बदल जाता है किन्तु स्वामित्व नहीं बदलता। किन्तु यहाँ पर जो जुद्ध रेहन के नियम में रखा गया है। वह केवल वैधानिक रेहन (Legal Mortgage) के लिये ही लागू है। वास्तव में रेहन कई प्रकार के होते हैं, किन्तु यहाँ पर हम केवल वैधानिक रेहन (Legal Mortgage) और मादे रेहन (Equitable Mortgage) के नियम में ही समझना है। वैधानिक रेहन रेहननामे के आधार पर होता है जिसे लिपाने के लिये एक सम्पूर्ण कागज का प्रयोग किया जाता है और जो रेहन के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कनाया जाता है। उसके विरोध में मादे रेहन (Equitable Mortgage) में केवल अभिचार-पत्र एकलौ ही अथवा एक स्मरण-पत्र (Memorandum) के साथ अथवा केवल स्मरण-पत्र (Memorandum of Charge) ही जिसके पास रेहन रखा जाता है उसे सौंप दिया जाता है। अतः, दोनों में यह अन्तर है कि तब कि पहले में रेहन की सम्पत्ति का स्थायित्व जिसके पास वह रेहन की जाती है उसका हो जाता है और इसीसे उसे ऋण की अदायगी न होने पर उसे बेच लेने का अधिकार रहता है, दूसरे में ऐसा नहीं हो पाता। इसमें जिसके पास रेहन रखा जाता है उसे पहले न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है और उसकी आज्ञा प्राप्त करने के बाद ही वह उसे बेच सकता है। मादे रेहन (Equitable Mortgage) भारतवर्ष में केवल फ्लॉक्ते, मद्रास, बम्बई, स्याची और उन शहरों में ही लिया जा सकता है जिन्हें गवर्नर जनरल समय-समय पर गजट में निकालता है। वैधानिक रेहन में भी ऋण की अदायगी के बाद रेहन रखनेवाले को रेहन रखी हुई सम्पत्ति का फिर से स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। रेहन रखनेवाले की यह अधिकार प्राप्ति छुटकारे का दावा (Equity of Redemption) कहा जाता है।

अतिरिक्त (आनुसंगिक) जमानतों के विभिन्न रूप

अतिरिक्त (आनुसंगिक) जमानते विभिन्न रूप की हो सकती हैं जो निम्नांकित हैं:—

Manufactable (१) Stack Exchange में बिकनेवाले पत्र

इनमें सरकार के और कम्पनियों के दोनों के पत्र आ जाते हैं। ये (अ) पूर्ण रूप से विनिमयसाध्य हस्तान्तरित होनेवाले (Fully Negotiable-Convertible) और (ब) अविनिमयसाध्य हस्तान्तरित न होनेवाले

(Non-negotiable Inconvertible) दोनों होते हैं । हस्तान्तरित न होनेवाले स्टॉक फिर से रजिस्टर में स्वयं हस्ताक्षर करने पर हस्तान्तरित होने वाले (Inscribed) और हस्तान्तर-पत्र (Transfer deed) भरकर हस्तान्तरित होनेवाले (Registered Stocks and Shares) स्टॉकों में विभाजित किये जा सकते हैं । पूर्ण रूप से विनिमयसाध्य स्टॉक दूसरो को देकर अथवा बेचान करके हस्तान्तरित किये जा सकते हैं । हस्तान्तरित न होने वाले वह स्टॉक जो रजिस्टर में स्वयं हस्ताक्षर करने पर हस्तान्तरित किये जा सकते हैं (Inscribed) वह हैं जिन्हें हस्तान्तरित करने के लिये हस्तान्तरकर्ता को स्वयं कम्पनी में जाकर अथवा अपना कोई प्रतिनिधि भेजकर कम्पनी के रजिस्टर में हस्ताक्षर करना पड़ता है । अतः, यह दूसरो को देकर अथवा बेचान करके हस्तान्तरित नहीं किये जा सकते । इसलिये इनके रेहन रखे जाने पर बैंकर को इन पर अपना पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिये इनके मालिक से इनके हस्तान्तरित किये जाने के प्रमाणस्वरूप कम्पनी के रजिस्ट्रों में हस्ताक्षर करवा लेने चाहिये । जहाँ तक हस्ताक्षर-पत्र भरकर हस्तान्तरित होनेवाले स्टॉकों (Registered stocks) का प्रश्न है उनके हस्तान्तर होने का प्रमाण उन्हें निकालनेवाली कम्पनी एक मुहरबन्द प्रमाण-पत्र देकर दे देती है और वह वैधानिक तौर से (Legal transfer) अथवा सादे तौर से (Equitable charge) हस्तान्तरित किये जा सकते हैं । वैधानिक तौर से हस्तान्तरित करने के लिये (Legal transfer) एक हस्तान्तर-पत्र लिखना अथवा लिखकर मोहर करवाना पड़ता है और जब उसका प्रमाण-पत्र (Certificate) हस्तान्तर-पत्र सहित कम्पनी के पास पहुँच जाता है तब वह उसके अधिकारी के स्थान पर बैंकर का नाम दर्ज करके बैंकर को एक दूसरा प्रमाण-पत्र (Certificate) भेज देती है । इसके विपरीत सादे तौर से हस्तान्तरित करने के लिये (Equitable charge) प्रमाण-पत्र (Certificate) को जमा करने के एक स्मरण-पत्र (Memorandum of deposit) सहित अथवा उसके बिना अथवा हस्तान्तरित करने के एक स्मरण-पत्र तथा एक सादे हस्तान्तर-पत्र पर हस्ताक्षर करके बैंकर के पास जमा कर देना पड़ता है । जब प्रमाण-पत्र (Certificates) जमा किये जाते हैं तब उनके साथ प्रायः जमा का एक स्मरण-पत्र (Memorandum of deposit) और हस्ताक्षर किया हुआ एक सादा हस्तान्तर-पत्र (Duly Executed Blank-Transfer) अवश्य रहता है । बात यह है कि जब इससे बैंकर के लिये यह सुविधा हो जाती है कि जब उसकी ऋण की रकम वसूल नहीं होती तब वह

हस्ताक्षर बिना धुने साटा हस्तान्तर-पत्र भरकर कम्पनी को सूचना देकर स्टॉक अपने नाम में हस्तान्तरित करवा लेता है। इसके विपरीत जो प्रमाण-पत्र ही जमा रहते हैं अथवा उनके साथ जमा का स्मरण-पत्र भी होता है, न तो उधार की रकम न मिलने, पर धेंकर देनदार को तुल्यकर उसने स्टॉकों को वैधानिक तौर से हस्तान्तरित करने को कहा है और उसने ऐसा न करने पर अदालत में उनके हस्तान्तर करने की और धेंचने की आशा प्राप्त करता है। इनमें उसे बहुत असुविधा होता है। अतः हम तब ही जमानत प्राय चालू नहीं है।

स्टॉक एम्प्लेचेंज में गिरने वाले पत्र

पूर्ण रूप से अन्धा अधिकार देने वाले स्टॉक—हस्तान्तरित होने वाले स्टॉक (इन्हें दूसरों को देकर अथवा बेचान करके हस्तान्तरित किया जा सकता है)

पूर्ण रूप से अविनिमय स्टॉक—हस्तान्तरित न होने वाले स्टॉक

रजिस्टर में स्वयं हस्ताक्षर करने पर हस्तान्तरित होने वाले स्टॉक (Inscribed stocks) इन्हें दूसरों को देकर अथवा बेचान करके हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता। इनके अधिकारी को स्वयं अथवा किसी प्रतिनिधि से कम्पनी के रजिस्ट्रों में हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं।

हस्तान्तर-पत्र भरकर हस्तान्तरित होने वाले स्टॉक (Registered stocks and shares)

वैधानिक तौर से हस्तान्तरित होना (Legal transfer) इसमें हस्तान्तर-पत्र भरकर कम्पनी में भेजना पड़ता है।

सादे तौर से हस्तान्तरित होना (Equitable charge)—इसमें प्रमाण-पत्र जमा के अथवा हस्तान्तर करने के स्मरण-पत्र के साथ

अथवा किसी ऐसे पत्र के बिना ही और एक सादे हस्ताक्षर किये हुये हस्तान्तर पत्र के साथ रख दिया जाता है।

गुण — (१) ये आसनों से और शीघ्रतापूर्वक वसूल किये जा सकते हैं।

(२) इनकी वास्तविक बाजार कीमत आसानी से मालूम की जा सकती है।

(३) इनकी कीमत बहुत नहीं घटती-बढ़ती।

(४) इनके स्वामित्व में कोई झगडा नहीं होता। अतः, यह आसानी से बेचे जा सकते हैं।

(५) पूर्ण रूप से विनिमयसाध्य स्टॉकों के सम्बन्ध में यदि उन्हें अच्छी नीयत से और उनकी पूरी कीमत चुका कर प्राप्त किया गया है तो बैंकर के पास उनका अच्छा अधिकार रहता है, और जब तक उसके ऋण की रकम का भुगतान नहीं हो जाता, वह उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के विरोध में भी अपने पास रख सकता है।

(६) यदि बैंकर द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है तो वह इन्हें केन्द्रीय बैंक में रखकर इन पर ऋण प्राप्त कर सकता है।

दोष—(१) जिन हिस्सों अथवा ऋण-पत्रों पर आशिक भुगतान हुआ है उन पर कुछ और भुगतान माँगा जाने पर बैंकर को वह भुगतान देना पड़ सकता है, क्योंकि भुगतान न पहुँचने पर उनके जन्त हो जाने का डर रहता है।

(२) कुछ कम्पनियों की यह शर्त होती है कि हिस्सेदार के ऊपर कम्पनी की कोई भी रकम बाकी रहने पर वह उसके हिस्से से वसूल की जायगी। यदि ऐसा है और बैंकर को यह नहीं मालूम है कि हिस्सेदार के ऊपर कम्पनी की कोई रकम चाहिये तो बाद में अपनी रकम वसूल करते समय उसे यह मालूम होने पर कि पूरी रकम वसूल नहीं की जा सकती उसे हानि हो सकती है।

(३) जब यह पूर्ण रूप से विनिमयसाध्य हस्तान्तरित होने वाली नहीं होती तब इनके हस्तान्तर करवाने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। ऐसी अवस्था में बैंकर का अधिकार हस्तान्तरकर्ता के अधिकार की ही तरह का होता है और उसके दूषित होने पर उसका अधिकार भी दूषित हो जाता है।

सावधानियाँ—स्टाफ एम्प्लोय में बिकने वाले पत्रों की जमानतों के सम्बन्धों में यदि निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहियें तो उनके रूप ठोस दूर हो सकते हैं।

(१) यथासम्मान गुणाद्वारा देनी चाहिये। जब कभी भी मूल्य गिर जाय, और अधिक जमानत मांग लेनी चाहिये।

(२) आशिक भुगतान वाले हिस्से और भ्रष्ट पत्र कभी नहीं लेने चाहिये।

(३) विनिमयसाध्य पत्रों की प्रवस्था में परिवर्तन के हस्तान्तर करवा लेना चाहिये।

(४) छटेमात्रे हिस्से नहीं लेने चाहिये।

(२) विनिमयसाध्य पुर्जे

हमें यह तो शायद ही है कि विनिमय बिल बैंकों से भुनवाये जा सकते हैं। अतः, जब वह ऐसा करते हैं तब उन पर उन्हें पूरे अधिकार मिल जाते हैं जिससे वे उन्हें बेच भी सकते हैं और दूसरों ने फिर से भुना भी सकते हैं। हाँ, यदि यह गिरवी रखने जाने हैं तो बैंकर ऐसा नहीं कर सकता। उन्हे इन्हें इनके पकने तक अपने पास रखना ही पड़ता है। अतः, बैंकर के विचार से तो इन्हें उसके हाथ बेच देना ही अच्छा है, गिरवी रखना नहीं।

गुण—(१) यदि बैंकर ने इन्हें अच्छी नीमत से प्राप्त किया है तो उसका इन पर अच्छा अधिकार ही रहता है।

(२) इनका मूल्य निर्धारित रहता है।

(३) इन्हें फिर से भुनाया जा सकता है।

(४) इनके पकने पर द्रव्य मिलना निश्चित है।

दोष—इनके पकने पर बैंकर को इनकी वसूली करना पड़ती है।

सावधानियाँ—जहाँ तक हो सके इन्हें भुना दिया जाय गिरवी न रक्खा जाय।

Goods and

(३) माल अथवा माल के अधिकार-पत्र

जब माल बैंकर के यहाँ गिरवी रक्खा जाता है तब या तो वह उसी के गोदाम में ले आया जाता है या उधार लेने वाले के पास ही छोड़ दिया जाता है। यदि वह उधार लेने वाले के पास ही छोड़ दिया जाता है तो उसके गोदाम की वालियाँ अवश्य बैंकर को ही दे दी जाती हैं। दोनों ही स्थितियों में माल

का बीमा करना पड़ता है और उसका खर्च उधार लेने वाले को देना पड़ता है। जन माल बैंक के गोदाम में रखा जाता है तब वह उसका किराया भी ले लेता है। माल के अधिकार-पत्र भी गिरवी रखे जा सकते हैं। इनमें जहाजी बिल्टी (Bill of lading), डाक पत्र (Dock-warrant), गोदाम वालों के प्रमाण-पत्र (Warehouses keeper's certificates) बट्टारे का प्रमाण-पत्र (Wharfinger's certificate), रेल की बिल्टी (Railway Receipt), माल देने के लिये आदेश पत्र तथा ऐसे ही कोई अन्य कागजात जो माल का स्वामित्व हस्तान्तरित करने में काम में लाये जाते हैं, सम्मिलित हैं।

गुण—(१) माल और माल सम्बन्धी कागजात एक प्रकार से स्वयं वास्तविक वस्तु हैं अथवा उनके प्रतिनिधि हैं। अतः, जमानत के लिये बहुत अच्छे हैं।

(२) इनके मूल्य नहीं घटते-बढ़ते।

(३) इन्हें बहुत आसानी से बेचा जा सकता है।

(४) इनकी जमानत पर जो ऋण दिया जाता है उसके अवश्यमेव भुगतान होने की सम्भावना रहती है। बात यह है वह द्रव्य इन्हीं के क्रय के लिये लिया जाता है और इन्हीं के विक्रय पर वापिस कर दिया जाता है।

(५) इनका मूल्य आसानी से मालूम हो जाता है।

दोष—(१) माल खराब हो सकता है।

(२) इनके मूल्य में दैनिक परिवर्तन होता है। हाँ, यह परिवर्तन बहुत अधिक नहीं होता।

(३) कभी-कभी एक ही माल कई किस्म का होता है। अतः, इसमें धोखा दिया जा सकता है।

(४) कुछ माल रखने में बहुत जगह की आवश्यकता पड़ती है।

(५) इसमें चोरी हो जाने की भी बड़ी आशंका रहती है।

(६) इन्हें देनदार थोड़ी थोड़ी रकम देकर थोड़े-थोड़े परिमाण में उठाता रहता है। अतः, माल देने में गलती हो सकती है।

(७) माल सम्बन्धी अधिकार-पत्रों में जालसाजी की बड़ी गुंजाइश रहती है।

भारतवर्ष में इनके प्रिय न होने के कारण—(१) यहाँ पर लाइसेन्स प्राप्त गोदाम नहीं के बराबर हैं।

(२) प्रायः माता भी उचित कि मे-निर्धारित नहीं हैं और जहाँ पर पैसा भी वहाँ पर उनका उचित ध्यान नहीं रखा जाता।

(३) बहुत सी जगहों में नृत्य-सौ चीजें एक भगवत सामान नहीं हैं। अतः, उनके मूल्य का पता लगाने में अनुमति दी जाती है।

सावधानियाँ - (१) लिव माता के समान हो जाने की अधिक सम्भावना है उनके नहीं रखना चाहिये और यदि यह रखा भी जाय तो उसका बीमा करवा लेना चाहिये। जहाँ तक माल गिराव हो जाने का डर है, सोना-चाँदी खराब नहीं होता है। अतः यह सर्वोत्तम है।

(२) माल के मूल्य का अगर पता लगाने रखना चाहिये। जमानत में उधार देने समय ही यथेष्ट गुमास्ता रख लेना चाहिये और यदि मूल्य बहुत कम हो जाय तो और अधिक प्रतिशत जमानत माँगा लेनी चाहिये।

(३) जो माल रखा जाय उसकी हिस्से समझ लेने के लिये एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति रखना चाहिये।

(४) जब माता छोड़ा जाय तब बहुत निगाह रखनी चाहिये। जहाँ तक हो सके इसके लिये एक अलग गुमास्ता होना चाहिये।

(५) माल नग्न-घी धागजों पर उधार देने के पहिले उनकी वास्तविकता का पता लगा लेना चाहिये। साथ ही उनके वास्तविक अधिकारी में भी जाँच-बढ़ताल करा लेनी चाहिये।

(६) बैकर को वही माल लेने चाहिये जिन्हें वह अपने गोदाम में आसानी से रख सकता हो। यदि माल श्रृणों के ही गोदाम में छोड़ दिया जाता है तो उसके गोदाम की जाँच करवा लेनी चाहिये और उसने दोग दूर करवा देने चाहिये। सत्तियों में कच्ची सत्तियों की तुलना में पक्की सत्तियों कहीं अच्छी होती हैं।

(७) सबसे आवश्यक तो यह है कि बैकर को श्रृण लेने वाले की ईमानदारी इत्यादि का पता लगा लेना चाहिये। जो काम वह करता हो उसमें उसे होशियार होना चाहिये।

(८) बैकर को अपने ग्राहकों के कर्मचारियों इत्यादि को उधार देने समय बहुत सावधान रहना चाहिये। प्रायः इनके अधिकार सीमित रहते हैं।

(९) माल गिरवी रखने जाने का प्रमाण बराबर लिखित रूप में ले लेना चाहिये।

(१०) जहाजी बिल्टी (Bill of lading) की कई प्रतिलिपियाँ होती हैं। अतः, सब ले लेनी चाहिये जिससे जाल न किया जा सके।

(४) जान बीमा-पत्र

बीमे का प्रस्ताव पत्र भरते समय यदि कोई बात गलत नहीं लिखी गई है तो जान बीमा-पत्र के आधार पर उसके परित्यज्य मूल्य (Surrender Value) तक की रकम बहुत ही अच्छी तरह से उधार दी जा सकती है। किन्तु बैंकों के पास प्रायः जो जमानतें रहती हैं उनमें यह बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता। बात यह है कि बीमा कम्पनियों के स्वयं ही बीमा-पत्रों के आधार पर रकम उधार देने के लिये तैयार रहने के कारण अधिकांश में इनके आधार पर उन्हीं से ऋण ले लिया जाता है और इसमें बीमा कम्पनियों को तथा उधार लेने वाले दोनों को बहुत ही सुविधा रहती है। इनका भी वैधानिक रेहन (Legal mortgage) अथवा सादा रेहन (Equitable mortgage) हो सकता है। सादे रेहन में बीमा-पत्र दे दिया जाता है, चाहे साथ में जमा करने का स्मरण-पत्र दिया जाय अथवा नहीं। इसके विपरीत वैधानिक रेहन में एक बेची-पत्र (Deed of assignment) भी भरा जाता है जिसमें मूलधन और व्याज देने का वायदा रहता है और बीमा पत्र के ऋण की अदायगी हो जाने पर छुटकारे की शर्त के साथ उसकी बेची भी रहती है।

गुण—(१) इनका त्याज्य मूल्य आसानी से मालूम किया जा सकता है। प्रायः, इनकी पीठ पर इसे निकालने का तरीका दिया रहता है। साथ ही बीमा कम्पनी से भी इसका पता लगाया जा सकता है।

(२) यदि बीमे का प्रतिफल बराबर चुकता होता रहता है तो इनका त्याज्य मूल्य भी बराबर बढ़ता जाता है।

(३) यदि बीमा-पत्र स्मरण-पत्र के बिना नहीं जमा कर दिया जाता है तो भी ऋण लेने वाले के दिवालिया हो जाने पर पहले बैंकर को बीमा-पत्र से ऋण की रकम वसूल करने का अधिकार रहता है और फिर उसके बाद सरकार द्वारा निर्धारित इतिवर्त का अधिकार होता है।

(४) ऋण लेने वाले के एक विशेष आयु पर पहुँचने पर अथवा मर जाने पर उसका जान बीमा-पत्र स्वयं ही पक जाता है।

(५) यदि जान बीमा-पत्र की बेची हो गई है और बीमा कम्पनी को सूचना दी जा चुकी है तो यह पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। इसमें अधिकार के खराब होने का प्रश्न नहीं उठ सकता।

(६) आश्रयका पदने पर बैंकर इसकी बेनी मिठी अन्य घनी के नाम भी कर सकता है ।

दीप—(१) यदि प्रमाण्य ठीक नहीं भरा गया था तो बीमा-पत्र के पकने पर यह प्रवेष्ट ठहराया जा सकता है ।

(२) यदि बीमा कराने वाले की आयु का प्रमाण बीमा कम्पनी के द्वारा पहले से स्वीकृत नहीं कराया जा चुका है तो बीमा कराने वाले की मृत्यु पर बैंकर को ऐसा कराने में फटिनाई पर सकती है ।

(३) प्रायः आत्महत्या और न्यायालय की ओर से कौसी भी सजा बीमा पत्रों के अन्तर नहीं सम्मिलित होती ।

(४) बीमा प्रायः विधवा और बच्चों के हित के लिये करवाया जाता है । अतः बैंक के लिये उसकी रकम लेना भलमनसाहत नहीं समझी जाती ।

(५) बीमे का मूल्य उसका प्रतिफल देने से ही बढ़ता है । अतः, यदि बीमा कराने वाला यह प्रतिफल नहीं देता तो उसे बैंक को देना पड़ सकता है ।

(६) यदि बीमा किसी अन्य व्यक्ति ने करवाया है तो जिसकी जान का बीमा हुआ है उसकी जान में बीमा कराने वाले की आर्थिक दिलचस्पी न होने के कारण बीमा अवैध सिद्ध हो सकता है ।

(७) यदि बीमा-पत्र नहीं ले लिया गया है तो यह किसी और के नाम बेचा जा सकता है । वास्तव में जो व्यक्ति भी पहले बीमा कम्पनी को बीमे की बेची की सूचना दे देता है वही उसे पाने का हकदार समझा जाता है ।

सावधानियाँ—(१) बैंकर को यह बात देख लेनी चाहिये कि जिसका जान बीमा कराया गया है उसकी आयु का प्रमाण बीमा कम्पनी ने मान लिया है ।

(२) उसे यह भी देख लेना चाहिये कि बीमा कराने वाले जिसका जान बीमा कराया गया है उसकी जान में बीमा कराने के समय आर्थिक दिलचस्पी थी ।

(३) उसे सादे रेहन की अपेक्षाकृत पैधानिक रेहन पर अधिक जौर देना चाहिये ।

(४) उसे यह बात देखते रहना चाहिये कि प्रतिफल देने की रसीदें बराबर उसके यहाँ जमा होती रहती हैं और प्रतिफल बराबर दिया जाता है ।

(५) उसे बीमा कम्पनी को रेहन की सूचना दे देनी चाहिये और इस बात का पता लगा लेना चाहिये कि वह पहले से तो रेहन नहीं थी ।

(६) बैंक की दृष्टि से एक निश्चित अवधि पर अथवा यदि उससे पहिले मृत्यु हो जाय तो उस पर पकने वाला बीमा (Endowment) केवल मृत्यु पर पकने वाले बीमे (Whole life) को अपेक्षाकृत कहीं अधिक अच्छा है ।

(७) कुंवारी स्त्रियों के बीमे के सम्बन्ध में उनका विवाह हो जाने पर बीमा-पत्र के ऊपर विवाह की बात लिखवा लेनी चाहिये ।

(८) प्रत्येक बीमा-पत्र की सब धारायें अपने अधिकार और दायित्व समझने के लिये बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिये ।

अचल सम्पत्ति

जब अचल सम्पत्ति जमानत की तौर पर दी जाती है तब प्रायः उसका रेहन-नामा होता है और जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है यह रेहन-नामा प्रायः वैधानिक होता है क्योंकि सादा रेहन-नामा तो हमारे यहाँ कुछ विशेष शहरों को छोड़कर अन्य शहरों में होता ही नहीं और न उसमें सम्पत्ति बेचने का ही अधिकार रहता है । अचल सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकार-पत्रों को भलीभाँति जँचवा लेना चाहिए अन्यथा उन पर का अधिकार झूठा प्रमाणित हो सकता है । उनका मूल्य भी भलीभाँति अँकवा लेना चाहिये और उनका बीमा भी करवा लेना चाहिये ।

गुण—सत्य तो यह है कि अचल सम्पत्ति में ऐसा कोई गुण ही नहीं है जिससे कि वह जमानत के तौर पर स्वीकृत की जाय, किन्तु प्रायः ऐसे ग्राहक मिलते हैं जिनके पास इन्हें छोड़कर और कोई चीज़ जमानत के तौर पर देने के लिये निकलती ही नहीं । अतः, इन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है ।

दोष—(१) वैधानिक रेहन में तो बहुत ही खर्च पड़ता है और वह अनुविधानिक भी होता है, और सादा रेहन कुछ विशेष शहरों को छोड़कर अन्य शहरों में हो ही नहीं सकता ।

(२) अचल सम्पत्ति के वास्तविक अधिकारी का पता लगाना बहुत ही कठिन है । बात यह है कि हमारे देश में हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम बहुत ही टेढ़े-मेढ़े हैं ।

(३) प्रचल सम्पत्ति का मूल्य ठोठ ठोठ प्राँक लेना बहुत ही कठिन हो जाता है और यह भी पटता-श्रद्धता रहता है ।

(४) इन्ने बेगने में बहुत ही असुविधा होती है क्योंकि इसमें बहुत सी वैधानिक कार्यवाहियाँ करनी पड़ती हैं । फिर इन्ने खरीदने वाले भी मुश्किल में ही मिलते हैं और भिन्न भिन्न व्यक्ति इन्ने भिन्न भिन्न मूल्य लगाते हैं ।

(५) कुछ मकान मरम्मत, इत्यादि न होने के कारण बहुत जल्दी ही खराब हो जाते हैं ।

(६) ऋण की अदायगी न होने पर गिरा दिन से जमानत पर गफ्तार गये मकान इत्यादि बैंक के दाय म आ जाते हैं, उस दिन से उन्ने उनमें किरायेदार रहने और उनकी मरम्मत कराने के दायित्व अपने ऊपर लेने पड़ते हैं ।

(७) इनके अधिकार-पत्रों की सार्वजनिकता का पता लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है ।

(८) जहाँ पर जमीन पट्टे पर होती है वहाँ पर किराया न पहुँचने पर पट्टे की समामि की आशंका रहती है ।

(९) इसके प्राग से नष्ट हो जाने का डर रहता है ।

सावधानियाँ—(१) प्रचल सम्पत्ति लेते समय ऋण लेने वाले का उस पर का अधिकार गलीभाँति पता लगा लेना चाहिये ।

(२) अधिकार पत्र अच्छी तरह से जँचवा लेने चाहिये ।

(३) भविष्य में मरम्मत इत्यादि के लिये प्रग्रन्ध कर लेना चाहिये ।

(४) पट्टे की सम्पत्ति के सग्रन्ध में किराया देने का प्रग्रन्ध हो जाना चाहिये ।

(५) इसका प्राग बीमा करवा लेना चाहिये और ऋण लेने वाले से वार्षिक प्रतिफल देने का जिम्मा भरवा लेना चाहिये ।

(६) जहाँ तक हो एक रेहन के बाद दूसरा रेहन नहीं स्वीकार करना चाहिये और यदि दूसरे रेहन की सूचना मिल जाय तो फिर और रकम उधार नहीं देनी चाहिये ।

प्रश्न

(१) 'उधार' (Advances) से आप क्या समझते हैं ? चालू (Continuing) और विशेष (Specific) जमानतों को भली भाँति समझाइये ।

(२) अतिरिक्त (आनुसंगिक) जमानत (Collateral securities) से आप क्या समझते हैं ? ये किस प्रकार की होती हैं ? इनमें से प्रत्येक के विषय में बताइये ।

(३) बैंक प्रायः किस प्रकार की अतिरिक्त जमानत ले लेते हैं ? प्रत्येक की विशेषताओं पर छोटी-छोटी टिप्पणियाँ लिखिये ।

(४) बैंकर की दृष्टि से स्ट्राक एक्सचेञ्ज में विक्रय के वाले साख-पत्रों की जमानत कैसी होती है ? इसके दोष कम करने के लिये अपने सुझाव रखिये ।

(५) माल और माल के अधिकार-पत्रों के अतिरिक्त जमानत की तरह से प्रयोग में आने के गुण और दोष भली भाँति समझाइये । इन्हें लेने के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ? भारतवर्ष में यह बहुत अधिक प्रिय क्यों नहीं हैं ?

(६) जान बीमा-पत्र जमानत की तरह पर लेने में कौन-कौन से गुण और दोष हैं ? इन्हें लेने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ?

(७) 'अचल सम्पत्ति अच्छी जमानत नहीं है' यह बात बैंकर की दृष्टि से समझाइये ।

(८) विनिमय साध्य पुर्जों को जहाँ तक सम्भव हो गिरवी की तरह से ही लेना चाहिये, इस पर अपने विचार लिखिये ।

अध्याय ११

बैंकों का निकासगृह (Clearing House)

बैंकों का निकासगृह वह संस्था है जहाँ स्थानीय बैंकों के पारस्परिक लेन-देनों का निपटारा हो जाता है । इसे समाशोधन गृह अथवा बलण भी कहा जाता है । जैसा कि छठे अध्याय में बताया जा चुका है । यह काम प्रायः सभी केन्द्रीय बैंक या तो चलन के अनुसार करते आ रहे हैं या विधान ने उन्हें ऐसा करने के लिये बाध्य कर रखा है । जिन देशों में केन्द्रीय बैंकों की स्थापना के बहुत पहिले ही से व्यापारिक बैंकों ने स्वयं ही अपने लेन-देनों का निपटारा

करने के लिये प्रवृत्त कर लिया था अथवा वहाँ पर केन्द्रीय बैंकों ने महत् काम बहुत दिनों तक प्रारम्भ ही नहीं किया था वहाँ पर स्वतन्त्र निमासद स्थानित हैं और उनके स्वयं के नियम बना काम करने के लिये बने हुये हैं। ६।, इतना प्रसन्न है कि वहाँ के केन्द्रीय बैंक भी उनके वक्ष्य हैं और जाय ही प्रतीक दिन की निरासी के अन्त में बैंकों के जो जग प्रचलित हैं उनके निपटारे का भी प्रवृत्त बड़ी करते हैं। अन्य देशों में तो वही निमासद के लिये स्थान देते हैं, वही काम करने के लिये नियम बनाते हैं, वही उनकी निगरानी करते हैं और वही अन्त में उच्च हुये जेप का निपटारा करते हैं। उपर्युक्त प्रध्याय में इस बात का भी संकेत कर दिया गया था कि बैंकों का अनुभव यह प्रतीत होता है कि एक विशेष समय के अन्दर एक विशेष बैंक के द्वारा द्वारा उक्त पर कटे हुये उन बैंकों की रक्त जो दूसरे बैंकों द्वारा उनके यहाँ बखली के लिये आती है उन बैंकों की रक्त के प्रायः जगार होती है जो उनके पास दूसरे बैंकों के ऊपर भी उक्तके द्वारा इसी काम के लिये आती है। वस्तुतः बैंकों के निमासद की सत्यापना ही इसी निदान के आधार पर की गई है।

काम करने का ढङ्ग

इन्हीं काम करने का दृढ़ बहुवचन ही आधारस्थ है। मान लीजिये कि प्र, च, स, प्रौर द नाम के चार बैंकों के बीच में निकासी का काम होना है। अब इनमें से प्रत्येक के पास जाने वाली निकासी के सम्बन्ध के विशेष तौर पर छपे हुये कागज (Summary sheets of out-clearing) होते हैं जिनमें उन सभी चेकों और बिलों इत्यादि का लेखा कर लिया जाता है जिनकी एक बैंक को अन्य बैंकों से बखली करनी होती है। प्रत. यदि 'अ' बैंक को चेकों और ड्राफ्ट छोटने पर 'ब' बैंक के ऊपर के चेक और ड्राफ्ट मिलते हैं तो वह इन्हें उक्त कागज में 'ब' बैंक का नाम लिखकर, लिख लेता है। इसी तरह से दूसरे बैंकों के ऊपर की रकमें भी अलग-अलग लिख ली जाती हैं। यह प्रत्येक बैंक करता है। इसके बाद चेक, इत्यादि फिर से देखकर उनके अलग-अलग बण्डल बना लिये जाते हैं। फिर, ये बण्डल निकासग्रह में ले जाये जाते हैं और चारों बैंकों के निर्धारित स्थान में प्रत्येक दूसरा बैंक इन्हें रख देता है। वहाँ पर इन बैंकों के कर्मचारी प्राप्त बण्डलों से उसी प्रकार के आने वाली निकासी के कागजातों (Summary sheets of in-clearing) में लेखे करते हैं। जिस प्रकार इनके लेखे जाने वाली

निकासी के कागजातों में पहले किये गये थे। अब यदि 'अ' बैंक को 'ब' बैंक से जो पाना है वह उसको जो उसे देना है उससे अधिक है तब उसे उससे पाना है और यदि इसका उल्टा है तो उसको उसे देना है। अतः, प्रत्येक बैंक से अन्त में जो पाना है अथवा उसे देना है वह एक साधारण चिट्ठे (General Balance-Sheet) में लिख लिया जाता है। इस चिट्ठे में निकासग्रह के सब सदस्य बैंकों के नाम, उनके पाउने और देने के खानों सहित छपे रहते हैं। अब, यदि किसी बैंक से पाना है तो वह पाउने के खाने में और यदि देना है तो वह देने के खाने में लिख लिया जाता है। अन्त में पाउने और देने के जोड़ों का शेष निकाल लिया जाता है और यदि पाउना ज्यादा है तो केन्द्रीय बैंक से अपना एकाउण्ट क्रेडिट करने (जमा करने) और यदि देना ज्यादा है तो अपना एकाउण्ट डेबिट करने (नाम लिखने) को कह दिया जाता है। केन्द्रीय बैंक इन लेखों के दोहरे लेख निकासी के एकाउण्ट (Clearing) में करता है। अब, यदि सब का हिसाब ठीक है तो निकासी के एकाउण्ट में दोनों तरफ के लेखे बराबर हो जाते हैं अन्यथा गलती ढूँढकर ठीक कर ली जाती है। अन्त में 'सब बैंक वाले अपने-अपने रूपर की चेक अपने यहाँ ले जाते हैं और वहाँ पर उनकी जॉच-पढताल करके उनके लेखे कर लेते हैं और यदि वहाँ पर वह ठीक नहीं जँचती तो दूसरे दिन की निकासी में वह बाहर जाने वाली चेकों के साथ वापिस कर दी जाती है।

लाभ

इस संगठन से बैंकों और जनता दोनों को बहुत से लाभ हैं। बैंकों के लिये तो यह इस प्रकार से लाभदायक है कि (१) उन्हें अपने कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न बैंकों में नहीं भेजना पड़ता। केवल एक कर्मचारी निकासग्रह में चला जाता है। (२) उन्हें व्यर्थ में नकदी में भुगतान नहीं करना पड़ता—एक तो प्रत्येक बैंक को भुगतान नहीं किया जाता, दूसरे सब बैंकों को मिलाकर भुगतान भी केवल केन्द्रीय बैंक में जो एकाउण्ट रहता है उसी में लेखा करने से हो जाता है। (३) इससे यह भी लाभ होता है कि बैंकों को अपने पास बहुत कम नकदी रखनी पड़ती है। यह जनता के लिये भी बहुत लाभप्रद है। (१) इससे उसका बहुत कम नकदी से काम चल जाता है। (२) इसके कारण चेकों इत्यादि का जो प्रयोग बढ जाता है उससे भी जो साख की वृद्धि होती है उससे भी जनता का बड़ा लाभ होता है।

अंग्रेजी निकासग्रह

जैसा कि छठे अध्याय में बताया जा चुका है, इंगलिस्तान में, लन्दन में

और ग्यान्ट प्रान्तीय शहरों में स्वतन्त्र निकासण है । इनमें से लन्दन में और सात प्रान्तीय शहरों में तो जहाँ एक आफ इंग्लैण्ड के अपने दफ्तर और शाखाएँ हैं, बैंक अपनी पारस्परिक बाँकी का निपटारा उनके बैंक आफ इंग्लैण्ड में जो स्थानीय एकाउण्ट है उन पर चेकें फाट कर कर लेते हैं । किन्तु उन चार शहरों में जहाँ निवासण तो है किन्तु बैंक आफ इंग्लैण्ड के दफ्तर और शाखाएँ नहीं हैं ऐसा नहीं हो पाता । अतः, वहाँ पर वह काम उनके लन्दन स्थित प्रधान दफ्तर के जो एकाउण्ट बैंक आफ इंग्लैण्ड में हैं उनके द्वारा करवाया जाता है ।

लन्दन में निकासी का काम—लन्दन में निकासी का काम तीन भागों में विभक्त है । (१) शहर से सम्बन्धित निकासी (Town clearing) (२) ग्रन्थ शहरों से सम्बन्धित निकासी (Country clearing) और (३) शहर के दूर स्थित स्थानों से अथवा वृहत् लन्दन से सम्बन्धित निकासी (Metropolitan clearing)

(१) शहर से सम्बन्धित निकासी—के अन्तर्गत वह चेन आता है जो बैंक आफ इंग्लैण्ड के दफ्तर से करीब है । इनकी प्रति दिवस प्रायः दो निष्पत्ती होती है, एक प्रातः और दूसरी मध्यरात में । निकासण एक प्रत्येक सदस्य बैंक हर निकासी के समय प्रत्येक बैंक के ऊपर की प्रथवा उन बैंकों के ऊपर की चेकों के जिनके ये सदस्य बैंक प्रतिनिधि हैं पृथक्-पृथक् मण्डल बनाकर जिन्हें वहाँ पर चार्जेज (Charges) कहा जाता है निकासण के दफ्तर में भेज देता है । वहाँ पर ये आपस में बदले जाते हैं और फिर इनसे लेखे तैयार किये जाते हैं और अन्त में जोड़, हट्वादि ठीक करके बाकी निकाली जाती है । फिर, वह सावाण्ण चिट्ठे में प्रत्येक बैंक के नाम के आगे डेबिट (नाम) अथवा क्रेडिट (जमा) में जैसा होता है लिख ली जाती है । इसके बाद दोनों पक्षों पृथक्-पृथक् जोड़कर उनकी बाकी निकाल ली जाती है । अतः, प्रत्येक बैंक का केन्द्रीय बैंक में एकाउण्ट ता होता ही है । अतः उसी एकाउण्ट में वह बाकी डेबिट अथवा क्रेडिट करके जैसा होता है इसका निपटारा कर दिया जाता है ।

(२) अन्य शहरों से सम्बन्धित निकासी—के अन्तर्गत वृहत् (समूचे) लन्दन को छोड़कर इंग्लैण्ड और वेल्स में फैले हुए सभी बैंकों और उनकी शाखाओं के चेकों की निकासी आ जाती है । लन्दन के बाहर जितने बैंक हैं प्रायः उन सभी ने लन्दन शहर में स्थित किसी न किसी बैंक को

निकासी के लिये अपना प्रतिनिधि अवश्य बना रखा है । अतः, इनके पास उनके जो अन्य बैंकों के ऊपर के चेक, इत्यादि रहते हैं वह आ जाते हैं । इसमें भी निकासी का वही क्रम चलता है जो शहर से सम्बन्धित निकासी में चलता है । हाँ, यह निकासी प्रतिदिन केवल एक बार ही होती है और इसमें साधारण चिट्ठे से जा बाकी निकलती है वह सीधे-सीधे न निपटकर तीसरे दिन की शहर से सम्बन्धित निकासी के साधारण चिट्ठे में शामिल कर ली जाती है । इस देरी का कारण यह है कि ऊपर वाले बैंकों के प्रतिनिधि बैंक जो चेक पाने वाले बैंकों के प्रतिनिधि बैंकों से पाते हैं उन्हें वह ऊपर वाले बैंकों के पास भेजते हैं और वहाँ से उनके सकर जाने पर ही उन्हें निकासी में सम्मिलित करने हैं ।

शहर से दूर स्थित स्थानों से अथवा बृहत् लन्दन से सम्बन्धित निकासी बहुत बाट में प्रारम्भ हुई थी । इसमें उस क्षेत्र के बैंकों को चेको की निकासी होती है जो न तो प्रथम और न दूसरे प्रकार की निकासी में सम्मिलित की जा सकती है । बात यह है कि बृहत् लन्दन का क्षेत्र बहुत बड़ा है । अतः, इससे लन्दन के उन बैंकों को सुविधा दी गई है जो बैंक आफ इंगलैण्ड के दफ्तर से दूर पर स्थित हैं । ये बैंक दस क्षेत्रफल में स्थिति बैंकों की चेकें इत्यादि छोड़कर लन्दन शहर के अपने प्रतिनिधि बैंकों के पास भेज देते हैं जो उन्हें ऊपर वाले बैंकों के अपने यहाँ के प्रतिनिधि बैंकों के बडलों में शामिल कर लेते हैं । इस निकासी से सम्बन्धित साधारण चिट्ठे की बाकी भी दूसरे दिन की शहर से सम्बन्धित निकासी के साधारण चिट्ठे में शामिल कर ली जाती है । इसमें भी प्रतिनिधि बैंक प्राप्त चेक ऊपर वाले बैंकों के पास सकरने के लिये भेजते हैं जिसकी सूचना दूसरे दिन आ जाती है ।

प्रत्येक निकासी की लौट्टी हुई चेक दूसरे दिन की उसी निकासी के लिये जाने वाली चेकों की निकासी में मिला दी जाती है ।

एक बात और ध्यान देने की है कि शहर से सम्बन्धित और बृहत् लन्दन से सम्बन्धित निकासी में चेकें और ड्राफ्ट दोनों सम्मिलित कर लिये जाते हैं किन्तु अन्य गहरों से सम्बन्धित निकासी में केवल चेके ही शामिल की जायी हैं ड्राफ्ट नहीं शामिल किये जाते ।

भारतवर्ष में निकासी

गॉर्चवै अध्याय में यह भी बताया गया था कि हमारे देश में भी रिजर्व बैंक की संस्थापना के पहले से ही कई जगह स्वतंत्र निकासग्रह थे जिनमें कार्य

की देरा-रेल स्वभावतः इंग्लिश बैंक ही अन्य सदस्य बैंकों की ओर ने लिया करता था। फिर, रिजर्व बैंक की गन्यापना होने पर यह काम रिजर्व बैंक के पास आ गया। किन्तु फिर भी कलकत्ता और फानपुर दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर रिजर्व बैंक के प्रमश दफ्तर और शाखा होने पर भी वहाँ के निवासियों की देरा-रेल रिजर्व बैंक के जिम्मे नहीं है। हाँ, बाकी का निपटारा तो अवश्य बैंकों के जो इनके यहाँ एकाउन्ट हैं, उन्हीं पर चेकें काटकर होता है। जिन स्थानों में रिजर्व बैंक का दफ्तर अथवा शाखा नहीं है वहाँ पर इंग्लिश बैंक न केवल निवासियों की देरा-रेल करता है वरन् बाकी का निपटारा भी करता है।

यहाँ पर इस समय अमृतसर, अहमदाबाद, आगरा, अलमोरा, इलाहाबाद, कलकत्ता, फानपुर, कालीकट, कोयम्बर, जालंधर, देहरादून, देहली, नागपुर, पटना, बंगलौर, बम्बई, मंगलौर, मद्रास, मदुरा, लखनऊ, रायकोट, पूना, गया और शिमला में भारतवर्ष में और पराँची, रायलगिषही, लयालपुर और लाहौर में पाकिस्तान में निवासियों हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसे शहर हैं जिनमें बहुत नये बैंक हैं किन्तु निवासियों नहीं हैं—उदाहरणार्थ जमलपुर, जमशेदपुर, बनारस, उरली, मेरठ, सरत इत्यादि हैं। अतः इनमें उन्हें खुलना चाहिये।

इनके अतिरिक्त कुछ स्थानों में लन्दन निवासियों की तरह ही अन्य शहरों से सम्बन्धित निवासियों का प्रबन्ध भी करना चाहिये। इसके लिये कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, फानपुर इत्यादि से प्रारम्भ किया जा सकता है।

भारतीय निवासियों ने कुछ ऐसे नियम बना रखे हैं जिनसे नये बैंक उनके सदस्य नहीं बन पाते हैं, उदाहरणार्थ कोई बैंक तब तक उसका सदस्य नहीं बन पायेगा जब तक तीन चौथाई सदस्य उसके पक्ष में न हों। अस्तु, कहीं-कहीं पर विदेशी बैंकों का प्रभुत्व है। अतः, वह नये भारतीय बैंकों को उनका सदस्य बनने देते। इसके परिणामस्वरूप कलकत्ते में कुछ बैंकों ने एक नई संस्था बना ली है जिसे मेट्रोपॉलिटन बैंकिंग एसोसियेशन कहते हैं। यह संस्था इनकी चेकें इत्यादि के निकासी का प्रबन्ध करती है।

भारतीय निवासियों में भी निकासी का क्रम वही है जो अन्य स्थानों में है। प्रत्येक निवासियों के कुछ सदस्य हैं। इनके अतिरिक्त इनमें कुछ उप-सदस्य भी हैं। जो बैंक सदस्यता की शर्तें पूरी नहीं कर सकते वह उपसदस्य बनने की प्रार्थना करते हैं। यह प्रार्थना किसी सदस्य बैंक द्वारा मंजूर होती है। अस्तु, उपसदस्य बैंकों की ओर से यही सदस्य बैंक निकासी का काम करते हैं।

अन्य देशों के निकासगृह

अमेरिका के निकासगृह बहुत लाभदायक काम करते हैं। वे जमा करने वालों को दिया जाने वाला न्यूनतम व्याज निश्चित करते हैं। साथ ही वे वैकों को ऐसे प्रमाण-पत्र देते हैं जिनके आधार पर उन्हें ऋण प्राप्त हो सकता है इत्यादि, इत्यादि। यूरोप में भी प्रत्येक बड़े देश में निकासगृह स्थापित हैं। हाँ, इनमें उतना काम नहीं होता जितना इंग्लैण्ड और वेल्स में होता है। बात यह है कि यूरोप में चेकों और रेखाङ्कन का चलन उतना नहीं है जितना इंग्लैण्ड और वेल्स में है।

प्रश्न

(१) निकासगृह की परिभाषा दीजिये और यह बताइये कि केन्द्रीय बैंक इस सम्बन्ध में क्या काम करते हैं? यह भी बताइये कि निकासगृहों में किस सिद्धान्त पर काम होता है?

(२) निकासगृह की कार्य-व्यवस्था सक्षेप में किन्तु स्पष्ट तौर पर समझाइये। अपने उत्तर के सम्बन्ध में एक उदाहरण ले लीजिये।

(३) निकासगृह के कौन-कौन से लाभ हैं? उनका वर्णन कीजिये।

(४) इंगलिस्तान को निकासी (Clearing) का वर्णन कीजिये। लन्दन में निकासी (Clearing) का जो प्रबन्ध है उसे विस्तृत रूप में बताइये।

(५) भारतवर्ष में निकासी (Clearing) का क्या प्रबन्ध है? उसका थोड़ा-सा विवरण दीजिये। क्या उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है?

अध्याय १२

भारतीय बैंकिंग

ऐतिहासिक दृष्टि

भारतवर्ष में आधुनिक बैंकिंग का प्रादुर्भाव तो अंग्रेजों के आने के साथ ही हुआ था, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उसके पहले हमारे यहाँ बैंकिंग थी ही नहीं। ऋण देने के प्रमाण तो यहाँ पर वैदिक काल में

ही ईसा से कम से कम दो हजार वर्ष पहले मिलते हैं। ऋग्वेद और अथर्व-वेद में 'ऋण' शब्द बार-बार आया है। फिर ऋण देने वाले महाजनों के नाम बौद्ध पुस्तकों (जातकों) में भी मिलते हैं जो गिन्टि भिन्स के अनुसार ईसा से पाँच-छे मी वर्ष पहले से सम्बन्धित हैं। इसके बाद सरस्वती नगर के महाजनो ने विरोजशाह को (१३५१-८८) बहुत काफी रक्कम उधार में दी थी जिसे उसने फौज के खर्च में लगाया था। इसी तरह ने हम साय-पत्रों का भी जन्म मिलता है। भगवान् कृष्ण के समय की एक कथा प्रसिद्ध है जिसमें जूतागढ़ के नरसिंह भगत ने द्वारिजापुरी के सेठ सौबल माह के ऊपर एक हुण्डी की थी। सम्भव है कि यह केवल कथा ही हो, क्योंकि बौद्ध पुस्तकों के और सूत्रों के समय तक हुण्डी का अर्थ कहीं जिक्र नहीं पाया जाता। किन्तु कुछ शहरों के बड़े-बड़े व्यापारी साय-पत्र (Letters of credit) तो अत्यन्त निकलते थे। इसके अलावा जमा का काम भी होता था—यहाँ तक कि ईसा की दूसरी और तीसरी शताब्दी में मनु के समय तक यह कामो बढ़ गया था क्योंकि उसने अपनी स्मृति में जमा और गिरवी पर एक पूरा अध्याय लिखा है। साथ ही सिक्कों के विनिमय का काम भी बहुत पहले ही होने लगा था और मुगलकाल तक तो यह बहुत ही अधिक उन्नति कर चुका था। बात यह है कि उस जमाने में बहुत से नये-नये सिक्के बनाये गये थे, जिनमें से कुछ तो एक ही नाम के थे, यद्यपि प्रत्येक का राजारू दर भिन्न था। इन सबसे यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष के ऐतिहासिक काल में तो अवश्य ही यहाँ पर बैंकिंग की एक ऐसी सुबढ़ प्रणाली चालू थी जो यहाँ की आवश्यकताओं के लिये पूर्ण रूप से उपयुक्त थी। हाँ, यह पश्चिमी प्रणाली से अवश्य भिन्न थी।

आधुनिक बैंकों के प्रवेश के पहले देशी बैंकों (Indigenous Bankers) का महत्त्व

आधुनिक बैंकों के प्रवेश के पहले यहाँ पर देशी बैंकों का बहुत महत्त्व था। उस समय के महाजनों के धनी-मानी होने से उनके व्यवसाय का लाभ-प्रद होना तो स्वयं विद्व है। इसके अतिरिक्त पश्चिम के यहूदियों के विपरीत, जनता और सरकार दोनों ही उन्हें बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि औरङ्गजेब जैसा धर्मरायण बादशाह भी उनका बड़ा सम्मान करता था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसने उस समय के सबसे प्रसिद्ध महाजन मानिकचन्द को 'सेठ' की उपाधि से विभूषित किया था। उसके बाद बादशाह

फर्खतियर ने अपने समय के महाजन फतेहचन्द को जो सेठ मानिकचन्द का दत्तक पुत्र था 'नगत सेठ' की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली उपाधि प्रदान की थी। फिर, इनका सम्बन्ध अंग्रेजों से भी बहुत अच्छा रहा। रेवेरेण्ड जे० लाद् के लेख के अनुसार क्लाइव ने सन् १७५६ में उस समय के नगत सेठ की चार दिन की आवभगत में १७३४ रु० खर्च किये थे जिसका बदला उसने उसका बगाल के नवाब के विरुद्ध साथ देकर दिया था। अब, जहाँ तक इनकी व्यवसाय कुशलता का प्रश्न है उसके लिये हम सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री जे० बी० टेवरनियर का लेख देख सकते हैं। उसने लिखा है कि इटली के सब यहूदी जो द्रव्य और विनिमय के काम में बहुत ही दक्ष हैं, भारतवर्ष के इन महाजनों के यहाँ काम सीखने वालों की भी मुश्किल से बराबरी कर सकते हैं।

देशी बैंकों की अवनति

किन्तु इनका व्यवसाय और इनकी शक्ति धीरे-धीरे कम होने लगी— यहाँ तक कि अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक इनका महत्त्व बहुत ही घट गया था। इसके निम्न कारण थे—

(१) अंग्रेजी व्यापारी इनकी लिखावट न समझ सकने के कारण इनका प्रयोग नहीं कर सके।

(२) इनका चलन भी नहीं बदला। ये अपने ही ढंग प्रयोग में लाते रहे और केवल कृपि, हाथ की कारीगरी तथा देशी व्यापार ही की सहायता करते रहे।

(३) यद्यपि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बहुत दिनों तक यहाँ पर पश्चिमी बैंकों को नहीं आने दिया किन्तु अन्त में वह आ ही गये और देशी महाजनों के व्यवसाय के कुछ अंगों में उनकी होड़ करने लगे और अन्त में उन्हें पछाड़ दिया।

(४) मुगल साम्राज्य की अवनति के बाद जो गडबड़ी मची थी उसके कारण भी देशी महाजनों की बहुत हानि हुई। प्रायः उन लोगों की जो रकम राजाओं इत्यादि के यहाँ थी वह वसूल नहीं हो सकी।

1 All the Jews who occupy themselves with money and exchange in the empire of the Grand Seigneur pass for being very Sharp, but in India they would scarcely be apprentices to these!

(५) देशी मद्रास तथा बेंगलूरु इत्यादि करने लगे जिनसे यह प्रतीत हो गये और अन्त में उनका व्यवसाय निर गया ।

(६) सन् १८३५ के बाद ब्रिटिश भारतीय कम्पनी अपने देश में चल जाने के कारण उनका विनिर्माण व्यवसाय भी अन्त हो गया जिससे उनकी पक्षी पानि हुई ।

(७) रेल, वायुयान, डाक और तार इत्यादि गुल जाने के कारण व्यापारिक मार्ग और सम्पन्न बढत गये जिससे भारतीय व्यापारियों को विदेशी व्यापारियों के लिये जगह छोड़नी पड़ी और वे अपने ही देशों को अधिक काम देने लगे ।

आधुनिक बैंकों की संस्थापना

जहाँ तक ज्ञात है सन् १८०० में पहला आधुनिक बैंक मद्रास प्रान्त में गुला या, यद्यपि पोर्तुगल पुस्तकों में कलकत्ते की आदती कोठियों के बैंकों (Calcutta Agency Houses) का जिक्र है । यह सरकारी बैंक था और इसका प्रमुख काउन्सिल के सदस्यों के हाथ में था । शायद यह सन् १६८८ में गुला या । क्रि. सन् १७२८ में बम्बई सरकार ने बम्बई शहर में ऐसा ही एक बैंक खोला । इसके बाद मद्रास में कई निज बैंक खुले और एक अन्य सरकारी बैंक भी गुला । पहिले तो ये सब बैंक जमा प्राप्त करने और एकाङ्क रखने के लिये खोले गये थे किन्तु बाद में इन्होंने अपने नोट भी चलाने प्रारम्भ कर दिये । बंगाल में सबसे पहिले आधुनिक बैंक कलकत्ते की आदती कोठियों द्वारा खोले गये । ये कलकत्ते की आदती कोठियाँ व्यापारिक सत्कार्य थीं और विशेषतः चाय और नील का काम करती थीं । बैंकिंग का तो इनका एक अतिरिक्त व्यवसाय था । अलेक्जेंडर एंड कम्पनी ने कुछ अन्य कम्पनियों के साथ मिलकर सन् १७७० में बैंक आफ हिन्दुस्तान खोला । बंगाल बैंक और जनरल बैंक आफ इंडिया लगभग सन् १७८६ में खुले । इनमें से प्रथम तो किसी भी आदती कोठी से सम्बन्धित नहीं था । और १६ मार्च सन् १७८६ के कलकत्ता गजट के अनुसार उसे व्यापार करने की मनाही भी थी । जहाँ तक दूसरे बैंक का प्रश्न है, अभी तक यही ज्ञात है कि वह सारे ब्रिटिश साम्राज्य में सीमित दायित्व का सबसे पहला बैंक था । वास्तव में इंगलिस्तान में यह सीमित दायित्व का सिद्धान्त बहुत देर में अर्थात् सन् १८५५ में लागू किया गया और वह भी बैंकों के लिये नहीं । बैंकों के लिये तो यह वहाँ सन् १८५७ के संकट (Crisis) के बाद माना गया और तब भी नोट इससे अलग

रखे गये। भारतवर्ष में इस सिद्धान्त को सन् १८६१ के भारतीय कम्पनी विधान में स्थान दिया गया।

जनरल बैंक आफ इंडिया उत्तरोत्तर वृद्धि करता गया। शीघ्र ही यह सरकार का बैंक बना दिया गया। वास्तव में इसका प्रबन्ध बहुत ही अच्छे हाथों में था और इसीसे इसने अपने प्रतिद्वन्द्वियों, विशेषकर बैंक आफ हिन्दुस्तान तथा बंगाल बैंक को पछाड़ दिया। किन्तु सन् १७८७ में अनेक वेसिटर पैर की बातें कही गईं और अनुचित आलोचना की गई। फिर, सन् १७८८ के दुर्भिक्ष के बाद जब यह सरकार को ८ प्रतिशत के व्याज से ऋण न दे सका तब सन् १७८९ में इसका सरकार से सम्बन्ध विच्छेद हो गया। इस वर्ष के अन्त तक बारम्बार की माँग पूरी न कर सकने के कारण बङ्गाल बैंक भी बन्द हो गया। केवल बैंक आफ हिन्दुस्तान ही बच रहा। इसने न केवल सन् १७९१ के सकट का बरन् सन् १८१६ और सन् १८२९ के सकटों का भी बड़ी सफलता से सामना किया। किन्तु अन्त में सन् १८३२ में अलेक्जेंडर एव कम्पनी के जिससे कि यह प्रारम्भ से ही सम्बन्धित था फेल होने पर यह भी फेल हो गया। आदमी कोठियों द्वारा खोले गए अन्य बैंकों का भी यही हाल हुआ। मैसर्स पामर ऐण्ड कम्पनी द्वारा खोला गया कलकत्ता बैंक तो सन् १८२९ में ही फेल हो चुका था। मैसर्स मैकिंटोश ऐण्ड कम्पनी से सम्बन्धित कमर्शियल बैंक आफ कलकत्ता सन् १८३३ में भङ्ग हो गया। ये सब बैंक नोट भी निकालते थे, अतः, इनके फेल होने से न केवल इनमें र० जमा करने वालों को ही जिनमें बहुत-सी विधवायें और बहुत से पेन्शन पाने वाले भी थे वरन् नोट रखने वालों की भी बड़ी हानि हुई। यह सब यूरोपीय धन्ये थे। अतः, इनके फेल होने का दायित्व भारतीयों के सिर नहीं मढ़ा जा सकता।

प्रेसीडेन्सी बैंक

बैंक आफ बंगाल जो कि सर्वप्रथम प्रेसीडेंसी बैंक था सन् १८०६ में कलकत्ता बैंक के नाम से स्थापित हुआ था, और उसे सन् १८०९ में बैंक आफ बंगाल के नाम से अधिकार-पत्र प्राप्त हुआ था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कोई विशेष जोखिम और असुविधा उठाये बिना जनता की सेवा करना और आवश्यकता पड़ने पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार को आर्थिक सहायता देना था। इसका एक उद्देश्य मुद्रा की पूर्ति करना भी था। सन् १८२३ में इसे नोट चलाने की भी आज्ञा प्रदान कर दी गई और सन् १८३६ में इसे अपनी शाखायें खोलने और भारतीय विनिमय का काम करने

भी भी आग दे दी गई—विदेशी विनिमय का काम करने की आग इसे नहीं मिली। बंगाल की सरकार ने इसके कार्य रद्द की सीमा के अन्दर रखने के उद्देश्य ने इसके प्रबन्ध में भाग लेने के लिए इसकी पंचमाश पैली भी अपने पास ले ली थी। अतः, बैंक का मेकेटिंग प्राय सिविल सर्विस का मदम्य होता था और कुछ सचालकगण (Directors) भी सरकार चुनती थी।

बैंक आफ बम्बई और मद्रास भी क्रमशः सन् १८४० और १८४३ में स्थापित हुए और इनकी पैली के भी कुछ हिस्से इनकी सरकारों ने बट्टाल की सरकार की तरह ही लिये। ये भी नोट चलाने थे। तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों की सरकार का बैंकिंग व्यवसाय करने का एकाधिकार भी दिया गया था। किन्तु नोट चलाने का अधिकार इनने सन् १८६१ में छीन लिया गया क्योंकि उन वर्ष स्वयं सरकार ने इसका एकाधिकार ले लिया। हाँ, नोट चलाने का अधिकार छीन लेने में इनकी जो क्षति हुई थी उसकी पूर्ति के लिये सरकार की नकदी प्रेसीडेन्सी शाहों में तथा अन्य स्थानों में जहाँ इनके दफ्तर और इनकी शाखाएँ, थीं इनके पास इनसे कुछ व्याज लिये बिना ही रकम जाने लगी।

सन् १८६८ में एक विशेष घटना घटित हो गई जिसके फलस्वरूप सरकार का प्रेसीडेन्सी बैंक से जो सम्बन्ध था उसमें एक बड़ा भारी परिवर्तन हो गया। यात यह थी कि अमेरिका के घरेलू युद्ध के कारण रूई की कीमत बढ़ गई थी और उसमें सट्टेबाजी होने लगी थी। अतः, बैंक आफ बम्बई इसमें फँस गया जिससे उसकी बड़ी हानि हुई। इसके फलस्वरूप उसे भङ्ग कर दिया गया। किन्तु फौरन ही एक दूसरा बैंक उसी नाम से एक करोड़ रुपये की पैली से गोल दिया गया। पुराने बैंक की जमा की रकम तो सब दे दी गई, किन्तु हिस्सेदारों को लगभग कुछ नहीं मिला। अतः, सरकार ने इसके बाद बैंक आफ बंगाल और मद्रास के हिस्से भी बेच दिये और फिर वह किसी भी बैंक को न तो सचालक चुन सकती थी और न उसके कार्यों में भाग ले सकती थी। साथ ही बैंक आफ बम्बई के फेल होने के कारणों का पता लगाने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति की गई और उसकी रिपोर्ट निकलने के बाद सन् १८७६ में एक प्रेसीडेन्सी बैंक विधान पास किया गया जिसके अनुसार इन बैंकों के कामों पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये। सक्षेप में ये निम्नांकित थे—

(१) वे विदेशी विनिमय का काम नहीं कर सकते थे।

(२) उन्हें भारतवर्ष से बाहर उधार लेने और जमा प्राप्त करने की भी मनाही कर दी गई थी।

(३) वे छः महीनों से अधिक के लिये उधार नहीं दे सकते थे ।

(४) उन्हें रेहन पर, अचल सम्पत्ति की जमानत पर, दो स्वतंत्र व्यक्तियों से कम द्वारा लिखे गये प्रण-पत्रों पर और माल पर जब तक कि वह माल अथवा उसके सम्बन्धी अधिकार-पत्र उनके पास न रख दिये जायें उधार देने की मनाही कर दी गई थी ।

वे अब सरकार की नकदी का भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सकते थे । बात यह थी कि प्रेसीडेंसी शहरों में सरकार के स्वयं के सुरक्षित कोष (Reserve Treasuries) खुल गये और उन्हीं में उसकी अधिकांश नकदी रक्खी जाने लगी । प्रेसीडेंसी बैंकों के पास सरकार की बहुत कम नकदी रहती थी ।

यद्यपि ये बैंक जमा प्राप्त करते थे, देशी बिल डिस्काउण्ट करते थे और वहाँ के सरकारी ऋण का प्रबन्ध करते थे, तो भी यह विदित हो गया था कि ये केवल प्रेसीडेंसी शहरों के लिये ही अथवा अधिक से अधिक थोड़े से बड़े-बड़े व्यापारिक शहरों के लिये ही उपयोगी थे, अन्य स्थानों के लिये नहीं । वास्तव में इनमें निम्न दोष थे—

(१) इनके बीच में किसी प्रकार का एकीकरण नहीं था । वास्तव में बैंक आफ बङ्गाल को सारे भारतवर्ष का बैंक बनाने की मॉग ईस्ट इंडिया कम्पनी के सञ्चालक बोर्ड के सामने सन् १८३६ ही में रखी जा चुकी थी । फिर सन् १८६० और ७६ में भी यह मॉग दोहराई गई । सन् १८६८ में भी फाउलर कमीशन के सामने कुछ लोगों ने एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की मॉग रखी । सन् १९१३ में चैम्बरलेन कमीशन ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक अनुभवी कमेटी की नियुक्ति का सुझाव पेश किया । प्रथम महायुद्ध के समय एक केन्द्रीय बैंक की अनुपस्थिति बहुत ही खली ।

(२) इन्होंने केवल उन्हीं स्थानों में अपनी शाखाएँ खोली थीं जिनमें उन्हें लाभ मिलने की सम्भावना थी । जिस समय ये तीनों बैंक एक किये गये, उस समय सब मिलाकर इनकी केवल ५६ शाखाएँ थीं ।

(३) देश के व्यापार को सहायता पहुँचाने के लिए इनके पास काफी रकम नहीं थी । इनकी सब की मिलाकर केवल ३३ करोड़ रुपये की पूँजी थी, इनका सुरक्षित कोष केवल ३, ७७, ७६,००० रु० था और इनकी जमा की रकम इनके एकीकरण के समय सन् १९२० में ८७,०४,५३,००० रु० थी । सरकार की अधिकांश नकदी उसके कोष और उपकोष में फालतू पड़ी रहती थी ।

(४) यहाँ के चालू नोटों के देश की व्यापारिक माँग के अनुसार घटने-बढ़ने के लिये फोर्ड प्रणाली नहीं था, परन्तु, उससे व्याज और डिस्काउण्ट की दरा में बहुत कमी वेशी होती रहती थी। सरकार का नियन्त्रण तो पार्लो पर था और माँग पर जो कुछ नियन्त्रण था वह प्रेमीडेंटों वैंकों का था। अतः, इनमें फोर्ड प्रणाली नहीं था।

(५) ऊपर जो पहले दो चरण दिये हुए हैं वह केवल जोगिम ने पचाने के लिये थे। किन्तु विनिमय दर स्थिर हो जाने पर भी जब विनिमय के काम में फोर्ड जोगिम नहीं रह गई तब भी यह प्रणाली चलते रहे। तीनों बैंकों ने लन्दन और भागनरप में उधार लेने और विदेशी विनिमय में काम करने की एक मयुक्त माँग सरकार से सन् १८७७ में पेश की थी। सन् १८८६ में बैंकों की माँग पर विचार करने के लिये एक मभा भी हुई थी किन्तु जनता के इनके पक्ष में रहने पर भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। लन्दन में उधार लेने का प्रश्न तो परावर अन्धरी तरह ने विचार किये बिना ही अस्वीकृत कर दिया जाता था।

(६) ये न तो बैंकों के बैंक ही थे और न अन्य किसी जगह ने उधार मिलने पर उधार देने का ही दायित्व स्वीकार करते थे। सब तो यह है कि यह इतने मजबूत ही नहीं थे कि उपर्युक्त कार्य कर सकने। जो हो, इन्होंने तो उतना भी नहीं किया जितना ये कर सकते थे।

स्वतन्त्र व्यापारिक बैंक

आदती कोठियों द्वारा स्थापित किये गये बैंकों के सन् १८३३ में फेल हो जाने के बाद, यहाँ पर स्वतन्त्र व्यापारिक बैंक खुले। सन् १८६० तक ये अपरिमित दायित्व के सिद्धान्त पर रहे। इसी बीच में सी० एच० कुक के अनुसार यहाँ पर लगभग १२ बैंक खुले और उनमें से लगभग आधे फेल भी हो गये। बात यह थी कि जब तक आदती कोठियाँ थीं तब तक तो वे सरकारी कर्मचारियों के लिये बैंकिंग का काम करती थीं। किन्तु सन् १८२६-३२ के संकट काल के समय इनके फेल हो जाने के बाद, बड़ी कठिनाई पड़ी। अतः, वह कठिनाई दूर करने के लिए शीघ्र ही आगरा ऐण्ड युनाइटेड सर्विस बैंक तथा गवर्नमेन्ट सेविंग्स बैंक, कलकत्ता खुले। फिर, आगरा सेविंग्स बैंक और अन्कवेनेटेड सर्विस बैंक स्थापित किये गए। किन्तु यह बैंक भी दीर्घ काल तक नहीं चल सके। इनके फेल हो जाने के कारणों में सट्टेबाजी और जालसाजी मुख्य थे। बात यह थी कि उस समय एकाउण्ट का निरीक्षण ठीक

नहीं था। अच्छी बैंकिंग के लिये अच्छा एकाउण्ट निरीक्षण बहुत ही आवश्यक है। जो हो, इस काल के कुछ बैंकों ने बड़ा अच्छा काम किया।

सन् १८६० भारतीय बैंकिंग के लिये विशेष महत्व का था। उस वर्ष यहाँ पर बैंकों को सर्वप्रथम सीमित दायित्व के सिद्धान्त की सुविधा दी गई। अतः, इसके फलस्वरूप और अमेरिका के घरेलू युद्ध के कारण वहाँ से रुई का निर्यात रुक जाने से भारतीय रुई की जो कीमत बढ़ गई थी उससे यहाँ पर जो धन-वृद्धि हो गई उसके फलस्वरूप यहाँ पर विशेषतः सन् १८६४-६५ में लगभग २५ बैंक खुले, किन्तु ये सब बहुत शीघ्र ही काल कवलित हो गये। सत्य तो यह है कि जिस सट्टे के कारण ये उत्पन्न हुये थे उसकी समाप्ति पर ही यह भी समाप्त हो गये। हाँ, बैंक आफ अरर इण्डिया जो सन् १८६४ में खुला था अवश्य सन् १९१४ तक चला।

सन् १८६५-१९०५ का समय विधाम का समय था। इन चालीस वर्षों में बहुत कम बैंक खुले। किन्तु जो खुले उनमें से कुछ ने तो बड़ा काम किया। इलाहाबाद बैंक जो सन् १८६५ में खुला था, आज तक है और पाँच बड़े बैंकों में से एक है। अलायन्स बैंक आफ शिमला सन् १८७४ में खुला था। यह बहुत ही सफल रहा और सन् १९२३ में जब फेल हुआ तब केवल अपने अभाग्य ही के कारण फेल हुआ। सन् १९२१ के उसके जो अर्द्ध प्राप्त हैं उनसे उसकी सुदृढ़ स्थिति का पता चलता है—

प्राप्त पूँजी	८८ लाख रु०
सुरक्षित कोष	५३ लाख रु०
स्थायी जमा	६०० लाख रु०
चालू जमा	६७६ लाख रु०
कुल जमा	१,६२७ लाख रु०
नकद रोकड़ा	४३६ लाख रु०
शाखाये	३६

अवध कमर्शियल बैंक सन् १८८१ में रजिस्टर्ड हुआ था। इसका प्रधान आफिस फैजाबाद में है। यह रिजर्व बैंक का सदस्य बैंक (Scheduled Bank) है। पंजाब नेशनल बैंक सन् १८६४ में खुला और इस समय यहाँ के पाँच बड़े बैंकों में से एक है। पिउपिल्स बैंक सन् १९०१ में खुला और सन् १९१३ में बन्द हो गया। इसका एक मात्र उद्देश्य औद्योगिक सहायें खोलना और चलाना था। किन्तु जिन परिस्थितियों में इसने यह काम अपने ऊपर लिया था वह सतोषजनक न थीं। उद्योग-धन्धे या तो थे ही नहीं या

अधूरी हालत में थे। अतः, इसके प्रबन्ध सचालक ने स्वयं ही फंड काम चले और उनका प्रबन्ध किया जिसका फल यही हुआ जो बैंकिंग और व्यापार सम्मिलित करने का होता है। ऐसी हालत में बैंकिंग के सिद्धान्त नहीं निभा पाते। सन् १९१० में हमनी जो स्थिति थी उसका पता नीचे दिये हुए अंशों में मालूम हो सकता है।

प्राप्त पैसे	११ ५ लाख रु०
मुद्रित फीस ..	१ ८ लाख रु०
जमा	६८ ४ लाख रु०
नफ़ा साख, मिल, प्रणपत्र	
और अधिभिर्य ७६ ३ लाख रु०	
दूसरे बैंकों के यहाँ जमा २ ४ लाख रु०	
ड्राफ्ट की राशि	१ ६ लाख रु०
अव्यय और दूसरी लागत ४ २ लाख रु०	
सरकारी ऋणज	४ २ लाख रु०
नक़द रोकड़ और बैंक में ७ १ लाख रु०	

सन् १८६५ में जो बैंक फेल हुये थे उसने बैंक स्थापकों की हिम्मत टूट गई थी। जो बैंक फेल हुये थे वे भारतीय और यूरोपीय दोनों के प्रबन्ध में थे। हम जानते हैं कि बैंक आफ़ चम्पई जैसा मजबूत बैंक भी अपमानित हो चुका था और प्रधानतः सन् १८६५ से सट्टे के कारण जो सकट पैदा हो गया था उसी के फलस्वरूप सन् १८६८ में भङ्ग किया जा चुका था। किन्तु उपर्युक्त विश्राम का एक अन्य कारण भी था जिससे स्थिति बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है। हमें ज्ञात है कि चोँदी का मूल्य सोने में सन् १८७१-७२ के बाद गिरने लगा था। अतः, भारतवर्ष के उस समय रजतमान पर होने के कारण, चोँदी के मूल्य में जो भी कमी होती थी उसका प्रभाव रुपये के विनिमय दर पर पड़ता था। इससे देश के विदेशी व्यापार में अनिश्चितता आ गई और उससे उद्योग-धन्धों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। यह स्थिति सन् १८६३ तक रही। फ्रन्सी की कठिनाइयों ने बैंकिंग पर दोहरा प्रभाव डाला। एक तो लोगों का ध्यान बैंकिंग की स्थापना की ओर से हटकर द्रव्य की इकाई स्थिति करने की ओर लग गया, और दूसरे व्यापार की अनिश्चितता से ऐसी परिस्थितियाँ और ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया जो बैंकों की स्थापना के विरुद्ध था।

इसके बाद के काल में सन् १९०६-१३ का विदेशी आन्दोलन चला जिसके फलस्वरूप इस बीच में ६८ बैंक स्थापित किये गये। इनमें से बहुत-से बहुत छोटे थे और सन् १९१३-१६ में फेल हो गये। किन्तु आजकल के बहुत से महत्वशाली बैंक भी इसी समय चालू हुए थे। इस समय के पाँच बड़े बैंकों में से दो तो जैसा कि पहिले ही बताया जा चुका है इसके पहले के काल में स्थापित हो चुके थे। अन्य तीन इसी काल में खुले थे। बैंक आफ इन्डिया सन् १९०६ में रजिस्टर्ड हुआ था, बैंक आफ बरोदा सन् १९०६ में और सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया सन् १९११ में रजिस्टर्ड हुये थे। अन्य बैंकों में से जो इस समय स्थापित हुए थे और आज तक चल रहे हैं, ये मुख्य हैं — इन्डियन बैंक (१९०७), पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक (१९०८) और बैंक आफ मैसूर (१९१३)। ये सभी रिजर्व बैंक के सदस्य बैंक (Scheduled Bank) हैं।

प्रथम युद्ध और युद्धोत्तर की तेजी ने बैंकिंग को एक और प्रोत्साहन दिया। सबसे पहिले टाटा इन्डस्ट्रियल बैंक सन् १९१८ में खुला। इसका भविष्य बड़ा ही उज्ज्वल प्रतीत होता था। किन्तु दीर्घकालीन और साधारण बैंकिंग के काम साथ-साथ करने के कारण और अधिकांश यूरोपीय कर्मचारियों की जिनके हाथ में इसका काम था, अनभिज्ञता तथा उसीसे उत्पन्न साधारण जनता और भारतीय कर्मचारियों की उदासीनता के फलस्वरूप यह फेल हो गया और सन् १९२३ में सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया के साथ मिला दिया गया। फिर, इन्डस्ट्रियल बैंक आफ वेस्टर्न इन्डिया, कारनानी इन्डस्ट्रियल बैंक, यूनियन बैंक आफ इन्डिया तथा अन्य कई बैंक जो आज तक चालू हैं और रिजर्व बैंक के सदस्य बैंक हैं इसी समय खुले। किन्तु बहुत से अन्य बैंक भी इसी अवधि के बीच में खुले जो केवल फेल होने वाले बैंकों की संख्या बढ़ाने के लिये ही थे। यद्यपि सन् १९१३-१६ के सकट की उग्रता कम हो गई तो भी सन् १९१६-२५ में भी बैंक फेल होते रहे। सब मिला कर इस अवधि में ५१ करोड़ ६० की पूँजी के ८४ बैंक फेल हुए जिनमें अलायन्स और टाटा जैसे सुदृढ़ बैंक भी थे।

इसके बाद के काल में भी बहुत से छोटे और बड़े बैंक स्थापित हुये। किन्तु द्वितीय युद्ध काल अर्थात् सन् १९४०-४५ के बीच में इनमें विशेष तौर पर उन्नति हुई। इसके मुख्य कारण निम्नांकित थे।—युद्ध की परिस्थितियों सुधर जाने के कारण विश्वास की मात्रा बढ़ जाना, युद्ध सम्बन्धी परिस्थितियों के कारण आर्थिक लेन-देनों की वृद्धि और सरकार द्वारा मित्र राष्ट्रों की

तरफ से फल करने के कारण कन्ती के परिमाण में अत्यधिक वृद्धि पाँच लाख और उससे अधिक की पूँजी और सुरक्षित कोष वाले सम्मिलित पूँजी के बैंकों की सख्या सन् १९२६ के २८ से बढ़कर सन् १९४० में ५८ (४१ सदस्य बैंक और १७ साधारण बैंक) और सन् १९४६ में १०० सदस्य बैंक हो गई थी। इसी तरह ने एक लाख और पाँच लाख के बीच वाले बैंकों की सख्या सन् १९२६ में ४७, सन् १९४० में १२० और सन् १९४५ में १७४ थी। हाँ, पचास हजार और एक लाख के बीच वाले बैंक सन् १९४० और सन् १९४५ में क्रमशः १२१ और ११४ थे और पचास हजार से नीचे वाले बैंक इन दोनों वर्षों में क्रमशः ३३२ और २४४ थे। छोटी पूँजी वाले बैंक अब कम खुलते हैं। विशेषतः पचास हजार से कम पूँजी वाले बैंकों का गुलनाम तो सन् १९३६ में विधान द्वारा ही रद्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो ऐसे बैंक हैं भी उन्हें अपने सुरक्षित कोष बढ़ाकर अपनी पूँजी बढ़ाने के लिये बाध्य किया जा रहा है।

इन वर्षों में बैंक फेल भी काफी हुये। सन् १९३१ में जिस वर्ष सबसे कम बैंक फेल हुये थे वह सख्या १८ थी और सन् १९४० में जिस वर्ष सबसे अधिक बैंक फेल हुये थे वह सख्या १०२ थी। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि सन् १९३६ के पड़ले जब भारतीय कम्पनी विधान में 'बैंक' शब्द की परिभाषा थी ही नहीं। यहाँ पर बैंक फेल होने का कोई विशेष अर्थ नहीं था। बात यह थी कि उस समय तक कोई भी सस्था चाहे वह बैंकिंग का काम करती रही हो अथवा नहीं अपने को बैंक कह सकती थी। अतः ऐसी सस्थाओं के फेल होने से यही समझा जाता था कि बैंक ही फेल हुये हैं, किन्तु वास्तव में यह बात न थी। फिर, प्रायः थोड़े ही दिनों के खुले हुये और थोड़ी ही पूँजी वाले बैंक ही अधिक फेल होते थे। हाँ बैंक आफ अपर इंडिया, अलायन्स बैंक आफ शिमला, पिउपिल्ल बैंक और टाटा इन्स्ट्रियल बैंक का फेल होना अत्यन्त कुछ अर्थ रखता था। किन्तु सन् १९३६ से तो बैंकों के फेल होने के विशेष अर्थ हैं यद्यपि इधर भी प्रायः कमजोर बैंक ही फेल हुये हैं। हाँ कुछ बड़े बड़े बैंक भी फेल हुये हैं। जैसे शिवराम अय्यर बैंक, मद्रास, बङ्गाल नेशनल बैंक ट्रावनकोर नेशनल ऐन्ड किलन बैंक, बनारस बैंक, और अभी हाल ही में ज्वाला बैंक। इनका फेल होना बहुत ही शोचनीय बात है। और विशेषतः इसलिए कि यह सदस्य बैंक थे।

इम्पीरियल बैंक

यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि सारे देश के लिए एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता तो सन् १८३६ से ही प्रतीत होने लगी थी। अतः, सन् १८२० में उस वर्ष के इम्पीरियल बैंक विधान द्वारा तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों का एकीकरण करके एक इम्पीरियल बैंक बनाया गया। इसकी प्राप्त पूँजी ५६२ करोड़ रु० रखी गई और इसे जनता के हित में काम करने के लिए कहा गया। यही कारण था कि इसके केन्द्रीय मंडल के १६ शासकों में से १० की नियुक्ति सपरिषद् गवर्नर-जनरल के हाथ में रखी गई। इसका निर्माण निम्न भाँति होता था—

(१) सपरिषद् गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्ति—

(अ) केन्द्रीय मण्डल की सिफारिश पर विचार करते हुए दो प्रबन्ध शासक (Managing Governors) ।

(ब) भारतीय हित का प्रतिनिधित्व करने वाले चार गैरसरकारी शासक ।

(स) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के तीनों स्थानीय मण्डलों के तीन भन्नी ।

(द) करन्सी संचालक (Controller of Currency) ।

(२) हिस्सेदारों द्वारा निर्वाचित—तीनों स्थानीय मण्डलों के सभापति और उप-सभापति ।

जिन बातों का सम्बन्ध सरकार की आर्थिक नीति अथवा उसका इसके पास जो नकद कोष रहता था उसकी रक्षा से होता था उनमें सरकार इसे कोई भी आदेश दे सकती थी। वह इसके कामों, कागजातों, पाउने और देने की सूची के सम्बन्ध में इसके किसी प्रकार की पूछ-ताछ भी कर सकती थी। वह इसके हिसाब की जाँच-पड़ताल करने और उस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए अपने निरीक्षक (Auditors) भी नियुक्त कर सकती थी। अन्तिम, नए स्थानीय दफ्तर और मंडल खोलने के पहिले बैंक को उसकी स्वीकृति प्राप्त कर लेना भी आवश्यक था ।

इस बैंक और भारत सचिव के बीच में एक समझौता भी हुआ था जिसमें यह तै पाया था कि बैंक सरकार के सब बैंकिंग के कार्य करेगा और उसके ऋण की भी व्यवस्था करेगा। साथ ही यह भी कि यह अपनी संस्थापना के पाँच वर्षों के अन्दर अपनी सौ नई शाखाएँ खोलेंगे जिनमें से कम से कम पच्चीस का स्थान स्वयं सरकार निश्चित करेगी। इनके एवज में जहाँ जहाँ इसकी

जापान या यहाँ पढ़ा इसे सरकार का नरुद कोष अपने पास रखने का अधिकार दिया गया था और यह अपना कोष कम्पनी द्वारा जहाँ चाहे वहाँ कुछ प्रतिफल दिए बिना ही भेज सकता था। इसके अतिरिक्त जिन दो म्यानों ने दूसरी गांथायें थी उनके बीच में सरकार ने कर्न्सी ट्रांसफर (Currency Transfer) और सप्लाई बिल (Supply Bills) न निकालने का वचन दिया था। हाँ, इसके लिए उसने कर्न्सी भ्र्वालक से म्नीशुत कमीशन पर जनता को एक जगह से दूसरी जगह द्रव्य भेजने की सुविधा देना स्वीकार किया था।

फिर, विधान ने यह भी निर्धारित कर दिया था कि यह बैंक बैंकिंग के धोन धान से काम नहीं कर सकेगा। इसके अलावा इने अन्दी श्रुतु म द्रव्य बाजार की सहायता करने की सुमता प्रदान करने के लिए मन्जर के कागजी मुद्रा विभाग को इसे देगी। विला और हुंडियो की जमानत पर १२ करोड़ ५० लक की अतिरिक्त कर्न्सी, पहले चार करोड़ तक तो ६ प्रतिशत व्याज पर और शेष ग्राट करोड़ ७ प्रतिशत व्याज पर, उधार रूप में दे देने का अधिकार दे दिया गया था।

किन्तु देश में एक सर्वांगी केन्द्रीय बैंक संस्थापित करने की मांग बराबर होती रही और अन्त में विल्टन यंग कमीशन ने इस बैंक से पृथक् एक केन्द्रीय बैंक स्थापित करने की बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सिफारिश की। अतः, सन् १९३५ में जो रिलर्व बैंक खोला गया वह उसी सिफारिश के फलस्वरूप था।

विदेशी बैंक

इस देश में जो बैंक खुले उनके अलावा कुछ विदेशी बैंक भी जिनके प्रधान कार्यालय यहाँ से बाहर हैं अपनी गांथाओं द्वारा यहाँ पर काम करते आ रहे हैं। पहले तो सन् १८५३ तक ईस्ट इंडिया कम्पनी ने आदती कोठियों की सहायता ने ओरियन्टल बैंकिंग कारपोरेशन को छोड़ कर जो यहाँ पर सन् १८४२ में खोला गया था अन्य विदेशी बैंकों को यहाँ पर नहीं खुलने दिया। इसका एक मात्र कारण यह था कि वह यह नहीं चाहती थी कि उसके अलावा अन्य कोई सस्था भारतवर्ष के किसी भी व्यवसाय से लाभ उठा सके। वह यह कहती थी कि तृतीय जार्ज के शासन काल में जो ४७वाँ विधान पास हुआ था उसने उसे ऐसे बैंकों को संस्थापित करने का अधिकार दिया था और उससे उन्हें अधिकार पत्र देने का जो राजकीय अधिकार था वह समाप्त हो चुका था। किन्तु सन् १८५३ तक यह निश्चित हो गया कि उपर्युक्त

विधान ने उसे अपने राज्य में बैंक स्थापित करने का अधिकार तो दिया था किन्तु उससे भारतवर्ष में बैंकों को व्यवसाय करने का अधिकार पत्र देने का राजकीय अधिकार समाप्त नहीं हुआ था। अतः, उक्त वर्ष, चार्टर्ड बैंक आफ इंडिया, आस्ट्रेलिया ऐण्ड चाइना और चार्टर्ड बैंक आफ एशिया (जो बाद में मर्केंटाइल बैंक आफ इण्डिया, लन्दन और चाइना हो गया) राजकीय अधिकार-पत्र द्वारा खोले गये। उपर्युक्त बैंकों में से ओरियन्टल बैंक तो सन् १८८४ में फेल हो गया और मर्केंटाइल बैंक को सन् १८६३ में अपना अधिकार-पत्र छोड़ कर अपने को फिर से संगठित करना पड़ा। अतः, इनमें से केवल चार्टर्ड बैंक आफ इण्डिया, आस्ट्रेलिया और चाइना ही रह गया। सन् १८६३ में कलकत्ता बैंकिंग कारपोरेशन खुला जिसका प्रधान कार्यालय कलकत्ते में था। किन्तु दूसरे ही वर्ष इसने अपना नाम बदल कर नेशनल बैंक आफ इण्डिया कर लिया और फिर दो वर्ष बाद इसका विधान कार्यालय लन्दन चला गया। अन्य जो अंग्रेजी और विदेशी बैंक यहाँ पर काम कर रहे हैं उनमें से कम्पट्रोर नेशनल डी एस्कापेट डी पेरिस सन् १८६२ में खुला, निदरलैंड्स इण्डिया कम्शियल बैंक सन् १८६३ में, हागकाग ऐण्ड शाघाई बैंकिंग कारपोरेशन सन् १८६४ में, योकोहामा स्पेशी बैंक सन् १८६४ में और ईस्टर्न बैंक सन् १८१० में खुले। सन् १८१३ में सत्र मिलकर यहाँ पर ऐसे १२ बैंक काम कर रहे थे। प्रथम युद्ध काल में तीन बैंकों ने अपना काम बन्द कर दिया और सन् १८१६-२२ के बीच में नौ नये बैंक खुले। आजकल इनकी संख्या १५ है।

सहकारी और भूमि-बन्धक बैंक

उपर्युक्त के अलावा हमारे यहाँ सहकारी और भूमि-बन्धक बैंक भी हैं। भारतवर्ष में सहकारी आन्दोलन सन् १८०४ से चल रहा है। उस वर्ष यहाँ पर पहला सहकारी विधान बना था। फिर सन् १८१२ में दूसरा सहकारी विधान बना। यह दूसरा विधान पहले विधान की बुराइयों दूर करने के लिये बना था। सहकारी बैंक भारतीय कृषकों को ऋण की सुविधा देने के लिये स्थापित किये जाते हैं। यह जमा प्राप्त करते हैं और ऋण भी लेते हैं। अतः, इनकी यह पंजी इनके सदस्यों को उनकी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार ऋण देने के काम में आती है। जिन सहकारी बैंकों की पंजी और सुरक्षित कोष मिलाकर पाँच लाख २० अथवा उससे अधिक है उनकी संख्या

उद्योग-धन्वों और विशेष कर चाय के धन्वों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। कुछ ऋण देने के साथ-साथ व्यापार भी करते हैं। निधि पहले-पहल मद्रास में चालू हुई थी। ये पारस्परिक ऋण देने वाली संस्थाएँ हैं। किन्तु अब इन्होंने आधुनिक बैंकों के कुछ कार्य करने प्रारम्भ कर दिये हैं और जमा प्राप्त करने तथा गेसट्सों को उधार भी देने लग गई हैं। चिट फण्ड भी कुछ लोगों की एक दीली-दाली समिति है जो मितव्ययता फैलाने में बड़ी सहायक है। इसके सदस्य कुछ किश्त इसके संस्थापक के पास बराबर जमा करने जाते हैं और वह पहली किश्त की पूरी रकम तो स्वयं अपने परिश्रम के लिये ले लेता है और शेष किश्तें एक-एक करके सब सदस्यों को बारी-बारी से दे देता है।

प्रश्न

(१) इस देश की बैंकिंग की क्रमिक उन्नति का इतिहास लिखिये और मध्यकाल में उसकी जो अवस्था थी उसका दिग्दर्शन कराइये। बाद में इसकी अवर्धति के क्या कारण थे ?

(२) इस देश के आधुनिक काल के बैंकों की प्रथम संस्थापना के विषय में एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। उनके फेल होने के क्या मुख्य कारण थे ?

(३) प्रेंसीडेंसी बैंकों का एक सक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण दीजिये और यह बताइये कि वह कौन-कौन से काम नहीं कर सकते थे ? उनमें कौन-सी कमी थी ?

(४) सन् १८३३ से अब तक आधुनिक बैंकों की जो संस्थापना हुई है और जो फेल हुये हैं उसका एक सक्षिप्त विवरण दीजिये और हर काल की विशेषताएँ बताइये। सन् १८६५ और १९०५ के बीच में जो बहुत कम बैंक संस्थापित हुये थे उसके कारण बताइये।

(५) इम्पीरियल बैंक की संस्थापन और सन् १९३५ तक उसकी कार्य-प्रणाली पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये और यह भी बताइये कि उसे कौन-कौनसे विशेष अधिकार मिले थे और उसके क्या दायित्व थे।

(६) भारतवर्ष में विदेशी बैंकों की संस्थापन और उन्नति का एक सक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण दीजिये।

(७) निम्न पर संचित टिप्पणियाँ निम्न— लन्दन की आदती कंठियाँ (Calcutta Agency Houses), सहकारी और भूमि-वन्दक बैंक, गणमानों के संचित बैंक, प्रगल के लोन ऑफिस, भद्रास के निवि और चिट फण्ड ।

अध्याय १३

बैंकिंग की देशी प्रणाली

(Indigenous System of Banking)

भारतवर्ष का बैंकिंग के ऐतिहासिक विवरण का अध्ययन करने के उपरान्त हम हमारे गहन-प्रत्यक्ष का अध्ययन करेंगे । प्रथम तो इनका एक पचमल सन्दर्भ है जिसमें अनेक प्रकार के ग्रामीण और शहरी महाजन तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के द्रव्य और साधन का काम करनेवाले अनेक लोग सम्मिलित हैं । इनके बहुत से नाम हैं जैसे तनिया, महाजन, साहूकार, गर्गाक और कोठीवाल तथा यह सारे देश में फैले हुये हैं । इनके सम्बन्ध में किसी प्रकार के स्पष्ट तो प्राप्त नहीं हैं, किन्तु ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनकी संख्या ३ और ४ लाख के बीच में होगी । ये सभी जाति के हैं और विशेषतः अग्रवाल, जैन, मावाड़ी, चट्टी, खत्री, अरोड़ा, मुल्तानी और बोहरा जाति के हैं । मुसलमानों में काबुली और पठान हैं ।

देशी बैंकिंग और देशी बैंकर के अर्थ

(Meaning of the term 'Indigenous Banking,
or 'Indigenous Bankers')

अंग्रेजी के इण्डोजेनस (indigenous) शब्द के अर्थ देश में ही उत्पन्न अथवा देश में ही प्राकृतिक रूप से जनित होने के कारण 'इण्डोजेनस बैंकिंग द्रव्य के लेन-देन की वह प्रणाली है जो इसी देश में विकसित हुई है और इण्डोजेनस बैंकर वह हैं जो इस प्रणाली के अनुसार बैंकिंग का व्यवसाय करते हैं । वास्तव में यह विदेशी प्रणाली और उसके अनुसार व्यवसाय करने

वालो से जो क्रमशः आधुनिक बैंकिंग तथा आधुनिक बैंकर कहे जाते हैं, बिल्कुल भिन्न है। इसके यह अर्थ हैं कि यदि इसी देश के निवासी विदेशी प्रणाली के अनुसार बैंकिंग का व्यवसाय करते हैं तो भी वह इंडीजेनस बैंकर नहीं कहे जा सकते। अस्तु, ऐसा हम उन्हीं को कहेंगे जो विशुद्ध भारतीय ढङ्ग के अनुसार बैंकिंग का व्यवसाय करते हैं और इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि इसके अन्तर्गत उधार देने और बैंकिंग के काम में कोई भेद नहीं समझा जाता। किन्तु बैंकिंग के विषय में अनुसन्धान करने वाली अनेक प्रान्तीय कमेटियों (Provincial Banking Enquiry Committees) के इस बात के कह देने के बाद भी आधुनिक काल के बहुत से भारतीय लेखकों ने इनमें विभेद उत्पन्न करने के प्रयत्न किये हैं। अतः, फल वही हुआ जो होना चाहिये था, अर्थात् वे इसमें सफल नहीं हो सके। वस्तुतः, उन्होंने एक गड़बड़ी पैदा कर दी है। उदाहरणार्थ वह कहते हैं कि उधार देने वाले और इंडीजेनस बैंकर में बड़ा भेद है। उधार देने वाला अपना द्रव्य उधार देता है, जमा नहीं प्राप्त करता। उधार उत्पत्ति और उपभोग दोनों के लिये देता है। साथ ही वह खेती, माल ढोने और दूसरे प्रकार का काम भी उधार देने के काम के साथ-साथ ही करता है। किन्तु सबसे विशेष भेद तो यह है कि उधार देने वाला प्रायः उपभोग के लिये ही अधिक उधार देता है और इंडीजेनस बैंकर प्रायः उत्पत्ति के लिये ही अधिक उधार देता है। इंडीजेनस बैंकर अपने और उधार लिये हुए द्रव्य से व्यवसाय करता है, जमा प्राप्त करता है, व्यापार और उद्योग-धन्यों को आर्थिक सहायता पहुँचाता है, केवल बैंकिंग का ही व्यवसाय करता है और हुडियों में भी लेन-देन करता है। फिर, इंडीजेनस बैंकर और आधुनिक काल के सम्मिलित पूँजी वाले बैंको के बीच में भेद बताते हुए वही यह कहते हैं कि सब इंडीजेनस बैंकर जमा नहीं प्राप्त करते और आधुनिक काल के बैंक जमा प्राप्त करके द्रव्य का संग्रह करते हैं। आधुनिक काल के बैंकों से बिल्कुल विपरीत, इंडीजेनस बैंकर केवल बैंकिंग ही का व्यवसाय नहीं करते वरन् उसके साथ ही प्रायः अन्य व्यवसाय भी करने हैं। इसके अतिरिक्त वे आधुनिक काल के बैंकों की तरह केवल उत्पत्ति के लिये ही उधार नहीं देते। इस सबसे यह स्पष्ट है कि वह कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ। एक स्थान पर तो ऐसा मालूम होता है कि वह यह कहते हैं कि इंडीजेनस बैंकर जमा प्राप्त करते हैं, अधिकांश में उत्पत्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करते और केवल बैंकिंग का ही व्यवसाय करते हैं और दूसरे स्थान पर

ऐसा मालूम होता है कि वह कहते हैं कि इंडीजेनस बैंक जमा नहीं प्राप्त करते, केवल उस्तादन को ही नहीं लायना देते और केवल पैसा का ही व्यवसाय नहीं करते। अतः, उन्होंने यह सूझा जा सकता है कि उधार देने वाले और इंडीजेनस बैंकरी में जो भेद बतलाते हैं वह कमजोर नहीं तर्क सही है। वैकिंग के विषय में मालुमवान करने वाली केन्द्रीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि हम जानते हैं कि कुछ उधार देने वाले जमा प्राप्त करते हैं और नाम ही कुछ वैकिंग का व्यवसाय करने वाले ऐसे लोग हैं जो जमा तो नहीं प्राप्त करते किन्तु जिन्हें जनता 'बैंक' कहता है। सत्य तो यह है कि जनता की दृष्टि में बैंक और उधार देने वाले के बीच में कोई भेद नहीं है। अतः, यदि हम पण्डित मेन्डो का तर्क ही यह कहते हैं कि दोनों में दर्जे का भेद है, अर्थात् जब कि इंडीजेनस बैंक वैकिंग और व्यापार दोनों करते हैं, वैकिंग मुख्य रहता है, अथवा तब कि वह उत्पत्ति और उपभोग दोनों के लिये ही उधार देते हैं, उत्पत्ति के लिये उधार देना मुख्य है तो यह भी केवल कालान्तर है। हम समझते हैं इस सम्बन्ध में जो अन्य बातें कही हैं उनमें सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है। अर्थात् (१) जब कि उधार देने वाला प्रायः गिना जमानत लिये ही उधार देता है; इंडीजेनस बैंक प्रायः जमानत लेकर ही उधार देता है। अथवा (२) उधार देने वालों के ग्राहक इंडीजेनस बैंकों के ग्राहकों की अपेक्षा निश्चित समय पर उधार की वापसी कम करते हैं, अथवा (३) उधार देने वाले इंडीजेनस बैंक की अपेक्षा अधिक व्याज लेते हैं, इत्यादि इत्यादि। हाँ, यदि हम दोनों में भेद करना ही चाहते हैं तो हम 'बैंक' बैंक की तरह ही यह कह सकते हैं कि भारतवर्ष में प्रायः इन दोनों में भेद उनकी कार्यशील पूँजी के परिमाण के अनुसार किया जाता है।

अब यह विषय छोड़ने के पहिले हम इंडीजेनस बैंकों की जो परिभाषायें प्रायः पाठ्य पुस्तकों में दी हुई हैं उन्हें भी देख लेना चाहिये। इनमें से एक तो यह है जो केन्द्रीय कमेटी ने दी है, अर्थात् इंडीजेनस बैंकों का अर्थ उन बैंकों से है जो इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया, विनिमय बैंक (Exchange Banks), सम्मिलित पूँजी वाले बैंक (Joint Stock Banks) और सहकारी समितियों से भिन्न हैं और इसमें कोई भी ऐसी वैयक्तिक अथवा निज्जु फर्म सम्मिलित है जो जमा प्राप्त करती है और हुंडियों का व्यवसाय करती है अथवा द्रव्य

उधार देती है यह स्पष्ट है कि इसमें द्रव्य उधार देना भी^१ सम्मिलित है। दूसरी परिभाषा वह है जो डाक्टर जेन ने दी है, अर्थात् इन्डोजेनस बैंकर के अर्थ हैं कोई भी ऐसी वैयक्तिक अथवा निजू फर्म, जो उधार देने के अतिरिक्त या तो हुन्डियों का व्यवसाय करती है या जमा प्राप्त करती है या दोनों काम करती है। इस परिभाषा में कम से कम दो कामों पर जोर दिया गया है जिनमें से एक अर्थात् उधार देने का काम आवश्यक है और दूसरा (१) जमा प्राप्त करने के काम अथवा (२) हुन्डियों का व्यवसाय करने के काम में से कोई भी एक हो सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि कम से कम दो कार्य होने क्यों आवश्यक हैं। क्या एक से काम नहीं चल सकता और फिर उधार देने का काम क्यों आवश्यक है, जमा प्राप्त करने का काम क्यों आवश्यक नहीं है। विवेकत तब हम यह जानते हैं कि आधुनिक विचार के अनुसार उधार देना और जमा प्राप्त करना दोनों मिलाकर ही वैकिंग के व्यवसाय की पूर्ति करते हैं।

अतः, उपसंहार में यह कहा जा सकता है कि जहाँ तक वैकिंग की देशी प्रणाली के क्रमिक विकास की दृष्टि से देखा जाता है, इन्डोजेनस बैंकों की परिभाषा के अन्तर्गत वह सब वैयक्तिक और निजू फर्म आ जाती हैं जो किसी भी रूप में द्रव्य का व्यवसाय करती हैं और जहाँ तक इसके आधुनिक विचार से देखा जाता है इसमें केवल वही वैयक्तिक और निजू फर्म आती हैं जो उधार देने के व्यवसाय के साथ-साथ जमा प्राप्त करने का व्यवसाय भी और विशेषतः चेकों द्वारा निकाली जा सकने वाली जमा प्राप्त करने का व्यवसाय करती हैं। अतः, यदि हम केवल यह दूसरी परिभाषा ही लेते हैं तो इस देश

^१वास्तव में इस परिभाषा के अन्तिम वाक्यांश के दो अर्थ होते हैं -
 (१) वह जो जमा प्राप्त करती है और हुन्डियों का व्यवसाय करती है अथवा केवल द्रव्य उधार देती है, (२) वह जो जमा प्राप्त करती है और या तो हुन्डियों का व्यवसाय करती है अथवा द्रव्य उधार देती है। लेखक का विश्वास है कि पहिला अर्थ सही है और इसी के अनुसार उसने इन शब्दों का प्रयोग किया है। किन्तु यदि दूसरा अर्थ ठीक माना जाता है तो यह चलन के विरुद्ध है क्योंकि इस देश में ऐसे इन्डोजेनस बैंकर नहीं मिलेंगे जो जमा प्राप्त करते हैं और हुन्डियों का व्यवसाय करते हैं किन्तु द्रव्य उधार नहीं देते।

ने एंटीजेनम सेवा की सेवा बहुत ही कम हो जाती है। तो हो, इस पुस्तक में यह सब उन व्यक्तियों और शक्तियों के लिये प्रयोग में लाया गया है जिनके पास बहुत अधिक पूँजी है और जो द्रव्य सम्पत्ति से भी व्यवसाय करती हैं।

उधार देने वाले और एंटीजेनम बैंकर

ये ग्रामीण और शहरी दोनों हैं। “देवता उधार देने वाले” और जैसा कि वह प्रायः कहे जाते हैं “बनिया” भाग्यशर्मा में बहुत पान्थ ने चले जा रहे हैं। नियमावली तो यह उधार देने का ग्राम प्राचीन भाग्य के व्यापारिक और श्री प्रोविजन्स वर्ग प्रदातृ बैंकों का ही है, किन्तु बहुत प्राचीन काल में ही इन वैश्या के प्राथमिक को ऊँचे वर्ग के उन लोगों ने समझ कर दिया था जो गमाव द्वारा दिये हुये सम्मान के स्थान पर धन को अधिक महत्व देते थे। शालग्राम उधार देने वाला भिन्न भी जाति का हो सकता है। रिपोटों में तो ब्राह्मण, राजपूतों, पन्थी, तेली, हलगाइ और अनेक प्रकार के वैश्यों का, जिनमें सर्वोच्च श्रेणियों में लेख्य निम्नतम कण्ट्रैकर सभी सम्मिलित हैं, उल्लेख मिलता है। बनिया वर्ग लालच और कमीनपन के लिये कई शताब्दियों से बहुत ही चरनाम है। “बनिया मारे जान, ठग मारे अनजान।” “ना बनिया मीत, न वैश्या सती।” “बनिया मुँह की तरह खुलता है और तलवार की तरह निकलता है।” किन्तु इन कहावतों में वह जैसा दर्शाया गया है वस्तुतः वैसा नहीं है। ग्रामीण उधार देने वाला ग्रामीण जीवन का अत्यावश्यक अङ्ग है—यह अङ्ग महंगा और कभी-कभी भयानक भी मिला होता है, किन्तु सदैव आवश्यक रहता है। जब कभी-कभी परिस्थितियों से मजबूर होकर वह उधार देना बन्द कर देता है तो दूर-दूर तक ग्राहि-ग्राहि मच जाती है।

यद्यपि ऊपर ‘बनिया’ शब्द उधार देने वालों के लिये प्रयोग में लाया गया है, किन्तु साधारणतया तो यह उधार देने वालों का वह वर्ग है जिसकी आटा, दाल इत्यादि वस्तुओं की दुकान होती है। बनिये उधार सामान भी बेचते हैं और छोटी-छोटी रकमें उधार भी देते हैं। ये छोटी जाति के वैश्य हैं। इनकी पूँजी थोड़ी होती है और इनका दर्जा इनके ग्राहकों की ही तरह का होता है।

एक दूसरी तरह के भी उधार देने वाले होते हैं जिन्हें महाजन कहा जाता है। बनिये की तुलना में महाजन की पूँजी और व्यवसाय दोनों अधिक

होते हैं। बनिये की तरह महाजन भी किसी जाति का हो सकता है, किन्तु प्रायः ऊँची जाति के उधार देने वालों को बनिया न कह कर महाजन ही कहा जाता है। महाजन का दर्जा प्रायः उसके ग्राहकों की तुलना में ऊँचा होता है और अधिकतर वह उसे बड़े सम्मान से देखते हैं। वह प्रायः जमींदार होता है अथवा बनिये के काम की अपेक्षा कोई अन्य ऊँचा व्यवसाय करता है।

शहरों में बनिये और महाजन ऋणदाताओं के अतिरिक्त साहूकार, सर्गाफ और कोठीवाल ऋणदाता भी होते हैं।

साहूकार महाजन ही की तरह का होता है। हाँ, प्रायः वह अधिक धनी होता है। साहूकार गाँव का भी काम करता है। इसके दो रूप हो सकते हैं। एक तो वह जमींदारों को उनकी सम्पत्ति रेहन रख कर उधार देता है। दूसरे, वह गाँव के महाजन को भी आवश्यकता पड़ने पर उधार दे सकता है।

सर्गाफ सोने, चाँदी का काम करता है। वह ऋण तो देता ही है, किन्तु साथ में हुडियों का भी व्यवसाय करता है और कभी-कभी जमा भी प्राप्त करता है। फिर, यह सब काम अन्न, धो, चीनी, कपड़े और अन्य वस्तुओं के दुकानदार भी करते हैं।

कोठीवाल प्रायः जमींदार और उच्चकोटि के व्यापारी होते हैं जो बैकिंग के भी मुख्य काम करते हैं। कभी-कभी वह भी अन्य बड़े और छोटे जमींदारों को ऋण देते हैं।

उपर्युक्त स्थायी ऋणदाताओं के अतिरिक्त फेरीवाले ऋणदाता भी होते हैं। ये लोग प्रायः गाँवों में ही होते हैं, हाँ, कभी-कभी शहरों में भी पाये जाते हैं।

फेरीवाले ऋणदाताओं में किस्तियाँ होती हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमीय भाग में इसे रहती वाला, अवध में उगाहीवाला, और उत्तर प्रदेश के पूरब में हुन्डीवाला अथवा थरक्कार कहते हैं। यह किस्त की प्रणाली पर ऋण देते हैं। प्रायः १० रु० का ऋण इसमें १ रु० की १२ किस्तों में वसूल किया जाता है। कुछ शहर के रहने वाले लोग भी अपने गुमाश्तों द्वारा यही काम कराते हैं, अथवा स्वयं जाकर करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के साहू अपने गुमाश्तों को भेज कर उख पैदा करने वालों को ऋण देते हैं और काबुली, हड़िया तथा व्यापारी स्वयं गाँवों में जाकर यह काम करते हैं। काबुली

अपमानितान के पठान हैं। प्रायः कपड़े का व्यवसाय करने हैं और उन्हें उधार देवते हुये तथा उसकी सीमित मित्त में बदल करने हुये दधर उधर घूमते रहते हैं। सभी-कमी मे द्रव्य भी उधार दे देते हैं। एशिया मिनोर के मध्योत्तर हैं। ये दोनों का भी व्यापार करते हैं। अन्य भागों में यह कानूनिया से मिलते-जुलते हैं। व्यापारी एशिया की तरफ के हैं किन्तु प्रायः उत्तर प्रदेश के हैं।

उपर्युक्त के अलावा और भी बहुत से लोग हैं। जिनके मन्ते का व्यवसाय करने वाले और उन्हें दोनो वाले होते हैं। वे प्रविष्टार सराई के इलाके में हैं। प्योशी क्माई मराजन हैं। पंगेवाले प्रायः उन सभी व्यापारियों को पकड़ते हैं जो धूम धुमरूरी चीजें बेचते हैं। किन्तु यहाँ पर यह उनके लिये प्रयोग में आया है जो उधार मान बेचते हैं और इसी कारण उन्हें दाम लेते हैं। सादनाली गाँड़ का व्यापार करते हैं और गन्ना उपजाने वाले स्थानों को इस शर्त पर उधार देते हैं कि वह उनके हाथ अपना गन्ना ग्ययना गुड़ पहले ही ने निश्चित दर पर बेचेंगे।

यह उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत के विषय में है। अन्य हिस्सों में ऐसे ही महाजन हैं किन्तु निम्न-लिखित नामों से पुकारा जाता है। दक्षिणी भारत में और बर्मा में चट्टी हैं। उनमें पुन्थाऊजी चट्टी छोटे व्यापारी हैं। ये अपने कन्धों पर जोले लटका कर पधर उधर व्यापार करते मित्त हैं और पाना-बदोश हों वा मस्त हैं। इनके अलावा नट्टूकोटाई चट्टी होते हैं जो बहुत धनी हैं। उनका काम करने का दद्दा फोटीमालो का सा होता है। सिन्ध में शिम्बरपुरी नुल्लानी हैं और गुजरात में शौला हैं इत्यादि, इत्यादि।

अभी तक जिन पेशेवर ऋणदाताओं के विषय में कहा गया, उनके अलावा बहुत से ऐसे ही ऋणदाता भी हैं जिनका पेशा ऋण देने का नहीं है। ये सभी वर्ग के हैं, उदाहरणार्थ पेंशन पाने वाले परछे, गाँवों के पटवारी और मास्टर्स जैसे छोटे-छोटे अफसर, नार्स, चमार, फकीर इत्यादि, इत्यादि। कुछ विधवायें भी यह काम करती हैं। फिर कृषक, जमीन्दार और रयत ऋणदाता भी होते हैं। इनमें और पेशेवर ऋणदाताओं में यह अन्तर है कि जब कि यह अपना रोजगार ऋण देने का नहीं बताते पेशेवर ऋणदाता अपने को ऋणदाता कहते हैं। इनकी ब्याज की श्राय बहुत कम है। ये अपनी श्राय के लिये किसी अन्य व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं।

यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि उपर्युक्त ऋणदाताओं में से कुछ तो विशेषकर सराई, कोठीवाल, नट्टूकोटाई चट्टी और दूसरे लोग जो

कोठीवालों के ही सदृश्य हैं, ऋण देने के अलावा बैंकिंग के अन्य कार्य भी करते हैं। हाँ, इनमें से अधिकांश जमा लेना नहीं पसन्द करते। फिर, यह इन्डियों का व्यवसाय भी बहुत नहीं करते, क्योंकि यह व्यवसाय यहाँ पर अधिकतर द्रव्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेजने के लिये किया जाता था, और अब इसे आधुनिक बैंको ने और सरकार के डाक विभाग ने छीन लिया है। किन्तु देश में कुछ लोग ऐसे अवश्य हैं जो जमा प्राप्त करते हैं और उसे चेको पर वापस करते हैं। वास्तव में उन्होंने आधुनिक बैंकों के तरीके अपना लिये हैं।

इनका काम करने का ढङ्ग—इनका काम करने का ढङ्ग बहुत ही सस्ता और सीधा-सादा है। न तो इनकी गदियों में अधिक रुपया लगा है और न यह आलीशानी ही मालूम पड़ती है। हाँ, नियमित गदियाँ अवश्य हैं, किन्तु वे बहुत सादे ढङ्ग की हैं। हिसाब-किताब का ढङ्ग भी बहुत सादा है। हाँ, सही और कुशल अवश्य है। जो लोग केवल उधार देने का ही व्यवसाय करते हैं और वह भी छोटे पैमाने पर उनके यहाँ शायद गदियाँ न हों। कुछ के यहाँ शायद हिसाब-किताब भी न हो। उधार मिलने के पहले कोई नियमित कार्यवाही नहीं होती, अतः, इसके मिलने में देर भी नहीं लगती। ये बिजापनो में भी विश्वास नहीं करते। इसके विपरीत ये अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में बहुत छिपाव रखते हैं। इस धन्धे की शिक्षा भी घर के लोगों ही से मिल जाती है। इनकी भाषा, लेखन-शैली, अङ्क, इत्यादि सभी स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न हैं और कहीं तो एक ही स्थान पर भी कई हैं। कुछ गोपनीय भाषा भी है। डाक्टर जैन ने अपनी पुस्तक इन्डीजेनस बैंकिंग इन इन्डिया में एक ऐसी ही गोपनीय भाषा का जो काठियावाड़ में चलती है जिक्र किया है जिसमें किट के अर्थ एक, घर के दो, ऊधन के तीन, गोठ के चार, मुई के पाँच हैं। हमारे प्रान्त में अंको के लिये निम्न शब्द प्रचलित हैं :—

साग = १, सवान = २, एकवाई = ३, फोक = ४, बुध = ५, डेक = ६, पैत = ७, मग = ८, कोन = ९, सलाय = १०।

उधार देने के तरीके

इस देश में ऋणदाता और महान्न उधार देने के लिये अनेक तरीके काम में लाते हैं। अब इनमें से निम्नांकित मुख्य हैं, अतः, हम इनका यहाँ पर अध्ययन करेंगे।

[१] प्रण-पत्र—यह ऋण की गहन नींव उस पर के व्याज की दर ऋण देने वाले और गन गन के बीच में हो जाती है तो ऋण लेने वाला ऋण की रकम व्याज के साथ साथ एक प्रथम एक विशेष श्रवधि मीन जाने के बाद वापिस कर देने का एक प्रण-पत्र लिए देता है। यदि रकम बहुत प्रथम होती है तो प्रण-पत्र पर अन्य लोगों के हस्ताक्षर भी फरवा लिये जाने हैं जो गारंटीन सफलता है। यदि मुख्य देनदार ऋण वापिस नहीं करता तो यह गारंटीन ऋण वापिस करते हैं, कभी-कभी प्रण-पत्रों में यह भी लिखवा लिया जाता है कि यदि ऋण की वापसी समय पर नही होगी तो और ऊँचा व्याज का दर लिया जायगा।

[२] रसीद अथवा टीप—यह प्रण-पत्र प्रयोग में नहीं लाये जाते तो ऋण लेने वाले ने एक रसीद अथवा टीप लिखवा ली जाती है। इसमें व्याज की दर भी लिखवा ला जाती है।

[३] दस्तावेज अथवा तमम्मुक्त—यह सरकारी दस्तावेज लगे हुये कागजों पर लिखे जाते हैं। इसमें ऋण-सम्बन्धी पूरी बातें लिखी होती हैं। प्रायः इनमें भी एक निश्चित तिथि पर ऋण की वापसी न करने पर ऊँचे दर से व्याज देने की शर्त रहती है।

[४] टिकट वही—इनमें रकम खाते में जाल दी जाती है और उस पर स्टाम्प लगाकर फर्जदार के हस्ताक्षर फरवा लिये जाते हैं। इनमें ऋण सम्बन्धी शर्तों और व्याज की दर इत्यादि का हवाला देने का चलन नहीं है। यह शर्तें प्रायः मौखिक रूप में ही ले हो जाती हैं।

[५] किस्त—यह धनज, रेहत और रेहाती भी कहलाती है। इसका वर्णन पहिले भी किया जा चुका है। कभी-कभी पहली किस्त तो ऋण देने के समय ही काट ली जाती है। इधर कुछ उधार लेने वालों के मुकर जाने के कारण किसी कितान पर अलग उनके हस्ताक्षर अथवा अँगूठे का निशान लेने की प्रणाली भी चालू हो गई है।

[६] रुजही—यह भी एक प्रकार की किस्त ही है इसमें ३० ४० उधार लेने वाला केवल २५ ३० ही पाता है और उसे १ २० रोज करके ३० दिन तक अदा करता रहता है।

[७] **हथउधार अथवा दस्तगर्दी**--इसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं रहता। उधार केवल जवानी ही दे दिया जाता है और कभी-कभी इस सम्बन्ध की ऋण लेने वाले से शपथ ले ली जाती है।

[८] **गिरवी**--इसमें सोना, चाँदी इत्यादि के आधार पर ऋण दिया जाता है। प्रायः जो माल रक्खा जाता है उसके मूल्य के एक अंश तक ही उधार दिया जाता है। भारतवर्ष के लोगों में, विशेषतः विधवाओं में यह चलन बहुत है।

[९] **रेहन**--इसमें भूमि अथवा मकान इत्यादि की जमानत पर उधार दिया जाता है। इसके सम्बन्ध में जो कागज लिखा जाता है वह रेहन-नामा कहलाता है और उसे उम जिले के रेहन के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है जिसमें सम्पत्ति होती है। इसमें ऋण की वापसी की किस्तों, इत्यादि की तारीखें लिखी रहती हैं। रेहन कई प्रकार के होते हैं और उनमें सब में कोई न कोई विशेष बात होती है। प्रथम तो सादा (Simple) रेहन होता है। इसमें सम्पत्ति उसके स्वामी के ही पास रहती है दूसरे इस्तेमाली रेहन (*Usufructuary mortgage*) होता है जिसमें सम्पत्ति ऋणदाता के पास आ जाती है। और उसमें उसे जो लाभ होता है वह व्याज के स्थान पर समझा जाता है। प्रायः ऋणदाता वह सम्पत्ति ऋण लेने वाले के पास ही छोड़ देता है और उससे किराया लेता रहता है। कभी-कभी यह शर्त भी रहती है कि ऋण लेने वाले के मूलधन एक विशेष समय के अन्दर वापिस न करने पर वह सम्पत्ति फिर ऋणदाता ही की हो जायगी, अर्थात् ऋण लेने वाले का रेहन के छुटकारे का अधिकार नहीं रह जाता। तीसरे, पट्टा पटावन रेहन भी हो सकता है। इसमें सम्पत्ति को एक विशेष समय तक प्रयोग में लाने का अधिकार ऋणदाता को दे दिया जाता है जिससे ऋण के मूलधन की और व्याज की अदायगी हो जाती है और फिर वह सम्पत्ति अपने पहिले स्वामी अर्थात् कर्जदार के पास वापिस आ जाती है।

ऊपर नरुद ऋण की प्रणालियों दी हुई हैं। इनके अतिरिक्त जिनो के ऋण (*Kind loans*) होते हैं। इनमें निम्न बहुत ही प्रचलित हैं —

(१) फसल कट जाने पर सवाये, ह्योडे अथवा दूने की वापसी की शर्त पर बोने के लिये अथवा घर खर्च के लिये अनाज उधार देना।

(२) जर्मीदार महाजन होने के लिए बीज और ग्याने के राने के लिये द्रव्य प्रायः इस शर्त पर देता है कि फसल तैयार होने पर यह यह नग वापिस ले लेगा और माय ही काल का कुछ और भी दिला लेगा ।

नकद और जिन्मा के नमिलित ऋण का भी नगान है । इसमें अनिया प्रायः रिमान को मारी प्राशयकगये पूरी करता है । यह उसे प्रयत्नी दूरान ने चीने भी देता है और नकद दण्य भी देता रहता है । चीनी को फासत और नकद उगाक दिसाय में पड़ती रहती है और फसल प्रा जाने पर यह मय अनिया स्वयं सरीद होता है और दिसाय माक कर देता है । फिर यही फसल प्राधिकाश में वह मदियों में भेज देता है । इसने उने मड़ा लाभ होता है ।

कभी-कभी इस शर्त पर भी ऋण दिये जाते हैं कि ऋण लेने वाले फसल तैयार होने पर उने ऋणदाता को पहले से ही निश्चित मूल्य पर बेच दें । यह उन ऋणदाताओं के यहाँ अधिक होता है जो उसी चीज का व्यापार करते हैं जो ऋण लेने वाले पैदा करते हैं । प्रायः यह देखा जाता है कि ऐसी परिस्थिति में जो मूल्य निर्धारित किया जाता है वह बहुत ही थोड़ा होता है और उमने ऋण लेने वाले की हानि ही होती है ।

व्याज तथा अन्य खर्च—व्याज स्थानानुसार तथा समयानुसार बदलता रहता है । जिन्नों के ऋण में यह २५ प्रतिशत से लेकर शत प्रतिशत तक होता है । ऊपर जो मवाया, ठोढ़ा और दूना दिया गया था उसमें यही तो है । फिर यह दर केवल ऋण की प्रवधि के लिये है जो आमतौर पर छ माह की होती है जब, वार्षिक दर दुगुनी होती है ।

नकदी ऋण के लिये यह जमानत रहने पर तो ८ प्रतिशत से १२ प्रतिशत तक रहती है, और जमानत न रहने पर यह १२ से ३७½ प्रतिशत तक होती है । कभी-कभी एक आना प्रति ६० मासिक होता है जो ७५ प्रतिशत वार्षिक पड़ता है ।

साहूकारों का पारस्परिक व्याज ६ प्रतिशत वार्षिक होता है । यह साहूकारी का व्याज कहलाता है ।

प्रायः चक्रवृद्धि व्याज लगाया जाता है । ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ मिश्रधन मूलधन का दुगुना, तिगुना, चौगुना अथवा पचगुना हो गया है । यह चक्रवृद्धि व्याज ही के कारण होता है ।

ऋणदाता सादे और चक्रवृद्धि व्याज के अविरक्त चलन के अनुसार अन्य खर्च भी लेते हैं । देहातो में आसामी महाजन का मुक्त काम करते प्राये

जाते हैं। विवाहादि अवसरों पर यह बहुत होता है। प्रायः नकदी और जिनसों की भेट की जाती है। जो हो, अब यह सब विधानतः बन्द कर दिया गया है। ऋणदाता के यहाँ एक धर्म-साता होता है जिसमें प्रायः ऋण लेने वाला ऋण लेने के समय कुछ अवश्य देता है। कुछ लिखाई के लिये भी काट लिया जाता है जिसे महाजन के मुनीम, आपस-में बाँट लेते हैं। अन्य जो खर्च सुनने में आते हैं उनमें नजराना, थैली की मुँह खुलाई और दस्तूरी बहुत ही प्रचलित हैं। हाँ, अब यह सब बन्द हो रहे हैं।

किन्तु जब अदालतों में नालिश होती है तब न तो ऊँची दर का व्याज और न यह सब खर्च ही मिलते हैं। किन्तु प्रायः महाजन अदालत नहीं करते, जहाँ तक होता है जोर दबाव से ऋण वसूल लेते हैं। प्रायः सभी प्रान्तों में ऐसे विधान बन गये हैं कि अदालतें ऋण के सम्बन्ध की तमाम बातों पर विचार कर सकती हैं और ऊँची दर के व्याज और यह सब खर्च काट सकती हैं। किन्तु यह उनकी तबियत पर होती है। हाँ, इधर कुछ जगह ऐसा करना उनके लिये आवश्यक कर दिया गया है।

ऋणदाताओं और इण्डीजेनेस बैंकों के काम

यदि हम पहिले केवल ऋणदाताओं को ही लें तो वह उत्पत्ति और उपभोग दोनों के लिये ऋण देते हैं। कभी-कभी तो वह किसानों को अनाज, बीज और जानवर भी उधार देते हैं। वे सभी तरह के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, चाहे गरीब हो अथवा अमीर, किसान हों अथवा अन्य कोई, चाहे वह जमानत दे सके अथवा नहीं। अमीर इनसे अपनी विलासिता की माँग पूरी करने के लिये उधार लेते हैं, गरीब ऐसा अपनी आवश्यकताओं की चीजें लेने के लिये करते हैं, किसान खेती करने के लिये ऐसा करते हैं, और अन्य लोग व्यापार, उद्योग-धन्वे तथा अन्य काम चलाने के लिये ऐसा करते हैं। अतः, वह लोगों के आर्थिक जीवन के एक आवश्यक अङ्ग बन गये हैं, और लोग यह जानते भी हैं। शायद यही कारण है कि वे इनका सम्मान भी करते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि उधार लेने वाले आधुनिक बैंकों की अपेक्षाकृत इन देशी महाजनों को अधिक पसन्द करते हैं। बात यह है कि यह उनकी माँगों पर उसी समय विचार करके उन्हें पूरी कर देते हैं। वे उन्हें अधिक देर तक नहीं ठहराते। फिर, यदि इन्हें यह मालूम हो जाता है कि जिस दिन ऋण की वापसी होनी है उस दिन ऋणी को उसे वापिस करने में कठि-

नाई देता यह उसे उसी दिन भूमि देने पर जोर नहीं देते। ये अपने आमा-
निया के बारे में जानते रहते हैं, मत, यह वह श्रृंग लेना प्राप्ति है तब उनके
सम्बन्ध में व्यर्थ तो पृष्ठ-ताड़ नहीं करते। जाना महत्व तो इसी में पता चल
जाता है कि इस देश में लोगों ने कितना रुकम इनसे उधार ले लिया है।
डाक्टर जो ने सन् १९२८ में यह कहा था कि यद्यपि औद्योगिक उद्योगों को
कठिन है किन्तु इन्होंने ब्रिटिश भारत में ८०० और २०० करोड़ रु० के करीब
उधार बांट रखा है। उनके बाद की दशा तो और भी खराब हो गई थी।
हा, कुछ के समय अनाज, इत्यादि के दाम बढ़ जाने के कारण कुछ लोगों का
फटना है कि किसान मछे म हो गये हैं। किन्तु यह बात भेद-भेद किसानों के
लिये सत्य हो सकती है, छोटे के लिये नहीं। मत, यह कहा जा सकता है कि
इस समय इन्होंने कुल भारतवर्ष में कम से कम १००० प्रयोग २२०० करोड़
रुपया बांट रखी होगी। इसी दृष्टि से समस्त आधुनिक ढाँचा के भिन्न मापनों
से भली-भाँति की जा सकती है।

अब यदि हम उन लोगों को जो उधार देने के अनिच्छित प्रेम के
अन्य कार्य भी करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि उनके कार्य अनेक तथा
भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं। जहाँ तक भारतवर्ष के मुख्य उद्योग रूप में आर्थिक
सहायता पहुँचाने का प्रश्न है, उनके विषय में तो यह कहा जा सकता है कि
वह यह अप्रत्यक्ष रूप में करते हैं। बात यह है कि उनके प्रायः गहरों में रहने
के कारण वे किसानों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध तो स्थापित कर ही नहीं सकते। अतः,
वह गाँवों में उधार देने वाले लोगों और व्यापारियों को इस काम के लिये
पकड़ लेते हैं। ये उनसे सहायता पाते हैं और उसके बदले में उन्हें गाँवों की
फसल लाकर देते हैं। किसान दो तरह से अपनी फसलें बेचते हैं। एक तो वह
हैं जो छोटे और बे-पड़े लोग काम में लाते हैं। ये अपने गाँव में ही किसी
व्यापारी के हाथ जिसके प्रायः यह पहले से ही श्रृंगी रहते हैं, अपनी मारी
फसल बेच देते हैं। गाँवों के यह व्यापारी श्रृंगदाता को रुकम काट कर चाकी
दाम उन्हें नकद चुका देते हैं। फिर, यह गाँवों में अपने बेचने लायक माल
रोककर शेष सब मंडियों में ले जाते हैं। वहाँ पर प्रायः यह सामान उन्हीं
महाजनों के हाथ बेचा जाता है जो इन्हें पहले से ही रुपया दिये रहते हैं। इस
समय बेकिंग का बहुत-सा व्यवसाय होता है, जैसे द्रव्य इधर-उधर भेजना,
हुड्डियों का बट्टे, पर भुगतान करना और माल की जमानत पर उधार देना
इत्यादि। यह सब काम यही मंडियों के व्यापारी महाजन करते हैं। दूसरा

तरीका यह है कि देश में अनेक छोटी छोटी मडियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक में उनके समीपवर्ती गाँवों का माल आता है। जो किसान किसी के ऋणी नहीं होते, अथवा पड़े-लिखे और चतुर हैं वह अपने गाँवों में ही माल न बेचकर इन मडियों में उसे ले आते हैं। इससे उन्हें यह लाभ होता है कि यहाँ पर पूर्ति और माँग के नियमों के अनुसार कीमतों के निर्धारित होने के कारण उनके ठगे जाने की कम सम्भावना रहती है। किन्तु यह उन्हीं लोगों के लिये सम्भव है जो काफी चतुर हैं और अन्य प्रकार से नहीं ठगे जा सकते तथा जिनके पास मडियों तक माल लाने के साधन हैं। इन मडियों में कई तरह के खरीदार रहते हैं, जैसे शहरों के व्यापारी, देशी महाजनों के श्रद्धालु जो या तो उन्हीं के लिये अथवा उनके ग्राहकों के लिये खरीदारी करते हैं, निर्यात करने वालों के प्रतिनिधि इत्यादि, इत्यादि। यहाँ प्रायः नकद दाम दिये जाते हैं। अतः, एक स्थान से दूसरे स्थान को बराबर रकम आती-जाती रहती है।

जहाँ तक अन्य उद्योग-धन्धों का प्रश्न है, यह लोग ऊँचे पैमाने पर किये जाने वाले धन्धों में तो अवश्य ही अधिक दिलचस्पी नहीं रखते। शायद ऐसा इसीलिये है कि उनके करने के जो ढङ्ग हैं उनके विदेशी होने कारण यह उनसे अनभिज्ञ हैं। किन्तु इधर ये लोग उनमें अधिकाधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। बहुत-सी मिले इन्हीं के उद्योगों के कारण खुल रही हैं, और अनेक इन्हीं के प्रबन्ध के अन्तर्गत हैं। कुछ शहरों में ये अपनी रकम मिलों में भी जमा कर देते हैं। बात यह है कि उन्होंने इनके हृदय में विश्वास पैदा कर लिया है। अतः, वह इनमें अपनी रकम स्थायी खातों में लगा देते हैं और जब यह निश्चित समय जो प्रायः दो महीनों का रहता है समाप्त हो जाता है तब यह या तो उसे फिर वहीं लगा सकते हैं या निकाल सकते हैं। इससे इन्हें इनकी आवश्यकता पड़ने पर अधिक लाभ के कामों में भी लगा देने का अवसर मिल जाता है।

किन्तु घरेलू धन्धों की तो एकमात्र यही आर्थिक सहायता करते हैं। वस्तुतः कारीगरों के पास तो स्वयं की पूँजी बहुत ही कम रहती है। ऋणदाता और महाजन इन्हे कच्चा माल देने हैं और उसके बदले में इनसे इस बात का वायदा करवा लेते हैं कि ये अपना बना हुआ माल उन्हीं के हाथ बेचेंगे। इससे इन्हें जो मूल्य मिलते हैं वह बहुत ही कम होते हैं। किन्तु अपनी बेवसी के कारण इन्हें ऐसा करना पड़ता है। प्रायः इनके बनाये हुये माल पर अच्छी फिनिश भी यह ऋणदाता तथा महाजन ही कराते हैं। फिर वह इन्हें स्वयं

बैस्मिग के सिद्धान्त और उनका प्रयोग

वेचते हैं। उदाहरण के लिये हम किसी भी शहर के कोठे की मशहूर घरेलू खेपा ले सकते हैं।

यह तो हम देख ही चुके हैं कि कृषि की उपज बाजारों में ऋणदाताओं तथा महाजनो द्वारा आर्थिक सहायता पहुँचाने के कारण ही आ पाती है। इनके अनिश्चित अन्य चीजों का वितरण भी इन्हीं की सहायता के कारण हो पाता है। यह अपने ग्राहकों की ओर से केवल अपनी आदत में मान रखकर ही नहीं बरन् वेचने वाले और खरीदारों के बीच में उनकी हड्डियों का भुगतान करके और अपनी हड्डियों द्वारा उनके द्रव्य शरीर से उधर भेज कर भी व्यापार में सहायता पहुँचाते हैं। हाँ यह विदेशी व्यापार में केवल उसका वह श्रद्धा छोड़ कर जो माल पन्द्रगारों ने मंडियों में और मंडियों से पन्द्रगारों में भेजने से सम्बन्धित है, अन्य किसी तरह से सहायता नहीं पहुँचाते।

वे जनता से बहुत कम जमा प्राप्त करते हैं, और जब करते हैं तब लाभ के विचार में नहीं बरन् अपने मित्रों पर एहसान करने के विचार में ऐसा करते हैं। इनमें परस्पर भी काफी उधार लिया-दिया जाता है। हूडी का काम उमा कि पहले भी बताया जा चुका है, अब पहले में कम होता है। जिनसे ऐसा नहीं है कि यह मिल्कुल न होता हो। मर्गफ अब भी हड्डियों बट्टे पर खरीद लेते हैं और जब उनके पास द्रव्य नहीं रहता तब वह उन्हें आधुनिक बैंकों से भुनवा लेते हैं। इम्पीरियल बैंक यह काम खूब सुगठित समझता है। बात यह है कि इन पर जो मर्गफ के बेचान हो जाते हैं उसमें वह भी इनका भुगतान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अन्तिम बात यह है कि उनमें से कुछ आधुनिक बैंकों की तरह ही बैस्मिग का व्यवसाय करने लग गये हैं, यद्यपि इनकी सख्या बहुत कम है।

ऋणदाताओं और इन्डीजेनस बैंकरो के संगठन में दोष

ऋणदाताओं और इन्डीजेनस बैंकरो के संगठन में बहुत से दोष हैं —

(१) इनमें से अधिकांश लकीर के फकीर हैं और पुराने दण्ड से ही काम करना चाहते हैं। हाँ, कुछ अवश्य ऐसे हैं जिन्होंने सुधार कर लिया है और जमा प्राप्त करते हैं, चेकें देते हैं, और अपने ग्राहकों के लिये वह सब काम करते हैं जो आधुनिक बैंक करते हैं, किन्तु इनकी सख्या बहुत ही कम है।

(२) इनमें पारस्परिक ईर्ष्या है जिससे इनका कोई अच्छा संगठन

नहीं है। हाँ, कुछ पुराने और नये संगठन अवश्य हैं किन्तु इनके सदस्यों की संख्या बहुत कम होने के कारण यह सबके प्रतिनिधि नहीं माने जा सकते। महाजन और पचासत जैसे पुराने संगठनों का महत्व तो अदालते खुल जाने से समाप्त हो गया है। अतः उनके केवल धार्मिक तथा सामाजिक कृत्य अवशेष रह गये हैं। आधुनिक सङ्घटनों में ब्रम्बई के उदाहरणार्थ ब्रम्बई सराफ, असोसियेशन, मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स, कमीशन एजेंट असोसियेशन, मुल्तानी बैंकर्स असोसियेशन के नाम लिये जा सकते हैं। देश के अन्य हिस्सों में भी कुछ और सङ्घटन हैं। ये अपने सदस्यों में मेल-जोल स्थापित करने में और उनके लाभ के काम करने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो चुके हैं। किन्तु स्थिति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती। इनके सदस्यों की संख्या कम होने के कारण इन्हें उनका प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता।

(३) इन्होंने देश के लोगों में बैंकिंग की आदत नहीं डाली। न ये साख का सृजन करते हैं। इन्होंने चेक और बिलों जैसे साख-पत्रों का प्रयोग प्रोत्साहित नहीं किया। दुडियाँ भी जिनसे यह बहुत दिनों से परिचित है, व्यापार की सहायता करने में काम में नहीं लाई जातीं, प्रायः वह नकद ही होता है।

(४) इनके मुख्य व्यवसाय अर्थात् उधार देने के काम में भी अनेक दोष हैं। उत्पत्ति और उपभोग की माँगों के बीच में तनिक सा भी भेद नहीं माना जाता। ब्याज की दर बहुत ऊँची रहती है और कुछ विशेषतः छोटे-छोटे ऋणदाता बेईमानी भी करते हैं। सत्तेप में यह बहुत ही दूषित है।

(५) छोटे छोटे ऋणदाताओं की तो बात ही क्या है बड़े-बड़े महाजन भी बैंकिंग के साथ-साथ व्यापार भी करते हैं। कुछ मौके वेमौके सरकारी साख पत्रों में सट्टेबाजी भी करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ अन्य देशों में भी कुछ निजू बैंकर हैं जो किसी नियम के अनुसार काम नहीं करते और बैंकिंग के साथ अन्य व्यापार भी करते हैं। किन्तु इसमें जो सबसे बड़कर दोष है वह यह है कि इनके व्यापार में नुकसान पहुँचाने पर इनके यहाँ जमा करने वालों का नुकसान हो जाने का डर रहता है। हाँ, भारतवर्ष में इनके यहाँ जमा न होने के कारण ऐसी जोखिम नहीं है। किन्तु तो भी रिजर्व बैंक जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे इन्हें अपने से सम्बन्धित करने के लिये तब तक तैयार नहीं है जब तक यह बैंकिंग के साथ अन्य व्यापार करना नहीं बन्द कर देते।

(६) इनमें से कुछ और अभिप्रेत केवल ऋण देने वाले हिसाब किताब भी नहीं रखते। आडिट से तो यह अनभिज्ञ ही हैं। अतः देश का केन्द्रीय बैंक इनकी सहायता नहीं कर सकता।

(७) इनके व्यवसाय सम्बन्धी कोष्ठ अरु नहीं प्राप्त हो सकते। बाल्य में यह बात जानने के लिये कि इनका सुधार किस ओर होना चाहिये इस बात की बहुत आवश्यकता है।

(८) इनमें और आधुनिक बैंकों में कोई भिन्न सन्बन्ध नहीं है। अतः, देश में एक दूसरे में मिलतुल भिन्न दोनो द्रव्य के बाजार हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जहाँ रयोनमें बैंकों के पास द्रव्य की कमी होने के कारण वे व्याज ही ऊँची दर लेते हैं दूसरी तरफ आधुनिक बैंकों के पास द्रव्य की अधिकता के कारण वे नमा पर बहुत कम दर का व्याज देते हैं और इन तरह वह स्रोत बन्द कर देते हैं जिसके द्वारा बैंकिंग की उन्नति होती है।

ऋणदाताओं और इन्डीजेनम बैंकों के सुधार के लिये कुछ सुझाव

ऋणदाताओं और इन्डीजेनम बैंकों के सुधार के लिये अनेक सुझाव रखे गये हैं। प्रायः बैंकिंग सम्बन्धी प्रान्तीय कमेटियों इन्हें प्रमाण-पत्र (License) देने के पक्ष में थीं। हाँ, इस बात पर अवश्य मतभेद था कि यह ऐच्छिक अथवा अनिवार्य हो। जो ऐच्छिक के पक्ष में थीं उनका कथन था कि (१) बहुत से महाजन इसका घोर विरोध करेंगे, (२) अपनी मजबूत स्थिति के कारण लगाये हुए प्रतिबन्ध तोड़ देने और (३) व्याज के बिना उधार देने वाले लोग काम बन्द कर देंगे।

इसके विपरीत अनिवार्य रूप में प्रमाण-पत्र देने के पक्षपाती यह कहती थीं कि (१) जरा तक ऐसा न होगा बेईमान महाजनों की बेईमानियों न रुक सकेंगे, और (२) कानून तथा चिकित्सा के सम्बन्ध में तो प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है और उसमें कोई कठिनाई नहीं पड़ती तब इसमें कैसे कठिनाई पड़ेगी।

प्रमाण-पत्र के लिये निम्न शर्तों का सुझाव था :— (१) व्याज पर प्रतिबन्ध (२) हिसाब-किताब एक विशेष प्रकार से रखना और आडिट कराना, (३) प्रत्येक ऋणी को समय-समय पर उसके हिसाब की प्रतिलिपि देना, (४) उसके ऋण की वापसी पर रसीद देना और उसका प्रतिरूप अपने पास रखना,

और (५) चक्रवृद्धि व्याज लगाने के लिये कम से कम एक वर्ष का समय निश्चित करना ।

उपर्युक्त प्रतिबन्ध मानने पर उसे निम्न अधिकार देना—(१) कृषि सम्बन्धी हुडियों और गोशमों की रसीदों की जमानत पर दिये हुये ऋण की वापिसी के लिये उसे वही अधिकार देना जो सरकार को अपनी वसूल करने के लिये मिले हुये हैं, (२) कृषि सम्बन्धी कागजों पर उधार पाने की सुविधा, इम्पीरियल बैंक और डाकखानों द्वारा उसी प्रकार द्रव्य भेजने के अधिकार जिस प्रकार आधुनिक बैंकों और सहकारी समितियों को मिले हुए हैं, और (४) डाकखानों में चालू खातों में रुपया जमा करने और उसे चेकों द्वारा निकालने का अधिकार, इत्यादि ।

किन्तु कुछ कमेटियाँ जिनमें केन्द्रीय कमेटी भी थी किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र देने के पक्ष में नहीं थीं । उनका कहना था कि प्रमाण-पत्र की बात तो केवल दो उद्देश्य ही लेकर सुझाई जा रही है, अर्थात् (१) महाजनो द्वारा जो अधिक व्याज लिया जा रहा है उसे कम करने के लिये, और (२) उनमें से कुछ जो अन्य बुरी बातें करते हैं उसे रोकने के लिये । इनका कहना था कि इनमें से पहला उद्देश्य तो जनता को शिक्षित बनाकर, उनमें मितव्ययता और बचत करने की आदत डालकर और महाजनों के ऋण देने के एकाधित्य को समाप्ति करके पूरा किया जा सकता है । जहाँ तक दूसरा उद्देश्य पूरा करने का प्रश्न है वह बुरी बातों के लिये अधिकाधिक दण्ड देकर रोका जा सकता है । तब से अब तक बहुत कुछ किया जा चुका है ।

बङ्गाल, आसाम, मध्यप्रान्त, बिहार, बम्बई और पंजाब में महाजन कानून बन गये हैं जिनके अनुसार प्रत्येक महाजन को सरकार से एक प्रमाणपत्र लेना पड़ता है । कुछ प्रान्तों में यह अनिवार्य है और कुछ में ऐच्छिक है । जहाँ ऐच्छिक है वहाँ जिन महाजनों के पास प्रमाणपत्र नहीं हैं वे अदालत की सहायता नहीं प्राप्त कर सकते । प्रमाणित महाजनों को नियमानुसार हिसाब रखना पड़ता है, निश्चित समय पर अपने ऋणी को उसके हिसाब की नकल देनी पड़ती है, रुपये की वापिसी पर रसीद देनी पड़ती है, इत्यादि इत्यादि ।

व्याज की दर तो लगभग सभी प्रान्तों में बाँध दी गई है । कुछ प्रान्तों में ऋणियों को कुछ छुटकारा भी दिया गया है । यहाँ पर एक बहुत पुराना दमदुपत सिद्धान्त है, जिसके अनुसार किसी ऋणी के ऋण की दुगुनी रकम दे देने पर

उस श्रृंग से खुटकारा मिल जाता है। अतः कुछ प्रान्तों में इस विद्वान्त का सफारा लिया गया है। श्रृंगी के शरीर और उसकी सम्पत्ति की भी प्रायः सभी जगह रक्षा की गई है। ऐसा कहीं नहीं है नहीं इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ न किया गया हो। किन्तु तो भी यह नहीं मिला जा सकता कि जो कुछ करने योग्य था वह सभी कर दिया गया है।

कुछ विधानों में तो बहुत नें दोष हैं जो समय आने पर दूर करने ही पड़ेंगे। वास्तव में इसका लिये अनुभव की आवश्यकता है। उगलिम्मान और अन्य पश्चिमीय देशों में भी जहाँ ऐसे विधान बहुत पहले से चले आ रहे हैं अतः भी अनेक दोष पाये जाते हैं और वा समय-समय पर दूर किये जाते हैं। मंच तो यह है कि वेदमानी के सामने विधान का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। हाँ, ईमानदार व्यक्ति के लिये अवश्य यह ईमानदारी के प्रमाणस्वरूप हो जाता है।

जो लोग श्रृंग देने के साथ-साथ बैंकिंग के अन्य काम भी करते हैं वह भी कुछ सुधारने के बाद देश के आर्थिक सङ्गठन के बहुत ही उपयोगी सदस्य बन सकते हैं। उनके रहने की आवश्यकता है। सम्मिलित पूँजी के नेत्र, इम्पीग्रियल बैंक और सहकारी सहाय्य सारे देश के लिये बैंकिंग की सुविधायें नहीं प्रदान कर सकती। अतः, यह इनका स्थान भी नहीं ले सकती। फिर यह एक बहुत ही उपयोगी काम कर सकते हैं। हमारे देश में मिलों की बलाली और उनकी स्वीकृति का काम बहुत कम होता है। इसे वह पूरा कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वह हुडी का काम बहुत प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, अतः, उनका यह अनुभव देश में मिलों का बाजार स्थापित करने में जो यहाँ की बैंकिंग प्रणाली के लिये बहुत ही आवश्यक है बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

बैंकिंग सम्बन्धी अनुसन्धान करने के लिये जो केन्द्रीय समिती बनी थी उनमें इन्हें रिजर्व बैंक से सम्बन्धित करने का सुझाव रखा था और इस काम के लिये इन्हें उपयुक्त बनाने के लिये इनके द्वारा कुछ शक्तें पूरी करने की योजना बनाई थी। किन्तु रिजर्व बैंक के स्थापित हो जाने पर भी अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं हो पाया है। रिजर्व बैंक विधान की ५५ (१) धारा में यह दिया हुआ था कि यह बैंक यथासम्भव शीघ्र अथवा अपनी स्थापना के तीन वर्ष के अन्दर (अर्थात् ३१ दिसम्बर, सन् १९३७ तक में) सपरिपद गवर्नर जनरल को निम्न विषयों पर अपनी सम्मति दे —

(अ) इस विधान की जो धाराये तालिका में सम्मिलित बैंकों (Scheduled Banks) के सम्बन्ध में दी हुई हैं उन्हें ब्रिटिश भारत में बैंकिंग के काम करनेवाले उन व्यक्तियों और स्थापनाओं के ऊपर लागू करने के सम्बन्ध में जो उक्त तालिका में सम्मिलित नहीं हैं, और

(ब) कृषि को आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिये जो अवलम्बन है उन्हें तथा उस धर्मे और बैंकिंग के व्यवसाय के बीच में सम्बन्ध स्थापित करने के लिये जो तरीके हैं उन्हें सुधारने के सम्बन्ध में ।

‘अ’ भाग तो स्पष्ट ही इंडोजेनस बैंकों से सम्बन्धित है, किन्तु जहाँ तक व कृषि के व्यापार की आर्थिक सहायता करते हैं और कृषकों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में उधार देते हैं, वहाँ तक कृषि को आर्थिक सहायता पहुँचाने का काम करने की हैसियत से उनके सुधार और उनके कार्यों का रिजर्व बैंक से सम्बन्धित करने के प्रश्न ‘ब’ में भी सम्मिलित हैं और इसीलिये यह दोनों विषय एक दूसरे से सम्बन्धित हैं ।

बैंक ने उक्त शर्तें पूरी करने के उद्देश्य से सन् १९३६ के दिसम्बर में एक प्रारम्भिक रिपोर्ट सन् १९३७ के दिसम्बर में एक वैधानिक रिपोर्ट प्रकाशित की थी । यह दोनों रिपोर्ट परस्पर पूरक हैं और इस सम्बन्ध में काफी प्रकाश डालती हैं । व्याज की दर और उनका काम नियन्त्रण में लाने के लिये विधान बनाने के सुझाव रखे गये थे । ऊपर जिन विधानों का जिक्र किया गया है वह इन्हीं सुझावों के कारण बनाये गये थे । इण्डोजेनस बैंकों को रिजर्व बैंक से सम्बन्धित होने के लिये जो शर्तें पूरी करनी हैं वह भी उसी समय इनके प्रतिनिधियों को बतला दी गई थीं । वास्तव में यह कोई नई नहीं थीं । बैंकिंग के विषय में अनुसन्धान करने के लिये जो कमेटियाँ बनाई गई थीं वे भी पहले ही लगभग यही सुझाव रख चुकी थीं । सच्चे में उन्होंने यह सुझाव रक्खा था कि यदि ये रिजर्व बैंक से सम्बन्धित होना चाहते हैं तो इन्हें अपने व्यवसाय का ढङ्ग सम्मिलित पंजीवाले बैंकों के ढङ्ग के अनुसार करना पड़ेगा और विशेषतः बैंकिंग का जमा प्राप्त करने का व्यवसाय अपनाना पड़ेगा । इन्होंने जो उत्तर दिये थे उनसे यह स्पष्ट है कि वे सब जमा प्राप्त करने का व्यवसाय अपनाने और हिसाब का विज्ञापन करने के विचार से सहमत नहीं थे । जहाँ तक अन्य प्रश्न थे उन सबके लिये वे तैयार थे । उदाहरण के लिये वे अपने हिसाब एक निश्चित रूप में रखने के लिये और सट्टेवाजी छोड़ देने के लिये सहमत थे । वे केवल बैंकिंग का व्यवसाय करने के लिये भी तैयार नहीं

ये। उनका विचार था कि अधिकांश उनके अपने आप दातों के गैर-बैंकिंग के व्यवसाय छोड़ देना से न केवल उनके लाभ का एक श्रोत ही बन्द हो जायगा बल्कि उनकी उस स्थानीय साध को भी भ्रष्टा लगेगा जो उनके लिये बैंकिंग का व्यवसाय करने के लिये बहुत ही आवश्यक है। यथार्थ में यह सत्य ही प्रतीत होता है। फिर, यह बात भी कुछ गमनाम नहीं आती कि जब वे बैंकिंग के अन्य व्यवसाय कर रहे हैं तब रिजर्व बैंक उन्हें जमा प्राप्त करने का व्यवसाय अपनाने के लिये क्यों इतना मजबूर कर रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि यह प्रमेयों में प्रणाली ही एक व्यवस्था की नकल है। क्या भारतीयों के अपने यहाँ विकसित देशी प्रणाली के अनुसार कार्य करने में कोई बड़ा भारी अपराध है? इण्डोनेजिया में स्वयं ही देश की बैंकिंग प्रणाली में एक बहुत ही ऊँचा स्थान प्राप्त करना चाहते हैं जो उससे किसी दशा में भी कम न हो जो भूतकाल में था। यदि कोई व्यक्ति अनुभव हो रही है तो वह केवल इसीलिये है कि हमारे गोरे महाप्रभु का दृष्टिकोण कुछ विचित्र था। अब तो हम लोगों के स्वतन्त्र हो जाने पर रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण बदलना ही चाहिये। हाँ, यह भी बहुत ही आवश्यक है कि इण्डोनेजिया बैंक भी समय के परिवर्तन के साथ-साथ अपने काम करने का ढाँचा बदल दें और अपने को एक केन्द्रीय बैंक के सदस्यों के योग्य बना लें।

वैधानिक रिपोर्ट में एक अन्य सुझाव भी है और शायद यह जैसा कि बैंक भी याशा करता है, भाग्य में इन्हें इनके काम का ढाँचा बदलने बिना ही और इनके ऊपर किसी विशेष प्रकार का प्रतिबन्ध लगाये बिना ही उससे प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित कर दें। हम जानते हैं कि वे बहुत प्राचीन काल से ही दुन्दियों का प्रयोग करते आ रहे हैं। अतः, यदि वे इन्हीं प्रोत्साहन दें तो अवश्य ही यहाँ पर एक बिल बाजार स्थापित हो जाय। बैंक ने यह वायदा कर लिया है कि वह बाजार में अपनी खुल्लम खुल्ला तौर पर काम करने की नीति दुन्दियों के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार लागू करने के लिये तैयार है जिस तरह से स्काफी कारों के सम्बन्ध में करता है। अतः, इस तरह से वे अवश्य ही हमने सम्बन्धित हो जायेंगे। बहुत दिनों तक तो इन पर इतने अधिक मूल्य के स्टाम्प लगते थे कि इनकी उन्नति असम्भव सी थी, किन्तु सन् १९४० से यह घटा दिया गया है जिससे इसकी उन्नति के सम्बन्ध में कम से कम एक बाधा तो हट गई है। इस विषय पर और विचार हम किसी अन्य स्थान पर करेंगे।

रिजर्व बैंक स्वीकृत (Approved) इण्डोनेजिया बैंकों की एक वार्षिक

रखता है और उन्हें द्रव्य इधर से उधर मेजने में उसी प्रकार की सुविधायें देता है जैसे दूसरे गैरसदस्य बैंकों को मिली हुई हैं।

इन्डीजेनस बैंकरों का रिजर्व बैंक से प्रत्यक्ष रूप में

सम्बन्धित हो जाने से लाभ

अब, प्रश्न यह है कि इन्डीजेनस बैंकरों को रिजर्व बैंक से प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित हो जाने से क्या लाभ होगा। कुछ लोगों का यह कहना था कि उनका यह सम्बन्ध सम्मिलित पूँजी के अन्य बैंकों तथा इम्पीरियल बैंक द्वारा ही होना चाहिये। उनके पास ऐसे स्वीकृत इन्डीजेनस बैंकरों की तालिका रहती है जिनकी हुन्डियों वे एक निश्चित सीमा तक लेने के लिये तैयार रहते हैं। अतः यह सुझाव था कि यह काफी है, रिजर्व बैंक को केवल इन हुन्डियों के इन्हीं बैंकों द्वारा लाने पर इन्हे ले लेना चाहिये। किन्तु इस सुझाव का बड़ा विरोध हुआ और अब तो यह छोड़ ही दिया गया है। बम्बई सराफ असोसियेशन के प्रधान चुन्नीलाल बी० मेहता ने जैसा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने सर जेम्स टेलर को अपने २४ सितम्बर, सन् १९३७ के एक पत्र में लिखा था, यह बैंक अधिकांश इन्डीजेनस बैंकरो की सहायता नहीं करते। बल्कि इन्होंने उनसे प्रतियोगिता करके उनका व्यवसाय छीन लिया है, अतः, यह सुझाव उन्हें कदापि नहीं पसन्द आ सकता। प्रत्यक्ष सम्बन्ध के निम्न लाभ हैं :—

(१) प्रथम महायुद्ध के समय से ससार के इतिहास ने यह तो स्पष्ट ही कर दिया है कि यदि किसी देश को आर्थिक दृष्टि से दृढ़ और स्वतन्त्र रहना है तो उसके यहाँ की बैंकिंग की प्रणाली ऐसी सम्बन्धित होनी चाहिये कि जिसमें देश के बैंकिंग के मुख्य-मुख्य काम पूर्णरूप से सम्मिलित हों और वह अपने केन्द्रीय बैंक के निरीक्षण तथा नियन्त्रण में भली-भाँति सगठित हों। हम जानते हैं कि इन्डीजेनस बैंकर भी बैंकिंग का एक मुख्य काम करते हैं और छोटे-छोटे कस्बों तथा गाँवों में तो केवल यही हैं ही, सम्मिलित पूँजी के बैंक या तो हैं ही नहीं अथवा इनकी तुलना में कुछ भी काम नहीं करते। बड़े-बड़े शहरों और बन्दरगाहों में भी, जहाँ ये बहुत महत्वशाली हैं, वह अवश्य पाये जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि वह भी रिजर्व बैंक से उसी भाँति सम्बन्धित हों जिस भाँति आधुनिक बैंक हैं। इससे देश में जो द्रव्य के देशी बाजार और आधुनिक बाजार हैं उनके कार्यों का पारस्परिक सगठन हो जायगा। साथ ही इससे

इन्डोजेनेस बैंकों का स्तर नया उनके कार्य करने का दृष्टि भी ऊँचा उठ जायगा।

(२) इन्डोजेनेस बैंकों के पास पण्डे जो जमा थे वह भी इधर निम्न गये हैं। हमारे कर्तव्य हैं, किन्तु ऐसा कि तुल्यता न हो, ने अपने उस पत्र में कहा था जिसका संकेत ऊपर किया जा चुका है, इसका एक मुख्य कारण सम्मिलित बैंकों के बैंकों और सरकार का अपने व्याज की दर ऊँची कर देना भी था। प्राचीन प्रणाली का इधर निर्मल हो जाने के चाहे जो कारण रहे हों, किन्तु यह निश्चित है कि यदि यह गिरव बैंक ने प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो जायें तो इनके पास अवश्य जमा आने लगेगी। अतः, यह स्पष्ट है कि जमा की प्राप्ति से जर्न सम्बन्धित होने के पहिले नहीं लगानी चाहिये बल्कि यह उनके फलस्वरूप अपने आप पूरी हो जायगी।

(३) ऐसी आशा की जाती है कि सम्बन्धित हो जाने के फलस्वरूप उनका बैंकिंग का व्यवसाय बढ़ जायगा। अतः, वह गैर बैंकिंग के व्यवसाय छोड़ सकेंगे। इसमें यह कहा जा सकता है कि यह भी सम्बन्धित हो जाने के फलस्वरूप होगा, पहले से इसे पूरा करने की शर्त एक प्रकार से व्यर्थ हो गई।

(४) सम्बन्धित हो जाने का एक अन्य लाभ यह होगा कि इन्डोजेनेस बैंकर रिजर्व बैंक से सीधे ऋण ले सकेंगे और अपनी हुण्डियाँ भुना सकेंगे। अतः, यदि इसके सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध लगाया जायगा, जैसे केवल विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही ऋण मिल सके तो प्रत्यक्ष सम्बन्ध का कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, जैसे-जैसे इन्डोजेनेस बैंकों की स्थिति सुधरती जाय, और यह उनके रिजर्व बैंक से सम्बन्धित होने के फलस्वरूप अवश्य होगा, वैसे वैसे ही इन सम्बन्ध में कड़ाई की जा सकती है।

(५) यद्यपि इन्डोजेनेस बैंकर अपने हिसाब की विज्ञप्ति के विरुद्ध हैं, किन्तु वह रिजर्व बैंक को उसकी इच्छित सूचनायें देने के लिये तैयार हैं। ये सब एकप्रकार के इनकी विज्ञप्ति की जा सकती है और उससे देश की आर्थिक स्थिति का बराबर ज्ञान हो सकता है।

(६) जब इनका बैंक से प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो जायगा तब इन्हें द्रव्य भेजने की सुविधायें भी मिल जायेंगी। आजकल भी कुछ इन्डोजेनेस बैंकों को निश्चित शर्तें पूरी कर दी हैं और जो बैंक की स्वीकृति तालिका में सम्मिलित हो गये हैं उन्हें यह सुविधायें मिली हुई हैं।

इण्डीजेनस बैंकरो का इम्पीरियल बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंकों से सम्बन्ध

इण्डीजेनस बैंकरो का इम्पीरियल बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंकों से जो सम्बन्ध आजकल है यह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इम्पीरियल बैंक और अन्य व्यापारिक बैंक अपनी स्वीकृत तालिका में इनमें से जिसका नाम लिख लेते हैं उन्हीं से अपना सम्बन्ध रखते हैं। बैंकिंग विषय के अनुसन्धान करने वाली बंगाल की कमेटी ने यह कहा था कि इम्पीरियल बैंक इनमें से बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध लोगों से भी काम करने में सकोच करता है। इम्पीरियल बैंक और दूसरे व्यापारिक बैंकों के व्यवस्थापकों की बराबर इस बात की शिकायतें होती रही हैं कि वे इनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते। ऐसा शायद इसलिये भी होता था कि प्रायः यह व्यवस्थापक गैर भारतीय होते थे और इनकी भाषा भी नहीं समझ पाते थे। किन्तु भारतीय व्यवस्थापकों ने भी इनमें वह दिलचस्पी नहीं ली जो उन्हें लेनी चाहिये थी। इसका कारण भी स्पष्ट है। वे बराबर एक शाखा से दूसरी शाखा को बदल दिये जाते हैं जिससे उनमें अपने ग्राहकों के विषय में यह ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता जो अत्यन्त ही आवश्यक है। यह भारतीय बैंकिंग का एक विशेष दोष है और इसी कारण-वश इसके दो अङ्ग देशी और आधुनिक बराबर एक दूसरे से पृथक् चले आ रहे हैं।

जहाँ तक उन इण्डीजेनस बैंकरो का सम्बन्ध है जिनका नाम इनकी स्वीकृत तालिका में है, उन्हें ये लोग प्रण-पत्रों की जमानत पर जिन पर कम-से-कम दो धनियों के हस्ताक्षर हाते हैं और जिनमें से एक व्यापारी भी होता है, नकद साख प्रणाली के अनुसार उबार दे देते हैं। इनकी दृष्टियाँ भी इनके यहाँ भुन जाती हैं। इन्हें इण्डीजेनस बैंकर पहले तो व्यापारियों से इनका नकद दाम देकर खरीद लेते हैं। प्रायः यह उन्हें अपने पास ही रखते हैं, अथवा परस्पर भुना लेते हैं। किन्तु कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर ये बैंकों से भी भुना ली जाती हैं। हाँ, यह उस रकम से अधिक की नहीं होती जो स्वीकृत तालिका में। उनके नाम के आगे दी रहती है। वास्तव में यह रकम उनकी स्थिति के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करने के पश्चात् निर्धारित की जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि इण्डीजेनस बैंकरो को इम्पीरियल बैंक और अन्य व्यापारिक बैंकों की स्वीकृत तालिका में अपना नाम लिखवा लेने से भी कोई विशेष लाभ

नाही होता। वे प्रायः साधारण प्रदत्तों के समान ही नमस्के जाते हैं। इनके ऊपर जो चेकें फानी जाती हैं, अथवा इनके पत्र में यदि रेग्युलर किया जाना है तो वह चेक यह एक नहीं लेते।

उपगृह्य में यह कहा जा सकता है कि स्थिति मतोपानयन नहीं है और सभी लोग को गृह्य करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में जर्मनी के क्रोमान्डिट विद्वान् के अनुसार यह लोग परस्पर सम्झा बना सकते हैं। उनमें एक श्रमों गानाये न गोलकर निजु वैकों को अपना प्रतिनिधि बना देते हैं और उनको ग्राह्य मठ करके रहते हैं। इससे जो लाभ होता है उसका दोना में बँटवारा हो जाता है। निजु वैकर का ऋण सम्बन्धी दायित्व स्थानीय परिस्थितियों अधिक समझ सकते के कारण अधिक रहता है। उनका अधिकार भी सीमित रहते हैं। किन्तु यह सब यहाँ पर तभी हो सकता है जब इन्डोजेनस वैकर अपने दण्ड का नुबान करें और परम्पर सगठित होकर अपने अधिकार प्राप्त करने के लिये श्वासाज लगावें। इसी तरह से यह अपने प्रति जनता की, गण्ट का निजु वैक जी और इम्पोरियल बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंकों की सहानुभूति आकर्षित कर सकेंगे।

प्रश्न

(१) इन्डोजेनस वैकिंग और इन्डोजेनस वैकर्म से आप क्या समझते हैं? क्या आप ऋणदाता और इन्डोजेनस वैकर के बीच में भेद बना सकते हैं? इन्डोजेनस वैकर को एक उपयुक्त, परिभाषा दीजिये।

(२) ग्रामीण तथा नागरिक क्षेत्रों में जाँ भिन्न भिन्न प्रकार के ऋण देने वाले पाये जाते हैं उनका एक सक्षिप्त विवरण दीजिये। उनमें से कौन कौन ऋण देने के अतिरिक्त अन्य वैकिंग व्यवसाय करते हैं?

(३) ऋणदाताओं और इन्डोजेनस वैकरो के काम करने के तरीकों, ऋण देने की प्रणाली और स्वर्णों के विषय में आप जो कुछ जानते हो उसे और इनके सम्बन्ध में जो पद प्रयोग में आते हैं उनके विषय में समझाते हुये लिखिये।

(४) ऋणदाताओं और इन्डोजेनस वैकरो के जो काम हैं उनका एक सक्षिप्त विवरण देते हुये जनता के लिये उनकी आवश्यकता दिखाइये।

(५) ऋणदाता और इन्डोजेनस वैकरो में क्या दोष हैं? इन्हे स्पष्ट तोर पर समझाइये।

(६) ऋणदाताओं को प्रमाण-पत्र देने के विषय में बैंकिंग सम्बन्धी अनुसन्धान करनेवाली भिन्न-भिन्न कमेटियों की क्या सम्मति थी ? भिन्न-भिन्न सम्मतियों पर प्रकाश डालिये ।

(७) भिन्न-भिन्न प्रांतों में ऋणदाताओं के व्यवसाय का नियन्त्रण करने के लिये जो कानून पास किये गये हैं उनका विवरण दत्त हुये यह बताइये कि इस विषय में क्या विचारधारा है ।

(८) ऋणदाताओं और इन्डीजेनस बैंकों का व्यवसाय सुधारने के लिये अपन सुझाव दीजिये । रिजर्व बैंक से सम्बन्धित हो जाने पर कौन-कौन से लाभ होंगे, यह बताइये ।

(९) रिजर्व बैंक न इन्डीजेनस बैंकों को अपने से सम्बन्धित करने के लिये जो नाति वरती है उस पर आपके क्या विचार हैं ?

(१०) ऋणदाताओं और इन्डीजेनस बैंकों का इम्पीरियल बैंक तथा दूसरे व्यापारिक बैंकों से क्या सम्बन्ध है ? उसके सुधार के सम्बन्ध में अपन सुझाव रखिये ।

—



अध्याय १४

कृषि सम्बन्धी आर्थिक व्यवस्था

कृषि सम्बन्धी आर्थिक व्यवस्था पर हमें न केवल इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिये कि इस देश में इस धन्धे का एक विशेष स्थान है बल्कि इसलिये भी कि इसे कुछ विशेष कठिनाइयाँ हैं । वास्तव में कृषि तथा अन्य धंधों के बीच में कुछ अन्तर है और सत्य तो यह है कि यही कृषि सम्बन्धी आर्थिक व्यवस्था के मूल में है । प्रथम तो कृषि की उपज की इकाई का संगठन प्रायः एक ही व्यक्ति के हाथ में होने से उसे जो साख प्राप्त हो सकती है वह बहुत सकुचित है । इसे साख पाने का आधुनिक तरीका अर्थात् संयुक्त प्रणाली उपलब्ध नहीं है । हम जानते हैं कि अन्य धंधेवाले भविष्य को पूँजी के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं अथवा यो कहिये कि अपनी कल्पित आय की शक्ति के आधार पर द्रव्य एकत्रित कर लेते हैं । किन्तु कृषक ऐसा नहीं कर सकता । उसकी कल्पना की वास्तविकता का साधारण लोगों की दृष्टि में कोई व्यापारिक मूल्य नहीं है । अतः उसके पास साख लेने के लिये केवल अपना

घातित हो है। दूसरे, व्यापारिक पैदाश का संगठन भी उसके लिये उपलब्ध नहीं है। उसकी मुख्य आवश्यकता तो स्थायी पूँजा की है जिससे वह अपने रेत का विस्तार अथवा उमम किसी प्रकार का सुचारु कर ले और यह दुबारा एक दीर्घकालीन ऋण निम्न भुगतान यह एक पसल अथवा कुछ पसलों की सहायता से नहीं कर सकता। फिर, नुमि तथा अन्य प्रकार की जो चीजें वह जमानत के तौर पर दे सकता है उन्हें जोर व्यापारिक एक पसल भी नहीं करता। हम जानते हैं कि उन्हें तो अपने को टपि। अवस्था में रगता है जो हम प्रकार की लागतों में पैसा देन से नहीं रह सकती। अतिस यह है कि यग पर कृषि का उद्यम आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है ही नहीं। कृषि पर जो शाही कमीशन बैठा था उसके व्ययानुसार यहाँ पर यह एक लाभप्रद व्यवसाय न होकर केवल एक जीवन निर्वाह का दग है। इसमें कठिनाइयाँ और भी बढ़ जाती हैं और ऋण की अदायगी सम्भव भी हो जाती है। शाही कमीशन के शब्दों में कृषक ऋण में पैदा होत हैं, ऋण में रहते हैं और अपना ऋण अपने उत्तराधिकारियों को देते हुए ऋण में ही मर जाते हैं। अतः, इसके भुगतान का भी प्रश्न है। सत्तर में कृषकों का आवश्यकताएँ तीन प्रकार की होती हैं - (अ) अल्पकालीन (Short-term), (ब) मध्यकालीन (Intermediate), और (स) दीर्घकालीन (Long-term)। अतः, हम इनकी समस्याओं और उनके हल की ओर ध्यान देंगे।

(अ) अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता

भारत में कृषकों की अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता उनके कृषि सम्बन्धी दैनिक व्यय के लिये उदाहरणार्थ, बीज के दाम के लिये, ऋम के भुगतान के लिये और जब यह कृषि का काम करते हैं अथवा अपनी उपज बाजारों में ले जाते हैं तब वे उनके और उनके कुटुम्ब के व्यय के लिये और उनके अन्य चालू खर्चों के लिये जैसे लगान तथा व्याज के भुगतान के लिये हैं। यदि किसी के पास आर्थिक दृष्टि से उचित भूमि है तो साधारणतः उसे यह सब अपनी एक वर्ष की उपज बेच कर दे देना चाहिये। अतः इनमें नौ महीने लग जाते हैं। कुछ लेखक इसमें विक्रय और चलानी के व्यय भी सम्मिलित कर लेते हैं। किन्तु कृषकों का अधिक लाभ तभी हो सकता है जब यह कुछ अधिक समय तक के लिये अर्थात् तीन वर्ष तक के लिये मिल जाय। ऐसी स्थिति में यह मध्यकालीन ऋण के अन्तर्गत आ जाता है। यहाँ पर अधिकतर तो उपज गाँवों में ही बिक जाती है। अधिकांश में कृषकों को अपनी गरीबी के कारण

अपनी उपज को अच्छा मूल्य पाने के समय तक रोक रखने की शक्ति न होने के कारण उसे फौरन ही कम मूल्य पर बेच देना पड़ता है। यदि उसे उचित आर्थिक सहायता मिल जाय तो वह अपनी सब उपज एक साथ न बेचकर धीरे-धीरे बेचे जिससे उसका उचित मूल्य भी प्राप्त हो सके।

हमें यह देखना चाहिये कि उधार देने वाले वर्तमान संगठन किस तरह से कृषकों की यह अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता पूरी करते हैं। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि जो संगठन ऐसा कर रहे हैं वह प्रायः भिन्न-भिन्न प्रकार की ऋण की आवश्यकताओं में कोई भेद नहीं करते। हाँ, कुछ अपवाद अवश्य हैं जिनका अध्ययन हम उचित स्थान पर करेंगे।

रिजर्व बैंक आफ इन्डिया

प्रथम तो सन् १९३५ में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया है। यह कृषि को निम्न प्रकार से आर्थिक सहायता दे सकता है।—

(अ) सरकारी कागजों के अथवा स्वीकृत भूमिवन्धक बैंकों के उन स्वीकृत ऋण-पत्रों के आधार पर जिनमें धरोहर रखी जा सकती है (Trustee Securities) और जो आसानी से बेचे जा सकते हैं, प्रान्तीय सहकारी बैंकों की और उन केन्द्रीय भूमिवन्धक बैंकों को जो प्रान्तीय सहकारी बैंकों के बराबर घोषित कर दिये गये हैं और उनके मार्फत क्रमशः सहकारी केन्द्रीय बैंकों को तथा प्रारम्भिक भूमिवन्धक बैंकों को नौ महीनों के अन्दर देय ऋण के रूप में,

(ब) केन्द्रीय सहकारी बैंकों के उन ऋण-पत्रों के आधार पर जो कृषी-सम्बन्धी कामों को मौसमी सहायता देने के लिये तैयार किये जाते हैं, प्रान्तीय सहकारी बैंकों को नौ महीनों के अन्दर देय ऋण के रूप में अथवा डिस्काउण्ट के रूप में,

(स) स्वीकृत सहकारी विक्रय और माल रखनेवाली समितियों के उन ऋण-पत्रों के आधार पर जिन पर प्रान्तीय सहकारी बैंकों के बेचान हो और जो उपज की बिक्री के लिये बने हों उन्हें को अधिक से अधिक नव्वे दिन के लिये ऋण के रूप में अथवा यदि वह नौ महीने के अन्दर परूनेवाले हों तो डिस्काउण्ट के रूप में अथवा उन्हीं के उन ऋण-पत्रों के आधार पर जिनके साथ माल रखनेवाली समितियों की रसीदें हों अथवा ऐसे माल की गिरवी रखी गई हो जिसके आधार पर इन्होंने विक्रय और माल रखनेवाली समितियों को नगद उधार अथवा जमा की हुई रकम से अधिक रकम निकालने दी हो इनको ऋण के रूप में।

रैफिंग के भिन्नान्त और उनका प्रयोग

अब यह समझने की बात है कि जो ऋण नव्ये दिन के अन्दर वापिस मिले जाने की शर्त पर दिये जाते हैं वह तो रूढ़ि के अधिक काम में आ ही नहीं सकते। इन्हें तो प्रान्तीय सहकारी बैंक अथवा वह केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंक जो इनके द्वारा घोषित कर दिये गये हैं, यदि उन्हें तीन महीनों के अन्दर अन्दर इनके वापिस कर देने का निश्चय है तो केवल अपनी अल्पकालीन क्षणिक बाग पूरी करने के लिये ही प्रयोग में ला सकते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि वह साधारणतः तो रूढ़ि की अर्थपूर्ति के लिये रिजर्व बैंक का सहारा नहीं ले सकते। हा, प्रत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर थोड़े समय के लिये ऐसा कर सकते हैं। किन्तु केन्द्रीय सहकारी बैंकों के उन प्रण-पत्रों को फिर से डिफेंड कर देने की शर्त भी है जो रूढ़ि के मौममी कामों की सहायता करने के लिये लिरो जाते हैं अथवा ऐसे ही ग्योहन सहकारी विषय और माल रखने वाली समितियों के प्रण-पत्रों का सम्भार में भी है, और दोनों स्थितियों में प्रण-पत्र नौ महीना में पसने वाले हो सकते हैं तथा सहायता प्रान्तीय सहकारी बैंकों की को प्राप्त हो सकते हैं। यह अवश्य ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है, किन्तु वहाँ तक सहकारी विक्रय अथवा माल रखनेवाली समितियों के प्रण-पत्रों का प्रश्न है वह तो यहाँ हो ही नहीं सकते क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इस देश में तो बहुत कम सहकारी विक्रय और माल रखने वाली समितियाँ हैं। उपर्युक्त से यह भी स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक सहायता देने के लिये केवल प्रान्तीय सहकारी बैंकों को मानता है, केन्द्रीय सहकारी बैंकों को नहीं मानता। हम जानते हैं कि कृषक प्रारम्भिक समितियों से ऋण लेते हैं और वह केन्द्रीय बैंकों के पास सहायता के लिये जाती है। अतः रिजर्व बैंक के केवल प्रान्तीय बैंकों को सहायता देने के कारण वह केवल इन्हीं में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सचमुच बहुत ही घुमाव-फिराव है। अतः, यह सुझाव रखना जा रहा है कि रिजर्व बैंक को उन केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भी सहायता देनी चाहिये जो उसके माप के अन्दर आ जायें।

इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया और अन्य

व्यापारिक बैंक

रिजर्व बैंक के नाद इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य व्यापारिक बैंक हैं। इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया प्रान्तीय सहकारी बैंकों को और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को क्रमशः केन्द्रीय सहकारी बैंकों के तथा प्रारम्भिक सहकारी

समितियों के प्रण-पत्रों के आधार पर नकद साख अथवा अधिविक्रय के रूप में ऋण देता है। किन्तु इधर यह ऐसे ऋण कम करता जा रहा है, क्योंकि यह प्रण-पत्र प्रायः भूमि के आधार पर लिखे होते हैं और यह भूमि का आधार उपयुक्त आधार नहीं मानता। दूसरे, यह कृषि की सहायता इन्डोजेनस बैंकों द्वारा भी करता है क्योंकि वे कभी-कभी अपनी इन्डियाँ इसके यहाँ डिस्काउन्ट कराते हैं अथवा उपज गिरवी रखकर ऋण प्राप्त करते हैं। अन्य व्यापारिक बैंकों में देश के सम्मिलित पूँजी वाले बैंक आ जाते हैं। यह लगभग वैसा ही व्यवसाय करते हैं जैसा इम्पीरियल बैंक करता है। इनमें से कुछ जमींदारों को उमकी जमीन, इत्यादि के आधार पर भी ऋण देते हैं।

साख सहकारी समितियाँ

(Credit Co-operative Societies)

अब हम साख सहकारी समितियों की ओर आते हैं। ये इस आधुनिक रूप में पहले-पहल सन् १८४६ में जर्मनी में खोली गई थीं। आजकल सहकारी समितियों की जो दो प्रणालियाँ हैं उनके चलानेवाले दो व्यक्ति ये जिनके नाम क्रमशः एफ० डबल्यू० रैफिसेन (F W Raiffeisen) और फ्रिज हरमन शुल्ज डेलिश (Fritg Hermann Schulze Delitzsch) हैं। ये प्रणालियाँ क्रमशः 'रैफिसेन और शुल्ज डेलिश प्रणालियाँ' कहलाती हैं। प्रथम में एक ही पड़ोस के अथवा स्थान के रहनेवाले बहुत से किसान अपनी इच्छा से मिल जाते हैं और पारस्परिक सहायता के लिये एक समिति बना लेते हैं। प्रत्येक सदस्य का दायित्व असीमित रहता है। समिति को जमा से, प्रवेश शुल्क से और कभी-कभी सदस्यों के पूँजी देने से और उधार के रूप में द्रव्य मिलता है और उसे वह अपने सदस्यों को उनकी आवश्यकतानुसार उधार दे देती है। प्रबन्ध प्रायः निशुल्क होता है, केवल लेखकों को वेतन मिलता है। सब की राय से उनमें जो बहुत ही बुद्धिमान् होता है वही मुख्य कार्य संचालन और देख रेख करता है। द्वितीय में एक ही शहर में रहनेवाले बहुत से कारीगर जो स्वयं अपने लिये काम करते हैं मिल कर एक समिति बना लेते हैं इसमें हर सदस्य को एक जमानती हिस्सा लेना पड़ता है जो काफी ऊँची रकम का होता है। यह कई किस्तों में वसूल की जाती है जिससे वह मितव्ययता सीखते हैं। यह समिति भी जमा और ऋण के रूप में रकम प्राप्त करती है और यह ऋण की रकम उतनी ही अधिक होती है जितनी जमानती पूँजी होती है। सदस्यों का दायित्व

प्रायः असीमित होता है किन्तु यह सीमित भी हो सकता है। समिति का द्रव्य सदस्यों में श्रृण के रूप में बाँट दिया जाता है। प्रमन्थक को प्रतिफल के रूप में उचित रकम भी दी जाती है और लाभ की बँटनी भी होती है तथा उसका एक सुरक्षित कोष भी बनता है। दोनों प्रकार की समितियों की मुख्य-मुख्य बातें मध्यम में तुलनात्मक रूप में दी जा सकती हैं :—

रेफिसेन समिति

(१) काम करने का क्षेत्र सीमित रहता है।

(२) पूँजी प्रायः नहीं होती। यदि वह होती भी है तो बहुत कम होती है।

(३) सदस्यों का दायित्व असीमित होता है।

(४) गैर सदस्यों को श्रृण नहीं दिया जाता।

(५) श्रृण प्रायः उत्पत्ति के कामों के लिये दिया जाता है।

(६) लाभ की बँटनी नहीं होती।

(७) प्रमन्थ निशुल्क होता है।

शुल्ज उल्लिश

(१) काम करने का क्षेत्र मितृत रहता है।

(२) पूँजी प्रायः होती है।

(३) सदस्यों का दायित्व कभी-कभी सीमित होता है।

(४) गैर सदस्यों को भी श्रृण दिया जा सकता है।

(५) श्रृण उपभोग के लिये भी दिया जा सकता है।

(६) लाभ की बँटनी होती है।

(७) प्रमन्थ के लिये प्रतिफल दिया जाता है।

भारतवर्ष में सहकारिता का विकास

यद्यपि भारतवर्ष में सहकारिता प्रारम्भ करने के लिये पहले भी प्रयत्न किये गये थे किन्तु सरकारी तौर पर यह यहाँ पर सन् १९०४ ही में प्रारम्भ हुआ। इसके सम्बन्ध के पहले वाले सुझाव पर विलियम वेडरबर्न और जस्टिस रान्डे के थे, किन्तु उनके भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर लेने पर भी भारत सचिव ने उन्हें स्थगित कर दिया। फिर, सर फ्रेड्रिक निकल्सन ने सन् १८९० में भारत सरकार को भूमि और कृषक बैंकों सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट पेश की और रेफिसेन प्रणाली की समितियों की स्थापना का सुझाव रखा। किन्तु यह भी कार्यरूप में नहीं लाया गया। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस के श्री० डुपरनैक्स ने प्रयत्न किया और वह कुछ सफल भी हुये क्योंकि उत्तर

प्रदेश, बङ्गाल और पञ्जाब में कुछ समितियाँ स्थापित हुईं। अन्त में सन् १९०१ में लार्ड कर्जन की सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसकी सिफारिसों के फलस्वरूप सन् १९०४ का सहकारी साख समिति विधान बना।

इस विधान में केवल साख सम्बन्धी समितियों के खुलने का ही प्रवन्ध था, और ग्रामीण समितियों पर नागरिक समितियों की अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया गया था। इसके अनुसार एक ही गाँव के अथवा शहर के अथवा वर्ग के अथवा जाति के कोई दस व्यक्ति अपने को एक समिति के रूप में संगठित करने के लिये आवेदन-पत्र भेज सकते थे। यदि सब सदस्यों के कम से कम ५ ग्रामीण होते थे तो वह समिति ग्रामीण साख समिति कहलाती थी, अन्यथा नागरिक कही जाती थी। प्रथम तो रैफिसेन वर्ग की थी और द्वितीय शुल्ज डेलिश वर्ग की। इनके निरीक्षण, आडिट और भुगतान करने का अधिकार सरकार को दे दिया गया था।

इस आन्दोलन ने खूब ही उन्नति की और सन् १९०४ का विधान अपर्याप्त प्रतीत होने लगा। अतः, सन् १९१२ में एक दूसरा विधान बना। इसने सन् १९०४ के विधान के दोष दूर किये और साख के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों से स्थापित समितियों की स्थापना के लिये भी नियम रक्खा। इसमें अभी तक समितियों का जो विभाजन था, अर्थात् ग्रामीण तथा नागरिक उसके स्थान पर एक अन्य अधिक वैज्ञानिक विभाजन का नियम बनाया जिसके अनुसार यह परिमित दायित्व वाली तथा अपरिमित दायित्ववाली कहलाई जाने लगी। अन्तिम बात यह थी कि इसने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सहकारी बैंकों की भी योजना की और इस तरह से इसका नीचे से ऊपर तक एक मजबूत संगठन बना दिया। किन्तु साख के अतिरिक्त अन्य कामों के लिये समितियाँ बनाने पर जो पहले बन्धन था उसे सन् १९१२ के विधान द्वारा दूर कर देने पर भी आज तक अधिकांश समितियाँ साख समितियाँ ही हैं।

सन् १९१४ में सहकारिता के सम्बन्ध में मैकलेगन कमेटी नियुक्त हुई। उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिये एक वर्ष लिया। उससे समितियों का पुनर्संगठन हुआ और उसके प्रवन्ध में बहुत-सा परिवर्तन हो गया। जो आयोग्य थीं वह बन्द भी कर दी गईं। ऋण की वापिसी के लिये समय पालन पर जोर दिया जाने लगा और इनके चलाने में जनता का हाथ बढ़ा दिया गया।

सन् १९१६ के सुधारों ने सहकारिता को एक हस्तान्तरित विषय बना

दिया। 'नत', इसके मन्त्रियों (Ministers) ने नहीं दिया चन्सी दिग्गलाटे और शीप ही बहुतनी समितियों स्थापित हो गई। तब ने लगभग प्रत्येक प्रान्त में इसके सुधार के लिये कमेटियाँ भी बना जिन्होंने अन्धे अन्धे सुझाव सकते। रिजर्व बैंक की वैधानिक रिपोर्ट में भी इस सम्बन्ध में काफी प्रकाश डाला गया है और पुनर्गठन के लिये अन्धे सुझाव रखे गये हैं।

देश में माख सम्बन्धी सहकारिता के आन्दोलन की वर्तमान स्थिति—भारतवर्ष में सात सम्बन्धी सहकारिता के आन्दोलन में (१) प्रारम्भिक सहकारी समितियों, (२) केन्द्रीय सरकारी बैंक तथा (३) प्रान्तीय सहकारी बैंक हैं। एय अखिल भारतवर्षीय सहकारी बैंक की भी आवश्यकता है किन्तु यह अभी तक नहीं बना है।

प्रारम्भिक सात सहकारी समितियाँ ग्रामीण तथा नागरिक दोनों प्रकार की हैं। इनकी सख्या क्रमशः लगभग ११ लाख तथा १८००० है। ग्रामीण सहकारी समितियों की पूँजी प्रवेश शुल्क से, हिस्सों (Shares) से, सर सदस्यों की जमा अथवा ऋण से, केन्द्रीय और प्रान्तीय सहकारी बैंकों और सरकार के ऋण से तथा अपने कोष से प्राप्त होती है। सत्र रकम काफी बड़ी है। सन् १९४७--४८ के अन्त में यह लगभग १७१ करोड़ २० यो। यह किस प्रकार प्राप्त हुई थी यह भी जानने योग्य है —

हिस्सों से प्राप्त पूँजी	रु० २६८५००००००
सुरक्षित तथा अन्य कोष	रु० १३८०००००००
जमा से प्राप्त पूँजी तथा ऋण	रु० १,१२,५८००००००

केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रायः जिले के मुख्य शहर में स्थित है। इनकी सख्या लगभग ४६६ है। इनका काम न केवल प्रारम्भिक समितियों को आर्थिक सहायता देना है बल्कि जिनके पास फालतू रकम है उनकी रकम जिनके पास उनकी कमी है उन्हें देना है और सत्र का पथ-प्रदर्शन और निरीक्षण करना भी है। इन्हें प्रारम्भिक समितियों तथा ग्राहरी लोग दोनों मिल कर बनाते हैं और इनकी पूँजी इनके हिस्सों से, सुरक्षित कोष से, जमा से और ऋण से प्राप्त होती है।

प्रान्तीय सहकारी बैंक इस समय पञ्जाब को छोड़कर प्रायः सभी बड़े-बड़े प्रान्तों में हैं। अधिकांश में इनका संगठन मिश्रित रूप से हुआ है, अर्थात् सदस्यता और संचालक मण्डल दोनों में जन साधारण तथा सहकारी समितियों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि हैं। इनकी कार्यशील पूँजी हिस्सों से

सुरक्षित तथा अन्य कोषों से, जनता से, समितियों से, प्रान्तीय और केन्द्रीय बैंकों से और सरकारी ऋण से प्राप्त होती है।

इसकी उन्नति सभी प्रांतों में एक सी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश १९४८ की २६२६१ समितियों के कारण सबसे आगे है। फिर, हैदराबाद में १९०४४ और मद्रास में १८६५६ समितियाँ थीं। सन् १९४८ में प्रारम्भिक समितियों के सदस्यों की संख्या लगभग १ करोड़ थी। यदि हम एक परिवार औसतन ५ व्यक्तियों का मान लें तो यह स्पष्ट है कि यहाँ पर इनसे ५ करोड़ लोगों को फायदा होता है। वास्तव में और कोई ऐसी समस्या हमारे यहाँ नहीं है जिससे इतने अधिक लोगों का सम्बन्ध हो।

इस आन्दोलन के मुख्य दोष—किसी भी सहकारी समिति की

सफलता उसके सदस्यों के अपना ऋण समय पर वापिस करने पर निर्भर रहती है। यह ऋण अल्पकालीन होते हैं। अतः, इनका भुगतान उपज के विक्रय के साथ-साथ हो जाना चाहिये। किन्तु यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता। यहाँ कृषक समितियों का सन् १९४०-४१ में १०४१ लाख रु० बाकी था जो कभी का वसूल हो जाना चाहिये था। यदि हम इसकी तुलना पूरी कार्यशील पंजी से करें तो यह ३४ प्रतिशत होगा। लोगों को जो ऋण दिया गया था और जो २२५० लाख रु० या उसका यह ४६ प्रतिशत है। यद्यपि इधर के अक प्राप्त नहीं हैं तो भी जो कुछ पता लगाया गया है उससे यह शत होता है कि उपज का मूल्य बढ़ जाने से इसमें से कुछ ऋण का तो भुगतान हो गया है, जिसका नहीं हुआ है वह नहीं हो सकता। अतः, उसे समाप्त करके इन समितियों का पुनर्निर्माण करना चाहिये।

समितियों के अधिकांश सदस्य उनके उद्देश्य नहीं समझ पाते। इनकी सहायता से उन्हें जो अधिकार प्राप्त हैं और उनके जो दायित्व हैं उन्हें वे नहीं समझते। उन्होंने इनसे मितव्यता और दूरदर्शिता का पाठ भी नहीं सीखा। फिर, सहकारी समितियों को अर्थ के अतिरिक्त अन्य बातों का भी सुधार करना चाहिये। उदाहरणार्थ अच्छी प्रकार रहने का, कृषि करने का, विक्रय का, शिक्षा का, इत्यादि इत्यादि।

केन्द्रीय और प्रान्तीय बैंकों के कार्यों में भी कुछ दोष हैं। इधर केन्द्रीय बैंकों से सम्बन्धित समितियों की संख्या बढ़ती जा रही है। रिजर्व बैंक की वैधानिक रिपोर्ट में एक ऐसे बैंक का नाम है जिससे ६८० समितियाँ सम्बन्धित थीं। जहाँ पर इतना काम बढ़ गया है वहाँ अच्छी देख-भाल नहीं हो सकती। न तो

प्रातीय देशों में और न केन्द्रीय देशों ही में प्रारम्भिक समितियों के प्रति अपना पक्षपालन किया है। उन्होंने अभी तक अपना ध्यान केवल इन्हें आधिक मदायता पहुँचाने की ओर ही रखा है। उन्हें तो इनके उन सभी कामों की ओर ध्यान देना चाहिये जिससे इनका स्तर ऊँचा हो और आन्दोलन दृढ़ होना बढ सके। फिर, इनका स्थिति भी बहुत ठीक नहीं है। प्रायः इनके माधन उतने द्रवित श्रमणा में नहीं हैं जितने होने चाहिये। अन्तिम, यह अपने उधार लेने और देने के व्यापार की दर में इतना भी अन्तर नहीं मानते कि वह अपना गन्ध पूरा करने के बाद कुछ सुरक्षित भोज में भी न टाल लें।

सुधार के लिये सुझाव—साथ सदस्यारी समितियों को केवल अल्प-पालीन मात्र का ही प्रयत्न करना चाहिये। अधिक से अधिक वह मध्यमालीन मात्र का भी प्रयत्न कर सकती हैं। दीर्घमालीन मात्र का तो प्रयत्न उन्हें किसी प्रयत्ना में भी नहीं करना चाहिये। जब कभी ऋण के लिये प्रार्थना-त्रय आवे, सदस्याओं को यह बात पता लगा लेनी चाहिये कि वह किस काम के लिये चाहिये। सदस्यारी समितियों को यदि अपना उद्देश्य पूरा करना है और केवल महान्तों का ध्यान नहीं लेना है तो उन्हें यह देखना चाहिये कि उनके सन्ध केवल उत्पत्ति के लिये उधार लेते हैं। इसके यह अर्थ नहीं है कि उपभोग के लिये ऋण दिया ही न जाय, किन्तु ऐसी आवश्यकता ही कम से कम कर देनी चाहिये। दूसरी बात जो देखने की है वह यह है कि ऋण लेनेवाले में उसे वापिस करने की क्षमता है अथवा नहीं। साथ सदस्यारी समितियों को यह भी देखना चाहिये कि उनके सदस्य अपनी आय से अधिक व्यय नहीं करते। सत्य तो यह है कि उन्होंने अभी तक इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और इसी से उनके ऋण की वसूली नहीं हो पाती। वास्तव में ऋण का उद्देश्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि ऋण देनेवाला उसे फल निकालने के बाद और कुछ परिस्थितियों में अधिक से अधिक तीन वर्षों के अन्दर ही वापिस करने की क्षमता रखता हो।

फिर, जैसा कि रिजर्व बैंक की प्रारम्भिक तथा वैधानिक रिपोर्टों में कहा गया है, जो ऋण वसूल नहीं हो रहे हैं उनका प्रश्न भी लेना चाहिये। चीजे टालने से और बार-बार समय बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होता। जहाँ पर ऋण पुराने हो गये हैं सहकारिता का आन्दोलन काम नहीं कर रहा है और सदस्य महान्तों से फिर से ऋण लेने लग गये हैं। ऋण की वसूली न होने से साथ की सतिता का बहाव रुक जाता है। अतः, इस समस्या को शीघ्र ही क्रियात्मक

रूप से सुलभाना चाहिये। इन्हें इतना घटा देना चाहिये कि वह आसानी से दिये जा सकें और फिर इनका प्रबन्ध भूमि बन्धक बैंको द्वारा फरवा देना चाहिये जो दीर्घकालीन साख का प्रबन्ध करने के लिये बने हैं। इनका अध्ययन हम आगे चलकर करेंगे। इससे जो हानि होगी उसे यह समितियाँ न छोड़ सके तो उसका भी प्रबन्ध करना चाहिये। समस्याओं को साहम के साथ सुलभाने में ही काम चलता है। जो बातें स्पष्ट हैं उनका सामना तो करना ही चाहिये।

इन समितियों को भविष्य में अपने ऋण लेने और देने के व्याज की दर के बीच में काफी अन्तर रखना चाहिये जिससे इनके पास अच्छे कोष संचित हो जायें। जो ऋण आज-कल वसूल नहीं हो रहे हैं उन्हें बट्टेवाते छोड़ने में यही कठिनाई है कि समितियों के प्राप्त काफी सुरक्षित कोष नहीं हैं। बात यह थी कि जैसा पहले भी कहा जा चुका है उन्होंने अभी तक ऋण लेने और देने के व्याज की दर के बीच में काफी अन्तर रखना ही नहीं। इसके यह अर्थ नहीं हैं कि भविष्य में हम ऐसे ऋण देंगे जो वसूल न होंगे और फिर उन्हें सुरक्षित कोष के सहारे बट्टेवाते में डाल देंगे। यह केवल उदाहरण के लिये है। सुरक्षित कोष अनेक कामों में खर्च किया जा सकता है। समितियों की स्थिति सुदृढ़ बनाने का यह एक दृढ़ है।

अन्तिम बात यह है कि किसी समिति का उद्देश्य ही यही है कि उसके सदस्यों की हर तरह से उन्नति हो। उसे कृषकों के सम्पूर्ण जीवन का ध्यान रखना चाहिये। वास्तव में सदस्यों को सहकारिता का सच्चा महत्व समझाना चाहिये। उसका उद्देश्य केवल ऋण देना ही नहीं है वरन् हर प्रकार से कृषकों का जीवन सुधारना है। उनकी आय बढ़नी चाहिये, कृषि आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो जानी चाहिये। सच तो यह है कि ग्रामीण अर्थ की समस्या उसके बिना सुलभ ही नहीं सकती। जैसा कि एक लेखक ने कहा है कि जब तक हम कृषि की उत्पत्ति इस प्रकार नहीं बढ़ा पाते कि एक श्रमिक वर्ग के कृषक को उसके वर्ष भर के परिश्रम के बाद उसने जो कुछ व्यय किया है उससे अधिक मिल जाय तब तक हम ग्रामीण अर्थ का प्रश्न सुलभ ही नहीं पाते।

केन्द्रीय और प्रान्तीय बैंकों के भी सुधार की आवश्यकता है। जिन स्थानों में एक केन्द्रीय बैंक से बहुत ही अधिक समितियाँ सम्बन्धित हैं, वहाँ पर उन्हें तहसीलों की इकाई के अन्तर्गत लाना चाहिये। इससे निरीक्षण और नियंत्रण में सुविधा होगी। फिर, केन्द्रीय बैंकों और प्रान्तीय बैंकों दोनों को बैंकिंग के

निधियों के अनुसार भुसंगति। होता चाहिए। उन्हें अपनी मर्यादा और पाठन द्रवित प्रकथा में रखने चाहिए। ऐसा प्रारम्भिक अभिविधा के सम्बन्ध में कहा जा चुका है उगी प्रकार इन्हें भी अपने उधार लेने और देने के व्याप की दर में सार्थक अन्तर रखा जाय। आज्ञा ज्ञा एम उर्ध्व ने दसम वर्ष में बच्चे की मर्यादा से जान की चाल है उसे शायद बढ़ाने में भी मन्द किया जा सकता है। अन्तिम बात यह है कि केन्द्रीय सरकारों और व्यापारिक बैंकों के बीच में सम्बन्ध बढ़ाने का बहुत आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकारों और व्यापारिक बैंकों में प्रयोग उनमें अपने अपने द्रव्य लगाने के लिये और सरकारी सामान्यता के आधार पर सृष्टि लेने के लिये पर सवते हैं। इसका विरुद्ध व्यापारिक बैंक केन्द्रिय सरकारों का प्रयोग उन स्थानों पर अपने ग्लो की वस्तुओं परने के लिए पर सक्त हैं जिनमें उनके स्वयं के दस्ता नहीं है। इस प्रकार की पास्वरिक सहायता ने दोनों लाभ उठा सकते हैं।

सहकारी समितियों और बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा दी गई द्रव्य भेजने की सुविधा—रिजर्व बैंक सहकारी समितियों और बैंकों ने १ अक्टूबर सन् १९४० ने द्रव्य भेजने के लिए निम्न गियायती व्यय लेता है—

५०० रु० तक	५००० रु० के ऊपर
प्रतिशत न्यूनतम	प्रतिशत न्यूनतम
दर व्यय	दर व्यय
११६ रु० आ० पा०	६० रु० आ० पा०
०—४—०	११२ ३—२—०

ऋण देनेवाले और इण्डोजेनस बैंकर

ऋण देनेवाले और इण्डोजेनस बैंकर कृषि की जिस प्रकार आर्थिक सहायता करते हैं उसका हम अध्ययन कर ही चुके हैं। उनके काम करने के दृष्टि की सादगी और ऋण लेनेवालों ने उनके व्यक्तिगत सम्बन्ध, उनके स्थानीय ज्ञान तथा अनुभव के कारण ऐसा भाव्य में भी बराबर होता रहेगा। निस्सन्देह, सन् १९३७ के बाद जो मन्दी चली थी, कृषक ऋण लेनेवालों की जो रक्षा कर दी गई है, सहकारी समितियों के विश्वास, डिप्टी देने में विलास तथा उनमें से कुछ जो बुरा बर्ताव करते हैं उसके कारण उन सभी के ऊपर सन्देह की दृष्टि के कारण उनकी दशा इधर बहुत बिगड़ गई है। किन्तु इधर उनका सुधार करने के लिये प्रयत्न किये गये हैं और ऐसी आशा है कि वह

भविष्य में अधिक लाभप्रद साबित होंगे । कृषि की आर्थिक सहायता की, किसी समस्या के हल की तथा उनके सुधार की कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि कृषकों के इस समय के ऋण का निपटारा और उनका भुगतान न हो जाय । आसाम, बंगाल, मध्यप्रांत और पञ्जाब में ऋण के निपटारे के सम्बन्ध में विधान बने चुके हैं । इनके अनुसार वहाँ की प्रान्तीय सरकारें इसके लिये बोर्ड बना सकती हैं । उनका उद्देश्य ऋणियों और महाजनो के बीच समझौता कराकर ऋण का निपटारा करने का है । कोई भी ऋणी अथवा महाजन उनके यहाँ इसमें लिये प्रार्थना-पत्र भेज सकता है । ऐसा होने पर वह महाजन और ऋणियों से कमरा उनके ऋण, सम्पत्ति तथा पाउने इत्यादि की सूचना माँगते हैं । ऋण के सम्बन्ध में उन्हें प्रमाण भी देने पड़ते हैं । जब सूचना मिल जाती है तब बोर्ड ऋणी का महाजन से समझौता करने का प्रयत्न करता है । यदि इसमें सफलता मिल जाती है तो समझौते की रकम २०, २५ किस्तों में देने की योजना बना दी जाती है । महाजनों के बोर्ड द्वारा किया हुआ कोई निपटारा न मानने पर उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । ऐसी स्थिति में बोर्ड ऋणी को एक प्रमाण-पत्र दे देता है और महाजन के अदालत में जाने पर उसे न तो उसका खर्च और न ६ प्रतिशत से अधिक व्याज मिलता है । जो महाजन निपटारा स्वीकार कर लेते हैं उनके ऋण की अदायगी का पहले प्रबन्ध कर दिया जाता है । निपटारे के स्वीकृति के जो लाभ और अस्वीकृति की जो हानियाँ हैं वह सब प्रान्तों में एक ही नहीं हैं । इसके अनिश्चित कहीं-कहीं तो जैसे पञ्जाब में बोर्डों के मामले बर्काल आ सकते हैं, और कहीं कहीं जैसे मध्य प्रान्त, आसाम, मद्रास और बंगाल में ऐसा नहीं हो सकता । इसी तरह से मध्य प्रान्त, आसाम और बंगाल में यह है कि यदि ऋणी कोई किस्त नहीं देता तो वह लगान वसूल करने वाले विभाग के द्वारा वसूल कराई जा सकती हैं । ऋण के निपटारे की योजना उसका उसी समय भुगतान का प्रबन्ध कर देने पर और भी सफल हो सकती है । ऐसा जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे भूमि बन्धक बैंको द्वारा ही सम्भव है । तब भी भिन्न-भिन्न प्रांतों में ऋण के निपटारे के जो अंक हैं उनसे इनकी लोकप्रियता का पता लग जाता है ।

कहाँ-कहीं तो कृषि की उपज की कीमतों में जो कमी हो गई थी उसी के फलस्वरूप कृषि सम्बन्धी ऋणों के छुटकारे के लिये जो विधान बने थे उनके अनुसार कृषकों के ऋण बहुत कम कर दिये गये थे ।

सामांज्य दिखाले या तो विधान है उसे उन शक्तियों के सम्बन्ध में अवश्य लगाना चाहिये जिनके पास पूर्ण शक्ति रखने के लिये भी भूमि नहीं है और निम्नो सम्पत्ति और ऋण गोप्यता समता इत्यादि भी नहीं है कि यह ऋण बहुत अधिक बढ़ा देने पर भी बढ़ा कर गढ़ें।

प्राप्त्यन्त ऋणगतियों और महाजनता का रूपों के ऊपर जितना ऋण है उसका निरन्तरा करने और उनमें कमी करने पर तथा उसका भुगतान करने और लाभ प्राप्ति का हो उसे समान कर देने के बाद और आम करने के दृष्टि सुधार देने पर वे गे लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। हा, ये अत्यन्त-लीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन तीन प्रकार के ऋण देने का प्रयत्न नहीं कर सकते। अति-ले-अधिक जो यह कर सकते हैं वह यह है कि यह प्रयत्न और हमारे ऋण देने का प्रयत्न कर दें। फिर, इस बात का भी प्रयत्न करना होगा कि क्राय कि ऋणग्रस्त न हो जायें, और यह नहीं हो सक्ता है जब उन्हें इनने असीमित ऋण लेने में रोक दिया जाय। उत्तर प्रदेश के एक विधान (Money Lender's Bill, 1939) में यह दिया गया है कि कोई महाजन एक वर्ष में जमीन रूपक की उपज का एक चौथाई से अधिक अपने ऋण की अदायगी में नहीं पा सकता और न ही यह ऐसा प्रत्यक्ष चार वर्षों में अधिक कर सकता है। इसके यह अर्थ है कि महाजन केवल उपज की कीमत तक ही ऋण दे सकता है। कैलवर्ट कमेटी के मुताबिक के अनुसार स्वीकृत ऋणदानाओं और महाजनों के उपज के आधार पर दिये दिये ऋणों के लिये उपज से ऋण पूरित करने का प्रयत्न अधिकार देना चाहिये।

(घ) मध्यकालीन ऋण की आवश्यकता

रूपि के ऋण के सम्बन्ध के जो व्यव हैं उनके लिये ऋण की जो आवश्यकता पड़ती है उसके अतिरिक्त रूपों को मवेशी खरीदने के लिये और खेती में प्रसार किये जानेवाले सुधार करने के लिए मध्यकालीन ऋण की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, इसमें फसल को लाभ पर बेचने के लिए भी जिसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसे भी सम्मिलित किया जा सकता है। इन कामों के लिए जो ऋण लिया जाता है उसका भुगतान एक वर्ष के अन्दर नहीं किया जा सकता। अतः उसके लिए एक लम्बी अवधि चाहिए जो तीन वर्ष से लेकर पाँच वर्ष तक की हो सकती है। इसके लिए रूपक जो जमानत दे सकता है, वह उसकी चल सम्पत्ति की हो सकती है, जैसे जेवरात अथवा मवेशी अथवा फसल।

मध्यकालीन ऋण देने के लिये वर्तमान संगठन और उनके सुधार के लिये सुझाव

अल्पकालीन ऋण के लिए जो संगठन है वही प्रायः मध्यकालीन ऋण भी देते हैं। यदि हमें फसल बेचने के लिए जो सहायता चाहिए उसे हम ले तो यह वहाँ से प्रारम्भ होती है जब वह खलिहान में तैयार हो जाती है। कभी-कभी तो यह उससे पहले भी प्रारम्भ हो जाती है, अर्थात्, उसी समय में जिस समय से कृषक इस शर्त पर ऋण लेता है कि वह उपज तैयार होने पर उसे ऋणदाता के हाथ पहले से निश्चित मूल्य पर बेच देगा। वस्तुतः, न तो कृषक ही और न यह ऋणदाता ही यह उपज बहुत दिनों तक अपने पास रख सकते हैं; अतः, वह बड़े बड़े महाजनों के पास पहुँच जाती है। यह प्रायः अदतिये होते हैं, और अन्त में आर्थिक सहायता का बोझ इन्हीं के ऊपर पड़ता है। यदि इन्होंने जिससे माल पाया है उसे पहले से ही ऋण दे रक्खा था तो यह केवल किताबी जमाखर्च कर लेते हैं। अन्य स्थितियों में इन्हे नकदी देनी पड़ती है। हाँ, यदि यह इन्हे आदत पर रखते हैं तो उन्हें उसका कुछ प्रतिशत व्यापारी से मिल जाता है। इन्हे भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है जो निम्न संगठनों से प्राप्त होती है—

(१) दूसरे महाजनों से अथवा इम्पीरियल बैंक और सम्मिलित पूँजी के बैंकों से—जिस शर्त पर और जितनी रकम के ऋण इनसे मिल सकते हैं वह उनकी साख पर निर्भर है। कभी-कभी तो उसे प्रण-पत्र लिखना पड़ता है, कभी-कभी हुण्डी से काम चल जाता है और कभी-कभी उसके पक्ष में एक चालू खाता खोल दिया जाता है। जब ऋण मुद्दी हुण्डी के आधार पर किसी अन्य महाजन से प्राप्त हो जाता है तब कभी-कभी वह हुण्डी फिर किसी व्यापारिक बैंक से भुना ली जाती है।

(२) माल भरती पर ऋण—माल गोदाम में भरा रहता है, अतः, उस पर भी ऋण मिल जाता है। यदि ऋणदाता कोई महाजन ही होता है तो वह उसके ऊपर ऐसे ही ऋण दे देता है। हाँ, यदि वह इम्पीरियल बैंक अथवा कोई अन्य सम्मिलित पूँजीवाला बैंक होता है तो वह गोदाम में अपना ताला और अपने नाम की तख्तों भी लगाता है।

(३) माल की चलानी पर ऋण—यदि माल वहाँ का वहीं बिक्रि जाता है तो उसका मूल्य नकद अथवा बाजार चलान के अनुसार एक उचित

प्रसवि के अन्दर मिन जाता है, और यदि वह बाहर जाता है तो भी मृत्यु या जो भी हो जाना हो जाता है। या उसके लिये दृग्गती दृग्गती कर ली जाती है जो गाली हो सकती है, अथवा जिनके मान बिन्दी भी हो सकती है। जाली दृग्गती होने पर बिन्दी मान लगाने के नाम दृग्गती होते ही उससे पास भेज दी जाती है और जब उसके साथ बिन्दी भी होती है तब वह दृग्गती को दे दी जाती है, जो अन्तो जाया गया अथवा अथवा किसी अन्य अदभिये उद्ग नोटों ने जो लाभ होता है उस काम में लगाया जा सकता है। गोदामों का प्रयोग भी इसी प्रकार से हो सकता है। हमने उसी ग्रीक मरान्ध साधन-पत्र का काम दे सकते हैं।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि प्राजस्न का जो दृग्गती है उसमें ग्रीक अदभिये हैं जिन्हें दूर करना चाहिये। प्रथम तो दृग्गती अपनी उपज अधिक दिना तक अपने पास नहीं रख सकता जिनसे उसे ऊँची कीमत नहीं मिल पाती। महसारी समितियाँ उसका माल लेकर उसे ऋण दे सकती हैं और फिर माल अच्छी कीमत पर बेच सकती हैं। इससे दृग्गती को न फेंकल ऊँचे दाम ही मिल जायेंगे वरन् उसकी माल बेचने की बहुत सी सुविधाएँ भी दूर हो जायेंगी। दूसरे, माल भ्रष्ट की कठिनाइयाँ हैं। दृग्गती अपना माल मटकों में, गोदों में चढ़ाई के चेरों में, मिट्टी और जालियों के घेरों में, अथवा जमीन के अन्दर की छतियों में रखते हैं। बाजार में भी यही सब चालें हैं। हाँ, वह कुछ बड़ी अवश्य होती हैं। प्रत, चूड़ों और घुन ने अथवा भूमि के अन्दर की नमी में बड़ी हानि होता है। प्रारम्भ के व्यय अधिक होने के कारण अच्छे तरीकों का प्रयोग तो नहीं हो सकता। हाँ, लाहसेन्स प्राप्त गोदाम अवश्य स्थापित किये जा सकते हैं। विधानतः इन्हें हवा सम्पन्धी, मिलावट करने के विरुद्ध, माल के वर्गीकरण की और प्रगन्ध की गतों का पालन करना पड़ता है। इन पर सरकार का निरीक्षण और नियन्त्रण भी रहता है। गोदामों की रसीद अच्छे अधिकार पत्र का काम देती है, और इसी से ऋण के लिए जमानत का अथवा दृग्गती के आधार स्वरूप काम देती है। तीसरे, अधिकांश व्यापार नकदी का होता है, जहाँ उधार होता भी है वहाँ भी केवल जमा त्वर्च कर लिया जाता है, साख-पत्र प्रयोग में नहीं लाये जाते। मुद्रती दृग्गती का चलन बढ़ाने की आवश्यकता है। यह विनिमय साध्य होने के कारण सब जगह स्वाकृत हो जाती है और यह साख की बुनियाद का काम करती है। चौथे, दर्शनी दृग्गती के आधार-स्वरूप मिलितियाँ बहुत कम होती हैं। अतः, उपर्युक्त सुधार होने से ये दृग्गती का व्यवसाय अधिक मात्रा में करेंगे।

कुछ प्रान्तों में वहाँ की सरकारें रुपया उधार देकर गोदामों के बनने में बड़ी सहायता कर रही हैं। तो भी यह काम रिजर्व बक बड़ी अच्छी तरह से अपने हाथ में ले सकता है और उसमें कृषि सम्बन्धी अन्वेषण करने के लिये जो इम्पीरियल काउन्सिल है वह भी इस सम्बन्ध की माल छाटने और रखने की जो समस्याएँ हैं उन्हें हल करने में बड़ी सहायता दे सकती है। नोटों में जो लाभ होता है वह इस काम में लगाया जा सकता है। गोदामों का प्रबन्ध भी इसकी देख-रेख में हो सकता है। इससे उनकी रसीदे सवोच साख-पत्र का काम दे सकती हैं।

अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति ऋणदाता और महाजन लोग कर सकते हैं। वे अल्पकालीन ऋण के साथ-साथ मध्यकालीन ऋण भी आसानी से दे सकते हैं।

दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकताएँ

भारतीय कृषक बहुत से कामों के लिये दीर्घकालीन ऋण लेते हैं। इनकी अवधि २० वर्ष से लेकर ३० वर्ष तक हो सकती है। इनके उद्देश्य सहकारी समितियों और महाजनों के पुराने ऋण का भुगतान करना, ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाना, खेतों का सुधार करना, मकान बनवाना, कुये खुदवाना, सिंचाइ की नालियाँ बनाना और मशीन, इत्यादि खरीदना हो सकते हैं। सहकारी समितियों और महाजनों के ऋणों का भुगतान करने की आवश्यकता के विषय में पहले ही काफी कहा जा चुका है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने और खेतों के सुधार करने की भी बड़ी आवश्यकता है। कहीं कहीं पर जहाँ सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है वहाँ कुये खुदवाना भी बहुत आवश्यक हो गया है। कृषकों के लिये अच्छे मकान बनाने की भी बड़ी आवश्यकता है। फिर, कुछ खेत तो बहुत ही छोटे हैं। अतः, बगल की जमीन खरीदने की बहुत आवश्यकता है। कभी-कभी अपने परिवार के ही उन लोगों की जमीन खरीदने की आवश्यकता पड़ जाती है जो कृषि का उद्यम नहीं करना चाहते। इन्हें खरीद लेने से अपने खेत बड़े हो जाते हैं, अथवा छोटे होने से रुक जाते हैं, और दूसरे लोगों के उन्हें खरीद लेने से जो भगड़े का डर हो जाता है वह नहीं रहता। अन्तिम बात यह है कि खेतों के एकीकरण और सुधार के फलस्वरूप मशीन, इत्यादि के प्रयोग की भी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। इन सब कामों के लिये जो ऋण लिये जाते हैं उनका भुगतान जल्दी नहीं हो सकता। सब तो यह है कि

इनने उत्पन्न लाभ बहुत दिनों तक चलते हैं अथवा इनका भुगतान भी उसी अवधि के अन्दर होना चाहिये।

भूमि-बन्धक बैंक

दीर्घकालीन ऋण की प्राप्ति के लिये कोई सगठन न होने के कारण कृषकों को अपनी इस मांग की पूर्ति के लिये महाजनों का दर्याजा पटपटाना पड़ता है और उन्हें खड़ी ऊँची दर के हिसाब ने व्याज देना पड़ता है तथा अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे उनके ऊपर एक बड़ा भारी बोझ लदता चला जा रहा है। यह मुझसे तो पहले ही रक्खा जा चुका है कि पुर्णने ऋणों का निपटारा हो जाना चाहिये और उन्हें याकी घटाकर उनका भुगतान हो जाना चाहिये। महाजन कृषकों की सब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। उन्हें केवल अल्पकालीन तथा मध्यकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिये। दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भिन्न-भिन्न देशों में वहाँ की सरकारों ने भूमि मन्गारों स्थापित कर रखी हैं। इधर हमारे देश में भी कुछ भूमि-बन्धक बैंक स्थापित कर दिये गये हैं। किन्तु उनकी सन्ख्या बहुत कम है। मन् १९४७-४८ में यह २७७ थी। इसी वर्ष इनकी कुल कार्यशील पूँजी लगभग ५ करोड़ ६० की थी। इसमें से ३०८५ करोड़ ६० का ऋण दिया गया था। देश का विस्तार देखते हुये यह स्थिति बहुत ही असन्तोष-प्रद थी।

यह बैंक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं—

(अ) नितान्त सहकारी, (ब) व्यापारिक और (स) अर्ध सहकारी (Quasi co operative)। नितान्त सहकारी भूमि बन्धक बैंक ऋण लेनेवालों के ऐसे सगठन हैं जो व्याज देवनिहार रेहन-पत्रों के आधार पर द्रव्य एकत्रित करते हैं। व्यापारिक भूमि बन्धक बैंक की हिस्सों की पूँजी होती है और वह लाभ के लिये काम करता है तथा लाभ की बँटनी करता है। अर्ध सरकारी बैंक के ऋण लेनेवाले तथा ऋण न लेनेवाले दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं और वे एक बहुत बड़े क्षेत्र में काम करते हैं। इनकी हिस्सों की पूँजी होती है और दायित्व सीमित होता है।

भारतवर्ष में अधिकांश बैंक अर्ध सहकारी हैं। बात यह है कि वे कुछ ऋण न लेनेवाले व्यक्तियों को भी प्रारम्भिक पूँजी प्राप्त करने और उनके व्यापारिक गुणों का सगठन करने और प्रबन्ध करने की शक्ति पाने के उद्देश्य से अपने सदस्य बना लेते हैं।

मद्रास में सहकारी भूमि बन्धक बैंक सबसे अधिक हैं। सन् १९२५ के लगभग सीमित दायित्व के आधार पर हिस्सों की पूँजीवाले और प्राप्त पूँजी से अठगुना और दसगुना ऋण देने की शक्ति रखनेवाले दस बैंक वहाँ पर स्थापित किये गये थे। ऋण देने पर उनके पास जो भूमि रेहन के रूप में प्राप्त हो जाती थी उसी के आधार पर उन्हें ऋण-पत्र निकालने का अधिकार दे दिया गया था। सरकार ने भी कम-से-कम जनता द्वारा क्रय किये गये ऋण-पत्रों के बराबर और एक बैंक के अधिक-से-अधिक ५०,००० रु० के ऋण-पत्र तथा सारे प्रान्त के अधिक-से-अधिक २१ लाख के ऋण-पत्र खरीदने का वचन दिया था। किन्तु अधिकांश बैंक जनता में ऋण-पत्र बेचने में काफी सफल नहीं हुये। अतः, टाउन्सैण्ड कमेटी की सिफारिश के अनुसार एक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक की स्थापना की गई जो सब बैंकों को आर्थिक सहायता देने के लिये और एक की बचत दूसरे को देने लिये बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। ऋण-पत्र निकालने का काम यही करने लगा और इसमें इसे सफलता भी प्राप्त हुई। प्रान्तीय सरकार ने इन पर सद् देने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। उसने १५००० रु० की मुक्त पूँजी भी दी। साथ ही उसके अनुभवी काम करनेवाले भी इसे दिये गये प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंक अपने रेहन इसे दे देते हैं और यह उनके आवार पर ऋण-पत्र निकालता है। सन् १९४२-४३ में प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंकों की संख्या ११६ हो गई थी।

अन्य प्रान्तों में भी भूमि बन्धक हैं। सन् १९४०—४१ में पञ्जाब में १०, बम्बई में १८, बङ्गाल में १० और आसाम में ४ भूमि बन्धक बैंक थे। पञ्जाब के दो बैंक तो सारे जिले भर में काम करते थे और शेष केवल एक तहसील ही में काम करते थे। मद्रास को छोड़कर अन्य प्रान्तों में केन्द्रीय बैंक नहीं हैं। अतः, वहाँ प्रारम्भिक बैंक ही अपने ऋण-पत्र निकालते हैं। वस्तुतः, एक केन्द्रीय सङ्गठन की तो सभी जगह आवश्यकता है इन सहकारी भूमि बन्धक बैंकों के दृढ़ भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न हैं। साधारणतया तो उनके यहाँ की सरकारों ने ऋण-पत्रों के व्याज अथवा उनकी पूँजी अथवा दोनों का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है और कहीं कहीं तो कुछ को खरीदा भी है।

भूमि बन्धक बैंक और भी उपयोगी बनाये जा सकते हैं। प्रथम तो उनमें काम करने का दृढ़ एक सा किया जा सकता है। दूसरे, हर प्रान्त में एक केन्द्रीय बैंक होना आवश्यक है। जहाँ वह नहीं खुल सकते वहाँ बम्बई, बंगाल और पञ्जाब की ही तरह प्रान्तीय सहकारी बैंकों की ऋण-पत्र निकालने का और

पारस्मिक बँकों की सहायता करने का काम दिया जा सकता है। तीसरा, जहाँ-जहाँ इनकी कृषि की शिक्षा पर गौर है, तब तब पर हमें ध्यान देना प्रसारित करने पड़ेगा कि उन्हें भूमि बन्धक बनाना प्राधान्य से मान्यता दी जा सके। चौथे, प्राथमिक में उनकी सहायता के लिये सरकारी सहायता की आवश्यकता रहेगी, अतः वह प्राप्त होनी ही चाहिए। अन्तिम बात यह है कि निम्न देशों में उन्हें बड़े प्रसार से सहायता देना चाहिए --

(१) वह उन केन्द्रीय भूमि बन्धक में जो प्राधान्य महसूस करते हैं अतः घोषित कर दिये गये हैं प्राधान्यता पत्र पर सहायता प्राप्तियों के आधार पर ६० दिन के लिये ऋण देने के लिये तैयार है।

(२) यदि उनके अग्रणी पर से अनाज और उनकी पैतृक या दाखिल प्राधान्य सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है और तब तब में अनाजों में अधिकारों हैं तो वह उन्हें सरकारी भी होता है।

(३) वह उनके कार्यों का भी अध्ययन करता रहता है और समय पर उन्हें सहायता भी देता है। हमने उनकी सहायता करने के सम्बन्ध में कुछ विषयों में बात की है और उनके केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों और सहायक समितियों के प्राधान्य रजिस्ट्रारों के पास भेजा है। हम ऋण-पत्र विज्ञान के सम्बन्ध में बहुत अच्छे सुझाव हैं। किन्तु बहुत से ऐसे काम हैं जो निम्न देशों में कर सकता है --

(१) वह उनके ऋण-पत्र बेच सकता है। द्रव्य बाजार से बाजार सम्बन्धित रहने के कारण वह यह जानता है कि इन्हें निस्ताने का कौन सा समय सबसे उपयुक्त है और इन पर ध्यान की क्या जरूरत है। एक साधारण भूमि बन्धक बैंक को अपेक्षा इसकी शक्ति अधिक अपार है। जब वह ऋण-पत्र निकालेगा तो वह बहुत ही सुरक्षित समझे जायेगा। (२) इसका भूमि बन्धक बैंकों के ऊपर कुछ नियंत्रण भी होना चाहिये। उनके हिसाब-किताब का हमी को आडिट करवाना चाहिये। इसे उनके व्यवसाय के सम्बन्ध में सहायता देनी चाहिये और उनके ऋण देने में भी नियंत्रण रखना चाहिये। (३) अचल सम्पत्ति के मूल्य आँकने का काम भी बहुत कठिन है। अतः, यह इनके लिये भी अपने अनुभवों कर्मचारी दे सकता है।

भूमि बन्धक बैंक केवल कृषकों की ही सहायता कर सकते हैं। किन्तु यदि वे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य लोगों की सहायता करने का भी प्रश्न है और इनमें बड़े-बड़े भूमिशाली भी हैं। अभी तक तो वह केवल उपयोग के ही लिये बड़े

ऊँचे व्याज पर ऋण लेते रहे हैं। किन्तु वे उत्पादन सम्बन्धी कामों के लिये भी ऋण ले सकते हैं। उदाहरण के लिये भूमि में और कृषि के ढङ्ग में सुधार करने के लिये भी वह ऋण ले सकते हैं। अतः, ऐसी अवस्था में इन्हें कम व्याज पर ऋण मिलने का प्रबन्ध होना चाहिये। बारहवें अध्याय में बङ्गाल के लोन आफिसों के विषय में बताया जा चुका है। बैंकिंग सम्बन्धी अन्वेषण करने वाली बंगाल की और केन्द्रीय कमेटियों ने इनके ऊपर भी नियन्त्रण रखने के सुझाव रखे थे। आजकल थोड़ी-थोड़ी पूँजी की ऐसी बहुत सी समस्याएँ हैं। इनका एकीकरण और सुधार होना चाहिये। इसके लिये एक अच्छे विधान की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिये अन्य प्रान्तों में भी सम्मिलित पूँजीवाले भूमि बन्धक बैंक स्थापित किये जा सकते हैं।

रिजर्व बैंक का कृषि-साख-विभाग और कृषि की सहायता सम्बन्धी उसके कार्य

इस अध्याय में और पिछले अध्यायों में भी रिजर्व बैंक के कृषि-साख-विभाग का कई बार उल्लेख किया जा चुका है। अतः, हमें यहाँ पर उसके कार्यों का एक साथ अवलोकन कर लेना चाहिये। इस विभाग के तीन अङ्ग हैं :—कृषि साख, बैंकिंग और अङ्क तथा अन्वेषण (Statistical and Research) यहाँ पर हमें केवल कृषि-साख-अङ्ग का अध्ययन करना है, अन्य अंगों का अध्ययन हम आगे चलकर उपयुक्त स्थान में करेंगे।

कृषि-साख-अङ्ग के तीन कार्य हैं। प्रथम तो वह ग्रामीण अर्थ की और विशेषतः सहकारिता की समस्याओं का अध्ययन करता है और ग्रामीण ऋण से मुक्ति दिलवाने के सम्बन्ध में कानून बनवाता है। दूसरे, यह अपने कर्मचारियों द्वारा सहकारिता के आन्दोलन से निकटतम सम्बन्ध रखता है। इसके लिये यह सारे देश में इसका अध्ययन करते हैं। उनके सुझाव बराबर छूटते रहते हैं। तीसरे, यह अपनी सेवाएँ उन केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के लिये और सहकारी तथा अन्य बैंकों के लिये देता है जो कृषि-साख-सम्बन्धी समस्याओं पर इसकी राय लेना चाहते हैं।

रिजर्व बैंक विधान की ५५ (१) धारा के अनुसार रिजर्व बैंक पर जो दायित्व रक्खा गया था उसके सम्बन्ध में जो प्रारम्भिक और वैधानिक रिपोर्टें निकली हैं उनका उल्लेख भी किया जा चुका है। इन्हें और इंगडोजेनस बैंकों को रिजर्व बैंक से सम्बन्धित करने के लिये जो योजना तैयार की गई थी उसे

दीवार करने या अन्य उमरो कृषि-साधन-संग्रह को ही है। जोदिनर के बैंकिंग सुनियन की रिपोर्ट सहायरी ग्राम्य बैंक, वर्मा में महत्कारी ग्रान्दोलन की गतिविधि और भारतवर्ष में उसका उपयोग, पञ्जाब के होशियारपुर जिले की रुना नद-खोल के एक गाँव पञ्जाब में गहरागिना प्रभृति समग्र-जन भी इसी ने निराले हैं। भिन्न भिन्न प्रान्तों में ऋण समन्वी जो भिन्न-भिन्न विधान बने हैं वह भी इसकी दोनो रिपोर्टों ने दिये हुये सुझावों के आधार पर ही बने हैं। विलो पर जो स्टाम्प कर लगता है उसमें जो कमी की गई है वह भी इसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप है।

किन्तु यह विभाग धन-ल इतना ही नहीं कर सकता। भारतवर्ष में दिन-राज का विकास बहुत ही आवश्यक है। अभी तक बैंक ऋण और डिस्काउण्ट दोनों के लिये एक ही दर रखे हुये हैं। इस विभाग को उम्मे यह सुझाना चाहिये कि ऋण पर जो व्याज की दर टिस्काउण्ट की दर से कुछ ऊँची रखनी चाहिये। इसे उम्मे यह भी सुझाना चाहिये कि यह सराफों और अन्य नागरिक महाजनों को गाँवों के महाजनों की मुद्दती विलों के आधार पर आर्थिक सहायता करने के लिये प्रोत्साहित करे। ग्रामीण महाजन कृषकों को जो ऋण देते हैं उसमें भी उन्हीं उनके ठप-बिल करने के लिये कटौत जा सस्ता है। यह बिल फसल की मुद्दत के होने चाहिये क्योंकि उम्मे की प्रिकी ने तो वे लोग इनका भुगतान कर सक्ते हैं। इस बैंक को भी अन्य केन्द्रीय बैंकों की तरह द्रव्य का व्यापार करनेवाले सभी लोगों से आवश्यकता पड़ने पर सीधा काम करने का अधिकार मिला हुआ है। किन्तु इस विभाग को उम्मे यह समझाना पड़ेगा कि वह कम से कम कुछ दिनों तक तो यह काम साधारण रूप में भी करता रहे। बात यह है कि विलों का प्रयोग प्रोत्साहित करने के लिये इसे प्रारम्भ में गाँव में ऋण देनेवाली सहपात्रों से अपना सीधा सम्बन्ध रखना पड़ेगा। दूसरे, इसे मूल्याकन और आडिट के लिये अपने कर्मचारी रखने चाहिये। इससे सहकारी और भूमि-सन्धक बैंकों को बड़ा लाभ होगा। तीसरे, इसे रिजर्व बैंक विधान का इस प्रकार संशोधन करा लेना चाहिये कि उसके अन्तर्गत देशी रियासतों के सहकारी बैंक भी आ जायें। ग्राजकल ऐसा नहीं है। चौथे, इसे बंगाल के लोन आफिसों और मद्रास के निधि और चिट फण्ड की समस्याओं का भी अध्ययन करना चाहिये और उन्हें अधिक उपयोगी बनाने के लिये सुझाव रखने चाहिये। पाँचवें, इसे जैसा कि पहले भी बताया जा

किन्तु अब देशी रियासतों की स्थिति ही बदल रही है।

चुका है बैंक को इस बात की आवश्यकता समझानी चाहिये कि वह उन केन्द्रीय बैंकों से सीधे काम करे जिनका काम करने का स्तर काफी ऊँचा है। अन्तिम बात यह है कि इसे जिस प्रकार के गोदामों का पहले भी उल्लेख किया जा चुका है उसी प्रकार के गोदामों की स्थापना के लिये भी प्रयत्न करना चाहिये। इससे कृषि की आर्थिक समस्या सुलझाने में बड़ी सहायता प्राप्त होगी।

कृषि-सारख और सरकार

कृषि को सारख देने के लिये सरकार कृषि ऋण विधान और सुधार ऋण विधान के अन्तर्गत काम करती है। यह जो ऋण देती है वह प्रचलित भाषा में तकावी के नाम से विख्यात है। साधारणतया तो हर साल प्रत्येक प्रान्त में कुछ ही लाख रुपये बाँटे जाते हैं। हाँ, मुसीबत के समय यह करोड़ दो करोड़ तक पहुँच जाते हैं। तकावी अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों होती है। अल्पकालीन तकावी प्रायः बीज और मवेशियों के क्रय के लिये काम में आती है और उसी वर्ष की उपज से वसूल कर ली जाती है जिस वर्ष की उपज के लिये वह प्रयोग में लाई जाती है। इसके विपरीत दीर्घकालीन तकावी स्थायी सुधारों के लिये काम में लाई जाती है और कई वर्षों में किस्त से वापिस की जाती है। साधारणतया दीर्घकालीन तकावी नहीं बाँटी जाती। अल्पकालीन तकावी में कभी-कभी बीज दिये जाते हैं। जब मुसीबत पड़ती है तब तकावी बहुत अच्छी समझी जाती है किन्तु साधारणतया तो कृषक ऊँचा व्याज होने पर भी सरकार की अपेक्षा महाजनों से ऋण लेना अधिक अच्छा समझते हैं। निश्चय ही इसका एकमात्र कारण यह है कि तकावी के वितरण में अनेक दोष भरे पड़े हैं। तकावी देने के पहले बहुत सी पूछ-ताछ की जाती है जिसके लिये पटवारी और कानूनगो काम में लाये जाते हैं। उनकी सिफारिशें प्रायः सत्य नहीं होती। अतः, तकावी अपेक्षित लोगों को न मिलकर उन्हें प्राप्त हो जाती है जो लेते हैं। फिर, इन्हें बाँटने के केन्द्र बहुत कम होने के कारण कृषकों को बहुत समय तो राह चलने में ही खराब करना पड़ता है। उन्हें वहाँ पर पहुँचकर भी कई दिनों तक पड़ा रहना पड़ता है। इसमें सब में खर्च पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह समय पर बहुत कम मिल पाती है, और प्रत्येक व्यक्ति को जो रकम मिलती है वह उसकी आवश्यकता से बहुत कम होती है। उसे वसूल करने के तरीके भी बहुत सख्त होते हैं। अतः, यह सब बुराइयाँ इन्हें सहकारी समितियों द्वारा वितरण कराने से दूर की जा सकती हैं। वास्तव में सरकार यह काम बहुत अच्छी तरह से नहीं कर सकती।

इस प्रकार न कृषि-विभाग का प्रश्न मुक्तमाने के लिये एक ध्वनीय मार-पोरेशन के निर्माण के लिये एक दिन बतवाया है। इसके तान दो ताने पर यह प्रश्न बहुत कुछ मुक्त माना जायगा।

प्रश्न

(१) कृषि सम्बन्धी श्रम में क्या विशेष कठिनाइयाँ पड़ती हैं? इनकी रीति का वर्गीकरण कीजिये और प्रत्येक वर्ग को स्पष्ट तौर पर समझाइये।

(२) रिजर्व बैंक कृषि सम्बन्धी प्रश्न किन-किन तरीकों पर देता है? इसमें कौन कौन से मुख्य दोष हैं?

(३) इन्प्रीरियल बैंक आफ इण्डिया और दूसरे सम्मिलित पूँजी के बैंक कृषि को कैसे सहायता करत हैं, इसे समझाइये।

(४) सरकारी मारुत समिति ने आप क्या समझते हैं? दो तरह की जो समितियाँ होती हैं उनके भेद बताइये।

(५) इस देश में महाकारिता के विकास का इतिहास बताइये। इस समय उसकी क्या स्थिति है?

(६) सरकारी मारुत समितियों और बैंकों को उनकी पूँजी कहाँ से प्राप्त होती है? वे उसका किस प्रकार उपयोग करते हैं?

(७) इस देश में आजकल के महाकारिता आन्दोलन में कौन-कौन से दोष हैं? उन्हें दूर करने के लिये सुझाव रखिये।

(=) एक ऐसी योजना बनाइये कि जिससे महाजन और अन्धों तरह से कृषि की सहायता कर सके। इस सम्बन्ध में निपटारे की कार्य-प्रणाली और उनके लाभ के विषय में बताइये।

(६) भारतवर्ष में कृषि की प्रकृति की किस प्रकार आर्थिक सहायता मिलती है? उसे सुधारने के लिये अपने सुझाव रखिये।

(१०) समस्त भारतवर्ष में भूमि बन्धक बैंकों की स्थापना की आवश्यकता के विषय में अपनी सम्मति दीजिये। वे किस तरह से और अधिक उपयोगी बनाये जा सकने हैं?

(११) रिजर्व बैंक का कृषि सारुत विभाग कृषि के सम्बन्ध में कौन-कौन से कार्य करता है और वह देश को कैसे और अन्धों तरह से लाभ पहुँचा सकता है? इस सम्बन्ध में यह भी बताइये कि वह

यहाँ पर बिल बाजार स्थापित करने के लिये रिजर्व बैंक का ध्यान और किन-किन बातों की ओर आकर्षित करे ?

(१२) तकावी से आप क्या समझने हैं ? इसके वितरण में कौन-कौन से दोष हैं ? क्या इसे किसी तरह से सुधारा जा-सकता है ?

अध्याय १५

उद्योग सम्बन्धी आर्थिक व्यवस्था

उद्योग-धनों की उन्नति के लिये आर्थिक व्यवस्था का उतना ही महत्व है जितना किसी अन्य वस्तु का हो सकता है। अतः, इस सम्बन्ध में अभी तक जो कुछ भी नहीं किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि औद्योगीकरण की आवश्यकता यहाँ पर कभी समझी ही नहीं गई है। अंग्रेजों के समय में तो उनकी नीति ही यह रही थी कि देश में उद्योग धनों की उन्नति न हो। हाँ, दोनों युद्ध काल में अवश्य यह बात बहुत अखरी, अतः जो कुछ भी किया गया इन्हीं दोनों काल में किया गया। कांग्रेस का भी इस विषय में पहले कोई अधिक अच्छा रुख नहीं था। युद्ध के पहले कुछ समय तक इसने जर्मन प्रान्तों में शक्ति ग्रहण की थी तब जो कुछ भी किया था, वह कृषि की आर्थिक व्यवस्था ही के लिये किया था। फिर, हमारे नेतागण जब कभी भी धनों की बातचीत करते थे केवल घरेलू धनों की ही बातचीत करते थे, फैक्टरी के धनों की नहीं। इधर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार से बड़ी-बड़ी आशाएं थी किन्तु वह देश के विभाजन से उत्पन्न हुई समस्याओं के कारण कुछ भी नहीं कर सकी है। हाँ, योजनाएं बहुत सी हैं, अस्तु होता क्या है यह देखना है।

उद्योग-धनों की आर्थिक आवश्यकताएँ

प्रायः उद्योग-धनों की भी वही आर्थिक आवश्यकताएँ हैं जो कृषि की हैं, अर्थात् अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन आवश्यकताएँ कच्चे माल और स्टोर्स के क्रय के सम्बन्ध की, उपज के विक्रय के सम्बन्ध की और मजदूरी देने तथा दैनिक व्यय पूरा करने के सम्बन्ध की हैं। मध्यकालीन आवश्यकताएँ भी उपर्युक्त के सम्बन्ध की ही हो सकती हैं और

उनके लिये हुये अणु या भुगतान एक वर्ष में पौनःपुन्य के अन्तर्गत हो सकता है। दीर्घकालीन अणु प्रारम्भ में तो जमीन को पथ के लिये पार-
गाने की इमारत बनाने के लिये और मशीन इत्यादि लगाने के लिये तथा
बाद में विमान उड़ान के लिये लिया जाता है। इसे अमेजी में ब्याङ्क कैपि-
टल भी कहते हैं। हिन्दी में यह घिरी हुई पूँजी कह जा सकती है। दीर्घकालीन तथा प्रत्यक्षकालीन आवश्यकताओं अथवा घिरी हुई और पार्थिवी पूँजी के बीच का अनुपात धन्यो के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। उत्पादन जितना ही पेचीदा होता है उतनी अधिक दीर्घकालीन आवश्यकताओं अथवा घिरी हुई पूँजी की जरूरत पड़ती है। पाट, रुई, लोहे और स्टील, मिजली और मदान जैसे सगठित धन्यो में घिरी हुई पूँजी बहुत लगती है। प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक शीशे, चइरी और पिरोमता परिलू धन्यो में उसका उल्टा है। सदैव में यह उपलब्ध के मूल्य पर और उत्तरे लिये जो समय लगता है उस पर निर्भर है। इनके प्रलाप और भी पारण हो सकते हैं, जैसे फूँचा मान गरीबने और रत्ता हुआ मान बेचने के तरीके, मूल्य भुगतान के तरीके इत्यादि। ऐसा कि हम आगे चलकर देखेंगे जितनी ही अधिक घिरी हुई पूँजी भी आवश्यकता पड़ती है उतनी ही अधिक गर्भ हो दिखाने होती है।

भारतवर्ष में वर्तमान स्थिति

भारतवर्ष में वर्तमान स्थिति तनिक भी सतोपजनक नहीं है। अमेजी व्यापारिक बैंकों का तो यह चलन है कि वे दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करते ही नहीं। उनकी यहाँ इसके लिये अलग मत्थाये हैं जैसे सिक्योरिटियों की व्यवस्था करनेवाले ट्रस्ट और बैंकों के औद्योगिक विभाग की कम्पनियों। हमारे यहाँ पर अमेजी चलन के ही अनुसार औद्योगिक बैंकों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है इस सम्बन्ध में पहला प्रयत्न टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना से हुआ था। इसमें सदेह नहीं कि वह बहुत दिनों तक नहीं चल सका, किन्तु उसी तरह के कुछ अन्य बैंक भी चलाये गये थे जिनमें से इन्डस्ट्रियल बैंक आफ वेस्टर्न इण्डिया, कारनानी इंडस्ट्रियल बैंक, रायकूट इंडस्ट्रियल बैंक, शिमला बैंकिंग ऐण्ड इंडस्ट्रियल कम्पनी, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल बैंक इत्यादि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किन्तु इनमें विदेशी बैंकों की-सी प्रभावोत्पादन स्थापन शक्ति, ज्ञान की दृढ़ता और संगठन करने की योग्यता नहीं है। देश के विस्तृत क्षेत्र का ध्यान रखते हुये इनकी सख्या भी बहुत कम है। सन् १९१८ के औद्योगिक कमिशन ने भी

सरकारी सहायता प्राप्त और एक निश्चित ढङ्ग पर काम करनेवाले औद्योगिक बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी। किन्तु केवल सन् १९३६ ही में पहले-पहल संयुक्त प्रान्त की सरकार ने औद्योगिक अर्थ कमेटी की वे सिफारिशें मानकर जिनमें उसने बड़े और छोटे धन्वों की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन श्रृंखला देने के लिये एक इंडस्ट्रियल क्रेडिट बैंक की स्थापना करने के लिये सुझाव रक्खे थे इस तरह का एक बैंक स्थापित किया। इस बैंक ने सरकार से एक समझौता कर लिया है जिसके अनुसार १५ वर्ष तक सरकार ने इसे इसकी प्राप्त पूँजी का ४ प्रतिशत और अधिक से अधिक ६०,००० रु० वार्षिक इस-लिये देने का वायदा किया है कि यह प्रतिवर्ष ४ प्रतिशत लाभ की बँटनी कर सके। किन्तु इसका कार्य बहुत प्रशंनीय नहीं रहा है और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है क्योंकि सरकार को इतनी कम मदद के साथ कोई बैंक कुछ अधिक कर ही नहीं सकता। सन् १९३७ में बङ्गाल की सरकार ने वहाँ के छोटे-छोटे धन्वों की सहायता करने के लिये एक इंडस्ट्रियल क्रेडिट कारपोरेशन की स्थापना में हाथ बटाया था। सन् १९४० में यही बम्बई इकानमिक बोर्ड ने भी किया था। किन्तु इन्होंने भी कोई प्रशंसात्मक कार्य नहीं किया। अन्त में सन् १९४६ में एक अखिल भारतीय इंडस्ट्रियल फिनान्स कारपोरेशन की स्थापना के सम्बन्ध में एक बिल पेश हुआ था जो बाद में विधान बन गया। यह कारपोरेशन २ वर्षों से काम कर रहा है, और इसने बहुत से उद्योग धर्मों को सहायता भी दी है। किन्तु यह सहायता आवश्यकता से बहुत कम है। जहाँ तक इम्पोरियल बैंक और दूसरे व्यापारिक बैंकों का सम्बन्ध है, वे दीर्घकालीन श्रृंखला नहीं देते। वे जो कुछ सहायता करते हैं यह केवल मध्यकालीन तथा अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही होती है, और इनका अध्य-यन हम आगे चलकर करेंगे।

उपर्युक्त स्थितियों में यहाँ पर दीर्घकालीन पूँजी के लिये केवल तीन ही साधन बच रहते हैं। इनमें से प्रथम तो जो यहाँ के धर्मों के प्रारम्भ करने में भी बड़ा सहायक हुआ है, व्यक्तिगत है। इसमें एक परिवार के लोग अथवा उसके कुछ मित्र ही उसकी सहायता करते हैं। इसीसे मैनेजिङ्ग एजेन्सी प्रणाली का सूत्रपात हुआ, अथवा यह कहिये कि वह यही है। दूसरे, कुछ स्थानों में इन्हें जमा प्राप्त हो जाती है जो एक तरह से स्थायी ही है। अन्तिम में योजना-पत्र निकालकर जनता में हिस्से और श्रृंखला-पत्र बेचे जाते हैं।

मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली

यदि हम प्रथम को ले तो कुछ ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म हैं जिनके पास अच्छी पँजी है और जो कीटें काम चलाने के लिये प्राग्निष्ठ काम करते हैं, उसकी सराफना करते हैं, उन्हें प्राक्क मगाना देते हैं अथवा उद्योग टास्किंग ले लेते हैं और प्रायः टास्की व्यवस्था करते हैं। इनके लिये मैनेजिंग एजेंसी कहते हैं, मुख्य काम नीचे दिए हुए हैं :—

(१) ये हमनी सराफन का काम करते हैं। हममें तनिक भी मन्दोर् नहीं है कि एक बात निज पर किसी औद्योगिक इकाई की रक्षणता निर्भर है यह है कि उसमें सम्बन्ध की योजना बहुत अच्छी मनी हो और वह अच्छी व्यवस्था में प्रारम्भ की गई हो। इसके लिये संगठनकर्ता में एक बड़ी रचनात्मक योग्यता होनी चाहिये। भारतवर्ष में व्याधुनिष्ठ धर्म, प्रारम्भ करने का प्रेय प्रेरणा दो ही वर्ग के लोगों को है। एक तो प्रयोजन व्यापारी जो प्रयोजन व्यापारिक कोठियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये प्रायेण और दूसरे उद्योग के और फिर प्रबन्धदाता तथा अन्य धार्मा के रुई के व्यापारी। जो कुछ भी उद्योग है उसमें से अधिभाषण प्रेय प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में इन्हीं को है। इस सम्बन्ध में सर्वथा दाटा सन्त ऐन्ड कम्पनी, एग्लियु वुल ऐन्ड कम्पनी, कैटिलवेल् प्रलेन ऐन्ड कम्पनी, कर्गम सांड इन्फ्रामो ऐन्ड सन्स लिमिटेड, निरला ब्रदर्स लिमिटेड गा बालेड ऐन्ड कम्पनी, नौरोतली बाडिया ऐन्ड सन्स, सी० एन० बाडिया ऐन्ड कम्पनी, गर्ट ऐन्ड कम्पनी, मार्टिन एन्ड कम्पनी, इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से कुछ ने तो दर्जनों धर्म स्थापित कर दिखाया है।

(२) ये नये धर्मों के हिस्सों की विक्री की जमानत भी ले लेते हैं। विदेशों में यह काम एक विशेष प्रकार के जमानत लेनेवाले अथवा औद्योगिक और व्यापारिक बैंक करते हैं। इनकी अनुपस्थिति में यहाँ पर यह काम मैनेजिंग एजेंट करते हैं। हमारे यहाँ यदि इन लोगों ने बहुतनी कम्पनियों के हिस्से बेचने की जमानत अपने ऊपर न ली होती तो शायद वह काम प्रारम्भ ही नहीं कर सकती थीं। जब किसी नई कम्पनी के हिस्से निकाले जाते हैं और उनके विक्रेता की जमानत के किसी मैनेजिंग एजेंट की कोठी के ले लेने की बात जनता के सामने आती है तो लोगों का उस पर विश्वास हो जाता है और यदि इतने पर भी लोग सच हिस्से नहीं ले लेते तो मैनेजिंग एजेंट स्वयं वह सब हिस्से ले लेती है।

(३) ये इस सस्था के व्यवस्थापक का काम भी करते हैं और प्रायः इनके विस्तृत अनुभव से लाभ भी हुआ है। किन्तु अयोग्य व्यवस्था के भी उदाहरण मिलते हैं। पहले इनके अधिकार पिता से पुत्र को मिल जाते थे, अतः, कुछ दिनों में यह अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में पड़ जाते थे। यह बेचे अथवा हस्तान्तरित भी किये जा सकते थे। अब, यह दोनों बातें सन् १९३६ के कम्पनी सशोधन विधान के अनुसार मना कर दी गई हैं। जब कम्पनी की स्थायी पूँजी में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती तब इनके हिस्सेदारों की हानि कर देने का डर रहता है। अन्तिम बात यह है कि यह अपने मित्रों और सम्बन्धियों को नौकर रख लेते हैं और यदि वह कार्य कुशल नहीं होते तो कम्पनी की बड़ी हानि होती है।

(४) वैकिंग और फारवार् के बीच में ये एक प्रकार का सम्बन्ध भी स्थापित कर देते हैं। बात यह है कि सन् १९२० के इम्पोरियल बैंक विधान के अनुसार बैंक को किसी व्यक्ति अथवा साझे की फर्म की किसी झुण्डी पुर्जे पर ऋण देने के लिये उस समय तक मनाही है जिस समय तक कि उस पर कम से कम दो ऐसे व्यक्तियों अथवा फर्म के हस्ताक्षर न हों जिनके बीच में कोई साझा न हो। अतः, कम्पनी की ओर से जिस डायरेक्टर के हस्ताक्षर होते हैं उसके अतिरिक्त मैनेजिङ्ग एजेण्ट के भी हस्ताक्षर लेने की प्रथा चल पड़ी है। इससे कम्पनी के ऊपर तो उसके डायरेक्टर के हस्ताक्षर के कारण दायित्व रहता ही है किन्तु मैनेजिङ्ग एजेण्ट के ऊपर भी अलग से दायित्व हो जाता है। यद्यपि दूसरे बैंकों के लिये कोई ऐसा विधान नहीं है किन्तु वे भी इस बात में इम्पोरियल बैंक का ही अनुसरण करते हैं। अतः, मैनेजिङ्ग एजेण्ट को हर हालत में हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। जब माल के ऊपर ऋण लिया जाता है तब भी मैनेजिङ्ग एजेण्ट की जमानत के लिये जोर दिया जाता है।

(५) ये औद्योगिक सस्थाओं को अर्थ सम्बन्धी महायत्ना भी देते हैं। यहाँ पर हिस्से बहुत अधिक प्रचलित न होने के कारण प्रायः षष्ठों की पूँजी कम रहती है और उन्हें ऋण के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। हम यह तो देख ही चुके हैं कि बैंकों से ऋण लेने के लिये मैनेजिङ्ग एजेण्टों को अपने हस्ताक्षर देने पड़ते हैं। किन्तु इसके अतिरिक्त वे स्वयं भी ऋण देते हैं।

ऊपर यह बताया जा चुका है कि कभी-कभी इनकी व्यवस्था खराब हो जाती है। किन्तु सन् १९३६ के कम्पनी सशोधन विधान के अनुसार मैनेजिङ्ग एजेण्टों के उत्तराधिकार और उनके अधिकारों के विक्रय तथा हस्तांतरित होने की

मलाही हो जाने के कारण और ऐसा नहीं हो सकता । हाँ, इसमें एक अन्य दोष है । हमारे कारण चीजों और पदार्थों में सीधा सम्बन्ध नहीं है । यह प्रणाली होने के कारण के होते हुए के कारण प्रयोगिक उत्पत्ति कर गटे । एन्ट्रॉपी के उभय निर्भर रहने के कारण के कारण में उनका विचार पुनरा है और वह प्रौद्योगिक योक्तानों को और विशेष ध्यान नहीं देने । घड़े स्थापित करने के लिये उस परामर्श समझन भी नहीं है, और इसी कारण उन्हें लाक्षणिक तथा आर्थिक प्रयुक्तों नहीं प्राप्त हो पाते । घड़े का दौड़ान उभरे कार्यन्वित तथा लाभप्रद होने की सम्भावना, ज्यादा का निश्चय इन्हीं द्वारा हो सकता है । फिर इनके आर्थिक माधन गोमिन् करने के कारण के निश्चयात्मकता में लाभप्रद धन निरंतर नहीं चले जा सकते । अन्य तो यह है कि इनका लागत लगानेवाली जनता के उत्पत्ति नहीं हो सकता जितना इसी का होता है । अतः, ये एक के बाद दूसरी कम्पनी के हिस्से न तो बेच दी सकते हैं और न ऐसा करने को विमोचनी ही ले सकते हैं । यह प्रणाली नेजी में तो सकलता प्राप्त कर लेती है, किन्तु मजदूरी में ऐसा नहीं होता । उक्त अवस्था में जब मैनेजिङ्ग एजेंट को अपना कारण सुद्ध यत्न के लिये द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है तब उन्हें द्रव्य नहीं प्राप्त हो पाता । जैसा प्राय होता है यदि किसी मैनेजिङ्ग एजेंट का कोई एक कारण बुरी अवस्था में पड़ जाता है तब उनके अन्य कारणों में भी दिक्कत हो जाती है । सन् १९३६ के कम्पनी संशोधन विधान में इन मजदूरी की कुछ उचित कर दी गई है । उसके अनुसार किसी कम्पनी के रुपये किसी ऐसी दूसरी कम्पनी के हिस्से लेने में श्रवण उसे प्रयुक्त देने में नहीं प्रयोग में लाये जा सकते जो एक ही मैनेजिङ्ग एजेंट के प्रयत्न में हैं । हाँ, यदि कम्पनी लागत लगानेवाली कम्पनी है तो यह चक्रावट नहीं है । फिर, यदि परीक्षेवाली कम्पनी के मध्य डाइरेक्टर निर्विरोध ऐसा करने के लिये निश्चित कर देते हैं तब भी ऐसा हो सकता है । किन्तु यह स्पष्ट है कि एक कम्पनी की कमजोरी का दूसरे पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा । अन्तिम दोष यह है कि कम्पनियों में सती मिलों के हिस्सों में मैनेजिङ्ग एजेंटों के कारण सट्टेबाजी होती है । प्राय ऐसा होता है कि मैनेजिङ्ग एजेंट जिस कम्पनी को अपने हाथ में लेते हैं प्रारम्भ में उसके अधिकार हिस्से स्वयं खरीद लेते हैं । किन्तु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कम्पनी अपने हाथ में लेना चाहते हैं । अतः, जब वे यह देखते हैं कि मैनेजिङ्ग एजेंट की आर्थिक अवस्था कमजोर है तब वह हिस्सों की कीमत बढ़ाकर उन्हें स्वयं खरीद लेते हैं । सच्चे में यह है कि वे तनिक सी कमजोरी देखने के साथ ही उसका लाभ उठाने के लिये तैयार रहते हैं और इससे कम्पनियों की

सूती मिलों के हिस्सों में बड़ी सट्टेबाजी होती है। यदि मिले द्रव्य के लिये मैनेजिङ्ग एजेन्टों पर इतना निर्भर न होती तो उनके हिस्सों में इतनी सट्टेबाजी न होती और जनता की जो उमने हानि होनी है वह रुक जाती।

सन् १९३६ के भारतीय कम्पनी संशोधन विधान में मैनेजिङ्ग एजेन्सी प्रणाली के टोप दूर करने के लिये जो व्यवस्था कर दी गई है उसका थोड़ा-सा अध्ययन तो हम कर ही चुके हैं। इस सम्बन्ध की जो अन्य धाराये हैं वह निम्न आशय की हैं —

(१) विधान प्रारम्भ होने के बाद से कोई भी मैनेजिङ्ग एजेन्ट २० वर्ष से अधिक के लिये यह पद नहीं पा सकता।

(२) नियमावली में चाहे जो कुछ लिखा हो अथवा परस्पर चाहे जो कुछ तैदुआ है किन्तु यह विधान पास होने के पहले भी यदि कोई मैनेजिङ्ग एजेन्ट २० वर्ष से अधिक के लिये नियुक्त हुआ है तो यह विधान पास होने के बीस वर्ष के बाद वह मैनेजिङ्ग एजेन्ट नहीं रह सकता। हाँ, उसकी फिर से नियुक्ति हो सकती है। जब किमी मैनेजिङ्ग एजेन्ट का समय समाप्त होने को हो वो वह कम्पनी से वह सब रचर्च ले सकता है जो उसने उमके लिये किये हो।

(३) यदि किसी मैनेजिङ्ग एजेन्ट ने कम्पनी के सम्बन्ध में किसी ऐसे अपराध के लिये सजा पाई है जो भारतीय पिनल कोर्ड के अनुसार दणनीय है और जिसकी जमानत नहीं है तो कम्पनी उसे निकाल सकती है। यदि मैनेजिङ्ग एजेन्ट कोई फर्म अथवा कम्पनी है तो यदि उसके किसी साम्ती अथवा डाइरेक्टर ने उपर्युक्त अपराध किया है और वह ऐसा अपराध करने के ३० दिन के अन्दर नहीं निकाला जाता है तो वह अपराध उस फर्म अथवा कम्पनी का समझा जायगा।

(४) यदि कोई मैनेजिङ्ग एजेन्ट दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो वह भी अपने पद से च्युत कर दिया जायगा।

(५) कोई मैनेजिङ्ग एजेन्ट उस समय तक अपना अधिकार हस्तान्तरित नहीं कर सकता जब तक कम्पनी की साधारण सभा में वह पास न हो जाय।

(६) यदि मैनेजिङ्ग एजेन्ट ने अपना प्रतिफल अथवा उसका कोई अंश किसी को हस्तान्तरित कर दिया है तो उसके सम्बन्ध का दायित्व कम्पनी के ऊपर नहीं पड़ सकता।

(७) किसी कम्पनी की इतिक्रिया होने पर मैनेजिङ्ग एजेन्ट का प्रतिफल, इत्यादि वैसे तो कम्पनी से वसूल किया जा सकता है। किन्तु यदि यह इतिक्रिया मैनेजिङ्ग एजेन्ट की भूल से हुई है तो ऐसा नहीं किया जा सकता।

को मिलों के लिये पूँजी के सदृश प्रयोग में लाने में एक और दोष है और यह यह है कि इसमें हिस्सा और ऋण-पत्रों का जो लागत के अच्छे रूप हैं अधिक प्रचार नहीं हो पाता। तब, भिन्न जमा प्राप्त करके एक ऐसा काम कर रही है जो उनके योग्य नहीं है और यदि वह कभी इन्ट्रॉमिंग पर न दे सकेगी तो उसमें जनता का विश्वास हट जायगा और वह न तो हिस्से हो परीदेगी और न बैंक ही में जमा करेगी। चौथे, यह प्रणाली पुरानी है। व्यापक ज्ञान आधुनिक बैंक है जमा उन्हीं में होना चाहिये। अन्तिम बात यह है कि बैंकों के अधिक लोकप्रिय हो जाने पर शायद यह जमा बैंकों में चली जाय, प्रतः, इस पर मिलों को निर्भर नहीं रहना चाहिये।

हिस्से और ऋण-पत्र निकालना

जब हम हिस्से और ऋण-पत्र ले सकते हैं। सारी पूँजी एक ही दृष्टि में नहीं प्राप्त हो सकती। मिलों और लागत लगानेवाली जनता दोनों की दृष्टि से यह अच्छा है कि इसके लिये कई दृष्टि अपनाये जायें। यह सब दृष्टि ऐसे होने चाहिये कि जो भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों को पसन्द हो। प्रथम तो सदा हिस्से (Preference shares) होने हैं, दूसरे साधारण हिस्से (Ordinary shares) और तीसरे स्थापकों के हिस्से (Founders or Deferred shares) होते हैं। सदा हिस्से साम्के के सदा हिस्से (Participating Preference shares) अथवा वर्धमान सदा हिस्से (Cumulative Preference shares) अथवा साधारण सदा हिस्से (Noncumulative Preference shares) हो सकते हैं। कभी-कभी स्थायी पूँजी का कुछ अंश ऋण-पत्र निकालकर भी इकट्ठा किया जाता है। इससे एक तरफ तो लागत लगाने वालों को व्याज मिलता रहता है और दूसरी तरफ हिस्सेदारों को इन्हें अपने लाभ में से बहुत अधिक नहीं देना पड़ता। हिस्से और ऋण-पत्र निकालकर जनता से प्रत्यक्ष तौर पर पूँजी पाने के इस तरीके में हमारे यहाँ तथा अन्य देशों में भी यह दोष है कि कभी तो लोग अच्छी आशा होने के कारण इन्हें आसानी से ले लेते हैं और कभी इसके विपरीत स्थिति के कारण इन्हें नहीं लेते। इधर के इतिहास में सन् १६२०-२१ और सन् १८३५-३७ के वर्ष पहली तरह के और बीच के वर्ष दूसरी तरह के थे। इसी तरह से द्वितीय युद्ध काल में हिस्सों की अच्छी बिक्री थी किन्तु युद्धोत्तर काल में अब नहीं है। ध्यान तो यह था कि राष्ट्रीय सरकार आ जाने से स्थिति सुधरेगी।

किन्तु ऐसा हुआ नहीं। वैसे तो प्रधान मंत्री और उद्योग मंत्री बराबर देश के पूँजीपतियों में विश्वास उत्पन्न कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु मजदूरी की स्थिति इतनी बिगड़ गई है और साम्यवाद का भूत इतना परेशान कर रहा है कि यह विश्वास उत्पन्न हो ही नहीं पाता। इसके अतिरिक्त उद्योग-धन्धों को अन्य कठिनाइयों भी नज़र आ रही हैं, जिनमें नये-नये कर, रेल की कठिनाइयों, सर्वत्र फैली हुई घूम खोरी मुख्य हैं। फिर यहाँ पर ऐसे होशियार लागत लगानेवाली की भी कमी है, जो अच्छी और बुरी योजनाएँ समझ सकें। पश्चिमी देशों में भी लोगों को इस सम्बन्ध की उचित सलाह देने के लिये कुछ सस्यायें हैं। अतः, भारतवर्ष में तो जहाँ शिक्षा की बहुत कमी है इनका होना बहुत ही आवश्यक है।

इम्पीरियल बैंक और दूसरे व्यापारिक बैंकों द्वारा उद्योग-धन्धों की आर्थिक सहायता

हमें यह तो शायद ही जाना है कि भारतवर्ष में आधुनिक उद्योग धन्धों की स्थापना मैनेजिङ्ग एजेंटों के कारण ही हुई है। बहुत दिनों तक तो केवल यही उन्हें आर्थिक सहायता भी देते रहे। उनकी स्वयं की अच्छी आर्थिक स्थिति और साथ ही उनके मित्रों की सहायता के कारण वे बैंकों की सहायता बिना यह काम करते रहे। किन्तु धीरे-धीरे और विशेषकर जब प्रथम युद्ध के बाद मन्दी आई तब जनता का उन पर से विश्वास उठ गया और उन्हें अपने मित्रों की सहायता मिलनी बन्द हो गई। अतः, उन्हें बैंकों से सहायता लेने की आवश्यकता पड़ी। किन्तु इनके दायित्व ऐसे थे कि ये उन्हें दीर्घकालीन पूँजी नहीं दे सकते थे। हाँ, ये उनकी अल्पकालीन आवश्यकताएँ अवश्य पूरी कर सकते थे, किन्तु वह भी सब नहीं। अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिये भी कुछ ऐसी पूँजी होती है जो हमेशा चाहती है। अतः, वह स्थायी पूँजी का ही धारण कर लेती है। कच्चे माल का, तैयार और अर्ध तैयार माल का स्टॉक एक न्यूनतम सीमा से कम रह ही नहीं सकता। अतः, इन्हें रखने के लिये जितनी पूँजी की आवश्यकता पड़ती है वह स्थायी ही के सदृश्य होती है। अतः, धिरी हुई पूँजी के साथ-साथ इसका भी प्रबन्ध करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो बड़ी जोखिम का सामना करना पड़ता है। सच तो यह है कि इस देश में बहुत से लोग यह सोच लेते हैं कि उनकी सारी कार्यशील पूँजी उन्हें अल्पकालीन ऋण के रूप में मिल जाने से उनका काम चल जायगा

और इन्हीं से वे सफल नहीं होत। वैदिक यदि इसके लिये तैयार नहीं होते तो हम उन्हें दोष न देना चाहिये। हम तो यह देखना चाहिये कि वे कार्यशील पुरुषों का यह भाग देने के लिये तैयार हैं अथवा नहीं जा समाप्त आती जाती है और इस तरह से समय समय पर वैदिक की आवश्यकता नहीं जा सकती है। किन्तु ध्यान देने योग्य पर यह बात लगता है कि वैदिक, यह भी गला प्रसार ने और हम जान पर नहीं करत। एम्पिरियल वैदिक और दूसरे वैदिक या तो (१) उनके पास आनामिष और मिषी योग्य जमानत गिरवी कर्तों पर गगन ने या (२) श्रृण लेनेवाले के ऐसे प्रसू-पा जिसने ऊपर किसी अन्य धनी के भी धनतात्पर हो लेता श्रृण देने के लिये तैयार रहते हैं। किन्तु अतिशय भिलमालिक श्रृण नहीं लेत। बात यह है कि उनका अपना माल वैदिक ने गिरवी रखने से डरती मान मारी जाती है। अतः, वे इसे पसन्द नहीं करते। यह तो पहल ही बताया जा चुका है कि वे विजेयन अदमदासाद न जनता ने जमा प्राप्त करत हैं। अतः, उनका मान मारी जाने से इस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसने उनके देश न होने के दो कारण हैं। वैदिक ने श्रृण-पत्रों पर जो दो धनियों के धनतात्पर लेने की प्रथा चला रखी है हमने भनैजिन्ना। जेन्तो का रचना बहुत जरूरी हो गया है। वैदिक जो श्रृण देते हैं उनका रूप या तो नष्ट मात का या अधिविषय का होता है। वैदिक और श्रृण लेनेवाले दोनों यहाँ पसंद करत हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि श्रृण लेनेवालों को उनके दैनिक श्रृण पर व्याज देना पड़ता है। हा, हर हालत में, न्यूनतम रज्जम अमश्य देनी पड़ती है। दूसरे, वैदिक जब चाहे तब यह सुविधा बन्द कर सकता है। किन्तु भिल डिस्काउण्टिन्ग पर अधिक जोर देना चाहिये। हा, इसके लिये एक तो यहाँ पर लाज्जेन्स प्राप्त गोशम होने चाहिये और दूसरे जिलों के प्रयोग की आदत बढ़नी चाहिये। फिर, वैदिक श्रृण देत समय श्रृण लेनेवाले की वैयक्तिक जमानत का जरा भी खयाल नहीं करत और अतिरिक्त जमानत अवश्य माँगते हैं। वे अतिरिक्त जमानत न माँगें इसके लिये यह आश्चर्यक है कि भारतीय कम्पनी विधान की उस धारा में संशोधन कर दिया जाय जिसके अनुसार उन्हें अपनी बैलन्स शीट में जमानती और गैरजमानती श्रृण अलग-अलग दिखाने पड़ते हैं। फिर, यह इस तरह से भी हो सकता है कि वैदिक मिलवालों को अधिक जानकारी प्राप्त करें। अन्तिम, व्याज की दर भी बहुत ऊँची रहती है। छोटे छोटे वैदिक तो १२ से १८ प्रतिशत तक लेते हैं।

वैद्यों के उद्योग-धन्धों की अधिकाधिक सहायता करने के लिये सुझाव

इम्पीरियल बैंक और दूसरे बैंक, विशेषतः वह जिनकी स्थिति काफी अच्छी है, निम्न ढङ्ग से उद्योग-धन्धों की अधिकाधिक सहायता कर सकते हैं।

(१) उन्हें पुरानी और नई दोनों प्रकार की कंपनियों के निकाले हुये हिस्सों का बीमा कर देना चाहिये। इसके लिये उनके यहाँ ऐसे अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी जो प्रत्येक धन्धे के विषय में, जानते हों और उसके सम्बन्ध में अपनी सम्मति दे सकें। इससे ऐसी कंपनियाँ कम खुलेगी जिनका भविष्य अच्छा नहीं होगा। हमारे यहाँ जो बहुत-सी कंपनियाँ असफल हो गई हैं वह उपर्युक्त व्यवस्था होने पर शायद खुलती ही नहीं और इस तरह से उनमें लागत लगानेवालों की जो हानि हुई है वह भी अवश्य बच जाती।

(२) बैंक जिन हिस्सों का बीमा कर देंगे प्रायः उन सबको जनता ले ही लेगी। इससे उनका उन पर विश्वास जम जायगा। किन्तु यदि कुछ हिस्से बच रहेंगे तो बैंकों को उन्हें लेना पड़ेगा। किन्तु यह बहुत दिनों तक उनके पास नहीं रहेंगे, क्योंकि कंपनियों की उन्नति के साथ-साथ वह बिक जायेंगे।

(३) बैंकों के प्रतिनिधि सचालक मंडलों में रहकर उन्हें बराबर सहायता से काम करने के लिये कहते जायेंगे।

(४) उन्हें वैयक्तिक जमानतो पर अल्पकालीन ऋण देने चाहिये।

(५) लाइसेन्स प्राप्त गोदाम अवश्य स्थापित किए जाने चाहिये। इससे तैयार माल उनके यहाँ रखने की परिपाटी चल जायगी और उनके यहाँ की रसीदों के आधार पर बैंक ऋण दे सकेंगे।

(६) बिल भुनाने की प्रथा को उस पर कम व्याज लेकर प्रोत्साहित करना चाहिये। इससे बैंकों की वह लागत मिल जायगी जो उनके लिये बड़ी लाभप्रद है। उनके न होने के कारण इस समय वे अपनी लागत सरकारी साख-पत्रों में लगाते हैं। उनका यह काम नहीं है। उन्हें पहले उद्योग-धन्धों और व्यापार की सहायता करनी चाहिए और फिर सरकार के साख-पत्र खरीदने चाहिए। हाँ, इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इसपर वे ऐसा ही कर रहे हैं। यदि यह बात होती रहे तो बहुत ही अच्छा है।

सरकार का कर्तव्य

कुछ लोगों का यह मतना है कि भारतार्थ में व्यापारिक क्षेत्रों को इस समय को गिरावट है तबमें उन्हें उद्योग क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान देनी चाहिए। उनका कहना है कि उनके स्थान पर सरकार को प्राथमिकता देना चाहिए। इस मुद्दा को समाजवाद के प्रचार से बड़ा प्रोत्साहन मिला है। इस समय में गिरावट आती है सरकार ने जो कुछ किया है पर वो हमें देना ही चुके है। यहाँ पर हम अभी हाल ही में मुझे अतिरिक्त नागरिकों को श्रमयोग्य श्रम के कारपोरेशन के विधान, सामर्थ्य सम्माननाओं का विचार करना है अध्ययन करेंगे।

उपर्युक्त कारपोरेशन संयुक्त राज्य (U K) के एक ऐसे ही कारपोरेशन के सदस्य हैं। इसका मुख्य ध्येय नये धन को वितरित करने में है। इसमें स्वयं की पूँजी पाँच करोड़ है जो ५००० कम्पनियों के १०००० हिस्सों में विभाजित है जो पूर्णरूप में प्राप्त है। प्रायः चल कर यह पूँजी १० करोड़ २० हो जायगी। इस समय केन्द्रीय सरकार और रिजर्व बैंक ने दो-दो हजार हिस्से दिये हैं। स्वीकृत वेकों तथा बीमा कम्पनियों और स्वीकृत इन्वैस्टमेंट ट्रस्ट्स ने दार्दिन्दाई हजार हिस्से और सहकारी बैंकों ने एक हजार हिस्से लिये हैं। सरकार ने पूँजी वापिस करने और दार्दि प्रतिशत वार्षिक प्रतिफल (प्राय कर शुना) देने का दायित्व लिया है। लाभ की वृद्धि अधिक से अधिक ५ प्रतिशत हो सकती है और वह भी पाँच करोड़ का सुगन्धित कोष बन जाने के बाद होगी। कारपोरेशन के लाभ पर न तो आय कर लगता है और न अतिरिक्त कर। कारपोरेशन के व्यापार संचालकों में से तीन केन्द्रीय सरकार द्वारा, दो रिजर्व बैंक द्वारा, दो स्वीकृत बैंकों द्वारा और दो बीमा कम्पनियों और इन्वैस्टमेंट ट्रस्ट्स द्वारा और दो सहकारी बैंकों द्वारा नियुक्त होते हैं। कारपोरेशन के चार दफ्तर हैं, एक मम्बई में, दूसरा कलकत्ते में, तीसरा दिल्ली में और चौथा मद्रास में। कारपोरेशन कम्पनी पूँजी जमा प्राप्त करके और नाण्ड तथा श्रृण-पन निकाल करके भी बढ़ा सकता है। आस्तिक दायित्व (Contingent Liabilities) मिलाकर सारे श्रृण की रकम उसकी प्राप्त पूँजी के चतुर्गुण से अधिक नहीं हो सकती दस वर्ष के पहले जो जमा का रकम देय न होगी वह दस करोड़ रुपये से अधिक की नहीं हो सकती।

कारपोरेशन उद्योग-धन को अधिक से अधिक २५ वर्षों के अन्दर वापिस होने वाले दीर्घकालीन श्रृण देता है। यह कम्पनियों के हिस्से और

ऋण-पत्र निकालने का बीमा भी करता है, किन्तु इसे इन्हे अधिक से अधिक सात वर्षों में जनता के हाथ बेच देना पड़ता है। यदि कोई कम्पनी बाजार में ऋण लेना चाहती है तो यह कुछ निश्चित कमीशन लेकर उसकी जमानत भी कर लेता है। यदि किसी कम्पनी को विदेशी कर्न्सी चाहिये तो इसे अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank of Reconstruction and Development) से ऋण लेने का अधिकार दे दिया गया है। इसे किसी कम्पनी से दूसरे ऋणदाताओं की अपेक्षा अपने ऋण की बसली का प्रथम अधिकार भी प्राप्त है।

यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष की सरकार ने अब तक जो कुछ भी यहाँ के औद्योगीकरण के लिये किया है उसमें इस कारपोरेशन की स्थापना सबसे प्रधान है। इसके काम धीरे-धीरे बढ़ जायेंगे और यह अनुभव प्राप्त करने के बाद अवश्य ही और कार्य कुशल हो जायगा। प्रारम्भ में इसे कुछ अधिक सावधान रहना पड़ रहा है। हाँ, बाद में यह कुछ ढील दे सकेगा। यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसी के ऊपर इसकी जमा की प्रति और ऋण-पत्रों की बिक्री निर्भर है।

भविष्य में यदि प्रान्तीय कारपोरेशन न स्थापित किये गये तो यह कारपोरेशन अपने ढङ्ग का अकेला कारपोरेशन रहेगा। अतः, इसके यहाँ माँग भी अधिक रहेगी। किन्तु यदि प्रान्तीय कारपोरेशन भी स्थापित हो गये तो इसे उनके बीच में सहयोग उत्पन्न कराना पड़ेगा। प्रान्तीय कारपोरेशनों के बन जाने पर इसे उन उद्योग-धन्वों की सहायता करनी पड़ेगी जो अन्तर्प्रान्तीय हैं और अखिल भारतीय महत्त्व के हैं जैसे स्टील के, इञ्जीनियरिंग के और भारी रसायनों के, इत्यादि।

यद्यपि केन्द्रीय और छ. प्रान्तीय बैंकिंग की कमेटियों ने सरकार से सहायता प्राप्त प्रान्तीय औद्योगिक कारपोरेशन की स्थापना के सुझाव रखे थे, किन्तु उनके विरुद्ध जो राय है उसके कारण उनकी स्थापना असम्भव है। प्रथम तो इनका बोझ बढ़ानेवाली जनता पर पड़ेगा। अतः, वह इसके पक्ष में नहीं हो सकती। दूसरे, यदि सरकार के पास इनके लिये धन है तो वह उसे अन्य उपयोगी कामों में लगा सकती है। तीसरे, यह भी अच्छा नहीं मालूम पड़ता कि सरकार से सहायता प्राप्त संस्था अन्य ऐसी ही संस्थाओं से प्रतियोगिता करें। किन्तु ये उन धन्वों की सहायता करने के लिये आवश्यक ही स्थापित किये जा सकते हैं जो जनता के लिये अत्यन्त ही उपयोगी हैं। इन्हें सहायता देनेवाली संस्थाओं की आवश्यकता कुछ प्रान्तों में अच्छी तरह से प्रतीत हो चुकी है।

मराम न मिलनी सम्भवितो। शक्तिदायक योजनाओं और विचारों के लाने की सरकार ने सराफा दी है। किन्तु उनके लिए जिस दूँ ने काम किया गया था वह ठीक नहीं था। पञ्जाब में जो दूँ बनाया था। इन उनका ने उपयोगी मानों में। अविशेष बात है और वह यह कि इनमें जो तागा-तागा गतों है उनका फलितन मिलने में कुछ समय लगा है। अब, अर्थनियों को आर्थिक सहायता देने में जो साधारण दूँ है वह मान लिये उपयुक्त नहीं है। किन्तु यदि कोई विशेष दूँ अपनाया जाय तो उनके द्वारा आर्थिक मिल सकता है। अतः, अर्थ-सावधानता के अर्थों में आर्थिक सहायता देने के लिये सरकारी औद्योगिक कारपोरेशन की सहायता करना बहुत ही आवश्यक है। ब्रिटिश इन्डिया की सहायता के लिये वे विदेशी अनुभवों आये हैं जो भी यही समझी थी। हाँ, पहले प्रत्यक्ष उनके विषय में कुछ मानेंद्र या किन्तु बाद में यह ठीक हो गया था। केन्द्रीय और उन दूँ इन्डिया की गय के विरुद्ध जो प्रान्तीय औद्योगिक कारपोरेशन की सहायता के पक्ष में थी वे एक अखिल भारतवर्षीय कारपोरेशन की सहायता करना चाहते थे। श्री सुन्दर तथा कुछ अन्य लोगों की भी यही समझ थी। मत्व तो यह है कि दोनों पक्ष की दलीलें बड़ी मार्गमिथ थी। प्रान्तीय कारपोरेशनों के पक्ष में निम्न दलीलें थी -

(१) उद्योग-पन्नों का विषय प्रान्तीय विषय है। अतः, इनके सम्बन्ध की सभी योजनाएँ प्रान्तीय सरकारों के नियन्त्रण में होनी चाहिये।

(२) केन्द्रीय सरकार के एक अखिल भारतवर्षीय कारपोरेशन की सहायता करने के प्रयत्न में प्रान्तीय सरकारों का अपने-अपने प्रान्तीय कारपोरेशन की सहायता करना अधिक आसान होगा।

(३) अखिल भारतवर्षीय कारपोरेशन के लिये पूँजी इकट्ठा करना कठिन होगा किन्तु प्रान्तीय कारपोरेशनों के लिये यही आसान होगा। बात यह है कि वह अपने प्रातः लोगों की प्रान्तीयता का लाभ उठा सके।

(४) प्रान्तीय कारपोरेशन अपने-अपने प्रातों के उद्योग-धर्मों की आवश्यकताएँ प्रासानी से समझ सके। किन्तु एक अखिल भारतीय कारपोरेशन को सारे देश के उद्योग-धर्मों की आवश्यकताएँ समझना कुछ कठिन-सा हो जायगा।

(५) प्रान्तीय कारपोरेशनों के पास उनके अपने-अपने प्रातों के धर्म जानने-वाले अनुभव रह सकते हैं, किन्तु एक अखिल भारतीय कारपोरेशन के पास सारे देश के धर्म समझनेवाले अनुभव नहीं रह सकते।

जो लोग एक अखिल भारतीय कारपोरेशन की स्थापना के पक्ष में थे उनकी निम्न दलीले थीं :—

(१) प्रांतीय सरकारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह प्रान्तीय कारपोरेशन स्थापित कर सकें। हाँ, केन्द्रीय सरकार की ऐसी स्थिति अवश्य है कि वह एक अखिल भारतीय कारपोरेशन स्थापित कर ले। यदि वह सारा बोझ स्वयं न भी उठा सकेगा तो उसे प्रान्तीय सरकारों की सहायता मिल सकती है।

(२) एक अखिल भारतीय कारपोरेशन के हिस्से और ऋण-पत्रों पर जनता का कहीं अधिक विश्वास होगा और विशेषतः जब केन्द्रीय सरकार द्वारा ही वह संस्थापित होगा। फिर, उसके निकाले हुए साख-पत्र विदेशों में भी बिक सकेंगे। इसके अतिरिक्त उसके संचालक भी देश के किसी हिस्से से भी लिये जा सकेंगे। अतः, उसमें योग्य व्यक्तियों के रहने की विशेष सम्भावना होगी।

(३) एक अखिल भारतीय कारपोरेशन की रकम भिन्न-भिन्न प्रकार के धर्मों में लगी होगी। अतः, संकट के समय उसे कुछ कम जोखिम रहेगी।

(४) अखिल भारतीय कारपोरेशन की केन्द्रीय सरकार में भी आवाज होगी। अतः वह यहाँ के धर्मों को उचित सहायता भी दिलवा सकेगा।

(५) अखिल भारतीय कारपोरेशन के कर्मचारी भी समस्त भारतवर्ष में से लिये जा सकेंगे। अतः, वह बहुत अनुभवी होंगे। फिर, एक प्रांत के धर्मों को दूसरे प्रांत के धर्मों के अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव का भी लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसे विदेशियों की सेवाएँ भी प्राप्त हो सकेंगी।

(६) इस देश में इस समय बहुत से काम किये जा सकते हैं किन्तु उन सबका एक साथ लेना तो असम्भव होगा। अतः, उनमें से जो अधिक लाभप्रद हैं वही पहले लिये जायेंगे।

किन्तु जैसा पहले भी कहा जा चुका है, अतः मे इस विषय पर सब की एक ही सम्मति हो गई और वह यह थी कि प्रत्येक प्रांत में उसका एक प्रांतीय कारपोरेशन होना चाहिये और उनके सबके ऊपर एक अखिल भारतीय कारपोरेशन भी होना चाहिये जो उनमें सहयोग स्थापित करेगा और अखिल भारतीय प्रश्न सुलझावेगा। इसके भिन्न काम बतलाये गये थे —

(१) प्रान्तीय कारपोरेशनों को उनके हिस्से और ऋण-पत्र बेचने में सहायता देना।

(२) प्रान्तीय कारपोरेशनों में सहयोग उत्पन्न कराना और वह बात देखना कि वह उपयोगी धर्म ही सर्वप्रथम लेते हैं।

() प्राचीन कारपोरेशनों के पद दर्शन के लिये कुछ साधारण सिद्धान्त ।

(४) केन्द्रीय सरकार ने इनके लिये सुविधाएँ मिलाना ।

औद्योगिक बैंकों की संस्थापना के लिये आवश्यक सुझाव

जैसा पहले ही कहा जा चुका है देश के देशजलों को देशों लिये इस समय औद्योगिक बैंकों की जो जरूरत है वह बहुत ही कम है । हा, यदि औद्योगिक बैंक तथा अन्य ध्वापारिक बैंक वह तरीके को अपना कर देश के औद्योगिकों की सहायता करने लग जायें तथा प्रचलित भारतीय औद्योगिक प्रयत्न कायमों-ज्ञान और प्राचीन औद्योगिक कारपोरेशन उपयोग धनवाँ क लाभ दृष्टि में अपने लिये काम करें तो अन्य प्रायोगिक बैंकों की संस्थापना की आवश्यकता नहीं रहनी । किन्तु यदि वह नहीं होता है तो प्रायोगिक बैंकों की संस्थापना बहुत ही आवश्यक होगी । हाँ, ऐसी स्थिति में उनके काम बनी होंगे जो इंपोरियल बैंक और अन्य बैंकों के लिए बताने जा चुके हैं । जो औद्योगिक बैंक इस समय स्थित हैं उनके भी इन्ही दृष्टि पर काम करना चाहिये । इस सम्बन्ध में ब्रिटेन में एक कान्ट्री बैंक थी जिसने इस विषय में निम्न सुझाव रखे थे :—

(१) वर्तमान औद्योगिक कम्पनियों को अर्थ सम्बन्धी मन्त्रणा देना ।

(२) स्थायी पूँजी की प्राप्ति, उसकी रकम और उसके भेदों के विषय में मन्त्रणा देना ।

(३) कम्पनियों के सात-पत्रों को निकालने पर उनका बीमा करना और तब तक वह जनता द्वारा न लिये जा सकें तब तक के लिये उन्हें अल्पकालीन ऋण देना ।

(४) देश तथा विदेशों में कम्पनियों के दीर्घकालीन कन्ट्राक्ट पूरा करने के लिये आर्थिक सहायता देना और स्थित कम्पनियों की उन्नति के लिये भी ऐसा ही करना ।

(५) नये धनधों के लिये कम्पनियों स्थापित करना ।

(६) एकीकरण के सम्बन्ध में मध्यस्थ का काम करना और अर्थ सम्बन्धी मन्त्रणा देना तथा प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रीय सत्याश्रो से समझौता करना, और

(७) सब तरह के आर्थिक सहायता के काम करना ।

ऐसे बैंकों की पूँजी आवश्यक ही दीर्घकालीन ऋण के रूप में होगी न कि अल्पकालीन ऋण के रूप में । इन्हें व्यापारिक बैंकों ने प्रतियोगिता नहीं करने देना चाहिये ।

औद्योगिक कम्पनियों के हिस्सों और ऋण-पत्रों को जनता में प्रचलित करने के लिये सुझाव

(१) प्रथम महायुद्ध के बाद के तेजी के काल में यहाँ पर बहुत-सी औद्योगिक कंपनियाँ खुली थीं। किन्तु बाद में मंदी के समय जब वह फेल हो गईं तब जनता का इन पर से विश्वास उठ गया। अतः, लोग अपनी बचत पड़ोसियों को उधार देने, अचल सम्पत्ति में, सरकारी, म्युनिसिपैलिटियों के और बन्दरगाहों के ट्रस्ट के साख-पत्रों में लगाना अधिक पसंद करते हैं। यदि वर्तमान बैंक और जिनकी स्थापना के लिये सुझाव रखे गये हैं वह नई कंपनियों की योजनायें पहले ही से समझ लिया करें तो उनके फेल होने की सम्भावना कम हो जाय और इससे जनता में उनके प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाय।

(२) केन्द्रीय कमेटी के सामने जिन लोगों ने साक्षी दी थी उनमें से कुछ ने यह भी कहा था कि यहाँ पर लोगों का यहाँ के घन्धों पर इसलिये भी विश्वास नहीं है कि वह जानते हैं कि यहाँ की विदेशी सरकार उनकी तनिक भी सहायता न करेगी और इसी कारण वह सफल न हो सकेंगे। हमारी अपनी सरकार अब यह डर दूर कर सकती है। किन्तु इधर साम्यवाद का जो डर फैल गया है उससे अवश्य कुछ अड़चन पड़ेगी।

(३) हमारे यहाँ ऐसी संस्थायें भी नहीं के बराबर हैं जो यहाँ के लोगों को और विशेषकर ग्रामीण लोगों को इस प्रकार के लागत से अवगत करें। वास्तव में इस सम्बन्ध के विज्ञापन की यहाँ पर बड़ी आवश्यकता है।

(४) प्रायः लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं और पूँजी एकत्रित करने के आधुनिक तरीके नहीं जानते। इनके विषय की शिक्षा देने की यहाँ पर बहुत ही आवश्यकता है।

(५) साख-पत्रों के क्रय और विक्रय में सुविधा देने के लिये यहाँ पर कोई भी संस्था नहीं है और यदि है तो वह शहरों में ही है। अतः, इनके विश्वास-पात्र दलालों की बड़ी आवश्यकता है।

(६) कुछ साख-पत्रों के हस्तांतर करने में बड़ा ऊँचा स्टाम्प लगाना पड़ता है। इसे भी घटा देना चाहिये।

(७) जिन लोगों के पास थोड़ी सख्या के हिस्से होते हैं उन्हें कभी-कभी उनके बेचने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। अतः, थोड़ी सख्या में भी हिस्से बेचने का प्रबन्ध होना चाहिये।

(८) हमारे यहाँ प्रौद्योगिक कर्मियों के भाग्य-दुर्गति की जमानत पर स्तब्ध बने के लिए जोर्टी भी अपना पैसा नहीं लेती। हमारे यहाँ भी सरकारों का ध्यान भी बसन्त उन्नीसवीं शताब्दी में, उनमें प्रचुर प्रगति पारितोष हो रहा है।

(९) '११' वर्ष की उमिर में उनमें प्रचुर उमिर में हमारे यहाँ भी छात्रों का ध्यान बसन्त उन्नीसवीं शताब्दी में से प्रचुर रूप से होता है। अतः इससे उद्योग-धंधों में प्रगति भी मिलती है। सरकारों की धनशक्ति का प्रयोग पर ध्यान लेना चाहिये।

घरेलू धन्यों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में सुझाव

घरेलू धन्यों को भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है; और यह तब तक सहायता देने के लिए ही निर्भर रहते हैं। धान्य में उनकी राशियाँ और उनकी नितर-नितर होने की अवस्था के कारण धान्य का तथा अन्य धान्य-धान्य की व्यवस्था करनेवाले लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो ही नहीं सकता। किन्तु इसी कारणों से यह सहायता के लिये बहुत ही उपयुक्त है। भिन्न-भिन्न कमेटियों ने यही राय भी दी है। ऐसे भवे जर्मनी और जापान में सरकारों की सहायता ने ही फल-फूल रहे हैं। अतः, कोई कारण नहीं कि भारतवर्ष में ऐसा न हो सके। किन्तु इसके लिये सहायता का सिद्धांत केवल धान्य के लिये ही नहीं सीमित रखना चाहिये। जैसे कृषि में देने ही यहाँ पर भी उसे दूसरे कामों के लिये भी प्रयोग में लाना चाहिये। हाथ में काम करने वालों और दूसरे छोटे पैमाने पर काम करनेवालों को बड़े पैमाने पर काम करनेवालों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिये सहायता की जो आवश्यकता है यह स्वयं सिद्ध है।

यद्यपि सन् १९०४ के सहायता विधान में ही नागरिक समितियों की स्थापना की व्यवस्था कर दी गई थी तो भी ये बहुत दिनों तक नहीं खुलीं। ऐसा कि पहले भी कहा जा चुका है यह अपनी रचना और कार्य-प्रणाली में कृषक समितियों से बहुत ही भिन्न हैं। नागरिक सहायता समितियों भी अनेक प्रकार की होती हैं, उदाहरण के लिये कर्मचारियों की समितियाँ, उपभोक्ताओं के सहायता स्टोर, हाथ से काम करनेवाले तथा जुलाहों की समितियाँ, दुग्ध इकाइयों और समितियाँ, श्रमा समितियाँ, विद्यार्थी स्टोर्स इत्यादि। किन्तु यहाँ पर हमारा विशेष प्रयोजन तो हाथ से काम करनेवालों और जुलाहों की समितियों से ही है। जुलाहों पर इसलिये विशेष जोर दिया गया है कि यहाँ

पर कपड़े का काम बहुत महत्वपूर्ण है। मन् १९३६-४० के अंत में बम्बई में गुलाबों की ३० समितियाँ थीं, मद्रास में यही १९१ थीं और पंजाब में ३५० से अधिक थी। अन्य प्रान्तों के यह अङ्क नहीं मिलते किन्तु प्रत्येक में ऐसी कुछ समितियाँ हैं अवश्य। इनके अतिरिक्त अन्य कारीगरों की समितियाँ भी हैं जिनके सम्बन्ध के भी अंक प्राप्त नहीं हैं। इधर युद्धकाल में घरेलू धन्धों को जो प्रोत्साहन मिला था उसके कारण भी अब इनकी संख्या और बढ़ गई होगी। इसमें मन्देह नहीं कि आजकल की समितियाँ केवल माप की ही व्यवस्था करती हैं, किन्तु वे कच्चे माल के क्रय में और तैयार माल के विक्रय में तथा औजारों इत्यादि के रखने में बड़ी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इस समय महाजन लोग यह सब काम करते हैं। प्रायः सभी शहरों में कुछ घरेलू धन्धे हैं और कुछ महाजन व्यापारी जो ऊँचे दामों पर कच्चे माल देते हैं और नीचे दामों पर तैयार माल लेते हैं। यदि यह काम सहकारी समितियाँ अपने हाथ में ले लें तो अवश्य ही इन कारीगरों की दशा बहुत कुछ सुधर जाय। अतः, जितनी ही जल्दी यह किया जाय उतना ही अच्छा है।

उद्योग एक प्रान्तीय विषय है। अतः, प्रत्येक प्रान्तीय सरकार अपने सीमित क्षेत्र में इसकी उन्नति के लिये जो कुछ कर सकती थी वह करती आ रही है। इनमें से कुछ तो भिन्न भिन्न धन्धों की आर्थिक सहायता करती हैं और इनमें छोटे पैमाने के धन्धे विशेष तौर पर महत्वपूर्ण हैं। यह सहायता थोड़े व्याज पर ऋण देने के रूप में अथवा निराये और खरीद पर मशीनरी की पूर्ति के रूप में अथवा भूमि अथवा अन्य कोई सरकारी सम्पत्ति देने के रूप में होती है। ये प्रोपेगण्डा करती हैं, धन्धों का क्रय क्रियात्मक रूप में दिखाती हैं और उनके सम्बन्ध की मन्त्रणा देती हैं, किन्तु जो रिपोर्टें निकली हैं उनसे स्पष्ट है कि इन्हें अभी कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। ये जो आर्थिक सहायता देती हैं वह बहुत कम होती है और प्रायः वास्तविक काम करनेवालों को नहीं मिलती। शायद यही कारण है कि उसमें से बहुत-सा बट्टे खाते ढालना पड़ता है। सत्य तो यह है कि सरकार यह काम कर ही नहीं सकती। यदि इसे यह काम करना है तो इसे यह सहकारी समितियाँ अथवा प्रान्तीय सहकारी बैंकों द्वारा करना चाहिये। प्रान्तीय सहकारी बैंक घरेलू धन्धे के लिये बहुत ही सिद्ध हो सकते हैं। फिर, सरकार यदि धन्धों की सहायता ही करना चाहती है तो वह चाहे बड़े पैमाने के हो अथवा छोटे के, अन्य तरीकों से सहायता कर सकती है। उसकी क्रय नीति भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कर सकती है।

उपसंहार

राज्य में औद्योगिक शक्ति के विषय में कोई ज्ञान निश्चित रूप से कभी हो नहीं जा सकता देश में अनुपम उन्नति की आवश्यकता है। शुद्ध औद्योगिक बैंकों के और खुलाप की जरूरत है। उन्हें बैंके सुझाव अब तक अनुभव प्राप्त करने दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार काम करना चाहिये। इम्पीरियल बैंक और दूसरे बैंक बैंकों को उद्योग-धन्यो को आर्थिक सहायता देनी ही चाहिए। फिर, यदि आवश्यकता हो तो जनता के लिए जो उद्योगी धन्य हैं उनको कम्पेन्सली सहायता की आर्थिक सहायता करने के लिए प्रांतीय कारपोरेशन भी खुलने चाहिये। जहाँ तक सरकार के उद्योग-धन्यो के प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता देने का प्रश्न है, वहाँ तक यदि यह सहायता अन्य तरह की हो तो भी यथेष्ट है। औद्योगिक बैंक, व्यापारिक बैंक तथा प्रांतीय कारपोरेशन किसी उद्योग-धन्यो को केवल उसके प्रारम्भ से उनके एक स्तर तक पहुँच जाने के काल में ही सहायक हो सकते हैं। अन्त में तो इसका योग्य जनता को ही उठाना पड़ेगा। अतः, उनके लिए हिस्से और अणु-पत्र अधिक प्रचलित करने चाहिए। हाँ, इम्पीरियल बैंक और दूसरे व्यापारिक बैंकों को इनकी अल्पकालीन आवश्यकताओं की तो आवश्यक ही पूर्ति करनी पड़ेगी। घरेलू धन्यो की सहायता के लिये तो सहायक समितियों की ही प्रोत्साहन देना पड़ेगा। यथार्थ में उनकी मुक्ति तो इन्हीं के हाथ में है।

प्रश्न

(१) उद्योग-धन्यो की किस प्रकार की आर्थिक आवश्यकताएँ होती हैं ? प्रत्येक का तुलनात्मक महत्व बताइये और यह भी स्पष्ट कीजिये कि उनका पारस्परिक अनुपात किन बातों पर निर्भर रहता है ?

(२) इस देश में उद्योग-धन्यो की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की कौन पूर्ति करता है ? उनके गुण और दोष बताइये। भारतीय औद्योगिक बैंकिंग ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

(३) इम्पीरियल बैंक तथा दूसरे व्यापारिक बैंक किस तरह से यहाँ के उद्योग-धन्यो की आर्थिक सहायता करते हैं ? इन्हें और अधिक उपयोगी बनाने के लिये अपने सुझाव रखिये।

(४) प्रांतीय औद्योगिक कारपोरेशनों की स्थापना के विषय में आपकी क्या सम्मति है ? इस सम्बन्ध में जो एक आखिल भारतीय

समस्या स्थापित हो चुकी है उसके उपयोगो के सबन्ध में भी प्रकाश डालिये ।

(५) औद्योगिक कम्पनियों के हिस्से और ऋण-पत्र जनता से अधिक चालू करने के लिये क्या करना चाहिये ? अभी तक वे यहाँ पर क्यों अधिक प्रिय नहीं हो सके हैं ।

(६) आपकी राय में यहाँ के औद्योगिक बैंको को किस प्रकार काम करना चाहिये ? क्या आप उनकी स्थापना के पक्ष में हैं ?

(७) मैनेज्ड एजेण्टो को शक्ति सीमित करने के सबन्ध में सन् १९३६ के भारतीय कम्पनी विधान में क्या-क्या बातें रखी गई हैं ? आपकी राय में क्या उनकी यहाँ पर अब भी आवश्यकता है ?

(८) घरेलू धन्धो को आर्थिक सहायता देने की यहाँ पर जो व्यवस्था है उसमें क्या दोष है ? उसे सुधारने के लिये अपने सुझाव रखिये ।

(९) भिन्न-भिन्न प्रांतीय सरकारें अपने यहाँ के उद्योग-धन्धो को आर्थिक सहायता देने के लिये क्या करती हैं ? आपकी सम्मति में वे उनके लिये और किस प्रकार अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं ?

(१०) भारतीय उद्योग-धन्धो को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये एक अच्छी योजना रखिये । इस सबन्ध में अब तक जो कुछ किया गया है उसका भी वर्णन कीजिये ।

अध्याय १६

व्यापारिक बैंक

वैसे तो इस शीर्षक में सम्मिलित पँजी के भारतीय बैंक, इम्पीरियल बैंक तथा विदेशी बैंक सभी आ जाते हैं, क्योंकि वे सभी अन्य कामों के साथ-साथ व्यापारिक बैंकिंग के काम भी करते हैं, किन्तु सुविधा के लिये हम यहाँ पर केवल सम्मिलित पँजी के भारतीय बैंक ही लेंगे । इम्पीरियल बैंक तथा विदेशी बैंकों के विषय में हम अगले दो अध्यायों में पृथक् पृथक् अध्ययन करेंगे । हाँ, इसमें वर्तमान औद्योगिक बैंक भी आ जायेंगे । सच तो यह है कि वह जो कुछ औद्योगिक बैंकिंग के काम करते हैं, उनके साथ-साथ व्या-

रह गई। फिर, सरकार ने भी ऐसे नियम बना दिये कि बैंक बहुत सी चीजों की गिरवी पर ऋण नहीं दे सकते थे। किन्तु इनकी जमा बराबर बढ़ती गई। अन्य तो यह है कि नास्तर्प ने बैंकिंग की उन्नति सदा से इसी कारण ही हुई है। युद्ध की व्यवस्था के लिये द्रव देश का केन्द्र बनाने का महत्त्व इस बार युद्ध प्रारम्भ होने ही प्रतीत होन लगा था। इसमें सरकार को अपनी और अन्य निर-राष्ट्रों का और से यहाँ पर फाँको व्यय करना पड़ा। अतः फल यह हुआ कि यहाँ की बचतों विशेषतः नोट कम्पनी बढ़ती गई और इसी कारण बैंकों के जमा भी बढ़ते गये। निस्तन्देह कम्पनियों युद्ध के विपरीत परिस्थितियों के कारण जमा घटी भी, किन्तु उससे बैंक को केवल अपनी स्थिति दृढ़ करने में सहायता ही मिली।

जब से युद्ध प्रारम्भ हुआ तबसे सितम्बर १९३६ से, तब से सदन्य बैंकों की सख्या बढ़ती ही गई। सन् १९४७ के अन्त तक में हम ने कम इस अवधि के बीच में ४२ नये सदस्य बैंक बन चुके थे। निस्तन्देह, इसमें से कुछ तो यहाँ पहले ही से काम कर रहे थे। किन्तु कुछ नये बैंक भी थे। इस बीच में कुछ गैरसदस्य बैंक भी स्थापित हुये।

सदन्य बैंकों और गैरसदन्य बैंकों की शारायें भी बढ़ती गई। जब नवम्बर १९३६ में सत्र सदस्य बैंकों के १२५० दफ्तर थे, मार्च, सन् १९४७ में यह ३५७६ थे। उपर्युक्त में से यदि इम्पीरियल बैंक को ४४७ और विनिमय बैंकों की ८० सरया घटा भी दें तो भी यह काफी थी। यह भी बहुत सन्तोष की बात है कि इनमें से कुछ दफ्तर तो उन स्थानों में खुले जिनमें पहले कोई बैंक था ही नहीं। दफ्तरों की सरया में यह वृद्धि नये बैंकों की स्थापना और उनके तथा पहले से ही स्थापित बैंक के सदस्य बैंक धन जाने के कारण और पुराने सदस्य बैंकों के अपने दफ्तरों की सरया बढ़ा लेने के कारण हुई। नवम्बर, सन् १९४६ में एक ऐसा प्रतिबन्ध पास किया गया कि जिसके कारण रिजर्व बैंक की आज्ञा बिना नये दफ्तर खुलने बन्द हो जाये।

इस अवधि के बीच में सदस्य तथा गैरसदन्य बैंकों की जमा भी बढ़ती गई। सदस्य बैंकों की जमा सन् १९३६ के सितम्बर में २३६ ६० करोड़ रु० थी और गैरसदन्य बैंकों की उसी दिसम्बर में १५ ६६ करोड़ रु० थी। इसकी तुलना में इन दोनों की जमा क्रमशः १०८७ ६१ (अप्रैल, १९४८ में) और ७८ ४४ (सन् १९४६ के अन्त में) करोड़ रु० थी। निस्तन्देह, प्रथममे इम्पीरियल बैंक और विनिमय बैंकों की जमा भी सम्मिलित है। किन्तु यह किसी संकोच के बिना कहा जा सकता है कि जो भी वृद्धि हुई थी वह सभी के यहाँ हुई थी।

बैंकों ने अपनी पूँजी भी बढ़ा ली वढे बैंकों ने तो ऐसा जमा में पूँजी का अनुपात बढ़ाने की दृष्टि से किया। ऐसा करने में उन्होंने बाजार की आर्थिक स्थिति से लाभ उठाया और अपने हिस्से आर्थिक मूल्य पर बेचकर अपना सुरक्षित कोप भी बढ़ा लिया। छोटे बैंकों ने ऐसा सदस्य बैंक बनने के लिये किया। सन् १९३६ के विधान की (६) धारा के अनुसार उनका सुरक्षित कोप भी बढ़ता रहा। इस तरह से पूँजी बढ़ाने की इस प्रथा पर भी एतराज किये गये। जमा में पूँजी का जो अनुपात होना चाहिये उसके विषय में कोई निश्चित तो बात है नहीं। कम अनुपात होने से किसी प्रकार की शका नहीं करनी चाहिये। अधिक पूँजी होने से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करना पड़ता है। अतः, इससे अनुचित लागत लगाने का भी डर रहता है। नये बैंकों में भारत बैंक की पूँजी (२ करोड़ रु० से भी अधिक) पाचों बड़े बैंकों की पूँजी से अधिक थी, हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक की (११ करोड़ रु०) केवल सेंट्रल बैंक को छोड़कर अन्य सब से बड़े बैंकों की पूँजी से अधिक और यूनाइटेड कामर्शियल बैंक की सेंट्रल बैंक और बैंक आफ इण्डिया को छोड़कर अन्य सब बैंकों की पूँजी से अधिक थी।

इनका नकद कोप भी बढ़ता रहा। युद्ध के पहले यह प्रायः जमा का १० प्रतिशत रहता था, किन्तु युद्ध काल में यही प्रायः १५ प्रतिशत रहता था।

जहाँ तक स्थायी और अस्थायी जमा के अनुपात का प्रश्न था प्रथम का अनुपात युद्ध पूर्व काल में भी घटता जा रहा था। वस, यह युद्ध काल में भी घटता गया। सन् १९३६ से जव से इनका पता चलता है, ये क्रमशः निम्नांकित हैं :—१९३६ में ४३४ ५४ ६ : १९३८ में ४३२ ५४ ८ १९४० में ४२९ ५७ १ १९४२ में २३ ८ ७६ २ १९४४ में २७ ०१ ७२ ६६ और १९४६ में २८ ४ ७१ ६। १९४६ में युद्ध समाप्त हो चुका था, अतः, तब से यह कुछ बढ़ने लगा है, किन्तु भविष्य में यह पहले की तरह तो हो ही नहीं सकता। युद्ध काल में लोग माग पर देय जमा इसलिये रखते थे कि जव चाहें तब उन्हें निकाल ले। साथ ही जैसे जैसे स्थायी जमा पर व्याज की दर घटती जाती है वैसे-वैसे ही उसका अनुपात भी घटता जाता है। यही कारण है कि भविष्य में भी उसके बढ़ने की विशेष सम्भावना नहीं है। बैंकिंग की दृष्टि से यह अच्छा भी है।

युद्ध-काल में बैंकों की अधिकतर लागत सरकार की साखपत्रों में थी। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है उद्योग-धंधों और व्यापार में लागत लगाने का अवसर तो कम ही होता जा रहा था। अतः यह स्वभाविक ही था।

उनके कार्य

ये बेहद गाय ४८ टनी काम करते हैं जो व्यापारिक प्रेरणा से काम चालिये।
 वे मराठी भाषा में, गाए जाते हैं, यथा के जाते हैं, फलस्वरूप प्रकृत के जाते
 हैं। व्यापारिक इच्छाओं का प्रभाव करते हैं। साथ ही वे व्यापार और उद्योग-
 भाषा में भी कुछ व्यापारिक सहायता प्रदान करते हैं, प्रदातृ नकद का प्रका-
 शित होता है, जिस और दूसरी डिम्बाउट करते हैं, द्रव्य को एक न्याय
 के दूसरे न्यायों में पहुँचाने की सुविधा देते हैं और जनता की अन्य दूसरे
 प्रकार के सेवाएं करते हैं। कृषि और उद्योग-धन्यो का व्यापार सहायता देने
 में उनका जो कार्य होता है उसके विषय में तो हम पहले ही अध्ययन का
 लक्ष्य हैं। आगे के - व्यापार में हम यह भी जानते हैं कि यह प्रत्यक्ष रूप से
 व्यापार को फायदा प्रदान करते हैं। हाँ, यहाँ पर यह कह देना भी
 आवश्यक नहीं है कि यह इस सम्बन्ध में भी कोई सन्तोषजनक काम
 नहीं करते। इसके अलावा जो कुछ भी गाय है, वह माता की वन्दनाओं ने उनके
 १. उन्हाकाशो वर आर मल्लिका ने वन्दनाओं तक पहुँचाने के सम्बन्ध में है।
 इतर भी यह उतना काम नहीं करते जितना इन्हें करना चाहिये। वास्तव में
 है कि विदेशी देशों ने अपनी शाखाएँ देश के भीतरी शहरों में भी जोल गयी
 हैं अथवा कुछ भारतीय देशों के मार्फत अपना काम करवा लेते हैं। अतः,
 इन्हें पूरा काम नहीं मिलता। इसके फलस्वरूप इनकी अधिकांश लागत सर-
 कारी साख्तियों से होती है। वास्तव में सरकारी साख्तियों यही पुरीदते
 ही हैं। यह बात निश्चित, इम्पीरियल बैंक तथा बड़े-बड़े बैंकों के लिये तो
 निश्चित ही सत्य है। यह अच्छा नहीं है। इन्हें और बिल डिस्काउंटिंग
 में अधिक लागत लगानी चाहिये।

जहाँ तक जमा पर व्याज का प्रश्न है, सेन्ट्रल बैंक को छोड़कर अन्य किसी
 बैंक के इन व्याज के दमों के विषय में कोई लेख नहीं मिलता। हाँ,
 प्रायः सभी बैंकों की स्थायी जमा एक साथ लेने पर उनके व्याज की श्रुति
 दर का पता चल जाता है। जहाँ तक हो चालू खाते में व्याज नहीं देना
 चाहिये और यही प्रथा अन्य देशों में है भी। लोग चालू खातों में तो जमा
 केवल अपनी सुविधा के विचार से करते हैं न कि वह उसे लाभप्रद लागत
 समझते हैं। अतः, व्याज की दर का इन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता।
 फिर, व्याज देने का प्रभाव बैंकों के ऊपर भी अच्छा नहीं पड़ता। इससे

उन्हे आय करने की आवश्यकता अनुभव होती है, अतः, वह मन्दी में लागत लगाने का प्रयत्न करते हैं जिसका फल अच्छा नहीं होता। इससे वे फेल भी हो जाते हैं। किन्तु यहाँ, विदेशी बैंक भी चालू खातों पर व्याज देते हैं। इम्पीरियल बैंक अवश्य ऐसा नहीं करता। सम्मिलित पूँजीवाले बैंकों में से कुछ बड़े बैंकों को छोड़कर और उन्होंने इधर ही ऐसा करना शुरू किया है। अन्य सभी कुछ न कुछ व्याज देते ही हैं। यह केवल इसलिये ही है कि वह जानते हैं कि वह इम्पीरियल बैंक और विदेशी बैंकों तथा बड़े बड़े बैंकों के सामने व्याज दिये बिना नहीं ठहर सकते। सन् १९३१ तक सेंट्रल बैंक माँग पर देय जमा पर औसतन २.०१ से २.५३ प्रतिशत तक व्याज देता था। इधर उसने यह बन्द कर दिया है। किन्तु स्थायी खातों पर व्याज देना एक दूसरी ही बात है। इस पर व्याज की दर के अनुसार इसकी रकम भी घटती-बढ़ती रहती है। स्थायी और अस्थायी खातों के बीच में भी यह बात है कि स्थायी खातों पर बहुत थोड़ी दर से व्याज मिलने पर लोग स्थायी खातों में जमा न करके अस्थायी खातों में ही जमा रखना अधिक पसन्द करते हैं। इधर हमारे यहाँ यही हुआ है, स्थायी जमा अस्थायी हो गई है।

स्थायी और चालू खातों में दोनों में इधर जो व्याज की दर कम हो गई है उसमें कुछ लोग यह कह रहे हैं कि कहीं लागत के स्रोत शुष्क न पड़ जायें, किन्तु ऐसा है नहीं। व्यापारिक बैंकों को तो अस्थायी खातों ही रखने चाहिये। अतः, उनके व्याज देने का प्रश्न तो नहीं उठता। उन्हें तो अपने ग्राहकों का अन्य सुविधाएँ देकर इन्हें खींचना चाहिये। हाँ, स्थायी खातों की तो बात ही दूसरी है। उन पर व्याज देकर ही उन्हें खींचना चाहिये। जो हो, यह काम व्यापारिक बैंकों का नहीं है। अतः, यदि व्यापारिक बैंकों की स्थायी जमा कम होती जा रही है तो कोई बुरा नहीं है। इसके लिये तो अन्य समस्याएँ होनी चाहिये। हमारे यहाँ डाकखाने, बीमा कंपनियाँ इत्यादि हैं। भूमि बन्धक बैंक भी इन्हें खींच सकते हैं। अन्तिम, औद्योगिक बैंकों को इनसे लाभ उठाना चाहिये।

जहाँ तक व्यापार की आर्थिक सहायता करने का प्रश्न है, वह कई रूप में की जाती है। दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋण में से चूँकि आजकल अल्पकालीन ऋण पर व्याज की दर बहुत अच्छी है और व्यापारिक बैंक के दायित्व अल्पकालीन होते हैं, इसलिये वह अल्पकालीन ऋण देना पसन्द करते

है। इनमें से यदि हम मुख्य ऋण (Loans & Advances) परसे लें, तो ऐसा कि द्वितीय युद्धकाल शीर्षक में दी हुई वारिन्ता में पता चलता है जन्म की तुलना में यह इतने प्रतिक नहीं है जितने कुछ अन्य देशों में पाये जाते हैं। ऋण व्यापार, कृषि, उद्योग-धर्मों इत्यादि सभी को मिल जाते हैं। मनु हम यह नहीं कह सकते हैं कि इनका वास्तविक प्रामाण्य क्या है। तो भी यह अवश्य है कि यद्यपि ऋण में सार किया जाय तो सभी तरह सुविधायें दी जा सकती हैं।

हमें इन ऋणों के रूप भी मालूम कर लेने चाहिये। देश में ऋण का चलन बहुत कम है। अतः, इनमें से प्रतिकाश ऋण नकदी के रूप में दिये जाते हैं। इनके लिये जो जमानतें दी जाती हैं वह प्रायः जमीन, मकान, जेवर, सोना चाँदी तथा सम्पत्ती माप-पतों की होती है। ऐसे ऋण देने के लिये अथवा कम तैयार होते हैं। जहाँ तक सम्भव होता है, वह ऋण लेने वाले ने अपने यहाँ एक चालू खाता खोल लेने को मजबूर है और उसमें आवश्यकता की प्राप्ति दे देते हैं। प्रायः वार्षिक पर ३० प्रतिशत की मुद्राश रक्खी जाती है। इन सब में नकद माप के रूप का ऋण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ऋण और प्रादक दोनों की दृष्टि से लाभप्रद है। बैंक तो ऐसा कि हम जानते हैं, जब चाहे तब और ऋण देना शक्त कर सकते हैं यात्रा प्रादक उनके ऊपर जितनी दैनिक बाकी निकलती है उसी पर व्याज देते हैं। इन ऋण की जमानत प्रायः व्यापार सम्पत्ती माल की होती है जो या तो व्यापारी के गोदाम में ही छोड़ दिया जाता है या बैंक के गोदाम में रख दिया जाता है। प्रथम स्थिति में तो बैंक उसमें अपना ताला लगा लेता है और उस पर अपने नाम की तस्वी भी टाँग देता है और द्वितीय स्थिति में वह गोदाम भाड़ा भी लेता है। दोनों स्थितियों में बीमा भी करवा लिया जाता है, अतः, उसका खर्च भी ऋण लेने वाले के ऊपर ही पड़ता है। वैयक्तिक जमानतों पर बहुत कम ऋण दिये जाते हैं और वह यदि दिये भी जाते हैं तो उनके लिये दो धनियों के हस्ताक्षर के प्रमाण लिखवा लिये जाते हैं।

यदि हम डिस्काउन्टिंग लें तो यह कहा जा सकता है कि यह बहुत चालू नहीं है। सदस्य बैंकों ने मार्च सन् १९४७ में केवल २२.०७ करोड़ रुपये के बिल डिस्काउन्ट कर रखे थे। यह उनके कुल दायित्व (८६३.७४ करोड़ रुपये) की तुलना में कुछ भी नहीं है। बैंकों की दृष्टि से इसके बहुत अच्छे होने के कारण इसे बढ़ाने के लिये प्रयत्न करने चाहिये। नये बैंकों में से

डिस्काउण्ट बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और भारत बैंक यह व्यवसाय काफी करते हैं।

अन्त में हम सरकारी तथा अन्य प्रकार के साख-पत्रों में लगी हुई लागत ले सकते हैं। इस सम्बन्ध के जो अंक हैं उनमें एक बैंक की दूसरे बैंकों में जो स्थायी जमा रहती है वह भी सम्मिलित है। अतः, इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। किन्तु इससे कुछ अनुमान तो लग ही सकता है। लागत की वसूली की दृष्टि से 'सरकारी साख पत्रों में लागत लगाना बहुत ही अच्छा है, किन्तु व्यापार की सहायता करने की दृष्टि से तो यह उतना अच्छा नहीं है। अतः, इन बैंकों को इसमें से रुपया खींच कर व्यापारियों को देना चाहिये।

सम्मिलित पूँजी के भारतीय बैंक रुपया एक स्थान से दूसरे स्थानों को मेजने में भी बहुत सहायता पहुँचाते हैं तथा अन्य प्रकार से भी लोगों की सेवाये करते हैं। जहाँ तक रुपया एक स्थान से दूसरे स्थानों को मेजने का सम्बन्ध है, इसके लिये वे बड़ी ऊँची दर चार्ज करते हैं और विशेषतः उन स्थानों में जहाँ उनकी प्रतियोगिता करने वाले दूसरे बैंक नहीं हैं। अतः, उन्हें इसे कम करना चाहिये।

इनका भविष्य

इस देश में सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों का भविष्य बहुत कुछ यहाँ की सरकार की नीति पर निर्धारित रहेगा। वैसे तो लोग स्वतन्त्रता मिल जाने पर भी बहुत उत्साहित नहीं हैं। साम्प्रदायिक और खाद्य स्थिति बिगड़ जाने के कारण भविष्य पर उनका कोई विश्वास नहीं रह गया है। फिर, लड़ाई चाहे न हो किन्तु उसके बादल तो घिरे ही हुए हैं। छोटी-मोटी लड़ाइयाँ चल भी रही हैं। घूसखोरी और अनाचार, व्यापार तथा औद्योगीकरण के रास्ते में खड़े हैं। प्रथम युद्ध के बाद बहुत से बैंक फेल हुये थे, अतः, इसी बात की आशंका इस बार भी थी। जब-जब कोई बैंक अथवा बैंक की शाख किसी नये स्थान में खुलती थी तब-तब वहाँ के लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखते थे। यहाँ पर अब तक बैंकिंग की प्रत्येक तेजी के बाद उसकी मन्दी आयी है। किन्तु शायद इस बार ऐसा न हो। प्रथम तो जितने बैंक युद्धकाल में स्थापित हुये हैं उनमें से अधिकांश यथेष्ट पूँजी के साथ हुये हैं। हमें ज्ञात है कि

सन् १९२६ के भारतीय कानूनी विधान की (४) भाग के अनुसार कि इस धुमाल में पहले भी था जो सुना है, छोटे की एक दर्शों पर ५०,००० २० के कम पूँजी के मातहत ही नहीं हो सकता था। फिर भारतीय मुद्रा संहिता नियमों के (६४ अ) नियम के अनुसार १० पर सन् १९२२ को जो बैंकों निगमालय के नियन्त्रण का आधिकार निगमना गया था उसने बैंकों कम्पनियों का व्यवसाय रोक दी था जिसका कुछ के उद चढ़ने की ओर सम्मानना नग्न दिखलाई पड़ती थी। अतः, हमने बैंकों भी नये २० के मुद्रा के पालन सरकार की आज्ञा प्राप्त करने के लिये कुछ प्रापेदन-पत्र देना पड़ता था और सम्भार उस पर निर्धारित की सम्मति लेकर अपनी अनुमति देती थी। अब नये विधान के अनुसार रिजर्व बैंक को अनुमति बिना कोई बैंक मुद्रा ही नहीं करना। दूसरे, पहले के स्थापित बैंकों ने भी अपनी पूँजी इत्यादि बढ़ाकर अपनी स्थिति दृढ़ कर ली है। तीसरे, अब रिजर्व बैंक का भी सहायक हाथ है। सदस्य बैंकों के साथ तो इसका सम्बन्ध इधर मुद्रा-माल में और भी दृढ़ हो गया है। यहाँ की बैंकिंग प्रणाली के ऊपर नगरपाल का भी नियन्त्रण अब बहुत बढ़ गया है। चौथे, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, बैंकों में नफ़ा स्थिति भी अच्छी हो गई है। ये रिजर्व बैंक के पास जो कोष रखते हैं वह प्रायः न्यूनतम से अधिक रहता है। गैरसदस्य बैंकों की भी नफ़ा स्थिति बहुत अच्छी है। अन्तिम बात यह है कि अब एन्ट्रें उन्नति करने का बहुत अवसर मिलेगा, विशेषतः इसलिये कि भविष्य में हमारी राष्ट्रीय सरकार इनकी सहायता ही करेगी न कि इनके रास्ते में जैसा कि विदेशी नगरपाल पहले किया करती थी, रोड़े अटकायेगी।

ऊपर जो बातें कही गई हैं उनका प्रमाण भी अभी हाल ही में मिल चुका है। नवम्बर, सन् १९४६ में बंगाल के कुछ छोटे-छोटे बैंकों के कठिनाई में पड़ जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। किन्तु सनी के लिये यह बहुत ही प्रशंसा की बात हुई कि सकट टल गया और उससे किसी की भी हानि नहीं हुई। प्रथम तो रिजर्व बैंक ने और भारत सरकार ने व्यर्थ की बातों का सख्तन किया। दूसरे, रिजर्व बैंक ने सब बैंकों से उनके सरकारी साख पा खरीद करके उन्हें रुपया देने की घोषणा कर दी। इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा और स्थिति शीघ्र ही संभल गई। हाँ, कुछ गैरसदस्य बैंकों को कठिनाई उठानी पड़ी जो केवल इसलिये थी कि उनकी व्यवस्था सराव थी। उन्होंने व्यर्थ के लिये बहुत सी शाखाएँ खोल ली थीं, उन्होंने ऋण भी समझौते के बिना दे रखे थे, वे

स्टाक एक्सचेंजों में सट्टेबाजी करते थे और उनके यहाँ विशेष शिक्षित कर्म-चारी नहीं थे। ऐसे बैंक सचमुच हमारी बैकिंग-प्रणाली के लिये बहुत ही शर्म की बात हैं। अतः, उन्हें आपस में अथवा उड़े-बड़े बैंकों से मिलकर अपनी स्थिति सुधरे बनानी चाहिये। फिर, देश के विभाजन के बाद पञ्जाब, भीमा प्रान्त तथा सिंध इत्यादि में जो गड़बड़ी हुई उससे भी वहाँ के बैंकों की स्थिति बहुत बिगड़ गई। उनके ऋण डूब गये और उनके यहाँ की जमा निकालने जाने लगी। ऐसे समय में उनके फेल हो जाने की आशका थी। अतः, २७ सितम्बर १९४७ को एक विशेष आदेश द्वारा सरकार ने ऐसे बैंकों को तीन महीने तक अपना दायित्व पूरा न कर सकने की छूट देने का अधिकार ले लिया। इस अवधि में ऐसे बैंक को प्रत्येक साख में अपनी कुल जमा का अधिक से अधिक १ प्रतिशत अथवा २५० रु० जो भी कम हो देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ऐसे बैंक को उचित ऋण देकर मदद भी कर सकती थी। १३ दिसम्बर, १९४७ को इस आदेश में मशोधन किया गया जिसके अनुसार ड्राफ्ट का ३० प्रतिशत अथवा ७५० रु० जो भी कम हो, देने का दायित्व रक्खा गया। २७ मार्च, १९४८ को इसकी आवश्यकता नहीं रह गई अतः, यह नमाप्त हो गया। इसमें बैंक संभल गये, किन्तु उनकी पूरी हानि का अभी तक पता नहीं चला है। बहुत से बैंकों ने अपनी पाकिस्तानी शाखायें बन्द कर दी हैं और हेड आफिस वहाँ से हटा लिये हैं। पञ्चाय नेशनल बैंक की बड़ी हानि हुई, किन्तु वह संभल गया।

उन्नति के लिये क्षेत्र

इन बैंकों की शाखायें लगभग १५०० शहरों में हैं। इसके यह अर्थ है कि लगभग १००० शहरों में अब भी कोई आधुनिक बैंक नहीं है। किन्तु ये व्यापार की दृष्टि से किसी महत्व के नहीं हैं। अतः, उन्हें इस समय छोड़ा जा सकता है इन समय जो आवश्यकता है वह वर्तमान बैंकों और उनकी शाखाओं के ठोम बनाने की है। इंग्लैण्ड में उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में और इस शताब्दी के आरम्भ में यही किया गया था। वहाँ के केवल १६ बैंकों की तुलना में हमारे देश में कई सौ बैंक हैं। छोटे बैंकों को परस्पर अथवा बड़े बैंकों से मिल जाना चाहिये। कुछ शहरों में तो बैंकों की बहुत बड़ी संख्या है। उदाहरणार्थ-कलकत्ते में ३८८, बम्बई में १८३, लाहौर में ६५, मद्रास में ८५, दिल्ली में ८०, अहमदाबाद में ५२, ढाका में ४७, कोयम्बटूर और अमृतसर में से प्रत्येक में

पर भी अपनी सम्पत्ति दे सकेंगे। इससे उन उद्योग-धन्वों की स्थापना भी रुक जायगी जिनकी सफलता के लिये कोई आशा नहीं की जा सकती है। बैंकों द्वारा पास किये धन्वों के हिस्से और ऋण-पत्र बड़े प्रिय हो सकेंगे और उन्हें जनता हाथो-हाथ ले लेगी। और यदि उन्हें पहले इन्हें लेना भी पड़ेगा तो बाद में वे इन्हें जनता के हाथों बेच भी सकेंगे।

कठिनाइयाँ और दोष

भारतीय बैंक अनेक कठिनाइयों और दोषों के होते हुये भी काम कर रहे हैं। अतः, यदि यह दूर हो जायें तो इनकी उन्नति हो सकती है।

(१) विदेशी सरकार और उसके अफसर भारतीय बैंकों को अपना काम नहीं देते थे। उनका सम्बन्ध इम्पीरियल बैंक तथा विदेशी बैंकों से रहता था। ऐसी आशा की जाती है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार उन्हें काम देगी और सबों को देगी न कि केवल इम्पीरियल बैंक को।

(२) इन्हे बड़े-बड़े शहरों में विदेशी बैंकों की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। अतः, वहाँ पर इनकी हानि ही होती है। केवल छोटे शहरों में ही जहाँ उनकी शखायें नहीं हैं इनका व्यवसाय अधिक चलता है और लाभ प्राप्त होता है। इधर बड़े-बड़े शहरों की शखायें वहाँ की अपनी हानि पूरी करने के उद्देश्य से छोटे-छोटे शहरों में भी अपनी उपशाखायें खोलने लग गये हैं।

(३) अधिकांश उद्योग-धन्वे और व्यापार, 'विशेषतः' विदेशी व्यापार विदेशियों के आधिपत्य में हैं। अतः, वे इस देश में अपने-अपने देशों के बैंकों की शाखाओं से ही सम्बन्ध रखना अधिक पसन्द करते हैं।

(४) बहुत से भारतीय व्यापारी भी विदेशी बैंकों ही में अपने हिसाब रखते हैं। उनमें देश प्रेम का अभाव है। अन्य देशों में यह प्रेम बड़ा काम करता है।

(५) इम्पीरियल बैंक पहले तो देश के मुख्य बैंक की हैसियत से और अब केन्द्रीय बैंक के एक मात्र अदलतिये की हैसियत से, अन्य बैंकों से बड़ी आसानी से प्रतियोगिता कर लेता है। अतः, उन्हें इसके सामने कठिनाई पड़ती है।

(६) इनके बारम्बार फेल होने के कारण इनमें विश्वास भी नहीं जम पाता है।

किन्तु एक तो न ये बैंकिंग का व्यवसाय समझने ही हैं और न इनके पास समय ही रहता है। अतः, ऐसे बैंकों का कार्य सुचारु रूप से नहीं चलता है।

(१४) कुछ दिनों पहले तक भारतीय बैंकों के अपने संगठन नहीं थे। इसका स्वाभाविक फल यह था कि उनमें पारस्परिक ईर्ष्या रहती थी और सह-योग का लेशमात्र भी नाम नहीं मिलता था। इधर भारतीय बैंकों का संगठन बन गया है।

(१५) कुछ विदेशी बैंकों के बड़े-बड़े कर्मचारी प्रायः भारतीय बैंकों को बदनाम करते रहते हैं। इससे सेन्ट्रल बैंक की बड़ी हानि हुई है, किन्तु वह उन्नति करता ही जा रहा है।

(१६) बैंकिंग शास्त्र के विशेषज्ञों की कमी है। अतः, साधारण लोग ही इस काम के लिये रखे जाते हैं। इधर बैंकों में अनुभवी लोगों को रखने की काफी होड़ रही है जिससे बैंकों के कर्मचारी इधर से उधर चले जाते हैं।

(१७) बैंकों की और उनकी शाखाओं की संख्या इधर बढ़ती रही है। अतः, उनके एकीकरण और सुदृढ़ होने की आवश्यकता है। हमारे बैंकों का और विशेषतः गैरदस्य बैंकों का औसत डील-डोल बहुत छोटा है। अतः, उन्हें परस्पर अथवा बड़े-बड़े बैंकों से मिल जाना चाहिये।

अतः, उपर्युक्त कठिनाइयाँ और दोष दूर करने के लिये निम्न बातें की जा सकती हैं—

(१) देश की सरकार को सब भारतीय बैंक अपनाने चाहिये, केवल इम्पीरियल बैंक को ही नहीं। इसने इन बैंकों के ऊपर सुरक्षा के विचार से कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। इनके साथ-साथ इन्हें कुछ रियायतें भी देनी चाहिये और उनमें सबसे महत्वपूर्ण रियायत यही है कि सरकार को इन्हें अपनाना चाहिये। उसे सारे भुगतान चेक से ही करने चाहिये और उसके नियन्त्रण में जितनी सस्याये हैं उन सबों को भी ऐसा करने के लिये बाध्य करना चाहिये।

(२) विदेशी बैंकों के खुलने और काम करने पर प्रतिबन्ध लगा देने चाहिये। उन्हें देश के भीतरी शहरों में शाखाएँ खोलने की आज्ञा नहीं प्रदान करनी चाहिये और परिमित जमा से अधिक जमा भी नहीं लेने-देने चाहिये। इस बात के लिये भी व्यवस्था कर देना चाहिये कि उनके और भारतीय बैंकों के बीच में प्रतियोगिता न हो।

(३) इन्जीनियरों को प्रत्यक्षित ज्ञानों के साथ भारतीय बैंकों के लोह न करके अन्तर्गत्रीय उद्योगों को अधिक सहायता प्रदान करने का काम अपने हाथ में लेना चाहिये ।

✓ (४) अभिन्तर गजरा में नाने रहने की प्राप्ति दे देनी चाहिये । बैंकों के लिए यह बहुत ही सुविधाजनक है ।

(५) रिजर्वडन्टिंग अधिक प्रिय धनाने के उद्देश्य के लिए योग्य दृष्टियों का प्रयोग करना चाहिये । ऐसा करने के लिये कुछ नाने करने पड़ेंगे जिनका अध्ययन हम प्राप्ति चलाने करेंगे ।

(६) बैंक को वैयक्तिक ऋण अधिक देने चाहिये । ऐसा तभी किया जा सकता है जब बजार के लोगों ने अधिक सम्पत्ति बढ़ाया जाय और उसके लिये बैंक प्रदान उसी स्थान के होने चाहिये न कि बाहर के । यह प्राप्ति देना गया है कि स्थानीय प्रत्यक्ष बाहरी प्रत्यक्षों की अपेक्षा अधिक व्यवसाय बढ़ा लेते हैं ।

✓ (७) बैंकों को उन्हीं भाग्यों में काम करना चाहिये जिन्हें उनके ग्राहक जानते हैं । इससे उन्हें काम करने में सुविधा पड़ेगी और काम भी अधिक मिलेगा ।

✓ (८) उन्हें देशी महान्तों की सहायता और मितव्ययता का अनुकरण करना चाहिये । उन्हें इनके साथ 'कमाण्डिट' सिद्धान्त पर भाषा कर लेना चाहिये । उन्हें अपने नियमों के पालन पर भी बहुत कटाई करनी चाहिये । भारतीय बैंक चेकों का भुगतान करने में जो देर लगाते हैं वह तो सभी जानते हैं । ग्राहकों को किसी भी बैंक से किसी भी चेक का भुगतान लेने में बड़ा समय गंवाना पड़ता है ।

(९) जो लोग बैंकिंग के सिद्धान्त समझते हैं और उद्योग काम देख-भाल करते हैं केवल उन्हीं को बैंकों के संचालक मंडलों में लेना चाहिये । बैंकों के लिये केवल उद्देश्य नामों का ही आकर्षण नहीं होना चाहिये ।

(१०) अभी हाल में ही जो भारतीय बैंकिंग सच बना है उसका प्रत्येक भारतीय बैंक को सदस्य बन जाना चाहिये ।

(११) रिजर्व बैंक की आवश्यकता पढ़ने पर उन सभी बैंकों की किसी दिक्कत-आवृत्ति के बिना सब प्रकार से सहायता करनी चाहिये, जो सहायता पाने के योग्य हैं । इससे उसके ऊपर उनका विश्वास बढ़ जायेगा ।

(१२) बैंकों को निम्नविभागों के स्नातकों को लेकर उन्हें विशेष शिक्षा देनी चाहिये । बैंकिंग के उन्नति के लिये ऐसा कोई काम करना बहुत ही आवश्यक है । बैंकिंग की योग्यतावाले वाणिज्य-ज्ञान के स्नातक हों । वे भी बड़ा काम कर सकते हैं ।

(१३) उन्हें प्रैक्टिसी बैंकों की तरफ़ परस्पर एकीकरण कर लेना चाहिये ।

सम्मिलित पूँजी के मुख्य-मुख्य भारतीय बैंक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की स्थापना सन् १९११ में हुई थी । इसका श्रेय मुख्यतः सोराबजी पुचगवाला को था । वह बड़े ही योग्य व्यक्ति थे और आजीवन कम्पनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर रहे । सन् १९३८ में उनकी मृत्यु हो जाने में भारतीय बैंकिंग को साधारणः और सेन्ट्रल बैंक को मुख्यतः बड़ा धक्का लगा । यह बैंक प्रत्येक दृष्टि से, चाहे पूँजी और सुरक्षित कोष, जमा, शाखाओं की संख्या अथवा बैंकिंग व्यवसाय का कोई काम ले लिया जाय, सम्मिलित पूँजी के सब भारतीय बैंकों में प्रमुख हैं । सन् १९२३ इसके लिये विशेष महत्व का था । उस वर्ष इसने टाटा इण्डस्ट्रियल बैंक को अपने में सम्मिलित कर लिया था । जिसमें हमकी पूँजी और इसका सुरक्षित कोष मिलाकर ८० लाख ६० से २६८ लाख ८० हो गया, जमा १४ करोड़ ८० से १८ करोड़ ८० हो गई और पूँजी और सुरक्षित कोष मिलकर जमा का ५७ प्रतिशत से १७१ प्रतिशत हो गया । बैंक ने प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ-काल में अपनी पहली शाखा कराची में खोली थी । युद्ध समाप्त होते-होते इनकी संख्या पाँच हो गई । सन् १९३४ में इसके दफ्तरों की संख्या ६८ थी, सन् १९३७ में यह ८९ हो गई । सन् १९३८ में यह २०१ थी, सन् १९४० में यह १३२ थी, सन् १९४३ में यह २१७ थी और सन् १९४५ में यह ३०८ थी । किसी भी भारतीय बैंक ने इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं किया जितनी इस बैंक को करनी पड़ी है । इसकी स्थापना के प्रथम २० वर्षों के अन्दर ही इसके ऊपर नौ आक्रमण हुये थे जिसे इतने सफलतापूर्वक रौंभाला ।

यह बैंक इम्पीरियल बैंक की तरह सभी प्रान्तों में है । स्थाई और अस्थायी जमा पर यह जो व्याज देता है उसकी दर अन्य बैंकों की दरों की अपेक्षा-कृत कम है । सन् १९२१ से यह चालू खातों और स्थायी खातों पर दिये गये व्याज की रकम पृथक्-पृथक् दिखलाता है । पहले तो स्थायी

बैंक आफ बड़ौदा

बैंक आफ बड़ौदा सन् १८०६ में स्थापित हुआ था। इसकी पहली शाखा सन् १८१६ में मोनों गई थी। सन् १८५० में इसके कुल दफ्तरी की संख्या ४६ थी और उनमें से अधिकांश व्यापारिक और गुजरात में थे। यह नगर का अनुपात बहुत अधिक रखता है—प्रायः ५४ १५ प्रतिशत रहता है। शाखा की दृष्टि से यहां के सम्मिलित पूंजी के प्रकाश में इसका पाँचवाँ स्थान है। इसके लाभ (Gross Profit) की दर बहुत कम है। जिस क्षेत्र में यह काम करता है उसमें द्रव्य बहुत है। अतः, बैंकों द्वारा मालजनों में परस्पर बढ़ती प्रतियोगिता रहती है जिससे पूंजी पर कम व्याज मिलता है।

भारत बैंक

भारत बैंक की रजिस्ट्री सन् १८४२ में हुई थी। अतः, अन्य बैंकों के आगे यह अभी उमरा ही है। किन्तु उसकी पूंजी उनमें सबसे अधिक है। यह २ करोड़ ६० से भी ऊँची है। इसके दफ्तरी की संख्या भी बहुत है। सन् १८५५ में यह २१४ थी। इसके पाग उमरा भी अच्छी है। इस समय यहाँ के बैंकों के बीच में इसका स्थान छठा है। उसने अच्छे-अच्छे बैंकों को मर्जित दिया है। इसकी सत्यापना के पहले इण्डियन बैंक और मद्रास बैंक का स्थान प्रथम छठा और सातवाँ था। इस प्रकार चलने में भविष्य में शायद यह पाँच बड़े बैंकों में से कुछ और को पछाड़ दे और उनका स्थान ले ले।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक सन् १८४४ में स्थापित किया गया था। इसकी पूंजी भी सेन्ट्रल बैंक को छोड़कर पाँचों बड़े बैंकों की पूंजी से अधिक थी। यह भी दोनदार बैंक मालूम होता है। सन् १८४५ में इसके ६२ दफ्तर थे।

इण्डियन बैंक

इण्डियन बैंक का स्थान यहाँ के बैंकों में छठा था। किन्तु अब यह स्थान भारत बैंक ने ले लिया है। इसकी रजिस्ट्री सन् १८०७ में हुई थी। यह अब भी दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसका प्रधान दफ्तर मद्रास में है और इसके सब दफ्तरों की संख्या सन् १८४५ में ६३ थी। इसके अधिकांश

दफ्तर सन् १९३५ के बाद ख ले गये हैं । इसके अधिकांश हिस्से नट्टूकोटाई चट्टियों के हाथ में हैं । अतः इसे उन्हीं का बैंक कहा जा सकता है । अधिकांश ऋण भी इन्हीं लोगो को दिया जाता है । चट्टी लोग स्वयं महाजन हैं और बैंक तथा ऋण लेनेवालों के बीच में मध्यस्थ का कार्य करते हैं । यह बैंक इनके वैयक्तिक दायित्व पर ऋण देना अधिक पसन्द करता है । माल की जमानत से यह यही जमानत अच्छी समझता है । यही कारण है कि यह सरकारी साल-पत्रों में भी अधिक रकम नहीं लगाता । इसकी अधिकांश लागत ऋण के रूप में है । इससे इसकी कभी कोई विशेष हानि भी नहीं हुई है । दूसरे बैंक इससे इस बात का सबक सीख सकते हैं । वे भी देशी महाजनों को मध्यस्थ बनाकर काम कर सकते हैं ।

बैंक आफ मैसूर

बैंक आफ मैसूर सन् १९१२ में स्थापित हुआ था । यद्यपि इसके साधन बहुत बड़े हैं किन्तु इसे रिजर्व बैंक की तालिका में केवल सन् १९४३ में ही सम्मिलित किया गया था । इसके पहले शायद ऐसा इसलिये नहीं हुआ था कि इसकी ब्रिटिश भारत में कोई शाख नहीं थी । इधर कई वर्षों से यह १४ प्रतिशत लाभ की बँटनी करता आ रहा है ।

अन्य बैंक

कुछ अन्य बैंक भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे कोमिला बैंकिंग कारपोरेशन, कोमिला यूनियन बैंक, बैंक आफ जैपुर, डिस्काउण्ट बैंक आफ इण्डिया, एक्सचेंज बैंक आफ इण्डिया ऐण्ड अफ्रीका, हवीव बैंक, हिन्दुस्थान कमर्शियल बैंक, पंजाब ऐण्ड सिन्ध बैंक, ट्रेडर्स बैंक और यूनियन बैंक ।

सदस्य बैंकों के दायित्व

यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि कौन से बैंक सदस्य बैंक बन सकते हैं । इनके कुछ दायित्व होते हैं —

(१) प्रथम तो प्रत्येक सदस्य बैंक को रिजर्व बैंक में अपनी चालू जमा का कम से कम ५ प्रतिशत और स्थायी जमा का २ प्रतिशत बैलान्स रखना पड़ता है । इसके लिये इसे रिजर्व बैंक के उस दफ्तर का नाम बताना पड़ता है जहाँ यह अपना मुख्य खाता रखेगा । सदस्य बैंक अपने हिसाब रिजर्व बैंक के उन सभी दफ्तरों में रख सकते हैं जो ऐसे स्थान में हों जहाँ उनके भी दफ्तर

है। यदि किसी सार्वजनिक बैंक का दफ्तर किसी ऐसे स्थान में नहीं है जहाँ गिरान्त बैंक के दफ्तर है तो यह रिजर्व बैंक के किसी दफ्तर में भी अपना दस्तावेज रख सकता है।

(२) दूसरे, सार्वजनिक तो रिजर्व बैंक विभाग की ४२ (२) धारा में जो पामें दिया हुआ है उसी के अनुसार प्रत्येक स्थिति की एक सार्वजनिक रिपोर्ट रिजर्व बैंक के पास और एक केन्द्रीय सचिव के पास भेजनी पड़ती है। जहाँ के लिये रिजर्व बैंक यह समझता है कि वहाँ की नैसर्गिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं आ सकती, वहाँ पर यह मानिक रिपोर्ट दी जा सकती है। यह रिपोर्ट उसी दफ्तर को जाती है जहाँ मुख्य खाता रहता है।

यदि (२) में दी हुई रिपोर्ट समय पर नहीं भेजी जाती तब (१) में दिया हुआ न्यूनतम बैलन्स रिजर्व बैंक के पास नहीं रक्खा जाता तो सजा दी जाती है। यदि रिपोर्ट नहीं भेजी जाती तो जितने दिनों की देर होती है उतने दिनों तक १०० रु० प्रति दिन के दंड से जुर्माना लगता है। और यदि न्यूनतम बैलन्स नहीं रक्खा जाता तो एक सप्ताह तक तो जितना बैलन्स कम होता है उस पर बैंक दर से ३ प्रतिशत अधिक व्याज लगता है और यदि यह दूसरी रिपोर्ट भेजने की तारीख के बाद भी कम रहता है तो एक दर से ५ प्रतिशत अधिक व्याज लगता है। यह दोना जुर्माना माँगने पर उसी समय देने पड़ते हैं और इन्हें वही दफ्तर माँगता है जिसमें उस सदस्य बैंक का मुख्य खाता होता है। यह जुर्माना न देने पर वह अदालत द्वारा भी वसूल किया जा सकता है। कुछ बैंक न्यूनतम बैलन्स न रख कर व्याज दे देते थे। अतः, यह रोकने के लिए रिजर्व बैंक के सन् १९४० के एक विधान से रिजर्व बैंक को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह अपराधी बैंक को और अधिक जमा प्राप्त करने से रोक सकता है और उन कर्मचारियों को भी सजा दे सकता है जिनकी जान-कारी से यह अपराध किया जाता है।

उनके अधिकार

सदस्यों को कुछ अधिकार भी प्राप्त हैं :—

(१) उन्हें अच्छे बिलों की डिस्काउण्टिंग के रूप में अथवा अच्छे साख-पत्रों की जमानत पर ऋण के रूप में रिजर्व बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। कौन से बिल अच्छे हैं और कौन से साख पत्र अच्छे हैं यह बात स्पष्ट रूप से रिजर्व बैंक विधान की १७वीं धारा में दी हुई है। रिजर्व बैंक

की ऋण देने की नीति और जिस प्रकार की आर्थिक सहायता वह सदस्य बैंको को दे सकता है, वह सब उसके ७ दिसम्बर, सन् १९३८ के एक स्मरण-पत्र में दिये हुये हैं। संसार के अन्य देशों में जो नीति बरती जाती है, उसी के अनुसार और इस देश में बैंकिंग का उचित ढङ्ग से विकास करने के उद्देश्य से सदस्य बैंकों को उधार देने के समय रिजर्व बैंक केवल उन साख-पत्रों पर ही ध्यान नहीं देगा, जिनके आधार पर ऋण मँगा जा रहा है बल्कि इन बातों पर भी ध्यान देगा कि प्रायः बैंक की लागतें साधारणतः किस प्रकार की हैं, उसका व्यवसाय कैसे किया जाता है। उदाहरणार्थ वह जमा प्राप्त करने के लिये व्याज की बहुत ऊँची दर तो नहीं देता, जब बाजार में रुपये की दान नहीं रहती तब वह रिजर्व बैंक से उधार तो नहीं लेता, अपनी शक्ति से अधिक व्यवसाय तो नहीं करता और चीजों पर तथा साख-पत्रों पर सट्टे के लिए ऋण तो अधिक नहीं देता अथवा बिना जमानती काम तो बहुत नहीं करता। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखना चाहिये कि रिजर्व बैंक केवल अल्पकालीन ऋण ही दे सकता है। फिर इस बात का विश्वास मिल जाने के लिये कि वह जो ऋण की सुविधा दे रहा है उसका दुरुपयोग तो न किया जायगा, वह मनचाही कोई भी बात पूछ सकता है अथवा किसी प्रकार की कोई भी शर्त लगा सकता है और ऋण लेने वाले बैंक को यह बात बतानी पड़ेगी तथा शर्त पूरी करनी पड़ेगी। अन्तिम यह कि अन्य बैंकों की तरह रिजर्व बैंक भी अपने विवेक के अनुसार कोई कारण बताये बिना ही किसी बैंक के बिल डिस्काउण्ट करने की अथवा उसे साख-पत्रों पर ऋण देने की मनाही कर सकता है। किन्तु यदि सदस्य बैंक उचित ढङ्ग पर काम करते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर उचित जमानत पर उन्हें रिजर्व बैंक से अवश्य ही अल्पकालीन आर्थिक सहायता मिल सकती है। सन् १९४५ में बङ्गाल में जो बैंकों के ऊपर सकट पड़ा था और १९४७ में उन पर जो पंजाब में सकट पड़ा था, उस समय उसने उनकी सहायता की थी। इसने कुछ निम्न श्रेणी की जमानतों पर ऋण देने के लिये सरकारी आजा प्राप्त कर ली थी।

(४) उन्हें जो दूसरा अधिकार प्राप्त है, वह रियासती दर पर इबार से उधार रुपया भेजने के सम्बन्ध का है। रिजर्व बैंक ने १ अक्टूबर, सन् १९४० को रुखा भेजने की सुविधा नाम की जो योजना घोषित की थी, उसके दूसरे परिशिष्ट के अनुसार कोई भी सदस्य बैंक रिजर्व बैंक के किसी भी दफ्तर साख अथवा एजेन्सी में उसके किसी भी दफ्तर, शाख, उपशाख इत्यादि में जो,

जाता है, उनके बीच में शक से श्रध्दा तार से भाग्य में निगा प्रार से रुपया भरा सकता है —

(१) (अ) रिजर्व बैंक के दफ्तर और शाखा में उसके जो गाने हैं उनके बीच में फोर्ड भी पार्च दिये बिना १०००० रु० श्रध्दा उसमें गुणित फोर्ड भी सम्म,

(ब) श्रध्दा रिमा भी दफ्तर में श्रध्दा शाखा में श्रध्दा उपशाखा इत्यादि में यदि फोर्ड रिजर्व बैंक की फोर्ड एजेंसी है तो उसके तारा रिजर्व बैंक के श्रध्दा मुख्य गाने में सप्ताह में केवल एक बार ५००० रु० श्रध्दा उसमें गुणित फोर्ड भी रखम किजी भी पार्च के बिना ।

(ग) मुख्य गाने ही को फोर्ड भी सम्म एक पैसा रु० सप्ताह के पार्च पर, किन्तु न्यूनतम पार्च १ रु० से कम नहीं मिलना चाहिये ।

(ङ) रिजर्व बैंक में श्रध्दा उसकी एजन्सिया में जो दूसरे गाने हैं उनके बीच में ।

५००० रु० तक १ आ० प्रतिशत व्यय पर न्यूनतम व्यय १ रु० ।

५००० रु० से ऊपर दो पैसा प्रतिशत व्यय पर न्यूनतम व्यय ३ रु० २ आना ।

(२) रिजर्व बैंक के राजानों के ऊपर अन्य व्यक्तियों के पक्ष में टी० टी० और ड्राफ्ट निम्न व्यय पर दिये जाते हैं —

५००० रु० तक १ आना प्रतिशत व्यय पर न्यूनतम व्यय १ रु० ।

५००० रु० से ऊपर दो पैसा प्रतिशत व्यय पर न्यूनतम व्यय १ रु० २ आ० ।

तार का व्यय इसके अतिरिक्त लिया जाता है ।

गैर सदस्य बैंकों के दायित्व

वेसे तो सन् १९४६ के भारतीय कम्पनी विधान में जो नियम दिये हुये हैं उनका पालन सभी बैंकों को करना पड़ता है किन्तु सदस्य बैंकों की तरह ही

नियत रिपोर्ट देने और न्यूनतम बैलन्स रखने के सम्बन्ध में उनके भी कुछ दायित्व हैं जिन्हे हमे यहाँ पर विशेष रूप से समझ लेना चाहिये —

(१) गैर सदस्य बैङ्को को सन् १९३८ के पहले तक तो अपनी रिपोर्टें प्रान्तीय रजिस्ट्रारों के पास भेजनी पड़ती थीं । किन्तु उस वर्ष के फरवरी महीने से प्रत्येक रजिस्ट्रार को इन सब रिपोर्टों को एक लिपि रिजर्व बैङ्क के पास भेजनी पड़ने लगी और बैङ्क रजिस्ट्रार के पास एक लिपि न भेजकर तीन लिपियाँ भेजने लगे । किन्तु १९४८ से रिजर्व बैङ्क सीधे यह रिपोर्टें मँगवाने लगा है ।

(२) वे अपने चालू जमा की और स्थायी जमा की कम से कम क्रमशः ५ प्रतिशत और २ प्रतिशत नकदी अपने पास रखते हैं । नया विधान पास होने के पहले २ प्रतिशत के स्थान पर १½ प्रतिशत ही था ।

यहाँ पर यह भी कह देना आवश्यक है कि इनकी रिपोर्टें मासिक होती हैं, सदस्य बैङ्कों की तरह साप्ताहिक नहीं और वह प्रतिमास के अंतिम शुक्रवार की होती हैं न कि प्रति सप्ताह के शुक्रवार की ।

उनके अधिकार

(१) १ अक्टूबर, सन् १९४० से रिजर्व बैङ्क ने रुपया भेजने की जो योजना घोषित की है उसके तीसरे परिशिष्ट के अनुसार उन गैर-सदस्य बैङ्कों को जिनके नाम रिजर्व बैङ्क की स्वीकृति तालिका में दिये हुये हैं और जो उपयुक्त प्रांतीय सरकारों की सम्मति से बनी है केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों द्वारा स्वीकृत रियायती दरों पर रुपया भेजने का अधिकार दिया गया है । सन् १९४७ के अंत में ऐसे ७८ बैङ्क थे । १९४८ के अंत में भारतीय यूनिथन में यह सख्या ६६ थी, जब की जनता के लिए ५००० रु० तक भेजने के लिए २ आ० प्रति सैकड़ा दर है और ५००० से ऊपर के लिए १ आ० प्रति सैकड़ा दर है, तब इनके लिए यही क्रमशः १ आ० प्रतिशत और २ पैसा प्रतिशत है । न्यूनतम व्यय सभी के लिए, कुछ न कुछ निर्धारित है । स्वीकृति तालिका में आने के लिए इन बैङ्कों को निम्न शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं :—

(अ) इन्हे भारतीय कम्पनी विधान के अनुसार रजिस्टर्ड कम्पनियाँ होना चाहिये ।

(ब) इन्हे भारतीय कम्पनी विधान में दिये हुये नियमों के अनुसार व्यवसाय करना चाहिये ।

(३) इनकी पूँजी इनका कोष मिनाकर कम से कम ५०००० रु० होनी चाहिये ।

(२) गैर सदस्य वैद्वों को अपने सम्बन्ध की सभी बातों पर लिखे वैद्व की सम्मति भी प्राप्त हो सकती है ।

(२) १५ फरवरी, सन् १९४५ में कोर्ट भी गैरसदस्य वैद्व निम्न बातों के साथ लिखे वैद्व के यहाँ अपना दिवाय भी मोल सकता है ।—

(१) उसे अपने व्यवसाय के विस्तार के अनुसार कम से कम कुछ बैलन्स अवश्य रखना चाहिये और यह १०००० रु० से कम तो होना ही नहीं चाहिये ।

(२) यह जाता साधारण जाता नहीं है यर्थात् इस पर चेकें नहीं काटी जा सकती । हाँ, इसे रुपया भेजने के लिए और वैद्वों के अन्य पारम्परिक कामों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है ।

प्रश्न

(१) सम्मिलित पूँजी के बैंको का किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है ? सदस्य बैंको के विषय में आप क्या जानते हैं ?

(२) सम्मिलित पूँजी के भारतीय बैंकों की वनम न विरहित क्या है ? उनके कार्यों का एक निरुद्ध वर्णन दीजिये और उनके सम्बन्ध की विशेषताये बताइये ।

(३) द्वितीय महायुद्ध का भारतीय बैंकिंग पर क्या प्रभाव पड़ा है ? यह प्रभाव आपकी समझ से अच्छा हुआ है अथवा बुरा ? इनके भविष्य के विषय में आप क्या सोचते हैं ?

(४) सम्मिलित पूँजी के भारतीय बैंको की क्या कठिनाइयाँ हैं और उनके क्या दोष हैं ? उनके सुधार के लिए अपने सुझाव रखिये ।

(५) सम्मिलित पूँजी के कुछ महत्वपूर्ण भारतीय बैंको के विषय में टिप्पणियाँ लिखिये ।

(६) सदस्य बैंको के कौन-कौन से दायित्व और अधिकार हैं ?

(७) गैरसदस्य बैंको से किस तरह से अपना सम्बन्ध रखता है ? उसने उन्हें कौन-कौन सी सुविधायें दे रखी हैं ?

अध्याय १७

इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया

जिन स्थितियों में इम्पीरियल बैंक स्थापित हुआ था और जिस तरह से यह बैंक रिजर्व की संस्थापना के पहले तक काम कर रहा था, उनका अध्ययन तो हम १२वें अध्याय में ही कर चुके हैं। किन्तु कुछ अन्य बातें भी ऐसी हैं जिन्हें हमें अब समझ लेना चाहिये और उनमें मुख्य तो यह है कि यह बैंक स्वयं ही पूर्ण रूप से केन्द्रीय बैंक क्यों नहीं बनाया गया और एक नया बैंक क्यों स्थापित किया गया। अतः, पहले हम इसी का अध्ययन करेंगे और फिर अन्य बातें लेंगे।

इम्पीरियल बैंक को पूर्णरूप से केन्द्रीय बैंक न बनाने के कारण

(१) प्रथम तो केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना चाहिये। ऐसा न होने से वह देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधार सकता और न वह उसमें राष्ट्रीय बैंकिंग का विकास ही कर सकता है। इम्पीरियल बैंक की कभी भी राष्ट्रीय दृष्टि नहीं रही। इसके विपरीत, हिल्टन यंग कमीशन के सामने कुछ ऐसे उदाहरण रखे गये थे, जिनसे यह साबित होता था कि इमने सरकारी माव-पत्र होते हुये भी कुछ भारतीय बैंकों को सहायता देने से इन्कार कर दिया था। एक ओर तो यह विदेशियों को ऋण देता था और दूसरी ओर भारतीयों को उसके लिये इन्कार कर देता था।

(२) भारतीय बैंकों को यह प्रतियोगिता की दृष्टि से देखता था। उन्हें प्रायः, यह यहाँ की बैंकिंग का एक आवश्यक अङ्ग न समझ कर अपना शत्रु समझता था। अतः, यदि इसे केन्द्रीय बैंक बना भी दिया जाता तो भी इसकी नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पाता।

(३) इम्पीरियल बैंक की जो बहुत सी शाखाएँ थीं, वह किसी केन्द्रीय बैंक के लिये अनावश्यक बोझ समझी जाती थीं, क्योंकि एक केन्द्रीय बैंक तो अपनी इनी-गिनी शाखाओं द्वारा ही द्रव्य बाजार को नियन्त्रण में ला सकता है। केन्द्रीय बैंक तो जितना काम अपनी उपस्थिति से ही कर लेता है, उतना काम करवे नहीं करता। अन्तिम यह कि बहुत सी शाखाएँ होने से इसकी सारी

जाने उन्हीं की व्यवस्था करने में पारन हो जाती और घर देश की बैङ्किंग प्रणाली को अपने नियन्त्रण में न ला सकता।

(४) बैंक के संचालन में लक्ष्य और व्यवस्थाओं में के आग्रिवाज के पुनो-धीय होने के कारण, इसके देश की आवश्यकताय समझ करने और उनके अनुसार काम करने की, विशेषतः जग देश। जन में उनके अपने देश की दानि होती, प्राप्ता नहीं हो ला सकती थी।

(५) उसे केन्द्रीय बैंक बनाने के लिये हमारे कार्यों में बहुत श्रद्धालु-बदली करनी पड़ती जो शायद इसके हितोद्योग सम्बन्ध न करने। जन उनके और राज्य के बीच में मनमुटाव उत्पन्न हो जाता जो एक केन्द्रीय बैंक के प्रारम्भ के लिये अनुचित होता।

(६) इंग्लिश बैंक तो एकमात्र लाभ कमाने के ही उत्प्रेष्य ने ही सम्पादित किया गया था किन्तु एक केन्द्रीय बैंक को तो प्रायः देश के हित में लाभ का प्रदान करना पड़ता है। अतः यह कैसे हो सकता था ? हम जानते हैं कि जब तेजी रोक्नी होती है, तब केन्द्रीय बैंक को व्याज जो दर उदात्त कर देने से इन्कार करना पड़ता है। भला कोई व्यापारिक बैंक ऐसा कैसे कर सकता है ? जब मदी गेफनी है तब हमका उल्टा करना पड़ता है। गाला में चुके दग से काम करने में भी वही कठिनाई है। केन्द्रीय बैंक जो तेजी में सात-पत्र कम मूल्य पर बेचने और मदी में उन्हें अधिक मूल्य पर खरीदने पड़ते हैं।

(७) फ्रांस में तो फ्रांस का केन्द्रीय बैंक, केन्द्रीय बैङ्किंग के कार्यों के साथ-साथ व्यापारिक बैङ्किंग के कार्य भी करता है। किन्तु हर देश में ऐसा नहीं किया जा सकता। सब देशों में एक ही भी स्थितियाँ नहीं हैं। फ्रांस के निर्यात में ऐसी वस्तुएँ बहुत कम हैं जिनके मूल्य बहुत जल्दी घटत-बढ़ते हैं। अतः उनका निर्यात भी बहुत जल्दी नहीं घटता-बढ़ता। साथ ही उसका बहुत कुछ द्रव्य विदेशों में लगा रहता है। अतः उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जल्दी फर्क नहीं पड़ता। इसके विपरीत भारत के निर्यात में ऐसी वस्तुएँ अधिक हैं जिनका मूल्य बहुत घटता-बढ़ता है, अतः, उनका निर्यात भी घटता-बढ़ता रहता है। फिर, उसके यहाँ विदेशी रुपया लगा हुआ है। (हाँ, अब स्थिति बदल गई है।) अतः इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंकिंग के कार्यों के साथ-साथ व्यापारिक बैंकों के कार्य करने की आशा नहीं दी जा सकती थी। साथ ही इसके अन्य बैंकों से प्रतियोगिता करने का भी प्रश्न था। कुछ बैंक इसके विरोध में आवाज

उठा ही रहे थे । यदि इससे इसके व्यापारिक बैङ्किंग के कार्य करने की शक्ति छीने बिना, इसे केन्द्रीय बैंक भी बना दिया जाता तो यह बड़ा शक्तिवान हो जाता और अपने कुछ प्रतियोगी बैंकों को तो समाप्त ही कर देता । यह तो उचित ही है कि जिसके पास सब का कोष हो उन जनता से काम करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये । नहीं तो वह दूसरों के द्रव्य से बहुत लाभ कमा सकता है । फिर यह बैंकों का बैंक कैसे बन सकती थी । उनका प्रतियोगी होने के नाते, यह उन्हें मदद ही कैसे कर सकता था और वही अपने सकल के समय इससे किसी प्रकार की सहायता पाने की आशा कैसे कर सकते ? वे तो इसे अपना प्रतियोगी समझते थे और इसके अधिकारों की ईर्ष्या की दृष्टि से ही देखते । फिर यह बैंक करन्सी की व्यवस्था अपने हित में करता न कि देश के हित में । अन्तिम यह कि बहुत बोझ हो जाने के कारण न तो यह केन्द्रीय बैंकिंग के कार्य और न व्यापारिक बैंकिंग के कार्य भली प्रकार से कर सकता ।

(८) यद्यपि इसे रुपये की टान होने पर उसके व्याज की दर बहुत बढ़ने से रोकने के उद्देश्य से अपने बिलों और ड्रिडियो की जमानत पर करन्सी विभाग से ४ करोड़ रुपया बैंक दर पर और न्यूनतम ६ प्रतिशत पर और इसके ऊपर ८ करोड़ रुपया ७ प्रतिशत पर उधार लेने का अधिकार प्राप्त था, किन्तु यह भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न भिन्न व्याज की दर एक-सी करने में और तेजी के समय उसे अत्यधिक बढ़ने से रोकने में सफल नहीं हो सका । इसमें सन्देह नहीं कि करन्सी का अन्तिम नियन्त्रण तो सरकार के हाथ में रख कर और व्याज की दर के एक सीमा पर पहुँचने पर उसमें से कुछ ऋण प्राप्त कर सकने का अधिकार इम्पीरियल बैंक को देकर, स्थिति बहुत नहीं सम्भाली जा सकती थी । किन्तु, तो भी इम्पीरियल बैंक व्याज की दर के अन्तर में कुछ तो कमी कर ही सकता था, लेकिन इससे राष्ट्रीय हित की अपेक्षाकृत अपने ही हित का अधिक ध्यान रख कर तेजी के समय की माँग से पूरा लाभ उठाया और करन्सी विभाग से करन्सी लेकर दर ऊँचा उठने से नहीं रोका । यह एक उदाहरण है । सच तो यह है कि इसे जो केन्द्रीय काम मिले हुये थे उनके ही द्वारा इसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की कि जिससे राष्ट्र का लाभ होता ।

इससे व्यापारिक बैंकिंग के काम छीन लेने के फल-
स्वरूप संभावित आशंकाएँ

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट ही हो गया है कि इम्पीरियल बैंक से उसके

व्यापारिक वैकिंग के काम करने के अधिकार छीन लेने से स्थिति बहुत कुछ ठीक हो जाता, किन्तु इसका बल अन्य तगकों से बहुत दुरा होता । ये निम्नांकित हैं .

(१) बहुत सी ऐसी जगहें थीं जहाँ पर इम्पीरियल बैंक जे की अफेली जाय थी । अतः, यदि उससे उसके व्यापारिक बैंक के काम करने का अधिकार ले लिया जाता तो वहाँ के लोगों को वैकिंग का सुविधा न रह जाती ।

(२) जिन स्थानों में इसके शाख के साथ किसी अन्य बैंक की भी शाखा थी, वहाँ पर इसके काम न करने से उस बैंक का प्रभुत्व हो जाता जिसने वह लोगों से अधिक संचा लेता । इससे जनता की हानि ही होती ।

(३) जनता का इम्पीरियल बैंक के ऊपर विश्वास है । लोगों ने अपनी वचत उसके यहाँ जमा कर रखी है । अतः, यदि उसे जमा प्राप्त करने के लिये मना कर दिया जाता और स्थायी जमा प्राप्त करने के लिये तो उसे अवश्य ही मना कर दिया जाता क्योंकि उस पर तो व्याज दिया जाता है और इसके लिये अन्य बैंकों से प्रतियोगिता होने की आशंका रहती, तो स्थायी जमा तो अवश्य ही उसके यहाँ से निकल जाते । इस सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट करना चाहिये कि रिजर्व बैंक को भी स्थायी जमा लेने का अधिकार नहीं दिया गया है । और जो लोग इम्पीरियल बैंक में स्थायी जमा रखने दिये थे उनमें बहुत से शायद किसी अन्य बैंक में जमा रखते ही नहीं । उनका इसे छोड़ कर किसी पर विश्वास ही नहीं है । फिर, इसके चालू खातों की अधिसंख्या जमा भी निकल जाती, क्योंकि यह तो प्रायः इसीलिये रखी जाती है कि हमसे वैकिंग की अन्य सुविधायें प्राप्त होती हैं । अतः, यदि इम्पीरियल बैंक वह सुविधायें न दे पाता तो उसके यहाँ से वह जमा भी निकल जाती । यदि इसका बहुत सी गज़ायें बन्द कर दी जातीं, तो स्थिति और भी निगड़ जाती और ऐसा होना सम्भव भी था क्योंकि इतनी अधिक शाखाओं के बोझ के साथ इसे केन्द्रीय बैंकिंग के काम दिये ही नहीं जा सकते थे । अतः, जिन लोगों को इम्पीरियल बैंक से जमा निकालनी पड़ती, शायद वह उसे और कहीं जमा न करते । इससे बैंकिंग की आदत कम हो जाती ।

(४) इम्पीरियल बैंक को अपनी काम करने की प्रणाली से व्यापारिक बैंकिंग का स्तर ऊँचा हो गया है । यदि यह बैंक व्यापारिक बैंकिंग के काम करना बन्द कर देता तो शायद अन्य बैंक अपना स्तर इतना अच्छा न रख सकते । उनके सामने कोई आदर्श न रह जाता ।

सन् १९३४ का इम्पीरियल बैंक (संशोधन) विधान

इम्पीरियल बैंक पूर्ण रूप से केन्द्रीय बैंक नहीं बनाया गया वरन् उसके स्थान पर एक नया रिजर्व बैंक खोल दिया गया । इससे इम्पीरियल बैंक विधान में कुछ संशोधन करने पड़े जो सन् १९३४ के विधान से किये गये । इसके फलस्वरूप यह पूर्णरूप से व्यापारिक बैंक बन गया और इसके ऊपर के कुछ प्रतिबन्ध भी हटा लिये गये । १२वें अध्याय में यह बताया जा चुका है कि अपने विधान के अनुसार यह कुछ व्यवसाय नहीं कर सकता था । अतः, इस विधान द्वारा इसे उनमें से कुछ व्यवसाय करने की आज्ञा दे दी गई । हाँ, मन् प्रतिबन्ध तो नहीं हटाये जा सके । इसकी स्थिति तो अच्छी रखनी ही थी । अन्य कारणों के साथ-साथ इसका एक विशेष कारण यह भी था कि इसे उन स्थानों के लिये जहाँ इससे दफ्तर थे और रिजर्व बैंक के नहीं थे, उसका अद-तिया बनाया गया है । उक्त विधान से इसे निम्न सुविधायें प्राप्त हो गई —

(१) इसके लन्दन के दफ्तर में इसे सब प्रकार के व्यवसाय करने की आज्ञा मिल गई—इसके पहले यह वहाँ पर केवल उन्हीं लोगों के हिमायत खोल सकता था, जो इसके अथवा किसी-किसी बैंकों के भारत-वर्ष में ऐसा हिमायत खोलने की तारीख की मिलाते तीन वर्षों में ग्राहक रहे हों ।

(२) यह लन्दन के अतिरिक्त अन्य बाहरी स्थानों में भी अपनी शाखा खोल सकता है—इसके पहले इसकी शाखा बाहर केवल लन्दन ही में थी । अन्य किसी स्थान में वह उसे खोल ही नहीं सकता था । किन्तु इस संशोधन से यह रोक हटा ली गई ।

(३) दश म हा पहले से अधिक स्वतन्त्रता के साथ व्यवसाय कर सकता है—इस संशोधन से यह, वहाँ पर पहले से अधिक स्वतन्त्रता के साथ व्यवसाय कर सकता है । अब से रिजर्व बैंक खुल गया है तब से यह उसके डिस्टों पर भी ऋण दे सकता है । इसी प्रकार यह म्युनिस्पैलिटीयों के ऋण-पत्रों पर भी ऋण दे सकता है । फिर, यह देशी राजाओं द्वारा निकाले हुये उन ऋण-पत्रों पर भी ऋण दे सकता है, जिन्हें निकालने की स्वीकृति सप-रिषिड गवर्नर-जनरल ने दे दी है । इसी तरह से यह सीमित दायित्व वाली कम्पनियों द्वारा निकाले हुये ऋण-पत्रों पर भी ऋण दे सकता है । जहाँ तक

माल की गिरवी पर नष्ट गांव देने का प्रश्न है, वह तो यह पहले भी दे सकता था। किन्तु अब यदि हमने यहाँ कोई ऐसा विशेष प्रस्ताव पार हो जाय और इसका केन्द्रीय मण्डल उठे मान ले तो यह केवल माल अपने नाम पर करवा कर भी, चाहे वह कहीं भी वण न रखा हो, नष्ट गांव दे सकता है। इसके प्रतिरिक्त जब पहले यह सभी क्षुण्य अधिकृत-अधिकृत जेबल है ही महीनों के लिये दे सकता था, इस मशोधन से 12 रुपि मरग की कामों के लिये नौ महीनों तक के लिये क्षुण्य दे सकता है। अन्तिम यह कि अब यह कुछ शर्तों के साथ अचल सम्पत्ति भी क्षुण्य की समानता के तौर पर स्वीकृत कर और रख सकता है।

(४) अपना काम करने के लिये भारतवर्ष से बाहर क्षुण्य ले सकना— इस मशोधन ने यह अपने काम के लिये भारतवर्ष के बाहर भी क्षुण्य ले सकता है। इसके पहले यह ऐसा नहीं कर सकता था।

उस पर सरकार का भी बहुत कम नियन्त्रण रह गया है। एक तो यह कि इसके केन्द्रीय मण्डल में सपरिषद गवर्नर-जनरल केवल अपने दो ही गैर-सरकारी सचालक भेज सकता है। हाँ, एक अन्य अफसर भी रहता है किन्तु वह अपना मत नहीं दे सकता। दूसरे इसके पुराने विधान का ५४ वाँ नियम भी हटा दिया गया जिसके प्रर्थ यह है कि सपरिषद गवर्नर-जनरल न तो इसे कोई प्राज्ञा दे सकता है न हमने कोई बात प्रत्युक्त करता है, न जिस रूप में चाहे उस रूप में ही इससे उसकी सम्पत्ति और पाउने तथा दायित्व छापने के लिये कह सकता है। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर वह इसके यहाँ अपना प्राडीटर भेज सकता है और उसने इसके कामों की रिपोर्ट माँग सकता है।

इम्पीरियल बैंक की कार्यकारिणी

देश के भिन्न-भिन्न भागों के हित की रक्षा के लिये और उन्हें उनके यहाँ की बैंकिंग का व्यवसाय करने की स्वतन्त्रता देने के लिये इसके तीन स्थानीय दफ्तर खोले गये हैं, जो पहले के तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों के मुख्य स्थानों में हैं। फिर, प्रत्येक स्थानीय दफ्तर का एक स्थानीय मण्डल भी है। इसके लिये प्रत्येक क्षेत्र के हिस्सेदारों के नाम के पृथक् पृथक् रजिस्टर हैं। जिस क्षेत्र के स्थानीय मण्डल के सदस्यों का चुनाव होता है, उसी क्षेत्र के हिस्सेदार उम्मीदवार में भाग लेते हैं। प्रत्येक स्थानीय मण्डल में एक तो उसका सभापति,

एक उपसभापति, एक मन्त्री और कम से कम तीन सदस्य होते हैं। इस मंडल को केन्द्रीय मंडल के बनाये हुये उपनियमों के अनुसार अपने यहाँ की बैंकिंग का व्यवसाय चलाने का अधिकार है। साथ ही यह स्थानीय दफ्तरों में रखे हुये शाख रजिस्ट्रारों की जाँच करते हैं। उनकी अदला-बदली की और हिस्सों के हस्तान्तरित होने की स्वीकृति अस्वीकृति देते हैं और उनके प्रमाण-पत्र तैयार करते हैं।

फिर, एक केन्द्रीय मंडल है जिसके निम्न सचालक होते हैं .—

(१) स्थानीय मंडलों के सभापति, उपसभापति और मन्त्री—सब मिलाकर नौ सचालक ,

(२) प्रत्येक स्थानीय मंडल के सदस्यों में से, उन्हीं के द्वारा उन्हीं में से चुना हुआ एक-एक सदस्य—३ सचालक ,

(३) एक व्यवस्था सचालक (Managing Director)—इसे केन्द्रीय मंडल स्वयं ही मनचाही शर्तों पर अधिक-से-अधिक पाँच वर्षों के लिये चुनता है। इनके बाद फिर भी यह प्रत्येक बार, अधिक से अधिक पाँच वर्षों के लिये चुना जा सकता है।

(४) सपरिषद गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त अधिक-से-अधिक ऐसे दो सचालक जो उसके यहाँ के अफसर न हों। ये प्रति वर्ष नियुक्त किये जाते हैं। हाँ, इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है ,

(५) केन्द्रीय मंडल के द्वारा निर्वाचित एक उप-व्यवस्था सचालक (Deputy Managing Director);

(६) सपरिषद गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त एक सरकारी अफसर।

(५) में दिया हुआ उप व्यवस्था सचालक, (१) में दिये हुये मन्त्री और (६) में दिया हुआ अफसर—ये लोग प्रत्येक बैठक में सम्मिलित तो हो सकते हैं किन्तु अपने मत नहीं दे सकते। हाँ व्यवस्थापक सचालक की अनुपस्थिति में उप-व्यवस्थापक सचालक भी मत दे सकता है।

केन्द्रीय मंडल बैंक के सभी कामों पर दृष्टि रखता है। फिर, उसकी जितनी भी शक्तियाँ हैं, उन सबका यही प्रयोग करता है। संक्षेप में यह बैंक के वे सभी काम करता है, जिन्हें विधान द्वारा अथवा इसने स्वयं स्थानीय मंडलों को नहीं सौंप दिया है। अपनी और स्थानीय मंडलों की सुविधा के लिये इसने इन सब कामों के सम्बन्ध में कुछ उपनियम भी बना लिये हैं।

समस्त हिस्सेदारों की माधायण तथा विशेष बैठक बुलाने के लिये भी विधान में हुए हैं। इसी तरह से प्रत्येक क्षेत्र के हिस्सेदारों की बैठक भी बुलाने के लिये नियम हैं।

बैंक के करने योग्य व्यवसाय

बैंक निम्न व्यवसाय कर सकता है :—

(१) यह निम्न जमानतों के आधार पर ऋण और नकद साव्य दे सकता है :—

(क) स्थानीय सरकार अथवा सीलोन की सरकार के अथवा अन्य सत्ताओं के स्टॉक, कूट तथा दृष्टी सिम्प्योरिटियों के और रिजर्व बैंक के हिस्सों के आधार पर,

(ख) सरकार द्वारा गहायता प्राप्त उन रेनों की सिम्प्योरिटियों के आधार पर, जिन्हें सरिपद गवर्नर-जनरल ने लागत लगाने के योग्य मानो-नीत कर दिया है उनके आधार पर,

(ग) उन ऋण पत्रों इत्यादि के आधार पर, जिन्हें निम्न सत्ताओं ने निकाले हैं :—

ब्रिटिश भारत^१ के किमी भी व्यवसायिना मडल द्वारा पास किये गये विधान के अनुसार किमी भी सत्ता द्वारा निकाले हुये अथवा;

किमी जिला अथवा म्युनिस्वल बोर्ड अथवा कमेटी द्वारा निकाले हुये अथवा

किसी देशी रियासत के राजा द्वारा निकाले हुये और सरिपद गवर्नर-जनरल द्वारा स्वीकृति हुये अथवा,

किमी सीमित दायित्व वाली कम्पनी द्वारा निकाले हुये किन्तु केन्द्रीय मडल द्वारा निर्धारित शर्त पूरा करने पर,

(घ) गिरवी रने हुए माल के आधार पर अथवा केन्द्रीय मडल की स्वीकृति पर एक विशेष प्रस्ताव द्वारा पास करा कर, माल अरने नाम कराकर उसके आधार पर अथवा उनके आधार पत्रों पर जमा करा कर अथवा उन पर बेचान करा कर, उनके आधार पर,

(ङ) स्वीकृति किये गिलों के आधार पर और पाने वाले धनियों द्वारा

चेचान किये गये प्रण-पत्रों के आधार पर और दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के अथवा फर्मों द्वारा लिये हुए संयुक्त और पृथक् प्रण पत्रों के आधार पर। दो व्यक्ति तभी पृथक्-पृथक् माने जायेंगे जब यह साम्ने से सवन्धित नही, और

(च) सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के हिस्सों के आधार पर अथवा जब (क) से (घ) तक दी हुई जमानतें तो पहले दी गई हैं और फिर अचल संपत्ति अथवा उसके सम्बन्ध के अधिकार पत्र दिये गये हैं, तब उनके आधार पर और यदि पहले (ङ) में दी हुई जमानत दी गई है तब केन्द्रीय मंडल द्वारा स्वीकृत शर्तों ऊपर पर दी हुई जमानतों के आधार पर। भारत सचिव^१ को बगैर जमानत के भी ऋण दिया जा सकता था।

(२) यदि किसी ऋण के सम्बन्ध में कोई प्रण-पत्र, ऋण-पत्र, स्टॉक (माल), रसीद बाण्ड (Bond), वार्षिक भत्ता (Annuity), स्टॉक, हिस्से सिक्योरिटियाँ अथवा माल अथवा माल सम्बन्धी अधिकार-पत्र बैंक के हाथ में आ जाते हैं तो, ऋण की वापिसी न होने पर वह उन्हें बेच और उनके मूल्य वसूल कर सकता है।

(३) वह कोर्ट आफ वाड्स को उनके हाथ में अथवा उनकी व्यवस्था में जो स्टेट हो, उनके आधार पर उन्हें ऋण दे सकता है और उसे व्याज सहित वसूल कर सकता है। किन्तु ऐसे ऋण उस स्थान की स्थानीय सरकार की स्वीकृति पाने के बाद ही और कृषि के कामों के लिए तो नौ महीनों के लिए और अन्य कामों के लिए छः महीनों से अधिक के नहीं होने चाहिये।

(४) यह विनिमय बिल और दूसरी हस्तान्तरित होने वाली सिक्योरिटियाँ लिख, स्वीकृति कर, भुना, क्रय और विक्रय कर सकता है।

(५) यह प्रथम में (क) से (ग) तक में दी हुई जमानतों में अपनी लागत लगा सकता है और उन्हें वहीं पर दी हुई अन्य तरह की जमानतों में बदल भी सकता है।

(६) यह आर्डर बैंक, पोस्ट बिल और साख-पत्र (Letters of credit) अथवा यही सब देखनहार और मार्ग पर देय शर्त के अतिरिक्त बना, निकाल और चला सकता है।

(७) यह मुद्रा के रूप में प्रयुक्त ऐसे ही माना और चांदी गने और बेच सकता है ।

(८) यह नामा प्राप्त कर सकता है और किसी भी जगह पर दिगम रख सकता है ।

(९) यह लेट, गवाहिरात, अभियोग-पत्र अथवा अन्य मूल्यवान् वस्तुओं में किसी भी जगह पर गवाह के रूप में रखा सकता है ।

(१०) यदि कोई चल प्रपत्ति अचल सम्पत्ति इनमें हाथ में आ जातो है तो यह उसे बेच कर उसके मूल्य की वसुली कर सकता है । साथ ही यदि इसके पास इनके कोई अभिकार आ जायें तो उन्हें भी यह ले, रखा और हर प्रकार के प्रयोग में भी ला सकता है ।

(११) यह कमीशन पर कोई अर्थ सम्बन्धी आदमी काम कर सकता है और जमानत पर अथवा बिना जमानत के ही किसी प्रकार की दत्ति पूर्ति या प्रतिभू (Surety-ship) का दायित्व ले सकता है ।

(१२) यह किसी भी स्टेट की सावक (Executor) की, वरोदारी (Trustee) की अथवा किसी अन्य स्थिति में व्यवस्था कर सकता है । साथ ही यह किसी सार्वजनिक कम्पनी के सात पत्रों और हिस्सों को कमीशन पर खरीद, बेच, हस्तान्तरित कर और अपने पास रखा सकता है । यह उनके मूल्य, व्याज, लाभ की बँटनी प्राप्त भी कर सकता है । अन्तिम, वह उपर्युक्त रकम को देश में अथवा बाहर कहीं भी सार्वजनिक अथवा निजी मिलों द्वारा पहुँचा भी सकता है ।

(१३) यह विदेशों में देय विनिमय के बिलों को लिख और ऐसे ही सात-पत्र निकाल भी सकता है ।

(१४) यह विदेशों में देय विनिमय बिल चाहे वह किसी भी अवधि के ही क्यों न हों (किन्तु यदि वह कृपि के सम्बन्ध के हैं तो नौ महीनों से अधिक के बाद देय न हों और यदि अन्य किसी व्यवसाय के सम्बन्ध के हैं तो छ महीनों से अधिक के बाद देय न हों), बेच सकता है ।

(१५) यह अपने व्यवसाय के लिए अपनी सम्पत्ति और अपने पाउने की जमानत पर अथवा बिना जमानत के ही द्रव्य उधार भी ले सकता है ।

(१६) समय समय पर यह प्रेसीडेन्सी बैंकों के पेन्शन कोष में रकम डाल सकता है ।

(१७) ऊपर जिन व्यवसायों के विषय में कहा गया है, उन्हें करने में अन्य जिन कामों के करने की आवश्यकता प्रसङ्गवश आ जाय, उन्हें भी यह बैंक कर सकता है ।

जो काम यह नहीं कर सकता है

ऊपर जो काम दिये गये हैं, उनके अतिरिक्त यह बैंक अन्य काम और विशेषतः निम्न काम यह नहीं कर सकता --

(१) (३) और (४) में लैसा दिया हुआ है उसके अनुसार यह छ' महीनों अथवा नौ महीनों से अधिक के लिये ऋण नहीं दे सकता । साथ ही ये इसके स्वयं के स्टॉक और हिस्सों पर भी नहीं दिये जा सकते । इसी तरह से (३) में दिया हुआ है, उसके अतिरिक्त अचल सम्पत्ति अथवा उनके पत्रों की जमानतों पर भी ये नहीं जा सकते ।

(२) प्रत्येक व्यक्ति अथवा सामे को जितने तक का ऋण देने के लिए इसकी स्वीकृति तालिका में अथवा बिल भुनाने के लिए लिखा हुआ है उससे अधिक का ऋण नहीं दिया अथवा बिल नहीं भुनाया जा सकता । हाँ, यह ऋण प्रथम में (क) से (घ) तक दी गई जमानतों पर दिया जा सकता है ।

(३) किसी व्यक्ति के अथवा सामे के ऐसे किसी अच्छा अधिकार देने वाले साख-पत्रों की जमानत पर न तो नकद साख दी जा सकती है, न ऋण दिया जा सकता है, न उसे खरीदा अथवा भुनाया जा सकता है जो उसी शहर में देय हो जहाँ वह भुनाया जा रहा हो और जिसमें कम से कम ऐसे दो व्यक्ति अथवा सामों के पृथक् पृथक् दायित्व न हों, जिनमें परस्पर सामे का सम्बन्ध नहीं है ।

(४) ऐसे विनियम साथ साख पत्रों की जमानत पर न तो नकद साख खाता खोला जा सकता है, न ऋण दिया जा सकता है, न उन्हें खरीदा जा सकता है और न उन्हें भुनाया जा सकता है जिनमें धरोहर की रकम नहीं लगाई जा सकती अथवा जो यदि कृषि की सहायता के लिए लिखे गए हैं, तो नौ महीनों के बाद और जो किसी अन्य काम के लिये लिखे गये हों तो छ' महीनों के बाद पकते हों ।

रिजर्व बैंक का इम्पीरियल बैंक से सम्बन्ध

रिजर्व बैंक विधान की ४४वीं धारा में रिजर्व बैंक और इम्पीरियल बैंक

के बीच में एक समझौते की बात लिखी हुई थी और उनके तीसरे परिशिष्ट में यह शर्त दी हुई थी, जिनका उल्लेख होना आवश्यक था। अतः, यह समझौता किया गया और संप्रतिष्ठ गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बाद इस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हुए। इसके अनुसार इम्पीरियल बैंक, उन मंत्रालयों में गिर्बत बैंक का अगला अद्वितीय नियुक्त किया गया, जहाँ इम्पीरियल बैंक का दफ्तर तो था किन्तु, रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग का कोई दफ्तर नहीं था। इम्पीरियल बैंक के रिजर्व बैंक की ओर से उन मामलों के करने के प्रति फलस्वरूप जिन्हें यह उन स्थानों पर पहले ही में संप्रतिष्ठ गवर्नर जनरल की ओर से करता आ रहा था, रिजर्व बैंक को उन्हें उस तत्काल समय पर जो यह उस स्थानों में वर्ष भर में पाता है अथवा देता है, एक कमीशन देना पड़ता है। प्रारम्भ में पहले के इस वर्षों में तो यह पहले के २३० करोड़ रुपये तो १ आना प्रतिशत या और बाकी समय पर दो पैसा प्रतिशत था। यह अथर्विगत जाने पर पहले पाँच वर्षों के लिए, इस कमीशन का निश्चय इम्पीरियल बैंक के यह काम करने में जो कुछ वास्तविक व्यय हुआ था, उसे आँचने के बाद करने के लिए है हुआ था। अतः, यह सन् १९४५ में हुआ। उसके अनुसार कमीशन की दर प्रथम १५० करोड़ रुपये के लिये १ आना प्रतिशत, दूसरे १५० करोड़ रु० के लिये २ पैसा प्रतिशत तथा ३०० करोड़ रु० के ऊपर ३०० करोड़ रु० के लिए एक पैसा प्रतिशत और शेष के लिये ३८ प्रतिशत निश्चित हुआ था। साथ ही रिजर्व बैंक ने इम्पीरियल बैंक को उसकी उतनी ही शाखाएँ खुली रहने देने के लिये, जितनी रिजर्व बैंक के खुलने के समय थीं। प्रथम पाँच वर्षों तक ८ लाख रुपये प्रति वर्ष, दूसरे पाँच वर्षों तक ६ लाख रु० प्रति वर्ष और तीसरे पाँच वर्षों तक ४ लाख रु० प्रतिवर्ष देने का वायदा किया था। इम्पीरियल बैंक अपनी कोई ऐसी शाखा बन्द करके, जो इस समझौते को करने के समय थी, कोई नयी शाखा नहीं खोल सकता। हाँ, रिजर्व बैंक किसी भी जगह पर, चाहे वहाँ उस समय तक इम्पीरियल बैंक उसके अद्वितीय का काम क्यों न करता रहा हो, अपनी शाखा बन्द चाहे उस खोल सकता है।

यह समझौता १५ वर्षों के लिये हुआ है। इसके बाद इसे कोई भी धनी ५ वर्षों की सूचना देकर समाप्त कर सकता है। साथ ही यह इस बात पर भी निर्भर है कि इम्पीरियल बैंक अपनी स्थिति बराबर अच्छी रखे। यदि रिजर्व बैंक के केन्द्रीय मंडल के विचार में किसी समझौते में यह आ जाता है

कि वह ऐसा नहीं कर रहा है अथवा समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है तब वह सपरीषद् गवर्नर जनरल के पास जा सकता है और वह इम्पीरियल बैंक को इस समझौते के सम्बन्ध में अथवा सरकारी द्रव्य की अथवा रिजर्व बैंक के नोट चलाने वाले विभाग के सम्पत्ति और पाउने की रक्षा के सम्बन्ध में कोई भी आदेश दे सकता है और उसे न पालन करने पर समझौता समाप्त कर सकता है।

इम्पीरियल बैंक से होने वाले लाभ

इम्पीरियल बैंक से अनेकों लाभ हुये हैं। वे निम्नांकित हैं,—

(१) जब प्रेसीडेंसी बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक बना था तब प्रेसीडेंसी बैंकों की कुल मिलाकर ५६ शाखाये थीं। इम्पीरियल बैंक तथा भारत सचिव के बीच में इस सम्बन्ध का जो समझौता हुआ था उसके अनुसार इम्पीरियल बैंक को प्रथम पाँच वर्षों के अन्दर १०० नयी शाखाओं की स्थापना करने के लिये वाध्य किया गया था। मार्च सन् १९२६ तक इसने अपना दायित्व पूरा कर दिया था और कुल मिलाकर १०२ नयी शाखाये खुल चुकी थीं। सन् १९४७ के अन्त में इसके ४४४ दफ्तर थे। इसने बहुत से स्थानों में जब अपने दफ्तर खोले थे, तब वहाँ पर कोई भी आधुनिक बैंक नहीं था। हाँ, उसके बाद कहीं-कहीं अन्य बैंकों के भी दफ्तर खुल गये हैं। किन्तु अब भी लगभग १०० के ऐसी जगहें हैं जहाँ केवल इम्पीरियल बैंक के ही दफ्तर हैं। इसके यह अर्थ है कि इन स्थानों को केवल इम्पीरियल बैंक के ही होने के कारण बैंकिंग का लाभ मिल रहा है।

(२) इसमें जनता का विश्वास पैदा हो गया है। हम जानते हैं कि सम्मिलित पूँजी वाले बैंक बराबर फेल होते रहते हैं। अतः, लोगों का उन पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। इम्पीरियल बैंक सन् १९३४ तक तो सरकार का भी बैंक था। अतः, लोग समझते थे कि यह फेल नहीं होगा। देश के प्रमुख बैंक अर्थात् रिजर्व बैंक के इसके अकेले अदतिये होने के कारण आज भी इसकी एक विशेष स्थिति है। इसके कारण इसमें द्रव्य जमा होता रहता था और है। फिर, इसने कुछ बैंकों की तो उनके सकट के समय सहायता की ही है, अतः, इससे इसने उन्हें फेल होने से भी बचाया है। इसका फल यह हुआ कि लोगों का उन सब पर भी कुछ न कुछ अधिक विश्वास तो अवश्य ही जमा। इससे

इम्पीरियल ग्रीक दूगरे देशों में जमा जदी। जिन स्थानों में इसने अपनी शाखायें खोलीं उनमें बहुत कुछ जमा इसके यहाँ पर स्थित था। अतः, इस तरह का कहना है कि इम्पीरियल बैंक ने देश की पैली चलायमान रूप से उसे अवश्य ज्ञान पहुँचाया है।

(३) जिन स्थानों में इसने अपनी शाखायें खोलीं वहाँ के लोगों ने इससे ऋण भी पाया। इतना ही नहीं बल्कि व्याज की दर भी बहुत कुछ कम हो गई। इसके गतिरिक्त जहाँ पर इसकी शाखायें नहीं हैं, वहाँ पर भी उनके मुसलाने के दर के मारे अन्य बैंकों ने कम दर का ही व्याज लिया। केवल देशी महाजनों ही ने नहीं बल्कि आप्रानिक लोगों ने भी यही किया। चूँकि इम्पीरियल बैंक के पास पले सरदार का द्रव्य भी रखा था, अतः, वह उसे भी प्रयोग में ला सकता था। ऐसा कि इस ज्ञान है इसे १२ करोड़ २० की गतिरिक्त करन्सी प्राप्त कर लेने का अधिकार भी दे दिया गया था। इसने तैली के समय व्याज की दर अवश्य बहुत कुछ बढ़ने में तो रुक ही जाती थी।

(४) इसकी शाखाओं को बहुत अधिक सख्या होने के कारण यह द्रव्य भेजने की भी बहुत सुविधा दे सकता था। फेला यही नहीं बल्कि अन्य बैंक भी इसी कारण इस काम में अधिकधिक सुविधा दे सकते थे। साथ ही द्रव्य भेजने का खर्च भी बहुत कम लिया जाता था।

(५) ऐसा सोचा गया था कि यह तिलों की अधिकधिक सख्या में डिस्काउट करने उनका प्रयोग भी बढ़ा सकेगा। किन्तु यह नहीं हो सका। दूसरे बैंक इसे अपने तिलों के निरक्षण नहीं बताना चाहते थे। उनका यह ध्यान था कि यह उससे लाभ उठाकर उनकी प्रतियोगिता करेगा। यह माल पर उधार देकर मिल डिस्काउट करके और माँग पर देय ट्राफ्टों और टी० टी० गीट करके कृषि की उरज के व्यापार में बड़ी सहायता करता है। इसने अपनी हुडी की दर और बाजार के व्याज के दर में भी बहुत कुछ अन्तर मिटा दिया है। इसी तरह से इसने बम्बई, फलक्ता और मद्रास के बाजारों के व्याज की दरों के अन्तर को भी बहुत कुछ कम कर दिया है।

(६) इसने प्रान्तीय और जिला सहकारी बैंकों से भी बहुत घना सम्बन्ध उत्पन्न कर लिया है और यह उन्हें जमा से अधिक निकालने, इत्यादि की भी सुविधा देता है।

(७) इसने अपनी बड़ी-बड़ी शाखाओं में निकासयुक्त भी स्थापित कर दिये

ये, जिससे बैंकों को इस सम्बन्ध की सुविधा प्राप्त हो सकी। इसके फलस्वरूप बैंकों का प्रयोग भी बढ़ा।

(८) यह सरकारी ऋण निकालता था और उसकी व्यवस्था करता था। अतः, जिन-जिन शहरों में इसकी शाखाएँ थीं, उन-उन शहरों के लोग सरकारी साख-पत्रों में रुपया लगाने लगे।

(९) इसकी साख लन्दन में भी थी। अतः, इसके ग्राहकों की सहायता के मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से सम्बन्ध रखने का अवसर प्राप्त हो सका।

रिजर्व बैंक की स्थापना का इसकी उपयोगिता पर प्रभाव

रिजर्व बैंक की स्थापना का इसकी उपयोगिता पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। जनता का अब भी इस पर पूर्ण विश्वास है। सच तो यह है कि इसके अब बहुत से बन्धनों से मुक्त हो जाने के कारण यह जनता के लिये और भी उपयोगी हो गया है। अब यह अधिक दिनों तक के लिये और बहुत सी जमानतों पर ऋण दे सकता है। फिर, अब यह विनिमय का व्यवसाय भी कर सकता है।

इम्पीरियल बैंक तथा जनता

उपर्युक्त से यह तो स्पष्ट ही है कि इम्पीरियल बैंक जनता के लिये, अपने ग्राहकों के लिये, सम्मिलित पूँजी वाले और सहकारी बैंकों के लिये तथा सरकार के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। यदि हम प्रथम को अर्थात् साधारण जनता को ही पहले ले लें, तो बैंकिंग के व्यवसाय के बढ़ जाने से उसको भी बहुत लाभ हुआ है। हमें यह तो ज्ञात ही है कि इसने किस तरह से अपनी नयी-नयी शाखाएँ खोलकर और सरकार का बैंकर बन कर तथा जब से रिजर्व बैंक स्थापित हुआ है, तब से उसका एकमात्र अद्वितीय बनकर और सबसे मुख्य तो सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों को सहायता देकर साधारण जनता का विश्वास अपने ऊपर जमा लिया है और उसमें बैंकिंग की आदत डाल दी है। इसके अतिरिक्त इसकी बहुत सी शाखाओं के होने के कारण इसको जो बहुत से कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ी, उससे देश के बहुत से बैंकिंग का काम जोख गये हैं। इस तरह से इस देश में बैंकिंग का धन्धा भी चल निकला है और उससे लोगों की जीविका का प्रश्न भी कुछ हल हो गया है।

इम्पीरियल बैंक तथा उनके ग्राहक

सरकार की रणनीति इसका नाम देने के माध्यम से इसका उनके अपने प्रयोग में लाने का प्रयास यह करने का प्रयास को प्रतीति और देना और उनसे हम व्याज लेना उनसे प्रत्यक्ष लाभ पाने का मतलब था । फिर, आवश्यकता पड़ने पर यह सरकार के कृन्ती विभाग ने प्रतिरिक्त करने की लेकर तैयारी और मन्त्री के समय में व्याज की दर को बहुत कुछ कम कर सकता था । इससे प्रतिरिक्त हमारी एक ग्राहक लन्दन में है । इससे एक ठा वर लाभ है कि इसके ग्राहकों का इसका लाभ भत्ता व एक मध्य द्रव्य राजा ने मोटा सम्पत्ति स्थापित हो सकता है । दूसरे, यह प्रयोजन व्यापारियों की स्थिति के सम्बन्ध में स्वयं पता लगा करके उन्हें अपने उन ग्राहकों को बना सकता है जो उनसे व्यापारिक सम्पत्ति स्थापित करना चाहते हैं । तीसरे, यह स्थानीय उद्योगों के लिये लन्दन में मास उत्पन्न कर सकता है और अपने भारतीय ग्राहकों की वृत्ति को बढ़ा लगा सकता है । चौथे और अन्तिम, अपनी बहुत सी शाखाओं के होने के कारण यह अपने ग्राहकों को वैमिंग की अधिकाधिक सुविधाएँ दे सकता है ।

इम्पीरियल बैंक तथा सम्मिलित पूँजी वाले बैंक

इम्पीरियल बैंक सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों के खिलाफ को फिर से डिस्काउट करके तथा उनकी अन्य प्रकार से सहायता करके उनके मित्र तथा सरकारी काम करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था । किन्तु इसमें यह बिल्कुल भी सफल नहीं हो सका । उनका प्रतियोगी होने के कारण यह उनके हृदय में अपनी ओर से विश्वास नहीं जमा सकता और इसी कारणवश यह उपर्युक्त कार्यों में सफल भी नहीं हो सकता । सम्मिलित पूँजी वाले बैंक इसलिये अपने मिल इससे नहीं डिस्काउट कराते थे कि ऐसा करने से इसे उनके सम्बन्ध की सब बातें मालूम हो जायेंगी और इससे यह उनके काम छीन लेगा । साथ ही वह इससे अन्य प्रकार से भी भ्रष्ट लेने में डरते थे । उन्हें यह आशंका थी कि यह जनता में कहीं उन्हें बदनाम न कर दे । कभी कभी तो इस पर उन बैंकों का पक्षपात करने का भी दोषारोपण किया जाता था जिनकी व्यवस्था विदेशियों के हाथ में थी । किन्तु इसने अन्य बैंकों की भी कई बार सहायता की और इससे अवश्य ही उन्हें फेल होने से बचाया । अलायन्स बैंक आफ

शिमला के फेल होते ही इसने उसकी समस्त जमा का ५० प्रतिशत उमी समय देकर उसके ग्राहकों की बड़ी ही मदद की । इसने उनकी अन्य प्रकार से भी सहायता पहुँचाई । इसने उन्हें द्रव्य भेजने की और चेकों के पारस्परिक निपटारे की भी सुविधाये दीं । इसके अतिरिक्त इसने उनके सामने अपने काम करने का दृढ़ इतना ऊँचा रक्खा कि जो अन्य बैंकों के लिए आदर्श स्वरूप था और जिसे उनमें से कुछ ने तो अपनाने का भी प्रयत्न किया ।

इम्पीरियल बैंक तथा सहकारी बैंक

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इम्पीरियल बैंक सहकारी बैंकों को जो जमा से अधिक रकम निकालने की आज्ञा देकर तथा अन्य प्रकार से ऋण देकर उनकी सहायता करता है । उनसे इसका बहुत अच्छा सम्बन्ध रहा है ।

इम्पीरियल बैंक तथा सरकार

इम्पीरियल बैंक तथा भारत सचिव के बीच में जैसे ही समझौता हो गया वैसे ही सरकार ने उन स्थानों पर अपने खजाने बन्द कर दिये, जिनमें इसके दफ्तर थे । फिर, यह दफ्तर बराबर बढ़ते गये । अतः, जैसे-जैसे यह बड़े वैसे वैसे ही सरकार के खजाने बन्द होते गये । इससे उसका बहुत कुछ व्यय बच गया । दूसरे, सरकार उन स्थानों के बीच में हंडियाँ (Currency transfers) निकालने की मर्यादा से भी बच गई, जिन स्थानों में इसके दफ्तर थे । तीसरे, यह उसे अपने सभी दफ्तरों में उसकी आवश्यकता के अनुसार रुपये देने लगा । अन्तिम यह कि इसके उसके ऋण की व्यवस्था करने के कारण उसमें बहुत ही सुविधा होने लगी । छोटे-छोटे लोग भी उसमें रुपया लगाने लगे ।

इम्पीरियल बैंक तथा विदेशी बैंक

इम्पीरियल बैंक की स्थापना से विदेशी बैंकों की तनिक भी हानि नहीं हुई जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, सन् १९३४ के पहले तो यह विनिमय का व्यवसाय कर ही नहीं सकता था, अतः इसका उनसे प्रतियोगिता करने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था । किन्तु इसके बाद भी जब से इसे विनिमय का व्यवसाय करने की आज्ञा मिल गई है, तब से भी इसने इस व्यवसाय को

तमना प्राप्त नहीं किया है। अतः, उनकी प्रतियोगिता नहीं की। किन्तु, हमने सम्भावनाओं और उनके व्यवसायों के बीच मर्मदा बहुत अन्तर्गत सम्पन्न होते गे।

इम्पीरियल बैंक की वर्तमान स्थिति और उनके काम

इम्पीरियल बैंक अपनी सम्भावना के मन्त्र ने ही बहुत ही उच्च तथा गौरवमय स्थिति में है। मन्त्र १९३४ तक वो यह सम्पन्न था और चीन का बैंक था और इसके बाद से यह देश के प्रमुख बैंक प्रगतिशील बैंक का एकमात्र सदस्य है। इसने जनता का हित पर बहुत विचारम जम गया है और इसी से उसके पास अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत बड़ा अधिक जमा है। दफ्तरी की रकबा की दृष्टि से (मन्त्र १९४६ में ३०७), बैंक की दृष्टि से (५६२, ५०,००० रुपये) मुद्रित की भी दृष्टि से (६ करोड़ रुपये से अधिक), जमा की दृष्टि से (२२८६६ करोड़ रुपये) और प्रत्येक दृष्टि से यह देश के सब से बड़े बैंकों में भी यहाँ तक की स्वयं प्रमुख बैंक से भी बड़ा है। यदि हम किमा एक वर्ग के सब बैंकों की भी एक साथ ले लें तो जायदा यह उनमें से भी बहुत ही भी बहुत बड़ा है।

इसके अपरिमित साधनों के कारण सम्मिलित बैंक वाले इस अपने अपना बहुत भयानक प्रतिद्वन्दी सम्भलते हैं। इसने बहुत सी शाखाएँ खोल ली हैं और इसने वहाँ पर उनका एकाधिकार जाता रहा है। इसने मरिज्यों में भी अपनी उपशाखाएँ खोल ली हैं और यहाँ पर यह दृष्टि के व्यापार की सहायता करने पर भी उनका प्रतिद्वन्दी बन गया है। इसके पहले यह केवल छ महिना तक के लिये ही ऋण देता था किन्तु जैसा कि हमने पहले ही ने ज्ञात हो चुका है अब यह नौ महिनों के लिये भी ऋण दे सकता है। फिर, अब यह सब तरह की जमानतों पर ऋण देता है। उदाहरणार्थ माल, अचल सम्पत्ति, उनके अधिकार पत्र, सिक्कोरिटियाँ इत्यादि। यह जो व्याज लेता है उसकी दर भी अन्य बैंकों की व्याज की दर से कम है।

अब यह विनिमय का व्यवसाय भी कर सकता है। किन्तु अभी तक इसने यह काम प्रारम्भ नहीं किया है। अतः, इसकी विनिमय के बैंकों से कोई प्रतियोगिता नहीं पड़ो है। किन्तु यह उससे बहुत अच्छी तरह से प्रतिद्वन्द्विता कर सकता है।

इसकी व्यवस्था बहुत कुछ गैरभारतीयों के हाथ में है। हमने भारतीयों को ऊँची-ऊँची जगहें बहुत कम दी हैं। इससे केवल इसका व्यय ही बहुत अधिक नहीं है, वरन् यह भारतीयों की दृष्टि में गिर गया है। किन्तु विश्वास-पात्रता की दृष्टि से यह उनमें बहुत ही प्रिय है।

इम्पीरियल बैंक की भविष्य के लिये नीति

इम्पीरियल बैंक की भविष्य के लिये यही नीति होनी चाहिये कि उसका दृष्टिकोण राष्ट्रीय हो। इसके कर्मचारियों को जनता की दृष्टि से यह निकाल देना चाहिये कि यह भारतीयों के प्रति उदासीन है। यदि ऊँचे-ऊँचे पद भारतीयों को दे दिये जायें तो शायद स्थिति बहुत कुछ सुधर जाय और इधर सुबर भी रही है। इससे उन लोगों के लोगों से अधिक सम्बन्ध में आने से हमका व्यवसाय भी बढ जायगा। फिर, हमसे इसके व्यय में भी कमी पड़ेगी। इसे भारतीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन देना चाहिये। इसके अतिरिक्त इसे भारतीय बैंक की व्यर्थ की प्रतिद्वन्द्विता नहीं करनी चाहिये। ऐसे अन्य बहुत ने काम हैं जिन्हें यह कर सकता है। प्रथम तो अब जब कि इसे विनिमय का काम करने की आशा मिल गई है, तब इसे यह काम अवश्य करना चाहिये। जैसा कि आगे चलकर मालूम होगा विदेशी बैंक जिनके हाथ में हमका एकाधिपत्य है, देश के हित के विरुद्ध काम करते हैं। वे अपने अपने देशों के व्यवसायियों का पक्ष करते हैं और भारतीयों के हित की अपेक्षाकृत उन्हीं के हित का अधिक ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसे भारतीय बैंकों की बहुत बड़ी आवश्यकता है जो उनके एकाधिपत्य को तोड़ सकें और इम्पीरियल बैंक को छोड़कर कोई अन्य बैंक ऐसा कर नहीं सकता। इसे उद्योग-धन्वों की सहायता करने में भी बड़ी दिलचस्पी दिखानी चाहिये। भारतीय बैंकिंग में जो ऐसा काम करने वाले बैंकों की कमी है, उसे यह बहुत ही अच्छी तरह से पूरी कर सकता है।

बैंक जो कुछ करता है, उसी में बहुत कर सकता है। प्रथम तो इसे देशी महाजनों के मिल और उदारता से डिस्काउण्ट करके, उनकी कमी पूरी करनी चाहिये। इसके लिए इसे अपना डिस्काउण्ट दर की व्याज दर से कुछ कम रखना पड़ेगा। दूसरे, इसे देशी महाजनों के प्रति अधिक उदार होना पड़ेगा। उसे बिलों और चेकों की बसूली के लिये उन पर उसी प्रकार विश्वास करना

चाहिये जिन प्रकार यह दूसरे बैंकों पर करता है। जहाँ-जहाँ इसके स्वयं के दफ्तर नहीं खुल सकते, वहाँ वहाँ यह उनसे लाभ का सकता है।

इसका राष्ट्रीयकरण

विक्टोरिया के राष्ट्रीय क्लब की भाँति के मामला-य इसके राष्ट्रीयकरण की भाँति भी उठी थी और सरकार ने यह कहा भी था कि ऐसा होगा। किन्तु फरवरी, १९४६ में राज्य मन्त्रि ने यह कह दिया कि ऐसा करना सुनामिच नहीं होगा। हाँ, इसे और लाभदायक बनाने के लिये दसके विधान में कुछ संशोधन किये जायेंगे। आशा है कि इन संशोधनों से हमारे दोष दूर हो जायेंगे।

प्रश्न

(१) इम्पीरियल बैंक पूर्णरूप से केन्द्रीय बैंक क्यों नहीं बनाया गया? इस सम्बन्ध में यह भी बताया कि इससे इसके व्यापारिक बैंकों के काम करने के अधिकार छीन लेने से किन-किन बातों का डर था।

(२) इम्पीरियल बैंक जो काम कर सकता है, इसके जो व्यवस्थापक मण्डल हैं उनकी रचना में तथा इसके कामों में सपरिषद गवर्नर जनरल के हस्तक्षेप करने की शक्ति में, इसके सन् १९३४ के विधान से कौन-कौन से परिवर्तन कर दिये गये हैं?

(३) इम्पीरियल बैंक के केन्द्रीय मंडल की रचना कैसे होता है? इसके स्थानीय मण्डलों के विषय में भी आप जो जानते हैं उसके विषय में भी लिखिये।

(४) इम्पीरियल बैंक कौन कौन काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता?

(५) इम्पीरियल बैंक और रिजर्व बैंक में जो समझौता हुआ था उसमें कौन-कौन सी बातें थी? इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

(६) इम्पीरियल बैंक की स्थापना से कौन-कौन से लाभ हुये हैं? रिजर्व बैंक की स्थापना का इसकी उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ा है?

(७) इम्पीरियल बैंक जनता के लिये, अपने ग्राहकों के लिये, सम्मिलित पूँजीवाले बैंकों के लिये, सरकार के लिये और विदेशी बैंकों के लिये कहीं तक उपयोगी सिद्ध हुआ है ?

(८) इम्पीरियल बैंक की वर्तमान स्थिति के विषय में अपनी सम्मति दीजिये । भविष्य में इसकी क्या नीति होनी चाहिये ?

अध्याय १८

विनिमय बैंक

विनिमय बैंकों के प्रधान दफ्तर भारतवर्ष के बाहर हैं । यद्यपि इनका विशेषण यह बतलाता है कि यह केवल विनिमय का ही काम करते हैं किन्तु ऐसा नहीं है । विनिमय का व्यवसाय करने के अतिरिक्त ये साधारण व्यापारिक बैंकों के काम भी करते हैं । इसके यह अर्थ हुये कि ये माँग पर वापिस होने की शर्त पर रुपया उधार भी देते हैं; लागत लगाते हैं, अन्य प्रकार से ऋण देते हैं । ब्याजिक साख-पत्र निकालते हैं, जमा प्राप्त करते हैं और आदत के अन्य कार्य करते हैं । किन्तु विशेषतः ये विदेशी मिल खरीदते और डिस्काउण्ट करते हैं तथा विदेशी मुद्रायें देते हैं और यही एक ऐसी बात है जिससे यह देश के अन्य बैंकों ने भिन्न हैं । भारतवर्ष के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता करने का काम इन्हीं के हाथ है । प्रेसीडेंसी बैंक यह काम कर ही नहीं सकते थे अतः, इन्हें इसमें विशिष्टता प्राप्त करने का बड़ा अच्छा अवसर मिल गया । फिर इम्पीरियल बैंक भी इसे सन् १९३४ तक नहीं कर सकता था और आज तक भी वह ऐसा नहीं करता । जहाँ तक सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों का प्रश्न है, उनमें से तो कोई भी कुछ दिनों पहले तक तो इसे कर ही नहीं सकता था । यह काम तभी किया जा सकता है जब इसके करने वाले के साधन बहुत अच्छे हों । हाँ, अब कुछ सम्मिलित पूँजी वाले बैंक अवश्य ऐसे हैं जो इसे कर सकते हैं, किन्तु विनिमय बैंक जो इसे बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, इससे ये उनकी बराबरी नहीं कर सकते । सेन्ट्रल बैंक ने कुछ वर्षों पहले इसे करना प्रारम्भ किया था, किन्तु वह इसमें कोई विशेष उन्नति नहीं कर सका । कुछ अन्य बैंकों ने भी इसे किया था, किन्तु उन्हें भी कोई विशेष सफलता नहीं

मिली। इस समय बैंक आफ इण्डिया अपनी जायगी और लन्दन की शान्ताओं द्वारा कुछ विनिमय का काम कर रहा है जिन विनियों ने विनिमय बैंक यहाँ मुले में जो तो हम पूर्णत्व में विहित हो है। अब हम उनकी वर्तमान अवस्था, उनके कार्य करने के तरीके और उनमें जो दोष हैं उन्हें दूर करने के तरीके देखने हैं।

वर्तमान स्थिति

इस देश में जो विदेशी बैंक काम कर रहे हैं उनकी संख्या १५ है, उनके सब मिलकर भारतवर्ष में ६५ दफ्तर हैं। इन में सबसे अधिक काम लाय-डूस बैंक ने हाथ में है। दूसरा ग्लान्ड विन्टन बैंक का मेसनल बैंक आफ इण्डिया का, चौथा चाटर्स बैंक आफ इण्डिया, ग्रान्देनिया और चारना का और पाचवां माट्टेडाल बैंक का तीसरा है। इनके यतिगिन चाटर्स बैंक आफ इण्डिया, ग्रान्देनिया और चारना ने इलाहाबाद बैंक में सम्मिलित होने के कारण जिसके बल में दफ्तर हैं, यहाँ का बहुत कुछ काम ले गया है।

क्योंकि ये बैंक अपनी भागत की स्थिति के सम्बन्ध में पहले सोई अक नती निकालन में गत, इनकी यहाँ की पूँजी और सुरक्षित कोष के विषय में कुछ नहीं ज्ञात जा सकता। किन्तु नये वैकिंग विधान ने परिस्थिति बदल दी है। अतः, अब यह अक उपलब्ध होने लगेंगे तो भी सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों और इम्पोरियल बैंक के जमा की तुलना में इनकी जमा भी कम नहीं हैं। ये माँग पर देय जमा पर भी व्याज देने हैं। अतः, भारतीय बैंकों को भी ऐसा ही करना पड़ता है जिससे हम यह कह सकते हैं कि इस दोष का दायित्व इन्हीं के ऊपर है।

नकद में इनकी जमा का प्रायः २८५ प्रतिशत रहता है।

भारतवर्ष में पहले इनकी लागत का पता नहीं था। अब, हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते।

उनके कार्य के तरीके

इनमें हमें केवल उनके यहाँ के विदेशी व्यापार को सहायता देने के तरीके देना है। इनके अन्य काम करने के तरीके तो वही हैं जो अन्य बैंकों के हैं। विदेशी व्यापार की सहायता में दो काम आते हैं। (१) भारतीय बन्दरगाहों में विदेशी बन्दरगाहों और विदेशी बन्दरगाहों से भारतीय बन्दरगाहों के बीच में

जो व्यापार होता है उसकी सहायता करना, और (२) भारतीय बन्दरगाहों से अन्दरूनी शहरों और अन्दरूनी शहरों से भारतीय बन्दरगाहों के बीच में जो व्यापार होता है उसकी सहायता करना। प्रथम के सम्बन्ध का सारा काम और दूसरे के सम्बन्ध का कुछ काम इन्हीं बैंकों के हाथ में है। इनकी अन्दरूनी शहरों में बहुत-सी शाखाएँ हैं और इनसे यहाँ के कुछ बैंक भी सम्बन्धित हैं। अतः, यह दूसरे प्रकार का काम उन्हीं से कगाने है।

भारत और विदेशों के बीच के व्यापार के हिसाब का निगटारा विलों से ही होता है। जब यहाँ से माल बाहर भेजा जाता है, तब विदेश में आयात करने वाले पर एक विल लिखा जाता है अथवा जब वह अपनी साख लटन की विल स्वीकृत करने वाली किसी कोठी में अथवा वहाँ के किसी बैंक में खोल लेता है तब यह विल उस कोठी अथवा बैंक पर हो लिखा जाता है। फिर, इसे तो यहाँ पर काम करने वाला कोई विदेशी बैंक खरीद लेता है अथवा उससे इसे भुना लिया जाता है। ऐसे विल की रकम प्रायः स्टर्लिंग में होती है। अतः, यह बैंक उसका मूल्य उस दिन के विनिमय की दर से यहाँ की करन्सी में देते हैं। प्रायः यह विल अधिकार पत्रों के साथ और ६० दिन के दर्शनी होते हैं। कभी-कभी विलकुल दर्शनी अथवा ६० दिनों से अधिक के दर्शनी विल भी लिखे जाते हैं। फिर प्रायः यह स्वीकृति पर अधिकार पत्र देने की शर्त के होते हैं, भुगतान पर अधिकार पत्र देने की शर्त के नहीं होते। यहाँ पर प्रायः सभी देशों के बैंक हैं जो अपने यहाँ के लोगों का अच्छा हवाला देते हैं जिससे वह स्वीकृति पर अधिकार पत्र देने की शर्त पर आयात कर सकते हैं। फिर, जब यह लोग किसी लटन की कोठी अथवा बैंक के यहाँ साख खोल लेते हैं तब तो हवाले की भी आवश्यकता नहीं रहती और स्वीकृति पर अधिकार पत्र देने की शर्त के ही विल लिखे जाते हैं। अतः, जब न तो अच्छा हवाला मिलता है और न वह लटन की किसी कोठी अथवा बैंक में साख ही खोल सकते हैं, तभी भुगतान पर अधिकार पत्र देने की शर्त के विल लिखे जाते हैं और ऐसा बहुत कम होता है। दर्शनी विल की अपेक्षाकृत तीन महीनों की अवधि के विलों की दर अधिक होती है। उसमें उतने दिन का व्याज भी सम्मिलित रहता है।

विदेशी बैंक खरीदे हुये अथवा डिस्काउण्ट किये हुये बिना माल के आयात करने वाले के अथवा जिस के यहाँ साख खुल जाती है, उसके यहाँ भेज देते हैं और वहाँ पर उसकी स्वीकृति हो जाती है। इसके बाद अधिकारी बैंक इसे

सुले बाजार में डिस्काउण्ट करा सकते हैं और इस तरह में यहाँ पर उनकी आय में जितना खपया गया है उनके बाजार का स्टर्लिंग उन्हें मिल जाता है। हाँ, यदि उन्हें द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती प्रमत्त पर उन्हें अधिक लाभ के कामों में नहीं लगा सकते तो उन्हें अपने ही पास रखने हैं, भुगतान नहीं।

आयात की भी दो प्रकार हैं मर्यादा की जाती है। एक तो प्रायः भारतीयों के आयात करने पर और दूसरी विदेशियों के आयात करने पर होती है। पहले में विदेशी निर्यातकर्ता इन देश के आयातकर्ता पर ६० दिनों का दर्जनों मिल लिखकर उन्हें किसी ऐसे बैंक में डिस्काउण्ट करा लेते हैं जिसका काम भारत में होता है। जो बैंक डिस्काउण्ट करते हैं उन्हें निर्यातकर्ता गिरवी पर (Letters of Hypothecation) भी दे देते हैं, जिसमें वे इन मिलों के पूर्ण अधिकारी हो जाते हैं। फिर, यह उन्हें अपनी यहाँ की आय द्वारा यहाँ के आयातकर्ता के यहाँ भेजवा देने हैं जो उन पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं किन्तु उन्हें माल के अधिकार पर नहीं प्राप्त होने। वह तो मिलों की शर्त के अनुसार केवल उनके भुगतान पर ही दिये जा सकते हैं। किन्तु उन्हें इन्हें प्राप्त करना तो आवश्यक ही रहता है क्योंकि इनके बिना माल तो छुटाया नहीं जा सकता और माल न छुड़ाने पर क्षति (Demurrage), इत्यादि देनी पड़ती है। अतः वह इन्हें बैंकों से धरोहर (Trust) पर ले लेते हैं, और माल पाने पर भी उनके धरोहर की तरह ही रहने हैं। इसके लिये वे बैंकों को धराहर की रसीद (Trust Receipt) दे देते हैं। अतः, जब तक मिलों का भुगतान नहीं हो जाता तब तक यह माल बैंक का ही समझा जाता है। इन सुविधा को दे कर ये बैंक आयात कर्ताओं से काफी लाभ उठा लेते हैं।

दूसरा तरीका प्रायः विदेशियों के सम्बन्ध में प्रयोग में लाया जाता है। भारतीयों के लिये तो बहुत कम श्रद्धा हवाला दिया जाता है। अतः, वह लन्दन का किसी कोठी अथवा वहाँ के किसी बैंक के यहाँ साख भी बहुत कम खोल पाते हैं। जहाँ ऐसा हो जाता है वहाँ यह तरीका भारतीयों के लिये भी प्रयोग में आता है। इस तरीके में विदेशी निर्यातकर्ता लन्दन की उस कोठी अथवा वहाँ के उस बैंक के ऊपर मिल कर लेते हैं जिसके यहाँ का आयातकर्ता साख खोल लेता है। यह साख किसी विनियम के बैंक के यहाँ भी खोली जा सकती है। विदेशी निर्यातकर्ता के यहाँ जब इन्वेंट मेन्ट भेजा जाता है, तभी यह

साख खोलने की सूचना भी उसके यहाँ भेज दी जाती है। ऊपर वाला धनी माल सम्बन्धी अधिकार पत्र पा जाने पर इस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। अतः, निर्यातकर्ता अब इसे भुना भी सकता है। आयातकर्ता बिल पकने की तारीख के पहले बिल का मूल्य ऊपर वाले धनी के यहाँ भेज देता है जिससे वह उचित समय पर उसका भुगतान कर देता है।

यहाँ के आयात के सम्बन्ध के बिल प्रायः स्टर्लिङ्ग ही में होते हैं। जब वह यहाँ के आयातकर्ता के ऊपर लिखे जाते हैं तब उनमें लिखने की तारीख से उनका धन वहाँ पहुँचने की सम्भावित तारीख तक का व्याज भी सम्मिलित कर लिया जाता है। यदि वह लन्दन की किसी कोठी के अथवा बैंक के ऊपर के होते हैं तब उन्हें वहीं पर वहाँ के डिस्काउण्ट की दर पर भी भुना लिया जाता है। डिस्काउण्ट की यह दर प्रथम तरह के बिलों में जो व्याज सम्मिलित होता है, उसकी दर की अपेक्षाकृत कम होती है। फिर डिस्काउण्ट तो केवल उसी अवधि के लिये जाता है जो इनके पकने में बाकी रहती है। इस सबसे यह स्पष्ट है कि गैरभारतीय आयातकर्ता और ऐसे भारतीय आयातकर्ता भी जो लन्दन में साख खुलवा सकते हैं, अन्य भारतीयों की अपेक्षाकृत बहुत लाभ में रहते हैं। इस सम्बन्ध में यह भी है कि जिन भारतीयों की साख लन्दन में खुल जाती है उन्हें साख खोलने वाले को साख के धन का १५ से २० प्रतिशत पहिले से दे देना पड़ता है। गैरभारतीयों को ऐसा नहीं करना पड़ता। अतः, इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय आयातकर्ता हर हालत में गैरभारतीय आयातकर्ता की अपेक्षाकृत हानि ही में रहता है।

हमारे प्रायः सभी आयात और निर्यात के बिल स्टर्लिङ्ग में लिखे जाते हैं। केवल चीन और जापान से जो व्यापार होता है उसके सम्बन्ध में ही वह अन्य करन्सियों में लिखे जाते हैं। चीन के व्यापार होने पर तो वे रुपयों में और जापान से व्यापार होने पर वे येन में लिखे जाते हैं।

साधारणतया तो भारत के व्यापार की विषमता (Balance of trade) भारत ही के पक्ष में रहती है। अतः, इन बैंकों के पास स्टर्लिङ्ग बच जाता है और उसे रिजर्व बैंक खरीद लेता है। वह इनके आधार पर यहाँ नोट निकालता है। जब कभी यहाँ के व्यापार की विषमता यहाँ के विपक्ष में होती है तब विनिमय बैंक रिजर्व बैंक से स्टर्लिङ्ग खरीद सकते हैं और रिजर्व बैंक स्टर्लिङ्ग सिक्योरिटियाँ बेचकर उन्हें स्टर्लिङ्ग दे देते हैं। इससे नोट वापिस हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह यदि रखना चाहिये कि रिजर्व बैंक को कोई भी बैंक १००००

अथवा उगने अधिक पाडाउ तब चार तन से ज्यादा है और इतना ही तब चार तन उससे ले मन्वा है । स्वर स्टलिन् के स्थान पर अन्य वस्तुयां भी दी-ली जा सकती हैं ।

विदेशी देशों के यहाँ के अन्तर्ग्राहीय व्यापार की सहायता करने के तरीकों में दोष

विदेशी देशों के यहाँ के अन्तर्ग्राहीय व्यापार की सहायता करने के तरीकों में जो दोष हैं वह जो ऊपर के वर्णन से स्पष्ट हो रहे हैं —

(१) हमारे निर्यात तथा आयात दोनों के मिल स्टलिन् में लिगे जाते हैं । जब उनका लन्दन के द्रव्य बाजार में भुनाया जाना आवश्यक हो जाता है । यदि मिल रुक्यों में लिगे जाने लगे तो यहाँ के द्रव्य बाजार को आवश्यक हो काफी प्रोत्साहन मिल पाय ।

(२) भारतीय आयात कर्ताओं को प्रायः मिलों के भुगतान पर अधिकार पत्र मिलने की शर्त पर आयात करना पड़ता है । यह इस कारण है कि विनिमय बैंक उनका अच्छा हवाला नहीं देते । इसने उनकी जो हानि होती है उससे तो हम अवगत हो ही चुके हैं ।

(३) जिन भारतीयों की लन्दन में सारा खुल जाती है, उन्हें भी इसके लिये १५ से २० प्रतिशत तक की रकम पहिले से ही देना पड़ती है । गैरभारतीय आयातकर्ताओं को ऐसा नहीं करना पड़ता ।

(४) मिलों के साथ जो अधिकार-पत्र होते हैं, उन्हें उनकी जाँच के लिये गैरभारतीयों के तो दफ्तरों में भेज दिया जाता है, किन्तु भारतीयों को इसके लिये पैसों के दफ्तरों ही में गुलाया जाता है ।

(५) विदेशी बैंक यहाँ के आयातकर्ताओं को अपने-अपने यहाँ के जहाजों से माल मँगाने के लिये विवश करते हैं ।

(६) जीमे के लिये भी वह उन्हें गैरभारतीय कम्पनियों ही के यहाँ बीमा कराने को कहते हैं ।

(७) विनिमय के फन्दाकटों के ढेर में पूरा करने पर भारतीय आयातकर्ताओं को पुर्माना देना पड़ता है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त इनमें कुछ अन्य दोष भी हैं —

(१) यद्यपि ये लोग यहाँ पर बहुत दिनों से काम करते चले आ रहे हैं तो भी इन्होंने अभी तक ऊँचे-ऊँचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की है ।

(२) यहाँ के बैंकों ने जव-जव विनिमय का काम करना प्रारम्भ किया तब-तब इन लोगो ने उन्हें असफल बनाने का प्रयत्न किया ।

(३) इन्होंने अपनी शाखायें देश के भीतरी शहरों में भी खोल दी हैं, जिससे यह भारतीय बैंकों से अन्य कामों में भी होड़ करते हैं ।

(४) इन्होंने सम्मिलित पूँजी वाले भारतीय बैंकों से भी अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया है, जिससे ये उन्हें अपने लाभ के लिये काम में लाते हैं ।

विनिमय बैंकों को लाइसेन्स देने और उन पर अन्य प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न

इन बैंकों के ऊपर जो उपर्युक्त बातों का दोषारोपण किया जाता था उसके कारण इन्हें लाइसेन्स देने और इन पर अन्य प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न कई बार उठा । बैंकिंग विषयक अनुसंधान करने वाली केन्द्रीय कमेटी ने इनके सम्बन्ध में मुक्तद्वारनीति का बड़ा विरोध किया था । जर्मनी, जापान, कनाडा आदि बहुत से देशों में विदेशी बैंकों को लाइसेन्स देने का चलन है । अस्तु १९४६ के बैंकिंग विधान के अनुसार अन्य बैंकों की तरह अब इन्हें भी रिजर्व बैंक से लाइसेन्स लेना पड़ता है । जो बैंक उक्त विधान पास होने के समय यहाँ पर काम कर रहे थे, उन्हें तो लाइसेन्स मिल ही गया है । नये बैंको को यह मिलने में अवश्य रुकावट पड़ेगी । पुराने बैंको के उचित व्यवहार न करने के कारण वे रह भी किये जा सकते हैं । लाइसेन्स की शर्तों में एक शर्त यह भी है कि यहाँ का हिसाब अलग रखे, इससे भविष्य में इनके विषय में बहुत सी बातें मालूम हो सकेंगी । दूसरे अब कोई बैंक भारतवर्ष में अपनी नयी शाख तब तक नहीं खोल सकता, जब तक कि रिजर्व बैंक उसकी आज्ञा न दे दे । नये बैंकिंग विधान के अनुसार रिजर्व बैंक इनके ऊपर अन्य बैंकों की तरह अन्य कई नियन्त्रण लगा सकता है । अतः आशा है कि भविष्य में यह यहाँ के लोगों की कोई विशेष हानि नहीं कर सकेंगे । रिजर्व बैंक को इस बात पर विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिये कि यह यहाँ के भारतीय बैंकों को खरीद

न गतें। फिर, यह बैंक अपने काम में स्वयं ही कुछ सुधार करने देगा में प्रिय पात्र बन सकें हैं।

विदेशी बैंकों के काम करने के सम्बन्ध में सुझाव

(१) इन्हें भारतीय आयातकर्ताओं के सम्बन्ध के तैम ही एमाले देने चाहिये जैसे ये गैरभारतीय आयातकर्ताओं के सम्बन्ध के देने हैं।

(२) इन्हें भारतीय आयातकर्ताओं को लन्दन की बिल स्वीकार करने वाली कोटिया और बैंकों के यहाँ उनसे १५ या २० प्रतिशत पेशगी दिलाये बिना ही शाग्वोलने की व्यवस्था कर देना चाहिये और यदि ये ऐसा न कर सकें तो इन्हें स्वयं ही उनके ऊपर के बिल स्वीकार कर लेना चाहिये।

(३) इन्हें बिला के कुर्यों में लिरो जाने में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिये। गिजर्व बैंक की धँह दर बहुत दिनों से तीन प्रतिशत है। अतः, यदि यह बिल कुर्यों में लिरो जाने लगे तो देश में बिल बाजार अवश्य ही बन जायें।

(४) इन्हें अपने यहाँ भारतीयों को ऊँचे-ऊँचे पद देने चाहिये। उससे न केवल इनका काम ही बढ़ जायगा बल्कि भारतीयों से अच्छा सम्बन्ध भी स्थापित हो जायगा।

(५) इन्हें भारतीय बैंकों के साथ सहयोग से काम करना चाहिये और भारतीय बीजों का बहिष्कार नहीं करना चाहिये। इन्हें भारतीय बीमा कम्पनियों के साथ समझौता कर लेना चाहिये। भारतीय जहाज चलाने का भी प्रयत्न हो रहा है। अतः, इन्हें उनकी भी सहायता करनी चाहिये।

भारतीयों के विनिमय के व्यवसाय करने के लिये सुझाव

किन्तु इतना सब होने पर भी भारतीयों को विनिमय का व्यवसाय अपने हाथ में तो लेना ही पड़ेगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत से ब्रिटिश बैंक स्थापित हो चुके थे तो भी अमेरिका, जापान, फ्रान्स, डच इत्यादि के बैंक यहाँ पर स्थापित किये गये। इसका एक मात्र कारण यह है कि किसी देश के लोगों का उस देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कितना हाथ रहेगा। यह बस इस बात पर निर्भर है कि उनके बैंक उन देशों में हैं अथवा नहीं जिनसे उनका व्यापार होता है। यह स्वाभाविक ही है कि किसी देश के बैंक ही उस देश के

लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता पहुँचा सकते हैं। जर्मन और जापानियों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इसी तरह से बढ़ सका था। बैंकिंग सम्बन्धी अन्वेषण करने वाली केन्द्रीय कमेटी और उसकी सहायता को आये हुये विदेशी अनुभवी व्यक्तियों ने भी यही बात कही थी। हमारा जो व्यापारिक मिशन सन् १९४६ में चीन गया था, उसने यह कहा था कि वहाँ पर भारतीय बैंकों की बड़ी आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त अन्य लोगों ने अन्य सुझाव भी रखे हैं। उनमें से प्रथम तो यही था कि इम्पीरियल बैंक को यह व्यवसाय करना चाहिये। इस सम्बन्ध का उस पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ था उसका लोग बहुत विरोध करते थे। प्रेसीडेंसी बैंकों के ऊपर तो यह प्रतिबन्ध इसलिये लगाया गया था कि इस व्यवसाय में उस समय बड़ी जोखिम थी, किन्तु जब से देश में विनिमयमान हो गया था तब से यह डर नहीं था। जो हो सन् १९३४ से इम्पीरियल बैंक के ऊपर यह प्रतिबन्ध नहीं है। जैसा कि बैंक के व्यवस्था शासक ने बैंकिंग सम्बन्धी अन्वेषण करने वाली कमेटी के सामने कहा था, यह काम करने की शिक्षा देना भी बहुत आसान था। किन्तु बैंक ने अभी तक ऐसा करना प्रारम्भ नहीं किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बैंक की नीति भारतीय विरोधी होने के कारण उसके ऐसा करने से भी कोई लाभ नहीं होता, वह विदेशी बैंकों से मिल जाता, किन्तु अब तो स्थिति बदल गई है। फिर, इम्पीरियल बैंक विधान में सशोधन होने वाला है। अतः, उसे अधिक लाभप्रद बनाया जा सकता है।

बैंकिंग सम्बन्धी अन्वेषण करने वाली केन्द्रीय कमेटी ने एक सरकारी विनिमय बैंक की स्थापना करने की सिफारिश की थी। किन्तु ऐसा करने के लिये तभी कहा गया था जब इम्पीरियल बैंक यह काम न करे। सरकारी बैंक की पूँजी सम्मिलित पूँजी वाले भारतीय बैंकों द्वारा खरीदी जाने की बात थी और उसकी कमी सरकार द्वारा पूरी करने की बात थी। कुछ सदस्यों की यह राय थी कि सरकार को ही सब हिस्से लेने चाहिये। इसके अतिरिक्त वे इस बात के विरुद्ध थे कि इम्पीरियल बैंक से विनिमय का व्यवसाय करने को कहा जाय क्योंकि उनका यह विचार था कि उसके हिस्से अधिकांश गैर-भारतीयों के हाथों में होने के कारण वह भारतीयों के हित में काम कर ही नहीं सकता है। वह सब हिस्सों के सरकार द्वारा खरीदे जाने के लिये इसलिये कहते थे कि विनिमय बैंकों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि

जिन्हीं भी भारतीय पैर का इसमें सुलझता प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि उनके साथ म मरफार की पूरी सज्जता हो। इस पैर के ऊपर माधारण अंगिका का व्यवसाय करने की मनाही कर देने में भी सम्भाव्यता नगण्य थी निम्नलिखित उक्त भी अन्य भारतीय पैरों के लिये प्रसार की प्रति-योगिता न हो।

उक्त लोग सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पैर पहनने के पक्ष में नहीं थे। कम्पटी के एक सदस्य श्री सुबेदार ने यह मान निर्धारित के एक विभाग द्वारा व्यवसाय का सुझाव रक्खा था। उनके अनुसार यह व्यवसाय का विभाग अलग करने की ओर इसकी राय पूरी करने के लिये इसमें एक अलग सुन्निह होना चाहिये थी आवश्यकता थी। उक्त यह विचार था कि सरकार विनिर्दिष्ट पैर पहनने की आवश्यकता थी। फिर, यह सरकार का काम भी व्यवसाय देने के विरुद्ध है। उनका विचार था कि निर्वहण का यह काम नली-नानि कर सकता है।

अंगिका सम्प्रदाय अन्वेषण करने वाली कमेटी का एक सुझाव और था कि यह व्यवसाय करने के लिये एक ऐसा पैर होना चाहिये जिसमें नियन्त्रण भारतीयों के हाथ में भी हो और उन देशों के लोगों के हाथों में भी हो जिनसे उनका व्यापार है। वे कहते थे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भिन्न भिन्न देशों के लोगों के बीच में होता है। अतः, उनकी सहायता करने वाले पैर के लिये यह आवश्यक है कि उनके नियन्त्रण में सब देश के लोगों के प्रातिनिधियों का हाथ हो। ऐसे पैर की जरूरतों की पूँजी भारतीयों की और अन्य कमनियों की पूँजी विदेशियों की होनी और इसका लाभ सभी में बँटता।

एक मत यह भी था कि जिन ब्रिटिश पैरों के हाथ में भारतवर्ष की विनिमय की अंगिका का काम है उन्हें अपनी रजिस्ट्री यहाँ करा लेनी चाहिये और अपनी कुछ पूँजी रकमा में कर लेनी चाहिये। साथ ही उन्हें यहाँ पर अपना एक प्रधान कार्यालय भी रखना चाहिये। इससे ब्रिटिश रिस्तेदारों का यह लाभ होता कि वह यहाँ के व्यवसाय का लाभ उठा सकते अन्यथा उन पर प्रतिवन्ध लग जायेंगे और उनका व्यवसाय बन्द हो जायगा। इसमें हम बात की भी आवश्यकता थी कि आगे से अधिक रिस्ते भारतीयों के हाथ में आ जायें। किन्तु ब्रिटेन के लोगों को यह योजना क्योंकर स्वीकृत हो सकती थी। हा, परिस्थिति बदल जाने में अब ऐसा हो सकता है।

अविध्य में चाहिए जो योजना हो हम बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि इधर भारतीय निर्माणी विदेशों में मशीनें मगवायेंगी। उनके दाम प्रायः वे

एक साथ न दे सकेगी। अतः जो भी सस्या हो उसे यहाँ पर एक निर्यात आयात साख योजना का प्रबन्ध करना पड़ेगा। ग्रेट ब्रिटेन में निर्यात साख योजना चालू है। इससे यहाँ के लोग किस्त पर दाम दे सकेंगे। दूसरे, भविष्य में सोवियत रूस से भी हमारा व्यापार काफी बढ़ेगा। किन्तु वहाँ की सैमी राज्य प्रणाली है उसके लिये यहाँ का प्रचलित ढङ्ग काम न देगा। वहाँ से तो हमारी सरकार को ही स्वयं व्यापार करना पड़ेगा। इसके लिये संयुक्त राज्य की यू० के० सी० सी० नामक सस्या की तरह एक सस्या की आवश्यकता पड़ेगी अथवा जो काम वह सस्या करती है वही काम यहाँ के विनिमय बैंक को करना पड़ेगा।

युद्ध काल में विनिमय व्यवसाय

युद्ध काल में हमारे आयात और निर्यात दोनों पर नियन्त्रण लगा हुआ था। जैसे-जैसे युद्ध क्षेत्र बढ़ रहा था। वैसे-वैसे हमारे माल की माँग भी बढ़ती जा रही थी। अतः सरकार का पूर्ति विभाग यहाँ से माल खरीदता और उसे बाहर भेजता था। इसके लिये वह विक्रेताओं को आर्थिक सुविधाएँ देता था जिससे विनिमय व्यवसाय बैंकों के हाथ में न रह कर स्वयं सरकार के अथवा उसके प्रतिनिधि रिजर्व बैंक के हाथ में आ गया था। इसी तरह से आयात भी सरकार द्वारा ही होता था। बहुत सा सामान तो संयुक्त राष्ट्र से उधार पट्टे समझौते के अन्तर्गत आता था, अतः उसके भुगतान का तो प्रश्न ही नहीं था। फिर, जिस माल के आयात का भुगतान करना होता था उसका भुगतान भी सरकार ही अपने डालर कोष से करती थी। साम्राज्यान्तर्गत देशों से जो आयात होता था उसका भुगतान भी सरकार ही करती थी। वह जो माल युद्ध के लिये भेजती थी उसके बदले में उसे स्टर्लिंग मिलते थे। अतः, इन्हीं से वह आयात का भुगतान करती थी। इस तरह से विनिमय बैंकों के हाथ में बहुत कुछ कम काम रह गया था।

प्रश्न

(१) विदेशी बैंकों के हाथ में विनिमय के व्यवसाय का एका-विपत्य क्यों है ? क्या उनको विनिमय के बैंक कहना न्याय सगत है ?

(२) विदेशी बैंकों का यहाँ के भीतरी व्यवसाय में क्या हाथ है और भारतीय बैंकिंग पर उनका क्या प्रभाव है ?

(३) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आर्थिक सहायता

जैसे की जाती है? इस सम्बन्ध में जो काम हो उसका विवरण दीजिये ?

(४) यहाँ के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक मात्तयता देने का जो व्यवसाय है उसमें क्या योग है ? उसे समझाइये ।

(५) जो विदेशी बैंक यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कौन सी शिकायतें हैं ? उनके सुधार के लिये अपने सुझाव रखिये ।

(६) विनिमय के बैंकों को लाइसेन्स देने और उन पर अन्य प्रतिबन्ध लगाने के विषय में आपकी क्या राय है ? इस सम्बन्ध में अपने सुझाव रखिये । आपकी राय में इन्हें अपने को किस प्रकार से सुधारना चाहिये ?

(७) भारतीयों को विनिमय के काम में कैसे भाग लेना चाहिये ? इस सम्बन्ध में आप को जो कहना हो कहिये । अन्य लोगों की भी इस सम्बन्ध में जो राय हो वह बतलाइये ।

अध्याय १६

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया सन् १९३४ के अपने विधान के अनुसार १ अप्रैल, सन् १९३५ को स्थापित किया गया था । प्रारम्भ में यह हिस्तेदारों का बैंक था, किन्तु एक आफ इंग्लैण्ड के राष्ट्रीयकरण के बाद इसके राष्ट्रीयकरण का भी प्रस्ताव पास हुआ । अतः, १ जनवरी, १९४६ से यह हमारी महासभा के ३ सितम्बर, १९४८ के विधान के अनुसार जिसकी विस्तृति १८ अक्टूबर को हो चुकी थी, सरकारी बैंक हो गया । इसकी पूँजी ५ करोड़ रुपये है जो १००-१०० २० के हिस्सों में बँटी थी और पहले हिस्तेदारों के पास थी। किन्तु राष्ट्रीयकरण होने पर प्रत्येक १०० २० के हिस्से के लिये सरकार ने हिस्तेदारों को ११८ ६० १० देने का, जो उस समय इनका बाजार भाव था १९७०-७५ तीन प्रतिशत प्रथम विकास ऋण का एक सरकारी ऋण पत्र दे दिया । इसके बाद ही सरकार ने नये केन्द्रीय और स्थानीय मंडल के सचालकों के नाम घोषित कर दिये । केन्द्रीय मंडल में अब सरकार द्वारा नियुक्त एक शासक और दो उपशासक चारों स्थानीय मंडलों में से एक एक सचालक, छह अन्य सचालक तथा एक सरकारी कर्मचारी हैं । स्थानीय मंडलों में प्रत्येक में सरकार द्वारा

नियुक्त तीन संचालक हैं। राष्ट्रीयकरण के पहले इन मंडलों की व्यवस्था भिन्न थी। उस समय केन्द्रीय मंडल के आठ सदस्य और स्थानीय मंडलों के पाँच-पाँच सदस्य हिस्सेदारों द्वारा चुने जाते थे। केन्द्रीय मंडल के शासक और उपशासक उसी की सिफारिश पर सपरिषद गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किये जाते थे। इनके अतिरिक्त चार अन्य संचालक और एक सरकारी अफसर भी सपरिषद गवर्नर-जनरल द्वारा ही नियुक्त किये जाते थे। स्थानीय मंडलों में तीन-तीन सदस्य केन्द्रीय मंडल द्वारा नियुक्त किये जाते थे। हिस्से वम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास तथा जब तक बर्मा भारतवर्ष से पृथक् नहीं हुआ था तब तक रगून क्षेत्र के हिस्से से बँटे हुये थे। प्रत्येक क्षेत्र के हिस्सेदारों के अलग-अलग रजिस्टर थे और प्रत्येक रजिस्टर में दर्ज हिस्सेदार केन्द्रीय मंडल के और अपने अपने स्थानीय मंडलों के अपने पृथक्-पृथक् प्रतिनिधि चुनते थे। हिस्से भी कुछ लोगों को नहीं मिल सकते थे। यह इसलिये था जिससे साम्राज्य के बाहर के लोग रिजर्व बैंक के मालिक न हो सकें।

नये विधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार बैंक शासक की सम्मति से बैंकों को कोई भी ऐसी आशा दे सकती है जो वह दरों के हित में आवश्यक समझती है। वैसे तो बैंक तथा सरकार के बीच में प्रारम्भ ही से पूर्ण एकता थी, किन्तु इस विधान से यह बात पूर्णतः स्पष्ट कर दी गई है कि अन्त में सरकार की राय ही चलेगी। हाँ वैसे आशा यही है कि बैंक के अनुभवी कर्मचारियों की राय ही मानी जायगी।

राष्ट्रीयकरण के पहले बैंक की आय में से हिस्सेदारों को उनके हिस्से पर तीन प्रतिशत लाभ की बँटनी हो जाती थी और शेष सरकार को मिल जाता था। अब सभी लाभ सरकार का होगा।

स्थानीय मंडल कुछ विशेष कार्य और कुछ वह कार्य जो केन्द्रीय मंडल उन्हें सौंपता है करते हैं। केन्द्रीय मंडल को बैठके साल में कम से कम छः बार और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होनी आवश्यक है।

इसके काम

इसके काम दो प्रकार के हैं—(१) केन्द्रीय और (२) साधारण।

[१] केन्द्रीय

(१) भारतवर्ष में नोट निकालने का एकमात्र अधिकार—इस बैंक को भारतवर्ष में नोट चलाने का एकमात्र अधिकार दिया

गया है। नोट चलाने के लिये दस्ता एव अलग विभाग है जिसके सम्बन्धि और वाउचर बैंकिंग विभाग से चलाने रखे जाते हैं। नोट विभाग की सम्पत्ति जोने के सिक्कों और सोने में विदेशी निम्नोसिटियों में, कसबा में (तुलनाई मन् १९४० ने रुपये के नोट भी सम्मिलित हैं) कसबे की निम्नोसिटियों में और व्यापारिक पिका में रखी जाती है। दस्ता म् में कम १० प्रतिशत सोने में और विदेशी निम्नोसिटियों में रहना चाहिए और उसमें भी सोना कम से कम १० फीट करके हो रहना चाहिए। गोता २१ रु० ३ आ० १० पाई प्रति पौला प पिका में लगाया जाय है। विदेशी निम्नोसिटियों में उन उर्मी दस्ता की निम्नोसिटियाँ सम्मिलित हैं जो अन्तराष्ट्रीय रूप में प्रचलन में हैं। एले कौन्स्टेबल निम्नोसिटियाँ भी यह सम्पत्ती में। मरिपद गवर्नर अन्तराल की म्पत्ति में से पाले तो नीचे दिन चलाने कम का जा सकती हैं और फिर द्वाती तरह से पन्द्रह-पन्द्रह दिन के लिये और भी कम की जा सकती हैं। फिन्नु जो कुछ कमी हो उसके लिये बैंक को द्वाते प्रतिशत तक की म्पत्ती के लिये मरिपद गवर्नर अन्तराल में बैंक दर से उठ-उठ करके प्रतिशत ऊपर का देना पड़ता है। फिन्नु यह सिमी स्थिति में भी द्वा प्रतिशत से कम नहीं हो सकता। शेष मरिपद कसबा में भारत सरकार की स्वयं की निम्नोसिटियों में और देशी बिलों और प्रण पत्रों में रहती है।

कम प्रती तक चालीय प्रतिशत में अधिक सोने और विदेशी निम्नोसिटियों में रहता है।

(२) मदस्य बैंकों की नकदी रखने का अधिकार—प्रत्येक मदस्य बैंकों को इसके पास अपनी चालू जमा का कम से कम पाँच प्रतिशत और स्थायी जमा का दो प्रतिशत रक्कत पड़ता है। इसका उद्देश्य यह है कि यह आवश्यकता पडने पर उसे मदस्य बैंकों की सहायता के लिए काम में ला सके। इससे यह खुले बाजार की नीति अपना कर अर्थात् नरकारी निम्नोसिटियों और बिल सीधे ही खरीद और बेच कर मदस्य बैंकों की जमा बढ़ा-बढ़ा कर उनकी सहाय देने की नीति भी प्रभावित कर सकता है। ऐसा बैंक दर नीति द्वारा भी किया जा सकता है, किन्तु बैंक ने आज तक ऐसा नहीं किया है। २२ नवम्बर, सन् १९३५ से बैंक दर ३ प्रतिशत चला आ रहा है। व्यापारिक बैंकों को उधार देने की जो इसकी नीति है उसका सकेत तो पहले हो किया जा चुका है। अन्तिम यह कि यह कृषि सम्बन्धी साध भी उनी गतों पर दे सकता निनका वर्णन कृषि सम्बन्धी साध के अध्याय में किया जा चुका है।

(३) रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिर रखने के उद्देश्य से एक निश्चित दर पर विदेशी करन्सियों का क्रय-विक्रय करने का दायित्व--प्रथम तो जो कोई इससे लन्दन की सुपुर्दगी के लिए तैयार स्टर्लिङ्ग माँगता था और उसका क्रय मूल्य कानूनन ग्राह्य करन्सी में देता था उसे तो इसे प्रति रुपया कम-से-कम एक शिलिंग ५४ $\frac{3}{4}$ पें० देना अनिवार्य था। दूसरे, इसे प्रति रुपये अधिक-से-अधिक १ शि० ६ $\frac{3}{4}$ पें० के हिसाब से स्टर्लिङ्ग खरीदना भी पड़ता था। हाँ, प्रत्येक हालत में कम-से-कम दस हजार पौंड का काम होना चाहिये था। इधर जब से भारत अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोष का सदस्य बन गया है तब से इस पर सरकार की निश्चित शर्तों पर किसी भी करन्सी के क्रय विक्रय का दायित्व रख दिया गया है। इसे सरकार की विनियम की आवश्यकताये भी पूरी करनी पड़ती हैं। अतः, इसके लिये पहले तो यह प्रति सप्ताह स्टर्लिङ्ग क्रय के लिए टेन्डर माँगता था, किन्तु शुद्धकाल से यह सीधे ही स्टर्लिङ्ग खरीदने लगा था।

(४) भारतवर्ष में सरकारी काम करने और बिना व्याज बैलन्स रखने का अधिकार--इसके लिए अप्रैल ५ सन् १९३५ को इसके और केन्द्रीय सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था। यह सरकार के हिसाब में रुपया प्राप्त करता है और जो उसका बैलन्स होता है, उसमें से उसके हिसाब में भुगतान देता है और उसके विनियम भेजने के और बैकिङ्ग के दूसरे काम कुछ चार्ज लिए बिना ही करता है। जिन स्थानों पर उसकी शाखा अथवा शाखत नहीं हैं, उनमें सरकार के लगभग १३०० खजानों और उपखजानों द्वारा यही काम होता है। यह सरकारी ऋण की भी व्यवस्था करता है और नए ऋण निकालता है। इसके लिए इसे प्रति करोड़ सरकारी ऋण पर २०० रुपया वार्षिक छमाही कमोशन मिलता है। अपने दफ्तरों, शाखाओं, शाखतों, खजानों तथा उपखजानों में यह नोट विभाग का करन्सी चेस्ट रखता है। इनमें यह सरकार के काम के लिए और जनता का रुपया इधर-से उधर भेजने के लिए काफ़ी नोट और रुपया रखता है।

सरकारी ऋण दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन दोनों हो सकते हैं। रिजर्व बैंक करन्सी और फाइनेन्स की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इसका विस्तृत विवरण देता है। दीर्घकालीन ऋण जिन कागजों के रूप में निकाले जाते हैं, वे अनेक प्रकार के होते हैं और उन सबको सरकारी सिन्डोरिटियाँ कहते हैं।

अल्पकालीन ऋण ट्रेजरी बिलों के रूप में निष्काले जाते हैं और ये प्रायः तीन महीने की अवधि के होते हैं। दिल्ली को छोड़कर गिरगिर के अन्य सभी दफ्तरों में और बैंकिंग विभाग की शाखाओं में इनके भ्रम की व्यवस्था टेण्डर पर अथवा बीच वाली दर पर की जाती है। टेण्डर मांगने का ज्ञान निश्चय हो जाता है तब टेण्डर मांगने की तारीख, टेण्डर के भुन, उनकी अवधि और उनकी स्वीकृति हो जाने पर उनका स्वयं जिन तारीख को देना पड़गा या तारीख, इत्यादि यह सब एक विज्ञप्ति द्वारा निश्चाल दिवस जान है और मुख्य-मुख्य बैंकों दलालों तथा कोटियों को भेज दिये जाते हैं। टेण्डर में बिल की शर्तें, टेण्डर देने वाला जितने के बिल लेना चाहता है, प्रति दिन वह जितना स्वयं, पाना और पैसा प्रत्येक १०० रु० के लिये देना चाहता है, दिये रहते हैं। ट्रेजरी बिल केवल २५०००, ५००००, १ लाख, ५ लाख, १० लाख और ५० लाख रुपये के होते हैं। ज्ञान बीच की दर पर ट्रेजरी बिल बेचने का निश्चय होता है तब प्रायः टेण्डर की स्वीकृति की विज्ञप्ति के साथ यह विज्ञप्ति भी दे दी जाती है। प्रायः ट्रेजरी बिल इंग्लिशियन बैंक और चड़े-चड़े बैंक ही ले लेते हैं।

यदि और थोड़े समय के लिये रुपयों की आवश्यकता होती है तो यह गिजर्व बैंक से वेजेज एन्ड मीन्स के रूप में (Wages & Means Advances) ले लिये जाते हैं।

१ अप्रैल, सन् १९३७ को प्रान्तीय स्वराज्य के प्रादुर्भाव के मायनाय ही रिजर्व बैंक का भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारों के साथ एक समझौता हुआ था। उसी वर्ष भारतवर्ष और ब्रह्मा की सरकार के बीच में भी एक समझौता हुआ था। कुछ बातें छोड़कर जैसे अन्तर्प्रान्तीय भुगतान के सम्बन्ध में रुपया भेजने और वेज एन्ड मीन्स के रूप में ऋण देने के सम्बन्ध में शेष सभी बातों में यह समझौते वैसे ही थे वैसे केन्द्रीय सरकार के बीच का समझौता था। स्वतन्त्र प्रान्तों को जो अधिकार प्राप्त हैं उनके अनुसार उन्हें उसी प्रकार दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन ऋण लेने का भी अधिकार है जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार को है। हाँ, प्रान्तीय सरकारों को बैंक के पास एक कम-से-कम बैलन्स भी रखना पड़ता है जो उनके और बैंक के बीच में समय-समय पर निश्चित होता रहता है। इसमें यदि कोई कमी हो जाती है तो वह वेज एन्ड मीन्स से पूरे की जाती है। एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जब रुपया भेजा जाता है तब बैंक उसी दर से कमीशन लेता है जिस दर से वह कमीशन सहकारी समितियों

और बैंकों से लेता है। उसी प्रान्त के अन्दर रुपया मेजने के लिए कोई कमीशन नहीं लिया जाता।

यह बैंक भिन्न-भिन्न सहकारों को आर्थिक समस्याओं पर अपनी सम्मति भी देता है।

(५) कुछ साधारण काम करने का दायित्व—उपर्युक्त काम केन्द्रीय बैंकिंग के मुख्य काम हैं। इनके अतिरिक्त कुछ साधारण काम भी हैं जिन्हें यह बैंक करता है। इसमें निम्न काम हैं—(१) भिन्न-भिन्न प्रकार की करन्सी देना, (२) रुपया मेजने की सुविधा देना, (३) निकासगृह की व्यवस्था करना, (४) आर्थिक मामलों में मन्त्रणा देना, (५) बैंकिंग के अङ्ग एकत्रित करके उन्हें जनता के सम्मुख रखना, इत्यादि।

यदि हम पहले (१) अर्थात् भिन्न-भिन्न प्रकार की करन्सी देने को लें तो बैंक को नोट के लिये रुपये और रुपयों के लिये नोट देना आवश्यक है। जुलाई, सन् १९४० से रुपयों में भारत सरकार के एक एक रुपये के नोट भी सम्मिलित हैं। इसे रेजगारी भी निकालनी और वापिस लेनी पड़ती है। चूँकि रुपया, रुपये के नोट और रेजगारी बनाने का अधिकार केवल सरकार को ही है, अतः, ऐसा नियम है कि सरकार बैंक की आवश्यकता के अनुसार नोटों के विनिमय में इन्हे दे और यदि यह उसके पास अधिक हो तो उससे वापिस ले ले।

अब यदि हम (२) अर्थात् रुपया मेजने की सुविधा लें तो इसके लिये यह अपने नोट चलाने के विभाग के दफ्तरों, शाखाओं, आदतों, खजाना तथा उपखजानों में करन्सी के बक्स रखता है और इसमें काफी नोट और सिक्के रखता है जिससे सरकारी लेन-देन हो सके और रुपया इधर से उधर भेजा जा सके। पहली अक्टूबर, सन् १९४० से इसने जनता, सहकारी बैंकों और समितियों, सदस्य बैंकों, कुछ गैरसदस्य बैंकों तथा देशी महाजनो का रुपया रियायती कमीशन लेकर इधर से उधर भेजने की एक योजना निकाली है। सहकारी बैंकों के लिये सदस्य बैंकों और गैरसदस्य बैंकों के लिये कमीशन के जो दर हैं उन्हें तो हम पीछे देख ही चुके हैं। देशी महाजनों के लिये भी वही दर हैं जो गैरसदस्य बैंकों के लिये हैं।

जनता के लिए निम्न दर हैं—

५००० रु० तक		५००० रु० के ऊपर	
प्रतिगा ८४	न्यूनतम चार्ज	प्रतिगा ८४	न्यूनतम चार्ज
० पा०	४ आ०	१ आ०	रु० ६-०-०
गारंटी, रत्यादि के लिये			
रु० १-०-०			
३० दि० के लिये			
(तार करने पर)			

लक्ष नम (३) अर्थात् विमानपट्टी की व्यवस्था का प्रश्न है, उसे हमने जनसत्ता और जनपुर् छोड़कर उन सभी स्थानों में ले लिया है जहाँ इसके दक्ष और शाखाएँ हैं। इनमें से हमने व्यवस्था विचित्रविचित्र पैरर्स अमो-सिगेशन की माध्याम्य समेटो राग निरुक्त १२ निर्गलर के हाथ में है और जनपुर् में १२ इन्सिगन बैंक के हाथ में है। अन्य स्थानों में भी जहाँ रिजर्व बैंक के दक्ष अथवा शाखाएँ नहीं हैं, उन स्थानों में भी यह काम इन्सिगन बैंक ही के हाथ में है। यद्यपि रिजर्व बैंक भी निरालाओं के सम्बन्ध में नियम बनाने के अधिकार प्राप्त हैं तो भी उसने उसकी आदर्यता नहीं समझी गई है और सब निरालाएँ अपने-अपने नियमों के अनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक काम कर रहे हैं।

हमके तार (४) अर्थात् आर्थिक मामलों पर मरणा देने का काम है। रिजर्व बैंक भिन्न भिन्न सरकारों, सदस्य बैंकों और गैरसदस्य बैंकों, सरकारों समि-तियों और बैंकों और भूमि-वन्दक मरवाओं को आर्थिक मामलों पर मरणा देता है। सत्तेर म यह मरवा को मरणा देने के लिये तैयार है।

अन्त में (५) अर्थात् बैंकिंग सम्बन्धी प्रक एजित करने और उन्ने जनता के सम्मुख रखने का काम है। प्रथम तो यह अपने नोट विभाग और बैंकिंग विभाग का साप्ताहिक हिसाब केन्द्रीय सरकार के पास भेजता है और उन्हें पत्रों में निकालता है। दूसरे, यह सदस्य बैंकों से प्राप्त सूचना भी एक में करके उनको एक साप्ताहिक रिपोर्ट निकालता है। फिर, इसने अब करन्सी और अर्थ सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट तथा यहाँ के बैंकों की अब सम्बन्धी तालिका निकालने का काम भी अपने हाथ में ले लिया है। अन्तिम यह है कि यह प्रकों का एक मासिक विवरण (Monthly statistical summary) और अपनी वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report) भी निकालता है।

२. साधारण बैंकिंग के काम

(१) बिना व्याज जमा प्राप्त करना और उसे वसूल करना ।

(२) भारतवर्ष में ही लिखे हुये और देय विनियम के गिलों और प्रणपत्रों का क्रय, विक्रय तथा फिर से डिस्काउण्ट करना :—
ये (१) व्यापारिक लेन देनों से (२) खेतों के कामों में अथवा कृषि के विक्रय से और (३) भारत सरकार की अथवा किसी स्थानीय सरकार की अथवा किसी ऐसी रियासत की सिक्योरिटियों को जिन्हे सारिषट गवर्नर जनरल ने केन्द्रीय मण्डल की सिफारिश से स्वीकार किया है, रखने से अथवा उनमें लेन-देन करने से उत्पन्न होते हैं । इनमें से प्रथम का क्रय, विक्रय और फिर से डिस्काउण्ट तो तभी किया जा सकता है जब उन पर दो या दो से अधिक ऐसे हस्ताक्षर हों जिनमें से एक किसी सदस्य बैंक का है, दूसरे का तब किया जा सकता है जब एक हस्ताक्षर किसी सदस्य बैंक का अथवा किसी प्रांतीय सरकार का है और तीसरे का तब किया जा सकता है जब केवल किसी सदस्य बैंक का ही हस्ताक्षर हो । इनमें पकने की अवधि रियायती दिन छोड़ कर ६० दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिये ।

(३) (अ) सदस्य बैंकों से कम से कम एक लाख रुपये की बरानरी के खरीदना और बेचना । अब स्वीकृत करन्सियाँ खरीदना और बेचना ।

(ब) अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोष के सदस्य देशों में लिखे हुये अथवा उनके ऊपर किये हुये उन विलों का क्रय-विक्रय और फिर से डिस्काउट करना जो क्रय की तारीख से ६० दिनों के अन्दर पकने वाले हों । हों, यदि इनका क्रय-विक्रय और फिर से डिस्काउट भारतवर्ष में किया जाता है, तो वह सदस्य बैंक से होना चाहिये ।

(स) अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोष के सदस्य बैंकों के पास बैलान्स रखना ।

(४) भारतवर्ष में देशी राज्यों, स्थानीय अधिकारियों, सदस्य बैंकों और प्रान्तीय सहकारी बैंकों की माँग पर देय अथवा अधिक से अधिक नब्बे दिन की अवधि पर देय ऋण देना । ये स्टार्को, कोष (Funds) और धरोहर की सिक्योरिटियों की जमानत पर (अचल सम्पत्ति की जमानत पर नहीं), सोने अथवा चादी अथवा उनके अधिकार-पत्रों पर, उसके द्वारा लिये जाने योग्य विलों पर और किसी सदस्य बैंक अथवा प्रान्तीय सहकारी बैंक के उन प्रण-पत्रों

पर जो माल के भंडों अधिभार-वन्ता के आभार-स्वरूप है और जो नगद धान लेने के लिये प्रथम वित्तीय व्यापार के लेन-देनों के सम्बन्ध में जमा के अधिक स्वल्प भिन्नाने के लिये प्रथम धूर्त धन-प्राप्ति, प्रथम कृषि की फीजों के प्रिय न लिये या तो उसे हस्तान्तरित कर दिये गये हैं अथवा उसके नाम पर दिये गये हैं अथवा उनके पास गिरवो रख दिये गये हैं, उनकी गमानत पर ही दिये जा सकते हैं।

(५) सरपिण्ड गवर्नर जनरल को अथवा किसी ऐसे सरकार को श्रृण देना जिनकी स्वयं की प्रान्तीय प्राय है। किन्तु यह श्रृण देने की तारीख में तो महीनों के अन्दर पाधिम हो जाना चाहिये।

(६) अथन दस्तगै पर देय दशनी ट्रास्ट देना अथवा बैंक पोन्ट विल निकालना।

(७) ऐसी विदेशी सरकारी सिन्धोरिटियों का क्रय और विक्रय करना जो क्रय या तारीख में इस वर्षों के अन्दर पकने वाली हों।

(८) भारत सरकार की प्रथम किसी स्थानीय सरकार को किसी भी प्रथम को सिन्धोरिटियाँ अथवा ब्रिटिश भारत के किसी ऐसे अधिकारी अथवा भारतवर्ष की किसी ऐसी देशी रियासत की सिन्धोरिटियों गरीदना और बेचना बिना केन्द्रीय मण्डल की निष्ठाति पर सरपिण्ड गवर्नर जनरल ने इस योग्य स्वीकार कर लिया है। यदि उत्तर्युक्त अधिकारी किसी सिन्धोरिटियों के मूलधन और व्याज के भुगतान का दायित्व ले लेते हैं तो यह उन्हें भी गरीद और बेच सकता है। इन सब सिन्धोरिटियों का सम्मिलित मूल्य किसी एक समय पर बैंक के हिस्सों की पँजी, मगतिन कोष और उनके बैंकिंग विभाग के जमा के दायित्व के ३ से अधिक और नहीं हो सकता। जो सिन्धोरिटियाँ एक वर्ष के बाद पकने वाली हैं वह पँजी तथा सुरक्षित कोष और बैंकिंग विभाग के जमा के दायित्व के २ से अधिक और जो सिन्धोरिटियाँ दस वर्ष के बाद पकने वाली हैं वह पँजी तथा सुरक्षित कोष और बैंकिंग विभाग के जमा के दायित्व के २ से अधिक की नहीं हो सकती हैं।

(९) द्रव्य, सिन्धोरिटियाँ तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुयें रखना तथा उनका मूल्य व्याज इत्यादि सहित वसूल करना।

(१०) यदि बैंक के हाथ कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति उसके पाउने के सम्बन्ध में आ जाय तो उसे बेचना और उसका मूल्य वसूल करना।

(११) सपरिपद् गवर्नर जनरल अथवा किसी स्थानीय सरकार अथवा अधिकारी अथवा भारतवर्ष की देशी रियासत की तरफ से सोना अथवा चाँदी खरीदने और बेचने के लिये, बिल, सिक्क्योरिटियाँ अथवा किसी कम्पनी के हिस्से खरीदने बेचने हस्तान्तरित करने अथवा सुरक्षित रखने के लिये, किसी सिक्क्योरिटियों के मूलधन, व्याज अथवा लाभ की बँटनी वसूल करने के लिये, और वसूल की हुई रकम उसके मालिक की आज्ञानुसार भारत में अथवा कहीं भी बिलों से मेजने के लिये तथा सरकारी ऋण की व्यवस्था करने के लिये अदतिया के तौर पर काम करना ।

(१२) सोने के सिक्के और सोना खरीदना और बेचना ।

(१३) किसी अन्य देश के केन्द्रीय बैंकों के यहाँ अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के यहाँ एकाउण्ट खोलना, उनमें आदत के सम्बन्ध स्थापित करना, उनके अदतिया का काम करना और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के हिस्से खरीदना ।

(१४) एक महीने के अन्दर के लिये ऋण लेना और उसके लिये जमानत देना । यह ऋण भारतवर्ष में केवल किसी सदस्य बैंक से अपनी पूँजी की रकम तक का और बाहर किसी केन्द्रीय बैंक से किसी भी रकम तक का लिया जा सकता है ।

(१५) बैंक नोट बनाना और चलाना ।

(१६) कोई ऐसा काम करना जो इसके उपर्युक्त कामों के सम्बन्ध में होने चाहिये ।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि यह बैंक जनता से इस तरह से काम नहीं कर सकता कि जिससे उसकी और किसी सदस्य बैंक की प्रतियोगिता हो सके । हाँ, वह ऐसा तभी कर सकता है जब उसके केन्द्रीय मण्डल की अथवा किसी ऐसे अधिकारी की सम्मति में जिसे केन्द्रीय मण्डल ने अपनी शक्ति दे दी है देश के व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धन्वों और कृषि के हित में साख का नियन्त्रण करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है । इसे कुछ काम करने की मनाही भी कर दी गई है ।

यह बैंक जो काम नहीं कर सकता

(१) यह बैंक व्यापार नहीं कर सकता और न किसी व्यावसायिक, औद्योगिक, किसी अन्य प्रकार की सस्था में कोई सीधा हित ही उत्पन्न करेगा । यदि किसी ऋण की वसूली में यह उसके पास आ जाय तो इसे ही बेच देना चाहिये ।

(२) यह अपने हिस्से पर्याप्त किन्हीं दूसरे की प्रशंसा किन्हीं कल्पना के द्वारा न तो समीक्ष्य मन्ता है और न उनकी समझना पर प्रयत्न ही दे सकता है ।

(३) यह अचल सम्पत्ति और उसके अधिभार-वत्ता के रेटन पर अवकाश उनकी किसी अन्य प्रशंसा की समझना पर न तो प्रयत्न ही दे सकता है और केवल अपने ध्यान के लिये छोड़कर न कोई अचल सम्पत्ति समीक्ष्य ही मन्ता है ।

(४) माग पर कागज होने की गर्त के प्रतिनिधि यह न तो प्रयत्न दे सकता है, न दित कर मन्ता है पर्याप्त स्वीकार कर सकता है और न चालू भावों पर व्याज ही दे सकता है ।

बैंक के संगठन

यह बैंक १ अप्रैल, सन् १९३५ को स्थापित हुआ था । हाँ, इसके विधान में तो गवर्नर जनरल की स्वीकृति ६ मार्च, सन् १९३४ ही की प्राप्ति हो चुकी थी, किन्तु मन्त्यापना के पक्ष बहुत कुछ काम करना था, इसी ने इतनी देर लगी । १० दिसम्बर सन् १९३४ को मरिफ़्ट गवर्नर जनरल ने इसका प्रथम शासक और उपशासक नियुक्त किये और तीन दिन बाद सचालकी का केन्द्रीय मण्डल बना । यह प्रथम केन्द्रीय मण्डल भी मरिफ़्ट गवर्नर जनरल ने ही बनाया था । किन्तु इसके हिस्से निकाले गये और इसके साथ ही अन्य प्राथमिक कार्य किये गए । इनमें इसके दफ्तर और शाखाओं के लिये उपयुक्त इमारतों की व्यवस्था की गई और सरकार के केन्द्रीय विभाग से तथा इम्पीरियल बैंक से इसके लिये कुछ कर्मचारी लिये गये । किन्तु इसके और सरकार के और इम्पीरियल बैंक के बीच में वह समझौते हुये जिनके विषय में पहले ही बताया जा चुका है और कार्य करने के लिये नियम बनाये गये । इनमें बैंक के साधारण नियम थे, चुनाव के नियम थे, हिस्सेदारों की बैठकों, सदस्य बैंकों, नोटों की वापसी, खर्च और कर्मचारियों के लिये नियम थे । जिस दिन यह स्थापित हुआ उसी दिन से इनने नोटों का, सुरक्षित कोष रखने का, स्टालिङ्ग गय का और सिक्योरिटियों की व्यवस्था का काम करन्ती फण्टोलर से ले लिया और सरकार के भिन्न हिसाब रखने, सरकारी ऋण और निकासण का काम इम्पीरियल बैंक से ले लिया । ४ जुलाई, सन् १९३५ को बैंक की पहली दर घोषित की गई और दूसरे दिन सदस्य बैंकों ने अपनी जमा का आवश्यक अर्ध हमके पास भेजा । हाँ, बैंक के अपने नोट पहले-पहल सन् १९३८ में ही निकल सके ।

बैंक का मुख्य दफ्तर जिसे केन्द्रीय दफ्तर भी कहा जाता है अब स्थायी रूप से बम्बई में ही है। हाँ, मन्त्री का विभाग शासक के साथ-साथ कलकत्ते और बम्बई दोनों में अदलता-बदलता रहता है। इस विभाग का सम्बन्ध मण्डल की और कमेटी की साधारण वार्षिक बैठकों से रहता है। यह केन्द्रीय सरकार से बरन्सी और विनिमय, भिन्न भिन्न सरकारों के ऋण और ट्रेजरी बिल निकालने और उनकी व्यवस्था और वेन और मीन्स के ऋण सम्बन्धी प्रश्नों पर लिखा-पढ़ी करता है। इसके अन्य विभाग मुख्य अकाउण्टेण्ट का विभाग, कृषि सम्बन्धी साख विभाग और विनिमय नियन्त्रण विभाग हैं और इनमें से प्रत्येक के उपविभाग हैं। कृषि सम्बन्धी साख के उपविभागों और कृषि सम्बन्धी साख उपविभाग के कामों का वर्णन तो पहले ही किया जा चुका है। बैंकिंग विभाग सदस्य तथा गैर सदस्य बैंकों की समस्त समस्याओं की व्यवस्था करता है, बैंकों और सरकार को आर्थिक समस्याओं पर सम्मति देता है और आवश्यकता पड़ने पर इनके सम्बन्ध की रिपोर्टें तैयार करता है। अङ्क और आविष्कार विभाग भिन्न-भिन्न अंक एकत्रित करके छपाता है। यह भिन्न-भिन्न समस्याओं पर आविष्कार भी करता है। अब, केवल मुख्य अकाउण्टेण्ट का उपविभाग और विनिमय नियन्त्रण विभाग रह गये हैं।

मुख्य अकाउण्टेण्ट का उपविभाग नोट विभाग का हिसाब रखता है और उसका निरीक्षण करता है। यह बैंक के व्यय की व्यवस्था भी करता है, नोटों की वापसी की अपीलें सुनता है, रुपया इधर-से-उधर भेजता है और बैंक की अन्य सब प्रकार की व्यवस्था करता है। विनिमय नियन्त्रण विभाग युद्धकाल में बना था और भारत रत्ना विधान के अनुसार बैंक को जो मुद्राओं, सोना, चादी, सिक्योरिटियों और विदेशी विनिमय का नियन्त्रण करने का काम दिया गया था उसे करता है। इधर इसके लिये एक पृथक् नियम बन गया है।

बैंक के दूसरे दफ्तर और शाख या तो बैंकिंग विभाग के दफ्तर अथवा शाख हैं या नोट विभाग के शाख हैं। बैंकिंग विभाग के वर्तमान दफ्तर बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में हैं तथा शाख कानपुर और नागपुर में हैं। इसी तरह से नोट विभाग की शाख बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली और मद्रास में हैं। अप्रैल, मन् १९३६ से इसका एक दफ्तर लन्दन में भी है जो भारत सरकार के रुपये के उस ऋण की व्यवस्था करता है जो लन्दन में है और यहाँ के वहाँ के राजदूत का हिसाब रखता है। इम्पीरियल बैंक उन सब स्थानों में जहाँ उसके दफ्तर तो हैं, किन्तु रिजर्व बैंक के दफ्तर नहीं हैं रिजर्व

बैंक का प्रदत्तियाँ हैं। सन् १९८७ ई० में इम्पीरियल बैंक के ४८४ दफ्तर थे। सन् १९८८ में केवल भारतवर्ष में यही संख्या ३६८ थी। जेप पाकिस्तान में थे। इसके अतिरिक्त लगभग १३०० से अधिकारी मजदूर तथा उपभोग करने वाले इसके सम्बन्धी थे।

बैंक की सफलतायें

यह बैंक की उड़ी उड़ी आशायें लेकर स्थापित किया गया था। अतः, हमें यहाँ पर यह भी देना चाहिये कि वह सत्र आशायें पूरी हुईं अथवा नहीं। प्रथम तो इसे नोट निष्कातने का एकाधिकार केवल इतीभिये दिया गया था कि जिससे इसका देश की नफ्ती और गार पर पूरा नियन्त्रण हो। इम्पीरियल बैंक इसमें इसी कारणों से सफल नहीं हो सका था कि उसे यह एकाधिकार नहीं दिया गया था। किसी देश में उसकी प्रत्यक्ष-प्रणाली का नियन्त्रण नहीं हो सकता है जब उसके क्रय-शक्ति पर नियन्त्रण हो। अब, क्योंकि कुछ देशों में तो यह क्रय-शक्ति केवल नोटों अथवा नोट और सिक्कों की ही होती है, अतः, नियन्त्रणकर्ता का इनके निष्कातने पर भी पूरा अधिकार होना चाहिये। यम, भारतवर्ष इसी तरह का देश है। हाँ, जहाँ तक नोटों और सिक्कों के मुलनात्मक महत्व का प्रश्न है, वह यह है कि श्वर कुछ दिनों में नोटों का चलन तो बंद रहा है और सिक्कों का बंद रहा है। अतः, यह कहा जा सकता है कि आजकल यहाँ पर नोटों का चलन सिक्कों की अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। अतः, नियन्त्रणकर्ता का नोटों पर आवश्यक नियन्त्रण होना चाहिये। जहाँ तक चेम्बा की करन्सी (Cheques) के नियन्त्रण का प्रश्न है, वहाँ तक इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। किन्तु इतना सत्र होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि बैंक ने इस सम्बन्ध में जिस नीति का अनुसरण किया है वह देश के बहुत हित में नहीं रही है। इसके स्वयं के लिए यह बहुत भाग्य की ही बात समझनी चाहिये कि यह ऐसे समय में स्थापित किया गया था जब मन्दी का समय बीत चुका था। यदि सन् १९२७ का बिल पास हो जाता तो सन् १९२८ में बैंक स्थापित हो जाता और शायद इसने भी सरकार की ही तरह मुक्त द्वारा नीति का पालन करते हुए उस समय का सकट असहाय दृष्टि से देखा होता और उसकी बुराई अपने ऊपर ली होती। किन्तु सन् १९३५ में भी यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और सन् १९३६-३७ में इस सम्ब-

*इनकी भी यह सल्लाह भारतवर्ष और पाकिस्तान दोनों को मिलाकर है।

२२ में काफी वाद-विवाद था जिसमें अधिकांश सम्मति रुपये का मूल्य घटाने (Devaluation) के पक्ष में थी।

सन् १९३८ में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और विनिमय की बहुत माँग थी जिससे हमारा स्टर्लिंग कोष कम होता गया। किन्तु रिजर्व बैंक ने उस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। द्रव्य की स्थिरता के सम्बन्ध में युद्धकाल में जो स्थिति रही है उसके विषय में भी कुछ कहना व्यर्थ ही है। करन्सी के पृष्ठ पर गिरे हुये मूल्य का स्टर्लिंग रखकर इसने जो ब्रिटेन के युद्ध व्यय का बोझ भारतवर्ष के ऊपर डाल कर मुद्रा-प्रसार किया था, वह तो किसी से छिपा ही नहीं है। वास्तव में इसने अपने करन्सी का कोष ऐसे रूप में एकत्रित होने दिया जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति समाप्त हो चुकी थी। इसके विपरीत केन्द्रीय बैंकिंग का तो यह सिद्धान्त है कि उसे अपना सम्पूर्ण कोष द्रवित स्थित में ही रखना चाहिए। फिर जहाँ तक विधान ने ही नोटों के सम्बन्ध के कोष के विषय में नियम बना रखे हैं उसमें रुपये के विनिमय का मूल्य स्थिर रखने का अधिक ध्यान दिया गया है। नोटों के भुगतान का उनका विचार नहीं रखा गया है। शायद ऐसा मान लिया गया है कि यहाँ की जनता का उन पर पूरा विश्वास है, किन्तु यह सत्य नहीं है। वास्तव में बात तो यह है कि उनका उन पर विश्वास न होने के कारण ही यहाँ पर लोगों में नोता चादी रखने का अधिक चाव है। इससे यहाँ की बैंकिंग प्रणाली को यथेष्ट दबनति नहीं हो पाई है। फिर, नोटों के और बैंकिंग के विभागों के अलग-अलग होने में भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। यह तो केवल अंग्रेजी प्रणाली की ही नकल है जिसे सन् १८४४ से जब यह वहाँ पर अपनाई गयी थी। इधर ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर किसी देश ने भी अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी है। वास्तव में अब करन्सी सिद्धान्त और बैंकिंग सिद्धान्त की कोई लड़ाई ही नहीं।

जहाँ तक जमा की करन्सी के नियन्त्रण का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि इस सम्बन्ध की केन्द्रीय बैंक की शक्ति एक तो इस बात पर निर्भर है कि बैंक अपनी नीति से इस पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं और दूसरे उन पर केन्द्रीय बैंक का कितना प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ बैंकों का जमा की करन्सी निर्धारित करने में तनिक भी प्रभाव नहीं है, वास्तव में यह साल की उत्पत्ति पर निर्भर रहता है। यहाँ पर बाजार प्रायः बैंकों ने श्रृण नहीं लेता। अतः, साल की उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता और फिर जमा की करन्सी के निर्धारित होने का प्रश्न भी नहीं उठता। जहाँ तक रिजर्व बैंक और सदस्य बैंकों के

करन्सी निकलवा ले वह यह अन्तर दूर नहीं कर सका। किन्तु यह बैंक अवश्य इसमें बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सका है। इसका बैंक दर नवम्बर सन् १९३५ से ही ३ प्रतिशत रहा है और यह तेजी के समय की करन्सी की सारी माँग अपने बैंकिंग विभाग की नोटों की सम्पत्ति कम करके पूरी कर लेता है। यह ऐसा कहाँ तक करता है, इस बात का पता उसके नोटों की अधिक से अधिक और कम से कम रकम के बीच की अन्तर का पता लगाकर मालूम किया जा सकता है। वास्तव में यह उस १२ करोड़ रुपये से अधिक रहता है जितने का अन्तर इन दोनों समयों में मन्दी के पहले के काल में अर्थात् सन् १९२१-२६ के बीच में इम्पीरियल बैंक की नकदी के बैलन्स में हो जाया करता था।

यह बैंक बैंकों का फेल होना रोकने के उद्देश्य से भी स्थापित किया गया है। ऐसी आशा की जाती है कि यह आवश्यकता पड़ने पर उन बैंकों की सहायता करेगा जो हमेशा अपनी स्थिति अच्छी रखते हैं। इसके पास जो केन्द्रित कोष हैं और नोट निकालने के अधिकार हैं उनसे यह ऐसा बहुत असानी के साथ कर सकता है। किन्तु इसने नावकोर नेशनल ऐन्ड क्लिलन बैंक के सम्बन्ध में जिसके ऊपर सन् १९३८ में संकट पड़ा था, ऐसा नहीं किया और वह फेल हो गया। उसके फेल होने के कुछ दिन पहले उसने इससे आर्थिक सहायता माँगी थी और इसने उसे यह देने से इसलिये अस्वीकृत कर दिया था कि यह इसके पहले उसके हिसाब-किताब इत्यादि का निरीक्षण करना चाहता था। इसमें सन्देह नहीं कि यह केवल उसके बड़े-बड़े ऋणों की ही जाँच करता। किन्तु जैसा कि उक्त बैंक की तरफ से कहा गया था और वह ठीक ही था, ऐसा करने से उसकी बदनामी हो जाती जिससे और भी बुराई पैदा हो जाती। यहाँ पर यह कह देना भी आवश्यक है कि अब तो बैंक जब चाहे तब किसी बैंक की भी जाँच कर सकता है। फिर, इसने उसे इसलिये भी श्रृण नहीं दिया कि इस बात का भी निश्चय नहीं था कि उसके कौन से पाउने ब्रिटिश भारत के लेनदारों के ऋण के भुगतान में और कौन से देशी रियासत के लेनदारों के ऋण के भुगतान में काम में आ सकेंगे। हाँ, अब तो स्थिति बहुत ही बदल गई है। उन रियासतों के बैंक भी इसके नियन्त्रण में आ गये हैं जो भारत के यूनियन में सम्मिलित हो गई हैं।

युद्ध काल में भिन्न भिन्न आदेशों से और अब १९४६ के नये बैंकिंग विधान से इसे बड़े अधिकार प्राप्त हो गये हैं। ईयर इसने बंगाल के बैंकों के आर्थिक संकट और देश के विभाजन से उत्पन्न हुई स्थिति से पता और

हिन्दू लोगोंने जो भी नष्ट पड़ा नाम डाला गिरा दिया था। ए-
ने जाने भीर मरगा। इनके पद में किम्वदन्तियाँ हैं। इनके मृत्यु
गोपनीय के लिये ५ दिनांका तथा तीसरे भाग में नामों पर १५ अक्षर
दिया। इनके इनके नाम में कोई भी नष्ट नहीं। हा, इस ईश्वर ने इन
मल में १० वर्ष के नाम दिया कि हिन्दू का नाम २५ नाम में पूरा होता
रहा। १० वर्ष के नाम प्रसार होता रहा जिसमें यहाँ के लोगों को बहुत बड़
नामों का नाम पड़ा। इनके अतिरिक्त इनके नामों पर भी प्रयोग भी
नहीं किया कि जिसने यहाँ के लोगों की बड़ी मान दृष्टि। फिर, इनमें हिन्दू
नामाङ्क के अक्षर गुरुगुरु अक्षरों के मोह में नानामाङ्कों में गिरा दिया
यह सब वर्ग पर होता। इनके ईश्वर नाम पर देखा। मन्दिर में यह नाम का
नक्का है कि यह मन्दिर का नाम बड़ी अच्छी तरह से मानता था। इनमें उन्हीं
अच्छी मन्त्रों में ही भीर यदि यह भी भी तो माननी नहीं गई। बल्लभ में
ऐसा नहीं होता चाहते थे। मन्दिर का गिरा दिया तो फोटे भी इन मन्त्रों में,
अन्वीरियत 'हूँ' ही यह नाम मन्त्रों का था।

बैंक दर नीति

माल नियन्त्रण के लिये यहाँ पर बैंक दर नीति का अन्त जेम्स ह्यूजे
रियन बैंक के गुरुने कर ही पहले-वर्ष उनसे दिया गया था। किन्तु ईश्वर नामों
से यह बात उपयोगी नहीं सिद्ध हो सका। प्रथम तो इंग्लिश बैंक स्थापित हो
इने साख-नियन्त्रण के लिये नाम में नहीं लाना चाहता था। वह तो लाभ बनाने
का उद्देश्य ही सामने रखता था और यदि अपनी बैंक दर में कुछ ह्रास
करता था, तो उन्हीं बिलों में करता था। फिर, इस नीति का प्रभाव तभी पड़ना
है जब बैंक केन्द्रीय बैंक के उपर मास उत्पन्न करने के लिये निर्भर रहते हैं।
किन्तु यहाँ यह बात नहीं थी। यहाँ के बैंक तो इंग्लिश बैंक ने बहुत कम
अर्थ लेते थे क्योंकि न तो वह इसे अपने बिल ही देना चाहते थे और न इससे
वैध ही अर्थ लेना चाहते थे। बिलों से इनके उनके ग्राहकों का नाम मालूम हो
जाता था और ऐसा होने से इनके उन ग्राहकों का व्यवसाय अपने हाथ में ले
लेने की आशंका रहती थी। जहाँ तक अर्थ का प्रश्न था, ऐसा करने से उन्हें
इस बात की आशंका रहती थी कि कहीं यह उन्हें उदनाम न कर दे। फिर, यह
उनमें से बहुतों की तो सकट के समय सहायता भी नहीं करता था। प्रन्तिम
बात यह कि यहाँ पर बाजार भी बैंकों से बहुत सहायता नहीं लेते थे। जहाँ तक

होता था, वह स्वयं अपनी आवश्यकता पूरी कर लेते थे। फिर, इनमें से प्रत्येक के व्याज की दर उसकी अपनी स्थिति के अनुसार रहती थी और उसमें भी चलन का बड़ा हाथ रहता था। द्रव्य की माँग और पूर्ति का बहुत कम प्रभाव पड़ता था। इंगलिस्तान में जैसा कि ७वे अन्वयाय में बताया जा चुका है कि बैंक दर और व्याज की अन्य दरों का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है, किन्तु भारत-वर्ष में न तो यह पहले ही था और न अब ही है।

फिर, हम यह भी देख चुके हैं कि विदेशों में बैंक दर वह दर है जिस पर केन्द्रीय बैंक प्रथम श्रेणी की जमानतों पर ऋण देते हैं अथवा प्रथम श्रेणी के बिल डिस्काउन्ट करते हैं। किन्तु इम्पीरियल का दर केवल प्रथम प्रकार का ही दर था। दुन्दियाँ डिस्काउन्ट करने के लिये एक दूसरा दर था जिसे डिस्काउन्ट दर कहते थे। यह दर कभी ऊँची तो बैंक दर से ऊँचा और कभी-कभी नीचा रहता था। बैंक दर सप्ताह में एक बार निर्धारित होता था और प्रायः उससे बीच में बदलता नहीं था, किन्तु दुखी दर बाजार की दैनिक स्थिति के अनुसार बदलता-बदलता रहता था।

हाँ, रिजर्व बैंक का बैंक दर अवश्य ऐसा है जिस पर वह प्रथम श्रेणी की जमानतों पर ऋण देने के लिये तैयार रहता है और साथ ही प्रथम श्रेणी के बिल भी डिस्काउन्ट करता है। यह अवश्य ही अन्य देशों के बैंक दर की तरह है, किन्तु यहाँ स्थिति भिन्न है। हमारे यहाँ बिल तथा दुन्दियाँ बहुत नहीं चलतीं। अतः, उन्हें चलाने के लिये यह आवश्यक है कि डिस्काउन्ट की दर व्याज की दर से भिन्न हो और कुछ कम भी हो। यह प्रचलित प्रथा के विपरीत तो अवश्य होगा किन्तु देश के लिये लाभप्रद होने के कारण अवश्य ही माना जाना चाहिये।

जब रिजर्व बैंक खुला था, यह सोचा गया था कि कई कारणों से इसका बैंक दर इम्पीरियल बैंक के बैंक दर की अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली होगा। प्रथम तो सदस्य बैंकों को इसके पास अपनी स्थाई तथा चालू जमा का क्रमशः कम से कम ५ प्रतिशत तथा २ प्रतिशत अवश्य बैलन्स के रूप में रखना पड़ता है और यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कमी पर बैंक दर से कुछ अधिक दर के हिसाब से व्याज देना पड़ता है। इससे यह सोचा गया था कि बैंक दर से नीची दर पर ऋण नहीं देंगे और साथ ही इसमें ऊँची दर पर जमा नहीं प्राप्त करेंगे। फिर इन बैंकों को इससे अपने बिल भुनाने में जरा भी

खुले बाजार में काम करने की नीति

रिजर्व बैंक खुले बाजार में भी काम कर सकता है, अर्थात् देश के व्यापार, व्यवसाय, उद्योग-धन्धों और कृषि के हित में साथ नियन्त्रण करने के उद्देश्य में आवश्यकता पड़ने पर बाजार में प्रत्यक्ष रूप से काम कर सकता है। किन्तु ऐसा करने की आवश्यकता अभी तक नहीं पड़ी है। हमें इस सम्बन्ध के नियम तो भली-भाँति समझ लेने ही चाहिये ताकि हमें यह मालूम हो सके कि इनका यह अधिकार अपने उद्देश्य तक पहुँचने में कहाँ तक सफल हो सकता है।

खुले बाजार में काम करने की नीति का प्रभाव इस बात पर निर्भर रहता

ह कि केन्द्रीय बैङ्क इस काम के लिये कितने साधन एकत्रित कर सकता है, कितनी प्रौर किस तरह की सम्पत्ति वह रख सकता है और जिस बाजार में काम करता है। उसका कैसा संगठन है।

रिजर्व बैङ्क के पास जो साधन हैं वह (१) पूँजी और सुरक्षित कोष (२) सरकार की नकदी, (३) सदस्य बैङ्कों की नकदी, (४) विलों की वसूली और द्रव्य इधर से उधर भेजने के लिये जिस सीमा तक इसका प्रयोग किया जाता है उनके और (५) नोटों के चलाने के हैं। जहाँ तक (१) पूँजी और सुरक्षित कोष का सम्बन्ध है, वह १० करोड़ रुपया है। इन्टीग्रियल बैङ्क की पूँजी और सुरक्षित कोष इसमें अधिक है। हाँ, इसकी पूँजी और कोष भी आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है। जहाँ तक (२) सरकारी नकदी का प्रश्न है, वह तो प्रत्येक वर्ष, माह, दिन बदलती रहती है। उसके पूर्ण धन और समय का खुले बाजार में काम करने की शक्ति पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ सकता है। जहाँ तक (३) सदस्य बैङ्कों की नकदी का प्रश्न है, वह भी बराबर बदलती रहती है। प्रायः बैङ्कों को जितनी नकदी इसके पान रखनी चाहिये उससे अधिक वे इसके यहाँ नकदी रखते हैं। किन्तु ऐसा भी होता था कि बैंक कम नकदी रखकर जुर्माना देकर काम चला लेते थे। अतः, इधर ऐसे नियम भी बन चुके हैं कि यह बैंक जब चाहे तब ऐसे बैंकों को अधिक जमा लेने से रोक दे। जहाँ तक (४) का अर्थात् इस बात का प्रश्न है कि विलों की वसूली तथा द्रव्य इधर से उधर भेजने के लिए इसका कहाँ तक प्रयोग किया जाता है, बैंक ने इधर द्रव्य भेजने की बड़ी सुविधाये दे दी है। किन्तु विलों के प्रयोग की श्राद्ध बढ़ाने का अब भी प्रश्न है। प्रायः द्रव्य टी० टी० से भेजा जाता है, दर्शनी ट्राफ्ट कम प्रयोग में आते हैं। वास्तव में दर्शनी ट्राफ्टों से ही द्रव्य भेजे जाने पर ही बैंक की खुले बाजार में काम करने की शक्ति निर्भर है और इस समय इस मद में इसके पास उतना द्रव्य नहीं रहता है जितना कि इस काम में सहायता पहुँचा सकता है। जहाँ तक (५) अर्थात् नोट निकालने का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इसके विधान में इसे काफी लोचप्रद बना दिया गया है।

बैंक के पास जो सम्पत्ति रह सकती है वह निम्नांकित है—(१) कुछ विदेशी सरकारों के वह साप पत्र जो फ्रय के दस वर्षों के अन्दर पकने वाले हों (यह कितने रुपयों के ही रखे जा सकते हैं) और (२) भारत सरकार

एक के पाग जितने के मास-पत्र रहत हैं अथवा बाजार में मिल पाते हैं उतनी ही कम्पनी का परिमाण घट-बढ़ नमूना है। इस मुद्दे में कम्पनी इसी बात पर ध्यान दी कि स्टॉर्किंग और खरीदो दोनों के मास-पत्र प्राप्त थे। इसी पर ने रुहे बाजार में बेचकर प्रत्येक मनुष्य को भी किया जा सकता है।

अतः, हमें उस बाजार के नियम में समझना है जिसमें बैंक काम कर सकता है। यहाँ के मुख्य स्टॉक एक्सचेंज प्रमुख और कलस्त्रे के हैं। किन्तु इनके कुछ सदस्यों की सहायता लन्दन और न्यूयार्क के स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों की सहायता की तुलना में कुछ नहीं है। अतः, इनमें काम करने का उतना प्रभाव नहीं पड़ सकता है। हाँ, यह अवश्य है कि बैंक की बहुत कुछ संपत्ति के स्टॉर्किंग मास पत्रों में होने के कारण जितने विदेशों में भी काम किया जा सकता है, कुछ कठिनाई कम हो जाती है।

बैलन्स शीट

रिजर्व बैंक की बैलन्स शीट दो भागों में विभक्त रहती है—(१) नोट विभाग में और (२) बैकिंग विभाग में। यह साप्ताहिक होती है। नीचे एक नमूना दिया हुआ है —

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया

(अ) मार्च २५, १९४६

नोट विभाग

(करोड रुपये मे)

दायित्व

निकाले हुये नोट :--

बाहर	११६६ ३५
बैंकिंग विभाग मे	२१ ७६

११६१ ११

पाउने

सोना ४० ०२

विदेशी साख-पत्र ७४१ ६२

७८१ ६४

रुपये—

भारतवर्ष के ४२ ०२

रुपयों के साख-पत्र ३६७ ४५

देशों विल, इत्यादि .

११६१ ११

सोने और विदेशी साख-पत्रों का सम्पूर्ण दायित्व में अनुपात

६५ ६२ प्रतिशत

बैंकिंग विभाग

(करोड रुपये मे)

पूँजी	५	
सुरक्षित कोष	५	नकद २१ ८८
जमा—		
(अ) केन्द्रीय सरकार की	१८३ ६३	कय किये हुए और डिस्काउण्ट किये हुये विल—
(ब) अन्य सरकारों की	२४ ५६	(अ) देशी ० ३८
(स) बैंकों की	५५ ०४	(ब) विदेशी
		(स) सरकारी ट्रेजरी विल १ ७५
		विदेशों में बैलन्स २०२ ५२
		सरकार के ऋण
		अन्य ऋण ६ ३६

विनियोग १३५ ६७

प्रश्न

(१) रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ ? इससे उत्पन्न परिणाम समझाएँ ।

(२) रिजर्व बैंक के केन्द्रीय और व्यापारिक बॉम्ब के कार्य बताइए । यह जान में कार्य नहीं कर सकता है ?

(३) रिजर्व बैंक को स्थापना के पक्ष में मान कोष में प्रारम्भिक काम करने पड़े थे । इसके कार्यों और विभागों के संगठन के विषय में आप जो कुछ जानने को चाहें ।

(४) रिजर्व बैंक ने क्या काम किया क्या किया है ? आपकी समझ में अब उसे क्या करना चाहिये ?

(५) आपकी समझ में रिजर्व बैंक को माध्य नियन्त्रण के लिए जो अधिकार दिए गए हैं वह काफी हैं या नहीं ? इस नियन्त्रण में आपकी क्या सुझाव हैं ?

(६) रिजर्व बैंक को एक कन्वियन बैलन्स शीट बनाइए और उसकी प्रत्येक सद समझाइए ।

अध्याय २०

बैकिंग विधान

सन् १९४६ के पहले भारतवर्ष में कोई पथक बैकिंग विधान नहीं था । हाँ, एक बैकिंग कम्पनी को एक साधारण कम्पनी से पृथक् करने के लिये १९१३ के कम्पनी विधान में कुछ प्रयुक्त अवश्य थे --

(१) जन साफे के साधारण संगठन में साक्षियों की संख्या २० हो सकती है तब बैकिंग के संगठन में यह केवल १० ही हो सकती है ।

(२) बैकिंग के काम करने वालों को रजिस्टार के यहाँ अपने काम करने के सभी स्थानों का नाम भेजना आवश्यक है ।

(३) बैकिंग कम्पनी को रजिस्टार के यहाँ नियत समय पर अपनी बैलन्स शीट भेजनी आवश्यक है और उसमें जमानत पर जिये गये श्रृंख और जमानत के बिना दिये गये श्रृंख अलग-अलग दिखाना अनिवार्य है ।

(४) दूसरा काम करने वाली कम्पनियों का निरीक्षण तो उनसे १० प्रतिशत सदस्यों की प्रार्थना पर किया जा सकता है, किन्तु वैकिङ्ग की कम्पनियों में ऐसा तभी हो सकता है जब कम से कम २० प्रतिशत सदस्यों की ऐसा करने की प्रार्थना हो ।

किन्तु देश में यह राय थी कि वैकिङ्ग के नियन्त्रण के लिये इतना ही यथेष्ट नहीं है । केन्द्रीय कमेटी तो एक विशेष विधान के पक्ष में थी । हाँ, विदेशी विशेषज्ञों ने कुछ सशोधन मात्र करने की ही सलाह दी थी । अतः, भारत सरकार ने उन्हीं की राय के अनुसार सन् १९३६ में कम्पनी विधान में निम्न सशोधन किये —

(१) वैकिङ्ग कम्पनी की एक परिभाषा दी । किन्तु यह सतोपजनक नहीं थी । रिजर्व बैङ्क के कार्यकर्ताओं ने यह शिकायत की थी कि ब्रिटिश भारत में ऐसे बहुत से गरसदस्य बैङ्क थे जो उक्त परिभाषा के अनुसार बैङ्कों की श्रेणी में नहीं आते थे । अतः, वह रिजर्व बैङ्क को वह सूचना नहीं देते थे जिसे देना उनके लिये अनिवार्य कर दिया गया था ।

(२) कोई वैकिङ्ग कम्पनी तब तक रजिस्टर्ड न हो, जब तक वह अपने योजना-पत्र में उद्देश्यों के अन्तर्गत यह न लिख दे कि वह केवल जमा प्राप्त करने के तथा वैकिङ्ग कम्पनी की परिभाषा में दिये हुये कामों में से कुछ अथवा सब काम ही करेगी, जो कम्पनियाँ पहिले काम कर रही थीं, उन्हें यह विधान पास होने के दो वर्षों के अन्दर ही अपने गैर वैकिङ्ग के कार्य बन्द कर देने होंगे ।

(३) उक्त विधान पास होने के दो वर्षों के बाद से कोई वैकिङ्ग कम्पनी किसी भी ऐसे मेनेजिङ्ग एजेंट द्वारा नहीं चलाई जा सकेगी जो वैकिङ्ग का काम न करता हो ।

(४) कोई वैकिङ्ग कम्पनी तब तक अपना व्यवसाय नहीं प्रारम्भ कर सकती जब तक कि उसके इतने हिस्से न बिक जायें कि उसके पास कम से कम पचास हजार रुपये आ जायें । सचालकों को इस सम्बन्ध का एक प्रमाण-पत्र भी देना होगा ।

(५) कोई वैकिङ्ग कम्पनी अपनी अप्राप्त पूँजी पर कोई ऋण नहीं ले सकेगी ।

(६) रिजर्व बैङ्क के सदस्य बैंकों को छोड़कर प्रत्येक बैंक को लाभ की वंटनी करने के पहले उससे उस समय तक कम से कम २० प्रतिशत सुर-

विषय में एक विशेष सूचना देनी पड़ेगी और उसे बैलन्स शीट की लिफ्ट के साथ-साथ दफ्तर में दिखलाना पड़ेगा। विदेशी बैंको को भी फार्म एच (H) में कुछ सूचनाये देनी पड़ेगी।

(१३) प्रत्येक कम्पनी सचालक को चाहे वह बैंकिंग की हो अथवा अन्य किसी व्यवसाय के सम्बन्ध की हो, हिस्से के हस्तांतरित करने के आवेदन-पत्रों पर अपनी स्वीकृति की सूचना अधिक-से-अधिक दो मास के अन्दर दे देनी पड़ेगी।

फिर, १९३६ में रिजर्व बैंक ने कुछ सशोधन पास करने के लिये सुझाव दिये। किन्तु प्रथम सशोधन १९४३ में पास हुआ। यह रिजर्व बैंक की वह शिकायत दूर करने के उद्देश्य से किया गया जो बैंकों के उसे वह सूचना न भेजने के सम्बन्ध की थी जो उन्हें उसके पास भेजना अनिवार्य था। अतः, तब से कोई भी ऐसी सस्था जो अपने नाम के आगे 'बैंक' शब्द लगाती थी, बैंक मानी जाने लगी।

सन् १९४४ में निम्न सशोधन पास हुये :—

(१) कोई बैंकिंग कम्पनी चाहे वह ब्रिटिश भारत में गठित हुई हो अथवा बाहर किन्तु यदि भारतवर्ष में काम करती है तो यह विधान पास होने के दो वर्ष बाद किसी मैनैजिङ्ग एजेंट द्वारा नहीं चलाई जा सकती। न वह कोई ऐसा व्यक्ति ही रख सकती है जिसका प्रतिफल अथवा जिसके प्रतिफल का कुछ भी अंश कमोशन के रूप में अथवा कम्पनी के लाभ के प्रतिशत के रूप में देने का निश्चय हुआ हो। न वह किसी से एक बार में पाँच वर्षों से अधिक तक उसे चलाने का कोई समझौता कर सकती है।

(२) जिस बैंकिंग कम्पनी का इस विधान के अनुसार सन् १९४७ की १५ जनवरी को अथवा उसके बाद संगठन हुआ है। वह इस सन् १९४४ के विधान के लागू होने के दो वर्ष बाद ब्रिटिश भारत में उस समय तक व्यवसाय नहीं कर सकती जिस समय तक वह निम्न शर्तें पूरी नहीं कर देती :—

(१) उसकी कीत पूँजी उसकी अधिकृत पूँजी की आधी है और उसकी प्राप्त पूँजी भी उसकी कीत पूँजी की आधी है।

(२) उसके हिस्से केवल साधारण हैं अथवा यदि सप्ल भी हैं तो वह यह सशोधन पास होने के पहिले के हैं।

(३) प्रत्येक हिस्सेदार का मताधिकार उसकी पूँजी के अनुपात में है।

किन्तु एक पृथक बैंकिंग विधान की आवश्यकता के कारण सन् १९४८ में नवम्बर में एक बैंकिंग बिल यहाँ की व्यवस्थापिका सभा में रखा गया और

(२) जोर देकर मुन्शी प्रहलन्त न निगल सके। कुछ देर ऐसा करने लग गये कि वे १० मिनटों नोट का श्राव करते थे।

(३) कोर्ट में, रिजर्व बैंक से ग्राहक जिना न वो कोर्ट नई शाह गीत सजेगा और न कोर्ट शाह गीत सजेगा। रिजर्व बैंक ग्राहक देने के पहले प्रार्थना देना शि. १५, व्यवस्था, ग्राहक धिति लाभ की सम्मानना जन-रित इत्यादि का ध्यान करेगा।

१९४६ का बैंक बिल १९४७ में केंद्रिय सभा में आया। किन्तु उसी वर्ष स्वतन्त्रता बिल पास हो गया। अतः सरकार ने एक नया बिल रखने का निश्चय किया जो १९४८ में रक्का गया और १९४९ में पास हुआ। १९४७ के एक आदेश द्वारा रिजर्व बैंक में कुछ साधारण जमानतों पर भी ऋण देने की गारंटी दे दी गई जिससे वह उस समय के संकट में पड़े हुये बैंकों को सहायता कर सकें। किन्तु इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी और वह १९४८ में समाप्त हो गया। इसके बाद कि यह उसी वर्ष बैंकिंग कंपनियों के नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश में सम्मिलित कर लिया गया। इसमें रिजर्व बैंक को बैंकों की साधारण तथा किसी भी विशेष बैंक की उधार देने की नीति निर्धारित करने और ऋण का उद्देश्य, उन पर जमानत तथा व्याज इत्यादि निश्चित करने का अधिकार भी दे दिया गया। साथ ही उसे निम्न अधिकार भी दे दिये गये—

(१) बैंकों से उनके देने और पाउने की मासिक सूचना और उधार तथा विनियोग के किस्मों की छमाही सूचना माँगने का अधिकार।

(२) बैंकों को उनके हिस्सों पर ऋण देने अथवा उनके संचालकों को अथवा उन फर्मों तथा निम्न कंपनियों को जिनमें कोई संचालक कोई अपना हित रखता हो, जिना जमानती ऋण देने की मनाही करने का अधिकार।

(३) प्रत्येक बैंक से भारतीय प्रान्तों में उसके देने का कम से कम ७५ प्रतिशत कुछ विशेष पाउनों में रखवाने का अधिकार ।

(४) बैंकों के एकीकरण के लिये इससे पूर्व आशा प्राप्त करने का अधिकार ।

(५) कुछ स्थितियों में बैंकों का इतिकर्ता नियुक्त होने का अधिकार ।

१९४६ के विधान में उपर्युक्त बातों के साथ-साथ निम्न बातें भी सम्मिलित हैं :—

(१) भारतवर्ष में काम करने वाले सब बैंकों के रिजर्व बैंक से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का दायित्व ।

(२) गैर सदस्य बैंकों का उनकी माँग पर देय तथा एक निश्चित अवधि पर देय जमा की उतनी ही प्रतिशत नकदी रखने का जितनी सदस्य बैंकों को रखनी पड़ती है और एक मासिक सूचना भेजने का दायित्व ।

(३) सब बैंकों के निम्न दायित्व .—

(अ) उपर्युक्त विधान पास होने के दो वर्ष बाद अपनी माँग पर देय और एक निश्चित अवधि पर देय जमा का कम से कम पचमाश नकदी, सोने अथवा भाररहित स्वीकृत सिक्कोरिटियों में रखने का दायित्व ।

(ब) भारतवर्ष के प्रान्तों और उसके अन्तर्गत रियासतों में उनकी जमा का कम से कम ७५ प्रतिशत रखने का दायित्व ।

(४) एक बैंक के संचालक दूसरे बैंक के संचालक न हों और न मैनेजिङ एजेण्ट ही नियुक्त किये जायें ।

*Please see last chapter
for its defects & proposals*

अध्याय २१

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

द्वितीय महायुद्ध के समय यह अनुभव हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति के लिये प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति आवश्यक है । कुछ राष्ट्र तो पहले ही से पिछड़े हुये थे, कुछ की दशा युद्ध काल में बिगड़ चुकी थी और शेष की युद्ध काल के बाद बिगड़ने की सम्भावना थी । प्रथम महायुद्ध के बाद ससार के देशों की जो स्थिति थी उसकी पुनरावृत्ति होने देना बुद्धिमानी नहीं थी ।

जिन्हें आवश्यकता है वे इसी कारणवश उसे प्राप्त कर सकते हैं। बैंक गारण्टी की हुई रकम पर कम से कम १ प्रतिशत और अधिक से अधिक ११ प्रतिशत फीस ले सकता है। कर्ज लेने वाले को ऋण दाता को सूद भी देना पड़ता है।

बैंक ने मई १९४७ में पहले-पहल फ्रान्स को २५ करोड़ डालर का ऋण दिया। फिर बाद में २६३ करोड़ डालर का ऋण निदरलैंड्स, डेनमार्क, लक्जमबर्ग और चाइल को मिलाकर दिया। इसके बाद तो यह बराबर दिये जा रहे हैं। इनकी ६½ वर्षों से ३० वर्षों तक के बीच में वापिसी की शर्त है और इन पर २½ से ३½ प्रतिशत तक का व्याज है। साथ ही एक प्रतिशत का कमीशन है जो एक विशेष कोष में एकत्रित किया जा रहा है। लक्जमबर्ग का ऋण बेल्जियन फ्रैंक और निदरलैंड्स का स्विस फ्रैंक में था और अन्य ऋण प्रायः संयुक्त राष्ट्र के डालर में हैं। यूरोपीय देशों को पहले जो ऋण दिये गये थे वह उनकी युद्ध के कारण बिगड़ी हुई परिस्थिति ठीक करने के लिये दिये गये थे किन्तु बाद में उन्हें तथा अन्य देशों को भी-ये ऋण वहाँ की विद्युत् शक्ति, यातायात, कृषि और औद्योगिक विकास के लिये दिये गये हैं। भारतवर्ष भी अब तक इस प्रकार के दो ऋण ले चुका है।

बैंक ने ससार के प्रमुख द्रव्य बाजारों में कुछ ऋण भी लिये हैं। इनमें से प्रथम दो तो संयुक्त राष्ट्र के द्रव्य बाजार से लिये गये थे। फिर, अन्य बाजारों से विशेषतः स्विस बाजार से लिये गये हैं।

बैंक एशियाई तथा अन्य पिछड़े हुये देशों की बड़ी सहायता कर सकता है।

अध्याय २२

देश का विभाजन और उसका बैंकिंग पर प्रभाव

१५ अगस्त १९४७ को देश का विभाजन हो गया। इसके साथ ही गवर्नर जनरल ने उस वर्ष का पाकिस्तान (द्रव्य प्रणाली और रिजर्व बैंक) आर्डर निकाला जिससे पाकिस्तान की करन्सी और बैंकिंग प्रणाली के पृथक् चलाने वाली मशीनरी स्थापित होने तक दोनों देशों में एक ही द्रव्य प्रणाली चलाने

अप्रैल १९४८ ने गिरा १९४८ ने पाकिस्तान सरकार ने अपने हुए नोट पाकिस्तान में चलाना प्रारम्भ कर दिया था। उसी दिन के यहाँ पर एक रुपये के नोट तथा अन्य पाकिस्तानी सिक्के भी चलाने लगे थे। ये सब ये रण पाकिस्तान ही में विधानतः मान्य थे।

जुलाई १९४८ ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बन गया। ११ सरकार और हिस्सेदारों में मिला हुआ बैंक है। इसकी ३ जगहों में ५१.९० फूँजी तो सरकार की है और शेष हिस्सेदारों का है। इसका प्रमुख दफ्तर कानून की एक सचालक मण्डल द्वारा किया जाता है, जिनमें से एक गवर्नर ब्रह्मनाथ है, छह सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं और तीन कराची, लाहौर तथा दामा के स्थानीय मण्डलों का और ने एक एक करके आते हैं। इसके भी रिजर्व बैंक-ग्राफ इण्डिया ही की तरह के तीन स्थानाय मण्डल हैं। उसके दफ्तर कराची, लाहौर, दामा चटगाँव और पेशावर में हैं। कराची और लाहौर में तो रिजर्व बैंक के पहले से ही दफ्तर थे। दामा में रिजर्व बैंक ने पाकिस्तानी सरकार की प्रार्थना पर अप्रैल १९४८ ने एक दफ्तर खोल लिया था। अतः, ये तीनों दफ्तर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर बन गये। बाद में दो अन्य दफ्तर भी खुले। जुलाई १९४८ से यह बैंक पाकिस्तानी नोट निकाल और अन्य कार्य कर रहा है।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अप्रैल १९४८ से जून १९४८ तक में ५१-५७ करोड़ रुपये के पाकिस्तानी नोट निकाले थे। अतः, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना पर वह सब नोट उक्त बैंक के दायित्व मान लिए गए और रिजर्व

बैङ्क नोट विभाग के इसी मूल्य के पाउने उसे दे दिए गए । दिए जाने वाले पाउनों में ३ ३२ करोड़ रुपये के एक एक रुपये के पाकिस्तानी नोट और सभी मुद्रायें भी थीं । भारत सरकार के पाकिस्तान में चलने वाले नोट तब से बराबर पाकिस्तान में एकत्र करके रिजर्व बैङ्क को वापिस दिये और उनके स्थान पर उससे उसके अन्य पाउने लिए जा रहे हैं ।

बैकिंग विभाग के पाउनों में से भी लगभग १२० करोड़ रुपये के पाउने जो पाकिस्तानी सरकारों और बैंकों के उसके पास बैलन्स थे वे स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान को हस्तान्तरित कर दिए गये । इनमें अधिकांश स्टर्लिङ्ग के रूप में थे ।

पाकिस्तान स्थित बैंकों का नियन्त्रण स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान के हाथ में है । उसके भी सदस्य तथा गैर सदस्य बैंक और उनके भी दायित्व तथा अधिकार हैं । यद्यपि वह बैंक भी रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ही की तरह काम करता है तो भी अभी हमारे पास उसके सम्बन्ध की पूरी सूचनायें नहीं हैं ।

यहाँ पर देश के विभाजन के उपरान्त पंजाब और दिल्ली में जो हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए उनसे बैंकों की जो हानि हुई उसका भी संकेत कर देना आवश्यक मालूम पड़ता है । बैंकों ने विभाजन के पहले ही पंजाब, इत्यादि से प्रायः अपने बहुत से पाउने हटा दिए थे । वहाँ पर उन्होंने अपनी लागतें भी कम लगा रखी थीं । जिनके प्रधान दफ्तर वहाँ थे उन्होंने उन्हें दिल्ली हटा लिया था । किन्तु तो भी दंगों का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा । लोगों की सम्पत्ति लुट गई । लाखों व्यक्ति भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत चले आये । उनकी अधिकांश सम्पत्ति वहीं रह गई । जिनकी बैंकों में जमा थी उन्होंने तो वह दूसरे राज्य में भी जाकर माँगी किन्तु जिनके ऊपर कर्ज था उनका पता ही नहीं लगा । कर्जदारों की सम्पत्ति लुट गई थी । ऐसी स्थिति में सचमुच बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई । किन्तु बैंकों को मदद दी गई । जमा लाटालने के सम्बन्ध में उन्हें समय दिया गया । उन्हें ऋण भी दिया गया है । फिर शरणार्थियों की सम्पत्ति के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच में समझौते भी हो रहे हैं । जो हो, स्थिति का बहुत ही उचित ढङ्ग से मुकामला किया गया ।

भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच में आर्थिक सहयोग आवश्यक होगा । दोनों में बैंकिङ्ग की एक ही सी स्थिति है वरन् पाकिस्तान को भारतीय बैंकों का सहारा और उनसे सहाय लेना पड़ेगा ।

अध्याय २३

दोष और भविष्य

विद्युत् प्रणाली में भारतीय बैंकिंग के अतिरिक्त विद्युत् का दिग्दर्शन किया गया है। अतः इस अध्याय में हम उसके दोष और भविष्य का अध्ययन करेंगे।

एक अच्छे संगठित द्रव्य बाजार की कमी—भारतीय के द्रव्य बाजार में निम्न समस्याएँ हैं—रिजर्व बैंक प्रायः स्थिर, इन्फ्लेशन बैंक प्रायः स्थिर, भूमिगत बैंक, निम्न विदेशी बैंक, सापेक्षतः नए नए सरकारी, भूमिगत बैंक, अल्प दत्त, निधि, चिट फंड, और अनुदानाग्राहों के लेख अनेक प्रकार के देशी महाजन जिन्हें बैंक भी करते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ दिनों पहले तक सरकार भी काफी भाग लेती थी। निम्न उक्त नीति तो अब रिजर्व बैंक के हाथ में है किन्तु अब भी उसके सम्बन्ध में जो बैंकिंग का काफी काम करते हैं। यह वचन और लागत के लिए जो कुछ करते हैं, उसका अध्ययन तो हम कर चुके हैं। उसके अतिरिक्त वे द्रव्य इधर से उधर भेजने की और बी० पी० में इसकी वसुली करने की सुविधा भी देते हैं।

रिजर्व बैंक की स्थापना के पहले इन सब के बीच में किसी प्रकार की साम्यता नहीं थी। उन्हें एक नेता की भी आवश्यकता थी। रिजर्व बैंक की स्थापना ने यह कठिनाइयाँ तो कुछ अंशों तक दूर हो गई हैं। उसका आधुनिक बैंकों पर पूर्ण नियन्त्रण है। इससे कुछ काल में और विशेषतः १९४६ के रेग्युलेशन विधान के पास हो जाने के बाद से तो यह बहुत ही दृढ़ हो गया है। किन्तु इसके अतिरिक्त अल्प दत्त, चिट फंड, निधि और अनुदानाग्राहों सहित बहुत से देशी महाजन हैं जिनके ऊपर इसका प्रतिकूल भी नियन्त्रण नहीं है। सच्चे में हम यह कह सकते हैं कि द्रव्य का भारतीय बाजार दो सगठन मिला-कर बना है—एक आधुनिक बैंकों का और दूसरा देशी महाजनों का और इनमें से आधुनिक बैंकों का सगठन रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में है किन्तु देशी महाजन प्रतिकूल स्वतन्त्रतापूर्वक काम करते हैं। जहाँ तक इनकी पारस्परिक साम्यता का प्रश्न है, वह भी आदर्शरूप में नहीं है।

यह दोष दूर करने के लिए पहले ही कुछ सुझाव रखे जा चुके हैं। इसमें

देशी महाजनों को रिजर्व बैंक से सम्बन्धित करना, और भिन्न-भिन्न वर्गों में साम्यता उत्पन्न करना सम्मिलित हैं।

विल बाजार न होना

यहाँ के द्रव्य बाजार का एक अन्य दोष विल बाजार न होना है। इसके निम्न कारण हैं।

(१) भारतवर्ष के बैंक सरकारी साख-पत्रों में लागत लगाना अधिक पसंद करते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना के पहले उन्हें यह विश्वास ही नहीं था कि इम्पीरियल बैंक उनकी हुण्डियों डिस्काउण्ट कर देगा। उसने उनका कोई स्तर तो नहीं रखा था और किसी भी हुन्डी को स्तर के अनुसार नहीं है, कह करके डिस्काउण्ट करने से इनकार कर देता था। फिर बैंक स्वयं भी उससे हुण्डियों डिस्काउण्ट कराने के स्थान पर सरकारी साख-पत्रों के अधिकार पर ऋण लेना अधिक पसंद करते थे क्योंकि हुण्डियों के भुनाने में उन्हें इस बात का डर रहता था कि इम्पीरियल बैंक उनके ग्राहकों का नाम जान जाने के बाद उनके प्रतिद्वन्द्वी होने के नाते कहीं लाभ न उठा ले। इसके अतिरिक्त यदि इम्पीरियल बैंक सरकारी साख पत्रों के आधार पर ऋण देना मना कर देता था अथवा चही इसके लिये इम्पीरियल बैंक के पास नहीं जाना चाहते थे तो इन्हें बाजार में बेचा जा सकता था। हाँ, रिजर्व बैंक की स्थापना से अब यह सब कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं, किन्तु पुरानी प्रथा तो चल ही रही है। ऐसा विशेषतः इसलिये है कि रिजर्व बैंक ऋण देने में और विल डिस्काउण्ट करने में एक ही ढर चार्ज करता है। ऋण देने में डिस्काउण्ट करने की अपेक्षाकृत कुछ ऊँची ढर चार्ज करने से डिस्काउण्ट करने का काम बढ सकता है। बैंक दर यहाँ पर केवल डिस्काउण्ट दर होना चाहिये।

सरकारी साख-पत्रों की लोकप्रियता का एक अन्य कारण उनके द्वारा काफी ऊँची आय मिलना भी था। किन्तु अब ऐसा नहीं है।

(२) माल के अधिकार पत्र चालू न होने के कारण यहाँ पर व्यापारिक बिलों और सहायक बिलों के बीच में भेद करना अमम्भव सा हो जाता है। इसके लिये गोदाम होने चाहिये और गोदामों की रसीदें हस्तांतरित करके माल को बिक्री होनी चाहिये जिससे उनके सम्बन्ध के जो बिल हों उनके सुवृत्त के लिये यही गोदामों की रसीदें रहे। ऐसा करने से व्यापारिक बिलों और सहायता के लिये किये गये बिलों में भेद किया जा सकेगा।

(३) नरक नाम की प्रणाली चालू होने से भी बिलों की गमी गन्ती है। 'सुग' या यह कर भी पैक और श्रृण लेने वाला दोनों की दृष्टि में अन्धा है। किन्तु बिलों के और अधिक लाभ हैं। यतः, उन्हें नरक नाम की अपेक्षा अधिक उपयोग में लाना चाहिये।

(४) फल यह मिल सम्पत्ति भी समझना चाहिये। यदि यह कि इन पर न्याय उठे तो बहुत नगानी थी, किन्तु इस पर तो यह दोष दूर कर दिया गया है।

(५) बिल दो विदेशी हैं। अतः, उनमें विदेशी भाषा का प्रयोग होने के कारण उन बिलों पर अधिक लोचप्रिय तो ही नहीं रहते। हमारे यहाँ विदेशी भाषा जानने वाले लोग तो बहुत कम हैं। किन्तु हमारी तो यहाँ पर अन्य दिनों ने चालू है। हाँ, हमारी इमारत इनकी फटिन है। यदि उन्हें याद रखना कुछ मुश्किल प्रमाण है। उन्हे कुछ सादी बना देना चाहिये। फिर, इनके सम्बन्ध में प्रच्छा अधिमा देने वाले पुनर्वा का विधान प्रवर्धन लागू है, किन्तु भवानीय चलन का भी अधिक महत्त्व है। अतः उनमें भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न होने के कारण उनका संख्या फोल्डिंग हो जाना प्रासज्य है।

(६) विदेशी व्यापार के कारण जो बिल उत्पन्न होते हैं वे प्रायः स्टिलिंग में होते हैं। यदि वह यहाँ की करों में हो तो यहाँ पर एक निल गजार बन जाय।

(७) यहाँ पर रगलिस्तान की तरह पर बिलों पर स्वीकृति देने वाली कोठियाँ नहीं हैं। पैक भी अपने प्रादको की ओर से मिल नहीं स्वीकार करते। यदि वह व्यवसाय बढ़ाया जाय तो भी यहाँ पर बिल गजार प्रवर्धन बन जाय।

(८) अन्य देशों में कृषि सम्बन्धी बिलों का भी प्रयोग होता है। इनके सम्भावित बिल (Anticipatory bills) कहते हैं, और यह अमेरिका में बहुत प्रयोग में लाये जाते हैं। अतः, यह यहाँ भी प्रयोग में आ सकते हैं। सहकारी गोदाम समितियाँ भी स्थापित की जा सकती हैं, जो कृषकों को उनका मदद होने पर उपज के ऊपर श्रृण दे सकती हैं। इसके लिये वे समितियाँ उन पर (कृषकों पर) बिल कर सकती हैं। फिर, ये समितियाँ उन्हें जिले की सहकारी सरया से और वे उन्हें सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों से ग्रहण रिजर्व बैंक से भुना सकती हैं। जिस तरह से सहकारी समितियाँ बिलों का प्रयोग कर सकती हैं, उसी तरह से श्रृण देने वाले महाजन भी उनका प्रयोग कर सकते हैं।

करन्सी की इकाई पर अविश्वास

भारतीयों का अपनी करन्सी की इकाई पर विश्वास नहीं है। जहाँ तक हो सकता है वह अपनी बचत सोने, चाँदी तथा भूमि की सम्पत्ति में रखते हैं। इसके कई कारण हैं। प्रथम तो उनका यह अनुभव है कि यहाँ की करन्सी का मूल्य मनमाना कर दिया जाता है। देश के अन्दर तो यह परिवर्तित हो ही नहीं सकती और इसका मूल्य दिन पर दिन गिरता ही जाता है। फिर, यहाँ के भूमिपति बड़ी मान-मर्यादा की दृष्टि में देखे जाते थे। इनका बड़ा प्रभाव है। हमारी स्त्रियों को भी गहनों का बड़ा शौक है। इसका एक आर्थिक कारण भी है। हमारे यहाँ विधवाओं को केवल उनका स्त्री धन छोड़कर जिसमें केवल उनका गहना ही रहता है और किसी धन पर अधिकार नहीं है। बैंक बैलन्स और सप साप-पत्र मदों के ही होने हैं, स्त्रियों को उनका उत्तराधिकार नहीं मिलता।

किन्तु अब स्थिति बदल रही है। जमींदारी प्रथा नष्ट हो रही है। स्त्रियों को भी उत्तराधिकार दिया जाने वाला है। अतः, स्थिति सुधरने की आशा है।

बैंकों पर अविश्वास

बैंकों पर अविश्वास स्थाई और अस्थायी दोनों हो सकता है। पश्चिमीय देशों में भी अविश्वास है, किन्तु वह केवल सकटकाल के ही समय रहता है। भारतवर्ष में वह स्थाई भी है और ऐसे समय में भी हो जाता है। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि सकटकाल के लिये जो रक्षा के उपाय किये जाते हैं उनसे दैनिक रक्षा और दैनिक रक्षा के लिये जो उपाय किये जाते हैं, उनसे सकटकाल के समय की रक्षा होती है। किन्तु सुविधा के विचार से इनका अध्ययन अलग-अलग ही किया जाना चाहिये।

स्थायी अविश्वास तो बैंकों के लगातार फेल होने से उत्पन्न हो जाता है। कोई भी ऐसा वर्ष नहीं होता जब कुछ बैंक फेल न होते हों, किन्तु इनका यहाँ पर उतना अधिक महत्व नहीं है जितना उन देशों में है जहाँ की बैंकिंग प्रणाली बहुत उन्नत अवस्था को पहुँच चुकी है, अथवा बैंकिंग अथवा कम्पनी विधान अधिक सख्त है। सन् १९३६ के भारतीय कम्पनी विधान के संशोधन के पहले बैंक शब्द की कोई ऐसी परिभाषा नहीं थी कि वह केवल अच्छी संस्थाओं के नाम के साथ ही लग सकता। अतः, बहुत सी सन्देहयुक्त संस्थाएँ भी बैंक की जाती थी और उनके फेल होने से बैंक का फेल होना समझा जाता था। तब से बैंक की परिभाषा बन गई है और उसकी पूँजी कम से कम

पन्नाम हजार स्यादा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनका दतना भी मरदिय होनी चाहिए। किन्तु पुगने के बाद ही नजर रहे। अगर जो बैंक फोन होंगे उनका जान करने पर हमें यह बात होना है कि उनमें से अधिकतर हमी तरह के हैं। अतः भविष्य में हम बैंक फोन होंगे। इस सम्बन्ध में भी अन्य बातें नीचे। एक तो प्रायः नये बैंक ही फोन होते हैं। यदि मोटे बैंक बहुत दिनों तक चला जाता है तो यही उनके अन्तर्गत प्रमाण हो जाता है। दूसरे, यह कि प्रायः योद्धा ही बैंकों के अध्यक्ष होते हैं और जो ऐसी भाषा की जाती है कि सभी बैंकों में बैंकी और उनका मरदिय होय एक साथ से कम न होगा तो उनका फोन होना भी कम में लक्ष्यगा।

अब हम यह देखेंगे कि प्रायः बैंक क्यों बन्द हुए, जिससे हमें रोड़े लाने के लिए उपाय मिल जायें।

एक तो बैंक प्रायः फालूनी होते हैं के कारण, जनता भी अज्ञानता के कारण और पुरे तथा बेदमान प्रबन्धकों के कारण बन्द हुए हैं। हमें जो बैंक सितार लिये हैं उनमें पूना बैंक, पूना, अमृतसर नेशनल बैंक, अमृतसर इन्डिस्ट्रियल बैंक, मुलतान, शिपगम प्रथम बैंक, मद्रास, पायनियर बैंक, बम्बई और क्रेडिट बैंक आदि आठवां जो हमें १९२४, १९२३, १९१४, १९३२, १९१६ और १९१३ में फेल हुए थे विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। क्रेडिट बैंक आफ इटाली के व्यवस्थापक ने अपनी नियुक्ति के समय सचालकों से अपनी बैंकिंग और एकाउंटिंग की अनभिज्ञता दिखाते हुए एक मजदूर फर्मेटो लाने की माँग रखी थी। बैंक फेल होने तक भी ऐसा कि हमने स्वयं कहा था, हमने कुछ भी नहीं सीखा था।

यह कमी फालूनी दूर की जा सकती है जिसने आवश्यकता यहाँ पर सन् १९१३-१४ के संकटकाल के समय से ही प्रतीत होने लगी थी। किन्तु यह बेबल १९३६ में ही अशत जमी १९४६ ही में पूर्णतः पूरी हो सकी। नये विधान में विशेषतः इस बात का ध्यान रखा गया है कि जनता बैंकों के अज्ञान तथा बेदमान सस्थापकों से बच सके। यदि सचालक प्रबन्ध व्यवस्थापक और एग्जीक्यूटिव गलत बात कहते हैं तो कई परिस्थितियों में वह जुर्म करते हैं। फिर, उनके ऊपर द्रव्य के गलत उपयोग का, गलत तरीके पर गैर रखने का और अमानत में खानत करने का विसमें कोई काम करके अथवा न करके कर्तव्य विमूढ़ होने का अपराध भी सम्मिलित है, अपराध लग सकता है। गलत हिमात्र रखने पर भी सजा देने का नियम रखा गया है।

दूसरे, बहुत से बैंक इसलिये भी फेल हुये हैं कि उन्होंने बैंकिङ्ग के कोष से उद्योग धन्यों को भी आर्थिक सहायता दी थी। इनमें से लाहौर के पिंडपिल बैंक और अमृतसर बैंक और टाटा इन्डस्ट्रियल बैंक के नाम जो क्रमशः सन् १९१३, १९१४ और १९२३ में फेल हुये थे, विशेष उल्लेखनीय हैं। वस्तुतः भारतवर्ष में लोग जर्मनी और जापान के तरीके पर सम्मिलित बैंकों के पक्ष में हैं, किन्तु यहाँ पर यह इसलिये सम्भव नहीं है कि यहाँ की बैंकिङ्ग की प्रणाली अंग्रेजी बैंकिङ्ग प्रणाली के सदृश्य विकसित हुई है और उसकी यह विशेषता है कि व्यापारिक बैंकिङ्ग और औद्योगिक बैंकिङ्ग अलग-अलग ही रहें। हाँ, कुछ बड़े बैंक विशेष आशा से यह काम करें, तो कोई हर्ज नहीं है।

तीसरे, बहुत से बैंक इस कारण भी फेल हुये हैं कि उनके अप्सरों ने सट्टेबाजी में भाग लिया था। ऊपर के कुछ बैंक इसलिये भी फेल हुये थे, किन्तु इंडियस स्पेशी बैंक के सन् १९१४ में फेल होने का यही एक कारण था। बैंक के प्रारम्भ से ही इस बात की खबर थी कि बैंक सट्टेबाजी में फँसा हुआ था, किन्तु यह कहा जाता था कि यह गलत है और छिपाया जाता था। श्री-चुनीलाल सरैया जो बैंक के व्यवस्था संचालक थे और जिनका नाम इससे सम्बन्धित था, बहुत ही चतुर व्यक्ति थे। वह ऊपरी सजावट में होशियार थे और वर्ष के अन्त में अच्छी बैलन्स शीट दिखला देते थे। किन्तु अन्त में एक साधारण हिस्सेदार ने जिससे इनकी वैयक्तिक शत्रुता कही जाती थी, इसके भग करने की प्रार्थना हाईकोर्ट में दी। पहले तो हिस्सेदारों और संचालकों ने इसका विरोध किया और सब ठीक मालूम पड़ने लगा, किन्तु फिर श्री चुनीलाल का यकायक हृदय की गति रुक जाने से देहान्त हो गया और संचालकों ने स्वेच्छा से बैंक की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रार्थना पत्र भेज दिया, बाद की जाँच से आरोप ठीक ही निकला।

चौथे और अन्तिम, प्रायः बैंक इस कारण भी फेल हुये हैं कि जनता का मत किसी न किसी समय उनके विरुद्ध हो गया। उन्हें तो अभाग्य का शिकार ही समझना चाहिये। इनमें से एक तो मेरठ का बैंक आक्रा और इंडिया था जिसकी रजिस्ट्री सन् १८६३ में हुई थी। यह सन् १९१४ तक बराबर उन्नति दिखलाता रहा, किन्तु उस वर्ष यकायक फेल हो गया। इसके जमा करने वालों और हिस्सेदारों दोनों को पूरा रुपया मिला। दूसरा, शिमला का अलायस बैंक था। सन् १८७४ में स्थापित होकर यह सन् १९२३ तक काम करता रहा, किन्तु उस वर्ष फेल हो गया। इसे तो इस कारणवश बुरे दिन देखने पड़े कि

बोल्डन वर्म ने जो हमके लन्दन के अदालतों में, इसके १२० लाख रुपये जो उनके द्वारा चालिये थे, नहीं दिये। इसके एक दूसरे कृष्णों अर्थात् पानर ट्रस्ट आफ इण्डिया की स्थिति भी अत्यन्त नहीं थी। ब्रिटिश सचानमै न प्रमो मन् १९२० की रिपोर्ट में यह बात साफ पढ़ने लगे। अन्तु, मोन्टगुमरी डर्ल वल्ली गवर करता ही जमा निकलने प्रारम्भ हो गई और वेष्ट फल हो गया। हम सम्प्रत्य न मानसो नेशनल मिलन वेष्ट का भी फल होना उन्नेपनीय है। हमने सन् १९३३ में भगवान देना ट्रस्ट कर दिया। भुगतान के समय हमकी स्थिति देखो ही ली है जो उस समय भी जरा दो वर्ष पहले मानसो नेजाल के और मिनट में दोनों एक हुए थे। इन दोनों ईसाई ग पहल का इतिहास बहुत ही उल्लेख है। फिर, रिपोर्ट में जो मर्यादा के बाद इसका हम प्रचार फल होता कुछ और नहीं था और मिनटन। हमने विचार किया कि यह उनका एक सदस्य है जो था। रिपोर्ट में इसकी मर्यादा क्यों नहीं की, यह तो पहले ही बताया जा चुका है। इस उदाहरण से भी पता हो गया है। हमें सम्प्रत्य ने जमा प्राप्त करने की मनाही कर दी थी। अतः जनता में हम पर ने निश्वास उठ गया और यह जमा निम्नलिखित लोगों और बैंक फल हो गया। किन्तु अब तो रिपोर्ट में प्रायः देश की मर्यादा करता है। १९४६ के अमान के और फिर १९४७ के पन्ना के मर्यादा के समय हमने बहुत से बैंक फल होने में प्रचार्ये।

अब हम फिर बैंकों के प्रति स्थायी निश्वास के कारणों की ओर आते हैं। उनके लगातार फेल होने के साथ-साथ इसके अन्य कारण भी हैं। एक तो एक अच्छी वैज्ञानिक विधान न होने में भी बड़ी हानि होती है। अन्तः वैज्ञानिक विधान से जनता का कई प्रकार से विश्वास बढ जाता है। प्रथम तो इनके कारण अच्छी व्यवस्था रहती है और शक्ति के साथ-साथ उनके दुर्न-प्रयोग की कम सम्भावना होती है। हम सम्प्रत्य में इधर सन् १९३३ का कम्पनी विधान और १९४६ का वैज्ञानिक विधान पार करके जो कुछ भी किया गया है, उसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। दूसरे, हमसे हिसाब की ठीक विज्ञप्ति भी हो जाती है। भारतीय कम्पनी विधान में बैलन्स शीट का एक रूप दिया हुआ है, जिसके अनुसार सब कम्पनियों को अपनी बैलन्स शीट बनानी पड़ती है। हाँ, बैंकों को कुछ विशेष बातें दिखानी पड़ती हैं। किन्तु यह असतोषजनक ही है। उनके लिए तो बैलन्स शीट का एक प्रथक रूप ही रोजना चाहिये। ऊपर जिन विधानों का उल्लेख किया गया है, उन्होंने भी ऐसा न किया। हाँ, पुरानी बैलन्स शीट में कुछ सुधार अवश्य कर दिये।

जब वैलन्स शीट में कुछ सूचनाये नहीं रहतीं तो उसके कई प्रभाव पड़ते हैं। प्रथम तो जो बैंक अच्छे हैं उनकी अच्छी स्थिति का पता नहीं लगता। दूसरे, बुरे बैंकों के सम्बन्ध में अनभिज्ञ जनता को कुछ नहीं मालूम हो पाता। तीसरे, उपयुक्त अक्र नहीं प्राप्त हो पाते। चौथे और अन्तिम यह है कि अन्तिम लेखों के सम्बन्ध में कोई सदृश्यता न होने से तुलना करने में कठिनाई पड़ती है। उपर्युक्त के अलावा बैंकिंग के कानून का यह ध्येय होता है कि उन्हें जब कठिनाइयाँ पड़े तब उन्हें वह दूर कर दे। वे जमा करने वाले की रक्षा करने हैं और यह कई प्रकार से हो सकती है। ऐसा इसलिए ही नहीं किया जाता कि इन लोगों की रक्षा का अधिकार अन्य व्यापारियों के लेनदारों की रक्षा के अधिकार से अधिक है, बल्कि इसलिए कि किसी बैंक के फेल होने से अन्य व्यापारियों पर भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है।

सकट के समय जो अविश्वास पैदा हो जाता है, उसे दूर करने के लिए बहुत से सुझाव रखे जा चुके हैं। प्रथम तो सरकार को उस समय बैंकों की सहायता करनी चाहिये। किन्तु भारत सरकार इस सम्बन्ध में बराबर हिचकिचाती रहती थी। इसका मुख्य कारण यही था कि वह विदेशी थी। मन् १९१३-१४ के बैंकिंग के सकटजाल में यद्यपि जनता बहुत कुछ कहती रही, किन्तु इसने कुछ भी न किया। हाँ, उस समय वाइसराय ने यह अवश्य कहा था कि यदि कुछ करने की आवश्यकता पड़ी तो वह कुछ ही बैंकों के सम्बन्ध में की जायगी और उसी समय के लिए होगी। सन् १९२३ में जब अलायन्स बैंक ने भुगतान करना बन्द कर दिया तब उसने इम्पीरियल बैंक को इस बात का आदेश दिया कि वह उसका काम अपने हाथ में ले ले और उसके चालू खातों और वचत खातों पर ५० प्रतिशत फौरन दे दे और इस तरह से उसके एक प्रधान कर्मचारी ने जो दस वर्ष पूर्व कहा था, उसे पूरा किया। जिन कारणों से यह किया गया था, वह भी बड़े मार्के के थे। पहिले तो अर्थ सचिव ने यह कहा था कि यह इसलिए किया गया था कि अंग्रेजी और भारतीय द्रव्य बाजारों में उस समय जो अच्छी स्थिति थी वह वैसी ही बनी रहे, जिससे सरकार को ऋण लेने में सुविधा रहे और साथ ही उसके अच्छे बजट के कारण जो अच्छा प्रभाव पड़ा था वह भी बना रहे। किन्तु बैंक के चालू और स्थायी खातों की जमा केवल ७ करोड़ ६० थी। अतः, इतने का हित बचाकर उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने की बात बड़ी विचित्र थी। अतः, यह बात समझ कर फिर उन्होंने यह कहा कि यह इसलिए किया गया था कि यह भारतीय अर्थ

और 'विनि' के हित के लिए बहुत ही आवश्यक था और इसने अन्य राष्ट्रीयताओं को प्रेरित किया, तात्पर्य यह है। अतः, इस तरह से जनजाति में उन्नति सरकार की जिम्मेदारी बढ़ा दी। विन्तु यहाँ के लोगों ने दूसरी ही बात सोची। उनका ध्यान था कि यह प्रलापन बैंक के अधिकार प्रादुर्भाव के कारण होने के कारण उनके हित की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। इस बात की परीक्षा का समय मई १९३८ में रावनकोर बैंक के फंड होने के समय आया। विन्तु इस सम्बन्ध में हमने कुछ नहीं किया। डॉ. य. क. कानना सरकारी, उस समय तक विपत्ति बहुत कुछ बढ़ गई थी। प्रांतीय सरकारों के अधिकार बढ़ाये जा चुके थे। अतः, इस सम्बन्ध की जिम्मेदारी उनकी हो गई थी। इस सम्बन्ध में मद्रास सरकार ने जो कुछ किया वह प्रशंसनीय था। रावनकोर बैंक की अधिकार शाखाएँ उसी प्रान्त में थी। यहाँ जो कुछ किया गया, वह स्वाभाविक ही था। जब बैंक के ऊपर सरकारी आया नहीं मद्रास सरकार ने रिजर्व बैंक ने सम्मति की और इसके ताले चराने के लिए कहा गया। विन्तु यह समय ताले का नहीं था। फिर, प्रधान मंत्री ने जनता में शान्ति करने की प्रतीति की और कहा कि वह अफवाहों में विश्वास न करे। उन्होंने यह भी घोषित किया कि अन्य बैंकों की भी जाँच की जायगी और कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इनके दो महीने बाद उन्होंने यह विज्ञापित किया कि वहाँ के सदस्य बैंक की विपत्ति बहुत अच्छी है और जिन लोगों ने रिजर्व बैंक ने सहायता ली थी, उन्होंने भी उसे वापिस कर दिया है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो रिजर्व बैंक फिर उनकी सहायता करेगा। यह भवमुच बढ़े माँके की बात थी। विन्तु जब कोई ऐसा बैंक है कि जिसकी शाखाएँ सारे भारतवर्ष में फैली हुई हैं तब तो केन्द्रीय सरकार को उद्वेग पड़ेगा। मई १९४६ में पंजाब में और १९४७ में पंजाब में तब बैंकों के ऊपर सरकारी हस्तक्षेप इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने जो कुछ किया, वह भविष्य के लिए आशा उत्पन्न करता है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक भी बहुत कुछ स्थिति सुधार सकता है। अगर वह कहीं तक ऐसा कर सकता है, इसके विषय में भी पहले ही बताया जा चुका है। पहले हमारे देश में कोई केन्द्रीय बैंक नहीं था। किन्तु यह कमी रिजर्व बैंक की स्थापना से दूर हो गई है। हाँ, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है, इस बैंक ने मई १९३८ में रावनकोर नेशनल एण्ड क्लिनिक बैंक की कुछ भी सहायता नहीं की। किन्तु १९४७ में पंजाब के सरकारी काल में

इसने जो कुछ किया है उससे हम आशा करते हैं कि भविष्य में यह बरतार बैंकों की मदद करतार होगा।

तीसरे, पत्रों और जनता की सम्पत्ति का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। सन् १९३१ के संयुक्त राज्य के आर्थिक संकट के समय उन्होंने यहाँ के जमा करने वालों में एक देश प्रेम की लहर पैदा करके, उनमें जो शांत विश्वास पैदा कर दिया था, वह बहुत ही प्रशंसनीय था। किन्तु इसके विपरीत संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में हगलैण्ड के संकट के बाद जब संकट पड़ा तब वहाँ के पत्रों और जनता ने इसके विपरीत किया। भारतवर्ष में भी यही बात होती थी। किस्तानी और अंग्रेजी पत्र यहाँ के सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों के विषय में बराबर झूठी अफवाहें उड़ाते रहे हैं। एक समय था जब यह पत्रों के मुख्य बैंक संस्थापक लाला हरिविशनलाल के विरुद्ध ऐसा किया करते थे। फिर जनता यहाँ आसानी से धनवाई जा सकती है। सेन्ट्रल बैंक के शत्रुओं द्वारा उड़ाई अफवाहों के कारण उस पर बराबर आक्रमण होते रहे किन्तु वह उन्हें बराबर संभालता रहा। किन्तु अब भविष्य में स्थिति सुधारने की आशा की जा सकती है।

अंतिम बात यह है कि बैंक स्वयं इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हें गम्भीर परिस्थिति के कारणों से बराबर अपनी रक्षा का उपाय करते रहना चाहिये और उसका प्रभाव कम कर देना चाहिये। यह वह अपने सम्बन्ध में अधिक प्रकाशन करके कर सकते हैं। वे जमा करने वालों के प्रतिनिधियों को अपने संचालक मंडल में लेकर उनमें विश्वास की मात्रा पैदा कर सकते हैं। चुनाव करने का अधिकार उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है, जिनका एक औसतन न्यूनतम बैलन्स रहता है और ऐसे लोगों की सूची दो या तीन वर्षों में दुहराई जा सकती है।

अन्य प्रकार की बैंकिंग की कमी

यहाँ के सम्मिलित पूँजी वाले बैंक केवल व्यापारिक बैंकिंग करने के लिए ही संस्थापित किये गये हैं। हाँ, औद्योगिक बैंकिंग का काम करने के लिए भी कुछ बैंक संस्थापित किये गए हैं, किन्तु उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई है। कृषि के अर्थ की कठिनाइयाँ दूर करने के लिये सहकारिता निकाली गई है किन्तु यह मिद्धान्त, उद्योग-धन्वों के लिये अर्थ देने के लिए नहीं अपनाया गया है। भारतीय बैंकों ने विनिमय व्यवसाय बिल्कुल छोड़ रखा है।

तन, ठाक इन्ने ग्रामाने की युग प्राप्तिप्रकृत है। मछेर में यह कहा जा सता है कि व्यापारिक वैदेशिक और कृषि वैदेशिक के व्यापार के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वैदेशिक के व्यापार पर नजर भी रखा नहीं दिया गया है।

अंग्रेजी प्रणाली की पूरी नकल

हमारे वैदेशिक अंग्रेजी प्रणाली की पूरी नकल है, जिसके फलस्वरूप सादगी का भारतीय आदर्श पूरी तरह से दुबरा दिया गया है। हमारे फलस्वरूप तो अतिनाइया उत्तरा की गई है उनका तो अध्ययन हम पर चुके है। यही कारण है कि इस देश में वैदेशिक, गोया में नहीं फैल सकी है।

विदेशी भाषा का प्रयोग

यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ के लोग बड़े लिखे की नहीं हैं, प्रेम की जानने की बात तो दूर रही। अतः वे अपने भाषा नहीं कर पाते। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग का कारण अंग्रेजी जानने वाले लोगों की निम्नलिखित की प्राप्तिप्रकृत पद्धति है जो उनको अच्छी बहुत कम होने के कारण, उनका चुनाव में नहीं छोड़ना है पड़ती है।

विदेशियों का प्रभाव

भारतीय ईश्वर पर विदेशियों का प्रभाव था और उनकी वास्तविक सहा-नुभूति भारतीयों से नहीं था। उनका उद्देश्य तो यहाँ लाभ कमाना था और यहाँ के लोगों को चूना था। ये लोग न तो यहाँ विश्वास ही उत्पन्न कर सके और न यहाँ की समस्याओं को ही सुनना सके। फिर, यहाँ के लोगों के साथ कोई निफटनम सम्बन्ध भी नहीं स्थापित कर सके। किन्तु अब परिस्थिति बदल रही है।

लोगों की कम आय

यहाँ की वैदेशिक की स्थिति इसलिये भी अच्छी नहीं है कि यहाँ के लोगों की आय बहुत कम है। उसकी धीमी उन्नति का कारण जितनी यहाँ की गरीबी है, उतनी अन्य कोई बात नहीं है। जो लोग आयकर देते हैं उनकी सख्या और आय की औसत, जमा करने वालों की सख्या, और औसत जमा की जाँच करने पर यहाँ के उस क्षेत्र की सकीर्णता का अनुमान किया जा सकता है जिसमें बैंकों को काम करना है। बहुत से मुश्किल लोग और उच्चतम समाज में रहने वालों के भी बैंकों में हिसाब केवल इसलिये नहीं हैं कि वह उनमें

न्यूनतम बैलन्स नहीं रख सकते। फिर, ऐसा भी है कि यह वैदिक न्यूनतम बैलन्स रखने का ऐसा नियम क्यों रखते हैं, जिससे बहुत से लोग उनसे लाभ नहीं उठा पाते हैं। किन्तु ऐसा इसलिये किया जाता है कि इससे उन सिद्धांतों का पालन होता है जिनका पालन होना वैदिक की सफलता के विचार से बहुत ही आवश्यक है। वैदिक इसीलिये न्यून बैलन्स निश्चित करते हैं कि उनके सदस्यों का एक न्यूनतम स्तर हो और उन्हें इतना लाभ भी हो सके कि वह उन्हें रखने का अपना खर्च पूरा कर लें।

वैदिक में शिक्षा की कमी

वैदिक के सिद्धान्तों और प्रयोगों की शिक्षा पाये हुये भारतीयों की भी बहुत कमी है। १६ वा शताब्दी के अन्त तक व्यवसाय तथा वैदिक की शिक्षा का तो यहाँ पर पूर्णरूप से प्रभाव ही था। इधर कुछ वर्षों से अवश्य इसकी व्यवस्था हो गई है किन्तु अभी तक जितनी सुविधाये दी जा चुकी हैं, लोग उनसे भी पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं। इसमें सफलता मिलने के लिये वैदिकों और विश्व-विद्यालयों में सहयोग की बड़ी आवश्यकता है।

वैदिकों के संगठन की आवश्यकता

वैदिकों का संगठन बहुत ही आवश्यक है। इसके उद्देश्य वैदिक के भिन्न-भिन्न वर्गों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना, उनकी समस्याये सुलभाने के लिये उनके एकत्रित होने का प्रवन्ध करना, पारस्परिक प्रतिद्वन्दता कम करना, लेक्चरों और पढाई का प्रवन्ध करके वैदिक के कर्मचारियों को शिक्षा देना, पुस्तकालय और वाचनालय रखना और पत्रिकायें, इत्यादि निकाल कर वैदिक सम्बन्धी साहित्य निकालना है। पश्चिमीय देशों में इन्होंने अपने काम करने के ढङ्ग में बड़ी उन्नति की है और लोगों में सदाचार पैदा कर दिया है। ये आकस्मिक भय दूर करने में बहुत ही सफल होते हैं। अतः इसलिये भी इनको इस देश में बहुत ही आवश्यकता है।

भविष्य

भारतीय वैदिकों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। देश में अब अपनी सरकार है। रिजर्व वैदिक राष्ट्रीय वैदिक है। इम्पीरियल वैदिक का राष्ट्रीयकरण यद्यपि अभी रुक गया है तो भी उसके विधान में आवश्यक सशोधन होने वाले हैं। रिजर्व वैदिक अब देश के हित में काम करेगा। उसकी करन्सी और साख नीति इसी ध्येय से चलेगी। व्यापारिक वैदिक अब उसके ऊपर अधिक निर्भर रह सकेंगे। उनके ऊपर उसका पूरा नियन्त्रण भी है। विदेशी विनिमय वैदिक भी

अपनी मर्यादा नहीं कर सकेंगे। उनके रूप में निर्देश का नियम है। देश में विनिमय दर मुक्त। मायद प्रसीमित बैंक की वह काम करने लगे। एक वैदेशीय प्रीमियम प्रमोशन का समर्थन हो हो चुका है। मायद इमीग्रेशन का उद्योग मन्त्री का सहायता पर श्रमिक प्रत्यक्ष बैंक-लेखा मायमि नकल का काम है। फिर इस काम में लिये अन्य बैंक की पुष्टि करेंगे।

निर्देशों का महत्त्व का एक स्पष्ट वहाच देशों में जनता की स्थिति सुधारना और पिछड़ी आर्थिक सहायता करना भी था। यह हमने नहीं किया। किन्तु अब वह नये प्रयत्न हो जाएगा। देश में यह प्रिय माना जा सकता है। हमने मजदूरों को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। उसके लिये प्रयत्न नोडाम मुलने चाहिये। अब हमारे विदेशी मित्र भी इसमें से ही लिये जायेंगे। अतः, यह बड़ी उन्नति की सम्भावना है।

यहाँ पर एक प्रश्न बहुत महत्व का है और वह वैश्व व्यापार के राष्ट्रीयकरण का है। समाजवादी तो इसके पूर्ण रूप से पक्ष में हैं। उनका कथन है कि बहुत कम गुना मात्र पैदा करने हमने लाभ कमाते हैं। अतः, यह काम राज्य को करना चाहिये। फिर, रक्षा के क्षेत्र में भी यह बात ही आवश्यक है। किन्तु हमारी सरकार के मामले अभी बहुत से अन्य काम भी हैं। उसकी मशीनरी अभी पुरानी ही है। अतः हमने लिये हम क्लिष्टता ठहर सकते हैं। बैंकों का नियन्त्रण तो अब उसके हाथ में ही है। अतः, वह इनका राष्ट्रीयकरण लिये बिना भी इन्हें जीने चाहें वेने चला सकते हैं। कुछ समय बाद तो यह होगा ही, किन्तु इसमें बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं और यह आवश्यक भी नहीं है।

प्रश्न

(१) भारतवर्ष की बैंकिंग की प्रणाली में कौन कौन से दोष हैं? इन्हें दूर करने के उपाय बताइये।

(२) भारतवर्ष में बिल क्यो नहीं चालू हैं, अधिक चालू बनाने के लिये कौन से उपाय हैं?

(३) इस देश में बैंक फेल होने के कौन कौन से कारण हैं? क्या इधर कुछ हालत सुधर गई है?

(४) देश की बैंकिंग की प्रणाली में जनता का विश्वास उत्पन्न करने के लिये कौन कौन से उपाय हैं? क्या इधर इस सम्बन्ध में कुछ किया गया है?